



विश्व का इतिहास

विश्व का इतिहास

लेखक

डा० शांतिलाल नागौरी

प्रकाशक

बाफना बुक डिपो'

चौडा रास्ता, जयपुर 3

विश्व का इतिहास

प्रकाशक	बाफना बुक डिपो, जयपुर
मुद्रक	राजस्थान कम्पोजिंग सेंटर, जयपुर
संस्करण	नवम्बर 1981
मूल्य	पिचहत्तर रुपये मात्र
©	प्रकाशकाधीन

विषय सूची

अध्याय

विषय

पृष्ठ संख्या

1 मध्यकालीन चर्च

1-25

(चर्च की स्थापना और उत्कर्ष के कारण चर्च की शक्ति में वृद्धि के कारण चर्च का समाज तथा राज्य पर प्रभाव चर्च के कल्पित चर्च का संगठन राज्य व धर्म के बीच संघर्ष इन्वैस्टीगैटिव स्ट्रुगल-संघर्ष के परिणाम चर्च के पतन के कारण चर्च की देन धर्म युद्ध (1096-1270) धर्म युद्धों के कारण-युद्ध की प्रमुख घटनाएँ-धर्म युद्धों के परिणाम)

2 सामन्तवाद

26-53

(सामन्तवाद के विकास के कारण सामन्तवाद का अर्थ तथा तत्त्व सामन्तवाद का स्वरूप-सामन्तवाद का संगठन-सामन्तों के अधि-कार-सामन्तों का जीवन-सामन्तों के फाय और उसकी समीक्षा-सामन्तता का चर्चों से सम्बन्ध सामन्त और राजा के बीच सम्बन्ध सामन्त तथा राष्ट्रीयता-सामन्तवाद से लाभ-सामन्तवाद के दोष सामन्तवाद के पतन के कारण सामन्तवाद का मूल्यांकन ।)

3 पुनर्जागरण

54-85

(आधुनिक युग का उदय-पुनर्जागरण का अर्थ-पुनर्जागरण की विशेषताएँ पुनर्जागरण के कारण-पुनर्जागरण का आरम्भ इटली में ही क्यों हुआ ? मानववाद का विकास मानववादी विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक-पुनर्जागरण के विकास का क्षेत्र (i) साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण (ii) कला के क्षेत्र में विकास (iii) विज्ञान के क्षेत्र में विकास (iv) भौगोलिक खोजों-खोजों के परिणाम पुनर्जागरण के प्रभाव ।)

4 धर्म सुधार आन्दोलन

86-115

(धर्म सुधार आन्दोलन का अर्थ धर्म सुधार आन्दोलन के उद्देश्य-धर्म सुधार आन्दोलन के कारण-आन्दोलन का विकास मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म का यूरोप पर प्रभाव प्रतिवादी धर्म सुधार धर्म सुधार आन्दोलन के परिणाम ।)

- 5 फ्रांस की राज्य क्रांति " 116 145
 (फ्रांस की राज्य क्रांति से पूर्व की स्थिति फ्रांस की राज्य क्रांति
 का कारण क्रांति की मुख्य घटनाएँ क्रांति की प्रगति फ्रांस की
 राज्य क्रांति का परिणाम ।)
- 6 नेपोलियन बोनापार्ट " 146 167
 (नेपोलियन का आरम्भिक जीवन-नेपोलियन के युद्ध नेपोलियन
 का वास्तुलेट काल (1799-1804) नेपोलियन के शासन
 सम्बन्धी बुधवार नेपोलियन की नीति (1804-1814 ई०) यूरोप
 पर प्रभुत्व का प्रथम-नेपोलियन पतन की ओर (i) महाद्वीपीय
 प्रणाली महाद्वीप व्यवस्था के परिणाम —
 (ii) नेपोलियन का पोप के साथ सम्बन्ध (iii) स्पेन में लड़ाई
 (iv) रूस के साथ युद्ध (v) राष्ट्रों से युद्ध (vi) वाटर लू का
 युद्ध 1815, वाटर लू युद्ध का महत्व-नेपोलियन के पतन के
 कारण नेपोलियन का स्थान ।)
- 7 औद्योगिक क्रांति - 168 189
 (क्रांति से पूर्व यूरोप की स्थिति औद्योगिक क्रांति का अर्थ
 औद्योगिक क्रांति का प्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई? औद्यो-
 गिक क्रांति के कारण-औद्योगिक क्रांति का विकास — (1)
 कृषि के क्षेत्र में विकास (2) वस्त्र उद्योग में क्रांति (3) लोहा
 और बाष्प शक्ति (4) परिवहन तथा संचार (5) प्रकाश के
 क्षेत्र में विकास-औद्योगिक क्रांति का प्रसार-औद्योगिक क्रांति का
 परिणाम ।)
- 8 राष्ट्रवाद (जर्मनी और इटली का एकीकरण) 190 231
 (राष्ट्रीयता का विकास नेपोलियन तथा राष्ट्रीयता वियना कांग्रेस
 तथा राष्ट्रीयता का विकास (1815-1848) जर्मनी
 का एकीकरण नेपोलियन और जर्मनी वियना कांग्रेस और जर्मनी-
 जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में कठिनाइयाँ जर्मनी में राष्ट्रीय
 एकता के प्रयास (1815-1850) जर्मनी का एकीकरण
 (1862-1871) —
 (i) डेनमार्क से युद्ध (1864)
 (ii) आस्ट्रिया से युद्ध (1866)
 (iii) फ्रांस प्रयास युद्ध (1870-71)
 युद्ध का कारण युद्ध की घटनाएँ फ्रांस प्रयास युद्ध के परिणाम इटली
 का एकीकरण इटली के एकीकरण के मार्ग में बाधाएँ इटली

के एकीकरण के अगुआ प्रयास मेजिनो (1805 1872)-नाम की 1848 की शान्ति का प्रभाव ताबूर और स्टो का एकीकरण एकीकरण की दूसरी सीढ़ी एकीकरण की तीसरी सीढ़ी और मेरी वाल्डी एकीकरण की अंतिम सीढ़ी जीर बिन्टर एमेनुअल जमनी और इटली के एकीकरण में अग्रगण्य हैं)

9 साम्राज्यवाद 232 245

(साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण अफ्रीका का विभाजन एशिया में साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद के परिणाम ।)

10 प्रथम विश्व युद्ध 246 274

(विस्माक की विशेष नीति विलियम द्वितीय की विश्व नीति त्रिगुण अंतर्राष्ट्रीय सन्धि (i) मार्को मवट (ii) वाल्कन सन्धि (iii) वाल्कन युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के कारण महामुद्र की घटाएँ विल्सन के चौदह सिद्धांत परिस शान्ति समझौता वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम ।)

11 रूस की क्रांति, 1917 275 300

(शान्ति से पूर्व रूस की दशा शान्ति के कारण-1905 ई० की शान्ति शान्ति की असफलता के कारण क्रांति का विवादास्पद — (i) मार्च 1917 ई० की शान्ति और जारशाही का पतन (ii) अक्टोबर 1917 ई० की समाजवादी शान्ति । (iii) बोल्शेविक क्रांति नवम्बर, 1917 शान्ति की सफलता के कारण रूस की शान्ति में लनिन और स्टालिन का योगदान शान्ति के परिणाम ।)

12 राष्ट्रसंघ 301 321

(राष्ट्रसंघ का जन्म राष्ट्रसंघ के उद्देश्य राष्ट्रसंघ का संरक्षकता प्रधान कार्यालय राष्ट्रसंघ के अगले डेट प्रणाली राष्ट्रसंघ की सफलताएँ — (i) राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएँ (ii) गर राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएँ राष्ट्रसंघ की अग्रगण्यताएँ राष्ट्रसंघ की अग्रगण्यता के कारण राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन ।)

13 आधुनिक चीन 322 345

(चीन में विद्रोहों का आगमन प्रथम अफगान युद्ध (1839 42) द्वितीय अफगान युद्ध (1856 1860) ताईपिंग विद्रोह शान्तिकारी सरकार के सुधार चीन का आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होना चीन की 1911 ई० की गणतन्त्रवादी शान्ति शान्ति के कारण डॉ० सनयातमेन प्रथम विश्व युद्ध और चीन

वाशिंगटन समझौता (1922) चीनी गृह युद्ध में बुओमितांग दल की शक्ति में वृद्धि 1911 ई० की क्रांति के परिणाम अथवा कोई देश का आधुनिकीकरण में योगदान चीनी जापानी युद्ध (1931) जापान का मंचूरिया पर अधिकार चीन में साम्यवादी क्रांति गृह युद्ध में साम्यवादी दल की विजय के कारण चीनी क्रांति में माओत्स तुंग का योगदान ।)

14 जापान का आधुनिकीकरण 346 363

(प्राचीन जापान जापान का पश्चिमी देशों से सम्पर्क में जी युग में जापान का विकास मुत्सोहिता का योगदान-जापान की साम्राज्यवादी नीति (i) चीनी जापानी युद्ध (1894-95) (ii) रूस के साथ युद्ध (1904-5) प्रथम विश्व युद्ध और जापान इक्कीस मार्च पेरिस क्रांति सम्मेलन और जापान वाशिंगटन सम्मेलन (1922) जापान द्वारा मंचूरिया पर अधिकार जापान की घोषणा (1934) साम्यवाद विरोधी समझौता (1936) द्वितीय विश्व युद्ध और जापान ।)

15 द्वितीय विश्व युद्ध 364 398

(अधिनायकवाद का उदय इटली में फासिस्टवाद का उत्थान फासिस्टवाद के उदय के कारण फासिस्टवाद के सिद्धांत मुसोलिनी की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध और इटली जर्मनी में नाजीवाद का उदय हिटलर का उत्थान नाजीदल के उत्थान के कारण हिटलर की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएँ द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम ।)

16 संयुक्त राष्ट्रसंघ 399 416

(संयुक्त राष्ट्रसंघ के जन्म का इतिहास संयुक्त राष्ट्रसंघ का चाट्टर संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धांत सन्स्थिता संयुक्त राष्ट्रसंघ के जग संयुक्त राष्ट्रसंघ की मुख्य समितियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ और राष्ट्रसंघ की तुलना संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपलब्धियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ की दुबलताएँ ।)

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
संलग्न प्रश्न सूची

16
67

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

अध्याय 1 मध्यकालीन चर्च

- 1 मध्यकालीन चर्च व्यवस्था का बणन कीजिए ।
- 2 धर्म युद्ध के क्या कारण थे ? उनके प्रभावों का बणन कीजिए ।
- 3 अद्वैत सभ्यता से आप क्या समझते हैं ? इस सभ्यता के कारणों और घटनाओं पर प्रकाश डालिए ।
- 4 मध्यकालीन यूरोप की चर्च की क्या दन है ? स्पष्ट कीजिए ।
- 5 निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) चर्च के उत्कर्ष के कारण (ii) बयम समझौता (iii) चर्च के राज्य के बीच सभ्यता के कारण ।

अध्याय 2 सामंतवाद

- 1 सामंतवाद के लाभ दापों का बणन कीजिए ।
- 2 सामंतवाद के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए ।
- 3 सामंतवाद का क्या तात्पर्य है ? इसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए ।
- 4 'इतिहास की अधिकांश आर्थिक और सामाजिक रचनाओं के समान सामंतवाद भी स्थान, समय और मानव स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुकूल था' इस बयन की पुष्टि कीजिए ।
- 5 निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) शालमन, (ii) कृष्ण दास की स्थिति, (iii) सामंतों के बल से, (iv) सामंतता का चर्चों के साथ सम्बंध

अध्याय 3 पुनर्जागरण

- 1 पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है ? इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि इसका सबसे प्रथम प्रारम्भ इटली में क्यों हुआ ?
- 2 पुनर्जागरण की विशेषताएँ क्या हैं ? इनका यूरोप की कला व साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- 3 पुनर्जागरण के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालिए ।
- 4 निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) मानववाद (ii) पुनर्जागरणकालीन कला (iii) भौगोलिक खोजों के कारण (iv) गैलीलियो (v) मार्टिन लूथर

अध्याय 4 धम सुधार आन्दोलन

- 1 धम सुधार आन्दोलन में आप क्या समझते हैं ? इसके कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए ।
- 2 मार्टिन लूथर कौन था ? धम सुधार आन्दोलन में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए ।
- 3 प्रतिवादात्मक धम सुधार से क्या आशय है ? उससे द्वारा कथोक्ति धम में किसे गण सुधारों का वर्णन कीजिए ।
- 4 "धम सुधार आन्दोलन पोप की सातारिखता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नवितर विद्रोह था" इस कथन को स्पष्ट कीजिए ।
- 5 निम्न पर सन्धिपत्र टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) मार्टिन लूथर (ii) जेरेडट सत्या (iii) पाप माचन पत्र
(iv) वाल्विग (v) पाप लियो त्रशम

अध्याय 5 फ्रांस की राज्य प्राप्ति

- 1 'फ्रांस की राज्य प्राप्ति के अन्त में गम्भीर कारण थे' इस कथन की पुष्टि में फ्रांस की राज्य प्राप्ति के कारणों का उल्लेख कीजिए ।
- 2 फ्रांस की राज्य प्राप्ति वहाँ के सामन्तों के अत्याचारों के विरुद्ध एक प्रतीक थी इस कथन को स्पष्ट कीजिए ।
- 3 फ्रांसीसी प्राप्ति के विकास में विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए ।
- 4 फ्रांस की राज्य प्राप्ति के परिणामों पर प्रकाश डालिए ।
- 5 निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) स्टेयस जनरल (ii) नेशनल क्लब (iii) आतंक का राज्य
(iv) रोसपियर (v) रूसी (vi) दाते (vii) बस्टाइल जेल का पतन

अध्याय 6 नेपोलियन बोनापार्ट

- 1 नेपोलियन की फ्रांस की राज्य प्राप्ति में क्या भूमिका रही ? प्रकाश डालिए ।
- 2 नेपोलियन के आंतरिक सुधारों का वर्णन कीजिए ।
- 3 नेपोलियन के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए ।
- 4 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) महाद्वीपीय व्यवस्था (ii) ब्रायड्वीप का युद्ध (iii) वाटरलू का युद्ध (iv) रूस का अभियान

अध्याय 7 औद्योगिक क्रांति

- 1 औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हैं ? इसके क्या कारण थे ?
- 2 औद्योगिक क्रांति सबसे प्रथम किस देश में ही क्यों हुई ? स्पष्ट कीजिए ।

- 3 औद्योगिक शक्ति से पूरे यूरोप की दशा का वर्णन कीजिए ।
- 4 औद्योगिक शक्ति के क्या कारण थे ? उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का वर्णन कीजिए ।
- 5 "औद्योगिक शक्ति यांत्रिक शक्ति है और यंत्रों के आविष्कार का परिणाम है" इस कथन पर प्रकाश डालिए ।
- 6 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए --

(i) जेम्स वाट (ii) जान के (iii) बग सघष (iv) वस्त्र उद्योग में प्रगति ।

अध्याय 8 राष्ट्रवाद (जर्मनी और इटली का एकीकरण)

- 1 "उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रवाद यूरोप की प्रबलतम शक्ति थी" इस कथन की पुष्टि उदाहरणों द्वारा कीजिए ।
- 2 इटली के एकीकरण में मजिनी, फायूर और मेरीवाल्डी का क्या योगदान रहा ? इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
- 3 "जर्मनी का एकीकरण भाषणा और बहुमतों से नहीं रक्त और लोह में होगा" इस कथन की पुष्टि में बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण के लिए किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए ।
- 4 जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का वर्णन कीजिए ।
- 5 फ्रांस प्रशा युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए ।
- 6 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए --

(i) विक्टर एमेनुअल (ii) मेडावा का युद्ध (iii) युवा इटली की समस्या (iv) कानूर

अध्याय 9 साम्राज्यवाद

- 1 साम्राज्यवाद के विकास के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालिए ।
- 2 अफ्रीका महाद्वीप का विभाजन यूरोपीय राज्यों में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था" इस कथन पर प्रकाश डालिए ।
- 3 अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद के प्रसार का वर्णन कीजिए ।
- 4 टिप्पणियाँ लिखिए --

(i) अफ्रीका का विभाजन (ii) साम्राज्यवाद का अर्थ (iii) साम्राज्यवाद की विशेषताएँ

अध्याय 10 प्रथम विश्व युद्ध

- 1 प्रथम विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए ।
- 2 1900 ई० से 1914 ई० तक के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मकड़ा का वर्णन कीजिए ।
- 3 बर्मांड की संधि का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए ।

4 विल्सन के चौह सिद्धांत का वर्साय की सधि म कहा तक पालन किया गया । स्पष्ट कीजिए ।

5 टिप्पणिया लिखिए —

(i) द्विगुट (ii) मोरक्को सक्ट (iii) हेग सम्मेलन (iv) बाल्कन सक्ट 1912-13 (v) विलियम द्वितीय की विश्व-नीति

अध्याय 11 रूस की क्रांति, 1917

1 रूस की बोल्शेविक क्रांति (1917) के कारणों पर प्रकाश डालिए ।

2 रूस की बोल्शेविक क्रांति (1917) के महत्व का वर्णन कीजिए ।

3 "1905 ई० की क्रांति की असफलता ही 1917 ई० की क्रांति की सफलता का कारण थी इस कथन को स्पष्ट कीजिए ।

4 रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए ।

5 क्रांति से पूर्व रूस की आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए ।

6 निम्न पर टिप्पणिया लिखिए —

(i) लेनिन (ii) करेत्की (iii) स्टालिन (iv) रासपुटीन
(x) नई आर्थिक नीति

अध्याय 12 राष्ट्रसंध

1 राष्ट्रसंध के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए तथा उसके विभिन्न अंगों को संक्षेप म बनाइए ।

2 राष्ट्रसंध अपने उद्देश्यों की प्राप्ति म कहा तक सफल रहा । स्पष्ट कीजिए ।

3 राष्ट्रसंध की उपनियमों पर प्रकाश डालिए ।

4 राष्ट्रसंध की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए ।

5 राष्ट्रसंध की सफलताओं और असफलताओं का वर्णन कीजिए ।

6 टिप्पणियां लिखिए —

(i) अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय (ii) मंडेट प्रणाली (iii) अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संध (iv) परिषद (v) राष्ट्रसंध के मानवीय कार्य

अध्याय 12 आधुनिक चीन

1 चीन के आधुनिकरण की विभिन्न स्थितियों का वर्णन कीजिए ।

2 डॉ. मायात्सेन का चीन की गणतन्त्रवादी क्रांति म क्या योगदान था ? स्पष्ट कीजिए ।

3 चीन की राष्ट्रीय क्रांति म भाद्रतम युग के योगदान का वर्णन कीजिए ।

- 4 चीन में साम्यवादी शक्ति के कारणों पर प्रकाश डालिए ।
- 5 चीनी गृह युद्ध में साम्यवादी शक्ति की सफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए ।
- 6 निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) सनयानसेन (ii) ध्याग कार्ड शेक (iii) माओत्सुंग
(iv) मचूरिया सवट

अध्याय 14 जापान का आधुनिकरण

- 1 जापान के आधुनिकरण से क्या आशय है ? इसमें मुत्सोहितों के योगदान का वर्णन कीजिए ।
- 2 'समस्त मानव इतिहास में किसी समय भी किसी राष्ट्र ने इतनी तीव्र गति से उन्नति नहीं की जितनी की जापान ने' इस कथन के सन्दर्भ में आधुनिक काल के जापान की प्रगति का वर्णन कीजिए । (राज 1966)
- 3 दो विश्व-युद्धों के बीच जापान की साम्राज्यवादी नीति का वर्णन कीजिए ।
- 4 जापान के विश्व शक्ति के रूप में उद्वेग के कारणों का उल्लेख कीजिए ।
- 5 टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) 1904-5 का रूसी-जापानी युद्ध
(ii) ब्रिटेन और जापान की संधि 1902
(iii) चीनी जापानी युद्ध 1894

अध्याय 15 द्वितीय विश्व युद्ध

- 1 जर्मनी में हिटलर के उत्थान के कारणों पर प्रकाश डालिए ।
- 2 इटली में मुसोलिनी के उत्थान के कारणों पर प्रकाश डालिए ।
- 3 द्वितीय विश्व-युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए ।
- 4 इंग्लैंड और फ्रांस की सुप्रीमसी की नीति का वर्णन कीजिए ।
- 5 निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) रोम बर्लिन टोकियो धुरी
(ii) म्युनिख समझौता (iii) स्पेन का गृह-युद्ध
(iv) स्टालिन (v) बर्लिन

अध्याय 16 संयुक्त राष्ट्रसंघ

- 1 संयुक्त राष्ट्रसंघ के क्या उद्देश्य हैं ? उन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में क्या तक सफलता मिली ? (राज० 1967)
- 2 संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंगों तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए ।
- 3 संयुक्त राष्ट्रसंघ पर एक निबंध लिखिए ।

- 4 "संयुक्त राष्ट्रसंघ अराजनीतिक कार्यों में तो सफल रहा जबकि राजनीतिक समस्याओं के समाधान में असफल" इस कथन पर प्रकाश डालिए ।
- 5 निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(i) वीटो (ii) यूनेस्को (iii) संरक्षण परिषद (iv) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (v) विश्व स्वास्थ्य संगठन ।

सदम ग्रंथ सूची

(अ) हिन्दी

- 1 एलिस आर जीन—संसार का इतिहास
- 2 गूच जी० पी०—आधुनिक यूरोप का इतिहास
- 3 ग्राट जी० टम्परले—यूरोप का इतिहास उन्नीसवीं जी० 20वीं शताब्दी में
- 4 प्लट जी० और ड्रेमंड—विश्व का इतिहास
- 5 नेहरो, जवाहरलाल—विश्व इतिहास की चमक
- 6 दिनाके हैराल्ड० एम०—पूर्व एशिया का आधुनिक इतिहास
- 7 हज्जिन—आधुनिक यूरोप का इतिहास

(ब) अंग्रेजी

- 1 आगस्टस लिडले—द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास
- 2 इजराइल ए सटीन—फ्रान्स जोसिफस वार टू लिबरेशन
- 3 केटलबी—ए द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास
- 4 क्लाइड०, पाल० एच०—द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास
- 5 वार ई० एच०—इंटरनेशनल रिलेशंस बिग्विन दी टू वर्ल्ड वार
- 6 गेयोर्न और हार्डी—ए द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास
- 7 ग्रेसरोल्ड ए० बिटनी—वार इस्टन पोलिसी आफ यूनाइटेड स्टेट्स
- 8 गिब्स, एच० ए०—यूरोप सिंस, 1918
- 9 प्रो० गोबिंस—मकिंग आफ माडर्न जापान
- 10 टायनबी—ए स्टडी आफ द्वितीय विश्व युद्ध
- 11 डेविस—वर्ल्ड इतिहास
- 12 डेविस थोमसन—वर्ल्ड इतिहास (1914-1945)
- 13 थोमसन डी०—यूरोप सिंस नेपालियन
- 14 थोमसन जे० एम०—द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास
- 15 फ एंस० बी०—द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास
- 16 फिलीप—माडर्न यूरोप
- 17 वीच० टल्थु० एन०—द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास

- 18 मैक्नल वनम-वैस्टन मिन्नीनेशंस
 - 19 मारगे थो-पौत्रिटिवम अमग नशंस
 - 20 मेरियट-प्री रिमाकिंग आफ माइन यूराप
 - 21 यनगा-जापान मिस परी
 - 22 ली-वेस-यूरोप सिम 1914
 - 23 लैगसम-दी वल्ड सिम 1919
 - 24 लिप्सन-यूराप ऱग नान्टिथ एण्ड टुवनटिय मचरीज
 - 25 वेल्स, एच० जी०-दी आउट नान्त आफ हिस्ट्री
 - 26 शूमन-इंटरनेशनल पौत्रिटिवम
 - 27 शविल-ए हिस्ट्री आफ यूरोप
 - 28 मवाईन-ए हिस्ट्री आफ वॉट मिन्नीनेशन
 - 29 साउथगट-हिस्ट्री आफ मान्त यूराप
 - 30 हनशा-मन वरुटम आफ यूरोपियन हिस्ट्री
-

मध्यकालीन-चर्च

मध्यकालीन युग में चर्च का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था। उसकी शक्ति पर किसी का नियंत्रण नहीं था। उम समय चर्च प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क पर छाया हुआ था। तीसरी शताब्दी के एक मठ मार्डप्रियन ने चर्च के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'जो अपने को चर्च से पृथक् रखता है, वह अपने को चर्च की आशाओं और प्रतिभाओं से बर्चित रखता है। वह एक विरोधी है अधार्मिक है शत्रु है। यदि वह चर्च को अपनी माता नहीं समझता, तो वह ईश्वर को किसी प्रकार भी पिता नहीं समझ सकता।' मेवाइन ने लिखा है कि 'मानव भाष्य पर इतना विस्तृत प्रभाव स्थापित करने वाली दूसरी मन्था की तलाश में मानव जाति का इतिहास व्यर्थ खोजा जा सकता है।'¹ बीच ने भी लिखा है कि 'जनता का दैनिक जीवन जन्म से बैप्टाइजेशन तक, विवाहों से अपराधों की क्षमा और मृत्यु से दफनाय जान तक पूणतया उनक (पादरिया) हाथ में था, किन्तु कुछ जातियों के प्रयासों को छोड़कर इस लोकप्रिय धर्म में व्यापारिमन्ता बहुत कम रह गई थी।'²

चर्च के पास अपार धन-शक्ति थी। उसने अधिकारियों का राजनीति में बहुत अधिक प्रभाव था। चर्च का सर्वोच्च धर्माधिकारी पोप था जो ईसाई जगत के लिए ईश्वर के समान था। मध्यकालीन युग में यदि कोई भी ईसाई व्यक्ति ईसाई धर्म के सिद्धांतों या चर्च के अधिकारियों का विरोध करता तो उम गद्दार समझ कर मृत्यु दण्ड दिया जाता था। वस्तुतः लिखा है कि 'मध्यकालीन चर्च में पोप का उत्थान और पतन इस बात की कहानी है कि जिसमें एक मयुक्त धार्मिक संसार का निर्माण नहीं हो सका।'³ गिरजाधरा की शक्ति का वर्णन करते हुए एलिय

1—मेवाइन—ए हिस्ट्री ऑफ वल्ट गियलीजेशन—पृ 321

2—बीच, डब्ल्यू एन—हिस्ट्री ऑफ दी वल्ट—पृ 421

3—वेम्प एच जा—दी आउट साइन ऑफ हिस्ट्री—पृ 688

और जोन न सिख है कि मध्यकालीन यूरोप का वास्तविक नान ईसाई चर्च का अध्ययन किये बिना सम्भव नहीं है। क्योंकि चर्च उस समय सबसे अधिक प्रभाव पूण सगठन था।¹

चर्च की स्थापना और उत्कर्ष के कारण—रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् चर्च यूरोप की सबसे अधिक शक्तिशाली सस्था बन गई। प्लट और जोन ने लिखा है कि जब रोमन साम्राज्य टूटा, तब चर्च ने बहुत सी शासन शक्तिया हथिया ली। मध्ययुग में ईश्वर को पिता और चर्च को माता का सम्मान प्राप्त था। जब ईसाई धर्म का अपने सरल सिद्धान्तों एवं सत्ता के बलिदानों के कारण सारे यूरोप में प्रचार होने लगा, तब ईसाई धर्म के प्रचारकों के उपासना करने के लिए चर्च का गठन किया। इस प्रकार बड़े बड़े नगरी शहरी और सभी स्थानों पर चर्च स्थापित किये गये। इन चर्चों के अपने अपने विधान और नियम बने हुये थे। नगरों के चर्चों में रहने वाले साधु अपना नेता चुन लते थे, जो बिशप कहलाता था। नगरों के बिशप मिलकर अपने प्रदेश के लिए एक अधिकारी का चुनाव करते थे जो जाच बिशप कहलाता था। प्रांतीय जाच बिशप मिलकर सबमें बड़े पादरी को चुन लेते थे जो पोप कहलाता था। पोप धर्म का सर्वोच्च अधिकारी होता था और रोम के केनोसा के महल में रहता था। इस प्रकार चर्च के गठन ने उसे शक्ति प्रदान की। जिस समय यूरोप में सामन्त आपस में लड़ने में व्यस्त थे उस समय चर्च ने अपनी जागीरा में वृद्धि कर ली।

चर्च की शक्ति में वृद्धि के कारण—चर्च की शक्ति में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

- (1) प्रारम्भ में ईसाई सत्ता न इन धर्म के प्रचार के लिए अपने बलिदान दिये, जिससे यह धर्म जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हो गया।
- (2) रोमन सम्राट कांसटंटाइन ने रोम के स्थान पर कांसटेन्टीनायल को अपनी राजधानी बनाया। इसमें चर्च को अपनी शक्ति में वृद्धि करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। राज्य का अकृश हट जाने पर चर्च न स्वतंत्र हान का प्रयास किया। रोमन साम्राज्य के पतन के बाल में चर्च न अपने प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि की।
- (3) जब शासक मामूली और अमीर लोग विलासिता में डूबकर जन साधारण पर अमानुषिक अत्याचार कर रहे थे। तब पादरियों ने इन अत्याचारों का विरोध किया और जनता को शोषण से बचाने के लिए कानूनों का निर्माण

1—एनिस और जोन—संसार का इतिहास—पृ 180

2—प्लट और जोन—विश्व का इतिहास—पृ 214

किया। पादरिया ने सप्ताह में चार दिन युद्धों पर रोक लगा दी। ईस्टर से 40 दिन तक भी युद्धों पर प्रतिबंध लगा दिया। सामंतों ने पादरिया की व्यय में युद्ध नहीं करने की बात को स्वीकार कर लिया। चर्च ने जन सेवा की भावना और शान्ति प्रियता की नीति से जनता में लोकप्रियता प्राप्त की। इस प्रकार चर्च का सामन्ता पर भी प्रभाव स्थापित हो गया।

- (4) चर्च ने जनता को पारलौकिक जीवन को सुधारने के विषय में सन्देश दिया। इससे प्रभावित होकर कुछ लोगों ने स्थायी रूप से चर्च में रहना शुरू कर दिया।
- (5) पादरी चर्चों में विद्यार्थियों एवं जनता को शिक्षा देने लगे और ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय में चर्च शिक्षा व सस्कृति के महत्वपूर्ण केन्द्र बन गये।
- (6) चर्च के नियमों का पालन करना प्रत्येक ईसाई के लिए आवश्यक था। नामकरण, विवाह और मृत्यु आदि सस्कार पादरियों के द्वारा सम्पन्न कराये जाते थे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ईसाई के जीवन की प्रमुख धार्मिक क्रियायें पादरियों के द्वारा सम्पन्न कराई जाती थी। इन प्रतिबंधों के कारण चर्च की शक्ति में काफी वृद्धि हुई।
- (7) सात सौ वर्षों तक यूरोप के किसी भी सम्राट ने गिरजाघरों के अधिकारों को चुनौती देने का प्रयास नहीं किया। राजाओं की शक्ति कम होने के कारण चर्च अपनी शक्ति में निरन्तर वृद्धि करता रहा।
- (8) चर्च की जन-सेवा की भावना, त्याग और शान्ति की नीति का बबर आक्रमणकारियों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने चर्चों में घुसने का प्रयास नहीं किया। हूणों के नेता एटिला ने रोम पर आक्रमण किया लेकिन पोप के कहने पर उसने अपनी सेनाओं का पीछे हटा लिया। परिणामस्वरूप रोम की जनता पोप को बबर आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना रक्षक समझने लगी। इससे पश्चात् किसी भी राजा या शक्ति ने चर्च को लूटने का साहस नहीं किया। उस समय चर्च की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि सारे यूरोप के लोग पोप के आदेशों का पालन करने लगे।
- (9) अन्त में पोपों के कारण चर्च अपनी शक्ति में निरन्तर वृद्धि करता रहा। पाचवीं शताब्दी में पोप इन्नोसेंट प्रथम ने चर्च का 'पाप के क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बना दिया। प्रत्येक विषय पर निर्णय देना हुआ वह कहता था कि 'रोम का यह आदेश है, विवाद समाप्त होता है।'¹ उसके पश्चात् पोप अपने लिये प्रथम में हुए नेता एटिला को अपने अध्यात्मिक बल से

रोम पर आक्रमण करने से रोका। इसके पश्चात् पोप ग्रीगोरी प्रथम ने कई धार्मिक ग्रन्थों की रचना की और अनेक धार्मिक मामलों पर अपना निणय दिया। उसके बाद पोप ग्रीगोरी सप्तम ने भी अनेक धार्मिक विषयों पर अपना निणय दिया।

अब तक सरकारी अधिकारी पादरिया की नियुक्ति में हस्तक्षेप करते थे। पोप ग्रीगोरी ने इसका विरोध किया। परिणामस्वरूप रोमन सम्राट हैनरी चतुर्थ और पोप ग्रीगोरी के बीच तनाव पूर्ण सम्बन्ध हो गया। इस पर पोप ने सम्राट को चर्च से बहिष्कृत कर दिया। सामंता ने इस समय पोप का साथ दिया। पोप के प्रयासों से हैनरी चतुर्थ के साम्राज्य में विद्रोह होने लगे। परिणामस्वरूप अपनी गलती का प्रायश्चित्त करने के लिए सम्राट 1077 में पोप से मिलने के लिए तीन दिन नगरे पाव ठिठुरती शीत में पोप के बेनोसा महल के द्वार के पास खड़ा रहा, लेकिन पोप ने उससे मिलने से इन्कार कर दिया। अंत में पोप ने उसे क्षमा कर दिया। प्लेट व जीन ने लिखा है कि यह घटना, जिसने कि एक शक्तिशाली सम्राट को इतना अपमानित किया था, पोपों की शक्ति की अधीनता के सूचक चिह्नो में से एक समझी जाती है।¹

सम्राट द्वारा मार्फी मागने के पश्चात् पोप ने उसे पुनः चर्च में लिया। सम्राट ने पादरिया की नियुक्ति में राजनतिक हस्तक्षेप न करना स्वीकार कर लिया। देश की विशाल भूमि पर चर्चों का अधिकार था। चर्चों के अपने-याया लय होते थे, जिसमें सामंतों और राजाओं के निणय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। पोप का निणय अंतिम समझा जाता था। उसके निणय का विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं था। इस समय पोप सर्वाधिक शक्तिशाली था। पोप ग्रीगोरी सप्तम तो कहता था कि 'पोप ही वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके चरणों को सब राजा चूमते हैं।'²

कुछ समय पश्चात् ग्रीगोरी के विरुद्ध पड़ोसों में रचे जाने के कारण वह 1085 ई० में रोम को छोड़कर भाग गया। 1122 ई० में पोप और सम्राट के बीच वाम समझौता हुआ। जिसके अनुसार पोप को पारोरी नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। पोप इन्नोसेंट तृतीय के समय चर्च अपनी शक्ति के सर्वोच्च बिंदु पर पहुँच गई थी। वेल्स ने लिखा है कि 'इस अवधि में रोम का पोप संयुक्त ईसाई साम्राज्य के सम्राट के समान हो गया। जसा वह पहले न कभी बन सका था और न भविष्य में बनने की आशा थी।'³

1—प्लेट और जीन ड्रमंड—विश्व का इतिहास—पृ 214

2—प्लेट और जीन ड्रमंड—विश्व का इतिहास—पृ 215

3—वेल्स, एच जी—दी आउट लाइन आफ हिस्ट्री—पृ 685

(12) चौथी शताब्दी में सम्राट गियोडोसियस ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित कर इसका राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ा दिया। रोमन साम्राज्य के पतन के समय धर्म का राज्य के मामलों में हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता रहा। शालिमान चर्च के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किये थे। वह पोप की सहायता के कारण ही सम्राट बन सका था। शालिमान को पोप ने 'ताज और सम्राट का पद प्रदान किया था। स्पष्ट है कि राजा लोग भी पोप के आशीर्वाद के लिये तरसते थे। ऐसी स्थिति में चर्च की राजनीतिक शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

धर्म का समाज तथा राज्य पर प्रभाव—चर्च के पास विद्रोहियों का दमन करने के लिए न तो सेना थी और न धर्म विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस थी। फिर, भी चर्च का समाज में बहुत अधिक प्रभाव था। उस समय धर्म का विरोध करने पर सम्राट को भी पोप के द्वारा दण्ड दिया जाता था। चर्च धार्मिक संगठन के साथ 2 राजनीतिक संगठन भी थे। राज्य के सभी राजनीतिक कार्य पोप अपने अधीन धर्माधिकारियों की सहायता से संचालित करता था। पोप धर्म और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च अधिकारी था। वह अपने किसी भी कृपा प्राप्त को 'पवित्र रोमन सम्राट' के पद पर नियुक्त कर सकता था। उस समय कोई भी सम्राट पोप से टक्कर लेने का साहस नहीं कर सकता था।

पोप की अदास्ततों में सम्राट और सामंता के निणय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। पोप का निणय 'याय के क्षेत्र में अंतिम माना जाता था। उसने विवाह, तलाक और जन्म मरण आदि के बारे में कानून बना दिए। ये कार्य पादरी के बिना सम्पन्न नहीं हो सकते थे। सम्राट अपने कार्यों के लिए पोप के प्रति उत्तरदायी होता था। पोप को विदेशों में अपने राजदूत नियुक्त करने का अधिकार था। उसके अधीन प्रान्तीय धर्माधिकारी आर्च बिशप जो प्रांतों में राजकुमारों की भाँति शासन करते थे। इसलिए वाल्टेपर ने मध्ययुग को धर्माधिकारियों का युग कहा है।

धर्म के कर्तव्य—चर्च के कर्तव्य किसी भी राज्य के कर्तव्य से कम नहीं थे। धीरे-धीरे लिखा है कि 'गिरजाघर के हाथ में जनजीवन ही नहीं था वरन् सबसे बड़ी बात जो कही जा सकती है वह यह है कि चर्च के केन्द्रीय संगठन ने यूरोप की एवता के विचार को जीवित रखा।' ¹

(1) धार्मिक कर्तव्य—चर्च का मुख्य काम लोगों को पारलौकिक जीवन सुधारने के लिए प्रेरणा देना था और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताना था। यदि कोई मनुष्य चर्च से अपना सम्बन्ध नहीं रखता तो उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता था। चर्च धर्म के दार्शनिक सतवा का प्रचार करता था और नतिकता का उपदेश देता

1 बीच, इन्व्यू० एन०—हिस्ट्री आफ दी चर्च—पृष्ठ-421

था। इसके अतिरिक्त पीड़ितों, रोगियों तथा असहायों की सेवा करना और भूले भटका को सही रास्ता दिखाना भी चर्च का नैतिक कर्तव्य था।

(2) सस्कारों को सम्पन्न करवाना—जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न सस्कारों का सम्पन्न करवाना चर्च का दूसरा महत्वपूर्ण काय था। ईसाईया के सस्कार चर्च के त्रिना सम्पन्न नहीं हो सकते थे। उम्र समय चर्च ने उस विचारधारा का प्रचार किया कि जो मनुष्य इन सस्कारों को चर्च के माध्यम से सम्पन्न नहीं करवाता उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक ईसाई चर्च के अधीन हो गया। नामकरण, सस्कार, विवाह और मृत्यु आदि अवसरों पर पादरी का होना आवश्यक था, क्योंकि उसके बिना ये सस्कार सम्पन्न नहीं हो सकते थे।

(3) पाप एवं दण्ड विधान—चर्च का तीसरा बड़ा कर्तव्य पाप प्रदान करना था। धार्मिक मामलों को निपटाने के लिये चर्च ने अलग-अलग यायालय स्थापित किये। इन यायालयों में चर्च के कानून और दण्ड विधान का पालन किया जाता था। चर्च के नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति का समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। कभी-कभी तो इन अदालतों में पोप के द्वारा धर्म विरोधी व्यक्तियों का मृत्यु दण्ड भी दिया जाता था। ग्रीक ने लिखा है कि 'चर्च के पास विद्रोह दवाने के लिए सेना और अपराधियों को दवाने के लिए कोई पुलिस नहीं थी, किन्तु उनके पास जो शक्ति थी वह बहुत प्रभावशाली थी।'¹

(4) सावजनिक आराधना का आदेश—चर्च का चौथा कर्तव्य विशेष अवसरों पर आम जनता को सावजनिक आराधना करने की स्वीकृत देना था। उसको किसी भी राज्य में सावजनिक आराधना पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार था। चर्च ने उस समय इस विचारधारा का प्रचार किया कि धर्माधिकारियों को नाराज करने में जनता का कल्याण नहीं हो सकता और सामूहिक रूप से आराधना करने से ही उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए जनता चर्च के आदेशों का पालन करती थी।

(5) राज्य काय में सहयोग—चर्च के धर्माधिकारी राज्य काय में सम्राट को सहाय्य देते थे। वे इस बात का प्रयास करते थे कि सम्राट धर्म और पाप के अनुसार शासन करे। सम्राट बिगड़ परिस्थितियों में चर्च के धर्माधिकारियों से सलाह लेता था। उस समय सम्राट ने कई विशपों को राजकीय पदों पर नियुक्त किया था। इंग्लैण्ड में बकट व वूल्जे तथा फ्रांस में रिशलू नामक विशप को प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया। विशपों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण फ्रांस के दार्शनिक वाल्टेवर ने मध्ययुग को विशपों का युग बताया।²

(6) भूमि प्रबन्ध—चर्च के पास अपार धन सम्पत्ति और विशाल भूमि

थी। इन विशाल भूमि का प्रबंध पादरियो द्वारा किया जाता था। पादरी भूमि का लगान वसूल करते थे और किसानों से भेंट जादि भी लेते थे। इस प्रकार मध्यकालीन युग में चर्चों ने जमींदारी का काम किया। चर्च को अपनी भूमि का सरकार को लगान नहीं देना पड़ता था। भूमि से वसूल किया गया कर चर्च की जाय का साधन था। इसके अनिर्दिष्ट जपराधियों पर किये गये जुर्माने और राजाशा से प्राप्त नियमित भेंट भी उनकी आय का साधन थे।

(7) सस्कृति का संचार—चर्च का सातवा वस्तव्य सम्स्कृति का संचार करना था। प्रारम्भिक ईसाई सन्तो ने चर्चों का धर्म प्रचार के लिए निर्माण करवाया था। किन्तु आगे चलकर ये चर्च मस्कृति के केन्द्र बन गये। इन चर्चों का मुख्य काम पूवजों में अर्जित सस्कृति को आने वाली पीढ़िया के हाथ में सापना था। पादरी जनसाधारण का शिक्षा देते थे और उन्हें सुसस्कृत बनाते थे।

चर्च का सगठन—प्रोपमर ह्यूकस के अनुसार चर्च के सगठन का आधार राजत लीय था। प्रारम्भ में चर्च का गठन अत्यन्त सरल और सीधे ढंग से किया गया था। चर्च वह कर्तृ था, जहाँ सभी व्यक्ति ईश्वर की उपासना या आराधना कर सकते थे और जिसके द्वारे सब लोगों के लिये खुले हुए थे। चर्च का सर्वोच्च अधिकारी पोप कहलाता था। इस गठन की मुख्य विशेषता यह थी कि 55 वर्ष की अवस्था से अधिक आयु वाला व्यक्ति ही पोप बन सकता था। मात्रा के गिरजाघरों में सगम छोटा प्रचारक पादरी होता था जो ईसाई धर्म का प्रचार और सेवा का काम करता था। प्रत्येक जिले में विशप नाम का धर्माधिकारी होता था और प्रत्येक प्रांत के लिए "आर्च विशप" नाम का धार्मिक पदाधिकारी होता था। पस्तुलुनिया, सिविलरिया और जर्सलम के चर्च की गिनती बड़े चर्चों में की जाती थी। इन गिरजाघरों में सेटपीटम द्वारा स्थापित रोमन गिरजाघर प्रमुख था।

राज्य में पोप के बीच सघष—चर्च ने अपने उत्कर्ष का लक्ष्य ही अपनी शक्ति में इतनी अधिक वृद्धि कर ली थी कि पादरियो ने राजा के कार्यों को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया। इन पादरियो पर सम्राट का कोई नियन्त्रण नहीं था। राजाशा को पोप के अधीन समझा जाता था। वे अपने कार्यों के लिये पोप के प्रति उत्तरदायी होते थे। परिणामस्वरूप राजा और पोप के बीच सघष होना अवश्यम्भावी था। यदि सम्राट शक्तिशाली होता तो पोप उसकी इच्छाओं का आन्तरिक करतृ था। यदि सम्राट दुबल होता तो पोप उससे अपने आदेशों का पालन करवाते थे। पोप की बढ़ती हुई शक्ति का यूरोप में कुछ शक्तिशाली शासकों ने चुनौती दी। वनसन लिखा है कि 'ऐसा हुआ कि सामंतवादी युग में चर्च के विवास के साथ-साथ महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों का भी उदय हुआ। सामारिक और आध्यात्मिक मता के बीच सघष टाना नहीं जा सका, क्योंकि दोनों द्वारा दावाकर्षण अधिकार क्षेत्र बढ़तायत में एक से थे।'²

शासने के पोप व साथ घनिष्ठ सम्बन्ध थे। इसका कारण यह था कि उस समय पोप की स्थिति असुरक्षित थी और शालमेन भी अपनी स्थिति को सुरक्षित करना चाहता था। पोप ने शालमेन को यूरोप में ईसाई धर्म का पहला पवित्र रोमन सम्राट बनाया था। शासने 768 ई० में गद्दी पर बैठा और 814 ई० तक शासन किया। वह अपने समय का एक योग्य और प्रतिभा सम्पन्न सम्राट हुआ। जिसने कानून का गठन किया और अपने साम्राज्य में सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की स्थापना की। वेल्स ने लिखा है कि 'शालमेन के माध्यम से यूरोप में रोम के सीजर की परम्पराओं की पुनरावृद्धि हुई।' ¹

शालमेन ईसाई धर्म का बहुत आदर करता था। उसने "सीटी आफ गौड" नामक पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके पश्चात् शालमेन ने बहुत से गिरजाघरों का निर्माण करवाया और धर्म को बहुत सी जागीरों उपहारस्वरूप प्रदान की। उसने लियो तृतीय का रोम के पोप के चुनाव में जितवाया था। पोप ने शालमेन को खुश करने के लिए उसे एक रत्न जड़ित सोन का मुकुट पहनाया और उस सीजर तथा आगस्टस की उपाधि से विभूषित किया। इतना ही नहीं पोप ने उसका राज्याभिषेक किया और उसे पवित्र रोमन सम्राट के पद पर नियुक्त किया। वेल्स ने लिखा है कि शासने इससे प्रसन्न नहीं हुआ। 'यदि उसे इस समारोह का आभास मिल जाता तो वह धर्म में ही नहीं जाता।' ²

शालमेन की मृत्यु 814 ई० में 78 वर्ष की अवस्था में हो गई, लेकिन पवित्र रोमन सम्राट का पद अगले एक हजार वर्ष तक चलता रहा। सेवार्डिन ने लिखा है कि "इस युग का एक अत्यधिक असाधारण अनुभव पवित्र रोमन सम्राट की स्थापना था। वह न तो पवित्र था न रोमन और न ही सम्राट फिर भी नाम तो एक हजार वर्ष तक चलता रहा।" ³

शालमेन के उत्तराधिकारी ओटो ने एक पोप को हटाकर दूसरे ऐसे व्यक्ति को पोप के पद पर नियुक्त किया, जो उसके आदेशों का पालन करता था। सम्राट हेनरी तृतीय ने भी इसी प्रकार की कायवाही की। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि पोप की शक्ति हमेशा के लिये कम हो जायेगी परन्तु हेनरी तृतीय की मृत्यु के पश्चात् पोप ने फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारम्भ किया। हेनरी तृतीय का पुत्र हेनरी चतुर्थ अभी नाबालिग था। इस कारण कुछ समय तक उसकी माता ने शासन किया। इस अवसर का लाभ उठाकर पोप ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली। हेनरी चतुर्थ ने बालिग होने पर पोप की शक्ति को चुनौती दी। अतः उसके समय से पोप

1 वेल्स, एन० जी०—दी आउट लाइन आफ हिस्ट्री—पृष्ठ-644

2 वेल्स, एच० जी०—दी आउट लाइन आफ हिस्ट्री—पृष्ठ-646

3 सेवार्डिन ए हिस्ट्री आफ बल्ड सिवलीजेशन—पृष्ठ-298

व राज्य के बीच में शक्ति के लिये सघर्ष शुरू हो गया। यह सघर्ष इतिहास में 'इंवेस्टीचर स्ट्रगल' (Investiture Struggle) के नाम से प्रसिद्ध है। इसको "अभिषेक का सघर्ष" भी कहते हैं।

इंवेस्टीचर स्ट्रगल—यूरोपियन दशा में प्रान्त के बिशपों का चुनाव ग्राम व नगर के पादरियों के द्वारा किया जाता था। इस पर बहुत से राजाओं ने बिशपों के चुनाव में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यदि कोई भी बिशप उनकी इच्छा के विरुद्ध चुना जाता, तो वे उस बिशप का अभिषेक करने से इन्कार कर देते थे। अभिषेक की प्रतीक वस्तु 'छड़ी और अगूठी' आदि देने से भी इन्कार कर देते थे। इतना ही नहीं उस बिशप को चर्च की भूमि और सम्पत्ति पर भी अधिकार नहीं करने देते थे।

पोप ग्रीगोरी सप्तम का यह मानना था कि चर्च अपने अधिकारियों के चुनाव में पूर्णतया स्वतंत्र है। चर्च की सम्पत्ति, प्रबंध और विनय आदि में राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत सम्राट हेनरी चतुर्थ का यह मानना था कि चर्च की जो भूमि है, उस पर पहले राज्य का अधिकार था और उसी भूमि पर चर्च ने अधिकार कर लिया है। इस प्रकार भूमि का स्वामी चर्च भी अर्थात् सामन्तों की तरह राजा का एक सामन्त है। इसलिये हेनरी चतुर्थ के अनुसार पादरियों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिये अर्थात् राज्य में अशांति फैला देंगे। हेनरी चतुर्थ 'राज्य के अन्दर राज्य' (State Within State) की स्थिति को समाप्त करना चाहता था।

जबकि पोप का यह मानना था कि चर्च को अधिक से अधिक अधिकार मिलने चाहिये क्योंकि ईश्वर के द्वारा सत्कार की धुराईयों को दूर करने के लिए चर्च की स्थापना की गई है। पोप ने ऐसे राजाओं का अभिषेक करने से इन्कार कर दिया, जो उसके आदेशों का पालन नहीं करते थे। ग्रीगोरी ने कहा था कि "पोप ही एक ऐसा व्यक्ति है, जिसके चरण सब राजा चूमते हैं।" उसके निषेधों और आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हेनरी चतुर्थ ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप आगे चलकर इन दो विरोधी विचारधाराओं में अभिषेक के सघर्ष का सूत्रपात हुआ।

यदि निष्पक्ष रूप से हम अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि दोनों पक्षों के तर्कों में कुछ सत्यता अवश्य थी। यदि किसी एक पक्ष की इसमें पूर्णरूप से विजय हो जाती तो वह मध्ययुग के लिये घातक सिद्ध हो सकता था। यदि सम्राटों को पादरियों के अभिषेक करने का और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिल जाता तो पोप की राजनतिक शक्ति नष्ट हो जाती और वह राजाओं के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता। यदि राजा यह स्वीकार कर लेते कि उसके राज्य में रहने वाले धर्माधिकारियों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा तो इसका परिणाम

मह होता कि यूरोप में अराजकता व अशांति फैल जाये और धर्माधिकारी तानाशाह बन जाते ।

सम्राट हेनरी चतुर्थ ने जब पोप की शक्तियाँ का चुनौती दी तो पोप ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया । हेनरी चतुर्थ ने जब पोप का आदेश का विरोध किया तो पोप ने ईसाई जनता को उससे विरुद्ध आन्दोलन करने के आदेश दिये । सम्राट को लाचार होकर पोप से माफी मांगने के लिए बनेवाया जाना पड़ा । यहाँ जाकर हेनरी चतुर्थ ने पोप के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अपनी गलती के लिये पोप से क्षमा माँचना की । पोप ने उसे माफ कर दिया और दोनों के बीच समझौता हो गया परन्तु यह समझौता अस्थायी सिद्ध हुआ और दोनों के बीच फिर सघष आरम्भ हो गया क्योंकि हेनरी ने पोप ग्रीगोरी को उसका राजमहल में बंदी बना लिया । इस प्रकार मध्ययुग के महानतम पाप ग्रीगोरी की बंदी गृह में ही मृत्यु हो गई । उसका अंतिम शास्त्र यथे मैंने पाया मैं प्रेम किया है और असमानता से घणा । इस कारण मेरी निर्वासन में मृत्यु हो रही है ।'

हेनरी ने उत्तराधिकार के इस सघष को पुनः प्रारम्भ कर लिया । काफी समय के पश्चात् 1172 ई० में हेनरी पंचम और पोप ग्रास्क्ल द्वितीय के बीच वमस नामक स्थान पर समझौता हुआ । जिसमें निम्नलिखित शर्तें तय की गई —

- 1) हेनरी पंचम ने पादरियों का अगुठी तथा अभिषेक करने का अधिकार त्याग दिया ।
- (2) पोप अपने धर्माधिकारियों का चुनाव करने में स्वतन्त्र रहेगा । सम्राट उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा ।
- (3) पाप ने यह स्वीकार किया कि चर्च के अधिकारियों का चुनाव सम्राट की उपस्थिति में किया जायगा । चुनाव के बाद जो पादरी चर्च के अधिकारी चुने जायेंगे, वे सम्राट की राजनीतिक अधीनता स्वीकार करेंगे ।

इस प्रकार की दुहरी प्रथा का अधिक समय तक सफलतापूर्वक नाश करना सम्भव नहीं था इसलिये बीस वर्ष पश्चात् फिर से सघष प्रारम्भ हो गया । जर्मनी का राजा फ्रेडरिक (1152-90) ने पोप की शक्तियों को फिर से चुनौती दी । उसका यह मानना था कि ईश्वर की इच्छा से ही व्यक्ति राजा बनता है इसलिए वह पोप से अभिषेक कराने की आवश्यकता नहीं है । उस समय का पोप फ्रेडरिक के विचारा का सफलतापूर्वक विरोध नहीं कर सका ।

पोप इन्नोसेंट तृतीय (1198-1216) ने जर्मनी के सम्राट के चुनाव में हस्तक्षेप किया । इंग्लैंड के राजा जान को भी उसका आदेश स्वीकार करना पड़ा । उस समय इंग्लैंड के राजा जान की सहायता से चुने गये सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने पोप को फिर चुनौती दी । इस पर पोप इन्नोसेंट चतुर्थ ने उसे चर्च से बहिष्कृत कर

दिया और 1245 ई० म उसे सम्राट पद से भी हटा दिया । परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । सषय राजाभा व पक्ष म रहा । उस समय फ्रांस के राजा फिलिप ने चर्च की सम्पत्ति पर कर लगाया । जब पाप न इस कर को देने स इन्कार किया तो उमन पाप बोनीवस अप्टम का बन्दी बना लिया और उसके स्थान पर आर्च बिशप बोडियस को पोप बना दिया । पोप की राजधानी वनोसा स हटाकर फ्रांस म एविमनोन को बनाया गया । एविमनोन 70 वष तक पोप की राजधानी बनी रही । इस प्रकार फ्रांस के सम्राट फिलिप न पोप को अपना एक सामन्त बनाकर उसकी शक्ति को बहुत बडा आघात पहुँचाया । पोप इन्फोसट चतुप व समय स ही पोप की प्रतिष्ठा व शक्ति म कमी होने लग गई थी । इस प्रकार धीरे धीरे चर्च का प्रभाव कम होता गया । जनता धार्मिक सुधार और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की ओर बढ़ने लगी । पुनजागरण काल म कई धर्म सुधारका न खुले रूप स पोप के अनतिकार्यों के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया ।

सषय के परिणाम—मकनल बनस के अनुसार इस सषय के निम्न चार परिणाम हुए —

- (1) इस सषय के फलस्वरूप पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा और उसकी शक्ति भी कम हा गई । धीरे धीरे उसका प्रभाव भी कम होने लगा ।
- (2) पोप को धर्म का सर्वोच्च अधिकारी बनने के लिए नय सिरे से प्रयास करना पड़ा ।
- (3) पाप का राजनीतिक क्षेत्र म प्रभाव समाप्त हो गया । जिसके फलस्वरूप फ्रांस और इंग्लण्ड म राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ ।
- (4) इस सषय न बुद्धीजिविया की गतिविधि को गति प्रदान की ।
- (5) पोप और राजा दोनों न अपने-अपने पदों को सफलता दिलाने के लिए पुराने साहित्य का महारा लिया ।
- (6) इस सषय के फलस्वरूप रोमन कानून की लोकप्रियता म वृद्धि हुई ।

चर्च के पतन के कारण—समय क साथ चर्च म भी अनेक दोष आ जाने व कारण जनता पर उसका प्रभाव कम होने लगा और धीरे धीरे उसका पतन होने लगा । चर्च के पतन व प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) विलासितापूर्ण जीवन—इन्फोसट तृतीय के धार्मिक आदेश पोपों का चरित्र नतिक दृष्टि स गिर गया था । अब एस शक्ति पोप बनने लगे, जिनका चरित्र शुद्ध नहीं था । उन्होंने त्याग और नम्रता के स्थान पर विलासितापूर्ण जीवन पत्तीत करना शुरू कर दिया । पोप अलबजेडर पब्लम (1492-1503) ने खुले आम विलासितापूर्ण जीवन पत्तीत किया । वास्तव म चर्च के पास इतना

अधिक धन था, कि उसने पादरियो की बुद्धि झूट कर दी थी। उन्होंने विलासिता पूरा जीवन व्यतीत करना ही अपनी जिन्दगी का मुख्य ध्येय समझ लिया था। जो चर्च पहले उपासना के वे द्र थे, अब विलासिता के चर्च बन गये। सांसारिक सुखों और सत्ता के लालची अधार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी पादरी बन गये थे। आम जनता ने ऐसे पादरियो को सम्मान नहीं दिया और उन्हें हीन दृष्टि से देखा जान लगा।

(2) राजा व पोप के बीच संघर्ष—पादरियो ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप करना और सम्राटों का विरोध करना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप अभिषेक के संघर्ष का सूत्रपात हुआ। शासक चर्चों की विशाल सम्पत्ति और भूमि को छीनना चाहते थे। हेनरी ने पोप को एक घमडी साधु बताया। फ्रांस के सम्राट फिलिप ने पोप को बंदी बना लिया और राजधानी वेनोसा से हटाकर फ्राम में एविमोन बना दी गई, जिससे पोप की शक्ति को गहरा आघात पहुँचा। इंग्लैण्ड के सम्राट हेनरी अष्टम ने चर्च की सम्पत्ति का लूटा और पोप की शक्ति का धक्का पहुँचाया। उसने पोप से अपने सम्बन्ध विच्छेद कर इंग्लैण्ड में एक अलग चर्च की स्थापना की। सम्राटों के इस प्रकार की चर्च विराधी कायदाही से उसकी शक्ति कम हो गई और पतन की ओर अग्रसर होने लगा।

(3) पादरियों द्वारा कृत्तव्यों की उपेक्षा—पादरियो ने अपने कृत्तव्यों की उपेक्षा की और जनता को शिक्षित करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप जनता अशिक्षित और अधविश्वासों में विश्वास करती रही। 12 वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद और राष्ट्रीयता का विकास होने के कारण चर्च का प्रभाव कम होने लगा। जनता ने अपने राष्ट्रीय राजा का समर्थन किया जो धार्मिक सिद्धांतों में तो विश्वास करते थे लेकिन आडम्बरों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के समर्थक थे। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जनता पादरियों के आडम्बरपूर्ण जीवन व कार्यों से घणा करने लगी। इससे पादरियों का प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होता गया।

(4) शिक्षा का प्रसार—शिक्षा के प्रसार ने भी पादरियो की शक्ति को आघात पहुँचाया। इस समय चर्च द्वारा मुक्ति पत्रों की बिक्री की जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि जो व्यक्ति इस पत्र को खरीदेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पादरियों के अनतिक बच्चा का चर्च में यूसू के नाम से प्रचार किया जाने लगा। अब जनता में शिक्षा का प्रसार होने लगा तो उन्होंने पादरियों के इन कार्यों की कटु आलोचना की और सुधारकों ने इन दोषों को दूर करने के लिए घम सुधार आन्दोलन चलाये।

(5) चर्च की आपसी फूट—चर्चों की आपसी फूट उसके पतन का कारण सिद्ध हुई। पश्चिमी पोप का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था। पूर्वी चर्च के पादरियों और पश्चिमी चर्च के पादरियों में धार्मिक विषयों पर गम्भीर मतभेद थे। पूब के चर्च मूर्ति पूजा व विरोधी थे जबकि पश्चिम के चर्च मूर्ति पूजा के समर्थक थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्यारहवीं शताब्दी में चर्च दो शाखाओं में विभाजित हो गया। पश्चिमी चर्च में विश्वास करने वाले इसाइ रोमन कैथोलिक और पूर्वी चर्च में विश्वास करने वाले आर्थोडॉक्स कहलाये। गिरजाघरों की इस आपसी फूट और सघर्ष ने उनकी प्रतिष्ठा को घटका पहुँचाया।

(6) चर्च के पतन के नियम युद्ध भी उत्तरदायी थे जिनका वर्णन आगे किया गया है।

चर्च की देन—चर्च अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिये सम्राटों में सघर्ष करता रहा। पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च के पादरियों में भी धार्मिक विषयों पर गम्भीर मतभेद थे। इतना हीन पर भी चर्च ने मध्यकालीन यूरोप को जोक वृद्धमूल्य देन दी।

चर्च का प्रमुख दन निम्न लिखित है

(1) ईसाई धर्म का प्रचार—ईसाई धर्म के प्रचार में चर्च ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् यत्र आक्रमणकारियों ने यूरोप में लूटमार प्रारम्भ की, तो ऐसे कठिन समय में चर्च ने जनता की रक्षा की। हूण आक्रमणकारी एटिला ने रोम पर आक्रमण किया, लेकिन पोप से प्रभावित होकर रोम का लूटे बिना वापस चला गया। शालिमा के प्रयासों से पश्चिमी यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। इस प्रकार चर्च ने ईसाई जनजीवन की रक्षा की और आशा से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार किया।

(2) दर्शन का विकास—चर्च ने इसाइ मत के दर्शन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि प्रारम्भिक इसाई सभ्यता ने यूनानी दर्शन को नहीं अपनाया। परन्तु कुछ समय पश्चात् ईसाई विद्वानों पर यूनानी दर्शन की छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। ओरिजन (185-254) तथा एथानसियस आदि पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रसिद्ध ईसाई दार्शनिक आगस्टाइन (354-430) ने चर्च का ही मुक्ति का एक मात्र माग्य बतलाया। चर्च ने ईसाई धर्म या दर्शन की क्रियाओं निश्चित की। इससे पश्चात् चर्च में स्कातिस्टिक दर्शन का विकास हुआ।

(3) शिक्षा का विकास—चर्च ने शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब जब जातियों ने यूरोप को लूटना प्रारम्भ किया तो चर्च ने जनता को अपने मठों में शरण दी। उस समय कई विद्वानों ने भी चर्चों में शरण ले ली थी। अतः पादरियों ने चर्चों में ही स्कूल व विश्वविद्यालय खोलने शुरू कर दिए। धीरे-धीरे चर्च समस्त यूरोप की शिक्षा के केंद्र बन गये। पादरों चर्च में बच्चों का नैतिक भाषा में शिक्षा देते थे। इस प्रकार चर्च ने लैटिन भाषा के विकास में भी अपना

महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इसी भाषा में धर्माधिकारिया ने अच्छे साहित्य की रचना की। एलिस और जौन न लिखा है कि 'जितने भी स्कूल थे, बरीब-बरीब सभी चर्च के हाथ में थे और वहाँ पढ़ने बोलने की भाषा लटिन थी।'¹ चर्च ने आगे चलकर विश्वविद्यालयों की स्थापना की। इटली के बोलोना क्रॉम के पेरिस और इंग्लैंड के आक्सफोर्ड तथा कम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की स्थापना चर्च के द्वारा की गई। इन विश्वविद्यालयों में सारे पश्चिमी यूरोप के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते थे।

पेरिस में अधिकांश स्कूल स्ट्रा स्ट्रीट में थे। इसका नाम स्ट्रा स्ट्रीट इसलिए पड़ा था कि इन स्कूलों के कमरों में पशु पर फूम बिछाकर उस पर विद्यार्थियों को बिठा दिया जाता था। जिस लटिन भाषा में 'स्ट्रा' कहा जाता था। इसी समय विद्यालयों ने बी० ए०, पी० एच० डा० आदि उपाधियाँ देने की प्रथा शुरू की। सभी से ये उपाधियाँ आज तक चली आ रही हैं। इस प्रकार संस्कृति के अविच्छिन्न काल में चर्च ने शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(4) कला के क्षेत्र में देन—चर्च ने कला के क्षेत्र में भी बहुमूल्य देन दी है। ईसाई धर्म के गिरजाघर सभार की स्थापत्य कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गिरजाघर प्राप्त की शकल के बने हुए होते थे जिनमें मोटी दीवारें और खिड़कियाँ बहुत कम होती थीं उनके निर्माण में विभिन्न शक्तियों का प्रयोग किया जाता था। उस समय गिरजाघरों के निर्माण में एक नई शक्ति का प्रयोग किया गया जिस 'गोथिक शैली' कहा जाता है।

चर्च ने मूर्तिकला के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की। इस समय मूर्तिकार ईसा के पुनर्जन्म के उसके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं को प्रदर्शन करने के लिए सुन्दर सुन्दर मूर्तियाँ का निर्माण करने लगे। चर्च ने चित्रकला के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की। चित्रकारों ने ईसा के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के चित्र चर्च की दीवारों पर बना दिए थे। यद्यपि प्रारम्भिक ईसाई सत सगीत के विरोधी थे, किन्तु बाद में उसकी उपयोगिता को समझा और भक्ति के लिए सगीत को आवश्यक माना गया। सत एब्रोस का प्राथना को भजनों और स्वरो में गाना शुरू किया।

(5) राजाओं की निरकुशता पर नियंत्रण—चर्च के धर्माधिकारियों ने राजाओं की निरकुशता पर नियंत्रण बनाये रखा और वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने में सफल नहीं हुए। चर्च ने समय-समय पर राजाओं के गलत कार्यों का विरोध किया। पोप ने जौन को मनमानी करने से रोका। चर्च ने सामन्तों को व्यर्थ के युद्ध न करने की सलाह दी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

(6) राजनैतिक एकता प्रदान करना—पवित्र रोमन सम्राट और पोप ने ईसाई धर्म के नाम पर यूरोप के एक बहुत बड़े भाग को राजनैतिक एकता के सूत्र

में बाध दिया। इस बात की पुष्टि धर्म युद्ध से होती है, जिसमें कि सभी ईसाईयों ने एक साथ सघर्ष में भाग लिया। चर्च के घर्षाधिकारियों ने सुव्यवस्थित व अनुशासित राज्यों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

(7) यूरोप को सभ्यता का केन्द्र बनाना—पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए निजिन और जगली स्थानों पर गये। वहाँ उन्होंने गरीबों की देखभाल और सेवा की तथा धर्म का प्रचार करने के लिए चर्चों की स्थापना की। बिल डयूरेट ने लिखा है कि “मध्ययुग की सबसे बड़ी विजय और सफलता यूरोप के अधिकांश भाग को जो निजिन और अरण्य था, सभ्यता के लिए उपयुक्त था। पादरियों ने इन जगली स्थानों में जंगलों को कटवाकर भूमि को खेती के योग्य बनाया और वहाँ पर शिक्षा का प्रसार किया। परिणामस्वरूप निजिन देशों में सभ्यता का विकास हुआ और चर्च यूरोपीय सभ्यता के केन्द्र बन गये।

धर्म युद्ध (1096-1270 ई०)—मध्यकालीन युग के अन्त तक चर्च की शक्ति बहुत कम हो गई थी फिर भी जनता उनसे काफी प्रभावित थी। चर्च ने अपने पतन के समय में भी ईसाईयों को मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्साहित किया। प्लेट और जीन ड्रमंड ने लिखा है कि ‘धर्म युद्ध (क्रूसेड) दो धार्मिक शक्तियों ईसाइयत और मुहम्मदीय में सघर्ष था।’¹ जाजफरियर ने कहा है कि मध्यकालीन युग में ईसाईयत और मुसलमानों के बीच धर्म के प्रश्न पर जो युद्ध लड़े गये, वे इतिहास में धर्म युद्ध अथवा क्रूसेड के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये युद्ध ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में लड़े गये थे। उस समय ईसाई राज्य और इस्लामी राज्य दोनों ही निकटपूर्व के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। इसलिये ये युद्ध लड़े गये थे। एच० जी० वेल्स ने लिखा है कि ‘मानव जाति का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार के लिये क्रूसेड में इतनी ही रुचि है कि दया से परिपूर्ण भावनाएँ इसमें जान डालकर सबप्रथम उस आकर्षित करती हैं।’² प्लेट और जीन ड्रमंड ने लिखा है कि “हाठों पर यह नारा और छाती पर एक लाल (क्रास) सलीब लिए हजारों ईसाई पैदल, घोड़ों पर सवार होकर या किसी जहाज पर चढ़कर पवित्र भूमि के लिए पवित्रतम नगर, जेरूसलम की ओर रवाना हुए थे। कब्रों धारण किए सूरमा, चौकड़ पहने कृपणदास, मुक्ति के अभिलाषी मनुष्य, लूट चाहने वाले लोग, स्त्रियाँ, बच्चे, अपराधी और कजदार ये सब इन धर्म युद्धों के योद्धा थे। ये धर्म युद्ध शस्त्र तीक्ष्ण यात्रायें होती थीं, जो पवित्र भूमि जेरूसलम को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिये की जाती थी।³

1—प्लेट और जीन ड्रमंड—विश्व का इतिहास—पृष्ठ—211

2—वेल्स, एच० जी०—दो आउट लाइन आफ हिस्ट्री—पृष्ठ 673

3—प्लेट और जीन ड्रमंड—विश्व का इतिहास—पृष्ठ 211

धम युद्धों के कारण—इन धम युद्धों व प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) तुर्कों द्वारा ईसाईया पर अमानुषिक अत्याचार—1076 म सल्जुक तुर्कों ने ईसाईया के पवित्र धार्मिक तीर्थ स्था जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। इसका पश्चात ईसाईया पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे। तुर्कों ने जेरूसलम की धार्मिक यात्रा पर कर लगा दिया। अब कर देने के पश्चात ही ईसाई धर्मावलम्बी जेरूसलम में प्रवेश कर सकते थे। तुर्कों ने ईसाई व्यापारियों से भी कर वसूल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं जेरूसलम के गिरजाघरों को तुर्कों ने अपने घाड़ों व लिए अस्तवत्त बना दिया था। पीटर नामक सत्त व अन्य यात्रियों ने यूरोप के ईसाईयों को तुर्कों द्वारा जेरूसलम में उन पर किये जाने वाले अत्याचारों की कहानिया सुनाई और उनको उत्साहित किया। पीटर ने फ्रांस जर्मनी आदि देशों की यात्राओं की और वहाँ तुर्कों के अत्याचार की कहानी सुनाई और ईसाईयों को अपने जेरूसलम के बंधुओं की रक्षा करने का आह्वान किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के ईसाईया ने जेरूसलम की रक्षा करने के लिए तुर्कों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मेवाइन ने लिखा है कि 'ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त से तेरहवीं शताब्दी का समाप्ति तक धम युद्धों ने बड़ी सख्या में पश्चिम यूरोप से अपने घर त्याग कर पूव की तरफ यात्रा की, ताकि पवित्र भूमि को आक्रमणकारी तुर्कों से बचा सके। क्रूसेड शब्द का महत्व ईसाई के फ्रांस से लिया गया है।'¹

(2) बाइजेंटाइन व दुबल साम्राज्य—700 वर्ष तक बाइजेंटाइन व साम्राज्य अरब आक्रमणकारियों से यूरोप की रक्षा करता रहा। सम्राट वसील द्वितीय (963-1025) के शासनकाल में बाइजेंटाइन साम्राज्य की सीमाएँ सेल्युक तुर्कों के साम्राज्य से जाकर मिल गई थी। इस समय सल्जुक तुर्कों ने बगदाद के अबासी खलीफा को हटाकर इस्लामी साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। 1071 ई० में मजीकट के मदान में बाइजेंटाइन के सम्राट रोमनुस और सेल्युक तुर्कों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में तुर्कों ने बाइजेंटाइन सम्राट को बुरी तरह पराजित किया और उसके कई नगरों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में विजय प्राप्त होने से तुर्कों का एशिया माइनर में प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ऐसी स्थिति में बाइजेंटाइन सम्राट को बाध्य होकर तुर्कों से संधि करनी पड़ी। इसी समय बाइजेंटाइन के सम्राट ने कर्तुतुनिया की रक्षा के लिए यूरोप से सहायता मागी। पोप ने सहायता देना स्वीकार किया। उसका यह मानना था कि इससे पूव और पश्चिम के मतभेद समाप्त हो जायेंगे और उसके प्रभाव में वृद्धि होगी।

(3) पोप द्वारा अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिये प्रयत्न—वास्तव में उस समय पोप अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिये युद्ध को आवश्यक समझ रहा था।

कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि पाप सम्राटों की शक्ति कमजोर बनाने के लिये सैनिक कार्यवाही को आवश्यक मान रहा था। पोप ने इस युद्ध में सहायता देना इसलिये स्वीकार किया क्योंकि उसका यह मानना था कि इस सहायता से पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च के मतभेद समाप्त हो जायेंगे और सम्पूर्ण ईसाई जगत फिर से एक सूत्र में बंध जायेगा। इससे उसके प्रभाव में वृद्धि होगी और वह सर्वशक्तिमान हो जायेगा। दूसरा, पोप का यह मानना कि यदि इस युद्ध में मुसलमान पराजित हुए तो पूरब में भी उसके प्रभाव का विस्तार होगा। तीसरा यदि इस युद्ध में पराजय हुई तो यूरोप के सम्राटों की शक्ति कमजोर हो जायेगी और पोप सारे यूरोप में अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लेगा। इस प्रकार पोप मुसलमानों को पराजित करने के लिए अपना सामंती को उनके विरुद्ध युद्ध में भेजना चाहता था, ताकि उनकी शक्ति समाप्त हो जाय और वह यूरोप का सर्वोपरि सम्राट बन सके। इसलिए पोप ने युद्ध का आह्वान किया।

(4) व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा - धर्मयुद्ध का चौथा कारण ईसाईयों और मुसलमानों के बीच व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा थी। इस समय पूरब में व्यापार ईसाई जहाजों के द्वारा होता था। उस समय तुर्कों के ईसाईयों के जहाज लूट लेते थे। इसलिये ईसाई पूर्वी भूमध्य सागर के प्रदेशों में मुसलमानों की व्यापारिक प्रभुता समाप्त कर अपनी व्यापारिक प्रभुता स्थापित करना चाहते थे। ईसाईयों का यह भी मानना था कि जब उन्होंने स्पेन में मुस्लिम शासन का अन्त कर उस पर अधिकार कर लिया तो उन्हें बहुत सी व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त हुयीं। अतः उनकी यह धारणा बन गई थी कि यदि वे जेरूसलम में मुस्लिम शासन का अन्त कर देंगे तो उन्हें बहुत सी व्यापारिक सुविधाएँ मिलेगी। इस प्रकार व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये इस युद्ध को धर्म युद्ध का रूप दे दिया गया। प्लेट और जीन ड्रमंड ने लिखा है कि "पूरब के देशों की अत्यधिक समृद्धि की कहानियों ने पश्चिम के बहुत से दरिद्र किसानों को इन युद्धों में भाग लेने के लिये प्रेरित किया। व्यवसायियों को इसमें पूरब के साथ व्यापार को बढ़ाने का सुअवसर दिखाई दिया। कुछ सरदार पूरब में राज्य स्थापित करने के सपने देखने लगे थे। राजाओं ने इस प्रकार के सरदारों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि यदि वे धर्म युद्ध पर चले गये तो राजाओं को स्वदेश में सत्ता हथियाने के लिये उनसे प्रतियागता न करनी पड़ेगी।"

(5) पोप की युद्ध के लिए घोषणा—पोप अपने प्रभाव और शक्ति को बनाये रखने के लिए युद्ध को आवश्यक मानता था। उसने 1095 ई० में दक्षिण फ्रांस के क्लेरमांट नगर में ईसाईयों की एक विशाल आम सभा में जोशीला भाषण

देते हुए कहा कि उहे जेरूसलम मे तुकों को भगाने के लिये हर प्रकार का बलिदान देना चाहिये। चर्च के अग्र धर्माधिकारिया ने भी समस्त ईसाईया को इस पवित्र युद्ध के लिये तयार किया। पोप को इस कायम राजाजा और सामन्त ने भी सहयोग दिया। उसने समस्त ईसाई जगत से अपील की कि वे आपसी मतभेद को भुलाकर मुसलमाना के आधिपत्य से जेरूसलम को मुक्त करायें तथा सगठित होकर धार्मिक यात्राओ पर लगे हुये प्रतिबन्ध को हटायें एव जेरूसलम के ईसाईयो पर होने वाले अत्याचारो मे उनकी रक्षा करें। इस प्रकार पोप की युद्ध के लिये घोषणा भी धर्म युद्ध का महत्वपूर्ण बनी। प्लेट जीन ड्रमड ने पोप के विचार का बणन करते हुए लिखा है कि जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए लडो। वहां का एक एक स्थान ईसा द्वारा उच्चारित शब्दो से और उसके किये चमत्कारिक कर्मों से प्रभावित हो रहा है।¹

(6) युद्ध का तत्कालीन कारण—पोप ने धर्म युद्ध की घोषणा कर दी, जिसका जनता पर अच्छा प्रभाव पडा। उसने जनता से अपील की कि जो लोग इस युद्ध मे भाग लें, उनके अपराध ईश्वर माफ कर देगा। परिणामस्वरूप विश्वप सामन्त, राजा, किसान और साधारण जनता भी इस युद्ध मे भाग लेने के लिये तैयार हो गई। सात पीटर सात हजार ईसाईया को लेकर तुकों पर आक्रमण करने के लिये जेरूसलम रवाना हुआ। उनमे स अधिकांश भाग मे ही बीमार हो गये, कुछ की भूख से मृत्यु हो गई और बचे हुए जो लोग जेरूसलम पहुँचे उनका तुकों ने बध कर दिया। यह दुघटना 1096 ई० मे घटित हुई। इस घटना से सारे पश्चिमी यूरोप मे युद्ध की अग्नि भडक उठी और यही स धर्म युद्ध प्रारम्भ हो गया। इन युद्धो को क्रुसेड भी कहा जाता है।

युद्ध की प्रमुख घटनायें—धर्म-युद्ध 1096 ई० से 1270 ई० तक चलते रहे। कुल मिलाकर धर्म युद्ध सात बार लडे गये—प्रथम 1096-1099 ई०, दूसरा 1147 ई०, तीसरा 1189 ई० मे, चौथा 1202-1204 ई० पाचवा 1218 ई०, छठा 1248 ई० और सातवा 1270 ई० में लडा गया।

(1) पहला धर्म-युद्ध-(1096-1099 ई०)—1097 ई० मे पहला धर्म युद्ध प्रारम्भ हुआ। काउण्ट रेमण्ड और गौड फ्रे के नेतृत्व मे ईसाई सेना को तुकों पर आक्रमण करने के लिये भेजा गया। इस बार ईसाईयो की सेना मे अधिकतर फ्रांसीसी और नामन लोग थे। मिसली के नामन राज्य का बोही मुड भी सेना मे था। ईसाईयो की इस सेना ने 1097 ई० में नाटिया पर अधिकार करने के पश्चात् एंटि ओक को घेर लिया। यह घेरा एक बर्ष तक चलता रहा। गौड फ्रे की सेना ने 1099 मे बेलेस्टाइन और सीरीया पर अधिकार कर लिया। इस समय

हजारों मुसलमानों को बर्बर कर दिया गया। इनके पश्चात् इस विजित प्रदेश का विभाजन सामन्ती व्यवस्था के आधार पर कर दिया गया और गौड फ्रे को जेरुसलम का सम्राट बनाया गया। प्रथम धर्म-युद्ध में ईसाईयों को विजय प्राप्त हुई। पचास वर्ष तक जेरुसलम और सीरीया पर ईसाईयों का राज्य बना रहा। 1100 ई० में गौड फ्रे की मृत्यु के पश्चात् उसका छोटा भाई वाल्डविन जेरुसलम का शासक बना। उसने बोहीमुड का एक प्रदेश एटिओक को लिया और ट्रिपोली पर रेम्पड ने अधिकार कर लिया।

(2) दूसरा धर्म-युद्ध—(1147 ई०)—प्रथम धर्म-युद्ध में ईसाईयों की विजय होने से व 1099 से 1187 ई० तक जेरुसलम पर शासन करते रहे। इस समय ईसाईयों के धार्मिक यात्रा और व्यापार पर लगे हुये प्रतिबंध को हटा दिया गया। अब ईसाई बिना रोक टोक के पुन जेरुसलम की यात्रा पर जाने लगे और पश्चिमी एशिया के तटों पर ईसाई व्यापारी पुन फल गये। चालीस वर्षों तक जेरुसलम में शान्ति व्यवस्था स्थापित रही। 1144 ई० में मोसुल के अमीर जागी ने जब लेबन्ट के ईसाई राज्य पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, तो दूसरा धर्म युद्ध प्रारम्भ हो गया।

इस युद्ध में जमन सम्राट केनाड तृतीय और फ्रांसीसी सम्राट लुई पष्ठम ने अपनी-अपनी सेना के साथ एशिया माइनर पर आक्रमण कर दिया। वे अमीर जागी के आक्रमण को विफल करना चाहते थे। अमीर जागी ने जमन सना को युद्ध में घुरी तरह पराजित कर भगा दिया, किंतु फ्रांस के सम्राट पष्ठम ने अपनी सेना के साथ दमिश्क पर घेरा डाल दिया। काफी समय के पश्चात् भी सम्राट पष्ठम दमिश्क पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। अंत में वह घेरा उठा कर फ्रांस को वापस लौट आया। इस युद्ध में 3 हजार ईसाई मारे गये। ईसाईयों की यह हार 1148 ई० में हुई थी।

अमीर जागी के पश्चात् मोसूल का अमीर खलादीन हुआ। उसने 1174 ई० में मिश्र पर, 1183 में सीरीया पर और 1187 में जेरुसलम पर अधिकार कर लिया और वहाँ के इसाई शासक लुसी गनान को बंदी बना लिया।

इस प्रकार अक्टूबर 1187 ई० में जेरुसलम पर पुन तुर्कों का अधिकार हो गया।

(3) तीसरा धर्म-युद्ध—(1189 ई०)—जेरुसलम पर खलादीन का अधिकार होने के पश्चात् यूरोप में ऐसी जफवाहें फैली कि खलादीन प्रात काल के नाशते में ईसाई बच्चा को खाता है। पोप ने ईसाई सम्राटों से जेरुसलम को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिये पुन अपील की। इस पर पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक, इंग्लण्ड का सम्राट रिचार्ड प्रथम और फ्रांस का सम्राट फिलिप आगस्टस अपनी सेना के साथ तुर्की पर आक्रमण करने के लिए खाना हुए। फ्रांस और

इ गलण्ड की सेना जल माग से और जमन सेना थल माग से जेरूसलम पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुई। पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक की तो एशिया माइनर में प्रवेश करते ही मृत्यु हो गई। इन तीनों शासकान एक घेरा डाला था परंतु खलादीन ने इनका सब तरफ ग घेर लिया। इसी समय फ्रांस के शासक फिलिप क इ गलण्ड के शासक रिचाड से मतभेद पटा हो गया इसलिये फिलिप बीमारी का बहाना बनाकर फ्रांस लौट गया किंतु इ गलण्ड का शासक रिचाड प्रथम युद्ध क मैदान म ही डटा रहा। ज ग्रेज फौजें निरंतर आगे बढ़ती रही। अंत म खलादीन को 1193 ई० म इ गलण्ड के सम्राट रिचाड प्रथम से समझौता करने क लिए बाध्य होना पडा। इस समझौते के अनुसार जेरेट के तटीय प्रदेशो पर ईसाईयो का अधिकार मान लिया गया तथा जेरूसलम म उह धार्मिक सुविधायें प्रदान की गई। इस प्रकार यह एक सम्मानजनक समझौता था। 1194 ई० म खलादीन की मृत्यु हो गई।

(4) चौथा घम-युद्ध—(1202-1204 ई०)—चौथा घम युद्ध 1202 ई० मे प्रारम्भ हुआ जो 1204 ई० तक चलता रहा। वेनिस के व्यापारियो ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। इन व्यापारियो ने बाइजेन्टाइन से व्यापारिक प्रतियोगिता म आगे बढ़ने के लिए घम युद्ध प्रारम्भ कर दिया। अमीर खलादीन की मृत्यु से वेनिस लोगो न जेरूसलम पर अधिकार करन का निश्चय किया। पोप इनोसेंट तृतीय ने इन व्यापारियो को सहायता प्रदान की। इस पर अल्पकाल के लिये पोप का जेरूसलम पर अधिकार हो गया। पाप न कस्तुतुनिया पर भी अधिकार कर लिया, किंतु ईसाईया म फूट पड जा। स मुसलमानो न कस्तुतुनिया पर फिर स अधिकार कर लिया। प्लट और ड्रमड न लिया हे कि बनियो ने एक घम-युद्ध छेडा जो कुछ समय के लिय सफल भी हुआ किंतु यह युद्ध जेरूसलम के मुसलमानो के विरुद्ध नही अपितु कस्तुतुनिया क अपन साथी ईसाईयो के विरुद्ध था।¹

(5) पाचवा घम-युद्ध—(1212 ई०)—पाचवा घम युद्ध 1212 ई० मे हुआ। इस घम-युद्ध को बालको का घम युद्ध भी कहत हैं। घम युद्धा की असफलता के पश्चात कुछ लोगो ने यह मत प्रकट किया कि बच्चा की एक सेना को जेरूसलम पर आक्रमण करन के लिय भेजना चाहिये। उनके मत का आधार बाईबिल का एक कथन था। बाईबिल म कहा गया था कि सकट के समय एक छोटा बालक उनका (ईसाईया) का नेतृत्व करेगा। इस आधार पर एक फ्रांसोमी बालक स्टीफेन 30 000 बालकों क साथ और निकालस नामक बालक 20,000 बालका के साथ जेरूसलम पर आक्रमण करन क लिए रवाना हुये। परंतु यह प्रयत्न भी असफल रहा। सेना के अधिकांश बालक माग म ही मृत्यु को प्राप्त हुये। जीर

बचे हुये बालका के जेरूसलम पहुँचने पर तुर्कों ने दाम बनाकर बेच दिया। सेवाइन ने लिखा है कि इस सारे युग का यह सबसे अधिक भाग्यहीन अभियान था।¹ वास्तव में इन घम युद्धों में सबसे दुःखद बच्चा का घम युद्ध था।

(7) छठा घम-युद्ध—(1228 से 1244 ई०)—छठा घम युद्ध 1228 ई० में प्रारम्भ हुआ और 1244 ई० तक चलता रहा। इस युद्ध का नतीजा पहले जान दो ग्रीन ने और बाद में फ्रेडरिक द्वितीय ने किया, परन्तु उनको सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इस समय पोप ने फ्रेडरिक को पवित्र रोमन सम्राट पद में हटा दिया। इस पर फ्रेडरिक ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए तुर्की सुल्तान के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार जेरूसलम, नैजरथ और वयलहम आदि धार्मिक स्थानों पर ईसाईयों का यात्रा करने की स्वतन्त्रता तो मिल गई परन्तु 1244 ई० में तुर्कों के सुल्तान ने इस समझौते को भंग कर दिया। इस प्रकार यह व्यवस्था भी अस्पाई सिद्ध हुई।

(7) सातवाँ घम-युद्ध—(1248-1270 ई०)—सातवाँ घम-युद्ध 1248 में प्रारम्भ हुआ और 1270 तक चलता रहा। इस घम युद्ध में फ्रांस के सम्राट लुई नवम ने दनता पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् जब लुई मिस्र को विजय करने के लिये आगे बढ़ा तो तुर्की सेना ने उसे बुरी तरह पराजित किया और बन्दी बना लिया। लुई ने तुर्की सुल्तान को बहुत सा धन देकर कदस मुक्ति प्राप्त की।

इसके पश्चात् लुई ने 1270 ई० में एक बार फिर तुर्की सम्राज्य पर आक्रमण किया किन्तु युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह घम युद्ध बीच में ही बंद हो गया। उचित अवसर पाकर तुर्कों ने पुनः सीरिया, जेरूसलम, कस्तुतुनिया और समस्त बल्कान प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 200 वर्षों के युद्धों और बलिदानों के बाद भी ईसाई अपने तीर्थ स्थान जेरूसलम को तुर्कों के आधिपत्य से मुक्त नहीं करवा सके। वैसे इतिहास में इनको व्यर्थ के युद्ध लड़े गये हैं लेकिन इन घम युद्धों का उन निरर्थक युद्धों की मेरिट में प्रथम स्थान है।

घम युद्धों के परिणाम—यूरोप के ईसाईयों ने अपने पवित्र धार्मिक स्थान जेरूसलम पर अधिकार करने का उद्देश्य से घम युद्ध लड़े थे, लेकिन वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहे और जेरूसलम पर अधिकार नहीं कर सके। फ्लट और जीन ड्रमह ने लिखा है कि 'घम युद्ध पवित्र भूमि जेरूसलम पर अधिकार प्राप्त में

इंग्लण्ड की सेना जल माग से और जमन सना थल माग से जेरूसलम पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुई। पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक की तो एशिया माइनर में प्रवेश करते ही मृत्यु हो गई। इन तीनों शासकों ने एक घेरा डाला था परंतु खलादीन ने इनको सब तरफ से घेर लिया। इसी समय फ्रांस के शासक फिलिप के इंग्लंड के शासक रिचार्ड से मतभेद पैदा हो गया इसलिये फिलिप बीमारी का बहाना बनाकर फ्रांस लौट गया, किंतु इंग्लण्ड का शासक रिचार्ड प्रथम युद्ध के मैदान में ही डटा रहा। अंग्रेज फौजें निरंतर आगे बढ़ती रही। अंत में खलादीन को 1193 ई० में इंग्लण्ड के सम्राट रिचार्ड प्रथम से समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस समझौते के अनुसार लंगर के तटीय प्रदेशों पर ईसाईयो का अधिकार मान लिया गया तथा जेरूसलम में उन्हें धार्मिक सुविधायें प्रदान की गईं। इस प्रकार यह एक सम्मानजनक समझौता था। 1194 ई० में खलादीन की मृत्यु हो गई।

(4) चौथा धम-युद्ध—(1202-1204 ई०)—चौथा धम-युद्ध 1202 ई० में प्रारम्भ हुआ जो 1204 ई० तक चलता रहा। वेनिस के व्यापारियों ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। इन व्यापारियों ने बाइजेंटाइन से व्यापारिक प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए धम युद्ध प्रारम्भ कर दिया। अमीर खलादीन की मृत्यु से वेनिस लोगों ने जेरूसलम पर अधिकार करने का निश्चय किया। पोप इन्नासेंट तृतीय ने इन व्यापारियों को सहायता प्रदान की। इस पर अल्पकाल के लिये पोप का जेरूसलम पर अधिकार हो गया। पोप ने कस्तुतुनिया पर भी अधिकार कर लिया, किंतु ईसाईयो में फूट पड़ जाने से मुसलमानों ने कस्तुतुनिया पर फिर से अधिकार कर लिया। प्लट और ड्रमंड ने लिखा है कि घनिया ने एक धम-युद्ध छेड़ा जो कुछ समय के लिये सफल भी हुआ किंतु यह युद्ध जेरूसलम के मुसलमानों के विरुद्ध नहीं अपितु कस्तुतुनिया के अपने साथी ईसाईयो के विरुद्ध था।¹

(5) पांचवा धम-युद्ध—(1212 ई०)—पांचवा धम युद्ध 1212 ई० में हुआ। इस धम-युद्ध को बालकों का धम-युद्ध भी कहते हैं। धम युद्धों की असफलता के पश्चात् कुछ लोगों ने यह मत प्रकट किया कि घच्चा की एक सेना का जेरूसलम पर आक्रमण करने के लिये भेजना चाहिये। उनके मत का आधार बाईबिल का एक कथन था। बाईबिल में कहा गया था कि सकट के समय एक छोटा बालक उनका (ईसाईयो) का नेतृत्व करेगा। इस आधार पर एक फ्रांसीसी बालक स्टीफेन 30,000 बालकों के साथ और निकोलस नामक बालक 20,000 बालकों के साथ जेरूसलम पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुए। परंतु यह प्रयत्न भी असफल रहा। सेना के अधिकांश बालक माग में ही मृत्यु को प्राप्त हुये। और

बचे हुए वालका के जेरुसलम पहुँचने पर तुर्कों ने दास बनाकर बेच दिया। सेवाइन ने लिखा है कि इस सारे युग का यह सबसे अधिक भाग्यहीन अभियान था।¹ वास्तव में इन घम युद्धों में सबसे दुःखद वरुचों का घम युद्ध था।

(7) छठा घम-युद्ध—(1228 से 1244 ई०)—छठा घम युद्ध 1228 ई० में प्रारम्भ हुआ और 1244 ई० तक चलता रहा। इस युद्ध का नेतृत्व पहले जान दी ग्रीन ने और बाद में फ्रेडरिक द्वितीय ने किया परन्तु उनका सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इस समय पोप ने फ्रेडरिक को पवित्र रोमन सम्राट पद से हटा दिया। इस पर फ्रेडरिक ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए तुर्की सुल्तान का साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार जेरुसलम, नैजरथ और वेथ लेहम आदि धार्मिक स्थानों पर ईसाईया का यात्रा करने की स्वतन्त्रता तो मिल गई परन्तु 1244 ई० में टर्कों के सुल्तान ने इस समझौते को भंग कर दिया। इस प्रकार यह व्यवस्था भी अस्पाई सिद्ध हुई।

(7) सातवा घम-युद्ध—(1248-1270 ई०)—सातवा घम युद्ध 1248 में प्रारम्भ हुआ और 1270 तक चलता रहा। इस घम युद्ध में फ्रान्स के सम्राट लुई नवम ने दनता पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् जब लुई मिश्र को विजय करने के लिये आगे बढ़ा तो तुर्की सेना ने उसे बुरी तरह पराजित किया और बर्बाद बना लिया। लुई ने तुर्की सुल्तान को बहुत सा धन देकर बंद स मुक्ति प्राप्त की।

इसके पश्चात् लुई ने 1270 ई० में एक बार फिर तुर्की राज्य पर आक्रमण किया कि तु युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह घम युद्ध बीच में ही बंद हो गया। उचित अवसर पाकर तुर्कों ने पुन सीरिया, जेरुसलम, कस्तुतुनिया और समस्त बल्कान प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 200 वर्षों के युद्धों और बलिदानों के बाद भी ईसाई अपने तीव्र स्थान जेरुसलम को तुर्कों के आधिपत्य से मुक्त नहीं करवा सके। जैसे इतिहास में उनकी व्यथ के युद्ध लड़े गये हैं लेकिन इन घम-युद्धों का उन निरर्थक युद्धों की मेरिट में प्रथम स्थान है।

घम युद्धों के परिणाम—यूरोप के ईसाईया ने अपने पवित्र धार्मिक स्थान जेरुसलम पर अधिकार करने का उद्देश्य से घम युद्ध लड़े थे, लेकिन वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहे और जेरुसलम पर अधिकार नहीं कर सके। फ्लट और जीन ड्रमंड ने लिखा है कि 'घम युद्ध पवित्र भूमि जेरुसलम पर अधिकार प्राप्त में

असफल रहे, किन्तु ये एक नये यूरोप का निर्माण करने में सहायक बने।¹ इन घम युद्धों के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हुए —

(1) जन की हानि—इन युद्धों में जन की अपार क्षति हुई। पोप ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति इन युद्धों में भाग लेता, ईश्वर उनके पाप क्षमा कर देगा, इसलिये सम्पूर्ण ईसाई जगत कृपक कारीगर और मजदूरों ने इन युद्धों में भाग लिया। परिणामस्वरूप हजारों व्यक्ति व्यर्थ ही इन युद्धों में मारे गये। पोप ने ईसाई धर्म की रक्षा के नाम पर एम लोगो का खून बहाया जो यूरोपियन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के आधार स्तम्भ थे।

(2) भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि—इन घम युद्धों की यात्रा से ईसाईयों का भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। पश्चिमी यूरोप के लोगों ने भूमध्य सागर व पश्चिमी एशिया के प्रदेशों की यात्रा की। जिससे इन देशों के विषय में उनको भौगोलिक अनुभव प्राप्त हुआ। मार्कोपोलो ने अनुसंधान के लिये बड़ी-बड़ी यात्रायें कीं। दूर देशों के बारे में भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपियन लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। प्रोफेसर नेविल ने लिखा है कि 'इस भौगोलिक ज्ञान के बिना पुनर्जागृति गण बसा नहीं हो सकती था जैसा कि वह था।'

(3) सामन्तवाद का अन्त—घमयुद्धों के कारण सामन्तों की शक्ति का अन्त हो गया। इन युद्धों से पहले यूरोपियन समाज पर सामन्तों का बहुत अधिक प्रभाव था। जनेक सामन्तों ने युद्धों में जान से पहले अपनी जमीनें व्यापारियों को बच दी थीं। युद्धों में अधिकांश सामन्त मारे गये और जो सामन्त युद्ध में पराजित होकर लौटे उनके समाज में अब पहलू जैसा प्रभाव नहीं रहा। इसके अतिरिक्त सामन्त युद्ध में जाने में पहले उनके जनेक दासों किसानों (सर्फों) की जमीन और उनके परिवारों को स्वतंत्र कर चुके थे। इसलिए घमयुद्धों के पश्चात् किसानों को सामन्तों के शोषण से मुक्ति मिली। परिणामस्वरूप सामन्तवाद सदा के लिये समाप्त हो गया।

(4) एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था—घमयुद्धों के कारण यूरोप में एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था के विचारों का विकास हुआ। इन युद्धों के कारण पश्चिमी यूरोप के सम्राट पूर्वी शासन व्यवस्था के सम्पर्क में आये। इसका यूरोपियन सम्राटों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोपियन सम्राटों का यह मानना था कि एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था के कारण ही मुसलमानों को इन घमयुद्धों में सफलता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त मुसलमान शासकों के ठाट बाट और दरबार ने भी यूरोपियन सम्राटों को काफी प्रभावित किया। घमयुद्धों के पश्चात् यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण शुरू हो

गया और वहाँ एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गयी। फ्रांस, इंग्लण्ड, पुतगाल, स्वीडन आदि देशों में धर्म युद्धों के पश्चात् तुर्कों के दरबार के आधार पर अपने वभवपूर्ण दरबारों का गठन किया।

(5) इस्लाम में कट्टरता का प्रवेश धर्मयुद्धों के कारण इस्लाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। धर्मयुद्धों के पूर्व इस्लाम उदारवादी था, लेकिन इस पश्चात् इस्लाम में कट्टरता ने प्रवेश किया। अब तुर्कों ने शक्ति से तलवार के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसकी रक्षा की।

(6) पोप के प्रभाव में कमी—इन धर्म युद्धों के कारण पोप का प्रभाव कम हो गया। जब ईसाई जगत जेरुसलम को तुर्कों के प्रभाव से मुक्त नहीं करवा सका तो पोप के प्रभुत्व को गहरा आघात पहुँचा। ईसाईयों ने जेरुसलम पर अधिकार करने के जिस उद्देश्य से युद्ध लड़े थे, वो पूरा नहीं हो सका। जनता की घम से आस्था उठ गई। पोप के आदेशानुसार 50,000 हजार बच्चे जेरुसलम को स्वतंत्र कराने के लिये भेजे गये थे। जब उनमें से एक भी वापस जिंदा नहीं लौटा तो पोप के इस कथन “ईश्वर यह कहता है” से जनता का विश्वास उठ गया। अब जनता को यह विश्वास हो गया कि पोप ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। पोप का यह विश्वास था कि यूरोप के बड़े-बड़े सम्राट इन युद्धों में भाग लेकर या ता मारे जावेंगे या उनकी शक्ति कमजोर हो जायेगी और तब वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन जायेगा लेकिन पोप की यह आशा भी पूरी नहीं हुई। इन धर्मयुद्धों के कारण पोप की शक्ति कमजोर हुई और उसके प्रभाव तथा सम्मान में भी कमी आई।

(7) धर्म सुधार आन्दोलन—इन युद्धों से पोप के प्रभाव में कमी हुई। इस समय पोप का नतिक पतन होने लगा। उसने सादगी को छोड़कर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया था। परिणामस्वरूप अब जनसाधारण पोप के आचरण पर आरोप लगाने लगा। बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में लियोस के एक व्यापारी पीटर वाल्टी ने पोप तथा अन्य धर्माधिकारियों को सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। पीटर वाल्टी स्वयं पादरी बन गया। उसने कहा कि ईश्वर और पुत्र के बीच पादरी की कोई आवश्यकता नहीं है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिर्फ बाईबिल पर्याप्त है, पोप के आर्शावाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर पोप ने पीटर को धर्मद्रोही बताया।

पोप के विरुद्ध दूसरा आन्दोलन दक्षिण फ्रांस के एल्वी नगर में प्रारम्भ हुआ। यहाँ के लोगो ने पोप की विलासिता का विरोध किया। उनका यह मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए चर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। पोप ने इस आन्दोलन को भी शक्ति से दबा दिया। इस प्रकार धीरे-धीरे पोप के आचरण के विरुद्ध धर्मसुधार आन्दोलन प्रारम्भ हो गया।

(8) उद्योग के क्षेत्र में विकास—घमयुद्धों के कारण यूरोप में उद्योग के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। उद्योगों के विकास के कारण यूरोपियन देशों में मजदूरों की मांग बढ़ी। अरबों ने यूरोपवासियों को नीबू, नारंगी व गन्ने आदि की खेती करना सिखाया। मुसलमानों ने यूरोपियन देशों को मशीनों का प्रयोग करना सिखाया। जब यूरोप में कुटीर उद्योगों के स्थान पर बड़े-बड़े कारखानों के द्वारा माल उत्पादित किया जाने लगा इसलिये इन घमयुद्धों को औद्योगिक क्रांति तयार करने वाला आधार माना जाता है।

(9) व्यापार में वृद्धि—घमयुद्धों के कारण यूरोप व पूर्व के व्यापार में वृद्धि हुई। यूरोप चावल, प्याज, लहसुन, मक्का, मलमल, रंग काच, गममसाले, रुई और रेशम आदि वस्तुओं को पूर्वी देशों से मँगवाता था और इसका बदले में चमड़ा, ऊन, धातु और कपड़े पूर्वी देशों को निर्यात करता था। इन घमयुद्धों के कारण यूरोप के व्यापार में काफी वृद्धि हुई और इटली तथा फ्रांस के अनेक नगर विशाल व समृद्ध हो गये। प्लेट और जीन डमड ने लिखा है कि 'इन नगरों की बढ़ोतरी व्यापार तथा निर्माण में वृद्धि और महाजनों के विकास में एक शक्तिशाली व्यवसायी बग उठ खड़ा हुआ।'¹

(10) गिल्ड प्रथा का प्रारम्भ—घमयुद्धों के कारण गिल्ड प्रथा प्रारम्भ हुई। यूरोप में प्रत्येक बग के व्यापारियों ने अपने उद्योग-घरों की रक्षा के लिये गिल्ड (श्रेणियाँ) या संघ बनाने लिये। उत्पादन गिल्ड और वितरण गिल्ड आदि श्रेणियों का व्यापार पर नियंत्रण स्थापित हो गया। इनके पश्चात् कुटीर-व्यवसायों और जूता निर्माताओं आदि के गिल्ड बने। ये गिल्ड ही वस्तुओं का उत्पादन मूल्य एवं बचन का मूल्य निर्धारित करते थे। मण्डियाँ व्यापार और बाजार आदि सभी तरह के नियंत्रण करती थीं। इसमें सामूहिक व्यापार की शुरुआत हुई, लेकिन इससे व्यापार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समाप्ति हो गई थी।

(11) मुद्रा के क्षेत्र में प्रगति—यूरोप ने घमयुद्धों के दौरान मुद्रा के क्षेत्र में प्रगति की। इन घमयुद्धों से पूर्व सामान और चक्र के घमाधिकारी अपने कृपकों में अनाज या धर्म के रूप में कर वसूल करते थे लेकिन व्यापार में उन्नति के साथ साथ मुद्रा का महत्व भी वर्धन लगा। व्यापार की प्रगति के कारण व्यापारियों के पास धन एकत्रित होने लगा। धीरे-धीरे व्यापारियों बग धनवान् होता चला गया। घमयुद्ध के दौरान यूरोप में मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था और इसे धन के रूप में भी परिणित किया जाने लगा था। इस समय प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलित विद्यमान था और धातुओं के आधार पर मुद्राओं के मूल्य निश्चित किये।

(12) सांस्कृतिक आदान प्रदान — इन घर्म युद्धों के कारण पून और पश्चिम देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान सम्भव हुआ। अरबा न यूरोप को ज्योमेट्री, कृषुवनुमा, वारुद, मुद्रण यंत्र और गणित के अरबों का प्रयोग करना सिखाया। छापखाने का आविष्कार के कारण यूरोप में शिक्षा का प्रसार हुआ। इस समय पूर्वो दशन का पश्चिमी देशों में प्रचार हुआ। प्लेटो, अरस्तु आदि के ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इन सम्भव का ईसाईयों के रहन-सहन और रीतिरिवाजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब यूरोपियन निवासी विलासिता की सामग्री और बढ़िया फर्नीचर का प्रयोग अधिक करने लगे। यूरोपियन शासकों ने मुसलमान शासकों की तरह अपने दरबार को सजाया।

खनीफाजा के समय की सांस्कृतिक गतिविधियाँ का यूरोप में प्रचार हुआ। पून और पश्चिम दोनों के बीच साहित्य, कला, विज्ञान और रीति रिवाजों आदि का आदान प्रदान हुआ। घर्मयुद्धों के पश्चात् पोप ने भी मुसलमान शासकों की तरह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। इन घर्मयुद्धों के कारण पुनर्जागरण सम्भव हो सका। सेवाइन ने लिखा है कि 'निर्णायक रूप से यह कहा जा सकता है कि घर्मयुद्धों ने नये विचारों के उदय और पुरानी व्यवस्था का पाठ पढ़ने में अत्याधिक योगदान दिया, जिन्होंने पुनर्जागरण सम्भव किया।'¹

1—सेवाइन—ए हिस्ट्री ऑफ वल्ड सिविलाईजेशन, पृष्ठ 349

प्रस्तावित सन्दर्भ पुस्तकें —

- 1 सेवाइन—एक हिस्ट्री ऑफ वल्ड सिविलाईजेशन
- 2 वीच, डब्ल्यू० एन०—हिस्ट्री ऑफ दी वल्ड
- 3 वेस्म, एच० जी०—दी आउट लाइन ऑफ हिस्ट्री
- 4 एलिम और जीन—संसार का इतिहास
- 5 प्लेट, जीन और डूमर—विश्व का इतिहास
- 6 मकनल यनस—वेस्मन सिविलाईजेशन

सामन्तवाद

मध्यकालीन यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण इन सामन्तवादी व्यवस्था है। उस समय का राजनीतिक व सामाजिक जीवन इसी प्रथा पर आधारित था। सामन्तवाद को जेफ्री मे फ्यूडलिज्म' कहा जाता है। फ्यूडल' शब्द का जन्म फ्यूडम' नामक शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है 'जागीरदार', प्रोफसर डेविस ने लिखा है कि सामन्तवाद किसी राजाना या किसी मनुष्य की देन नहीं थी अपितु वह तो मध्यकालीन युग की एक स्वाभाविक देन थी। प्लट व जीन डूमड ने लिखा है कि 'मध्ययुगीन सामन्त तत्र न कोई प्रणाली न योजना और न कोई आयोजना ही थी। यह यूरोप के सब क्षेत्रों में ठीक एक जसा भी नहीं था। यह तो आवश्यकता के कारण हुआ विकास भर था।'¹

इसका यह अर्थ नहीं है कि सामन्तवाद का विकास आकस्मिक रूप से हुआ। वास्तव में प्राचीन सभ्यताओं के काल से ही यह प्रथा विकसित हो रही थी। चीन और मिथ्र आदि देशों में सामन्तों ने कई बार अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया था। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों के सामन्तों को विरोधाधिकार प्राप्त थे। मध्यकालीन युग में अराजकता एवं अशांति के कारण सामन्तवाद का विकास हुआ। समस्त यूरोप और भारत में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी व्यवस्थाएँ सामन्तवादी व्यवस्था पर आधारित थीं।

रोमन साम्राज्य के पतन के समय जब रोम पर बबर जातियों के आक्रमण होने लगे तब इन आक्रमणकारियों से रोमवासियों की रक्षा करने का भार कुछ वीर पुरुषों ने अपने कंधों पर ले लिया। इन वीर पुरुषों ने यूरोप के नगरों व ग्रामों में दुर्गों का निर्माण करवाया और उनमें कुछ शस्त्र व सैनिक रखे जिनकी सहायता से वे दुर्गों से ग्राम व नगरवासियों की रक्षा करते थे। उन्होंने आसपास की भूमि पर अधिकार कर लिया। कृषकों, श्रमिकों और व्यापारियों ने सामन्तों की अधीनता

स्वीकार कर ली। जिसाना न आक्रमणकारियों ने अपनी भूमि की रक्षा करने के लिये भूमि पर वीर सामन्ता को अधिकार दे दिया। इन वीर सामन्तों ने भूमि की रक्षा के बदले किसानों से कर मागा, जिस उद्दान दना स्वीकार कर लिया। कुछ धार्मिक लोग ने अपनी भूमि का अधिकार चर्च को दे दिया। चर्च ने इसके बदले में उनको आजीवन खेती करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार समय के अनुसार वीर पुरुषों और जन साधारण के बीच एक समझौता सम्पन्न हुआ। इसमें सामन्तों की उत्पत्ति हुई और उनका नाम सामन्तवाद कहलाया।

डब्ल्यू० एन० वीच ने लिखा है कि—'केन्द्रीय सरकार के समाप्त हो जाने पर जनता अपनी रक्षा के लिये स्वतः उन समूह बना ले, जो किसी शक्तिशाली के चारों तरफ हो समाज के उसी गठन को सामन्तवाद कहते हैं।' वनस ने लिखा है कि—'सामन्तवाद की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि समाज का विखंडित टांचा जिसमें सरकार की शक्ति अपन पर आधारित लोगों के सामन्त में हो।'²

प्रोफेसर विन्डूर ने लिखा कि—'इतिहास की अधिकांश आधिक और सामाजिक रचनाओं के समान सामन्तवाद भी स्थायी समय और मानव स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुकूल था।'

यूरोप में छठी शताब्दी से लेकर 15 वीं शताब्दी तक सामन्तवाद का विकास होना रहा। सामन्तवादी शासन व्यवस्था के अन्दर स्थानीय शासक राजा के अधिकारों का प्रयोग करता था। सामन्तवाद का स्वरूप विभिन्न देशों में अलग अलग था। विशाल रामन साम्राज्य की रक्षा के लिये सम्राट ने अपने वंशज और सम्बन्धियों को राज्य के कुछ भाग पर अधिकार दे दिया। ये व्यक्ति अपने अधीन राज्यों में शांति व्यवस्था बनाय रखते। अपने अधीन लोगों से कर वसूल करते और जापसी झगडा पर निणय करते थे। युद्ध के समय में सामन्त अपनी सेना लेकर राजा की सहायता के लिये युद्ध के मैदान में पहुँच जाते थे। धीरे धीरे ये पद पतक हो गये। यही व्यक्ति आगे चल कर सामन्त कहलाये। सेवान ने लिखा है कि—'मध्यकालीन सामन्तवाद इन्हीं परिस्थितियों का दूसरा प्रत्यक्षीकरण था।'³

सम्राट शासन द्वारा नियुक्त प्रांतों के अधिकारी आगे चलकर सामन्त बन गये। शासन के समय इन प्रांतीय अधिकारियों का 'मैसीडोनीनिसाह' के नाम से पुकारा जाता था। शासन के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी धर्मोद्योग और दुर्ग सिद्ध हुए। उद्दान सामन्ता का सहयोग प्राप्त करने के लिये, उद्दान

1—वीच डब्ल्यू० एन०—हिस्ट्री आफ दी वर्ल्ड—पृ 419

2—मैकनेल वनस—वैस्टा सिविलीजेशन—पृ 274

3—सेवान—ए हिस्ट्री आफ वर्ल्ड सिविलीजेशन—पृ 299

विशेष अधिकार और सुविधायें प्रदान कीं। जिससे प्रागे चल कर सामन्तवाद का निरन्तर विकास होता रहा।

सामन्तवाद के विकास के कारण—सामन्तवाद के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) विशाल साम्राज्य की स्थापना—मध्ययुग में राजा विशाल साम्राज्य की स्थापना तो कर लेता था, लेकिन यातायात के साधनों के अभाव के कारण और स्वयं की दुबलताओं के कारण अपने विशाल साम्राज्य को ठीक तरह से नहीं सभाल सकते थे, इसलिये उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपना विशाल साम्राज्य कई भागों में विभक्त कर दिया और वहाँ पर उन्होंने अपने सम्बन्धियों का शासन करने के लिये नियुक्त किया। इससे सामन्तवाद का तीव्र गति से विकास हुआ।

रोमन प्रशासन व्यवस्था में स्थानीय शासन का दायित्व कुलीनों पर निभार करता था। शक्तिशाली सम्राट के शासनकाल में स्थानीय कुलीन अधिकारियों के द्वाय आदेशों के अनुसार शासन करते रहे। जब वे द्र दुबल हो गया तो इन स्थानीय कुलीन अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से शासन करना आरम्भ कर दिया, और अपनी सुरक्षा के लिये अपने से अधिक शक्तिशाली कुलीनों का संरक्षण प्राप्त कर लिया।

(2) राजनीतिक अवस्था—अपने उत्थप काल में रोम ने सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप पर अधिकार कर लिया था और एक ही समय तक उन्होंने वहाँ पर शक्ति और सुव्यवस्था बनाये रखी। रोमन साम्राज्य के पतन के समय पश्चिमी यूरोप में अराजकता अशांति और अव्यवस्था फलने लगी। इसी समय बाहरी आक्रमण प्रारंभ हो गये। इससे किसान बहुत भयभीत हुए क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। रात्रि में बड़े बड़े कुलीन सरदारों ने अपने साधियों के साथ आमपास के किसानों का लूटना प्रारम्भ कर लिया। इतना ही नहीं इन कुलीन सरदारों ने अपने बराबर के कुलीनों को भी लूटना प्रारम्भ कर लिया।

कुलीन सरदारों की लूट के कारण किसान बहुत चिन्तित हो गये। उनको हमेशा अपनी फसल चोरी होने का भय रहता था लेकिन उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। इस समय किसान बहुत दुखी थे इसके अतिरिक्त कुलीन सरदार भी दुखी थे। क्योंकि उन्हें आय दिन बड़े सरदारों के हमले का भय लगा रहता था। कुलीन सरदारों के पास अस्त्र शस्त्र और दुग थे इसलिए किसान चाहते थे कि कुलीन सरदार उनकी रक्षा करे। कुलीन सरदार अपने दुग की रक्षा करने के लिए ऐसे लोगों की तलाश में थे जो उनकी सहायता में भर्ती हो सकें। इसके अतिरिक्त वे धन भी प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए कुलीन सरदारों और किसानों के बीच में एक समझौता हो गया।

इस समझौते के अनुसार किसानों ने अपनी भूमि सरदारों को सौंप दी और यह निश्चित हुआ कि सरदार न तो उनको लूटेंगे और न ही उनकी फसल को

किसान पट्टे चायेंगे। इससे अतिरिक्त यदि किसी अन्य सरदार न उन पर आक्रमण किया तो वे उनकी रक्षा करेंगे और अपने किले में आश्रय देंगे। इससे बदले में किसान अपनी उपज का एक निश्चित भाग सामन्तों को कर के रूप में देंगे, और उनके अन्य काम निःशुल्क करेंगे। इस व्यवस्था से किसानों को अपनी सुरक्षा की गारंटी तो प्राप्त हो गयी, परन्तु अब किसान स्वतंत्र नहीं रहे। उनकी भूमि पर सामन्तों का अधिकार हो गया। अब किसानों की दशा अद्ध दास (सफ) जसी हो गई थी। इसी प्रकार दुबले सामन्तों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने से शक्तिशाली सामन्तों के साथ समझौता कर लिया। बड़े सामन्तों ने छोटे सामन्तों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। इससे बदले में छोटे सामन्तों ने धन तथा सैनिकों से बड़े सामन्तों की सेवा करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक नई सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ।

(3) आर्थिक व्यवस्था—सामन्तवाद प्रथा के विकास में आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रोमन साम्राज्य का सारा काम दास ही करते थे। खेती भी दासों के द्वारा ही की जाती थी, लेकिन दासों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनके स्वामी उनका शोषण करते थे। उन पर नाना प्रकार के जबरन कर चलाए जाते थे। परिणामस्वरूप दासों ने खेती करना छोड़ दिया, जिससे राज्य की पदावार घटने लगी।

ऐसी स्थिति में रोमन लोगों ने पदावार बढ़ाने के लिए गुलामों का कुछ सुविधाएँ प्रदान कीं। उन्होंने गुलामों को भूमि दी और उन्हें दासता से मुक्त कर दिया। अब गुलामों ने खेती का काम करना शुरू कर दिया लेकिन उन्हें अपनी भूमि की उपज का कुछ हिस्सा कर के रूप में अपने स्वामी को देना पड़ता था। इससे अतिरिक्त गुलामों का अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य काम निःशुल्क करने पड़ते थे। इस प्रकार गुलामों को ज्यादा सुविधाएँ तो नहीं मिलीं परन्तु उन्हें पारिवारिक जीवन तथा भरण पोषण करने की सुविधा अवश्य प्राप्त हो गई। जब इन गुलामों को अद्ध दास या कृषक दास या सफ जैसी कम्मा के नाम से पुकारा जान लगा। इन नये किसानों की रक्षा करने का क्वान्त सरदार सामन्तों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक सामन्त के अधीन कई सफ होते थे। एक बड़े सामन्त के अधीन कई छोटे सामन्त होते थे। इनमें से प्रत्येक अपने स्वामी के जगह स्वामी बनने की शपथ ग्रहण करता था। एक सफ अपना सिर सामन्त के चरणों में रखकर शपथ ग्रहण करता था कि "आज के दिन से आजीवन मैं शरीर और आत्मा से आपका आामी बनता हूँ और आपको प्रति सच्चा और बफादार रहूँगा।"

तब सामन्त उस सफ को उठा कर उसका मुँह चूमता था। इन प्रकार किसान सामन्तों की, सामन्त बड़े सामन्तों की और बड़ा सामन्त राजा की अधीनता स्वीकार करता था। अब भूमि पर सामन्तों का अधिकार था। वह जब चाहें तब

कृषक को भूमि से वेदखल कर सकता था। इसलिए सामंतवादी व्यवस्था को एक कृषि सम्बन्धी सामाजिक व्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि कृषक और सामंत के आपसी सम्बन्धों का मुख्य आधार भूमि वितरण था।

(4) जमनी का प्रभाव—मैकनल बनस ने लिखा है कि “यदि जमनी का प्रभाव नहीं होता तो मध्य युग में सामंतवाद विशेष स्वरूप धारण नहीं करता।”¹

रोम से पहले जमनी में सामंतवाद का विराम आरम्भ हो गया था। जमनी में इस विक्रम का श्रेय कोमीटेस नामक संस्था को दिया जाता है। कोमीटेस एक ऐसी संस्था थी, जिसका प्रत्येक सदस्य बफादारी और ईमानदारी से अपने मुखिया की सेवा करने का वायदा करता था। इसके बदले में मुखिया उसे भूमि पर खेती करने का अधिकार देता था एवं शस्त्र देता था। इस संस्था के प्रत्येक सदस्य का बाइबल पर हाथ रखकर बफादारी की वसम खानी पड़ती थी। जमनी के सामन्तवाद का स्वरूप रोमन स्वरूप से भिन्न था। जमनी की इस संस्था में मुखिया और अर्थ योद्धा बराबर थे। बनस ने लिखा है कि “कोमीटेस का सम्मान और बफादारी के सम्बन्धों के विचार ने ही आगे चलकर साम्यवाद में अपना रूप बदल दिया।”

यहां के सामंतवाद में सामंत के द्वारा प्रत्येक सदस्य को बफादारी की शपथ दिलवाई जाती थी। उस कमीशन कहने से। यह शब्द कोमीटेस से ही लिया गया है। जमनी के कोमीटेस नामक संस्था के सदस्यों को सम्पत्ति रखने का अधिकार था। इस संस्था का मुखिया जनता को अपनी सम्पत्ति भी लजान की स्वीकृति देता था। इससे स्पष्ट है कि जमनी में सामंतवाद को संगठित किया। सामंतवाद के कानून और परम्परा पर भी जमन प्रभाव स्पष्ट रूप से छिप्टगोचर होता है।

जमन समाज विभिन्न कबीला में विभाजित था। यहां प्रत्येक जाति के कबीला का अलग-अलग नेता होता था। जब जमनी के कबीला न काफी भूमि पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने प्रत्येक कबीले के नेता को भूमि बांटनी। इस समय दोनों के बीच यह समझौता हुआ कि नेता उनकी रक्षा करेगा लेकिन उसके अधीन सरदार अपना नेता के लिए सैनिक तथा राजनीतिक सवाये देंगे। इस प्रकार विभिन्न कबीला का नेता बहुत बड़ा सामंत बन गया।

(5) शालमन की नीति—रोमन साम्राज्य के पतन के समय सामन्तवाद का विनाश हो रहा था। रोम के पतन के काल में आठवीं शताब्दी में पेपिन नामक संस्थापति ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पेपिन के करलोमैन और शालमन दो पुत्र थे। पेपिन के दोना पुत्र ने विशाल साम्राज्य का दो भागों में विभाजित कर दिया। करलोमैन ने अनेक प्रदेश विजय कर साम्राज्य का विस्तार किया किंतु कुछ ही वर्षों में उसकी मृत्यु हो गई।

1 मैकनल बनस—वस्टन सिवलीजेशन—पृष्ठ-275

2 मैकनल बनस—वस्टन सिवलीजेशन—पृष्ठ-276

शालमेन के लिये इस विशाल साम्राज्य पर यातायात के साधनों के अभाव के कारण नियंत्रण रचना बहुत कठिन था। उसने इस समस्या को हल करने के लिये अपने विशाल साम्राज्य का विभाजन कर लिया तथा प्रत्येक प्रांत में अपने स्थानीय सेवकों को नियुक्त कर लिया। प्रांत का प्रत्येक स्थानीय शासक एक निश्चित मात्रा में सेना रख सकता था और वह में एक बार शालमेन के दरबार में उपस्थित होकर उसको लगान और उपहार स्वरूप अनेक वस्तुएँ देता था। शालमेन एक योग्य और पराक्रमी सम्राट था। कमलिये उसके शासन काल में प्रांत के किमी भी स्थानीय शासक ने विद्रोह करने का साहस नहीं किया किंतु शासन की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकायियों का दुर्बलता के कारण सभी स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गये। ये स्थानीय शासन सामान्य कहलाये। इस प्रकार यूरोप में शालमेन ने सामन्त प्रथा का समर्थन किया। एलिस और जीन ने लिखा है कि शालमेन का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उस पर एक व्यक्ति अकेला शासन नहीं कर सकता था। इसके अनिश्चित उसके समय में घात का अभाव था। कमलिये शालमेन ने युद्ध सहायता देने वाला को बड़े बड़े भूखण्ड दिये। हम पर उन्हें शासन करना था। इन भूखण्डों को काउण्टी डची और माय कहते थे। इनके शासक काउण्ट ड्यूक और मार्किज कहलाते थे। इस तरह इन उपाधियों की उत्पत्ति हुई जो यूरोप में प्रचलित हैं। इस प्रथा के कारण लोगों के पास बड़ी बड़ी भूमि सम्पत्तियाँ बन गईं और किसान अपनी भूमि के स्वामित्व से वंचित रह गये।¹ इस प्रथा को इतिहासकारों ने सामन्तवाद के नाम से पुकारा है।

(6) यातायात के साधनों का अभाव—अग्नेयों ने विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। विकसित यातायात के साधनों के कारण व एक लम्बे समय तक अपने विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करते रहे। प्राचीन काल में यातायात के साधनों के अभाव के कारण शासक अपने विशाल साम्राज्य को सभालने में असमर्थ थे इसलिये राजाओं ने विशाल साम्राज्य को विभक्त कर अपने मर्दाधियाँ और स्वामीभक्त सेवकों को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इससे आगे चलकर सामन्तवाद का विकास हुआ।

मध्य कालीन युग में पश्चिमी यूरोप में अराजकता, अशांति और अव्यवस्था फैली हुई थी। उस समय यातायात के साधनों के अभाव के कारण राजा के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना एक श्रमपूर्ण कठिन कार्य था। ऐसी परिस्थिति में सामन्तवाद के विकास का प्रास्तावक मिला। इस समय प्रत्येक अवसरवादी ने अपनी शक्ति में वृद्धि की। पादरी रोमन अधिकारी तथा प्रत्येक अवसरवादी सरदार ने अपन प्रभाव में वृद्धि की। ऐसे समय

म गरीब लोगो ने अपनी सुरक्षा व निय शक्तिशाली लोगो की शरण ली। बीच न लिया है कि जराजगता और सन्धिघता के सागर म यूरोप डूबा जा रहा था। तभी राजनीतिक सगठन व नाम पर सामतवाद का बडी तजी स सगठन हुआ।¹

सामतवाद के चि ह यूरोप म आज भी स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर हाते हैं।

(7) विदेशियों के आक्रमण—मध्ययुग म विदेशिया के आक्रमण के कारण सामतवाद का तीव्र गति से विराम हुआ। आठवीं शताब्दी मे नोमस, स्लाव और मुसलमान पश्चिमी यूरोप पर लगातार आक्रमण करने रहे। ये आक्रमण कर लूटमार मचात और अनन व्यक्तिया का निदयता स बल कर देत थे। मुख्यरूप से नोम स के आक्रमणा का पश्चिमी यूरोप पर भारी आतक छाया हुआ था। इन आक्रमणकारिया से रक्षा पान के लिये किसानो ने ऐस शक्तिशाली व्यक्तिया का शरण ली जिनके पास हथियार और सुरक्षा के लिये दुग थे। इस प्रकार विदेशी आक्रमणा की वृद्धि व कारण जनता का शरणागत और शासका की सामत के रूप म परि वर्तित कर लिया। यूरोपियन सम्राटो ने विदेशी आक्रमणा से जनता की रक्षा करने के लिये सेनापतिया और वीर पुरपो को भूमि प्रदान की। इसके बदले मे उनसे अच्छी सेना की माग की गई कालांतर मे ये सेनापति ही सामत बन गय।

(8) धम युद्ध—यूरोप म इस्लाम का विस्तार रोकने के लिय छोटे छोटे जागीरदारा ने धम युद्धो म चच की सहायता की और इन युद्धो म उहोने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। इन जागीरदारा न पश्चिमी यूरोप म इस्लाम के प्रसार पर रोक लगा दी। परिणाम स्वरूप जन साधारण को यह विश्वास हा गया कि सवट के समय ये जागीरदार या सामत उनकी रक्षा कर सक्ते हैं। इसलिये आम जनता सामतो के दुगों के नीचे चारो ओर बस गई ताकि आक्रमण के समय वे अपनी जान की रक्षा करने के लिए गडी मे शरण ले सके।

गढ म रहन वाल ड्यूक और काउंट आदि कुलीन पुरुष धम युद्धो म प्राप्त ध्याति का लाभ उठाकर सामत बन गये। प्राचीन काल म सम्राट चच को उपहार स्वरूप जागीर और जमीनें आदि दान म देत थे। चच ने जिन जिन किसानो को अपनी भूमि खती करन के लिय दी वे किसान चच के वफादार और स्वामीभक्त सेवक बन गये। चच के जाधार पर अय समृद्ध लोगो ने भी अपनी भूमि खती करने के लिए कुछ लोगो को दी। वे लोग उनके वफादार सवक बन गये। इस प्रकार सामतवाद प्रारम्भ हो गया। यद्यपि सामतो के नेतृत्व म ईसाई धम युद्ध म मुसलमानो का पराजित नहीं कर सके लेकिन धम युद्धो म उहोने ईसाई सेना का नेतृत्व किया। जिसके कारण ईसाई जगत म उनका सम्मान और प्रतिष्ठा बडी। इस अवसर का लाभ उठाकर इन सामन्तो ने अपनी शक्ति मे वृद्धि की।

1 बीच ड्यूक एन—हिस्ट्री आफ दी वर्ल्ड

(9) सामन्तों का आदश चरित्र—एक तरफ तो कुछ ऐसे सामन्त थे जो छूटत और उनके परिवार के सदस्यों को गुलामों की तरह बेच देते थे। उनकी इस प्रकार की छूटमार से सब तरफ अराजकता अशान्ति और अव्यवस्था का आतंक छाया हुआ था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे धर्म परायण सामन्त भी थे जिनके अच्छे चरित्र व कर्मों से जन साधारण उनकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने किसानों की अन्वमणकारियों से रक्षा की और गरीबों को शोषण तथा दासता से मुक्ति दिलवाई। उनकी कला के क्षेत्र में बहुत अधिक रुचि थी इसलिये उन्होंने अपने यहां कई कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। परिणामस्वरूप इन मध्य समृद्ध और शक्तिशाली सामन्तों की जनसाधारण ने अधीनता स्वीकार करली। इस प्रकार सामन्तवाद का विकास होता चला गया।

(10) रोमन प्रथाओं का प्रभाव—रोमन साम्राज्य की 'कोलोनेट' और 'प्रिसेरियम' आदि प्रथाओं ने सामन्तवाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोलोनेट प्रथा में तो सामन्तों ने अपनी उपज में बढ़ि करने के लिये गुलामों को थोड़ी स्वतंत्रता देकर अपनी भूमि उन्हें खेती करने के लिये दे दी। इससे सामन्तों की शक्ति में वृद्धि हुई।

प्रिसेरियम प्रथा के अंतर्गत समृद्ध लोग अपनी जीती हुई भूमि को किसानों को किराये पर खेती करने के लिये दे देते थे। इसी प्रथा के अनुसार कई किसानों ने अपनी सुरक्षा के लिये या बज से मुक्ति प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि सामन्तों को सौंप दी। इस प्रथा के अनुसार भूमि स्वामी अपने किरायेदार किसानों की रक्षा का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता था और सकट के समय उनकी रक्षा करता था। मैक्सवेल ब्रनस ने लिखा है कि "इन अंतिम रोमन प्रथाओं का जिन्हें कोलोनेट और प्रिसेरियम कहते थे। रोमन इतिहास में सामन्तवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान है।" ¹ कालांतर में किरायेदार किसान केवल सामन्त के मात्र सबक बनकर रह गये और उनका सम्राट के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

सामन्तवाद का अर्थ तथा सत्य—साधारण तौर से जब एक कमजोर व्यक्ति अपनी भूमि तथा स्वयं की सुरक्षा के लिये अपनी भूमि को एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में सौंप देता और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता तो वह शक्तिशाली व्यक्ति उसकी सुरक्षा करता था। इसके बदले में कमजोर व्यक्ति उसको अपनी उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में देता था। इस व्यवस्था को सामन्तवाद के नाम से पुकारा जाता था। अराजकता के समय में सामन्तवाद का विकास हुआ। इसका विकास धीरे धीरे हुआ। इस व्यवस्था को पूर्ण विकसित होने में कई शताब्दियाँ बीत गईं। आरम्भ में सामन्तवाद एक समझौते की तरह था। इस व्यवस्था के

अनुसार कृषक और सामन्तों के बीच एक समझौता हो जाता था और दोनों ही समझौते के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। धीरे-धीरे चर्चों, राजाओं और नगर के समृद्ध लोगों ने भी सामन्त बनना आरम्भ कर दिया। कुछ ही समय में सामन्तवाद सभी सभ्यताओं पर छा गया।

सामन्त को 'लाड' तथा उसकी भूमि को 'फीफ' के नाम से पुकारा जाता था। राजा सामन्त को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि देता था उसे वह फिराप पर खेती करने के लिये किसानों को दे देता था। दोनों के बीच में एक समझौता ही जाता था। उसके अनुसार सामन्त खेती करने के बदले में किसान का उपज का एक निश्चित भाग देता था। शेष उपज पर सामन्त का अधिकार रहता था। इसी प्रकार छोटे सामन्त बड़े सामन्तों से समझौता करते थे। इसके अनुसार बड़ा सामन्त छोटे सामन्त की रक्षा करता था। इस रक्षा के बदले में छोटा सामन्त बड़े सामन्त को उपज का एक निश्चित भाग देता था। उस समय बड़े सामन्त वल्लास (आसामी) रखते थे। सामन्त अपने स बड़े लाड की सैनिक सेवा करता था और अनेक वस्तुएँ उसको उपहार स्वरूप भेंट करता था। यदि युद्ध में लाड का बंदी बना लिया जाता तो सफ उससे हरजाना देकर छोड़ाकर लाते थे। इसी प्रकार लाड की लड़की की शादी में सभी सफों को उपहार स्वरूप वस्तुएँ भेंट देनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त लाड का लड़का ब्यस्क होने पर उसे 'नाईट' की उपाधि प्रदान की जाती थी और उसके अधीन किसानों को उपहार देने पड़ते थे।

समय के अनुसार सम्राटों ने प्रांतों के स्थानीय सामन्तों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया और राजस्व सम्बन्धी मामलों में निर्णय करने का भी अधिकार दिया। इससे सामन्तों की शक्ति में और वृद्धि हुई। छोटे सामन्त को अपनी जागीर से बाहर जाने के लिये बड़े सामन्त की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उनके शादी ब्याह लेने देना भी बड़े सामन्त की इजाजत के बिना नहीं हो सकता था। सिर्फ लोगों के लिये अध्ययन भी वर्जित था। उनको पढाई करने के लिये सामन्त की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। जब लाड अपने वेलास (आसामी) को भूमि सौंपता था तो वेलास इमानदारी और बफादारी से काम करने की कसम खाता था। वेलास की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र के ब्यस्क होने पर सामन्त उसको भूमि सौंप देता था। उस समय देश का शासन सामन्तों के हाथ में था। यह कहना गलत न होगा कि मध्यकालीन यूरोप में शासन की वास्तविक शक्ति सामन्तों के हाथों में निहित थी। सामन्त अपनी रक्षा के लिये पत्थर की मजबूत दीवारों से दुर्गों का निर्माण करवाते थे। प्रागे चलकर इन दुर्गों में टावर का भी निर्माण किया जाने लगा। जिनकी ऊँचाई 190 फीट तक होती थी। इन टावरों में सतरी पहरा देता था। सामन्त के लड़के की बचपन से ही सभी प्रकार के शस्त्रों की चलाने की शिक्षा दी जाती थी। इस काल में वीर पुरुष को आदर की दृष्टि से देखा जाता

था। उसे समाज में बहुत सम्मान दिया जाता था। प्लेट जीन और डमड ने सामन्त-काल के एक मीन की निम्न पत्निया दी है 'जान्ति में मुझे नहीं आनन्द, युद्ध तू बनजा मेरा भाग्य।'¹

उस समय छोटा भाई अपने बड़े भाई की भूमि पर अधिकार करने के लिए उमकी हत्या तक कर देता था। बड़े साम्राज्यों के पतन के समय सामन्तवाद का तेजी के साथ विकास हुआ।

सामन्तवाद का स्वरूप—सामन्तवादी व्यवस्था का आधार भूमि वितरण व्यवस्था थी। उस समय इस प्रथा के दो स्वरूप थे—1-राजनीतिक दृष्टि से सामन्तवाद का स्वरूप 2-आर्थिक दृष्टि से सामन्तवाद का स्वरूप।

(1) राजनीतिक दृष्टि से सामन्तवाद का स्वरूप—राजनीतिक स्वरूप के अन्तर्गत सामन्तवादी व्यवस्था में कमजोर सम्राट भी सर्वोपरि होता था। देश की सम्पूर्ण भूमि पर सम्राट का अधिकार माना जाता था। वह कुछ भूमि को अपने पास रखना था और शेष भूमि को लाड में बांट देता था। य लाड बड़े सामन्त होते थे, जो विशाल भूमि के स्वामी होते थे। बड़ा सामन्त अपनी पीफ पीफ को छोटे-छोटे भाग में विभाजित कर छोटे सामन्तों में बांट देता था। य छोटे सामन्त बड़े सामन्तों के वासाल (आसामी) थे। इनका अपनी योग्यतानुसार ड्यूक, काउण्ट बैरन और 'नारिट' की उपाधि प्रदान की जाती थी।

काउण्ट की नियुक्ति सम्राट के द्वारा स्थायी रूप से की जाती थी और वह सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। उसकी नियुक्ति करना तथा पद से हटाना सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। त्रेन क्रिस्टल न लिखा है कि काउण्ट आर्थिक-आर्थिक व मनुष्यिक प्रबंध के साथ शासन के प्रतिनिधि के रूप में करता था। इसने अतिरिक्त वह सिर्फ सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था।

ड्यूक को लैटिन भाषा में ड्यूक्स कहा जाता है। जिसका अर्थ होता है 'विशाल भू-भाग का स्वामी' इससे पता चलता है कि ड्यूक काउण्ट से बड़ा और अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। युद्ध के परीक्षण में सफल व्यक्तियों को राज्य की आर से नारिट (गुरबोर) की उपाधि प्रदान की जाती थी। य नारिट भी अपनी भूमि का कुछ भाग दूसरा का देकर उन्हें अपना सेवक बना सकता था। चर्च के धर्माधिकारी भी भूमिपति (लाड) अपना अनुचर (वासाल) बना ही बन सकता था। सामन्तवाद का सबसे छोटा व्यक्ति मर्फ² होता था।

(2) आर्थिक दृष्टि से सामन्त प्रथा का स्वरूप—आर्थिक दृष्टि से सामन्त

1 प्लेट जीन और डमड-निर्वाह का इतिहास पृ 202

2 भूमि के छोटे-छोटे भाग को पीफ कहा जाता था।

3 ड्यूक दास को मध्य युग में मर्फ के नाम से पुकारा जाता था।

प्रथा का स्वरूप सामन्त और कृषक के बीच सम्बन्धों पर आधारित था। इसके अन्तर्गत सामन्त की भूमि से प्राप्त होने वाली आय और उसके कृषक दास से सबंध निश्चित किये जाते थे। छोटे सामन्त गावों में मुदड़ दुग बनाकर रहते थे और दुग के आसपास की भूमि पर उनका अधिकार होता था। कभी कभी बड़े सामन्त अपने अधीन छोटे सामन्तों में भूमि को बांट देते थे। जिन शर्तों पर बड़ा सामन्त कृषक दास के साथ समझौता करता था। वही शर्तें बड़े सामन्त छोटे सामन्त के साथ भी रखता था। छोटे सामन्तों को "मनर" कहा जाता था।

एक शक्तिशाली सामन्त के पास हजारों की संख्या में मनर होते थे। ये मनर जीवन भर अपने स्वामी की सेवा करते थे। यदि कोई "मनर" बेच दिये जाते अथवा दूसरे भूमिपति के अधिकार में चले जाते तो कृषक दास भी बिके हुए समझे जाते थे और उन्हें नये स्वामी की आजीवन भर सेवा करनी पड़ती थी। सामन्त कृषक दासों का योग्य शोषण करता था। छोटे सामन्त भी बड़े सामन्तों की तरह अपनी भूमि कृषक दासों में बांटकर उनसे खेती करवाते थे।

सामन्तवाद का सगठन—जब राजा बड़े सामन्तों की और बड़े सामन्त छोटे सामन्तों की भूमि का हस्तांतरण करता था, तब एक शासदार समारोह आयोजित किया जाता था। इस समारोह में सामन्त निःशस्त्र होकर नग सिर राजा अथवा बड़े सामन्त के चरणों में झुक जाता था, और उनका हाथ चूमकर यह शपथ लेता था कि मैं आजीवन भर वफादारी और इमानदारी के साथ अपने स्वामी की सेवा करता रहूँगा और सामन्त का आदमी बनकर रहूँगा। लैटिन भाषा में आदमी का 'होमो' कहा जाता था। इसलिये यह शपथ 'होमोज' कहलाती थी। इसके पश्चात् कृषक दास बाईबल पर हाथ रखकर कसम खाता कि मैं जीवन भर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता रहूँगा। इस शपथ को फिफन्टी की शपथ कहा जाता था। इसके पश्चात् सामन्त या लाड अपने किसानों को मिट्टी का डेला या टहनी देता था। इसका अर्थ यह था कि किसान का जमीन दे दी गई। इसी के साथ मालिक अपने सामन्तों की रक्षा करने का वचन देता था।

उपरोक्त समारोह में सर्वोच्च स्थान राजा का और उसके बाद लाड का होता था, परन्तु वास्तविक स्थिति यह थी कि राजा का स्थान नाम मात्र का हुआ करता था और व्यावहारिक दृष्टि में लाड (बड़े सामन्त) का प्रभाव सर्वाधिक होता था। प्रशासन व्यवस्था का आधार बड़े बड़े सामन्त थे जिनका शासन पर पूर्ण नियन्त्रण था। राज्य के सभी उच्च पदा पर बड़े बड़े सामन्तों का अधिकार था। उस समय सामन्तों की प्रथा का मुख्य आधार सैनिक सेवा थी। राजा के पास स्याही और नियमित सेना नहीं होती थी। उसकी सैनिक शक्ति सामन्तों पर निर्भर करती थी। इसलिये सामन्तों का महत्त्व बना स्वाभाविक सी बात थी। ये सामन्त अपनी जागीरों में बने हुए मुदड़ दुगों में रहते थे। इनके राजा के दरबार में अधिकारी

और कमचारी रहते थे। कई बड़े-बड़े सामन्त ने राजाओं की तरह सिकके ढलवाय। राजा लोग विशेष अवसरों पर सामन्तों की सलाह लेने के लिये सभा बुलाते थे। इससे आगे चलकर ससदीय प्रणाली का सूत्रपात हुआ।

मध्य युग के सामन्तों के पास अपार धन सम्पत्ति और विशाल भूमि थी। उनका प्रशासन पर भी नियन्त्रण था। फिर भी ये लोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करते थे और अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा के साथ करते थे। वे अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिये हमेशा चिन्तित रहते थे। वे प्रजा की भलाई के लिये सावजनिक निर्माण के अनेक कार्य करवाते थे। पुल, और नहरों का निर्माण करवाते थे। सड़कों की मरम्मत करवाते थे। इतना ही नहीं मार्गों की सुरक्षा के लिये विशेष प्रबंध करते थे, ताकि व्यापार बिना किसी बाधा के उत्पन्न कर सके।

छोटे सामन्तों के कर्तव्य

1 वय में 40 दिन तक अपने बड़े सामन्त के लिये युद्ध करना पड़ेगा।

2 लाह के बुलाने पर उसके दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा।

3 वय में तीन बार बड़े लाह को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ वस्तु अवश्य देनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त छोटे सामन्त को लाह के लड़के को 'नाईट' की उपाधि मिलने के समय और उसकी गड़की की शादी में भेंट देनी पड़ती थी। साथ ही लाह के बन्दी बन जाने पर हरजाना देकर उस मुक्त भी करवाना पड़ता था।

सामन्त अपने किसानों के साथ लिखित समझौते करते थे।

बड़े सामन्तों के कर्तव्य—बड़े सामन्तों के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित थे—

1 बड़े सामन्त अपने क्षेत्र के निवासियों की आश्रमण के या बाह्य के समय रक्षा करने थे। उन्हें अपने गढ़ में मरक्षण देते थे। इसके अनिश्चित शत्रु से मुनाबला करने के लिये उन्हें अस्त्र शस्त्र आदि देते थे।

2 वे अपने क्षेत्र में कृषि, वाणिज्य व्यापार तथा उद्योग धंधों का प्रोत्साहन देते थे।

3 युद्ध के समय बड़े सामन्त अपनी सलाह लेकर राजा की सहायता के लिये पहुँच जाते थे और राजा की तरफ से युद्ध में भाग लेते थे।

4 बड़े सामन्त किसानों से उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में लेते थे।

5 वे अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखते थे।

6 राजा के बुलाने पर दरबार में उपस्थित होते थे और उसकी प्रत्येक राजकीय कार्य में सहयोग देते थे।

7 जनता में आपसी विवादों को निपटाना।

8 जनता को "याय प्रदान करना ।

9 जनता के धर्म की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य था ।

10 दुबल "यक्तिया तथा नारियो की रक्षा करना ।

11 किसान के बीमार हो जाने पर वह उसको आर्थिक सहायता प्रदान करता था ।

12 वह अपन क्षेत्र म जनहित के लिय नहरों पुल और सडकों आदि बनवाना था ।

प्रोफेसर ल्यूक्स न माग तो के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि मध्य युग म सामन्त आधुनिक सगठित राज्य की भांति काय करते थे । व अपने क्षेत्र म शांति और सुखवस्था बनाये रखते और आर्थिक उन्नति के लिये भी विशेष प्रयत्न करते थे । वे ये सब काय सनिको की सहायता से करते थे ।

सामन्तों के अधिकार— एक सामन्त अपने क्षेत्र म राजा की तरह अधिकार का प्रयोग करता था । वेवेस्टर ने लिखा है कि "सामन्तवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसम स्थानीय शासक उन सब शक्तिया का प्रयोग करते हैं जो कि एक सम्राट या राजा अथवा किसी केंद्रीय शक्ति को प्राप्त होते हैं । सामन्त अपने क्षेत्र की प्रजा पर इच्छानुसार शासन कर सकता था । उसे अपने अधीन प्रदेशों में याय के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त थे ।

एक सामन्त का अपने अधीन दासों पर पूर्ण नियन्त्रण था । वह उनसे मन चाहा ले सकता था । सामन्त अपनी व्यक्तिगत भूमि पर खेती कराने के अलावा दासों से बगार भी ले सकता था । उनको युद्ध म भाग लेना पड़ता था तथा सामन्त के कई घरेलू कामों को भी करना पड़ता था । यूरोप म इस प्रकार के दास बहुत अधिक सख्या म थे ।

एक सामन्त कृषक दास से भूमि के बदले में उपज का एक निश्चित भाग लगान के रूप में वसूल करता था । वह जब चाहे कृषक को भूमि से बेखल कर सकता था । एक कृषक की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी सामन्त की स्वीकृति के पश्चात् ही उस भूमि पर खेती कर सकता था । अपराध करने पर वह अपने किसान को कठोर से कठोर सजा दे सकता था । यहाँ तक कि उसका वध भी कर सकता था ।

कृषक दास के कर्तव्य — कृषक दास को 20 कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था । जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे —

(1) कम्मी (कृषक दास) अपने सामन्तों की खेती पर बिना मजदूरी के काम करता था । उन्हें अपनी उपज का एक निश्चित भाग सामन्तों को कर के रूप में देना पड़ता था । कृषक दास वष भर म सामन्त को तीन प्रकार से कर चुकाता

था। (अ)—सामन्त द्वारा राजा को दिया जाना वाला कर (ब)—सामन्त का कर (स) भूमिपति द्वारा इच्छानुसार लगाया गया कर।

(2) सफ (कपक दास) अपनी उपज का 1/10 भाग कर के रूप में सामन्त को देता था।

(3) सामन्त अपने कपक दास से मनचाहा वेगार ले सकता था। सफ अपने स्वामी के लिये रोटी पकाता था, शराब तैयार करता था, लकड़ी पाड़ता था और शिकार के समय अपने स्वामी की सहायता करता था।

(4) कपक दास अपने स्वामी के शराब के खर्च लिये शुल्क देता था।

(5) कपक दास को युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र धारण कर सामन्त की सना में भर्ती होना पड़ता था और युद्ध में सामन्त की ओर से लड़ना पड़ता था।

(6) सफ (कपक दास) अपने द्वारा बनाई गई जो भी वस्तु बाजार में बेचना उस वस्तु पर भी उसे सामन्त को कर देना पड़ता था।

(7) यदि कोई कपक दास अपने धनुआ को अपने स्वामी की भूमि पर चराता तो उसके बदले में उसे अपने सामन्त को कर देना पड़ता था।

(8) सामन्त के बनी धन जान पर सफ हरजाने की रकम देकर उसे मुक्त करवाते थे।

(9) सामन्त के पुत्र का 'नाईट' की उपाधि मिलान पर कपक दास उसे उपहार देते थे।

(10) सामन्त की पुत्री को विवाह में भी कपक दास को उपहार देना पड़ता था और उसके स्नेह के लिये भी धन देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त शादी के अवसर पर आयोजित किया जान वाले समारोहों का खर्चा भी देना पड़ता था।

(11) कम्मी या सफ के लड़के के लिये खर्च में जान पर तया पढ़ाई करने पर प्रतिबन्ध था। यदि कोई सफ इस आदेश की अवहेलना करता तो उसे सजा दी जाती थी, जबकि स्वामी के पुत्र की शिक्षा का व्यय उन्हें देना पड़ता था।

(12) यदि कोई कपक दास एक स्थान से दूसरे का जाना चाहता तो उसे अपने स्वामी की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी।

(13) यदि कोई कपक दास दूसरे सामन्त के प्रदेश में अपने पुत्र का विवाह करना चाहता तो उसे अपने स्वामी को जुमाना देना पड़ता था।

(14) यदि सामन्त चाहता तो अपने अधीन किसी भी कपक दास को नव सिन्हा पालन के साथ प्रथम रात्रि को सम्भोग कर सकता था।

(15) यदि कोई कपक दास निश्चयान मर जाता तो सामन्त उसकी धन सम्पत्ति छीन लेता था।

कपक दास का जीवन बहुत दुःख भय था। उसकी मेहनत का

उसका स्वाधी कर के रूप में ले लेता था। इस प्रकार सामन्त कृष्ण दासा का शोषण कर रहे थे लेकिन कभी कभी यदि सामन्त अपने कृष्ण दास के साथ सुहानुभूति उदारता एवं दया का व्यवहार करता तो इससे उसके जीवन में नव उत्साह का संचार हो जाता था।

सामन्तों का जीवन — (1) सामन्त की शक्तियाँ-सामन्त अपने क्षेत्र क्षेत्र का शासक होता था और अपने अधीन प्रदेशों में वह राजा की तरह अधिकारों का प्रयोग करता करता था। वह दूसरे सामन्तों से युद्ध और संधि कर सकता था और अपनी जागीर में राजा की तरह सिक्के ढलवाता था। सामन्त युद्ध में जो बचपहन कर जाता था उसका वजन 10 पौंड था।¹

सामन्त समय समय पर अपनी जागीर का निरीक्षण करता रहता था। इस निरीक्षण के समय वह गले में भारी जञ्जीर अगुली में मुद्दर अगुठिया, पैरों में लम्बे नुकीले जूने और एक बहुत मुद्दर गोटा किनारी लगा लम्बा वस्त्र धारण करता था। वह अपराधियों के कोठे लगाता था। उन्हें फाँसी पर लटकाने सकता था या बत्तल करवा सकता था। यदि कोई व्यक्ति राज्य द्रोही या धमद्रोही सिद्ध हो जाता तो उस मोत की सजा दी जाती थी।

(ii) आवास एवं खानपान—प्रत्येक सामन्त शत्रु से रक्षा करने के लिये शानदार बढियाँ व गुल्ड गड (दुग) का निर्माण करवाता था। यह पहाड़ों पर बनाये जाते थे। जिसके चारों तरफ चौड़ी खाई खोदी जाती थी। जब कभी गड पर आक्रमण होता तो गड के अन्दर से लोग शत्रु पर पत्थर और गरमशाशा आदि फेंकते थे। शत्रु लम्बे समय तक गड को घेरे रहता ताकि गड के लोग भूखे मर जायें। गड में खाद्यान्न के बड़े बड़े भण्डार भरे रहते थे। इनमें रहने के लिये विनोद सुविधा नहीं थी ये गड सीलनगर ठंडे और अंधेरे कमरों की तरह थे। इनमें सम्पन्न मनुष्य आराम से नहीं रह सकते थे। गड में गुलाब की पखुडियाँ बिखेर कर दुग्ध को दूर करने का प्रयास किया जाता था। सामन्तों का मुख्य भोजन सूप मास मछली पत्त और मिठाई आदि थे।

(iii) सामन्तों के समय स्त्रियों को दशा यद्यपि गड में महिलाएँ बड़ी शान शोक्त और ठाठ से रहती थी परन्तु उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त उन्हें बहुत कम स्वतन्त्रता थी। तेरह वष की लडकी का साठ वष के बुढडे के साथ विवाह किया जा सकता था। किसी कृष्ण दास की मृत्यु होने पर सामन्त उसकी लडकी से विवाह करता था। लडकी को वचपन से ही ऐसे हाव भाव और तरीके सिखाये जाते थे ताकि वह अपने पति को आजीवन खुश रख सके। उस

समय लड़कियां अपनी साम को गुणधित रखने के लिये विशेष प्रकार के बीज मानी रहती थी।¹

उस समय लड़कियां अपने शरीर को नाजुक, पतला, सुन्दर और आकर्षक बनाये रखने के लिये कम भोजन करती थी। उनकी गाना, बजाना, नृत्य करना घुड़सवारी करना और योद्धाओं को आकर्षित करना सिखाया जाता था। इसके अतिरिक्त उनको बढ़िया बुनाई और बसीदा निकालना सिखाया जाता था। उस समय प्रत्येक स्त्री यह चेष्टा करती थी कि उसका पति उसे जीवन भर प्यार करता रहे। पति की अनुपस्थिति में वह उसकी जागीर की देखभाल करती थी। सामन्ता में बहुपत्नि विवाह प्रथा प्रचलित थी। उस समय स्त्री के द्वारा गलती की जाने पर पति उसे पीट सकता था। पति को पीटना कानूनी रूप से वैध था।

(iv) सामन्ता के समय बच्चों की दशा — सामन्त का सबसे बड़ा लड़का उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। उसके बचस्क हान पर उसे 'नाईट' की उपाधि प्रदान की जाती थी। नाईट की उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति बहादुर होता था। जो अच्छा तैराक और तलवार चलाने में दक्ष होता था। नाईट की उपाधि के लिये बच्चे को बचपन से ही प्रशिक्षण दिया जाता था। सामन्त का सबसे बड़ा लड़का सात वर्ष का हो जाता तो उसे गढ़ में भेज दिया जाता था। जहाँ उसे महिनाएँ खाने-पीने का तरीका और शिष्टाचार आदि सिखाते थे। पादरी उस शिक्षा देता था तथा बीरता की कहानियां सुनाकर उस योद्धा बनने के लिये प्रोत्साहित करता था। उसे शिकार करना, नाचना और गाना आदि भी सिखाया जाता था। पन्द्रह वर्ष की आयु का होने पर उसे घुड़सवारी करने और हथियार चलाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर वह नाईट की उपाधि लेने के लिये जिम्ह बख्तर लेकर बच में पहुँच जाता था। जहाँ रात भर वह सिजदे में झुका रहता था। प्रातःकाल होने पर उसे स्नान कराया जाता था और उसके पश्चात् उसे जिम्ह बख्तर पहना लिया जाता था। इसके बाद सामन्त उसके कंधे पर तीन बार तलवार में हल्का बार कर करता था और कहता था कि "ईश्वर के सन्त माईकेल और सन्त जाज के नाम पर मैं तुम्हें नाईट की उपाधि प्रदान करता हूँ। बहादुर बनो शिष्ट बना, वफादार बनो।"²

(v) आमोद प्रमोद — मनोरंजन के मुख्य साधन नृत्य संगीत आदि थे। इसने अतिरिक्त जादूगर और नट जनता को अपने करिश्मे दिखाकर उसका मनोरंजन करत थे। इस शातिकाल में समास्य दूर्नामट आयोजित किये जाते थे। इसमें सूरमा

1 फ्लैट जीन व डमड-विश्व का इतिहास—पृष्ठ 205

2 एलिस व जोन-ससार का इतिहास—पृष्ठ—198

लोग द्वन्द्व युद्ध करते थे। इस समय सूरमाजा की पत्नियाँ हाथ में शस्त्र लेकर बठी रहती थीं। द्वन्द्व युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला सूरमा हारन वाले का गडा ल लेता था।

सामन्त के कार्य व उसकी समीक्षा — मध्य युग में सामन्त बठोर जीवन व्यतीत करता था। वह अपने स्वामी के लिये वफादार रहता था तथा उसकी हमेशा सहायता करता था। अपने प्रदेश में विद्रोह का निग्रह करने के लिये उस कई युद्ध करने पड़ते थे। कभी कभी वह कमजोर व्यक्तियाँ, स्त्रियाँ और धर्म की रक्षा के लिये भी युद्ध करता था। अपने प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाय रखना था। इसके अतिरिक्त भागों की सुरक्षा का प्रबंध करता था ताकि चिना किंगी अवरोध के व्यापार और वाणिज्य उत्थित कर सकें। वह अपना अधिकांश समय प्रजाहित के कार्यों पर व्यतीत कर देता था। यद्यपि उसके पान धन का अभाव नहीं था फिर भी जनता के समक्ष अपना आदश उपस्थित करने के लिये भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करता था।

यद्यपि सामन्त मध्यकालीन युग के प्रारम्भिक वर्षों में इन आदर्शों का पालन करते रहे, परन्तु इस युग की अन्तिम शताब्दियों में उन्होंने आदर्शों व कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दिया और भोग विलास पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। प्रारम्भ में वे जिस नारी के सतीत्व की रक्षा के लिये जान की बाजी लगाते थे अब उसी का अपहरण कर लेते। अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिये उन्होंने पड़ोसी सामन्तों से युद्ध करना प्रारम्भ कर लिया। किसानों पर मनमाना अत्याचार करने लग गये और उनका शोषण करने लगे। इन कार्यों के फलस्वरूप उनके अधीन प्रदेशों में अराजकता अशांति और अव्यवस्था फैलने लगी तथा जनता में सामन्तों के विरुद्ध असंतोष प्रारम्भ हो गया। जिसके कारण स्थान स्थान पर जनता ने उनके विरुद्ध विद्रोह करने प्रारम्भ कर दिये।

सामन्तों का चर्चों से सम्बन्ध — सेवान् ने लिखा है कि 'सामन्तवाद की बलिष्ठता गिरजाघर के प्रभाव से और भी बढ़ गई थी। गिरजाघर सबसे अधिक जमीन का मालिक था और कई विशेष अधिकार रखता था। जो उसे बाद के रोमन सम्राटों और फ्रैंको ने दिये थे।¹ गिरजाघरों को अधिपत्य धन सम्पत्ति और भूमिदान के रूप में प्राप्त होती थी। चर्च व धर्माधिकारी विशेष और पादरीयों ने सामन्तों की तरह कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। जिस भूमि को पादरी किसानों में बाँटते थे। उस भूमि पर चर्च स्थाई रूप से अधिकार कर लेता था। कई सामन्त तो युद्ध में मारे जाते थे और कईयों की निःसंतान मृत्यु हो जाती थी। कुछ का राजा बदल देता था किन्तु जिस भूमि पर चर्च का अधिकार हो जाता उसका स्वामी कभी नहीं

बदलता था क्योंकि चञ्च बभी नहीं मरता। राज्या को इससे यह नुकसान होता था कि नया सामन्त (चञ्च) बनने पर भी उसको कोई आय प्राप्त नहीं होती थी गिरजाधरो के न तो लडके होते और न ही उनको नार्ईट की उपाधि दी जाती थी। इसलिये जो किमान चञ्च के अनुचर होते थे, उन्हें इन अवसरों पर भेंट आदि भी नहीं देनी पडती थी। परिणामस्वरूप सामन्त व शोयण स बचने के लिये गरीब लोगों न चञ्च की भूमि किराय पर लेना प्रारम्भ कर दिया।

गिरजाधरा ने सामन्त प्रथा म कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये। 1000 ई० मे "पीस आफ गौड" तथा 1027 ई० म प्रभू की धम सधि के नाम स सामन्तो को व्यथ के युद्ध न करने पर सहमत कर लिया। इस प्रकार चञ्च ने सामन्ता से आग्रह किया कि वे सप्ताह म चार दिन युद्ध न करें। सामन्तो ने इसे स्वीकार कर लिया। इम प्रकार चञ्च ने शांति का वातावरण बनान म महत्वपूर्ण योगदान दिया। चञ्च ने सामन्तो क शोपण स गरीब जनता का बचाने का यथा सभव प्रयास किया। इसी प्रकार चञ्च न ईस्टर् स पहले 40 दिन तक सामन्ता को युद्ध न करने की बात पर राजी कर लिया। गिरजाधर क प्रभाव का वणन करते हुए एलिस व जोन न लिखा ह कि 'युद्ध के दौरान किसाना व्यापारियो और स्त्रिया न सताने की मनाही की गई।'¹

चञ्च को इम बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने इन बहादुर सामन्तो को मानवीय दृष्टिकोण स मोचने के लिय विवश किया, ताकि युद्ध से पदावार और व्यापार को कोई हानि नहीं पहुँचे और आवश्यक वस्तुआ का उत्पादन बिना किसी बाधा क होता रहे।

सामन्त और राजा के बीच सम्बन्ध—मध्य युग म राजा नाम मात्र का शासन होता था और राज्य की वास्तविक शक्ति सामन्ता के हाथ म केन्द्रित थी। फ्रांस म अनवर ऐम सामन्त थे जिसके पास सम्राट से भी अधिक धन, भूमि और सना थी। छुटकारा देने की प्रथा के जतगत उस समय अनेक सामन्त सम्राट क नियन्त्रण से मुक्त हो चुके थे। इस प्रकार अनेक ऐसे सामन्त थे जो यद्यपि सम्राट क राज्य म रहने थे पर सम्राट का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं था। राज्य मे केवल मध्यम वर्ग ही सम्राट का स्वामी भक्त था। प्रत्येक सामन्त वष म तीन बार सम्राट को उपहार और वर देने के लिए जाता था। राजा को अपने अधीन सामन्ता के विवादो को निपटाने का अधिकार नहीं था। राज्य की सारी राजनीतिक शक्ति सामन्तो क हाथ म निहित थी।

सामन्त तथा राष्ट्रीयता—सेवाइन ने लिखा है कि "सामन्तवादी राज्य को

राष्ट्रीयता का पूवज कहा गया है।¹ यूरोप में अनेक ऐसे राज्य थे, जिनमें सामंत कई शताब्दियों तक शासन करते रहे। परिणाम स्वरूप अनेक देशों की अपेक्षा उन राज्यों में राष्ट्रीयता का विकास सबसे पहले हुआ। इलीडी, फ्रांस की रियासत के सामंतों के द्वारा फ्रांस का एकीकरण संभव हो सका था। अरागोन और कास्टिल रियासतों के सामंतों ने स्पेन का एकीकरण किया था। हेसबर्ग के सामंतों ने आस्ट्रिया का एकीकरण किया था। इस प्रकार सामंत रियासतों से एक राष्ट्र का निर्माण करने लगे। इंग्लैण्ड में विजेता विलियम ने 1806 में अपनी जाति के लोगों को एक करने की शपथ ग्रहण की। इस सालिलबरी शपथ कहा जाता था। वास्तविकता यह है कि सामंतवादी प्रथाएँ सारे यूरोप में आज तक प्रचलित हैं। फ्रांस में सामंतों द्वारा जनता का बहुत अधिक शोषण करने पर 1789 ई० में क्रांति हुई। 1917 ई० की रूसी क्रांति का मूल कारण भी सामंतों द्वारा जनता शोषण था। इस प्रकार सामंतवाद के कारण यूरोप में पहले राष्ट्रीयता की भावनाएँ विकसित हुईं और उसके बाद क्रांतिकारी विचारों का विकास हुआ।

सामंतवाद से लाभ—यद्यपि यह सत्य है कि सामंतवाद उपयोगी प्रथा नहीं थी। जिस भा देश में सामंतवादी शासन व्यवस्था होती थी वह कमजोर हो जाता था। और पतन की ओर अग्रसर हो जाता था। इतना सब कुछ होत हुए भी इस प्रथा से यूरोप के तत्कालीन समाज को बहुत लाभ हुए, क्योंकि मध्ययुग में यूरोपवासियों के जीवन के प्रत्येक अंग पर इस प्रथा का काफी प्रभाव पड़ा था। इस प्रथा के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

(1) साम्राज्य की सुरक्षा—रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् सामंतों ने बबर आक्रमणकारियों से अपने राज्यों की रक्षा की और जनता को शांति तथा सुरक्षा प्रदान की। यूरोप में जर्मनी की असभ्य जातियों के आक्रमणों के कारण भ्रष्टाचार, अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई थी। सामंतों ने इसका अंत किया और अपने राज्य की रक्षा करते हुए जनता को भी शांति और सुरक्षा प्रदान की। उस समय राजा की शक्ति कमजोर हो चुकी थी तब सामंतों ने आक्रमणकारियों से सामना करने के लिए राजा का अपनी सैनिक सहायता देकर उसके सारे साम्राज्य की रक्षा की। उन्होंने मध्य युग में व्याप्त अराजकता एवं अव्यवस्था का अंत किया और अपने अधीन प्रदेशों में शांति और सुव्यवस्था बनाये रखी। इस प्रकार सामंतों ने केन्द्रीय शक्ति के अभाव को पूरा कर दिया। इस प्रथा से राजा को समय पर सामंत सैनिक सहायता देते थे और सुरक्षा का भार भी अकेले राजा पर न होकर सामंतों में बँट गया था।

(2) शासकों पर नियंत्रण—सामंत प्रथा का दूसरा लाभ यह था कि उसने राजाओं की निरकुशता और स्वेच्छापरिता पर अकुश लगा दिया। सामंतों ने

राजाआ की शक्ति को नियंत्रित कर उसके अधिकारों को सीमित कर दिया। जिससे वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकें।

सामन्ता से पहले सम्राट अपने राज्य का सर्वोच्च होता था। सामन्तवादो व्यवस्था के विकास के कारण सम्राज्य की शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ गया। परिणाम स्वरूप सम्राट जन हित के कार्यों की तरफ ध्यान देने लगे, ताकि जनता में उनके विरुद्ध असंतोष नहीं रहे और सामन्त उसका खर्चा पलटने में सफल नहीं हो सकें। कुछ देशों में सामन्तों का सम्राट पर बहुत अधिक नियंत्रण था। वह चाहत हुए भी उनके अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता था। इंग्लैण्ड के राजा जॉन ने सामन्तों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया तो सामन्तों ने अपने मेग्नाकार्ट (अधिकार पत्र) पर जॉन का हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार सामन्तों ने जनता के अधिकारों का सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड में आगे चलकर प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था बरसित हुई।

(3) पाय एव वण्ड व्यवस्था—सामन्त प्रथा से पाय व्यवस्था को लाभ पहुंचा। सामन्तों की अदालत में उन्हें 'न्यायाधीश' 'माई लाड' या 'योर लाड शिप' आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाता था। आप भी अदालत में 'न्यायाधीश' के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह सामन्तवाद की एक महत्वपूर्ण देन है। आधुनिक यूरोप का कानून सामन्तों की अदालतों के कानून का विकसित रूप है। सामन्तों के दरबार में दो अदालतें होती थीं। एक में सिर्फ किसानों और प्रजा के झगड़े सुने जाते थे और दूसरा में केवल सामन्तों के आपसी झगड़े निपटारे जाते थे। आज की छोटी और बड़ी अदालतों का स्वरूप सामन्तों की अदालतों पर आधारित है। रामन नियमा के लागू हो जाने से सामन्तों ने अपनी पाय पद्धति के द्वारा उस कमी को पूरा किया। सामन्तों के न्यायालय में दिए परोक्षा, जिस 'आडियल' भी कहते थे, उसके द्वारा मुकदमों पर निणय दिया जाता था। इसके अतिरिक्त वादी और प्रतिवादी के बीच युद्ध करावाकर भी फैसला किया जाना था। अपराधी सिद्ध होने वाले व्यक्तियों को कीड़े लगाये जाते थे अथवा उन्हें दामा जाना था। घमदाही का अपराध मिट्ट होने वाले व्यक्ति का जिंदा अग्नि में डाल दिया जाता था।

(4) सामन्तों के कानून का विकास—सामन्तवाद ने सामन्तों के कानून के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामन्तवाद से पहले स्थानीय परम्पराएँ प्रचलित थीं, किन्तु आगे चलकर सामन्तों के कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश के लिए एक समान कानून बनाने का भाग प्रशस्त हो गया। सामन्तों ने देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

(5) नगरों की उन्नति—सामन्तों की प्रथा ने नगरों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय सामन्तों में प्रतिस्पर्धा थी इसलिए प्रत्येक

सामन्त अपने गढ़ तथा नगर को अपने पड़ोसी सामन्त से सुन्दर और समृद्ध बनाने का भग्सक प्रयास करता था। इससे नगरो का विकास हुआ। सामन्तो की इस प्रतिस्पर्धा के कारण उ होने अपन निवास स्थान को सुन्दर नगरो म परिणित कर दिया। पहले केवल देश की राजधानी ही एक बडा नगर माना जाता, किन्तु अनेक सामन्तो के कारण जीन नये नगरा का विकास हुआ। मध्यकाल म भारत के राजस्थान राज्य म 18 सामन्तो न 18 अच्छे नगरा का विकास किया। इम प्रकार सामन्तवाद न नगरा क विकास म अपना सहयाग दिया।

(6) आर्थिक विकास—सामन्तो प्रथा के कारण आर्थिक विकास बहुत अधिक हुआ। इस प्रथा क कारण कृषि और व्यापार के क्षेत्र म बहुत अधिक उन्नति हुई —

(i) कृषि—भूमि का स्वामी सामन्त होने क कारण भूमि छोटे छोटे टुकडा म नही हाती थी। सामन्त अपनी भूमि पर कृषका से खेती करवाता था। और उनकी महन्त क बन्ने मे वह उनको उपज का एक निश्चित भाग दे दना था। वह किसाना का भूमि हमशा के लिए नही देना था। इससे भूमि छोटे छोटे टुकडो म विभाजित होने स प्रच जाती थी।

सामन्त अपनी सारा भूमि पर एक साथ रिमानो स खेती करवाना था। भूमि की उबरना बनाय रखने क लिए वह भूमि के एक भाग को प्रति बष खाली छोड देता था। जिसस भूमि की उबरता बती रहती थी और उपज भी बहुत अधिक होती थी। उहाने अपने अधीन प्रदेशा म दलदला को मुखाकर कृषि याग्य बनाया तथा कृषि के विकास क लिए सिंचाई के साधन सुनभ कराये। सामन्तो ने अपने प्रदेशा म नहरो क बाधा का निर्माण करवाकर सिंचाई की समुचित व्यवस्था की।

(ii) व्यापार—सामन्तो के समय व्यापार के क्षेत्र म बहुत अधिक उन्नति हुई। व्यापारी बग इस युग मे हा धनवान बने। सामन्त व्यापार को इसलिय प्रात्साहन देते थे क्यकि व्यापारी उनको विकाम काय के लिए और युद्ध क लिए धन जादि देते थे। सामन्तो न डाकुजा का दमन कर दिया और सडका की मरम्मत करवाई नाकि दिना किमी बाधा क व्यापार उन्नति कर सके। सामन्त प्रत्येक व्यापारी से जो भी उसने सीमा म से हाकर गुजरात थी चुगी बसूल करत थे। यदि काइ व्यापारी चुगी बचाकर भागन का प्रयास करता ता उसका माल लूट लिया जाता था। इस प्रकार चुगी स सामन्तो को जाय हाती थी। सामन्तो ने व्यापार का प्रात्साहन दन के लिए अपने अधीन प्रदेशो म सडको का निर्माण करवाया।

(7) धम की रक्षा—सामन्त धम की रक्षा के लिए अपनी जान का बाजी तक लगा देते थे। वे धम के विराधियो स युद्ध करना अपना कर्तव्य समझते थे। इम समय ईसाई और मुसलमानो क बीच धम युद्ध हुए थे। इन युद्धो से ईसाई धम की प्रतिष्ठा को काफी घक्वा पहुचा। सामन्तो ने ईसाई धम की रक्षा करने के लिए

उत्साह के साथ इन धर्म युद्धों में भाग लिया और इसी धर्म की रक्षा कराने में सफल हुए ।

(8) साहित्य के क्षेत्र में प्रगति—सामन्त साहित्य के क्षेत्र में रची गयी थी, इसीलिए उन्होंने अपने दरबार में साहित्यकारों और कवियों को सुरक्षा दिया, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में प्रगतिशील रचनाएँ रचीं । उस समय यूरोप में साहित्यकारों ने वीरतापूर्ण रोमांचकारी साहित्य के क्षेत्र में अनेक रचनाएँ रचीं ।

(9) कला के क्षेत्र में प्रगति—सामन्तवाद के प्रादुर्भाव के कारण यूरामियन दशक ने कला के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की । सामन्त कला के प्रेमी थे इसलिए उन्होंने कला की बहुत प्रोत्साहन दिया । परिणामस्वरूप उस समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई । उस समय भवन निर्माण के क्षेत्र में रोमन और गार्थिक शैली का प्रयोग किया जाता था । रोमन शैली सामन्त की वीरता की प्रतीक थी । इस शैली के अनुसार बनाये गये मकान मजबूत और माटी दीवारों के होते थे । सामन्त रोमन शैली के आधार पर सुरक्षा के लिए मजबूत दुर्गों का निर्माण करवाते थे ।

गोथिक शैली सामन्तों की विलासिता का चिह्न थी । इस शैली के अनुसार बने हुए भवनों में भव्यता और सुन्दरता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती थी । इस प्रकार स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ । सामन्तों ने अपने दरबार में अनेक संगीतकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों को सुरक्षा दे रखी थी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रगतिशील रचनाएँ रचीं ।

सामन्तवाद के दोष—सामन्तवाद से न तो जनसाधारण को लाभ हुआ और न ही शासकों का । सामन्तवाद के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं —

(1) साम्राज्य में एकता का अभाव—सामन्तवाद के प्रादुर्भाव ने विशाल साम्राज्य का विभाजन कर दिया । इससे केन्द्र कमजोर हो गया और जनता की स्वामिभक्ति राजा और सामन्तों के बीच विभाजित हो गई । इस प्रथा के कारण देश प्रेम और राष्ट्रीयता का स्थान स्वार्थ और स्थानीयता ने ले लिया । सामन्तों के अधीन प्रदेशों की जनता राजा की अपेक्षा सामन्तों के प्रति अधिक स्वामिभक्त रहती थी । इस प्रकार सामन्तवाद ने राष्ट्रीयता के स्थान पर स्थानीयता की भावना को बढ़ावा दिया । सामन्तों अक्सर मिलते ही स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे । इस प्रकार साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर कई सामन्तों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये थे ।

(2) शक्ति का अभाव—सामन्तों ने शक्ति का अभाव को बढ़ावा दिया । अमीर गरीब, उच्च नीच का भेद बढ़ता गया । धनवान् लोग गरीबों का शोषण करते थे । इससे सभ्यता की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई । गरीब और अमीर के बीच शक्ति के अभाव में सामन्त अमीर का पक्ष करते थे । यहाँ तक कि अमीर

जपराध करने पर भी वानून उमका उतना दड नहीं देता था, जितना कि उसे मिलना चाहिए था। सामंत अपने किसानों पर अत्याचार करते थे और उनका शोषण करते थे। उस समय धर्माधिकारी भी सामंतों का पक्ष लेते थे।

(3) अधिनायक वाद का उन्त्य—सामंतवाद के प्रादुर्भाव से अधिनायक वाद का जन्म हुआ। अधिनायक वाद के बीटाणु सामंतवाद के समय से ही विकसित हो रहे थे जो 19 वीं शताब्दी में जाकर पूर्ण रूप से विकसित होकर विश्व के समक्ष प्रकट हुए। इससे अधिनायकवाद का तेजी से विकास हुआ। सामंत दूर-दूर प्रांतों में नियुक्त होते थे, इसलिये उन्हें राजा का कोई भय नहीं था और जनता के परवाह नहीं करते थे। उस समय सामंत अपने कोष को भरने के लिए जनता से मनमाने कर वसूल करते थे। इस प्रकार सामंत अपने अधीन प्रदेश में शासक की तरह स्वतंत्र रूप से शासन करता था और अपनी सैनिक शक्ति पर ही विश्वास करता था।

(4) कृषकों का शोषण—सामंत किसानों का शोषण करते थे। उस समय सामंत किसानों से अनेक उपहार भेंट और ब्रैगार आदि लेते थे। जैसे जैसे सामंतों को किसानों से धन मिल गया वैसे वैसे उनकी धन की लालसा बढ़ती गई। अब उन्होंने किसानों पर कई नये नये कर लगाये। मध्यकालीन फ्रांस में सामंत किसानों से रोटी बनाने, शराब बनाने और शादी करने का कर भी वसूल करते थे। इस युग में किसान सिर्फ सामंतों की सेवा करने के लिए ही जीता था। इतना होने पर भी सामंत कृषकों के हितों के लिए कोई ध्यान नहीं देते थे।

(5) यूरोप में अशांति—राजाओं ने विशाल साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए साम्राज्य का विभाजन कर सामंतों को नियुक्त किया था। परंतु इस प्रथा के कारण यूरोप में अराजकता अशांति और अयवस्था पली। सामंत अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आपस में युद्ध करते थे। राजा कमजोर होने के कारण उन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ था क्योंकि उसकी स्वयं की शक्ति का आधार भी सामंत थे। इस प्रकार युद्ध और अराजकता बढ़ती गई।

(6) सामंती का विलास प्रिय जीवन—कालांतर में सामंतों ने अपने आदर्श को भूलकर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर दिया और जनता पर अत्याचार करने लगे। सामंतों वृषक दास का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। उनका नतिक पतन भी होता जा रहा था।

पादरी लोग भी सामंत बनने लगे। यूरोप की अधिकांश भूमि पर चर्च का अधिकार था। चर्च के धर्माधिकारी सामंतों का पक्ष करते थे और उनके हितों की रक्षा करने के लिए यथामुभव प्रयास करते थे। सामंत और कृषकदास पादरियों को टाईय नाम का एक धार्मिक कर भी देते थे। इस प्रकार चर्च के धर्माधिकारी सामंत बनने लगे और उन्होंने भोगविलासपूर्ण जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर

दिया। गिरजाधरा में पादरियो व अनैतिक बच्चे पलने लगे। पाप भी गरीबों पर अत्याचार करने लगा था। पोप इन्फोसेंट तृतीय ने तो यहाँ तक कहा था कि "कर्मियों को ईश्वर ने ही गुलाम बनाया है।"

प्रारम्भ में सामन्त स्त्रियाँ की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देने से लेकिन अब उन्हीं सामन्तों ने स्त्रियाँ का भ्रष्टकरण करना शुरू कर दिया था। सामन्तों में बहु यत्न प्रथा प्रचलित थी। सामान्यतः वे अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्रियाँ के साथ कें साथ रगरेलियाँ मनाते थे। पादरियों के भोगविलास के कारण उनका नैतिक पतन शुरू हो गया और सुधारों की माँग होने लगी। परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आन्दोलन आरम्भ हुआ।

(7) व्यापार—वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति न होना—कुछ विद्वानों का मानना है कि सामन्ती प्रथा के समय व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकी। उनका मानना है कि सामन्तों का केवल अपनी जागीर की चिन्ता थी। वे सावजनिक भागों की सुरक्षा के लिए और सड़क की मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। सब नरक डाकुआ का बोल-बाला होने के कारण वे व्यापारियों का सामान मूट लेते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी प्रत्येक सामन्त की जागीर से गुजरते समय अपने सामान की चुगी देता था। इससे व्यापारियों का बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रत्येक सामन्त की चुगी चुवाते हुए जब वह अपना सामान लेकर अपने निर्धारित स्थान तक पहुँचता था तो उसकी कीमत काफी बढ़ जाती थी।

सामन्त युग में मुद्रा का प्रचलन बहुत कम था इसलिए लोग विशाल पैमाने पर उद्योग घाट्टे स्थापित नहीं कर सके। उस समय अनाज ही विदेशी विनिमय का साधन था। विदेशी व्यापार में लन दे के लिए मुद्रा के स्थान पर अनाज का प्रयोग किया जाता था। इस कारण इस युग में लोग नये उद्योग घाट्टे आरम्भ नहीं कर सके। ऐसी परिस्थितियों में व्यापार वाणिज्य का विकास होना सम्भव नहीं था।

सामन्तवाद के पतन के कारण—यद्यपि सामन्तों ने बबर आश्रयकारियों से यूरोप की रक्षा की, परन्तु उनके शासन में जनता पूर्णरूप से सुखी नहीं थी। सामन्त जनता पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे। परिणाम स्वरूप सामन्तों के विरुद्ध जनता में असन्तोष फैलना गया। यही कारण था कि मध्यकालीन युग के अन्तिम वर्षों में स्थान-स्थान पर जनता ने सामन्तों के विरुद्ध विद्रोह कर लिये, जिससे उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। प्रारम्भ में सामन्त जनता के सामने आश्रय उपस्थित करने के लिए सादरपूज्य जीवन व्यतीत करते थे और जनहित की आरंभ विशेष ध्यान देने से। अब सामन्तों ने विनासपूर्ण जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया और अपने अधीन जनता का शोषण करने लगे, इसलिए उनका पतन अवश्यम्भावी था। सामन्तवाद के पतन के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे —

(1) नवीन अस्त्रों शस्त्रों का प्रचलन — सामन्तवाद के पतन का पहला कारण नवीन अस्त्रा शस्त्रा का प्रचलित होना था। प्रारम्भ में सामन्त प्रथा के उत्कर्ष का कारण सामन्तों के पास अपार शक्ति थी। उनके पास सुदृढ़ दुर्ग अस्त्र शस्त्र तथा सैनिक थे जिनके द्वारा वह अपने अधीन प्रदेशों की जनता की रक्षा करता था। सामन्त सक्त के समय जनता का अपने दुर्गों में मरक्षण देता था। इन सुदृढ़ दुर्गों पर अधिकार करना बहुत कठिन भी था। सामन्त घोड़े पर गवार होकर भाले और बरछा से युद्ध करते थे। परन्तु 13 वीं शताब्दी में युद्ध नीति में परिवर्तन होने लगे। अब युद्ध में धनुष गाणा का उपयोग अधिक होने लगा। जिसके फलस्वरूप सामन्तों के भाले और बरछे बेकार सिद्ध हुए। भाले और बरछे निकट से युद्ध करने के लिए उपयोगी थे जबकि धनुष बाण द्वारा दूरी से ही शत्रु पर वार किया जा सकता था।

बाह्य के उपयोग के कारण सामन्तों की शक्ति का अन्त हो गया। सम्राटों ने बाह्य से सामन्तों के दुर्गों को धाराशाही कर दिया। इस प्रकार सामन्तों की शक्ति के केन्द्र दुर्गों के ध्वस्त हो जाने से उनकी शक्ति ही क्षीण हो गई। मध्य युग में बार्बुको के प्रचलन ने भी सामन्तों के शाय और महत्त्व को समाप्त कर दिया। राजाओं ने बार्बुको का उपयोग करने के लिये एक नई प्रशिक्षित पदल सेना का गठन किया जिसके सामने सामन्तों की घुड़सवार सेना बेकार सिद्ध हुई। अब राजाओं ने बाह्य पर एकाधिकार कायम कर लिया और बार्बुकोधारियों की एक स्थायी सेना का गठन किया। इस सेना का वेतन भी दिया जाने लगा। अब राजा के पास एक स्थायी सेना थी। उस सामन्तों की सैनिक सेवा की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार इन नवीन अस्त्रों शस्त्रों के प्रचलन ने सामन्तों की शक्ति का अन्त कर दिया।

(2) धार्मिक युद्धों का प्रभाव — तुर्कों ने ईसाईयों के पवित्र तीर्थ स्थान जेरुसलम पर अधिकार कर लिया था। इसाई पुनः जेरुसलम पर अधिकार करना चाहते थे इसलिये तुर्कों और ईसाईयों के बीच में युद्ध लड़ें गये। ये युद्ध इतिहास में घम युद्ध अथवा क्रूसेड के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये घम युद्ध 1095 ई. में लकर 1453 ई. तक चलते रहे। इन घम युद्धों ने अप्रत्यक्ष रूप से सामन्तों की शक्ति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता की। पोप की अपील पर सबका सामन्तों ने अपने सैनिकों और कृषक दामो के साथ इन घम युद्धों में भाग लिया। उनमें से अधिकांश सामन्त युद्ध में मार गये। जो कृषक दास युद्ध में बच गये उन्हें पाप न स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया। जब अनेक कृषक दास युद्ध से वापस लौटकर आये तो पोप ने अपने वायदे के अनुसार उनका स्वतंत्र कर लिया। इससे सामन्तों की शक्ति को गहरा धक्का पहुँचा। जिन सामन्तों के कृषक युद्ध में भाग लेने गये उनकी भूमि पर खेती नहीं हो सकी क्योंकि कृषकों के अभाव में खेती का काम बौन करता। इसलिये सामन्तों की आय में कमी हुई।

परिणाम स्वरूप राजाआ न ऐसे कमजोर सामन्तों की रही-सही शक्ति को भी कुचल दिया।

(3) किसानों का असंतोष — 14वीं शताब्दी के आरम्भ में सामन्तों के विरुद्ध किसानों ने असंतोष फैलाने लगा। इसका कारण यह था कि सामन्त किसानों का बहुत अधिक शोषण करते थे और उस धन में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए किसान सामन्तों से बहुत नाराज थे।

1338 ई. में यूरोप में एक भयंकर महामारी फैली जिससे यूरोप की आधी जनसंख्या समाप्त हो गई। इस महामारी का काली मृत्यु भी कहा जाता है। इसके कारण आधी जनसंख्या बचने से भूजमी और किसानों का अभाव हो गया। बचे हुए किसानों ने अधिक भूमि पर सामन्तों का काम करना स्वीकार कर लिया। अब सामन्तों ने किसानों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करना प्रारम्भ किया क्योंकि उनकी जमीन बिना वास्तु के बंजर हो जाती थी और उनकी आमदनी भी काफी घट गई थी। फिर भी किसानों में असंतोष बढ़ता ही गया।

1381 ई. में वाट टाईलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के हजारों कृषकों ने सामन्तों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया उसी समय फ्रांस में भी सामन्तों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। सामन्तों ने इन विद्रोहों का बुरी तरह से कुचल दिया किन्तु किसानों का असंतोष सामन्तों के विरुद्ध निरंतर बढ़ता रहा। इन विद्रोहों के कारण सामन्तों की शक्ति कमजोर हो गई। मैकनल बर्नस ने लिखा है कि किसानों के स्वतंत्र होना ही जो कि सामन्तवाद का मशीन का सबसे महत्वपूर्ण पुरजा था, इस प्रथा का जीवित रहना असंभव हो गया।¹

(4) नये व्यापारिक बंधन का उत्थान — धर्म युद्धों के कारण यूरोप में एक नये व्यापारिक बंधन का उत्थान हुआ, जिसके कारण यूरोप में व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की। यूरोप के व्यापारियों ने अब पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना प्रारम्भ किया। जस-जस व्यापार का विकास होता गया, वैसे-वैसे व्यापारिक बंधन भी घना बनता गया। व्यापारिक सामन्तों का अधिक महत्त्व देने से, इसीलिए सामन्त उनसे दूर रहने लगे थे। व्यापारिक बंधन के पास धन तथा बुद्धि का अभाव नहीं था किन्तु सामन्तों की तरह उनको ममाना तथा प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था इसीलिए यह बंधन सामन्तों में जलन लगा और उनका मन के तन्त्र मसालों का अधिक महत्त्व देने लगा।

यूरोप में व्यापार-वाणिज्य तथा उद्योग धंधों के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। जिससे फरफराते अनेक नये-नये शहरों का जन्म हुआ तथा अनेक नगर भी विकसित हुए। उदात्त नगरों के व्यापारियों ने गांवों के किसानों और कृषकों को ऊंची मजदूरी का प्रलोभन देकर बड़ा आकर बसाने के लिये प्रेरित किया। सामन्तों का यह पगल नहीं आया। जिससे फरफराते शहरों में मजदूरों का प्रारम्भ हो गया। ऐसी स्थिति

मे व्यापारी बग ने सामंतों के दमन के लिये राजाओं को हर प्रकार की सहायता प्रदान की ।

(5) चंच के प्रभाव में कभी — मध्य युग में चंच और सामंतों के बीच एक प्रकार का समझौता हो चुका था । जिसके अनुसार सामंत चंच की भूमि दान में देते थे और इसके बदले में चंच के धर्माधिकारियों सामंतों का पक्ष लेते थे । सामंतों की तरह चंच भी विशाल भूमि का स्वामी थी । चंच की भूमि की रक्षा करने के लिये सामंत धर्माधिकारियों को सहायता देते थे । जब मध्य युग के अंत में चंच का प्रभाव कम हो गया तो सामंतों की शक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक बात थी । इस प्रकार चंच के प्रभाव में कमी होने के साथ-साथ सामंतों की शक्ति भी क्षीण होने लगी ।

(6) राजाओं की शक्ति का विकास — राजाओं की शक्ति कमजोर हो जाने के कारण ही सामंतवाद का प्रादुर्भाव हुआ था । घम युद्धों में अनेक सामंत मारे जाने से राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई । अब राजाओं ने एक नई सेना का गठन किया और बारूद का प्रयोग करके सामंतों की शक्ति के केंद्र गढ़ों को ध्वस्त करना प्रारम्भ कर लिया । इसमें सामंतों की शक्ति क्षीण हो गई और राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई । ऐसी स्थिति में राजाओं ने सामंतों की शक्ति को आसानी से कुचल दिया । राजाओं और सामंतों के सघर्ष में सामंतों को कहीं से सहयोग नहीं मिला जबकि जनता और व्यापारियों ने इस सघर्ष में सम्राट की हर प्रकार की सहायता की । राजाओं ने विदेशी व्यापार को संरक्षण देकर अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली थी । इस प्रकार राजाओं की शक्ति का विकास ने सामंतों की शक्ति के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

(7) मुद्रा विनिमय प्रथा—मुद्रा विनिमय प्रथा भी सामंतों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई । मध्य युग में विशाल पैमाने पर मुद्रा का प्रचलन हुआ । जिसने जायिक व्यवस्था में नातिकारी परिवर्तन किये । अब मुद्रा का माध्यम से वस्तु विनिमय होने लगा । इसके पूर्व सामंतवर्गीय व्यवस्था में अनाज का माध्यम से वस्तु विनिमय होता था । सामंतों ने भोग विलास तथा अन्य आवश्यकताओं की वस्तुएं मुद्राएं देकर खरीदना प्रारम्भ कर दिया । ऐसी स्थिति में सामंतों ने कृषकों, दासों और कृषकों से भी अनाज के स्थान पर द्रव्य की मांग की । इससे सामंतों का प्रभाव कम हो गया । उस समय बहुत से दास धन देकर सामंतों से स्वतंत्रता प्राप्त करने लगे । मुद्रा के प्रचलन से राजाओं ने भी एक स्थायी सेना रखना प्रारम्भ कर दिया और उसे वेतन देने लगे । अब राजाओं का सामंतों की सैनिक सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही ।

(8) राष्ट्रीय भावना का प्रसार — राष्ट्रीय भावना का प्रसार सामंतों के पतन के लिये एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ । यूरोपियन देशों में राष्ट्रीय भावनाओं

के प्रसार में व्यापारी वर्ग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय प्रत्येक व्यापारी यह चाहता था कि उसके देश में दूसरे देश के व्यापारी न बसें। जब दूसरे देश के व्यापारी उनके देश में बसने लगे तो व्यापारियों में आपसी सघर्ष प्रारम्भ हो गया। इस सघर्ष में राजाओं ने अपने-अपने देश के व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए भाग लिया। यूरोप में व्यापारिक हितों की रक्षा के लिये 1381 ई. से लेकर 1443 ई. तक सौ वर्षीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में व्यापारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इससे यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ। यूरोप में राष्ट्रीय भावना के प्रसार के कारण जनता ने स्पानीयता के स्थान पर राष्ट्रीय हित को महत्व देना शुरू कर दिया और सामन्तों का विरोध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना के प्रसार के कारण सामन्तों की शक्ति दिनो-दिन क्षीण होती गई, और 15वीं शताब्दी के अन्त तक सामन्तों का पूर्ण रूप से पतन हो गया।

सामन्तवाद का मूल्यांकन—मध्य कालीन युग में यूरोपियन देशों में सामन्तवाद का प्रादुर्भाव व उसका विकास तथा पतन हुआ। उस समय सम्पूर्ण मानव समाज पर सामन्तवाद छाया हुआ था। इस सामन्ती प्रथा ने शासन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किये। इस समय कृषि तथा कला के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। सामन्तों के दरबारों में आश्रय प्राप्त कवियों ने शौर्य और प्रणय के क्षेत्र में कई प्रशंसनीय रचनाएँ रचीं। इसके अतिरिक्त सामन्तों ने समाज तथा स्त्रियों की दशा में भी सुधार किया। इतना सब कुछ होत हुए भी जनता सामन्तों के शासनकाल में सुखी नहीं थी।

जब सामन्त वर्ग का भुमलमाना का पराजित करन में सफलता नहीं मिली तो इससे जन साधारण पर उसका प्रभाव हो गया और उसकी प्रतिष्ठा घट गई। उस समय सामन्तों में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी और वे विलासप्रिय जीवन व्यतीत करते थे, इन्हीं स्त्रियों की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। सामन्तों के समय अच्छी विद्वानों की मुद्रा का चलन नहीं हान के कारण व्यापार का विकास नहीं हो सका। उनके शासनकाल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षित नहीं था और उन्होंने किसानों का बहुत अधिक शोषण किया। अतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सामन्तवादी शासन व्यवस्था मध्यकालीन युग के अनुकूल थी तथापि उसके अनेक भयकर दुष्परिणाम भी निकले।

प्रस्तावित सादर पुरतकें

- 1 प्लेट व जीन ड्रमंड—विश्व का इतिहास
- 2 बाच डब्ल्यू एन—हिस्ट्री आफ दी वर्ल्ड
- 3 मैरुन व बनम—वस्टन सिविलीजेशन
- 4 सेबाइन—ए हिस्ट्री आफ वर्ल्ड सिविलीजिंग
- 5 एलिस और जीन—मनार का इतिहास

3

पुनर्जागरण

पंद्रहवीं शताब्दी न केवल यूरोप के लिए बल्कि समस्त विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस शताब्दी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि इसने यूरोप के मध्य और आधुनिक काल के इतिहास को संयुक्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंद्रहवीं शताब्दी से पहले यूरोप के देशों की दशा बड़ी शांतिपूर्ण थी। रोमन साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। इसलिये यूरोप में एक केंद्रीय सरकार नहीं थी। जर्मनी और इटली में सामंतों का शासन था जिन पर राजा का नाम मात्र का नियंत्रण था। यद्यपि यूरोप के कई देशों में सामंतों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, फिर भी कृषक वर्ग का शोषण जारी था। उस समय एक सामंत का दूसरे सामंत के साथ युद्ध और राजा का सामंतों के साथ संघर्ष हाता रहता था। धर्म मनुष्यों के स्वतन्त्र चिंतन के मार्ग में बाधक बना हुआ था। शिक्षा के अभाव के कारण लोग अज्ञानी थे। उस समय के विद्वान लैटिन भाषा में पुस्तकें लिखते थे। जो जनसाधारण की समझ से परे थी। धार्मिक विचारों के कारण बला का पूरा रूप से विकास नहीं हो रहा था। साहित्य के क्षेत्र में उदात्तता छाड़ हुई थी। उस समय वैज्ञानिक खोज करने का मनलब था मानव समाज का अपना शत्रु बना देना। पंद्रहवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना ने मध्यकालीन मानव समाज के अविश्वासों को दूर कर दिया। उस समय शिक्षा का विकास हुआ स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन दिया गया एवं नई नई चीजें हुईं। इस महत्वपूर्ण घटना को इतिहासकार पुनर्जागरण के नाम से पुकारते हैं।

आधुनिक युग का उदय 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की। प्राफसर डेविस ने लिखा है कि पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में अनेक भौगोलिक खोजें हुयीं और धर्म मुद्दों पर अनेक प्रारम्भ हुआ। इसके अनिश्चित पुनर्जागरण भी इसी समय की देन है। इन खोजों के कारण यूरोप मध्य युग से आधुनिक युग की ओर अग्रसर हुआ। इस प्रकार यूरोप की सभ्यता और संस्कृति के विकास में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण स्थान है।

पुनजागरण का अर्थ—तेरहवीं शताब्दी व उत्तरार्द्ध से सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप ने मध्यता और सस्कृति के क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक प्रगति की, उसे पुनजागरण (रेनेसा) कहा जाता है। पुनजागरण शब्द के अनेक अर्थ हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से पुनजागरण शब्द का अर्थ नूतन जन्म अथवा पुनजन्म होता है, परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से मनुष्य की बौद्धिक चेतना और स्वतंत्र चिंतन शक्ति के पुनजन्म को पुनजागरण कहा जाता है।

रोमन साम्राज्य ने सांस्कृतिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ साथ यूरोपवासी प्राचीन यूनानी और रोमन पान को भूल गये। उन्होंने सस्कृति के विकास का और कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय मनुष्य स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर सकता था। सामंता की शिक्षा के प्रति रुचि नहीं होने के कारण विद्यालय बंद हो चुके थे। शिक्षा के विकास का भाग अवरुद्ध हो चुका था। उस समय धर्म तथा धर्म का मानव समाज पर इतना अधिक प्रभाव था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर सकते थे। धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई थीं अथवा धर्माधिकारी जो कुछ कहते थे, उसे जनता पूर्ण सत्य समझ कर स्वीकार कर लेती थी। जो व्यक्ति धर्माधिकारियों की बात का विरोध करता था, उसे मृत्यु दण्ड दिया जाता था। उस समय की जनता के पास इतना समझ नहीं था, कि वह प्राचीन प्रचलित परम्पराओं के विरुद्ध कुछ सोच सके। इस प्रकार प्राचीन काल में बौद्धिक दृष्टि से जागृत मानव भ्रम एक गहन निद्रा में सो गया। मध्य काल के उत्तरार्ध में यूरोपीय मानव ने स्वतंत्र रूप से चिंतन करना प्रारम्भ कर दिया और जन जीवन के सम्बन्ध में एक नई विचारधारा को अपनाया।

पुनजागरण का प्रभाव सम्पूर्ण मानव समाज पर पड़ा। इसके प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। अब विद्वानों ने पुस्तकें लैटिन भाषा के स्थान पर बोल्शान की भाषा में लिखना शुरू कर दिया, ताकि जन साधारण उसे पढ़ सके और आसानी से उसकी समझ में आ सके। धार्मिक बंधना से मुक्त होकर कलाकार स्वतंत्र रूप से कला के क्षेत्र में विकास करने लगे। साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं में सुन्दर शैली का प्रयोग कर प्राचीन साहित्य का नया रूप देने का प्रयास किया। कथानकों में कई नई खोजें करनी प्रारम्भ कर दीं। इस प्रकार प्राचीन सस्कृति को आनोक्ति कर उसे वर्तमान में मिला दिया। प्राचीन सस्कृति की प्रगति और परिवर्तन को ही पुनजागरण अथवा बौद्धिक चेतना कहते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने पुनजागरण की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ दी हैं।

प्रोफेसर डेविन ने कहा है कि पुनजागरण शब्द मानव स्वातंत्र्य प्रिय ग्राहमी विचारों को जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बन्नी बना दिये गए थे, स्थान करता है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि "पुनजागरण का अर्थ विद्या का पुनजन्म तथा कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय देशों की भाषा का

विकास है।¹ प्रोफेसर स्न ने लिखा है कि बौद्धिक परिवर्तन ही पुनजागरण है। इसमें भूतकाल के प्रति रुचि और वतमान को समझने की बौद्धिक चतना दिखाई देती है। सवाइन ने लिखा है कि 'पुनजागरण एक समुक्त अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग मध्यकाल के अन्त में और आधुनिक युग के आरम्भ के समय दृष्टिगोचर सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया गया था।² एलिम और जोन ने लिखा है कि पुनजागरण ने मनुष्य के भित्तिज का विस्तार किया। यूरोप में पुनजागरण युग मध्य युग और आधुनिक युग के बीच में पुल की तरह है। पुनजागरणकालीन लोगाने मध्ययुगीन यूरोप की संस्कृति के आधार पर एक नई संस्कृति का विकास किया जिसमें उन्होंने यूनानी और रोमन सभ्यताओं से प्राप्त प्रणयों और विचारों का योगदान लिया।³ प्लट जीन व डूमड ने लिखा है कि 'पुनजागरण ने मनुष्य में, उसकी उपलब्धियों में और उसके सस्यार में रुचि को पुन जीवित किया।⁴ संक्षेप में पुनजागरण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि मध्य युग के अन्त में और आधुनिक युग के आरम्भ के समय अनेक सांस्कृतिक या बौद्धिक परिवर्तन हुए थे। इस समय लोगाने प्राचीन संस्कृति को आलोकित कर उस वतमान में मिला दिया। इस प्रगति या परिवर्तन को पुनजागरण कहा जाता है।

पुनजागरण की विशेषताएँ—पुनजागरण का प्रमुख विशेषताएँ निम्न लिखित हैं —

1 स्वतंत्र चिन्तन—पुनजागरण ने स्वतंत्र चिन्तन की विचार धारा का विकास किया। मध्यकालीन युग में धार्मिक प्रतिबंधों से मनुष्य स्वतंत्र रूप से चिन्तन नहीं कर सकता था, परन्तु पुनजागरण के कारण मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से चिन्तन करना आरम्भ कर दिया। अब वह धर्म में व्याप्त बुराईयों पर विचार करने लगा और परम्परागत विचारधाराओं को स्वतंत्र रूप से आलोचना की कसौटी पर कसने लगा।

2 व्यक्तित्व का विकास—पुनजागरण की दूसरी विशेषता व्यक्तित्व का विकास करना था। पुनजागरण के कारण मनुष्य ने अंध विश्वास, प्राचीन रूढ़ियों तथा चर्च के बंधना से छुटकारा प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात् उसने स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास किया।

3 मानववादी विचारधारा—पुनजागरण की तीसरी विशेषता मानववादी विचारधारा का प्रसार करना था। मध्य युग में चर्च इस बात का प्रचार कर रही

1—नेहरू, जवाहरलाल—विश्व इतिहास की झलक

2—सेवाइन—ए हिस्ट्री आफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, पृ० 353

3—एलिम और जोन—सस्यार का इतिहास पृष्ठ 238

4—प्लट जीन और डूमड—विश्व का इतिहास पृष्ठ 248

था कि दुनिया में जन्म लेना भयंकर पाप है। मनुष्य को चाहिये कि इस जीवन का आनन्द नहीं उठाये और मरण्या तथा निवृत्ति मार्ग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करे। पुनजागरण ने चर्च की इस विचारधारा का विरोध किया वहाँ कि और मनुष्य को इस जीवन का पूरा आनन्द उठाना चाहिये। मनुष्य को अपना जीवन साधक बनाने का प्रयास करना चाहिये। धर्म और मुक्ति के स्थान पर मनुष्य को सम्पूर्ण मानव समाज का उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार पुनजागरण ने पारलौकिक कल्पना के स्थान पर मनुष्य का ध्यान यथावत्वादी समस्याओं की ओर आकर्षित किया।

4 देशी भाषाओं का विकास—पुनजागरण ने देशी भाषाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुनजागरण से पूर्व विद्वान लटिन भाषा में पुस्तकें लिखते थे, जिसकी जनसाधारण ने तो पढ़ सकता था और न ही समझ सकता था, लेकिन पुनजागरण के कारण विद्वान लोगों ने बोल चाल की भाषा में पुस्तकें लिखीं, ताकि जनसाधारण उन्हें पढ़ सके तथा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस प्रकार पुनजागरण के कारण बोल चाल की भाषा की गरिमा एवं सम्मान में वृद्धि हुई।

5 चित्रकला का विकास—पुनजागरण ने चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चित्रकारों ने अपने चित्रों में कल्पना चित्र के स्थान पर यथावत्वादी चित्रण करना प्रारम्भ कर दिया। पहले चित्र कल्पना प्रधान होते थे। अब चित्रा में वास्तविक सौन्दर्य का चित्रण होने लगा।

6 वज्ञानिक विचारधारा के क्षेत्र में विकास—पुनजागरण के कारण वैज्ञानिक विचारधाराओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसका कारण मनुष्य ने प्रत्यक्ष विषय का निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार मध्य युग के अंध विश्वासों व रूढ़ियों का उसने मानने से इन्कार कर दिया।

पुनजागरण के कारण—पुनजागरण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसने लिये एक लम्बे समय से शांतावरण तैयार हो रहा था। जिससे यूरोपीय समाज में अनेक बौद्धिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के पराकाष्ठा पर पहुँचने में दो तीन शताब्दियों का समय लगा। महाइन ने लिखा है कि—“जहाँ अनेक योग्य नेताओं का मार्ग-दर्शन होने लगा था, वहाँ वज्ञानिक भावना, एक धार्मिक जोश, कला की एक नई शैली और एक नवीन प्रकार का साहित्य, पुनजागरण की वास्तविक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना है।”¹

पुनजागरण के कारण—पुनजागरण व प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1 घम युद्ध—घम युद्ध ने पुनजागरण का वातावरण तयार कर दिया। यूरोप की अधिकांश जनता ईसाई धर्म की अनुयायी थी। ईसाईया का धार्मिक तीर्थ स्थान जेरूसलम था जिसकी जीवन में एक बार यात्रा करना प्रत्येक ईसाई अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था। जब मुसलमानों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया एवं उन्होंने ईसाईयों की जेरूसलम की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। तुर्क लोग धार्मिक रूप से असहिष्णु थे इसलिये जो भी ईसाई जेरूसलम की यात्रा पर आता उसे या तो ब लूट लेते या जान से मार देते थे। इतना ही नहीं यात्रा के समय ईसाईयों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे। ऐसी परिस्थिति में यूरोपीय ईसाई समाज ने अपने पवित्र तीर्थस्थान जेरूसलम को तुर्कों व आधिपत्य से मुक्त कराने के लिये उनके साथ जो युद्ध लड़े थे इतिहास में घम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे।

इन घम युद्धों के कारण यूरोपियन जनता का पूर्वी देशों की जनता से सम्पर्क स्थापित हुआ। इससे पूव यूरोप अज्ञान एवं अंध विश्वासों की गहन निद्रा में सोया हुआ था जबकि पूर्वी देशों ने यूनान तथा भारत की सभ्यताओं के सम्पर्क में आने के कारण एक नई सभ्यता का विकास कर लिया था। जब यूरोपवासी पूर्वी देशों के सम्पर्क में आये तो उन्होंने मुस्लिम देशों की नवीन सभ्यता व अनेक तत्व ग्रहण किये। यूरोपियन देशों की जनता ने पूर्वी देशों से तत्काल शक्ति प्रयोग पद्धति तथा विज्ञान व क्षेत्र में अनेक बातें सीखीं। मुस्लिम देशों के गान-पान रहन सहन एवं सफाई ने भी यूरोपवासियों को बहुत अधिक प्रभावित किया।

घम युद्धों के कारण यूरोप व पूर्वी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए और निरंतर व्यापार बढ़ना गया। इस व्यापार के कारण यूरोपवासियों को नये मार्गों, नये देशों और सामुद्रिक मार्गों का पता चला। इससे उनमें भौगोलिक खोज की प्रवृत्ति जाग्रत हुई। जिसके परिणामस्वरूप अनेक यूरोपियनों ने भौगोलिक खोजों के लिए पूर्वी देशों की यात्रायें की और अपनी यात्राओं का दिलचस्प वर्णन लिखा। इन यात्राओं के वर्णन को पढ़ने के पश्चात् यूरोपवासियों को सकीण विचारों से मुक्ति मिली और उनकी चित्त शक्ति का विकास हुआ।

पूर्वी देशों में रहने वाले यूरोपियनों ने मुस्लिम साहित्य का अध्ययन किया जिसका उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। घम युद्धों में पोप की सम्पूर्ण शुभ कामनाओं और आशीर्वाद व बावजूद भी जब ईसाईयों को युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हुई तो पोप की प्रतिष्ठा को जबरन धक्का पहुँचा और उसकी शक्ति क्षीण हो गयी। अब घम के बन्धन कमजोर होने लगे। यूरोपियनों ने पूर्वी देशों व सम्पर्क में आने के पश्चात् अपने जन जीवन में भी उसी के अनुकूल परिवर्तन करने शुरू कर दिये। इस प्रकार घम युद्धों ने पुनजागरण का वातावरण तयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

2 व्यापार में वृद्धि—पुनजागरण के कारण यूरोपियन देशों के व्यापार में काफी वृद्धि हुई। घम-युद्धों से लौटने वाले ईसाई अपने साथ पूर्वी देशों से गम ममाने मखमन, कानोन व कशीके की वनी हुई वहुत सी वस्तुयें अपने साथ लेकर आते थे। यूरोपवासी नीबू, गजूर और कई प्रकार के फल पूर्वी देशों से मगाते थे।

घम युद्धों के समय यूरोपियन देशों का पूर्वी देशों से व्यापारिक सम्पर्क स्थापित हो चुका था। घम-युद्ध से यूरोप के व्यापारिक क्षेत्रों का बहुत हानि पहुँची। द्वितीय घम युद्ध के बाद यूरोपियनों ने व्यापार में काफी वृद्धि की क्योंकि इन समय अनेक यूरोपियन व्यापारी जेरुसलम और एशिया माइनर के पश्चिमी किनारा पर बस चुके थे। उस समय वेनिस, मिसानलूका और फ्लोरेंस के नगर विदेशी व्यापार के प्रसिद्ध बन्दर बन चुके थे। यूरोपवासियों का व्यापार के माध्यम से विदेशों से सम्पर्क हुआ। इसके उनके मान में वृद्धि हुई। विदेशों से उन्होंने कई तत्व ग्रहण किये और उसका प्रचार अपने देश में किया। व्यापारिक प्रगति के कारण अनेक नगरों का जन्म तथा विकास सम्भव हो सका। व्यापार के विकास के कारण घन में वृद्धि हुई। जिससे नये उद्योगों का विकास सम्भव हुआ।

यूरोपियन व्यापारियों ने बगदाद काहिरा और कोरडोवा से पुस्तकें खरीदीं और उनको यूरोप लेकर आये। इन पुस्तकों को जब विद्वानों ने पढ़ा तो उससे बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी वर्ग व्याज पर अपना उधार लेकर व्यापार करता था। चर्च इस बात का विरोधी था। इसलिए व्यापारी चर्च के प्रति उन्मासीन हो गये और उन्होंने चर्च के सुधारों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस प्रकार विदेशी सम्पर्क के कारण यूरोपियनों का विवेक जाग्रत हुआ और व्यापार में वृद्धि के साथ साथ पुनजागरण का वातावरण भी तयार होता गया।

3 अरब और मंगोल सम्पर्क—अरबों और मंगोलों ने भी पूर्वी देशों के संचित ज्ञान का यूरोपवासियों तक पहुँचाया। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अरबों के लोग बस गये थे। ये लोग स्वतन्त्र रूप से चिन्तन करते थे और प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों का अध्ययन करते थे। इस प्रकार अरब विद्वानों ने यूरोपीय विद्वानों का ध्यान दार्शनिक क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। इससे यूरोपीय विद्वानों में उत्तम प्रभावित हुए। परिणामस्वरूप यूरोपियन विद्वानों ने पेगिस ऑक्सफोर्ड और कानोन के विश्वविद्यालयों में बौद्धिक आन्दोलन को प्रारम्भ किया। इसमें यूरोपवासियों का तब शास्त्र के प्रति विश्वास जाग्रत हुआ।

13 वीं शताब्दी के मध्य में मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने इस बात का प्रयास किया कि यूरोप और एशिया के देशों का एक सूत्र में बाँध दिया जाय। कुबलाई खान ने अपने दरबार में पौरों के दूत पेरिस, इटली और एशियाई देशों के विद्वानों तथा साहित्यकारों को आश्रय दे रखा था। प्रसिद्ध इटालियन यात्री मार्कोपोला भी कुछ समय के लिये उसने

दरबार में रहा था। उसने अपनी यात्राओं का वर्णन किया। जब उस वर्णन को जनता ने पढ़ा तो उनके मन में सभ्यता के विकास की भावना जाग्रत हुई। प्रसिद्ध जिनेवा यात्री फिस्टोफर कोलम्बस भी कुबलाई खा के दरबार में रहा था। वह कुबलाई खा से प्रभावित होकर समुद्री यात्राओं के लिये रवाना हुआ। कुबलाई खा के दरबार में रह कर अनेक यूरोपियनों ने पूर्वी ज्ञान विज्ञान को सीखा। अरबों और मंगोलों ने पूर्वी दशा के आविष्कार जैसे छापाखाना, मुतुबनुमा और बारूद आदि को यूरोपियन देशों तक पहुँचाया। इन आविष्कारों के कारण यूरोप निरंतर विकास करता रहा।

4 वस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार—पूर्वी रोमन साम्राज्य जो इस समय बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। उसकी राजधानी वस्तुनतुनिया थी, जिस पर 1453 ई० में उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। मध्य युग में वस्तुनतुनिया ज्ञान, दशम एवं कला का एक प्रसिद्ध केन्द्र था, परन्तु असम्य तुर्कों के लिये इसका कोई महत्व नहीं था, इसलिये बाइजेंटाइन के ईसाई विद्वान इटली के बड़े-बड़े नगरों में जाकर रहने लगे। वहाँ जाकर उन्होंने रोम के यूनान के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और प्राचीन ज्ञान का रोम के अनेक नगरों में प्रचार किया। रोम के माध्यम से ही यूरोप में प्राचीन ज्ञान का प्रकाश फलने लगा। इस प्रकार पुनर्जागरण सब प्रथम इटली में प्रारम्भ हुआ और धीरे-धीरे इसका प्रभाव समस्त यूरोप पर दिखाई देने लगा।

वस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय का दूसरा परिणाम यह निकला कि यूरोप में पूर्वी दशा को जानने वाला स्थल मार्ग पर अब उनका अधिकार हो चुका था। तुर्क लोग इस रास्ते से गुजरने वाले यूरोपियन व्यापारियों को लूट लेते थे। परिणाम स्वरूप यूरोपियन दशा का व्यापार पूर्वी दशा के साथ ठप्प हो गया, इसलिए यूरोपवासियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करना शुरु किया। इसी प्रयास के कारण भारत और अमेरिका आदि देशों के जल मार्ग की खोज सम्भव हो सकी। उपर्युक्त कारण से पुनर्जागरण सम्भव हो सका।

(5) सामन्तवाद का पतन—मध्यकाल में यूरोपीय राजनीति पर सामन्तों का प्रभाव था। इस समय राज्य की वास्तविक शक्ति सामन्तों के हाथ में केन्द्रित थी, और सम्राट नाम मात्र के शासक थे। सामन्त जनता से कर वसूल करते थे। इतना ही नहीं वे जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। सामन्तों की अत्याचारपूर्ण नीति एवं अमानुषिक व्यवहार के कारण जनता के लिए कला और साहित्य के विकास के बारे में सोचना असम्भव था। उस समय की जनता सामन्तों से भयभीत थी। जनता को इतना अधिक कर सामन्तों को देने पड़ते थे कि वह मुँह से शाम तक कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी अपना जीवन निर्वाह बड़ी मुश्किल से कर पाती थी।

मध्यकाल के अंत तक सामंती की शक्ति क्षीण होन लगी। सामंती का पतन हो जान के कारण जनता ने चन की सांस ली। अब उनके मन से सामंतों का भय निकल गया। इसलिए अब जनता स्वतंत्र रूप से चिंतन एवं मनन करने लगी। जिसके फलस्वरूप पुनजागरण का वातावरण तयार हुआ।

(6) नगरों की वृद्धि—सामन्तवाद के कारण यूरोप में अनेक बड़े-बड़े नगरों की स्थापना हुई। इन नगरों के कारण व्यापार के क्षेत्र में प्रगति हुई। इससे व्यापारी बग धनवान बनता चला गया। इसलिए यह बग जीवन की विलासिता की वस्तुएं खरीदना चाहता था। अतः इस बग ने कठोर नियमों का उल्लंघन कर स्वतंत्र रूप में विचार करना प्रारंभ कर दिया।

इसके अतिरिक्त सामंती के नेतृत्व में जिन नगरों का विकास हुआ था, उनका स्वरूप यूनान के नगर राज्या के जसा बन चुका था। उन नगरों में शासन की वास्तविक शक्ति वहां के सामंतों के हाथों में निहित थी। इन नगरों की सामंतीक विचार धारणों भी स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही थी। ये नगर एक दूसरे से पूरा रूप से स्वतंत्र थे। इटली का फ्लोरेंस नगर सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विकास कर रहा था। इन प्रकार नगरों के विकास के कारण पुनजागरण की स्थिति उत्पन्न हुई।

(7) कागज एवं छापेखाने का आविष्कार—कागज एवं छापेखाने के आविष्कार ने पुनजागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरबों ने कागज और छापेखाने का प्रयोग चीन से सीखा। इसके पश्चात् यूरोपवासी जब अरबों के सम्पर्क में आए तो उन्होंने उनको भी कागज और छापेखाने का प्रयोग करना सिखा दिया। यूरोप में 1439 ई० में लेकर 1450 ई० तक छापेखाने का विकास होता रहा। कुछ ही समय में यूरोप के बड़े-बड़े नगरों में 200 से अधिक छापेखानों की स्थापना हो गई। प्रेस जान गुटन बग ने सब प्रथम मित्र में छापेखाने की स्थापना की। इसके पश्चात् छापेखाने का प्रचार निरंतर बढ़ता रहा। सब प्रथम पुनजागरण इटली में प्रारंभ हुआ और उसने पुनजागरण के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

शुरू में छापाखाने में धार्मिक पुस्तकें बाइबल को ही छापना प्रारंभ किया। उससे पश्चात् कहानियाँ भी छपने लगीं, लेकिन अभी तक नये नताशा के लेखों को प्रभावित नहीं किया जाता था। जब छापाखाने ने स्थानीय भाषा में बाइबल, गिरजा घर सम्बंधी साहित्य और प्राचीन कहानियाँ का छापना शुरू किया तो इससे साहित्य का विकास हुआ। इससे जनसाधारण की साहित्य के प्रति रुचि बढ़ने लगी। छापाखाने के कारण पुस्तकें सस्ती और अधिक संख्या में मिलने लगीं। बाइबल हर ईसाई के घर में पहुंच गई। छापाखाने के कारण जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ। पुस्तकें प्रसार में लोगों के विचारों में सजी के साथ परिवर्तन लाने

परिणामस्वरूप यूरोपवासियों की ध्व्ययन के प्रति रुचि जाग्रति हुई। अब उन्होंने स्वतन्त्र रूप से चिन्तन करना प्रारम्भ कर दिया, जिसके कारण उनकी बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। वेन फिंगर ने लिखा है कि 'छापेखाने के आविष्कार ने मध्यकाल के भारत को दूर कर दिया तथा रहस्यमय चिन्तन के स्थान पर बौद्धिक मनन को स्थान दिया तथा व्यक्तिवाद की भावना स्थापित की। प्रत्यय मन्त्र यह सोचने लगा कि उसका विचार भी कुछ महत्व के हैं।

(8) भौगोलिक अनुसंधान—भौगोलिक खोजों ने यूरोप के पुनुरुत्थान और विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। व्यापार की वृद्धि के लिए यूरोपियन देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई। भौगोलिक खोजों के कारण व्यापार के क्षेत्र का विस्तार होता गया। यूरोप के व्यापारी भूमध्यसागरीय क्षेत्र से बाहर निकल कर अरब महासागरों में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने लगे। उस समय मार्कोपोलो, कोलम्बस और वास्को डगामा जैसे साहसी यात्रियों ने भारत, चीन और अरब आदि देशों के जल मार्गों की खोज की।

वस्तुतः तुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाने से नये समुद्री मार्ग की खोज के प्रयत्न किए गये। पुतगाली राजकुमार हेनरी नाविक ने अफ्रीका के समुद्री मार्ग की खोज की। 1486 ई० में स्पान डाइज ने अफ्रीका के दक्षिणी भाग की खोज की, जिसे आगे चलकर कैप आफ गुड होप के नाम से सम्बोधित किया गया। सन 1497 ई० में ऐमरिगो नामक नाविक ने अमेरिका की खोज की और उसका नाम पर इस देश का नाम अमेरिका रखा गया।

मैगलन नामक नाविक ने प्रशांत महासागर में फिलीपाइन द्वीप समूह की खोज की। जब यूरोपीयन दानी मैक्सिको और पीरू पहुँचे तो वहाँ के सभ्य लोग से वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। निकोनीरोलो ने अपनी एशियाई यात्रा का विवरण लिखा। उसके पुत्र मार्कोनीरो ने भी अपनी यात्रा का विवरण लिखा। इस यात्रा विवरणों को पढ़कर यूरोप के अनेक साहसी नाविकों ने विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँचने के लिए जल मार्ग खोज निकाले। अब यूरोप निवासी व्यापार एवं धर्म के प्रचार के लिए विश्व के विभिन्न भागों में पहुँचने लगे। इससे वे दूसरे देशों की सभ्यता से सम्पर्क में आए। इसका उनके चिन्तन और विचारधारा पर काफी प्रभाव पड़ा। अब उन्होंने धर्माधिकारियों और सामंता के अत्याचारों से मुक्त होना का प्रयास किया। परिणामस्वरूप पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई। डट्यू० एन० बीच ने लिखा है कि 'पुराने मूर नाविक धर्म है जिसे होने पुतगाल को प्रेरणा दी। पुतगाल अथवा किसी राष्ट्र से अधिक अच्छी स्थिति में था, जो समुद्री अभियान उठाकर भाग खोज सकता था।'¹

(9) विज्ञान का विकास—मध्यकाल के उत्तरार्द्ध से विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति प्रारम्भ हुई। वनानिज खोजों के कारण अब जहाजों पर पाल लगा दिए गये, जिससे वे तीव्र गति से चलने लगे। यूरोपियना ने चीन के सम्पर्क में आने के पश्चात् उनसे कुतुबनुमा का प्रयोग करना सीखा। कुतुबनुमा की सहायता से ही मार्कोपोलो, कोलम्बस और वास्कोडिगामा आदि साहसी नाविका ने समुद्र के जल मार्गों की खोज की। इसी प्रकार बारूत के आविष्कार ने सामन्तों की शक्ति को समाप्त करने में सहायता की। अब सामन्तों के स्थान पर राजाओं के साम्राज्य स्थापित होने लगे। मशीनों के प्रयोग से आगे चलकर औद्योगिक क्रांति हुई।

इस समय प्राचीन मान्यताओं की संरचना को परखने के लिये विभिन्न प्रयोग होने लगे। कापरनिस बूतों और लिलियो आदि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने ज्योतिष एवं खगोल के क्षेत्र में अनेक नई खोज कर प्राचीन मान्यताओं का खण्डन किया। शरीर विज्ञान के क्षेत्र में डा० हार्वे ल्यू पाश्चर और डॉ० जेनर ने अनेक नये प्रयोग किये और प्राचीन मान्यताओं का खण्डन किया। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण प्राचीन रूढ़ियाँ और अंधविश्वासों की समाप्ति हुई। और मनुष्य को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैज्ञानिक विचारधारा के कारण अब मनुष्यों के विचारों में परिवर्तन आया। अब मनुष्य किसी बात को सुनने के पश्चात् उस पर विश्वास नहीं करता था। बल्कि उस पर प्रयोग करता था और प्रयोग में सही पाये जाने पर ही उस पर विश्वास करता था। इससे मनुष्य की मानसिक स्थिति में परिवर्तन आया और वह बौद्धिक क्षेत्र में आगे बढ़ा। इस प्रकार इन वैज्ञानिक खोजों पर पुनजागरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।

10 शिक्षा का विकास—मध्य युग के अंत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। उस समय यूरोप के बड़े बड़े नगरों में विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके थे। इन पर धार्मिक नियंत्रण नहीं था, इस लिये विद्यार्थी इनमें किसी भी विषय का अध्ययन कर सकता था। शिक्षा के विकास के कारण मनुष्य प्राचीन ज्ञान की तर्कों की बमौटी पर कसने लगा। जिसके फलस्वरूप अंधविश्वासों की समाप्ति हुई और अब मनुष्य प्रत्येक विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने लगा।

11 यूरोपीय दशन—मध्ययुग का यूरोपीय दशन अस्तु का तक शास्त्र और आगस्टाइन के तत्व ज्ञान पर आधारित था। इसमें धार्मिक विश्वास तथा तर्क ज्ञान का सम्बन्ध था। मध्य युग में यूरोपीय दशन को स्वातंत्र्य कहा जाता था। तरहवी शताब्दी में इस दार्शनिक विचारधारा का बहुत अधिक प्रचार हुआ। देकन नामक दार्शनिक भी इसी समय पैदा हुआ। उसने वैज्ञानिक प्रयोगों पर जोर दिया इस वैज्ञानिक चिन्तन ने पुनजागरण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1453 ई० की तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कन्स्तान्टिनियल

पर अधिकार कर लिया जिसके कारण वाइजेन्टाइन साम्राज्य की सदव के निये समाप्ति हो गई परन्तु पश्चिमी यूरोप में ज्ञान का प्रसार हुआ। अब तुर्कों ने बल्कान प्रदेश में लूटमार करना प्रारम्भ किया तो अनेक यूनानी विद्वान अपना प्राचीन साहित्य लेकर पश्चिमी यूरोप में भागकर चले आये। जब यूरोप में बौद्धिक वग न यूनान के साहित्य को पढा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उस समय का यूरोपीय दशन अरस्तु का तक शास्त्र और आगस्टाइन के तत्व ज्ञान पर आधारित था। इस दशन ने यूरोप में खलवली मचा दी। इससे बौद्धिक वग बहुत अधिक प्रभावित हुआ। आगे चलकर तेरहवीं शताब्दी में वेकन ने अरस्तु के विचारों का विरोध करते हुए वैज्ञानिक प्रयोगों पर जोर दिया। वह मशीन से चलने वाली टैन बस और हवाई जहाज की कल्पना करता था इस प्रकार इन वैज्ञानिक प्रयोगों ने पुनजागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पुनजागरण का प्रारम्भ इटली में ही क्यों हुआ?—उपयुक्त कारणों से यूरोप में पुनजागरण सम्भव हो सका। अब प्रश्न यह उठता है कि पुनजागरण का प्रारम्भ इटली में ही क्यों हुआ? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि उस समय इटली (इतालवी) के नगर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने समृद्ध हो गये थे, इसलिये वे सस्कृति का प्रोत्साहित करने के योग्य थे। इतालवी नगरों के समृद्ध व्यापारियों के पास अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिये अवकाश और धन सम्पत्ति दोनों ही तत्व मौजूद थे। वे लोग सुन्दर त्रयीदार कपड़े पहनते थे। उनके घरों में सभी प्रकार की सुख सुविधा और सौन्दर्य प्रसाधन का सामान मौजूद था। ये धनी लोग रंग रेलिया मनाते थे और बड़े-बड़े प्रीति भोजों का आयोजन करते थे। उन्होंने अपने रहने के लिये विशाल भव्य भवनों का निर्माण करवाया और उन्हें चित्र तथा मूर्तियों से सजाने के लिये कलाकारों को प्रोत्साहित किया। इससे इतालवी नगरों के स्वरूप में परिवर्तन होना लगा।

पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी और घम युद्धों से वापस लौटने वाले सैनिक इटली के नगरों में रुकते थे। ये लोग तुर्कों की उच्च सम्पत्ता के बारे में इटली के लोगों को बताते थे। जब तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो उस समय अनेक यूनानी विद्वान और कलाकार इतालवी के नगरों में भाग कर आ गये। इसलिये यूनानी साहित्य का अध्ययन एवं चिन्तन सब प्रथम इटली के नगरों में प्रारम्भ हुआ।

नवम युग में जब अधिकांश यूरोपीय नगर अधिकार में डूबे हुये थे तब इटली के नगरों में ज्ञान का प्रकाश फल रहा था। इटली के नगर एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते थे और वे धीरे धीरे समृद्धिशाली होते गये। उनमें से कुछ नगरों ने पवित्र रोम साम्राज्य की अधीनता से स्वतंत्रता प्राप्त करली। इटली के ये नगर यूनान के नगर राज्यों जस बन गये। इन स्वतंत्र नगरों के धनी

लोगा ने कलाकारों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन दिया। यही कारण था कि रेनेसा काल के कई प्रमुख व्यक्ति दार्शनिक 'पेट्राक', 'डवि दांते कथाकार बीफेकि' तथा, चित्रकार लियोनार्डो, विंची माइकल, एजिलो और राफिन आदि इतालवी नगरों में ही पैदा हुये।

इतालवी के नगरों में सबसे प्रथम पुनजागरण होने के कुछ अर्थ कारण भी उत्तरदायी थे। प्राचीन रोमन साम्राज्य सभ्यता एवं सस्कृति का केन्द्र था। इटली के नगरों को पुनजागरण के लिये रोमन सस्कृति से प्रेरणा मिलती रही, इसलिये इतालवी के नगरों में पुनजागरण सबसे प्रथम प्रारम्भ हुआ। रोम ईसाई धर्म का मुख्य केन्द्र था। कुछ गोपा ने पुनजागरण की भावना से प्रेरित होकर अनेक विद्वानों और कलाकारों को रोम में आश्रय दिया। जिन्होंने यूनानी पांडुलेखों का लैटिन भाषा में अनुवाद किया। पोप निकोलस पंचम ने सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया और वैटिकन पुस्तकालय की स्थापना की। पोप निकोलस पंचम के इन कार्यों का इटली के अन्य नगरों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उस समय वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान के नगरों में बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

इटली की भौगोलिक स्थिति के कारण भी वहाँ सबसे पहले पुनजागरण का काम प्रारम्भ हुआ। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली का यूनानी साम्राज्य और सस्कृति से कई शताब्दियों से सम्पर्क चला आ रहा था। पश्चिम और पूर्व के देश, भूमध्य सागर के जल मार्ग से व्यापार करते थे। उस समय भूमध्य सागर के जल मार्ग पर इटली का अधिकार था। उपरोक्त सभी कारणों से इतालवी के नगरों में पुनजागरण सबसे पहले प्रारम्भ हुआ।

मानववाद का विकास—बौद्धिक चेतना को पैदा करने में मानववादी विचारधारा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस विचारधारा का प्रवर्तक 'पेट्राक' था जो इटली के फ्लोरेंस नगर का रहने वाला था। मध्य युग में प्रत्येक मनुष्य प्राचीन विद्वानों को जान व तक की बसीटी पर बसने के पश्चात् सही होने पर उसे स्वीकार करता था। विद्वानों ने मनुष्य की इस स्वतंत्र विचारधारा की प्रवृत्ति को मानववाद के नाम से सम्बोधित किया है। जिन विद्वानों ने यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन किया, वे मानववादी के नाम से प्रसिद्ध हुये।

मानववाद को अंग्रेजी में ह्यूमैनिज्म (Humanism) कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ह्यूमैनिटीज से हुई है। जिसका अर्थ है उच्च ज्ञान अर्थात् मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान निकालना। इस विचारधारा के विद्वानों का मुख्य काम मनुष्य के महत्त्व को स्थापित करते हुए उसके जीवन को सुखी एवं उन्नत बनाना था।

मध्य युग में मानव जीवन का कोई विशेष महत्त्व नहीं था। उस समय मानव जीवन पर धर्म का प्रभाव छाया हुआ था। धर्म की ओट में विश्वास

और ऋद्धिया का सबस्व धायम था। उस समय मनुष्य का मुख्य उद्देश्य परतोक को सुधारना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करन के लिए सभी मनुष्य हर सम्भव प्रयास करते थे। उनका सम्पूर्ण धन, श्रम और समय धम प्रथा व चिन्तन करने में व्यतीत होता था। उस समय कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र रूप से चिन्तन नहीं कर सकता था। यदि कोई मनुष्य परम्परागत मान्यताओं का उल्लंघन करता था, उन्हें असत्य सिद्ध करने का प्रयास करता तो उस धम द्रोही घोषित कर कठोर से कठोर सजा दी जाती थी।

मानववाद के विकास के कारण वातावरण में नातिकारी परिवर्तन हुआ। इस विचारधारा के विद्वान धम के स्थान पर मनुष्य का अधिा महत्व देते थे। परिणाम स्वरूप देवी देवताओं की स्तुतिया तथा इहलोक सम्बन्धी उपदेशों के स्थान पर मानव की विभिन्न समस्याओं पर रचनायें रची जाने लगी। मानववादियों का कहना था कि मनुष्य को चाहिये कि वह परलोक की चिन्ता छोड़कर इस लोक को ही स्वर्ग बनाने का प्रयास करे। देवी देवताओं के स्थान पर रोगियों गरीबों और अनाथों की सेवा करे और बिना किसी भेद भाव व प्रत्येक मनुष्य को उन्नति के लिये अवसर दे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धम की स्वतन्त्र रूप से उपासना करे और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बना रहे। पठन पाठन का विषय भी धम के स्थान पर मनुष्य तथा ससार होना चाहिये।

मानववादी विचारधारा का मुख्य प्रवक्त

मानवावादी विचारधारा का मुख्य प्रवक्त पेट्राक था। जिसका जन्म इटली के फ्लारेन्स नामक नगर में 1304 ई. में हुआ था। उसने अपनी अधिकांश कविताएँ धम निरपेक्षता पर लिखी और परलोक के सुख के स्थान पर इस लोक को सुख प्रवक्त व्यतीत करने पर अधिक जोर दिया। पेट्राक ने प्राचीन यूनानी तथा रोमन ग्रन्थों का अध्ययन करके के लिये जनसाधारण का प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं उसने ग्रन्थों की सुरक्षा के लिये पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर दिया।

इस विचारधारा के लागू का मानना था कि हम प्राचीन ज्ञान का तर्क के आधार पर परीक्षण करना चाहिये और यदि बात सत्य हो तो स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार की विचारधारा के प्रसार के कारण यूरोप का प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रचलित बातों को तर्क की कमौगी पर कसने लगा। इससे यह पता चला कि समाज में अनेक निराधार बातें भी प्रचलित हैं। इस विचारधारा के प्रसार से दो लाभ हुए। पहला तो यह कि हर व्यक्ति तार्किक हो गया। दूसरा यह कि समाज में प्रचलित अध विश्वास समाप्त हो गये। अब व्यक्ति किसी भी बात को तभी स्वीकार करता था जबकि वह तर्क की कसौटी पर लरी उतरती थी। बाद के मानववादियों ने यूरोप के सभी भागों में इस विचारधारा का प्रसार किया।

पुनर्जागरण के विकास का क्षेत्र

पुनर्जागरण विश्व इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है।

पुनजागरण के साथ ही विश्व ने नवगुण में प्रवेश किया। मध्यकाल में मनुष्य प्राचीन रुढ़िया और अधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। अब मनुष्य न जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चिन्तन करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय मानव ने प्राचीन विचारों को तर्क की कसौटी पर कसा। उसमें जो बातें तर्क की कसौटी पर सही साबित हुईं, वे स्वीकार कर लीं और जो गलत सिद्ध हुईं उस तिलाजलि दे दी। इस प्रकार नवीन विचारों की लोच प्रारम्भ हुई।

पुनजागरण मध्यप्रथम इटली के नगरों में प्रारम्भ हुआ। उसके पश्चात् यूरोप में इसका प्रसार हुआ। पुनजागरण साहित्य विद्या और कला तक ही सीमित नहीं था अपितु इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत था। इसमें मानव के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप जन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीनता द्रष्टिगोचर होने लगी। पुनजागरण के कारण जिन क्षेत्रों में नवीनताएँ उत्पन्न हुईं उसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है —

बौद्धिक जागृति

पुनजागरण में यूरोपियन जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। यूरोपियन लोग प्राचीन परम्पराओं और अधविश्वासों से बुरी तरह जकड़े हुए थे। इस समय यूरोपियन प्राचीन विचारों को आखिरी मूँद कर स्वीकार कर लत थे। पुनजागरण के काल में एक वैचारिक क्रांति हुई। जिसने मानव को प्राचीन अधविश्वासों और आडम्बरों से मुक्ति दितवाई। यह वैचारिक क्रांति मानववादी विचारधारा के कारण सम्भव हो सकी।

पुनजागरण का जन्मदाता इटली का महाकवि दाँत था। जिसने तेरहवीं शताब्दी में सबसे पहले अपनी कविताएँ लेटिन भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा में लिखी। इसके पश्चात् फ्लोरेंस निवासी पेद्राक (1304-1374) ने अनेक प्रथाओं का अध्ययन कर मानवीय दृष्टिकोण पर बहुत सारी पुस्तकें लिखीं। पेद्राक के विचारों का समकालीन विचारकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इटली के अनेक विद्वानों ने पेद्राक के विचारों का प्रचार किया।

डो कज़िया नामक विद्वान ने डेकाभरोन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने धार्मिक प्रभाव से मुक्त मानवीय विचारों, गुणों और विशेषताओं का वर्णन किया। बार्नेशिया के शिष्यों ने उसके विचारों का प्रचार किया। इसी समय कस्तुनतुनिया का एक विद्वान, मैथ्यूअल त्रीमोलारस इटली आया। इसने भी वैचारिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने इटली के विद्वानों को यूनानी भाषा सिखाई। इसी समय यूनानी विद्वान बेसारीयोन ने बर्निस के सेंट मार्क चर्च का अपना पुस्तकालय उपहारस्वरूप दे दिया। यही चर्च ने पुनजागरण के विकास में अपना सहयोग देना शुरू कर दिया। जब प्रसिद्ध यूनानी विद्वान निकोलस पंचम पोप बना तो उसने सभी चर्चों को पुनजागरण की प्रगति में योगदान देना शुरू कर दिया।

क्रिस्टियानिआन नामक विद्वान ने इस बात का प्रचार किया कि राजदूतों और राजनीतिज्ञों का भी चाहिये कि वे मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर काम करें।

भेकियावली ने दि ग्रिन्स नामक पुस्तक लिखी। इसमें उसने नवीन राजनीतिक आदर्शों के बारे में वर्णन किया है। इटली के विद्वानों और साहित्यकारों ने अपनी इस नवीन विचार धारा का प्रसार सम्पूर्ण विश्व में किया। जब यूरोप में मानववादी विचारधारा का प्रसार हुआ तो यूरोप के विभिन्न देशों में मानववादी दृष्टिकोण से साहित्य सृजन का वायु हान लगा। अब यूरोप में साहित्य विज्ञान, कला और अन्य क्षेत्रों में भी पुनर्जागरण प्रारम्भ हुआ। जिसका फलस्वरूप यूरोपियन लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ।

1 साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण

इटली फ्रांस इंग्लैंड स्पेन पुनर्जागरण जर्मनी और हालण्ड आदि देशों में साहित्य के क्षेत्र में तीव्र गति में विकास हुआ। इस समय बोल चाल की भाषा में साहित्य सृजन किया गया। पुनर्जागरण काल का साहित्य तब और दशक पर आधारित था। वाईबन का सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। इस समय लेटिन भाषा से लगभग सौ बोल चाल की भाषाएँ विकसित हुईं। छापेखानों के प्रयोग के कारण पुनर्जागरण अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गया। साहित्य के क्षेत्र में हुए पुनर्जागरण का समस्त यूरोप पर प्रभाव पड़ा।

(1) इटली

पुनर्जागरण का फलस्वरूप मानव के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जिसका कारण मानसिक परिवर्तन हुआ और वैचारिक क्रांति संभव हुई। इस क्रांति के कारण इटली में नवीन साहित्य का सृजन हुआ। यहाँ के विद्वानों यूनानी साहित्य का अध्ययन के प्रति रुचि रखने लगे और प्राचीन साहित्य के आधार पर नवीन साहित्य का सृजन करने लगे। इटली के साहित्य में नवीनता उत्पन्न करने का श्रेय दांते पेट्राक गिओवानी बार्कशिया एरियस्टो और भेकियावली आदि विद्वानों को दिया जाता है।

महाकवि दांते (1265-1321 ई०)

इटालियन साहित्य में नवीनता उत्पन्न करने का श्रेय महाकवि दांते का दिया जाता है। उनका जन्म 1265 ई० में हुआ था और 56 वर्ष की आयु में 1321 ई० में उनकी मृत्यु हो गई। दांते की तुलना यूनानी भाषा एवं साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान होमर के साथ की जाती है। उनमें इटालियन भाषा में दि डिवाइन कॉमेडी नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने मृत्यु के पश्चात् नरक और स्वर्ग की कल्पित यात्रा का वर्णन किया है। इसके माध्यम से दांते ने मानवता को प्रेम एवं एकता का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न किया है। दांते ने अपनी कविताओं की रचना मातृभाषा में की। उसके द्वारा अपनी कविताओं में जनभाषा का प्रयोग करना साहित्य पुनर्जागरण का सकेत माना था। दांते को इटालियन कविता के पिता के नाम से भी पुकारा जाता है।

पेट्राक (1304-1374 ई०)

इटली का दूसरा प्रसिद्ध कवि और विद्वान व्यक्ति पेट्राक था। यह इटली के फ्लोरेंस नामक नगर का रहने वाला था। इसका पिता दान के घनिष्ठ मित्रा म से एक था। पेट्राक ने विद्वाना का ध्यान यूनाय तया रोम के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने हेतु आरंभित किया। उसने अनेक कविताओं की रचना की। इससे अपनी कविताओं में प्रकृति एक मनुष्य के हों एक विषादा का मामिक ढंग से वर्णन किया है। उसने यूनानी और लटिन भाषा के पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को संप्रहित किया। इससे पुस्तकालयों की स्थापना का सिलसिला प्रारम्भ हुआ और कुछ ही समय में यूरोप में अनेक पुस्तकालयों की स्थापना हो गई। यूरोप में मानववादी विचार धारा को विकास करने का श्रेय भी पेट्राक को ही दिया जाता है। उसके द्वारा लिखे हुए गीत बहुत अधिक प्रसिद्ध है। पेट्राक को प्रथम आधुनिक मनुष्य और "पुनर्जागरण का पिता" के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है।

गिओवानी बोकेगियो (1313-1375 ई०)

बोकेगियो का इटली के गद्य साहित्य का पिता कहा जाता है। उसने "दिकामरौन" नामक पुस्तक लिखी। इसमें उसने एक सौ हास्य कहानियाँ लिखी हैं। बोकेगियो ने अपनी कहानियों में सामंता पार्लिया और सरदारों का बड़े भड़े ढंग से मजाक उड़ाया है लेकिन मनुष्य जाति से इसे गहरा प्रेम और महानुभूति थी।

एरियस्टो (1474-1533 ई०)

एरियस्टो (1474-1533 ई०) इसी प्रकार एरियस्टो नामक साहित्यकार ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने प्रौढ गद्य एक पद्य साहित्य की रचनाओं ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की।

मकियावेली (1474-1520 ई०)

मकियावेली इटली का प्रसिद्ध राजनीतिक, विचारक और महान् साहित्यकार था। उसने 'दो प्रिंस' और 'दो घाट व्याप वाट' नामक दो ग्रंथों की रचना की। 'दो प्रिंस' नामक ग्रंथ में राजनीति के बारे में विवरण दिया है। कुछ इतिहासकार मकियावेली के दो प्रिंस नामक ग्रंथ की तुलना चाणक्य के अथशास्त्र से करते हैं। उसने इटली की राजनीति का गम्भीरता से अध्ययन किया। इसके पश्चात् उसने कहा कि शासन का सुचारु रूप से शासन चलाना चाहिए। उसने लिखा है कि यह बहुत अच्छा है कि लोग राजा से भी प्रेम करते और उससे डरते भी, किन्तु चूँकि ऐसा हो पाना कठिन है इसलिए आवश्यक है कि लोग उससे डरें। मकियावेली के विचारों का तात्कालीन राजनीतिज्ञ दुराचाराओं पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा।

(1) हास्य

इटली में साहित्य के क्षेत्र में जो नातिवारी परिवर्तन हुए उसका यूरोप

के अन्तर्गत देशों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। पन्द्रहवीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली मानववादी लफ्फ डेसीडेरियस इरस्मस (1466-1536 ई०) था। जिसका जन्म 1466 ई० में हालण्ड में हुआ था। वह अपनी योग्यता शरीर और विद्वता के लिए इतना अधिक प्रसिद्ध था कि लोगों ने उसे यूरोप का विद्वान की उपमा दे दी थी। उसने अपनी रचनाओं में माध्यम से अंध विश्वास, भ्रष्टहिण्डुता और अज्ञान के विरुद्ध आवाज उठाई। वह विश्व शांति का समर्थक था। उसने निरंकुश अत्याचारों से निवृत्तता की कठु आलाचना की। और 'मूखत्व की प्रशंसा (इन दी प्रेज आफ फौली)' नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उसने व्यंगपूर्ण शैली में धर्माधिकारियों का भजाव उड़ाया और धर्माधिकारियों के दुष्चारा का वर्णन किया है।

(iii) फ्रांस

फ्रांस में रेबीलस, मोण्टेन आदि विद्वानों ने साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रेबीलस (1495-1533 ई०) फ्रांस के गद्य साहित्य में नवीनता उत्पन्न करने का श्रेय रेबीलेस का दिया जाता है। यह अपने समय का एक भ्रष्ट गद्य लेखक था। उसने गद्य साहित्य में उपन्यास पद्धति को जन्म दिया। और अपने उपन्यासों में मानव के स्वतन्त्र चिंतन के महत्व के बारे में वर्णन किया है। रेबीलेस ने पाठकों को अध्यापकों के अपने उपन्यासों में व्यंग का प्रयोग करते हुए भजाव उड़ाया। वह उस समय में प्रचलित शिक्षा का विरोधी था। उसका यह मानना था कि अध्यापक छात्रों को व्यर्थ की बातें रटा देते हैं। फ्रांस में मोल्यो नामक विद्वान निबन्ध का जन्मदाता था। उसने कहा था कि कुछ पराजय विजयों से भी बढ़कर विजयपूर्ण होती है।

मोण्टेन (1533-1592 ई०) मोण्टेन अपने समय का एक भ्रष्ट निबन्धकार था। उसके निबन्धों को इस समय भ्रष्टी प्रसिद्धी मिली। वह अपने निबन्धों में नवीनत्वपूर्ण शैली का प्रयोग करते हुए भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता था। परिणामस्वरूप वह उस समय फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ गद्य लेखक बन गया।

रामसड अपने समय का एक भ्रष्ट गीतकार था। उसकी रचनाओं को इस समय काफी ख्याति मिली। इसके अतिरिक्त कार्लोस रासीन माल्थियर मद्याम और दसन्निमे आदि साहित्यकारों की रचनाएँ भी काफी प्रसिद्ध हुईं।

(iv) इंग्लण्ड

इंग्लण्ड में भी साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ और 16वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण अपने सर्वोच्च शिखर पर जा पहुँचा। वहाँ के साहित्य के विकास में कवि चासर एडमंड स्पंसर, सर टामस मूर मार्लोव और विलियम शेक्सपियर आदि विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कवि चासर (1340-1400 ई०)

कवि चासर इंग्लण्ड के मध्यकाली युग का महान कवि था। उस अग्रणी

काव्य का पिना के नाम में भी पुकारा जाता है। उसने अपनी रचनायें उस समय की प्रचलित भाषा में लिखीं। श्रीर अपनी रचनाओं में लोगों के गुण व दोषों का वर्णन किया। चासर न ग्रनर मनोरजक कहानिया भी लिखीं। उसकी ये कहानिया 'क्वैण्टरबरी टेल्स' नामक संग्रह में प्रकाशित हुईं।

एडमंड स्पेसर

स्पेसर न साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने फेयरी क्वीन' नामक पुस्तक लिखी, जिसको उस काल में काफी ख्याति मिली।
सर टामस मूर (1478-1535 ई०)

सर टामस मूर न 'यूरोपिया' नामक पुस्तक लिखी, जो 1516 ई० में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक लेटिन भाषा में लिखी गई थी बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया था। उसने अपनी पुस्तक में अपने युग के समाज और सरकार की हास्यपूर्ण ढंग में आलोचना की है। टामस मूर प्लेटो के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित था और वह इंग्लैण्ड में श्रेष्ठ शासन व्यवस्था स्थापित किये जाने के पक्ष में था। उसने अपनी पुस्तक में आदेश समाज और आदेश राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया है।

मालोव (1564-1593 ई०)

क्रिस्टोफर मालोव इंग्लैण्ड का प्रसिद्ध गीतकार था। उसने कई नाटक लिखे। उगन 'डा फाउस्टस' नामक नाटक भी लिखा। जिसमें नायक पान और शक्ति को सार अपनी आत्मा शान को बेच देता है।

क्रिस्तिफर शेक्सपियर (1564-1616 ई०)

इंग्लैण्ड के पुनजागरण कालीन साहित्यकारों में शेक्सपियर को सर्वश्रेष्ठ गायिकाकार का स्थान प्राप्त है। यह अपने युग का सबसे प्रसिद्ध नाटककार और कवि था जिसकी तुलना विश्व के विद्वान व्यक्तियों से की जाती है। शेक्सपियर एलिजाबेथ के शासनकाल में हुआ। उसने अपनी रचनाओं में मानवीय कल्याण और मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का गहनता से वर्णन किया है।

शेक्सपियर ने हैमलेट नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की। उसमें उसने बताया कि किस प्रकार नायक अपनी आत्मसम्पत्ति के कारण मर जाता है। उगन "मेरबय" नामक पुस्तक भी लिखी। इसमें उगन यह बताया कि एक युग व्यर्थ गति राजा बनना चाहता था वह भी जन साधारण की महानुभूति प्राप्त कर सकता है। उस पर बहुत से अच्छे ही नज़र आती हैं। शेक्सपियर की तीसरी रचना 'क्रिस्तिफर मीजर' है। यह एक नाटक है जिसमें विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्धी प्राप्त की है।

प्रसिद्ध कृतियाँ—

प्रसिद्ध कृतियाँ भी इस समय का एक अच्छा निबन्धकार था। उनके निबन्धों

की गणना अच्छे निबन्ध लेखका में की जाती है। वेन फिगर ने लिखा है कि बकन ने मनुष्य का ध्यान 'यय के धार्मिक विचारों से हटा दिया और उसे प्रकृति के अध्ययन एवं मानवहित के कार्यों को करने के लिये प्रोत्साहित किया।

मिल्टन भी इस काल का सर्वश्रेष्ठ कवि था। उसने 'पेराडाइज लास्ट' नामक ग्रन्थ की रचना की। जिसे उस समय बहुत अधिक प्रसिद्धी मिली। हाब्स भी राजनीतिशास्त्र का सर्वश्रेष्ठ विद्वान था

(v) जर्मनी—

जर्मनी के साहित्य में नवीनता उत्पन्न करने का श्रेय बहा के रून्डेलको कोनाड और काल्टस आदि साहित्यकारों को दिया जाता है। माटिन लूथर नामक धर्म सुधारक जर्मनी में पन्ना हुआ था। यह धर्म शास्त्र का प्राध्यापक था। उसने बाईबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और धर्म में 'याप्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया।

(vi) स्पेन—

पुनजागरण के कारण स्पेन के साहित्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। स्पेन में सर्वातिस और ब्रेल्डेस नामक विद्वानों ने साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(vii) सर्वातिस—

सर्वातिस इस काल का सर्वश्रेष्ठ लेखक था। उसने डान विवकजोट नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक मनोरंजन में भरपूर है। इसमें मध्यकालीन रूढ़ियाँ और परम्पराओं की कटु आलोचना की गई है। इसका मुख्य कथानक डान विवकजोट दुनिया को सुधारने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसकी बड़ी दुःशा होती है। वह अपने अनुयाईयों के साथ पवन चक्रियों से इस प्रकार से युद्ध करता है जैसे कि वह सैनिकों से युद्ध कर रहा हो। बच्चे मनोरंजन के लिये इस पुस्तक को पढ़ते हैं। उसी में यह कहा था कि 'हर कुत्ते का अपना दिन आता है एक से पक्षी के पंभी एक साथ रहते हैं।

लोपडी धगे नामक विद्वान स्पेन के रंगमंच का जन्मदाता था। ब्रेल्डेस नामक व्यक्ति स्पेन का सर्वश्रेष्ठ कवि था। उसने नवीन विचारों को आधार बनाकर अपनी कविताएँ रचीं। इस समय बेमाज पुतगाल का एक सर्वश्रेष्ठ कवि था। उसने 'तुसियाड' नामक महाकाव्य स्पेनिश भाषा में लिखा। यह महाकाव्य पुतगाल साहित्य की उत्कृष्ट कृति की रचना मानी जाती है। उपरोक्त विद्वानों के द्वारा सभी रचनाएँ स्पेनिश भाषा में ही लिखी गई थीं।

उपरोक्त विवचन से स्पष्ट है कि पुनजागरण के कारण यूरोपियन देशों में स्थानीय भाषाओं में साहित्य का नृजन हुआ। जिसके फलस्वरूप यूरोप की स्थानीय या प्रादेशिक भाषाओं का विकास सम्भव हो सका। उस समय लोगों में प्राचीन

यूनानी तथा रोमन ग्रन्थों का अध्ययन करने तथा मानववाद को समझने की अभिरूचि उत्पन्न हुई।

पुनजागरण के फलस्वरूप धर्म के प्रभाव की समाप्ति हुई। पहले धर्म पर ही साहित्य लिखा जाता था किंतु अब साहित्यकार स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन समस्याओं का आलोचनात्मक ढंग से साहित्य में वर्णन करने लगे। अब मनुष्य का पारलौकिक जीवन के सम्बन्ध में मापताओं से विश्वास उठ गया। इस प्रकार पुनजागरण के कारण मनुष्य की स्वतन्त्र रूप से चिन्तन करने की शक्ति का विकास हुआ।

2 कला के क्षेत्र में विकास

प्रोफेसर डेविस ने लिखा है कि 'पुनजागरण के कारण कला के क्षेत्र में अत्यन्त क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ। मध्यकाल में कला पर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। उस समय धर्म का प्रचार करने के लिए ही कला का उपयोग किया जाता था। परन्तु पुनजागरण के कारण कला धर्म के प्राचीन बंधन से मुक्त हो गई। अब कलाकारों ने स्वतन्त्र रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने वास्तविकता व स्वभाविकता को निकट लाने का प्रयास किया।

पुनजागरण के काल में प्राचीन एवं मध्यकालीन के समन्वय से एक नवीन कला का विकास हुआ। जिसके फलस्वरूप प्रेम, सौन्दर्य एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के निरूपण पर चित्रों का निर्माण किया जाने लगा। कला के क्षेत्र में भी सर्वप्रथम पुनजागरण इटली के फ्लोरेंस नगर में प्रारम्भ हुआ। यहाँ पर कलाकार धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से कलाकृतियाँ बनाने लगे। पुनजागरण के कारण यूरोप में भी कला के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। कला के क्षेत्र में अब वास्तविकता दृष्टिगोचर होने लगी। धीरे धीरे सभी यूरोपियन देशों में इस नवीन कला का प्रसार हो गया।

(1) स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास

पुनजागरण से पूर्व मध्य काल में स्थापत्य कला में गार्थिक शैली का प्रयोग किया जाता था। इस शैली के आधार पर धार्मिक भवनों का निर्माण किया जाता था। पुनजागरण के कारण कला पर व्याप्त धार्मिक बंधन समाप्त हो गये। इटली ने सर्वप्रथम प्राचीन यूनान और रोम की कला का समन्वय कर एक नवीन शैली का विकास किया। इस नवीन शैली में अनेक डिजाईना और शृंगारों को प्रोत्साहन दिया गया और इस शैली के आधार पर विशाल राजमहल और चर्चों का निर्माण करवाया गया। भवनों में सौन्दर्य की दृष्टि से फून्-पत्तियाँ एवं पत्तियों के चित्र अंकित किये गये। वास्तुकला में पत्थर के साथ लकड़ी का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। उस समय लकड़ी पर मुन्दर शूटर्स का कार्य भी किया जाता था। इस गई शैली का जन्मनाम पनोरम निवासी बूनलेस्सी (1379-1446 ई०) था। अब अरवा के प्रभाव में स्थापत्य कला में गोथ महाराज का निर्माण किया जाने लगा।

16वीं शताब्दी में इस नवीन शैली का पूरा रूप से विकास हो चुका था। इस शताब्दी का प्रमुख वस्तुकला विद्वान् माइकेल एंजिलो था। रोम का सेंट पीटर का गिरजाघर पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का सुन्दर नमूना है। इसका निर्माण माइकेल एंजिलो और रफेल जैसे प्रसिद्ध कलाकारों ने करवाया था। एंजिलो 90 वर्ष की आयु तक इसके निर्माण में व्यस्त रहा। इस गिरजाघर का विशाल गुम्बज बहुत प्रशंसनीय है। यह गिरजाघर इतना विशाल है कि इसमें 80 हजार व्यक्ति एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं।

वेनिस के सन्त मार्क का गिरजाघर और इंग्लैण्ड में सेंट पॉल के गिरजाघर का निर्माण भी इस नवीन शैली के आधार पर किया गया था। इस समय अमीरों ने भी इस नवीन शैली के आधार पर विशाल भवनों का निर्माण करवाया। पेरिस का लुव्रे का संग्रहालय और जर्मनी का हैडेलबर्ग का दुर्ग उस समय की नवीन वास्तु कला के सुन्दर नमूने हैं। यद्यपि अमेरिका के बड़े बड़े नगरों में टाउनहाल पुनर्जागरण कालीन शरतों के जैसे बनाये गये हैं परन्तु सुन्दरता, विशालता और प्रभाव में ये प्राचीनकला का मुकाबला नहीं कर सकें।

फ्रांस में भी इस नवीन शैली के आधार पर अनेक भवनों का निर्माण किया गया। स्पेन के सम्राट फिलिप ने भी इस नवीन शैली के अनेक भवन बनवाये। इंग्लैण्ड में 1619 ई० में 'हाइट हाल' में दावत घर का निर्माण किया गया। इसका निर्माण प्रसिद्ध कलाकार इनिगोजानस ने करवाया था। उस प्रकार स्पष्ट है कि पुनर्जागरण कालीन कलाकार स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्राचीन कला को मान नहीं दे सके।

(11) चित्रकला के क्षेत्र में विकास

पुनर्जागरण से पूर्व मध्यकाल में चित्रकला धार्मिक बंधनों में जकड़ी हुई थी। पुनर्जागरण के कारण चित्रकला धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गई और चित्रकला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। अब धार्मिक चित्रों के स्थान पर जन जीवन से सम्बन्धित भौतिक एवं यथार्थ चित्रों का चित्रण किया जाने लगा। इससे चित्रकला में सजीवता दृष्टिगोचर होने लगी। इस काल के प्रसिद्ध चित्रकार सिमावू गिटो एड्रिया साइमोन, मार्टिन और मेसेक्विमो आदि थे।

गिटो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। यह पहला चित्रकार था जिसने मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्रों का चित्रण किया। मध्यकाल में अधिकांश चित्रकार भवन की दीवारों पर चित्रों का निर्माण करते थे। इन चित्रों का रंग कच्चा होता था जो थोड़े समय में अपने आप उखड़ जाता था। 17वीं शताब्दी में बेल्जियम के वान ड्राइक नामक दो भाईयों ने चित्रों का अधिक सख्या में बनाने के लिए उनमें तेल मिलाने का प्रयोग शुरू किया। इस समय लकड़ी और पत्थरों पर भी चित्रों का निर्माण किया जाने लगा। और चित्रकारों ने रंगों को

मिश्रित करने की विधि ग्राज निजानी। जिसके कारण चित्र और अधिक सुन्दर बनने लग। प्लट और जीन डमड ने लिखा है कि 'रंग का समझदारी से, परिदृश्य का चतुरता से और प्रकाश छाया का सफाई से प्रयोग करके रेनेसा के चित्रकार विश्व के आश्चर्य बन गये।'¹

लियो नार्ने दाविंची (1452-1519 ई०) यह उस समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। उसके चित्र साद और भाव से परिपूर्ण होते थे। वह चित्रों के लिए उपयुक्त सुन्दर रंगों का प्रयोग करता था। और उनमें शरीर के अंगों और प्रतिजगों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता था। उसके चित्र लास्ट सपर "(अन्तिम भोजन) और 'मानालिमा" विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वास्तव में वह पुनजागरण कालीन प्रथम प्रसिद्ध चित्रकार और श्रेष्ठ प्रतिनिधि था।

इटली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार माइकेल एंजेलो था। वह मनुष्य को ससार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानता था। एंजेलो का चित्र 'लास्ट जजमेंट' (अंतिम निणय) विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस चित्र का निर्माण करने में उसे 20 वर्ष का समय लगा। इसके 145 चित्र आज भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा निर्मित 400 मूर्तियाँ भी आज तक सुरक्षित हैं। रोजेला ने दाऊद और मूसा की विशाल तथा सजीव मूर्तियों का निर्माण किया था। ये मूर्तियाँ सगरमर की बनायी गई थीं। उसने भक्त पीटर के गिरजाघर के भीतर छत पर ईसा के जन्म से प्रलय तक की कहानी चित्रों के रूप में चित्रित की है। इन चित्रों को बनाने में उसे पाँच वर्ष का समय लगा और इसी काम में वह अर्धा हो गया। यह चित्र आज भी देखने वालों को आश्चर्य में डाल देता है। दुर्भाग्य से यह अपने जीवन में विश्व प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सका।

यद्यपि राफेल नामक प्रसिद्ध चित्रकार की छोटी उमर में ही मृत्यु हो गई, किन्तु जीवन के 37 वर्षों में (1483-1520 ई०) उसे जो प्रसिद्धी मिली वह अन्य चित्रकारों का नहीं मिल सकती। उसके 'सिस्टाइन महोना' नामक चित्र की गणना सर्वश्रेष्ठ चित्रों में की जाती है। राफेल दवी दवताआ के भावपूर्ण और प्रेमपूर्ण चित्रों का निर्माण करता था। इसलिए पोप उस पर बहुत प्रसन्न था। उसने जर्मन एक चित्र में यूनानी दार्शनिकों को आपस में शस्त्राध करके दृष्ट दिखाया है। और अपने रंगील चित्रों में वर्णियों के समृद्ध लोगों का जीवन चित्रित किया है। वह मानवत्व और वास्तव्य के सजीव एवं सुन्दर चित्रों का निर्माण करता था। उसके द्वारा बनाये गये चित्रों में सजीवता और सुन्दरता दृष्टिगोचर होती है। प्लट और जीन डमड ने लिखा है कि माइकेल एंजेलो के मुखावत राफेल का काम शान्त,

मधुर और नारी सुलभ भाहिनी से परिपूर्ण प्रतीत होता है ।¹

हासण्ड म नवीन चित्रकला विकसित करने का श्रेय हूबट आइव तथा जान वान आइव आदि प्रसिद्ध चित्रकारों को दिया जाता है । जर्मनी के प्रसिद्ध चित्रकार डयोरार और हेन्स दालवीन ने लकड़ी तथा तांबे के बतनों पर आश्चर्यजनक चित्रों का निर्माण किया ।

स्पेन में चित्रकला का विकास करने का श्रेय एलग्रीका और वेलेजव्यूज आदि प्रसिद्ध चित्रकारों को दिया जाता है । वेलेजव्यूज सांसारिक चित्रों का निर्माण करता था । उसने विलासपूर्ण राजदरबारों पर अनेक चित्र बनाये । चित्रकार रुवेस (1577-1640 ई०) भडकीले चित्रों का निर्माण करता था । वह चित्रों में नारियों के अंगों का सुन्दर ढंग से प्रदर्शन करता था । उसका चित्र "सलीब स अबरुहन" विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ।

पुनजागरण कालीन चित्रों को देखकर पादरी नाराज होते थे । क्योंकि महान सत्ता और शहादों का चित्र भी साधारण लागाव जैसा बनाया जाता था । एक पादरी ने चित्रकारों को फटकारते हुए कहा कि चित्रों में तुम घुरा करते हो, तुम मिर्जों में अहंकार लाते हो तुम पवित्र मेरी (ईसा की माता) को ऐसी वशभूषा में प्रस्तुत करते हो माना वह कोई सामान्य स्त्री है । पुनजागरणकालीन कला ने समस्त यूरोपियन देशों को प्रभावित किया ।

(iii) मूर्तिकला के क्षेत्र में विकास—पुनजागरण के कारण मूर्तिकला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ । प्रसिद्ध मूर्तिकार दानोतेली ने धर्म के स्थान पर मनुष्य की मूर्तियों का निर्माण करना प्रारम्भ किया । यह इटली के फ्लोरेन्स नगर का रहने वाला था । उसके द्वारा बनाई गई वेनिस के सेंट मार्क की आदमवद मूर्ति मूर्तिकला का एक सुन्दर नमूना है ।

दूसरा प्रसिद्ध मूर्तिकार लारेजो गिबर्टी (1378-1455) था । उसने फ्लोरेज नगर के गिरजाघर में कीसे का द्वार बनाया । इसकी गिनती पुनजागरण काल के शिल्प के उत्कृष्ट नमूनों में की जाती है । इस कृति ने उस हमेशा के लिए अमर बना दिया । मार्सेल गेजेला ने उस द्वार के बारे में यहाँ तक कहा था कि 'यह द्वार तो स्वर्ग के द्वार पर रखने योग्य है । यूरोप में भी मूर्तिकला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ । समाधिषा पर मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा । इसका प्रारम्भ स्पेन के सम्राट फर्नान्ड की समाधि से हुआ ।

(iv) संगीत कला के क्षेत्र में विकास—पुनजागरण के कारण संगीत कला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ । इतिहासकार हेज ने लिखा है कि 16वीं शताब्दी में संगीत कला के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई । इसका कारण यह था कि मध्यकाल में

गिरजाघरो में संगीत पर प्रतिबन्ध था। बाद में सेंट एम्ब्रोस ने गिरजाघरा में संगीत के प्रयाग का आवश्यक माना। अब तक गिरजाघरो में ही प्रायःनाएँ गीत के रूप में गाई जाती थी लेकिन अब अथ क्षेत्रों में भी संगीत का प्रचार प्रारम्भ हुआ।

पुनर्जागरण काल में ही वायलिन और पियानो का आविष्कार हुआ। इस समय वाद्य संगीत की लोकप्रियता में वृद्धि हुई और पहली बार आर्केस्ट्रा का प्रचलन हुआ जिसमें एक साथ कई वाद्य बजाये जा सकते थे। इस समय का प्रसिद्ध संगीतज्ञ पैताम्ब्रिना था जो इटली का निवासी था। पुनर्जागरण के कारण धार्मिक तथा लौकिक संगीत का भेदभाव समाप्त हो गया।

(3) विज्ञान के क्षेत्र में विकास—पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। मध्यकाल में यूरोपियन अधविश्वासा और प्राचीन रूढ़ियों के बन्धन में जकड़े हुए थे। उन पर घमाधिकारियों का बहुत अधिक प्रभाव था। जो उस समय स्वतंत्र चिन्तन के प्रबल विरोधी थे। मध्यकाल में प्राचीन रूढ़ियों का विरुद्ध आवाज उठाने वाले एक प्राचीन साहित्य की जाच करने वाले व्यक्ति को घमटोही की सजा दी जाती थी।

पुनर्जागरण के कारण वैज्ञानिक श्रान्ति हुई। जिसके कारण जन साधारण का अधविश्वासा तथा मिथ्या विचारों से विश्वास उठ गया। मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से चिन्तन करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय कई नई खोजें और आविष्कार हुए। इस वैज्ञानिक श्रान्ति के कारण मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों का पता लगाने का प्रयास किया और प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करके मानव जीवन का सुखी बनाने में सफलता प्राप्त की।

(1) खगोल एवं भूगोल के क्षेत्र में विकास—सेवाइन ने लिखा है कि "नये दशा की खोज और ज्योतिष की छानबीन ने जनता को पहली बार यह अनुभव करवाया कि उनके कई लोकप्रिय विश्वास गलत हैं। प्रथम वस्तुओं और प्रमाणाओं को देखने के पश्चात् जनता ने विज्ञान पर विश्वास करना प्रारम्भ कर दिया। सामुद्रिक यात्रियों ने नये-नये प्रदेशों की खोज की और ज्योतिषियों ने एक नये ग्रहाण्ड की खोज की। दूसरी शताब्दी में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री टॉलेमी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य व चन्द्रमा उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चर्च में टॉलेमी के इस सिद्धांत का स्वीकार किया और लोगो ने इस पर विश्वास कर लिया।

खगोल शास्त्र के क्षेत्र में श्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति निकोलस कोपर्निकस (1473-1543 ई०) था। यह पालण्ड का रहने वाला था। उसने टॉलेमी के मत को गलत बताया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी

सूय के चारो ओर चक्कर लगाती है। उस समय लोगो ने इस बात पर बहुत आश्चर्य किया और एकाएक उसके सिद्धांत पर विश्वास नही कर मने। कोपरनिकस का सिद्धांत बाईबल के विरुद्ध था। चर्च ने इस सिद्धांत का बड़ा विरोध किया। पोप के आदेश से कोपरनिकस ने अपने विचारो का प्रचार बंद कर दिया और बह दंड से बच गया।

जर्मनी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कपलर ने गणित के अका से कोपरनिकस सिद्धांत को सही प्रमाणित कर दिखाया। इटली के वैज्ञानिक जाइडिना गालीली कोपरनिकस के सिद्धांत का प्रचार करना शुरू किया। परिणामस्वरूप पोप ने उसे मृत्यु दण्ड दिया। धार्मिक अत्याचार और बबरता के बावजूद भी वैज्ञानिक खोजे निरंतर होती रही।

इटली के प्रसिद्ध विद्वान गलीलियो (1564-1642) ने कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की। उसने एक ऐसी दुरबीन का निर्माण किया जिससे सूर्य चंद्रमा और ग्रहो आदि को देखा जा सकता था। पोप ने गलीलियो को बन्धन कर लिया और उसको बाध्य होकर अपने विचारो को वापस लेना पडा।

इंग्लण्ड का निवासी आईजक न्यूटन (1642-1727 ई०) एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। उसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने बताया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है इसलिए हर वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है ऊपर की प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। इस समय पृथ्वी का आकर्षण और घूमने का सिद्धांत ये दो बड़ी खोजें हुईं। इस प्रकार यूरोप ने ससार का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया।

(1) गणित के क्षेत्र में विकास—डेकार्त (देकार्त) एक प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ था। उसने यह बताया कि किसी भी बात का तक की कसौटी पर बसने के उपरांत यदि सत्य प्रतीत होती हो तो उस स्वीकार कर लेना चाहिए। परिणामस्वरूप रूढ़ीवादी लोग उसका शत्रु बन गए। उसने बीज गणित का ज्यामिती में उपयोग करने के बारे में खोज की।

अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया इसका लोगो पर भारी प्रभाव पडा। जब उनको पता चल गया कि हमारी पृथ्वी धूमशास्त्रो के अनुसार कोई देवयोग या आकस्मिक घटना नही है अपितु यह तो प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना घुरी पर घूम रही है। गणित के क्षेत्र में गलीलियो और स्टेविन नामक विद्वानों ने भी अनेक खोजें कीं।

(II) भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रगति—भौतिक शास्त्र की प्रगति में गलीलियो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले यह मत प्रचलित था कि गिरने वाली वस्तु की गति उसके वजन पर निर्भर करती है, गलीलियो ने अरस्तु के इस मत का खण्डन किया। 1593 ई० में उसने चर्च के झूलते हुए दीपक को देखकर पहलम

क मिद्धात का आविष्कार किया। इस सिद्धांत के अनुसार उमने इस मत का प्रतिपादन किया कि गिरन वाली वस्तु की गति उसके भार पर नहीं अपितु उसकी दूरी पर निर्भर करती है। उमने एयर तथा हार्डनीस्टिक तुला की भी पाज की। गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने मगनेट के मिद्धात का आविष्कार किया था।

(iv) रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रगति—रसायन शास्त्र के क्षेत्र में कई खोजें हुईं। बाल हेल्मॉट ने 1630 ई० में कार्बन डाईऑक्साइड नामक गैस का आविष्कार किया। कोडस नामक वैज्ञानिक ने गंधक और ऐल्कोहल को मिलाकर इथन का आविष्कार किया। राबर्ट बॉयल ने गैसों के विस्तार पर बॉयल सिद्धांत का आविष्कार किया। स्विटजरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक परसीलमस ने रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन किया।

(v) चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में प्रगति—चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। नादरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पसेडियम (1516-1564) ने 'मानव शरीर की बनावट' नामक पुस्तक लिखी। उसने इस पुस्तक में शल्य चिकित्सा के व्यवहारिक प्रयोग पर अधिक जोर दिया। परिणामस्वरूप पुरानी मायताओं समाप्त होनी लगी। एंडा विसालियस नामक विद्वान ने मानव शरीर की हड्डियों का अध्ययन करने के पश्चात् अस्थिपंजर पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।

स्विटजरलैंड के वैज्ञानिक परसीलमस ने चिकित्साशास्त्र एवं रसायन शास्त्र के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन किया। इस समय जड़ों वृद्धि का प्रयोग रोगों के इलाज के लिए किया गया। इंगलैंड के विलियम हार्वे ने मनुष्य के शरीर में रक्त संचारण की विधि का आविष्कार किया। इसमें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हलचल मच गई। उसने इस मत का प्रतिपादन किया कि हृदय खून को घमनियों के माध्यम से सारे शरीर में फैकता है और शिराओं द्वारा खून वापस लेता रहता है। इस आविष्कार के पश्चात् खून चटान तथा हृदय और ग्रन्थियों जैसी बीमारियों का इलाज आसानी से किया जाना लगा। जर्मन विद्वान केपलर ने शक सम्बन्धी नियमों की खोज की।

(vi) नये यंत्रों का आविष्कार—यूरोप में इस समय कई नये यंत्रों का आविष्कार हुआ। जकारियाज ने सूक्ष्म दशक यन्त्र बनाया। 16वीं शताब्दी में घड़िया का आविष्कार हुआ। गेलीलियो ने दूरदर्शक यंत्र का आविष्कार किया। छापेखाने का आविष्कार चीन की प्राचीन सभ्यता के समय में ही हुआ था परन्तु वास्तविक विकास पुनजागरण काल में यूरोप में सम्भव हो सका। इस समय तक वैज्ञानिकों ने वायु शक्ति की खोज कर ली थी। अरब मशीनों की वायु शक्ति की सहायता से चलाया जाना लगा। इस प्रकार आज के विकसित वैज्ञानिक युग की नींव पुनजागरण काल के समय में ही रखी गई थी।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुनर्जागरण ने मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। इससे मनुष्य को मध्य काल में प्रचलित रूढ़ियों और प्राचीन परम्पराओं से छुटकारा मिला और अब मनुष्य ने नये युग में प्रवेश किया। प्लेट और जीन ड्रमंड ने लिखा है कि 'इन घणानिकों ने जो केवल अस्पष्ट सामाग आलोचित किया था। उनके बाद के लोग ने इस अस्पष्ट से माग की बज्ञानिक प्रगति के छोटे राजपथ में बदल दिया।' 1 फिर भी आज तक लोग अद्यविश्वासों और रूढ़ियों को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।

(4) भौगोलिक खोजें मध्यकालीन युग में यूरोप में बबर जातियों के आक्रमण के कारण अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई और यूरोपियन देशों का विदेशों से सम्पर्क टूट गया। मध्य युग में अंत में जब राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और आर्थिक शक्ति हुई तब यूरोपियन देशों ने दूर-दूर के देशों के साथ अपना सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया। इस वार उन्होंने एशिया के जलमार्ग द्वारा व्यापार करने का निश्चय किया। इसलिये आधुनिक युग के प्रारम्भ में ही यूरोपियन देशों ने नये जलमार्गों की खोज करने का निश्चय किया। इन खोजों से यूरोपियन देशों को अमेरिका का पता लगा और उसके साथ उन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया। भौगोलिक खोजों की प्रवृत्ति का जाग्रत करने में निम्न परिस्थितियों का योगदान रहा—

भौगोलिक खोजों के कारण भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण निम्न लिखित थे—

- (1) अरबवासी दूर-दूर के देशों से स्पष्ट तथा जल मार्ग के द्वारा व्यापार करते थे। जब घम युद्ध हुए तो यूरोपियनवासियों ने इन युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों से लौटने वाले यूरोपियनों की पूर्वी देशों के प्रति ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि हुई।
- (2) ईसाई धर्म के प्रचारक नये नये देशों में ईसाई धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना चाहते थे। मार्कोपोलो ने अपनी चीनी यात्रा का वर्णन तेरहवीं शताब्दी में लिखा। उसने इस मत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी गोल है और जहाजा के माध्यम से पूर्वी देशों में पहुँचा जा सकता है। मार्कोपोलो के विचारों का यूरोपियनों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब उनकी ससारा के विषय में जानने और उससे सम्पर्क स्थापित करने की जिज्ञासा में वृद्धि हुई।
- (3) यूरोप में आर्थिक शक्ति हुई जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। अब

यूरोपियनवासी अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिये पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिये उतावले हो उठे ।

- (4) यूरोपियनवासियों ने स्थल मार्गों द्वारा भारत और चीन में व्यापार करने का प्रयास किया किन्तु 1453 ई० में तुर्कों द्वारा कन्स्टान्टिनोपल पर अधिकार कर लेने से उनके लिये स्थल मार्ग द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का मार्ग अवरोधित हो गया । तबसे ही यूरोपियन देशों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिये नये जल मार्गों की खोज करना प्रारम्भ कर दिया ।
- (5) यूरोपवासियों ने कुतुबनुमा का प्रयाग अरबवासियों से सीखा । जिसके द्वारा अंधेरी रात में भी दिशा का पता लगाया जा सकता था । कुतुबनुमा ने यूरोपियन नाविकों के मानसिक बल में वृद्धि की ।
- (6) पुनर्जागरण के काल में मनुष्यों में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा बढ़ी । इससे प्रेरित होकर उन्होंने नये-नये देशों की खोज की ।
- (7) राष्ट्रीय राज्यों ने व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में विकास करने के लिये आवश्यकों की राजकीय सुरक्षा प्रदान किया ।
- (8) इस समय यूरोप की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़नी जा रही थी । इस बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिये नये-नये देशों की खोज करना आवश्यक हो गया ।

भौगोलिक खोजें— भौगोलिक खोजों में पुतगाल सबसे आगे था । इसी देश के बहादुर नाविकों ने उत्तरी अफ्रीका, भारत का पश्चिमी तट और अमेरिका की खोजें की । यूरोप के अन्य देशों में भी पुतगाल का अनुसरण किया ।

पुतगाल के राजा प्रिंस हर्नरी (1394-1460) ने जल मार्गों की खोज करने के लिये एक नाविक स्कूल की स्थापना की । इस स्कूल के नाविकों ने अफ्रीका के तटीय प्रदेशों की खोजें की । परन्तु कालम्बस, वास्कोडिगामा और मैगेलान ने भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर यूरोपियन देशों का मार्ग दर्शन किया ।

(1) कालम्बस (1451-1506) का योगदान—स्पेन का नाविक क्रिस्टोफर कालम्बस जिनात्रा का निवासी था । यह पहले पुतगाल के राजा के दरबार में नौकरी करता था । कालम्बस ने मार्कोपोलो के यात्रा विवरण और भूगोल के टोसकेनेली के लेखा को पढ़ने के पश्चात् पश्चिम के मार्ग से घूमकर भारत का जल मार्ग खोजने का निश्चय कर लिया । इस कार्य में उसे स्पेन की रानी ईसा बत्ता ने बहुत महत्वपूर्ण सहायता दी ।

3 अगस्त, 1492 ई० को कालम्बस तीन जहाजों में 28 व्यक्तियों के साथ भारत का जलमार्ग खोजने के लिये चल पड़ा । कनरी द्वीप में पहुँचने के पश्चात् वह

पश्चिम जिशा की ओर निरन्तर बढ़ता रहा। पाच मप्ताह तक धरती नहीं दिखाई दी। इस समय कोलम्बस बड़ी विकट परिस्थिति में फँस गया क्योंकि घम भीरु मल्लाहो ने विद्रोह कर दिया। 6 अक्टूबर को दूर क्षितिज पर पक्षी उड़न हुए उस दिखाई दिये और पाच दिन बाद कोलम्बस अमेरिका के 'वहामा द्वीप समूह' में जा पहुँचा। उसने दो अभियान और किये। अन्त में 1502 ई० में वह अमेरिका की खोज करने में सफल हुआ। 1506 ई० में इस महान नाविक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी खोज के कारण उन वाणी प्रसिद्धि प्राप्त हुई।

(2) वास्कोडिगामा का योगदान—1497 ई० में पुतगाली नाविक वास्कोडिगामा भारत के जल माग की खोज करने के लिये रवाना हुआ। 1498 ई० में वह भारत के दक्षिणी समुद्री तट पर स्थित कालीकट के दरगाह में जा पहुँचा। वास्कोडिगामा पहला व्यक्ति था, जिसने सब प्रथम भारत के जल माग की खोज की। उसकी इस खोज के कारण यूरोप में हलचल मच गई।

(3) मेगेल्लन का योगदान—मेगेल्लन ने भौगोलिक खोजों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेगेल्लन पुतगाल का रहने वाला था। स्पेन के राजा ने "मसालों के द्वीपों" का जल माग खोजने के लिये उसे अपने महा नौकरी दी। मेगेल्लन पाच पुराने जहाजों में तीन सौ बहादुर व्यक्तियों को लेकर मसालों के द्वीपों की खोज करने के लिये चल पड़ा। रास्ते में उसकी खाद्य सामग्री समाप्त हो गई, इसलिये उसे तथा उसके साथियों को समुद्री चूहे खाकर अपना गुजारा करना पड़ा। उनमें से काफी लोग मर गये थे। फिर भी मेगेल्लन ने फिलीपीन्स द्वीप समूह की खोज करने में सफलता प्राप्त की। इस द्वीप समूह में पहुँचते ही उसकी स्थानीय लोगों से झड़प हो गई जिसमें मेगेल्लन अपने कई साथियों के साथ मारा गया। इस संधप में एक जहाज किसी प्रकार बच निकला जो भफीका का चक्कर काटता हुआ स्पेन पहुँच गया। इस जहाज में 18 अघमरे नाविक पड़े हुए थे। मेगेल्लन की यह खोज ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

स्पेन और पुतगाल अमेरिका में अपने उपनिवेश बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस बात को यूरोपियन देश सहन नहीं कर सका। अब यूरोपियन देशों ने भी जलमार्गों की खोज करने के लिये साहसी नाविकों को भेजना प्रारम्भ कर दिया। इंग्लैंड के सर फ्रांसिस ड्रेक तथा जॉन हाक्सिन्स ने स्पेन के जहाजों और अमेरिका में स्पेन के अधिकृत प्रदेशों में लूटमार करना प्रारम्भ कर दिया। यूरोपियन देशों ने भी अमेरिका और पूर्वी देशों के साथ वापारिक सम्बन्ध स्थापित किये और वहाँ अपने उपनिवेश बनाये। कुछ ही समय में यूरोपियन देश अमेरिका और पूर्वी देशों में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए।

भौगोलिक खोजों के परिणाम — भौगोलिक खोजों का यूरोप के आधुनिक

इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान हैं। इन भौगोलिक खोजों के प्रमुख परिणाम निम्न लिखित हैं —

- (1) यूरोप के प्रत्येक देश ने खोजे गए देशों में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार साम्राज्यवादी भावनाएं विकसित हुईं। यूरोपियन देशों में अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई। कोई भी देश इस प्रतिযোগिता में पीछे नहीं रहना चाहता था। साम्राज्य स्थापित करने की प्रतियोगिता के कारण यूरोपियन देशों में आपसी मतभेद और तनावपूर्ण वातावरण का सूत्रपात हुआ, जिन्होंने कई शताब्दियों तक संसार को आनातल पर दिया।
- (2) यूरोपियन देशों ने इन देशों में निरक्षरता पूर्वक शासन किया और इनका आर्थिक शोषण करके अपनी शक्ति में वृद्धि करने में सफल हुए।
- (3) यूरोपियन देशों ने इन देशों के साथ व्यापारिक सम्बंध स्थापित किए और अपने देशों में उद्योग और व्यापार का विकास करने में सफल हुए। वे इन देशों से कम मूल्य पर कच्चा माल प्राप्त करते थे और मशीनों का बना हुआ माल इनमें बेचते थे। इनका परिणाम यह हुआ कि यूरोपियन देश समृद्धशाली होते गये और इनकी आर्थिक दशा गौर्धनीय होती गई। यूरोप में व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति हुई और उसका सभी यूरोपियन देशों में धीरे धीरे प्रसार हुआ। जिसके फलस्वरूप यूरोपियन देशों का व्यापार विकसित हुआ और वे समृद्ध बन गये।
- (4) भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपियन देश अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को हल करने में सफल हुए। उन्होंने अमेरिका आदि कई देशों में काफी संख्या में यूरोपियन लोगों को बसाया।
- (5) यूरोपियन देशों के सम्पर्क के कारण विश्व के असभ्य, अर्द्ध-सभ्य और पिछड़े हुए देश विज्ञान के क्षेत्र में विकास कर सके।
- (6) यूरोपियन देशों के सम्पर्क ने उसके अधीन देशों की कला एवं साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया।
- (7) दूर देशों में बसे यूरोपियनों के लिए धार्मिक क्रियाओं का कठोरता से पालन करना सम्भव नहीं था। इसके फलस्वरूप वे धर्म का आडम्बर से मुक्त होने लगे और भौगोलिक खोजों के कारण उनके धर्म में वृद्धि हुई। जिसके फलस्वरूप धर्म सुधार का दोलन प्रारम्भ हुआ।
- (8) अमेरिका अफ्रीका व आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों पर यूरोपियनों द्वारा भयंकर अत्याचार किया गया। उन्होंने इन देशों के निवासियों को पकड़ कर यूरोप में बाजारों में गुलामों के रूप में बेचना शुरू कर दिया। यूरोपियनों ने वहाँ की मूल सभ्यता को नष्ट कर ईसाई धर्म का प्रचार किया।

इस प्रकार जमीन जैसे पिछड़े हुए देश में यूरोपियन ने अपनी सभ्यता एवं सस्कृति का प्रसार किया। भारत और चीन आदि देशों में भी यूरोपियन देशों का व्यापार का बहाना लेकर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। इस प्रकार यूरोप सम्पूर्ण ससार का भाग्य विधाता बन गया।

पुनजागरण के प्रभाव, — पुनजागरण के कारण साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। इससे मनुष्य प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हुआ। पुनजागरण के निम्नलिखित प्रभाव हुए —

(1) राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव —

- (i) संयुक्त यूरोप का कई राष्ट्रीय राज्यों में विभाजन हुआ गया।
- (ii) यूरोप में सामन्तता की शक्ति समाप्त हो गई और उसके स्थान पर शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष सम्भव हुआ।
- (iii) पोप का राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप समाप्त हो गया।
- (iv) जन-साधारण में राष्ट्रीय भावनाएँ विकसित हुईं।
- (v) शक्तिशाली राष्ट्रों में साम्राज्यवादी भावना का विकास हुआ।
- (vi) पुनजागरण के कारण जनता राज्य को ईश्वर की कृति के स्थान पर मानव का कृति मानने लगी। इसलिए अब जनता शासक के गलत कार्यों की आलोचना करना अपना कर्तव्य समझने लगी।

(2) धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव —

- (i) जनता में धार्मिक अविश्वास धीरे-धीरे समाप्त होने लगा।
- (ii) पोप का प्रभाव जनता पर से धीरे-धीरे समाप्त होने लगा। फलस्वरूप यूरोप में धर्म सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।
- (iii) जन साधारण ने रोम की अपेक्षा अपने राष्ट्र को अधिक महत्त्व देना शुरू किया।
- (iv) अब लोग न धर्म क्षेत्र में भी स्वतन्त्र रूप से चिन्तन करना प्रारम्भ कर दिया।

(3) सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव —

- (i) मानववाद का विकास सम्भव हो सका।
- (ii) व्यापारिक वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई।
- (iii) कुलीन वर्ग के लोगों के सम्मान में कमी आई।
- (iv) जनता में शिक्षा का विकास होने लगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनजागरण मानव सभ्यता के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुनजागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने विज्ञान, कला साहित्य और व्यवसाय के विकास का माग प्रशस्त किया। इसी माग पर चलकर मानव अपनी आधुनिक सभ्यता एवं सस्कृति का निर्माण करने में सफल हो सका।

प्रस्तावित सद्म पाठ्य पुस्तकें —

- 1 नेहरू, जवाहरलाल—विश्व इतिहास की क्षत्रक
- 2 मेवाइन—ए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाईजेशन
- 3 एलिम और जोन—मसार का इतिहास
- 4 प्लेट, जोन और ड्रमंड—विश्व का इतिहास
- 5 बीच, डब्ल्यू० एन० —हिस्ट्री आफ दी वर्ल्ड



धर्म सुधार आन्दोलन

धर्म-सुधार आन्दोलन पुनर्जागरण की देन है। मध्य युग में सर्वोच्च धर्माधिकारो पोप था। उस समय पोप तथा पादरियो का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था। पोप तथा अन्य धर्माधिकारी धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च अधिकारी थे। पोप जिस व्यक्ति को चाहता उसे सम्राट बना सकता था और जिसे वह नहीं चाहता उसे गद्दी से हटा सकता था। उस का व्यक्तिगत जीवन पवित्र नहीं था। धर्माधिकारियों के पास अपार धन सम्पत्ति होने के कारण वे विलासितापूर्ण जीवन यत्नीत कर रहे थे। उस समय धर्माधिकारी धन संग्रह करने के लिये जनता से नाना प्रकार का कर वसूल करते थे। इतना ही नहीं उस समय जनता को स्वर्ग में भेजने का प्रलोभन देकर नियत मूल्य पर पोप द्वारा मोचन पत्र भी बेचे जाते थे।

मध्य युग में धर्माधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दिया था और उन्होंने कई प्रकार के अंध विश्वास प्रचलित कर दिये ताकि जनता पर उनका प्रभाव बना रहे। चर्च के बढ़ते हुये प्रभाव का घणन करते हुए वेवेस्टर ने तो यहाँ तक लिखा है कि मध्यकालीन युग में मनुष्य ने अपनी आत्मा व शरीर को चर्च को सौंप दिया था।

इस प्रकार वभवता धर्माधिकारियों के चरणों में लौट रही थी। जन साधारण को पादरियो के आदेशों का पालन करना पड़ता था। कोई भी व्यक्ति उनके आदेशों की आलोचना नहीं कर सकता था। निकोलस पंचम ने प्रजातान्त्रिक भावना को कुचल दिया। उसके समय में यदि कोई व्यक्ति पोप से वाद विवाद करता था तो उसे या तो फाँसी दी जाती थी या देश में निर्वासित कर दिया जाता था। उस समय यूरोप में केवल कथोलिक धर्म ही लोकप्रिय धर्म बना हुआ था।

धर्म सुधार आन्दोलन का अर्थ—वारनर और मार्टिन ने लिखा है कि धर्म सुधार आन्दोलन पोप पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक

विद्रोह था। वास्तव यह एक धार्मिक क्रांति थी जिसका सम्बन्ध धर्म से था। मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जनता पर भयंकर भयाचार किये जा रहे थे। मध्य युग के अन्त तक पुनर्जागरण के कारण मानव का बौद्धिक विकास हुआ। जिसके कारण यूरोप का व्यक्ति प्रत्येक विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक विचार एवं चिन्तन करने लगा। अब जनता पोप के अत्याचारा को सहन करने के लिये तैयार नहीं थी। इसलिये उस समय यूरोपियन ने चर्च के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास किया। उन्होंने कथोलिक धर्म में व्याप्त बुराईयाँ और आडम्बरो को दूर करने का हर सम्भव प्रयास किया। अब यूरोपियन विद्वानों ने धर्म में प्रचलित प्रभाव से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से चिन्तन करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार पुनर्जागरण ने धर्म सुधार व आन्दोलन का माग प्रशस्त कर दिया।

प्रोफसर डेविस ने लिखा है कि— यदि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आन्दोलन को एक दूसरे का सहयोगी कहा जाय तो गलत नहीं होगा।

पुनर्जागरण की तरह यूरोप में 16 वीं शताब्दी में एक धार्मिक क्रांति हुई, जिसे धर्म सुधार आन्दोलन कहा जाता है। पोप का धर्म के साथ-साथ राजनीति में भी अनुचित प्रभाव था। उस समय राजा, प्रजा, अमीर, गरीब ने चर्च की बुराईयाँ का दूर करना, पादरियों के विलासितापूर्ण जीवन पर प्रतिबंध लगाना, पोप के प्रभाव को चुनौती देना, चर्च के आडम्बर और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिये जो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया उसे यूरोपियन इतिहास में धर्म सुधार आन्दोलन के नाम से जाना जाता है।

वेन पिगर ने लिखा है कि— प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आन्दोलन को चर्च की बुराईयाँ के विरुद्ध सफलता मिली। इतिहासकार डब्ल्यू० एन० बीच ने लिखा है कि— 'धर्म सुधार आन्दोलन ही था, जिसने ईसाई धर्म सगठन का आखिरी चिह्न भी मिटा दिया, रेनसा का काय पूरा किया और यूरोप के भिन्न भिन्न भागों में जाग्रत मत भेदों को स्पष्ट और स्वाई बना दिया।'¹ एलिस और जौन ने लिखा है कि— "जिन दिनों यूरोप के लोग नये व्यापारिक माग व नये देशों की खोज कर रहे थे और अपने जगत का विस्तार कर रहे थे, उन्हीं दिनों ईसाई धर्म के अन्दर कुछ नये परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे थे। व्यापार और साम्राज्यवादी भावनाओं के साथ ईसाई धर्म का सुधार आन्दोलन भी गुरु हुआ।"²

मैकनल वनसन ने इस क्रांति को प्रोटेस्टेंट क्रांति के नाम से पुकारा है। रोमन कथोलािक धर्म में व्याप्त शोषों को दूर करने के लिये धर्म-सुधार आन्दोलन

1—बीच, डब्ल्यू० एन०—हिस्ट्री आफ दी चर्च, पृ 54।

2—एलिस और जौन—ममार का इतिहास, पृ 262

आरम्भ हुआ था। मार्टिन लूथर ने 1517 ई० में अपने वक्तव्यों में इस आन्दोलन को प्रारम्भ किया जिसने 1600 ई० में जाकर सफलता प्राप्त की।

धर्म आन्दोलन के उद्देश्य — धर्म आन्दोलन के निम्न उद्देश्य थे —

(I) धर्म सुधारकों का पहला उद्देश्य धर्म में याप्त धुराईयों और धर्माधिकारियों में याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना था।

(II) धर्म सुधारकों का दूसरा उद्देश्य धर्म में याप्त आडम्बरो को दूर करना और पादरियों के नतिक जीवन को उच्च बनाना था।

(III) उस समय पादरियों में विलासितापूर्ण जीवन यतीत करना प्रारम्भ कर लिया। इसलिये पवित्र जीवन यतीत करने के लिये मनुष्यों के लिये यह सम्भव नहीं था कि वे पादरियों के साथ रहकर चर्च में ईश्वरोपासना कर सकें। इसलिये ऐसे मनुष्यों ने चर्च में सुधार करने की माग की।

धर्म सुधार आन्दोलन के कारण — पुनर्जागरण के कारण यूरोपवासियों ने स्वतंत्र रूप से चिन्तन करना प्रारम्भ कर दिया था। जिसके कारण मध्य युग की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में काफी परिवर्तन हुआ। चर्च का जनसाधारण पर अभी तक बहुत अधिक प्रभाव था। इसी प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और सुधारों की माग की जाने लगी, जिसके कारण धर्म सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इस धर्म सुधार आन्दोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(1) राष्ट्रीय भावना की जगति — पुनर्जागरण के प्रभाव से यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ। इसलिये यूरोपियन जनता यह नहीं चाहती थी कि उनके राष्ट्र का धन कर के रूप में रोम के पाप के खजाने में जाये। परिणामस्वरूप पोप के विरुद्ध आन्दोलन होना स्वाभाविक हो गया।

(2) पोप की विलासिता 15 वीं शताब्दी में पोप का नतिक स्तर गिर चुका था और उसने विलासितापूर्ण जीवन यतीत करना प्रारम्भ कर दिया था। पोप जनता पर अनेक प्रकार के कर लगा कर धन संग्रह कर रहा था। इस संग्रहित धनराशि को वह अपने जीवन को सुखी बनाने में खर्च कर देता था।

सेवोनरोला ने लिखा है कि प्रत्येक भ्रष्ट परम्परा रोम से प्रारम्भ होती है और इसके पश्चात् यूरोप में उसका प्रसार होता है। उसने इस सम्बन्ध में लिखा है कि— 'यद्यपि रोम और यूरुसे भी निकृष्ट हैं। रोम में तुम पाओगे कि भौतिक उपयोग की सभी वस्तुएँ अनतिक्रमिक तरीके से प्राप्त की जाती हैं। पोप अपने बच्चों तथा भाईयों को बहुमूल्य वस्तुएँ बाँट देते हैं। उनको महत्वाकांक्षा को कभी सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता है। वे सिर्फ स्वर्ण और पद के लिये ही घटिया बजाते हैं। यदि कोई पादरी साधारण और मरन जीवन यतीत करना चाहता है तो उस पर 'यग कस जाते हैं। उसे धोखेबाज बट्टा जाता है। जनता यह कहने

से नहीं चुकती कि यदि तुम अपने बच्चे के जीवन का नष्ट करना चाहते हो तो उम पादरी बना दो।”

पोप ग्रेगरी सप्तम ने अपने राज्य, जागीरो व धन सम्पत्ति को अपने सम्बन्धियां भ बांट दिया था। उस समय पोप न एशो आराम पूर्वक जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया था। वैभव व मद में चूर पोप अनेकजण्डर पप्टम के वार म इतिहासकार देन पिगर न लिखा है कि—“पोप बनते ही उमन अपना ध्यान धन और शक्ति के सचय म लगाया। वह धनी, अग्रिमहीन राजनीतिग था।”

पोप पप्टम धीरे धीरे इतना अधिक विलासी और भ्रष्ट हो गया कि वह अपने धार्मिक कर्तव्या को भूल गया। उमका जनता पर प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसक समय म हर रात को तीन चार नाशे राम की सडवा पर पडी हुई मिलती थी। पोप पप्टम उस समय अपनी आलाकिक वीवीया व साथ रग रेलिया मना रहा था, जबकि अन्य पातरिया व लिण जीवन थापन करना भी मुश्किल था। बनस न लिखा है कि— अलेक्जण्डर पप्टम की स्वर्गीय वगमा न आठ अबघ बच्चो को जम दिया, जिनम से सात बच्चे उसके पोप बनन मे पहले ही जम ले चुके थे।¹

(3) पोप का राज्य कार्यों में हस्तक्षेप —

(1) पोप का राज्य के आंतरिक मामला म हस्तक्षेप—पोप द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करन व कारण धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारम्भ हुआ। उमका ग्टनी के एक बहुत बडे भाग पर अधिकार था। सालमन के समय से ही पाप न राज्य के घरेलू मामलों म हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। यूरोपियन राजाओ का राज्याभिषेक पोप की स्वीकृति मे किया जाता था। वह राज्यो के आंतरिक और वैदेशिक मामलो में हस्तक्षेप करता था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पोप जिस व्यक्ति को चाहता वही सम्राट बन सकता था और जिस सम्राट को वह नहीं चाहता उम पर आरोप लगाकर सिंहासन से हटा सकता था। यदि कोई सम्राट पोप व आदेश का विरोध करता था तो पोप उसे चर्च मे निष्कासित कर देता था। जमे कि पोप ग्रेगरी सप्तम ने राजा हनरी चतुथ को चर्च से बहिष्कृत किया था। उस प्रकार का बहिष्कार उस शासक के लिये सामाजिक मौन के समान था। अन्त ही नही पोप उस शासक की प्रजा को उसके आदेश का पालन न करन का आदेश दे सकता था। विभिन्न दशा के विश्व भी राज्य कार्यों मे हस्तक्षेप करते थे। राजा पोप के खर्च के लिये प्रतिबध बहुत बडी धन राशि उम देता था। विरोधियो को पोप जिंदा जलवा देता था। पोप की स्वाकृति व बिना उम समय शासक शादी व तलाक नहीं दे सकते थे। इन प्रकार पोप का राजनीतिक क्षेत्र में असोमित प्रभाव था।

दूसरी तरफ पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण राजा-राजो शक्ति में वृद्धि हो चुकी थी और राष्ट्रीय राज्या का उत्कर्ष हो चुका था। ऐसी समय राजा लोग राज्य कायों में पोप के हस्तक्षेप का सामना करना चाहते थे। इसीलिए दोनों के बीच सघर्ष अवश्यम्भावी हो गया।

रोम का पोप धर्म का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण विभिन्न देशों के धर्माधिकारियों को नियुक्त करना अपना अधिकार मानता था। परन्तु यह बात राजाओं के लिये असहनीय थी क्योंकि राजा अपने-अपने राज्या में अपनी-अपनी सत्ता को सर्वोपरि मानते थे। इसलिये वे चाहते थे कि अपने राज्य में चर्च के धर्माधिकारियों की नियुक्ति के स्वयं करें। इसका एक कारण यह था कि पोप राजा के विरोधी व्यक्तियों को ही धर्माधिकारियों के पद पर नियुक्त करता था। इससे राज्य में वे धर्माधिकारी कई प्रकार की समस्याएँ खड़ी कर देते थे।

(ii) चर्चों की याय व्यवस्था—पोप द्वारा राज्य के समस्त भागों में 'यायालय' स्थापित किए जा चुके थे। यह 'यायालय' राजाओं और पोप के बीच सघर्ष के कारण बने। सामंजस्य के समय रोमन यायालय और कानून की समाप्ति होने के कारण चर्च ने लोगों को याय प्रदान करने के लिये समस्त देश में अपने 'यायालयों' की स्थापना की। पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के पश्चात् भी कई मामलों में चर्च के यायालय अपना फसला देते थे। राजा-राजो ने अपने यायालयों का महत्त्व कायम करने के लिए चर्च के यायालयों का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया।

चर्च के यायालयों को लेकर राजा-राजो और पोप के बीच वाद विवाद प्रारम्भ हुआ। कई बार ऐसे अवसर भी जाते थे कि एक ही मामले पर राज्य का यायालय और चर्च का यायालय दोनों ही फसला दे देते थे। तब विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। चर्च के यायालय राज्य के यायालय के फसले को खारिज कर देते थे। जनता इन धार्मिक यायालयों से परेशान हो चुकी थी। उस समय चर्च विश्वत छोटी और भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गए थे। पुनर्जागरण के कारण जनता की सहानुभूति राजाओं के साथ थी।

(iii) शासकों की महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि—पुनर्जागरण के कारण राजाओं की शक्ति में वृद्धि हो चुकी थी। अब राजा अपनी इच्छानुसार शासन करना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि पोप उसके कायों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें। राजा धर्म को अपने प्रभाव क्षेत्र से अलग मानने के लिये तैयार नहीं थे। अब राजाओं ने अपने राज्यों में चर्च की स्थापना की, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। राजा का यह काय पोप और उसके बीच सघर्ष का कारण बना।

(iv) चर्च द्वारा धार्मिक कर वसूल करना—उस समय चर्च जनता से धार्मिक कर वसूल कर धन का संग्रह कर रहा था। राजाओं ने पोप के इस काय का

विरोध किया। जनता भी इस कर को चुकाने के विरुद्ध थी, क्योंकि पोप कर से संग्रहित धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन पर करता था।

(v) विरोधियों को राजकीय संरक्षण—उस समय सम्राट् ने पोप के प्रभाव का समाप्त करने के लिये उनके विरोधियों को राजकीय सहायता और संरक्षण देना प्रारम्भ कर लिया। यदि राजा योग सुधार आदिमा की सहायता नहीं करते तो वे अपने आन्दोलन में इस सीमा तक कभी सफल नहीं हो सकते थे। डी० जे० हिल ने लिखा है कि 'यदि प्रोटेस्टेंट आन्दोलन केवल धार्मिक आन्दोलन ही होता तो यह अपने सृजनकर्त्ताओं के जीवन काल तक भी न पनप पाता। जिस वस्तु ने इस सफल बनाया वह थी, इसमें राजनीतिक उद्देश्य तथा प्रभाव और विशेषकर कूटनाति।'

यह सत्य है कि लूथर के पूर्वाधिकारी धम सुधारका का शासना का सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण पोप ने उन्हें मृत्यु दण्ड दे दिया लेकिन लूथर को राजकीय सहायता प्राप्त होने से पोप उस को दण्ड नहीं दे सका।

(4) धर्माधिकारियों के नतिक स्तर में गिरावट धर्माधिकारियों के नतिक स्तर में गिरावट होना भी धम सुधार आन्दोलन का कारण बना। मध्ययुग में पादरी अपने नतिक्यों को भूल चुके थे और पोप की तरह विलासी जीवन-यत्नीत कर रहे थे। चर्चों में पादरियों के साथ स्त्रियाँ भी साधु के रूप में रहती थीं। उनके साथ पादरियों के अनतिक सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे। पाप ने जनता पर अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिए और भोग विलास में डूब रहने लगे। उस समय धर्माधिकारी विवाह नहीं करते थे लेकिन चर्चों में उनके अवयव बच्चे 'यीसू' की सत्तान के नाम से पाले जाते थे।

उस समय बहुत से पादरियाँ न शादियाँ भी कर ली थीं और चर्च का धन वे अपना विलासिता पर खर्च करने लगे। कालांतर में ईसाई चर्च में मठ अत्याचार के बन्धन बंध गए। पाप की विलासिता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि उस समय का सबसे प्रसिद्ध पाप अलेक्जेंडर पण्टम अपनी वीधियों के साथ भोग विलास में डूबा हुआ था, जबकि वे पादरियों के लिये जीवन यापन करना कठिन था। इस प्रकार पोप स्वयं इस सुधार आन्दोलन के लिये जिम्मेदार था। धर्माधिकारियों का नतिक पतन ही जनता के कारण जनता उन्हें घणा की दृष्टि से देखने लगी।

(5) रोम के वैभव का विरोध—मध्य युग में रोम ईसाई धम का प्रसिद्ध नगर था। ईसाई धम का सर्वोच्च अधिकारी पोप रोम में निवास करता था। पोप ने रोम में नये गिरगाघरा का निर्माण करवाया। कलाकारों ने अपनी कला कृतियों से रोम का सुन्दर और आकर्षक नगर बना दिया। सभी यह जानते थे कि रोम का पाप जनता के पक्ष पर ऐश आरामपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है और रोम के वैभव में वृद्धि कर रहा है। पटली के बाहर वाले यह नहीं चाहते थे कि उनके पैसे

से रोम के बभ्रव में निरंतर वृद्धि होती रहे। रोम की विलासिता को देखकर स्वयं मार्टिन लूथर ने यह कहा था कि 'रोम का पोप ऐसा चोर व डाकू है जसा आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ और न होगा। हम दीन जमना को घोषा दिया गया है। हम पदा तो स्वामी बनने के लिये हुए हैं और हम झुकने के लिये बाध्य किया है।

(6) चर्च की आंतरिक दुबलता—रोमन चर्च की आंतरिक दुबलता के कारण घम सुधार का दालन प्रारम्भ हुआ। चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कई घम सुधारको 7 पोप तथा पादरिया का ध्यान आकर्षित किया। बाई क्लिफ तथा जान हस ने जब चर्च में सुधार करने की माग की तो पोप ने उन्हें सजा दी।

15वीं शताब्दी में कौंसिलर आ गेलन प्रारम्भ हुआ। उस समय चर्च में सुधार का प्रारूप तय किया गया परंतु पोप के हस्तक्षेप के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। धीरे धीरे पाप का ईसाई समाज पर प्रभाव कम होता जा रहा था। कुछ समय के लिये तत्कालीन पोप ने फ्रांस के राजा की शरण ली और बाद में पोप पद के लिये दो उम्मीदवार उठ खड़े हुए। एक उम्मीदवार को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था दूसरे को इटली का समर्थन प्राप्त था। पोप पद के लिये होने वाले इस संघर्ष के कारण जनता की पोप के प्रति निष्ठा कम हो गई। इस संघर्ष से पहले जनता पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानती थी। अब जनता ने सोचा कि पोप धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि कस हा सकते हैं? यदि उनका निर्वाचन फ्रांसीसी राजा करा सकता है।'

1377 ई० से 1417 ई० तक चर्च के सदस्यों के सामने यह समस्या थी कि वे किस अपना पोप मानें। इस घटना से चर्च की एकता को भारी धक्का पहुंचा। पुनर्जागरण के प्रभाव तथा कुछ प्रगतिशील पादरियों के सहयोग के कारण इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में राष्ट्रीय तथा स्थानीय देश भक्ति की भावनाएँ जाग्रत हो चुकी थी और यहाँ के निवासी पोप के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे।

(7) मानववादी विचारधारा—रोमन कथोलिक चर्च के अनेक पादरियों ने मानववादी विचारधारा को स्वीकार कर लिया था। जिनमें ईरस्मस भी था। जिसने चर्च में प्रचलित बुराईयों पर प्रकाश डाला। मानववादी विचारधारा के समर्थक घम में प्रचलित बुराईयों की जालोचना करते थे। पुनर्जागरण के कारण मनुष्य ने स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करना प्रारम्भ कर दिया। अब वह किसी भी बात को तर्क पर सही उत्तर देने के बाद ही स्वीकार करता था। अब मानव पोप के आदेशों

को और धर्म में व्याप्त अध विश्वासों को आँख मूंदकर स्वीकार नहीं करता था। चर्च में घूणा एवं अहंकार की भावनाएँ मौजूद थीं, जबकि पुनजागरण के काल का मानव, धर्म और महानुभूति में विश्वास करता था।

मानववाद के विकास के साथ साथ आम जनता में रोमन कैथोलिक धर्म के विरुद्ध असंतोष में वृद्धि होती जा रही थी। इरस्मस ने जब चर्च में व्याप्त बुराईयाँ पर प्रकाश डाला तो उसे पाछुण्डी की सजा ली गई। इस सत्यता को मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मानववादी विचार धारा ने धर्म सुधार आन्दोलन की नींव रखी थी और इसी के विचारों को मार्टिन लूथर ने साकार रूप प्रदान किया था।

(8) भौगोलिक अनुसंधान का प्रभाव—यूरोपियन देशों ने नए-नए देशों की खोज की और वहाँ पर अनेक ईसाई लोग जाकर बस गये। इन नवीन देशों में जाकर बस हुए ईसाईयाँ के लिये धर्माधिकारियों द्वारा बतलाई गई धार्मिक क्रियाओं का पालन करना असंभव था। वे अन्व देशों से सम्पर्क में आये, जिसके कारण उनके पान में वृद्धि हुई। अब वह धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करने लगे।

(9) धर्माधिकारियों का सासारिक जीवन—धर्माधिकारियों के पास बड़ी-बड़ी जागीरें और अपार धन सम्पत्ति थी। इसलिये उन्होंने विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। पाप पाल तृतीय और अलेक्जेंडर षष्ठम के समय मेंट में अधिक धन देने वाले पादरियों को शाही सम्मान दिया जाता था। उस समय चर्च भ्रष्टाचार और विलासिता के क्षेत्र में बढ़ गये थे। पादरी जनता से बलपूर्वक धन वसूल करते थे।

16वीं शताब्दी में पादरी गिरजाघर में सिर्फ उसलिये घटिया बन्नाने थे कि उन्हें स्वर्ण और पद प्राप्त हो सके। उस समय पादरियों के द्वारा गिरजाघरों का निर्माण करने के लिये और उन्हें सुन्दर बनाने के लिये जनता से बलपूर्वक धन वसूल किया जाता था। जनता इस प्रकार पादरियों का धन देने में पक्ष में नहीं थी। उस समय पादरी अपने कार्यों से यूरोप में बुरी तरह से बदनाम हो चुके थे। मज्जन यक्ति चर्च में जान से बचता था।

पोप लिओ दशम (1513-1521) ने तो चर्च के पदों को बचकर पसे कमान का धंधा शुरू कर दिया। उसने अपने महल को हीरे जवाहरात और सुन्दर कालीनों से सजाया। उस समय अन्य पादरियों ने भी लिओ दशम का अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया। सवात्न ने लिखा है कि 'उन्होंने अपने धार्मिक कर्तव्यों की अवहेलना की और सामंती की तरह रहने लगे' 11

उस समय भ्रष्ट गिरजाघर और पाप का विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना धर्म सुधार आन्दोलन का आधार बना। पादरियों की दशा का वर्णन करते

हुए मकनल वनम न लिखा है कि 'अनेक क्यालिज पादरी इतन जगानी ये कि विश्वास नही किया जा सकता । व जनता म प्रचलित साधारण लटिन भाषा म भी परिचित नही थे । ऐस भी पादरी ये जो प्रमु की प्राधना और दनिन धार्मिक मतव्य भी नही बोल सकते थे । इमते भी आगे अधिकाश पादरी बन्नाम जीवन बिता रहे थे ।" १

कई पादरिया न अपने भोग विलास व लिय एम अड्डे बना रखे थे जग जुम्राँ और शराब आदि विक्रम था । अब तक जनता यह जान चुकी थी कि चर्च म कितन ऐस भ्रष्ट और निरक्षर धर्माधिकारी हैं । उस समय इस बात की अपवाहें फल रही थी कि कोई भी सांसारिक ब्यक्ति धन नेकर चर्च के ऊँचे स ऊँचे पद को खरीद सकता है और फिर वह जनता का शोषण कर सकता है । ऐसी घटनाओ से चर्च की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा । पादरिया की बदनामा व कारण धम मुधार आन्दोलन तेजी स प्रारम्भ हुआ ।

(10) धार्मिक विद्रोही — 13वीं शताब्दी म पोप इनोमट तृतीय व समय दक्षिण फ्रान म चर्च म व्याप्त बुराईयो के विरुद्ध धार्मिक विद्रोह प्रारम्भ हुए । दक्षिणी फ्रांस के एन व्यक्ति आल्विग ने खुले तौर पर पोप की आलोचना की । उसने संस्कार के महत्त्व को मानने स इन्कार कर दिया । सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाल पादरिया की कट्टु जानोचना की और अपनी एक स्वतंत्र चर्च का अलग से स्थापना की । पोप न अपनी शक्ति स आल्विग और उसका अनुयाईया को कुचल दिया । आल्विग व अनुयाई आल्विग स क नाम स प्रसिद्ध हुए ।

पहला धम विद्रोह अभा पूण रूप स समाप्त ही नही हुआ था कि दक्षिणी फ्रांस म इस समय दूसरा धार्मिक विद्रोह प्रारम्भ हो गया । इस धार्मिक विद्रोह का नेतृत्व पादरी वाल्टर स कर रहा था । इमन कहा कि मनुष्य का सिर्फ उन बातों का पालन करना चाहिये जो बाइबिल म लिखी हुई हैं । पाप जो आदेश नेता है उसका पालन नही करना चाहिये । उसन अधिक धन सम्पत्ति का संग्रह करना, युद्ध करना बुरा माना और पोप म निष्ठा न रखन की अपील का । पोप ने वादस पर धमद्रोही का अपराध लगाकर उस जितना जलवा दिया । प्रत्यक्ष रूप स तो यह आन्दोलन समान हा चुका था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप म शक्ति व बीज धीरे धीरे विकसित होने जा रहे थे । आल्विग और बाद त क बलिदान महत्वपूर्ण सिद्ध हुए । इन बलिदानों न धम मुधार आन्दोलन को बल प्रदान किया ।

फ्रान्स की तरह इंग्लैण्ड म भी धम मुधार आन्दोलन आरम्भ हुआ । यहा पर इस आन्दोलन का नेतृत्व एक अग्रज प्रोफेसर पादरी वार्डनिकस कर रहा था । उसने यह प्रचार किया कि बाइबिल ही हमारा सर्वोच्च प्रमाणिक धार्मिक ग्रन्थ है न

कि पोप के आदेश। उसने चार्डविल का अग्रणी भाषा में अनुवाद किया और तीर्थ यात्रा, सस्कार और सामारिक पादरियों की पूजा की बुराइयों पर प्रकाश डाला। उसका मानना था कि राजनीतिक दृष्टि से राजा पोप से भी अधिक महान है। इससे उम राजा का सम्मान प्राप्त हो गया। इसके पश्चात् उसके शिष्य लोदारों ने इस बात का प्रचार किया कि सभी मनुष्य एक समान हैं। उसने कुलीन वर्ग के व्यक्तियों और युद्धों का विरोध किया। परिणामस्वरूप गरीबों और किसानों ने धनवान व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस पर शासक ने लोदारों पर राज्य द्रोह का अपराध लगाया और पोप ने उसे पाखण्डी और धमद्रोही घोषित किया। इसके पश्चात् लोदारों को जिंदा जला दिया गया और उसके साथियों का बुगी तरह से दमन किया गया। इतना ही नहीं पोप ने 1415 ई० में चार्डविलफ की लाश को कब्र से निकाल कर उसे भी पाखण्डी घोषित किया और इसके बाद उसे जला दिया गया।

चार्डविलफ के विचारों का प्रसार जॉन हस (1373-1415 ई०) ने आधुनिक चरित्रवाकिया के एक भाग बोहीमिया में किया। इस पर पोप ने उसे पाखण्डी घोषित किया और उसे पकड़कर जिंदा जला दिया गया। प्लट और जॉन ड्रमड ने लिखा है कि अपने अनुपाईया सुसवादियों के लिए प्रोपसर हम एक जातीय वीर और साथ ही धार्मिक शहीद बन गया।¹

ये धार्मिक बलिदान व्यर्थ नहीं गये। इन बलिदानों ने धर्म सुधार आन्दोलन की नींव का मजबूत कर दिया।

(11) साहित्य के क्षेत्र में जागरण—पुनर्जागरण के प्रभाव से साहित्य के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ जिनमें से एक धार्मिक साहित्य भी था। इस समय चार्डविल का सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका था। अब कोई भी व्यक्ति चार्डविल को पढ़ सकता था। उसे पादरी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। अब धर्म की वास्तविक बातें जनसाधारण के सम्पर्क में आईं।

इस समय का प्रसिद्ध लेखक इरासमस था जो हीलेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा था। इरासमस का जन्म 1466 ई० में हीलेण्ड के राटडूरम नामक नगर में हुआ था। इटली, जर्मनी, पेरिस और आवसफोर्ड में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् पादरी बना। यह गिरजाघरों में अनेक परिवर्तन करना चाहता था और पादरियों के जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना चाहता था। उसने तीन पुस्तकें लिखीं, जिन्होंने इसाई जगत में हलचल मचा दी।

उसकी पहली पुस्तक 'पाविट डगार' का प्रकाशन 1503 ई० में हुआ। इसमें उसने पादरी की आवश्यकता का वर्णन किया है और प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर के प्रति उत्तरदायी माना है। उसने दूसरी पुस्तक दी प्रिजे आफ दी फाली (सुखता

की प्रशंसा) लिखी। इसमें उसने पारिषो के आडम्बरपूर्ण जीवन पर अनेक-यग कसे हैं। इस पुस्तक में इरासमस को काफी प्रशंसा मिली। उसकी तीसरी पुस्तक 'यू टेस्टामेंट' 1516 ई० में प्रकाशित हुई। यह धार्मिक साहित्य से सम्बन्धित थी। इस पुस्तक ने उम अमर बना दिया। इन सभी पुस्तकों से चर्च की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँचा। इसलिए यह कहा जाता है कि इरासमस ने क्रांति के अडा को जन्म दिया और लूथर ने उह विकसित कर शरीर का रूप प्रदान किया। साहित्य के क्षेत्र में जाग्रति आने के कारण लूथर का नाम आसान हो गया। इरासमस ने पोप को जितनी हानि पहुँचाई उतनी लूथर नहीं पहुँचा सका।

(12) शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति—मध्ययुग में मठों या गिरजाघरों में पाठ रिया के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। उस समय की शिक्षा प्रणाली समाज में अनुकूल नहीं थी। पारिषो चर्चों में लेटिन भाषा में शिक्षा देते थे। चर्चों में सिर्फ जमीरों और सामंतों के बच्चे पढ़ते थे। कृपक गुलाम और कारीगर आदि जनसाधारण के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। शिक्षा पर धर्माधिकारियों का पूरा रूप से नियंत्रण था। धर्माधिकारी ही शिक्षक के विषय पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति निश्चित करता था। चर्चों में किसी विषय पर विद्यार्थी तक वितक नहीं कर सकते थे। इसलिए उस समय जनता चर्च द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के विरुद्ध थी।

पुनजागण के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास होता जा रहा था। इसलिए उस समय में मानव ने प्रचलित ज धविशवासों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। अब मानव समाज लेटिन भाषा के स्थान पर स्थानीय और प्रादेशिक भाषाओं को अधिक महत्व देने लगा। परिणामस्वरूप प्रादेशिक भाषाओं का बहुत अधिक विकास हुआ और प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य की रचना को जाने लगी ताकि जन साधारण उसे आसानी के साथ पढ़ सकें।

1453 ई० में तुर्कों ने कुन्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। जब यूनान में तुर्कों राज्य की स्थापना होने लगी तब यूनानी विज्ञान अपने प्राचीन साहित्य को लेकर यूरोप चले गये। इसके पश्चात् यूनानी विद्वानों ने यूरोप में प्राचीन ज्ञान का प्रचार किया। फलस्वरूप यूरोपियन विश्वविद्यालयों में प्लेटो अरस्तु सोफिस्टा और एपीक्यूरेस आदि दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन किया जाने लगा। पुराने रोमन साम्राज्य के विद्वानों के ग्रन्थों का अध्ययन किया जाने लगा। उस समय जिनासा और पुराने ग्रन्थों के अध्ययन में मानव में एक नई जागृति हुई और मानववादी विचारधारा का विकास हुआ। यूनानी तथा रोमन विद्वानों के ग्रन्थों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया जाने लगा। इस समय विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व बढ़ने लगा। अब किसी बात को तक सिद्धांत के आधार पर सत्य उत्तरने पर ही स्वीकार किया जाता था। अब प्राचीन विश्वास समाप्त होने लगे।

(13) चर्च की सम्पत्ति पर राजाओं की दृष्टि—कुछ विद्वानों का यह मानना है कि पोप और राजाओं के बीच संघर्ष का मुख्य कारण यह था कि राजा लोग चर्च की धनसम्पत्ति पर अधिकार करना चाहते थे। चर्च के पास बहुत अधिक भूमि थी, परंतु उसे धन भूमि का आधिकार नहीं चुकाना पड़ता था। कई शताब्दियों से राजाओं सामंती और जनता ने चर्च को काफी भूमि दान में दी थी। जिसके कारण चर्च के अधिकार में बहुत सी भूमि थी। इसके अलावा चर्च जनता से धार्मिक कर वसूल करता था। चर्च को अपने 'यायाज्यों' से भी काफी आमदनी होती थी। कुछ मिलाकर चर्च अपार धन सम्पत्ति का स्वामी था और इसके धर्माधिकारी भोग-बिलास तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दूसरी तरफ राजाओं को, प्रशासन का खर्च चलाने के लिए और सशक्त शक्ति को मजबूत बनाने के लिए धन की जरूरत थी। इसलिए वे चर्च की भूमि व आय पर कर लगाकर अपनी धन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते थे। इसलिए दोनों में संघर्ष अवश्यम्भावी हो गया। शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा यह चाहते थे कि चर्च की सम्पत्ति पर अधिकार कर उसे मध्यम वर्ग, जमींदारों और प्रभावशाली व्यक्तियों में बांट दिया जाये, ताकि वे हमेशा चर्च के स्थान पर उनका समर्थन करेंगे।

(14) व्यापारियों का असंतोष—पुनर्जागरण के कारण व्यापारिक वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जो चर्च से असंतुष्ट था। व्यापारी दूर-दूर देशों में व्यापार करने धन संचित कर जब स्वदेश लौटता तो उसे अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग चर्च को भेंट स्वरूप देना पड़ता था। उस समय शामक वर्ग व्यापारियों की मदद करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह पोप को चुनौती दे सके। इसलिए व्यापारी वर्ग ने शामक का आर्थिक सहायता देकर उसे शक्तिशाली बनाया।

ईसाई धर्म के अनुसार उस समय कोई भी व्यापारी अधिक लाभ नहीं बना सकता था और न ही व्याज पर रकम उधार दे सकता था क्योंकि व्याज लेने वाले को ईसाई धर्म में दकती की सजा दी गई थी। जैसे-जैसे व्यापार का विकास होता गया जैसे-जैसे व्याज पर बज लेना आवश्यक हो गया। इसलिए व्यापारी वर्ग में चर्चों के प्रति भयंकर असंतोष व्याप्त था। वे धर्म में परिवर्तन चाहते थे, ताकि वे स्वतन्त्रता-पूर्वक व्यापार कर सकें। इस प्रकार व्यापारिक वर्ग ने असंतोष न भी धर्म सुधार आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(15) चर्च द्वारा जनता का आर्थिक शोषण—पोप जनता से अनेक प्रकार के कर वसूल करने गरीबों का शोषण कर रहा था। इन प्रकार के शोषण के कारण जनता का धर्म में विश्वास उठ गया। आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए धर्म सुधार आन्दोलन आवश्यक हो गया। मेकनन वनस ने लिखा है कि "एक आर्थिक

कारणा मे सबसे प्रमुख करा के विरुद्ध आवाज उठाना था ।'¹

पोप ने जनता पर अनेक पर लगा रखे थे, उनमें सबसे अधिक भारी कर नागवार "पीटस पस" था। यह कर प्रत्येक घर को प्रति ब्य (लगभग एक डालर) पोप को देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त 'टीषी' कर भी ईसाईया को देना पड़ता था। जो प्रत्येक ईसाई अपनी आय का एक तिहाई भाग पोप को देता था। इसके अतिरिक्त अपराधा का दण्ड, सरकारों की फीस और चर्च के "यायालय" में अपील आदि अनेक तरीकों से गिरजाघर जनता की अधिकांश आमदनी को ले लेता था।

राम के "यायालयों में अपीला की सुनवाई और उनके निणया की खुले आम बिक्री होती थी। यह धर्म सुधार आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया, क्योंकि इस प्रकार की याय-यवस्था में गरीब लोग वास्तविक याय से वंचित रह जाते थे और धनी वर्ग अपने धन से इच्छानुसार याय पान में सफल हो जाते थे। मैकनल बनस ने लिखा है कि 'आन्दोलन का मूल कारण वास्तव में आर्थिक था, नतिक नहीं।'²

(16) पोप मोचन पत्र का विक्षय—पोप मोचन पत्र या क्षमा पत्र के इस विषय को 'इंडलजेंस' भी कहते हैं। जब चर्च 1 घम और मोक्ष का व्यापार प्रारम्भ किया तो उसकी घन लालसा चरमोत्कृष्ट बिन्दु पर पहुँच गई थी। यद्यपि सूयर से पहले कई ऐसे सुधारक दृष्टे थे जिन्होंने घम में याप्त बुराईयों को दूर करने का प्रयास किया था। सूयर पहला व्यक्ति था, जिसने इस बात का प्रचार किया कि रोम की चर्च से सम्बन्ध त्याग लिये जाने चाहिये। उसने पोप मोचन पत्र अपना क्षमा पत्रों की बिक्री के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर लिया। इण्डजेंस का अर्थ होता है मुक्ति पत्र। यह एक ऐसा मुक्ति पत्र था जिसको प्रत्येक व्यक्ति पोप द्वारा अधिकृत व्यक्ति से घन देकर खरीद सकता था। जो व्यक्ति अपने अपराधों को क्षमा करवाना चाहता हो तो वह व्यक्ति पोप के ऐजेन्ट को घन देकर ऐसा मुक्ति पत्र खरीद लेता था। जिसमें उसके सब पापों को क्षमा किये जाने का आश्वासन था और उस व्यक्ति का स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता था।

1513 ई० में फ्लोरेन्स के मेडिकी परिवार का सदस्य लियो दशम पाप बना। वह मानववादी विचारधारा, प्राचीन यूनानी साहित्य और पुनर्जागरण कालीन कला की प्रशंसा करता था। पोप लियो दशम ने ही रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया था। जो पुनर्जागरण कालीन कला का एक सुन्दर नमूना है। पोप ने गिरजाघरों के लिये घन एकत्रित करने के लिये क्षमा पत्रों को सस्ते दामों पर बेचने के आदेश दिये। उसने जनता से अपील की कि वह

1 मैकनल बनस—बस्टन सिविलीजेशनस—पृष्ठ—401

2 मैकनल बनस—बस्टन सिविलीजेशनस—पृष्ठ—398

अधिक से अधिक मात्रा में इन पत्रों का खरीदने और भयानक से भयानक पाप से मुक्ति प्राप्त कर लें। आजकल जिस तरह एम० ए० और पी० एच० डी० की डिग्री लोग मन्वा कर अपने बैठक के कमरे में टांग देते हैं। उसी प्रकार उस समय चोर और डाकुआ न बड़ी बड़ी कीमत लेकर इन क्षमा पत्रों को खरीदा और अपने बैठक के कमरे में मन्वा कर टांग दिया।

पोप लियो दशम न जर्मनी में इन पत्रों के विशय का उत्तरदायित्व आक विषय अलबट को सौंपा। अलबट पर बहुत कर्जा था। इसलिये वह इन मुक्ति पत्रों की बिक्री से लाभ उठाना चाहता था। अलबट ने पत्रों के बिक्रय का काम पादरी टेटजेल को मापा। जो इन पत्रों को बेचने के लिये यूरोप के दौरे पर रवाना हुआ। टेटजेल न अपने जोशील भाषणा से इस बात का प्रचार किया कि जो ध्यक्ति इन मुक्ति पत्रों को खरीद लेगा, उसे बिना पश्चाताप किये पाप से मुक्ति मिल जायगी। उसने तो यहाँ तक कहा कि यदि कोई ध्यक्ति भविष्य में पाप करना चाहना है तो वह इस पत्र को अभी खरीद ले, ताकि उसे भी पापा से मुक्ति मिल जायगी और उसने लिये स्वयं में स्थान सुरक्षित हो जायेगा।

टेटजेल इस प्रकार इन पत्रों को बेचत हुए जब 1517 ई० में जर्मनी के एक नगर प्रिटेन बग में पहुँचा तो उसने वहाँ के पादरी मार्टिन लूथर को जो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था, इन पत्रों को बेचने के लिये कहा। तब मार्टिन लूथर ने इन पत्रों को बेचने से इन्कार कर दिया। टेटजेल ने लूथर की शिकायत आक विषय अलबट को की। अलबट ने लूथर को चर्च से बहिष्कृत कर दिया। इस पर लूथर ने धम सुधार आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। पोप को लूथर का दमन करने में सफलता नहीं मिल सकी। एच० जो वेल्स ने लिखा है कि—“पोप के राज्य के खिलाफ इस और चाईकिलक के समय से चली आ रही क्रांति को असाधारण आर कौतूहल पूर्ण क्षमा पत्रों की बिक्री ने और भड़का दिया।”¹

स्पष्ट है कि क्रांति पहले से चल रही थी लेकिन इन क्षमा पत्रों की बिक्री न उसमें अग्नि में घी का काम किया। मेदाइन ने लिखा है कि ‘क्षमा पत्रों के बारे में बड़ी ध्रांतिमा थी। इस प्रथा को टेटजेल ने अधिक धन प्राप्ति के लिये और प्रष्ट बना लिया। लूथर ने इस प्रथा की भत्सना की और क्षमा पत्रों की प्रथा को चुनौती दी।’²

जब लूथर ने क्षमा पत्रों की बिक्री की आलोचना की और उसका चुनौती दी तो इस चुनौती के साथ ही सारे यूरोप में क्रांति भड़क उठी। उस समय राजा, व्यापारी, सामंत और गरीब सभी ऐम ही अवसर की तलाश में थे। वे चर्च के

1—वल्स, एच० जी०—दी वाउट लाईन आफ हिस्ट्री—पृ 787

2—मेदाइन—ए हिस्ट्री आफ वल्ड सिविलाइजेशन

घटना में मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। क्षमा पत्रों की विप्री और लूथर की चुनौती से उन्हें यह अवसर प्राप्त हो गया। लूथर ने घम-सुधार आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। कुछ ही समय में उसके अनुयाईयां न पोप से सम्बन्ध त्याग दिये। इसके पश्चात् उन्होंने एक नया मत प्रचलित किया। जो प्रोटेस्टेंट कहलाया।

घम सुधार आंदोलन का विकास — इस क्रांति के अनेक ऐसे दूत थे, जिन्होंने क्रांति को अवश्यमभावी बना लिया। इनमें जान वार्डविलफ, जान हंस, जाल्दिग, वाल्टेस सेरोनारिना इरास्मस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जिन लोगों को पोप के विरुद्ध क्रांति करने में सफलता प्राप्त हुई, इनमें लूथर काल्विन और विंगली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड का शासक हैनरी अष्टम, नार्वे का सम्राट फर्डरिक तथा हालैण्ड और फिनलैण्ड के शासकों ने भी इस धार्मिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

(1) मार्टिन लूथर (1483-1546) — घम सुधार आंदोलन का सफल नेता लूथर था, जिसका जन्म 10 नवम्बर 1483 ई० को जर्मनी के इजलबन नामक नगर में एक साधारण परिवार में हुआ। उसके पिता खान में मजदूर थे यह चाहते थे कि उनका लड़का बड़ा होकर वकील बन। लूथर का बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी गई। उसने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध इरेफ्ट के विश्वविद्यालय से 1505 ई० में घम शास्त्र में एम० ए० किया और 1508 ई० में वह ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गया। वहाँ उसने आगस्टाइन की रचनाओं का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। आरम्भ में वह रोमन कथोलिक चर्च का अनुयायी था। पोप के प्रति उसकी जगाह श्रद्धा थी। जब कभी उस पोप के पादरियों के साप्ताहिक जीवन के बारे में कोई व्यक्ति कुछ कहता था तो उसे उस पर विश्वास नहीं होता था।

1511 ई० में जब लूथर रोम की यात्रा पर गया। वहाँ वह पोप से मिला। लूथर पोप के विलासमय जीवन को देख कर आश्चर्य चकित रह गया। अब लूथर को रोमन चर्च में घणा हो गई जब उसने बाइबिल का गहन अध्ययन प्रारम्भ किया और पवित्र मस्कारों को अप्रावश्यक माना। इसके पश्चात् 1517 ई० में जब पोप लियो का दूत क्षमा पत्रों का वेंचता हुआ ब्रिटेन के नगर में आया तो लूथर ने इन पत्रों का आलोचना की और पोप के विरुद्ध घम सुधार आंदोलन प्रारम्भ कर लिया।

लूथर ने 1517 ई० में ब्रिटेन के विश्वविद्यालय के गिरजाघर के दरवाजे पर 95 सिद्धांतों का एक शतक कील से लगा लिया। इस पत्र में पोप तथा पादरियों के अधिकार तथा घम में व्याप्त बुराईयां पर प्रकाश डाला गया था। लूथर ने अपने सिद्धांतों को लटिन भाषा में लिखा। जो आसानी से जन साधारण के समझ में जा सके। उसने अपने सिद्धान्तों का बहुत प्रचार किया। कुछ ही समय

मे जमनी मे उसके अनुपाईयो की सभ्या बढने लगी । जमनी मे लोगो ने लूथर को खपना धार्मिक नता स्वीकार कर लिया । वहा के वृषको ने भी उमका समथा किया । कुछ शासको व सामन्तो ने लूथर के सिद्धांता का विरोध किया और कुछ शासका व सामन्तो ने लूथर को अपना सहयोग दिया । जिसके फलस्वरूप लूथर के आन्दोलन को बल मिला ।

1520 ई० मे लूथर ने "एन ओपन नेटर टू दी थ्रिचन स्टेट" (ईसाई जगत को एक नया पत्र) लिखा । जिसमे उसने गिरजाघरा की अथार धन सम्पत्ति, जागीर और धर्माधिकारिया के सामारिक जीवन की गुराईयो पर प्रकाश डाला । उमने जमनी के लोगो से पोप की सत्ता को उखाड फेंकने की अपील की । लूथर ने राजा से यह मांग की कि वह इन गुराईया को रोकने के निचे कदम उठाये और अपने अधिकारो को प्रयोग करते हुए एक धर्म सभा का आयोजन करें । जिसमे धर्माधिकारियो को उनके कल व्या का पालन करने का आदेश दें । परिणामस्वरूप जमन शासका ने रोमन चर्च से सम्बन्ध ख्याग लिया और लूथर के अनुपाई बन गये । उन्होंने चर्च की भूमि और धन सम्पत्ति पर भी अधिकार कर लिया, परन्तु कुछ जमन शासक पोप के प्रति निष्ठावान थे । इसलिये उन्होने लूथरवाद को नहीं अपनाया । इस प्रकार जमनी मे चर्च का विभाजन हो गया । कैथोलिक राज्या ने रेटिस बोन मे अपना एक सप बनाया । वसी प्रकार लूथर के अनुपाईयो ने भी अपना एक सप बनाया । ये दोना सप एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे । इससे जमनी मे गृह-युद्ध का वातावरण बन गया । लूथर के आन्दोलन से किसान बहुत प्रभावित हुए । उन्होने सामन्तो के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी छोनी हुई भूमि पर बचपूवक अधिकार कर लिया ।

लूथर ने अपनी दूसरी वृत्ति "चर्च का बर्दीनोनिया ना कनी" मे मस्कारा का विरोध किया । उमने अपनी तीसरी वृत्ति "ईसाई स्वतन्त्रता" मे पोप को चुनौती दी । इसमे उसने यह लिखा कि वह ईसाई धर्म मे व्याप्त धर्म, अष्टाचार और पापुण्ड के विरुद्ध आन्दोलन करता है ।

टिचजन ने लूथर के कालो की पाप तथा अन्ध विश्वास अन्धकार मे शिक्षाधन की । इस पर पोप ने एक धर्म सभा का आयोजन कर लूथर को उसमे भाग लेने का लिय बुलाया । मकसदोनी का राजा लूथर का समर्थक था । उसने लूथर की रक्षा का भार अपना कंधा पर लिया । लूथर पोप की सभा मे उपस्थित हुआ और बिना किमी सशोधन के अपने सिद्धांता को सभा के सम्मुख पुन दाहरा दिया । इस पर पोप ने त्रुधित हाकर उसको चर्च से निबाध किया । उसने सम्पूर्ण ईसाई समाज को लूथर से सम्बन्ध विच्छेद का आदेश दिया । इस समय ता द्वारा व्यक्ति और वृद्ध मे शासक लूथर के अनुपाई बन गये थे । इसलिये लूथर ने पोप के आदेश पत्र को एक भरा सभा में जला दिया । धीरे धीरे लूथर के अनुपाईया की संख्या बढने लगी ।

पोप न 1529 ई० की दूसरी धर्म सभा में लूथर की धारणा की और सम्राटों को उसका दमन करने का आदेश दिया। जर्मन के सामंता ने पोप के इस निणय का प्रतिवाद (प्रोटेस्ट) किया। इसलिए लूथर के अनुयायी प्रोटेस्टेंट के नाम से प्रसिद्ध हुए। लूथर की मृत्यु के पश्चात् भी उसका अनुयायी उसके सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट धर्म सम्पूर्ण यूरोप में फैल गया।

लूथरवाद के सिद्धांत — लूथरवाद का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है —

- (1) लूथर ने कहा कि व्यक्ति पाप करने के पश्चात् पश्चात्ताप करे और ईश्वर की भक्ति करे तो ईश्वर उसके पापों को क्षमा कर देता है। पोप की कृपा से या क्षमा याचना पत्रों से व्यक्ति को क्षमा नहीं मिल सकती। क्षमा सिर्फ ईश्वर भक्ति के द्वारा ही मिल सकती है।
- (2) लूथर ने कहा कि पोप सर्वोच्च शक्ति नहीं है। मध्य युग में जनसाधारण की अज्ञानता का लाभ उठाकर पोप ने धीरे धीरे अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली है।
- (3) लूथर के अनुसार रोमन प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिये, क्योंकि पोप की अहंकारी भावना ने धर्म को पगुवना दिया है। लूथर का मानना था कि सभी व्यक्ति धर्म ग्रन्थ का अध्ययन कर सकते हैं। धार्मिक ग्रन्थ किसी की भी बपौती नहीं है।
- (4) लूथर के अनुसार पोप की कृपा से मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति केवल ईश्वर भक्ति और शक्ति से ही प्राप्त हो सकती है।
- (5) लूथर के अनुसार यदि कोई भी धर्माधिकारी अपराध करता है तो उसे साधारण लोगों की भाँति सजा मिलनी चाहिये, क्योंकि कानून का समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है।
- (6) चर्च में व्यापक भ्रष्टाचार दूर करने के लिये पादरी लोगों को विवाह करके सभ्य नागरिकों की भाँति साधारण जीवन यतीत करना चाहिये।
- (7) लूथर अरस्तु की पाठ्यपीठों और विधियों मानता था। इसलिए उसने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जाना चाहिये। उसके अनुसार पाठ्यक्रम धर्म पर आधारित होना चाहिये।
- (8) ईसाई धर्म के सात संस्कारों में से चार — अभिषेक, विवाह, अनुमोदन और अवलेपन को समाप्त कर दिया जाना चाहिये, केवल तीन संस्कारों नामकरण, प्रायश्चित्त और यूरेवेस्ट को लागू रखना चाहिये।
- (9) पादरियों के लिये अलग से अदालतें नहीं होनी चाहिये तथा उन्हें याप करने का अधिकार भी नहीं दिया जाना चाहिये।
- (10) लूथर के अनुसार पादरियों को सिर्फ धर्म उपदेश देना चाहिये।

लूथर के इन सिद्धांतों के कारण जर्मनी में गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया।

प्रोटेस्टेंट और रोमन कथोलिक चर्च के सदस्या के बीच भयंकर सघर्ष प्रारम्भ हुआ जिसकी समाप्ति 1555 ई० में जागसबुर्ग की धार्मिक संधि से हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी —

- (1) पहली शत के अनुसार यह निश्चित किया गया कि साम्राज्य परिषद में कथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया जायगा।
- (2) पासा की संधि से पूर्व जितनी सम्पत्ति चर्च के अधिकार में थी, उस पर चर्च का अधिकार रहेगा, लेकिन अब राज्य चर्च को किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं देगा।
- (3) "जो राजा का धर्म होगा, वही उसकी जनता का धर्म होगा", इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया।

प्रोटेस्टेंट धर्म का यूरोप पर प्रभाव — जब लूथर ने प्रत्यक्ष रूप से पोप का विरोध किया तो उससे अल्प देशों में धर्म सुधारकों के साहस में वृद्धि हुई। प्रोटेस्टेंट मत का बड़ी तेजी के साथ यूरोपियन देशों में प्रचार हुआ। विभिन्न देशों के शासकों ने अपने हितों को देखते हुए इसका समर्थन किया अथवा विरोध किया। स्वीट्जरलैण्ड, फ्रांस, इंग्लैण्ड, नार्वे, स्वीडन, स्काटलैण्ड, डैनेमार्क, हंगरी, नीदरलैण्ड और इटली आदि देशों में धर्म सुधार आन्दोलन की प्रगति के संक्षिप्त इतिहास का वर्णन निम्न प्रकार है —

(1) स्वीट्जरलैण्ड पर प्रभाव — (1) ज्विगली (1484-1531 ई०) रोमन कथोलिक धर्म का विरोध जर्मनी के अतिरिक्त यूरोप के अल्प देशों में भी हुआ था। ज्विगली ने स्वीट्जरलैण्ड में कथोलिक धर्म का विरोध किया। यह भी लूथर का समकालीन था और एक किसान परिवार में पैदा हुआ था, परन्तु लूथर के विचारा से यह बहुत प्रभावित था। यद्यपि ये दोनों समकालीन धर्म सुधारक थे, परन्तु उनके विचारों में भारी अंतर था। ज्विगली उग्र विचारा का था, जबकि मार्टिन अनुदार विचारा का।

1529 ई० में उसने 67 लेख प्रकाशित किये। जिनमें पोप की गुरादियों पर प्रकाश डाला और चर्च में साप्ताहिक पूजा, मूर्तिपूजा और चित्र रखने की प्रथा का घोर विरोध किया। इतना ही नहीं ज्विगली ने कॅण्टन में विशप की सत्ता को समाप्त कर दिया और क्षमा पत्र के विक्रय वाले लोगों को उसने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उसने लटिन भाषा में आईबिल के अध्ययन पर रोक लगा दी। पादरियों को विवाह करने का अधिकार दिया गया। उसने अपने देशवासियों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति पोप की सेना में भर्ती नहीं होगा।

ज्विगली के प्रतिपादित धर्म सुधार को केवल पूर्वी स्विट्जरलैण्ड में ही सफलता मिली, परन्तु इस आन्दोलन में कथोलिक चर्च के अनुयायी भयंकर नाराज हुए। परिणामस्वरूप 1531 ई० में कथोलिक कैंटा की लीग और प्रोटेस्टेंटों की

लोग के बीच केपेल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें कथोलिकों ने प्रोटेस्टेंटों को बुरी तरह पराजित किया। ज्विगली इस युद्ध में लड़ता हुआ 11 अक्टूबर, 1531 ई० की मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस वीर सुधारक के अन्तिम शब्द निम्न थे—'व शरीर का मार सकते हैं आत्मा को नहीं।'

(11) कालविन (1509-1564) —ज्विगली के अधूरे काय को फ्रांसीसी जॉन कालविन ने पूरा किया। वह 11 जुलाई 1509 ई० में विवार्डी के नोमोन नामक नगर में पैदा हुआ था। यह फ्रांस का रहने वाला था परन्तु प्रोटेस्टेंट मत का समर्थक होने के कारण उसे फ्रांस से निर्वासित कर दिया गया। कालविन ने स्विटजरलैण्ड में शरण ली और अपने विचारों का प्रसार करने लगा। स्विटजरलैण्ड को कुछ समय पहले ही रोमन साम्राज्य में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और ज्विगली के धर्म सुधार आन्दोलन के कारण यहाँ पर युद्ध भी हो चुका था। इसके पश्चात् यह निश्चित हुआ था कि 13 कंटनों के लोग अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने के लिये स्वतंत्र होंगे। जिनेवा का भाग भी प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी था। इसलिये जान ने यहाँ पर शरण ली और अपने विचारों का प्रसार करने लगा।

कालविन का मानना था कि बाईबिल का ठीक अर्थ लगाया जाना चाहिये। मनुष्य को चाहिये कि आचार विचार का कठोरता से पालन करें। त्यौहार नहीं मनाएँ और थियेटर बन्द कर दिष्टे जाने चाहिये। धीरे धीरे वह जिनेवा का सम्राट बन गया। उसके शासन काल में स्त्रियों को घुघराले बाल बनाने या आकषक पोशाक पहनने की मनाही थी। ताना खेलना शराब पीना और नाचना उसने गरीबानुकी घोषित कर दिया था।¹

उसका यह मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को प्रभु ईसा की भाँति सादा और सरल जीवन बिताना चाहिये। कोई भी व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा रखकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कालविन ने चर्चों की व्यवस्था के लिये वड पादरिया को नियुक्त किया, जिसे "प्रोसीविटर" कहा जाता था। उसी आधार पर कालविन के अनुयायी 'प्रोसीविटेरियन' के नाम से प्रसिद्ध हुए। अन्य देशों में उसके अनुयायी "प्यूरिटियन" के नाम से प्रसिद्ध हुए।

कालविन ने स्विटजरलैण्ड, जर्मनी, पोलैण्ड और स्काटलैण्ड आदि देशों में अपने मत का प्रचार किया। उसने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात् 'सीटीयूटिया' नामक पुस्तक लिखी जिसकी गिनती उच्च कोटि के धार्मिक ग्रंथों में की जाती है। फ्रांस में उसके अनुयायी हनूजनों के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1598 ई० में फ्रांसीसी सम्राट हनरी चतुर्थ ने हनूजनों का एक आदेश के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी।

(2) फ्रांस पर प्रभाव — फाल्किन के विचारा का पहले तो फ्रांस में भयकर विरोध हुआ, परन्तु कुछ समय पश्चात् फ्रांस में उसके समयको की सभ्या बढ़ने लगी। उसके अनुयाई हनूजनों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके समयको पर फ्रांसीसी राजा ने भयकर अत्याचार किये।

(3) स्कॉटलैण्ड पर प्रभाव — स्कॉटलैण्ड पर पुनर्जागरण का प्रभाव बहुत कम पड़ा था। दूसरे देशों में धर्म सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हो गये थे, परन्तु यहाँ के निवासियों पर रोमन कैथोलिक धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। सर्वप्रथम इंग्लैण्ड के विद्वान वार्डविलफ ने यहाँ पर अपने विचारा का प्रसार किया। यहाँ की जनता उसके विचारों से काफी प्रभावित हुई। अग्रे देशों की भाँति स्कॉटलैण्ड में भी धर्म सुधारकों को जिंदा जला दिया जाता था। 1520 ई० में यहाँ लूथर की विचारधारा का प्रसार हुआ। 1528 ई० में यहाँ पेट्रिक हेमिलटन को इसलिए जीवित जला दिया गया, क्योंकि उसने कैथोलिक धर्म में 'याप्त बुराईयाँ की आलोचना की थी। 1543 ई० में जाज विशहट ने यहाँ पर नवीन धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार किया। फलस्वरूप इसे भी धर्मद्रोही घोषित कर जिंदा जला दिया गया।

जॉन-नॉक्स—इस प्रकार स्कॉटलैण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन शनैः शनैः चल रहा था। इस आन्दोलन को प्रबल रूप देने का श्रेय जॉन नॉक्स को दिया जाता है। नॉक्स का जन्म 1515 ई० में हुआ था। आरम्भ में वह जाज विशहट के साथ रहा, परन्तु 1546 ई० तक उसे अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर नहीं मिला। इसलिये 1549 में वह इंग्लैण्ड और 1552 में जिनेवा की यात्रा पर गया और जिनेवा में रहना शुरू कर दिया। इस समय नॉक्स का परिचय फाल्किन से हुआ।

1555-56 ई० में वह अपने देश स्कॉटलैण्ड लौटा और वहाँ उसने प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करना प्रारम्भ किया, परन्तु अपने जीवन को सकट में देखकर वह पुनः जिनेवा लौट आया। 1559 ई० में स्कॉटलैण्ड वामियों के निमंत्रण पर नॉक्स पुनः वहाँ आया और वहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करना शुरू किया। स्कॉटलैण्ड में जॉन-नॉक्स के अनुयाई प्रेसबिटेरियन के नाम से प्रसिद्ध हुये।

(4) नार्वे पर प्रभाव — नार्वे में धर्म सुधार आन्दोलन वहाँ के राजा द्वारा प्रारम्भ किया गया। नार्वे का शासक फ्रेडरिक प्रथम लूथर के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात् उसने धर्म सुधार आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया। उसने चर्च की सम्पत्ति के एक बहुत बड़े भाग पर कर लगा कर लिया और उसे जनहित कार्यों में खर्च कर दिया। 1533 ई० में फ्रेडरिक प्रथम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात् नार्वे में

गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया। 1534 ई० में इस गृह युद्ध में फेडरिक प्रथम व ज्येष्ठ पुत्र क्रिश्चियन को सफलता मिली और वह नार्वे का राजा बना। वह भी प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थक था। इसीलिए उसके शासन काल में प्रोटेस्टेंट धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ।

(5) स्वीडन पर प्रभाव — 1521 ई० में गुस्तावस स्वीडन का शासक बना। उस समय राज्य का आर्थिक दशा बहुत शालीन थी। उसने राज्य कोप में वृद्धि करने के लिए चर्च के धर्माधिकारियों से धन वसूल करने का निश्चय किया। इसलिये उसने खुले रूप में धर्माधिकारियों की बुराईयों की आलोचना करना प्रारम्भ कर दिया।

1521 ई० में उसने लूथर की विचारधारा से प्रभावित होकर प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर लिया तथा चर्च की सम्पत्ति पर राजा बनने के लिये कथो लिक् धर्म की कटु आलोचना की। उसके शासन काल में प्रोटेस्टेंट धर्म का बड़ी तेजी से प्रचार हुआ। उसने काईबिल का स्वीडन की भाषा में अनुवाद करवाया और उसकी प्रतिमा जन साधारण में वटवाइ। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार जर्मनी के बाद नार्वे और स्वीडन में हुआ।

(6) पोलैण्ड तथा हंगरी पर प्रभाव — काल्विन के धार्मिक विचारों का प्रसार पोलैण्ड में भी हुआ। जिससे प्रभावित होकर यहाँ के सामन्त और मध्यम वर्ग के मनुष्य प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी बन गये। हंगरी के प्रत्येक वर्ग के मनुष्यों ने भी इस नये धर्म को स्वीकार कर लिया। 16 वीं शताब्दी के अन्त तक वहाँ के अधिकांश व्यक्ति प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी बन चुके थे। कथोलिक धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी।

(7) नीदरलैण्ड पर प्रभाव — नीदरलैण्ड के धनी एवं शिक्षित मनुष्यों ने धर्म सुधार आन्दोलन का समर्थन किया। यद्यपि फ्रांस के राजा ने अपन अधीन प्रदेशों में इस आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया। फिर भी नीदरलैण्ड में काल्विन के समयको की सत्ता में निरन्तर वृद्धि होती रही।

(8) इटली पर प्रभाव — इटली का धर्म सुधारक सेवीनारोला जो पहले पादरी था और पोप एलेक्जण्डर चतुर्थ का परम भक्त था। किन्तु जागे चल कर 1494 ई० में उसने पोप की बुराईयों की आलोचना करना प्रारम्भ कर दिया। पोप ने उसे जितना जलवा देने का प्रयास किया, किन्तु बर्षा आ जाने से वह बच गया। जन में पोप ने उसे फाँसी पर सटकवा दिया। जैसे जस पाप प्रोटेस्टेंट धर्म का अन्त करता जा रहा था वैसे वैसे यह धर्म तर्जो के साथ यूरोप के अन्य देशों में फैलता जा रहा था। ऐसी स्थिति में पोप ने कथोलिक धर्म में सुधार करने के लिये कुछ प्रयास किए। जिससे प्रति धर्म सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

(9) इंग्लण्ड पर प्रभाव - मध्य काल से ही इंग्लैण्ड में रोमन कथो-
लिक चर्च का विरोध प्रारम्भ हो गया था। उस समय 'पीपम एनोपैन' और
"द कंटरबरी टल्स' नामक दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें पादरियों के पैपव
और विनाशिता के बारे में बर्णन किया गया था। इन पुस्तकों का समाज पर
गहरा प्रभाव पड़ा। तीसरी पुस्तक में धर्मोपनिवेशियों का धम तालिका के चार में
बर्णन किया गया था। जब जनता को यह पता लगा कि इंग्लण्ड की एक तिहाई
भूमि पर चर्च का अधिपति है तो वह आश्चर्य बरत लगी। बने चर्च का विरोध
तो काफी पहले शुरू हो गया था। 1351 ई० में इंग्लण्ड का संसद हेनरी
अष्टम पोप के हस्तक्षेप का समाप्त करना चाहता था, इसलिए उसने एक आदेश
जारा किया जिससे अनुसार इंग्लण्ड में पाप द्वारा पादरियों की नियुक्ति पर प्रति-
बन्ध लगा दिया गया। हेनरी अष्टम ने एक मामूली विवाह के तलाक के लिए पाप
में अपने सम्बन्ध तोड़ दिए 1534 ई० में उमर इंग्लण्ड में पोप की सत्ता का
उच्छाद फैका और स्वयं को धम का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया। उसने
इंग्लण्ड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना की।

उस समय सभी स्थानों पर धम सुधारकों के द्वारा पोप विरोधी आंदोलन
चलाया जा रहा था। इससे हेनरी अष्टम बहुत प्रभावित हुआ। इन घटनाओं
न उस पोप से सम्बन्ध तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हेनरी का पोप से
सम्बन्ध तोड़ने का मुख्य कारण यह था कि पाप अपनी सातवीं रानी
कथरीन को तलाक देकर आठवां विवाह करना चाहता था। पोप ने
हेनरी को ऐसा करने से रोकना नहीं चाहा, क्योंकि कथरीन स्पेन के कैथोलिक
राजा फर्नान्ड की पुत्री थी और पोप उस राजा को नहीं करना चाहता था। इस
लिए हेनरी ने इंग्लण्ड के एक प्यापल में कथरीन को तलाक दे दिया और फिर
एक 16 वर्ष की बच्ची कृष्णाशी सुन्दरी एन्बोलीन से शादी कर ली। कथरीन
के सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाना से हेनरी ने उत्तराधिकार की समस्या को हल करने
के लिए कृष्णाशी से आठवां विवाह किया था। पाप ने कथरीन के तलाक और
हेनरी से कृष्णाशी से हुए विवाह को अर्बप घोषित कर दिया।

इस पर हेनरी ने पोप के समक्ष पादरियों का बंधन हटाने का आदेश दिया और उनकी
सम्पत्ति अपने समयके नये सामन्तों में बांट दी। उसने चर्च की अधिकांश भूमि पर
अधिकार कर लिया। इस प्रकार इंग्लैण्ड में प्रोटेस्टेंट धम सुधार आन्दोलन
प्रारम्भ हो गया। एलिज और जोन ने लिखा है कि—“इस प्रकार इंग्लण्ड के
चर्च ने पोप की शक्ति का जोड़ा उतार फेंका।”

इस आंदोलन के कारण इंग्लण्ड में चर्चों में काम करने वाले हजारों पादरी

और किमान बेरोजगार हो गये, इतना ही नहीं बच म जो स्कूल चल रहे थे, वे बन्द हो गये ।

हेनरी अष्टम की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र एडवर्ड षष्ठम 1547 ई० म अल्पायु मे इंग्लैंड का सम्राट बना । उसके सरदाय सीमरसेट और नाथम्बरलैंड दोनो ही प्रोटेस्टेण्ट धर्म क अनुयाई थे । इसलिय इस समय प्रोटेस्टेण्ट धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ । बमनर ने धर्म म अनेक परिचलन किये । इस समय वाईबिल का अग्रजी भाषा म अनुवाद किया गया । गिरजाघरो म लटिन भाषा के स्था पर अग्रजी भाषा म प्राथना की जान लगी । उस समय 42 धाराआ वाला एक कानून पास किया गया । गिरजाघरो स मूर्तिया हटवा दी गई और दीवारो पर चित्रित चित्रो को मिटा दिया गया । मठो व गिरजाघरो की सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया । इस प्रकार एडवर्ड षष्ठम क समय म प्रोटेस्टेंट धर्म का काफी प्रचार किया गया ।

एडवर्ड षष्ठम की मृत्यु के पश्चात् मेरी ट्यूडर 36 वष की आयु म इंग्लैंड की शासिका बनी । यह कथोरिन की पुत्री थी और कथोलिक धर्म की समर्थक थी । उसने ससद को पोप की मायता देा क त्रिय बाध्य किया । उसने कथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित किया और पोप की आज्ञा नही माना वाले व्यक्तियों को बठोर सजायें दी । मेरी ने प्रोटेस्टेंट धर्म क नेताआ जेमनर, लटियर टिडले और हुयर आदि को त्रिदा अग्निदेव को चढा दिया । उसने इस प्रकार की दमन नीति का पालन करते हुये प्रोटेस्टेंट धर्म को समाप्त करन का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश अग्रज रोमन कथोलिक धर्म के विरोधी थे । मेरी इस प्रकार क निमम अत्याचारा के कारण 'खुनो मेरी' के नाम से प्रसिद्ध हो गई । 1538 ई० म मेरी को बन्दी बना कर प्राण दण्ड दिया गया ।

मेरी ट्यूडर की मृत्यु के पश्चात् हेनरी अष्टम की लडकी एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड क सिंहासन पर बठी । वह प्रोटेस्टेंट धर्म की समर्थक थी । इसलिय उसने इस नवीन धर्म को राजकीय सरक्षण प्रदान किया । इस प्रकार इंग्लैंड के लागू की पोप के प्रभाव से हमशा के लिय मुक्ति मिल गई ।

प्रतिवादी धर्म सुधार—जारम्भ म तो पोप तथा पादरिया ने निममता पूर्वक धर्म सुधार आन्दोलन का कुचलन का प्रयास किया । जब तीस वष का युद्ध भी सुधार आन्दोलन को दबान में असफल रहा, तो पोप का सिंहासन डोलन लगा । उस समय की परिस्थितिया ने उस बाध्य किया कि दूसरो को धर्म द्रोही सिद्ध करने के बजाय स्वयं म और कथोलिक धर्म म कुछ सुधार करें । यद्यपि उस समय फ्रांस और स्पेन क शासक पोप के समर्थक थे परंतु कथोलिक और प्रजा यह चाहती थी कि धर्म को बचान के लिय उसमें जातिरिक्त सुधार करना आवश्यक है । इसलिये 16 वीं शताब्दी म पोप और रोमन कथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट धर्म के

बढते हुए प्रभाव को रोकने के लिए स्वयं में और कथोलिक धर्म में जो सुधार किये, उसे इतिहास में प्रति धर्म सुधार आन्दोलन कहा जाता है ।

उस समय रोमन कैथोलिक धर्म के समर्थक न कहा कि यदि धर्म में सुधार नहीं किया गया तो कुछ ही समय में धर्म समाप्त हो जायगा । इसलिये कैथोलिक धर्म में व्याप्त अनतिक्रम, अराजकता और अधार्मिकता को दूर करने के लिये मार्क्वल ए जूलो, क्विन्ती विक्टोरिया को-लोआ और घामस कजेटन आदि विद्वानों ने अपनी कलाकृतियों में धर्म में महत्वपूर्ण सुधार किया ।

प्रोटेस्टेंट आन्दोलन के बाद भी यूरोप की अधिकांश जनता का कैथोलिक धर्म में विश्वास था । उस समय सभी लोगों का यह मानना था कि प्रोटेस्टेंट पोप विरोधी आन्दोलन था न कि कथोलिक धर्म विरोधी आन्दोलन । यदि पोप अपने जीवन में ईमामसोह की शिक्षाओं का पालन करता रहता तो प्रोटेस्टेंटों को धर्म विरोधी आन्दोलन करने का मौका ही नहीं मिलता । उसका अनुसरण करते हुए अथ पाररिया ने भी अनतिक्रम जीवन विताना शुरू कर दिया था । इसलिये पोप कनीमेट न कैथोलिक धर्म में सुधार करने के लिए 1530 ई० में चार तरीके अपनाए —

(1) पोप के व्यक्तिगत जीवन में सुधार —पोप की विलासिता, सासारिक जीवन और तानाशाही के विरुद्ध धर्म सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । यदि पोप सादा जीवन यतीत कर पुन ईसा क बताये हुए भाग पर चलना शुरू कर देता, तो यह आन्दोलन स्वयं ही समाप्त हो जाता । इसलिये पोप कनीमेट ने 1530 ई० में शाही टाट वाट को त्याग कर सादा जोर पवित्र जीवन यतीत करना प्रारम्भ किया । उसका राद अनक पापो न भा उसका अनुसरण किया । इन सुधारक पोपों ने विभिन्न सम्मेलनों में पाररिया और विशपा को भी सादगीपूर्ण जीवन यतीत करने का आदेश दिया ।

पोप ने अथ अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करना प्रारम्भ कर दिया । पुनजागरण काल के पोपों ने साहित्य एवं कला का विकास करने के लिये अनक कलाकारों और साहित्यकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया । इस प्रकार फिर न वही प्रगतिशील तरीका अपनाया गया । पाप ने अपने व्यक्तिगत जीवन और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर धर्म सुधार आन्दोलन की नींव का ठोस बना दिया ।

(2) ट्रेट के धार्मिक अधिवेशन—रोमन कथोलिक चर्च का पुनर्गठन करने के लिये पोप ने 1545 ई० में इटली के नगर ट्रेट में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया । इस ट्रेट नगर में जगले 18 वर्षों में 25 धार्मिक सम्मेलन बुलाये गये । प्रत्येक अधिवेशन या सम्मेलन में 200 से अधिक कैथोलिक पाररियों को आमंत्रित किया जाता था । इन अधिवेशनों में चर्च का पुनर्गठन, अनुशासन और

व्यवस्था में सुधार करने के लिये अनक नियमों का निर्माण किया गया। मध्यकालीन चर्च के उपदेशों की पुष्टि की गई कि —

- (i) पोप चर्च का सर्वोच्च अधिकारी है और सभी सिद्धान्तों पर उसका नियम अंतिम माना जायेगा।
- (ii) चर्च ही धर्म ग्रंथ का अर्थ लगा सकता है।
- (iii) बाईबल का अनुवाद लैटिन भाषा में किया जायेगा और इस नई बाईबल का नाम वल्लेट मस्करण रखा जायेगा।
- (iv) भविष्य में चर्च के पदों को नहीं बेचा जायेगा।
- (v) विशप अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे।
- (vi) पादरियों को स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जायेगी।
- (vii) धर्म के उपदेश सरल भाषा में दिये जायेंगे।
- (viii) कुछ पुस्तकों को कथोलिका को पढ़ने के लिये मना कर दिया गया।

इस प्रकार कथोलिक चर्च को संगठित और शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया।

(3) जेसुइट संस्था—जिन लोगों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर लिया था उन लोगों का पवित्र कर पुनः कथोलिक बनाने के लिए एक संस्था स्थापित की गई जिसे जेसुइट संस्था के नाम से पुकारा जाता है। इस संस्था की स्थापना स्पेन में स्पेन निवासी इग्नाशियस लायेला के द्वारा 1534 ई० में की गई थी। लायेला एक सैनिक था। उसने 1491 ई० से 1556 ई० तक एक सैनिक के रूप में कार्य किया। एक युद्ध में घायल हो जाने के कारण उस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहाँ उसने ईसा मसीह और अन्य धार्मिक महात्माओं की जीवनिया पढ़ी। इन धार्मिक पुस्तकों से प्रभावित होकर उसने कथोलिक धर्म की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। इस समय उसने पोप की स्वीकृति से कथोलिक धर्म की रक्षा करने के लिये जेसुइट नामक संस्था की स्थापना की। इसका गठन सैनिक अनुशासन पर आधारित था। इस संस्था का काम ईसा के आदेशों का पालन करवाना था। इसके अनुयायी जेसुइट के नाम से प्रसिद्ध हुए।

जेसुइट संस्था के सदस्यों को सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता था। यह प्रशिक्षण बहुत कठोर होता था। इस संस्था के नेता को जनरल (सनापति) के नाम से पुकारा जाता था, जो पोप के प्रति कर्णदारी से कार्य करने की शपथ ग्रहण करता था। इस संस्था का प्रत्येक सदस्य पोप के आदेशों का पालन करने की तथा प्रत्येक और अनुशासन में रहने की शपथ लेता था। किंगी की सम्पत्ति की पादरी के पद पर नियुक्ति देने में पहले उसे न्यायमानता का प्रमाण दिया जाता था। उस अवधि में उन्हें धर्म और मानवतावादी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिये विश्व के किसी भी कोने में भेजा जा सकता था।

इस सस्या के सन्स्था का मुख्य काम स्कूला म छोटे बच्चो के दिल म कथोलिक धम के प्रति श्रद्धा पदा करना था । जा लोग प्रोटस्टैण्ट धम स्वीकार कर चुके थे, उह वापस पवित्त कर कथोलिक बनाना था । इसके सदस्या को दूर-दूर क देशा में कथोलिक धम का प्रचार करने क लिय भेजा जाता था । वहा पर य मदस्य गैर ईसाई लाया को रोमन कथोलिक धम स्वीकार करने क निय प्ररित करत थे ।

इस सरथा के सदस्य बडे उरसाह क साथ एक् स्थान स दूसरे स्थान घूम कर धम का प्रचार करत रहे और कथोलिक धम की रक्षा करने म सफ्त हुए । इन सदस्या क प्रयासा क परिणामस्वरूप बल्जियम इटली स्पेन, फ्रांस और पोण्ड के लोग कथोलिक धम क अनुयाई बन रहे । इहान भारत, चीन, अफ्रीका और अमेरिका जादि दर्शा मे भी पड़े उरसाह क साथ कथोलिक धम का प्रचार किया । इगनण्ट की शासिका एलिजाबेथ प्रथम जमुइट सस्या क सदस्यो मे परेशान रही क्यकि इ ही के प्रयासा स प्रोटस्टैण्ट धम की प्रगति में बाधा उपस्थित हो गई थी । इस सस्या क बहादुर सदस्य जेक्यूअम नाक्वैत न मिसीसिपी घाटी के उत्तरी भागो की खोज की और वहा अनेक अमरिक्न आदिवासिया को कथोलिक धम ग्रहण कर थाया । इसी प्रकार एक अय सदस्य फ्रांसिस जेवियर ने जापाा पहुच कर कथोलिक धम का उरसाह के माथ प्रचार किया । यह सस्या चच क गठन क लिये बहुत लाभ दायक सिद्ध हुई ।

(4) धार्मिक अदालतें—मध्यकालीन समय म रोमन कथोलिक चच के अपने 'यायालय थे । जिसम राजाओं की अदालतना में हुए फसलो क विरुद्ध अपील की जाती थी । जिस पर धर्माधिकारी अपना अंतिम निणय सुनाते थे और धम द्रोहिया को सजा देते थे । धम सुधार आन्दोलन के कारण चच ने अपने 'यायालयो का फिर स गठन किया जिसे 'इक्विजिशन ' के नाम से जाना जाता है ।

जेसुइट सस्या की स्थापना के दा वप पश्चात् पोप पाल तृतीय ने इक्विजेशन अदालत क छ मुख्य 'यायाधीशों (इक्विजिशन जनरल) की नियुक्ति की । इस अदालत का मुख्य काय धम पाखडिया को बठोर से बठोर दण्ड देना था । इसके अतिरिक्त सदेहजनक व्यक्तियो को गिरफ्तार करना उन्हें शारीरिक यातनाएँ देना, धम विरोधी पुस्तको को जलवा देना इसके मुख्य काय थे । इस अदालत ने धम विरोधियों का दमन बडी निममता पूचक किया । स्पेन, हालण्ड, बेल्जियम और इटली आदि देशा में हजारो व्यक्तियों को धम द्रोही घोषित कर जिन्म अग्नि को भेंट कर दिया गया और लाया व्यक्तियो को शारीरिक दण्ड दिये गये ।

इम प्रकार स्पष्ट है कि प्रति धम सुधार आन्दोलन कथोलिक धम की रक्षा करने मे सफल हुआ । इस समय कथोलिक धम प्रगति के पथ की ओर निरन्तर बढ़ता रहा ।

धम सुधार आन्दोलन के परिणाम—यद्यपि धम सुधार आन्दोलन एक धार्मिक

आन्दोलन था, तथापि इसका प्रभाव शासन स्वल्प तथा मानव समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। धर्म-सुधार आन्दोलन का निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा—

(1) एकता की समाप्ति—मध्य युग में धर्म में यूरोपवासियों की एकता के सूत्र में बाध लिया था। धर्म सुधार आन्दोलन के कारण यह एकता समाप्त हो गई। इस आन्दोलन से पहले सम्पूर्ण यूरोप पर कथोलिक धर्म की घाक जमी हुई थी, परन्तु प्रोटेस्टेंट धर्म ने पोप की सर्वोच्च सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। अब पोप के लिये समझ नहीं था कि सम्पूर्ण यूरोप के लोगों को धर्म के नाम पर एकता के सूत्र में बाध सके। इस आन्दोलन के कारण ईसाई धर्म दो सम्प्रदायों कथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित हो गया। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट धर्म भी अनेक सम्प्रदायों में विभाजित हो गया। इस तरह बार-बार धर्म का विभाजन होने के कारण धर्म की एकता समाप्त हो गई।

(2) कथोलिक धर्म में आंतरिक सुधार—प्रोटेस्टेंट धर्म ने कथोलिक धर्म की प्रगति में बाधा उपस्थित कर दी थी। इसलिये कथोलिक धर्म के धर्माधिकारियों ने प्रोटेस्टेंट धर्म की गति को रोकने के लिये प्रयास करने प्रारम्भ कर लिये थे।

1545 ई०-1560 ई० तक ट्रेण्ट नामक नगर में रोमन कथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने तथा धर्म के सिद्धांतों पर पुन विचार करने के लिये विभिन्न धर्म सम्मेलन आयोजित किये जाते रहे। जिसमें अनेकों पादरियों ने भाग लिया। इस धर्म अधिवेशन में कथोलिक धर्म में सुधार करने के सम्बन्ध में अनेक निणय लिये गये। रोम के पोप ने इन धार्मिक सम्मेलनों में भाग लिया तथा कौंसिल के निणय को लागू करने का वचन दिया।

इस कौंसिल के निणयानुसार पोप ने सादगीपूर्ण जीवन अयत्न करना प्रारम्भ कर दिया। अब पादरी के पद पर योग्य एवं चरित्रवान अयत्तियों को ही नियुक्ति दी जाने लगी और क्षमा पत्रों की बिक्री बंद कर दी गई। स्कूलों में छात्रों को बाइबिल का विषय पढ़ाया जाने लगा। चर्च में इन सुधारों के कारण एक नई स्फूर्ति आ गई। और प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति धीमी हो गई। इतिहास में रोमन कथोलिक धर्म के आंतरिक सुधार को प्रति धर्म सुधार आन्दोलन के नाम से पुकारा जाता है।

कथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिये लायला द्वारा जेसुइट संस्था की स्थापना की गई थी। इस प्रकार धर्म सुधार आन्दोलन के कारण पोप के व्यक्तिगत जीवन में सुधार किया गया और रोमन चर्च में व्याप्त आंतरिक कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार प्रतिधर्म सुधार आन्दोलन ने जहाँ एक ओर धार्मिक सुधार आन्दोलन की गति धीमी कर दी, वहाँ दूसरी ओर चर्च का पुनर्गठन किया गया और उसके आन्तरिक सुधार किया गया।

(3) ईसाई धर्म की एकता का नष्ट होना धर्म सुधार आन्दोलन ने

ईसाई धर्म की एताका को नष्ट कर दिया, जिससे धर्म सम्प्रदायों का विनाश हुआ। सम्पूर्ण यूरोप पर रोमन चर्च का एक छत्र शासन नहीं रहा और अनेक देशों में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की गई। ईसाई धर्म दो बड़े सम्प्रदायों में विभाजित हो गया। पहला, रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय और दूसरा, प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय। प्रोटेस्टेंट धर्म में भी अनेक सम्प्रदाय बन गये, क्योंकि इस सम्प्रदाय के लोग बाइबल को ही धर्म का आधार मानते थे और प्रत्येक विद्वान् बाइबल का अलग-अलग अर्थ लगाता था। इसलिये प्रोटेस्टेंट धर्म में भी अनेक सम्प्रदाय बन गये।

(4) धार्मिक असहिष्णुता की भावना का विकास— धर्म सुधार आन्दोलन के कारण धार्मिक असहिष्णुता की भावनाएँ प्रकट हुईं और धार्मिक सहिष्णुता की भावनाएँ समाप्त हो गईं। उस समय प्रत्येक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों को सर्व्व सिद्धांत बनाते हुए प्रचार कर रहा था और दूसरे सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की आलोचना कर रहा था। उस समय एक सम्प्रदाय ने दूसरे सम्प्रदाय को समाप्त करने का हर सम्भव प्रयत्न किया।

इसने परिणामस्वरूप यूरोप में धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता की भावना का विकास हुआ। जिसने कारण 30 वर्ष तक यूरोप में मध्य चलता रहा। इस समय की समाप्ति 1555 ई० की प्राग वग की संधि से हुई। धर्म के नाम पर हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गया। यदि किसी राज्य में शासन प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी होता तो वह अपने अधीन कैथोलिक धर्म के अनुयायियों पर निमग्न अत्याचार करता था और यदि कैथोलिक धर्म का अनुयायी होता तो वह अपने अधीन प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों पर अथवा अत्याचार करता था।

इसके बाद की शासिका मैरी ने कई प्रोटेस्टेंटों को जिया जला दिया। इसके पश्चात् नामकेन ने हजारों कैथोलिकों को धर्मद्रोही घोषित कर उनके मौत के घाट उतार दिया। जर्मनी में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच में 30 वर्ष तक भयंकर संघर्ष चलता रहा। फ्रांस के शासक ने भी प्रोटेस्टेंटों पर अमानुषिक अत्याचार किये। इस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता के कारण लम्बे समय तक के लिये यूरोपियन शान्ति भंग हो गई।

(5) राजाओं की शक्ति में वृद्धि— धर्म सुधार आन्दोलन के कारण यूरोपियन राजा अपनी शक्ति में वृद्धि करने में सफल हुए। अब राजाओं में निरंकुश और शक्तिशाली बनने की भावनाएँ विकसित हुईं। राजाओं ने अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिये और अपने स्वायत्त का पूरा करने के लिये पाप से सम्बन्ध टाहन शुरू कर दिया। इस प्रकार इस आन्दोलन के कारण यूरोप में निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति का विकास हुआ।

पहले सम्पूर्ण यूरोपियन देशों में राजा पाप की अधीनता में शासन कर रहे थे, परन्तु प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार करने वाले राजा पाप की अधीनता से मुक्त हो

भूरे थे। एक राज्याधीनता की सभ्यता बहुत अधिक थी। इन भागवा १ अथवा राज्याधीनता की राष्ट्रीय धर्म की स्थापना की जिम्मेदारियों का अधिकार मन्त्रिमंडल हुआ करता था। अब प्रोटेस्टेंट धर्म का मानने वाला राज्याधीनता पर किंगी का नियंत्रण नहीं था और राज्य की सावधानीय शक्ति उगम हाथ में बद्धित थी। इसविषये अब राजा धीरे धीरे निरस्त होने लगे।

(6) राष्ट्रीयता का विकास—धर्म मुद्दारा आन्दोलन के कारण जनता में राष्ट्रीयता की भावनाओं का तेजी से विकास हुआ। इस भावना १ लोगों को एक मूल में बांध दिया। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर सभी देशों १ लोग विरोधी आन्दोलन चलाया। अब धर्म का स्थान मन्त्रिमंडल के अंदर धर्म का स्थान राज्य के ले लिया। सेवान् १ लिखा है कि 'राष्ट्रीयता का जन्म इसी विद्रोह में हुआ था। प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय कई प्रकार से राष्ट्रीयता का निर्माता सिद्ध हुआ। व्यापार पर स मध्यकालीन प्रतिबंध उठ गये, अधिक ध्यान सेना जापन व्यापार बन गया और पुरानी वाईबिल के विचारों के विपरीत सम्पत्ति प्रमुख का आशीर्वाद समझी जाने लगी।'

(7) वैश्विक धर्म का प्रसार—प्रति धर्म मुद्दारा आन्दोलन के कारण जेसुइट सभ्यता के सभ्य वैश्विक धर्म का प्रचार करने के लिए विश्व में सभी भागों में पहुँचे। उन्होंने बड़े साहस और उत्साह के साथ अपने धर्म का प्रचार किया। परिणामस्वरूप वैश्विक धर्म का चीन जापान, अफ्रीका और अमेरिका आदि देशों में भी प्रचार हुआ।

(8) शिक्षा के क्षेत्र में विकास—धर्म मुद्दारा आन्दोलन के कारण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। जब वैश्विक धर्म का पतन होने लगा तो लोग ने शिक्षा के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। स्कूलों में छात्रों को धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। दूसरी तरफ धर्म मुद्दाराओं ने भी शिक्षा के विकास की ओर ध्यान दिया ताकि वैश्विक धर्म में व्याप्त दुराइयों का निवारण किया जा सके। प्रोटेस्टेंट तथा प्यूरिटन के धर्म प्रचारकों ने बच्चों की सम्पत्ति को जप्त करके शिक्षा का विकास किया। उनका यह मानना था कि शिक्षा के विकास से जनता को धार्मिक भ्रम विस्थापित से मुक्ति मिल जायेगी।

स्कूलों में लोक भाषा में शिक्षा दी जाने लगी ताकि अधिक से अधिक शिक्षा का विकास हो सके। उस समय लोक भाषा में ही साहित्य को प्रकाशित करवाया गया ताकि अधिक से अधिक लोग उसका अध्ययन कर पायदा उठा सकें। लूथर ने जर्मनी की भाषा में वाईबिल का अनुवाद किया था। उसका अनुसरण करते हुए अन्य देशों में लोक भाषाओं में वाईबिल का अनुवाद किया गया। धर्म प्रचारकों ने

अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया। जिसने फलस्वरूप लोगों में अपनी स्थानीय भाषा के प्रति श्रद्धा की भावनाएँ विकसित हुईं। मकनल वनस ने लिखा है कि इसने "इसने व्यक्तिवाद और लोकप्रिय शिक्षा के विस्तार को गति प्रदान की। शिक्षा का प्रभावशाली प्रसार हुआ। लूथरवादी, कन्वर्जेंट और जम्ब्वेन सभी समाज की शिक्षित बनाने में लग गये।"

(9) नतिक जीवन में सुधार — धम सुधार आन्दोलन के कारण पादरियों के नतिक जीवन में सुधार हुआ। अब उन्होंने आदर्श और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। पोप ने क्षमा पत्रों की प्रिन्टों पर रोक लगा दी। प्रोटेस्टेंट धर्म के पादरियों का विवाह करने की अनुमति दे दी, परन्तु उन्हें सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। प्रोटेस्टेंट धर्म के गिरजाघर सादे बन हुए होते थे, ताकि पादरी गिरजाघर को देखकर अपने जीवन में सादगी और सच्चरित्रता आदि गुणों का समावेश कर सकें। गिरजाघरों में नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें प्रभावित होकर जन साधारण ने नतिक जीवन की ओर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहास में धम सुधार आन्दोलन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस काम को पुनर्जागरण ने प्रारम्भ किया था उस काम को धम सुधार आन्दोलन ने पूरा किया। इसने समाज और राष्ट्र की प्रगति की ओर अग्रसर किया। यह धमसुधार आन्दोलन ही था जिसने यूरोप को आधुनिक रूप प्रदान किया। फ्रेन चिन्टन ने लिखा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयाईयों ने आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारधारा का विकास किया।

1 मकनल वनस — वस्टन सिवलीजेशंस, पृष्ठ 417 18

प्रस्तावित सवध पाठ्य पुस्तकें —

- 1 बीच डब्ल्यू० एन० — हिस्ट्री आफ दी चर्च
- 2 एलिस और जॉन — मसार का इतिहास
- 3 मकनल वनस — वस्टन सिवलीजेशंस
- 4 प्लेट जॉन और डमड — विश्व का इतिहास
- 5 सेवाइन — ए हिस्ट्री आफ चर्च सिवलीजेशंस
- 6 वेल्स एच० जी० — दी आउट लाइन आफ हिस्ट्री।

फ्रांस की राज्य-क्रान्ति

फ्रांस की राज्य क्रांति का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति ने नये समाज का निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्य युग में राजा लोग दबिब सिद्धांत का अनुसार प्रजा पर शासन करते थे। वे अपना को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उनकी इच्छा ही कानून थी और राज्य की सारी शक्ति उनके हाथों में केंद्रित होती थी। उनका नियम अतिम नियम समझा जाता था। वे जनता पर निरंकुश रूप से शासन करते थे। जनता को आघ मूढ़ कर उनकी आवाज का पालन करता पड़ता था। राजा के कामों की आलोचना करने का अधिकार जनता को प्राप्त नहीं था।

मध्यकाल में कुलीन वर्ग के सदस्य राजा का निरंतर समर्थन करते थे। इसलिए सम्पूर्ण प्रशासन की बागडार इसी वर्ग के हाथों में थी। राजा ने इस वर्ग को विशेषाधिकार दे रखे थे। कुलीन वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए जनता का शोषण करते थे।

सांसारिक क्रांति और पूँजीवाद के उदय के कारण एक नये वर्ग, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। जिसके पास धन सम्पत्ति और बुद्धि थी। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को समाज में भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इस वर्ग को कुलीन वर्ग की भाँति राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे इसलिए मध्यम वर्ग ने देश में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के लिए माँग की। शक्ति ही नहीं इस वर्ग ने भाषण, लेखन और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सघन प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप जनता राजनीतिक अधिकारों की माँग करने लगी और सभी स्थानों पर लोग एक ही नारा लगा रहे थे कि 'जनता की आवाज ही परमेश्वर की आवाज है।'

यह सघन सब प्रथम हालैंड में प्रारम्भ हुआ। इंग्लैंड की रक्तहान्य क्रांति और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने इस सघन का प्रोत्साहित किया। उत्तरी

अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ के निवासियों ने अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर 1779 ई० में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सघन प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप 1783 ई० में उन अंग्रेजों की दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली। इसी समय फ्रांस में भी सामाजिक और राजनीतिक सबूट उत्पन्न हुआ, जिससे समस्त विश्व का राजनीतिक वातावरण अशांत बना दिया।

फ्रांस की राज्य क्रान्ति का मुख्य आधार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, जबकि अंग्रेजी व अमेरिकन स्वतन्त्रता क्रान्ति का मुख्य आधार राजनीतिक व्यवस्था थी। इसीसे फ्रांसीसी क्रान्ति तत्कालीन समाज के लिए भयंकर सिद्ध हुई। इस क्रान्ति से अंग्रेजी व अमेरिकन क्रान्ति की अपेक्षा किसानों को अधिक लाभ पहुँचा था।

इतिहासकाराने अठारहवीं शताब्दी की एक क्रान्ति की शताब्दी माना है क्योंकि इस शताब्दी में अनेक क्रान्तियाँ हुईं, जिसके कारण यूरोप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परन्तु फ्रांस की राज्य क्रान्ति के कारण सम्पूर्ण सभ्यता के दश प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।

फ्रांस में क्रान्ति पहले निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम थी। राज्य की सारी शक्ति सम्राट के हाथों में केन्द्रित थी। उस समय फ्रांस पर सुई सोनहवा जसा अयोग्य शासन शासन कर रहा था, इसलिये फ्रांस में अराजकता एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। उस समय पादरी आर सामन्त जनता को शासन कर रहे थे। जनता को अनेक कर देने पड़ते थे। इसलिये जनता बहुत परेशान थी। जनता को शायद नहीं मिल पा रहा था। 175 साल के तानाशाही शासन से परेशान होकर घर्माघारियों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए फ्रांस की जनता के सामने क्रान्ति के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं था। इसलिये फ्रांसीसियों ने 1789 में इस निरंकुश शासन के जुए का उतार फेंकने के लिये जा प्रयत्न किया, उस इतिहास में 'फ्रांस की राज्य क्रान्ति' के नाम से जाना जाता है।

प्रोफेसर डेविस ने लिखा है कि फ्रांस की राज्य क्रान्ति से मानव जाति के इतिहास में एक नया युग आरम्भ हुआ। इसने सामन्तवाद की समाप्ति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और व्यक्तियों को सामाजिक व धार्मिक स्वतन्त्रता एवं समानता का अधिकार दिलवाया। इस क्रान्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी मनुष्य एक समान हैं इसलिये सभी को एक समान अधिकार मिलने चाहिये।

प्रोफेसर ल्यूकस ने इस क्रान्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि फ्रांस की राज्य क्रान्ति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना है जिनमें मध्य युग की परम्पराओं को पूर्ण रूप में नष्ट कर दिया।

सभी इतिहासकार फ्रांस की राज्य क्रान्ति का आधुनिक युग की सवम

महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। यूरोप के अन्य देशों में फ्रांस की भांति राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था विद्यमान थी, फिर प्रश्न यह उठता है कि यह क्रांति सब प्रथम फ्रांस में ही क्या आरम्भ हुई थी? इस क्रांति के कारणों का हम नीचे बर्णन करेंगे।

कुछ इतिहासकार फ्रांस की राज्य क्रांति को सामाजिक क्रांति का नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों का कारण यह क्रांति प्रारम्भ हुई थी। फ्रांस के शासक लुई सोलहवें की मूर्खता के कारण क्रांति अवश्यम्भावी हो गई। इस क्रांति के द्वारा कुलीन वर्ग और पादरिया का विशेष अधिकारों की समाप्ति की मांग की गई थी। इसको निम्न दो तत्वों में प्रेरित किया। पहला, पुरानी व्यवस्था की बुराईया और दूसरा फ्रांस का मध्यम वर्ग में बढ़ता हुआ असंतोष।

18 वीं शताब्दी के अंत में मध्यम वर्ग के लोगों ने सामंता के विशेष अधिकारों का विरुद्ध आंदोलन आरम्भ कर दिया। इस आंदोलन से फ्रांस में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, जिससे नये समाज का निर्माण सम्भव हो सका।

फ्रांस की क्रांति से पूर्व की स्थिति — इतिहासकारों ने सत्रहवीं शताब्दी को फ्रांस के उत्थान की और अठारहवीं शताब्दी को उसके पतन की शताब्दी बताया है। लुई चौदहवें के शासन काल में फ्रांस अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गया था। लुई चौदहवें की मृत्यु के पश्चात् उसने उत्तराधिकारी अयोग्य और दुबल सिद्ध हुये, जिसके कारण फ्रांस का विशाल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया। इतिहासकार बेन फिंगर ने लिखा है कि लुई चौदहवा विलासी शासक था। लुई पंद्रहवा अयोग्य शासक था जबकि लुई सोलहवा एक दुबल शासक था।

इस प्रकार फ्रांस के प्रशासन में अव्यवस्था फल रही थी। लुई सोलहवें के समय फ्रांस की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। इस पर भी वह दृष्टिकोण सिद्धांत के अनुसार निरंकुश शासक की तरह शासन कर रहा था। उसने सब से कहा था कि 'सावभौमिक सत्ता मेरे में निवास करती है। कानून बनाने की सारी शक्ति मेरे में है।'

लुई सोलहवाँ ने शासन करने की योग्यता का अभाव था। इसलिये उसके शासन काल में उसके दरबारियों और चाटुकारों के द्वारा शासन चलाया जाता था। उस समय फ्रांस का समाज तीन वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग सामंतों का और दूसरा वर्ग धर्माधिकारियों का एवं तीसरा वर्ग जनसाधारण था। पहले और दूसरे वर्ग के लोग किसानों का एवं मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे थे और वैभवतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। मध्यम वर्ग और किसानों से अत्यधिक मात्रा में सरकारी कर वसूल किया जाता था। किसानों को बेगार भी देनी पड़ती

फ्रांस की राज्य क्रांति

थी तथा अपने शासन बग के आमोद प्रमोद के खब वा भार भी उह वहन करना पडता था ।

शिक्षा पर घर्माधिकारियो का नियन्त्रण था, इसलिये शिक्षा का क्षेत्र अनुदार बना हुआ था । नवीन विचारो की पुस्तका के प्रकाशन पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा था । इस समय फ्रांस मे कई अच्छे विचारक और विद्वान पदा हुए थे परन्तु सरकार ने उनके विचारो के प्रसार पर कठोर नियन्त्रण लगा रखा था ।

फ्रांस के शहरो के कारखानो मे उस समय लगभग 25 लाख मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन औद्योगिक विकास नही होने के कारण इन मजदूरों की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी । उह बहुत घटो तब कारखानो मे काम करना पडता था । इस प्रकार स्पष्ट है कि 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे फ्रांस मे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रति भयकर असंतोष व्याप्त था । इसे फ्रांस वाले प्राचीन व्यवस्था भी कहते हैं । इस प्रकार की परिस्थितियो म फ्रांसीसी जनता का दम घुटा जा रहा था । इसलिये 1789 ई० मे फ्रांस की जनता ने अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा छडा कर दिया ।

फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण — 1789 ई० म हुई फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) राजनीतिक कारण — फ्रांसीसी क्रांति सम्राट की सत्ता को समाप्त करने के लिए आरम्भ नही हुई थी । इस क्रांति के नेता यह चाहते थे कि राजा की शक्ति को सीमित कर दिया जाये । उस समय फ्रांस के शासक लुई सोलहवें ने कुछ ऐसे मूलतापूण कदम उठाये, जिसके कारण क्रांति का स्वरूप ही बदल गया तथा फ्रांस म निरकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई । इससे यह स्पष्ट है कि उस समय की फ्रांसीसी जनता न शासन व्यवस्था मे व्याप्त बुराइयो को दूर करने का प्रयास किया ।

(2) राजा की निरकुशता — फ्रांस की भांति यूरोप के कई अ्य देशो म भी निरकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी । सम्राट की इच्छा ही मानून था । आरम्भ मे जनता सिर्फ यह चाहती थी कि सम्राट जन हित के कार्यों की ओर भी ध्यान देता रहे । प्रशा, आस्ट्रिया, रूस और स्पेन आदि देशो ने शासको ने भी जनता पर स्वेच्छाकारी शासन किया । परन्तु उनके विरुद्ध विद्रोह इसलिये नही हुआ, क्योंकि वे जनता के हित का ध्यान रखते थे । फ्रांस के सम्राट जन हित कार्यों की उपेक्षा करते हुए जब निरकुश रूप से शासन करते रहे, फलस्वरूप उनके विरुद्ध विद्रोह होना अवश्यम्भावी हा गया ।

फ्रांस के ये निरकुश राजा दबो सिद्धांत के अनुसार अपनी प्रजा पर शासन करते थे । लुई चौदहवें ने फ्रांस म सुदृढ़ रूप से निरकुश राजतन्त्रात्मक शासन

महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। यूरोप के अन्य देशों में फ्रांस की भांति राजनतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था विद्यमान थी, फिर प्रश्न यह उठता है कि यह क्रांति सब प्रथम फ्रांस में ही क्या आरम्भ हुई थी? इस क्रांति के कारणों का हम नीचे वर्णन करेंगे।

कुछ इतिहासकार फ्रांस की राज्य क्रांति को सामाजिक क्रांति के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों के कारण यह क्रांति प्रारम्भ हुई थी। फ्रांस के शासक लुई सोलहवें की मूर्खता के कारण क्रांति अवश्यम्भावी हो गई। इस क्रांति के द्वारा कुलीन वर्ग और पादरिया के विशेष अधिकारों की समाप्ति की भाग की गई थी। इसको निम्न दो तत्वों ने प्रेरित किया। पहला पुरानी व्यवस्था की बुराईया और दूसरा फ्रांस के मध्यम वर्ग में बढ़ता हुआ असंतोष।

18 वीं शताब्दी के अन्त में मध्यम वर्ग के लोगान सामन्तों के विरोध अधिकारों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। इस आन्दोलन से फ्रांस में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, जिससे नये समाज का निर्माण सम्भव हो सका।

फ्रांस की क्रांति से पूर्व की स्थिति — इतिहासकारों ने सत्रहवीं शताब्दी की फ्रांस के उत्थान की ओर अठारहवीं शताब्दी को उसके पतन की शताब्दी बताया है। लुई चौदहवें के शासन काल में फ्रांस अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गया था। लुई चौदहवें की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और दुबल सिद्ध हुये, जिसके कारण फ्रांस के विशाल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया। इतिहासकार वेन फिगर ने लिखा है कि लुई चौदहवा विलामी शासक था। लुई पन्द्रहवा अयोग्य शासक था जबकि लुई सोलहवा एक दुबल शासक था।

इस प्रकार फ्रांस के प्रशासन में अव्यवस्था फल रही थी। लुई सोलहवें के समय फ्रांस की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। इस पर भी वह दबिब सिद्धांत के अनुसार निरकुश शासक की तरह शासन कर रहा था। उसने यह से कहा था कि 'सावभौमिक सत्ता भरे में निवास करती है। कानून बनाने की सारी शक्ति भरे में है।'।

लुई सोलहवाँ में शासन करने की योग्यता का अभाव था। इसलिये उसके शासन काल में उसके दरबारियों और चाटुकारों के द्वारा शासन चलाया जाता था। उस समय फ्रांस का समाज तीन वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग सामन्तों का और दूसरा वर्ग धर्मधिकारियों का एवं तीसरा वर्ग जन-साधारण था। पहले और दूसरे वर्ग के लोग किसानों का एवं मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे थे और वृद्धतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। मध्यम वर्ग और किसानों से अत्यधिक मात्रा में सरकारी कर वसूल किया जाता था। किसानों को बेगार भी देनी पड़ती

थी तथा अपने शासन बग के आमोद प्रमोद के घब का भार भी उह वहन करना पड़ता था ।

शिक्षा पर घर्माघिकारियों का नियंत्रण था, इसलिये शिक्षा का क्षेत्र अनुदार बना हुआ था । नवीन विचारों की पुस्तकों के प्रकाशन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था । इस समय फ्रांस में कई अच्छे विचारक और विद्वान पदा हुए थे, परंतु सरकार ने उनके विचारों के प्रसार पर बड़ी नियंत्रण लगा रखा था ।

फ्रांस के शहरों के कारखाना में उस समय लगभग 25 लाख मजदूर काम पर रहे थे, लेकिन औद्योगिक विकास नहीं होने के कारण इन मजदूरों की आर्थिक शक्ति बहुत शीघ्रनीय थी । उह बहुत घटो तक कारखाना में काम करना पड़ता था । इस प्रकार स्पष्ट है कि 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में फ्रांस में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रति भयंकर असंतोष व्याप्त था । इसे फ्रांस वाले प्राचीन व्यवस्था भी कहते हैं । इस प्रकार की परिस्थितियों में फ्रांसीसी जनता का दम घुटा जा रहा था । इसलिये 1789 ई० में फ्रांस की जनता ने अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा फड़ा कर दिया ।

फ्रांस की राज्य प्राप्ति के कारण — 1789 ई० में हुई फ्रांस की राज्य प्राप्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) राजनीतिक कारण — फ्रांसीसी प्राप्ति सम्राट की सत्ता को समाप्त करने के लिए आरम्भ नहीं हुई थी । इस प्राप्ति के नेता यह चाहते थे कि राजा की शक्ति को सीमित कर दिया जाये । उस समय फ्रांस के शासक लुई सोलहवें ने कुछ ऐसे मूखतापूर्ण कदम उठाये, जिसके कारण प्राप्ति का स्वरूप ही बदल गया तथा फ्रांस में निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई । इससे यह स्पष्ट है कि उस समय की फ्रांसीसी जनता न शासन व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया ।

(2) राजा की निरंकुशता — फ्रांस की भांति यूरोप के कई अन्य देशों में भी निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी । सम्राट की इच्छा ही मानून था । आरम्भ में जनता तब यह चाहती थी कि सम्राट जन हित के कार्यों की ओर भी ध्यान देता रहे । प्रज्ञा, आम्तिमा, हस और स्पेन आदि देशों के शासकों ने भी जनता पर स्पेष्टानारी शासन किया । परंतु उनके विरुद्ध विद्रोह इसलिये नहीं हुआ, क्योंकि वे जनता के हित का ध्यान रखते थे । फ्रांस के सम्राट जन हित कार्यों की उपेक्षा करते हुए जब निरंकुश रूप में शासन करते रहे, तब स्वरूप उनके विरुद्ध विद्रोह होना अवश्यभावी हो गया ।

फ्रांस में वे निरंकुश राजा दसवीं गिदान्त के अनुमार अपनी शक्ति पर शासन करते थे । लुई सोलहवें ने फ्रांस में निरंकुश रूप में निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन

यवस्था का स्थापना कर दी थी। वह तो यज्ञ तो कहता था कि "मैं ही राज्य हूँ तथा मेरे शब्द ही बानून हैं" फ्रांस व शासन जनता का राज्य बाँटने में भाग देने के विराधो थे।

फ्रांस का राजा बापपात्रिका यवस्थापिका और यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा शासन व सभी अधिकारियाँ की नियुक्ति स्वयं करता था और जिस चाहता उसे पदच्युत कर सकता था। उसकी इच्छा से बानूनो का निर्माण करता था और इच्छानुसार उन्हें समाप्त कर देता था। यायपात्रिका के शेष में उमराव नियम जतिम समझा जाता था। वह जिसे चाहता दण्ड दे सकता था। उसकी स्वीकृति व बिना गिरजाघरा की मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी।

फ्रांस में उस समय किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं थी। राजा जिस व्यक्ति को चाहता, गिरफ्तार करवा सकता था और बिना मुद्दमा चलाये उस व्यक्ति को जितनी सजा देना चाहता दे सकता था। राजा के चाटुकार भी इस अधिकार का उपयोग कर रहे थे। वे राजा द्वारा बंधे जाने वाले लटस डी कचेट" (गिरफ्तारी पत्र) को घन पैकर खरीद लेते थे। इसमें गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के नाम का स्थान रिक्त रखा जाता था ताकि इस पत्र को खरीदने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाना चाहे उस व्यक्ति का नाम रिक्त स्थान में भर देता था जिससे कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्य की सारी शक्ति राजा के हाथों में केन्द्रित थी और राजा निरवुण रूप से जनता पर शासन कर रहे थे। इसीलिए फ्रांस के शासक ने 175 वर्ष तक स्टेटस जनरल (प्रतिनिधि सभा) की बख्त नहीं घुलाई थी। यही कारण था कि फ्रांस की जनता राजा की निरवुण शक्ति का विरोध करने लगी।

(11) शासकों की अयोग्यता — लुई चौदहवें के उत्तराधिकारी अयोग्य एवं दुबल सिद्ध हुए। उन्होंने भोग विलास पूर्व जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया और राजकीय कार्यों व प्रति उदासीन हो गये। वे अपने चापलूस और स्वार्थी सलाहकारों की सलाह से शासन चला रहे थे, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे हुए थे।

लुई चौदहवें की मृत्यु के पश्चात् लुई पन्द्रहवा फ्रांस का शासक बना। वह स्वयं आलसी और विलासी था। उसके मंत्री भी दुबल तथा अयोग्य थे। उसमें शासन करने का योग्यता का अभाव था। उसके दरबारी विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके समय में हुए युद्धों के कारण फ्रांस की राजनीतिक और आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। जब 1774 ई० में लुई पन्द्रहवें की मृत्यु हुई तो लोग ने शोक के स्थान पर खुशी जाहिर की और उसकी शव यात्रा के समय लागा न गाने गाने गाने एवं अशिष्ट गाने गाने।

तुई पात्रहवें ी मृत्यु के पश्चात् तुई सोलहवा 16 वष की आयु म फ्रांस का शासक बना । वह राज्य की समस्त शक्ति को अपन लाया म केन्द्रित करना चाहता था परंतु उसम श सत् करने की माग्यता का अभाव था । उसक शासनकाल म सत्ताह्वारो का प्रभाव प्रशासन पर इस तरह छाया हुआ था कि वह चाहने हुए भी जनहित क लिय कोई काय नही कर सका । वह अपन छोटे भाई व अपनी रानी की सलाह से शासन चला रहा था । ये लोग अपन स्वाध पूति में लगे हुए थे । इसलिये तुई सोलहवें के शासनकाल म राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई । प्रोफेसर हस न मत्य ही लिखा है कि फ्रांसीसी सम्राट इतना अयोग्य और दुबल थे कि व समस्या को हल करने म असफल रह, जिसक कारण फ्रांस म प्राति हुई ।

(iii) शासन व्यवस्था के दोष—फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था म अनेक दोष विद्यमान थे । फ्रांसीसी सम्राट ने इन दोषो को दूर करने का कभी प्रयास नही किया । कई शताब्दिया के फ्रांसीसी सम्राट अपन चापतूस और स्वार्थी सलाहकारों की सहायता स निरकुश रूप से करते आ रहे थे । फ्रांस की शासन व्यवस्था अत्यन्त दूषित थी । यहां क सम्राट ने बिना किसी आधार के जिला तथा प्रांतो का विभाजन कर दिया था । प्रत्येक प्रांत व जिले म भिन्न भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था व कर प्रणाली विद्यमान थी । प्रांतोय शासका पर केंद्र का नियन्त्रण नाम मात्र का था । व अपने प्रांत म निरकुश रूप से शासन कर रहे थे । वे किसी भी मनुष्य को बिना जांच किये जेल म डाल सवने थे ।

(iv) दोषपूर्ण याय व्यवस्था—फ्रांस की याय व्यवस्था मे व्याप्त अयाय और निरकुश याय प्रणाली ने भी जनता को प्राति करने के लिय प्रेरित किया । यहां के प्रत्येक प्रांत म भिन्न भिन्न याय प्रणालियां प्रचलित थीं । देश के भिन्न भिन्न भागा म अलग अलग कानून प्रचलित थे । यदि किसी एक राज्य मे जमान कानून प्रचलित था ता दूसरे राज्य म रोमन कानून प्रचलित था । सम्पूर्ण फ्रांस म 400 याय प्रणालियां प्रचलित थीं । इन प्रकार फ्रांस म एक जैसी याय व्यवस्था नही थी, इसलिये किसी प्रांत म एक अपराध के लिये बठोर सजा दी जाती थी तो दूसरे प्रांत म उसी अपराध के लिये साधारण सजा दी जाती थी ।

फ्रांस म दण्ड विधान बहुत बठार था । कानून नियमो और याय हीन थे । साधारण अपराध क लिये भां कडी से कडी सजा दी जाती था । उम समय अपराधी को चक्र के नीचे पीसकर उसकी हड्डिया का चूरा बना दिया जाता था, अथवा नाक या कान काट लिये जाते थे । प्रभावशाली व्यक्ति जिस व्यक्ति को जेल भिजवाना चाहत उसे बिना मुकदमा चलाये अनिश्चितकाल के लिये जेल भिजवा सकत थे । फ्रांस मे जीवन पय 'व काय करन वाले मायाधीश को "चोगे वाले सामंत" के नाम से पुकारा जाता था । यह पद उचा व छरीदा जा सवता था । ये यायाधीश अपराधियों से भारी जुमनि वसूल करत थे और अपनी जेबें भरते थे । फ्रांस म ऐसे

यायाधीशा की सख्या लगभग पचास हजार थी। इस प्रकार यह वष फ्रांस के समाज के लिये एक अभिशाप बना हुआ था।

(v) शासकों का विलासी जीवन—लुई चौदहवें ने पेरिस से 12 मील दूर वर्साय नामक नगर में 30 करोड़ रुपये खर्च करके एक सुन्दर शीश-महल का निर्माण करवाया था, जिसमें सम्राट बड़ी ध्यान से विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करता था। लुई चौदहवा और उसके उत्तराधिकारी वर्साय के शीश महल में अत्याशी जीवन व्यतीत करते रहे।

लुई सोलहवें के लिये 1600 दास तथा महारानी मेरी के लिये 800 दासिया काम करती थीं। सम्राट लुई सोलहवें ने अपने दरबार में अनेक चापलूस सामन्त और जागीरदार नियुक्त कर दिये थे, जो राज्य के पक्ष पर गुलछरें उड़ा रहे थे। 1789 ई० में राजा के विलासी जीवन पर लगभग 6 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था। महारानी मेरी एंटोयनट बहुमूल्य वस्तुएँ खरीदने के लिये प्रजा का पैसा पानी की तरह बहाती थी। ऐसा अनुमान है कि क्रान्ति से पूर्व पन्द्रह वर्षों में लुई सोलहवें ने 30 करोड़ रुपये अपने चापलूसों और वृषपापात्रों में बांट दिये थे। इस प्रकार धन के अपभ्यय के कारण राजकीय कोष रिक्त होता जा रहा था।

(vi) समारों की साम्राज्यवादी नीति—प्रोफेसर एच जी वल्स ने लिखा है कि इंग्लण्ड और अमेरिका की भांति फ्रांसीसी क्रान्ति का एक कारण यह था कि यहाँ के सम्राट साम्राज्यवादी नीति का पालन कर रहे थे। लुई चौदहवें के उत्तराधिकारी उसकी साम्राज्यवादी नीति पर चल रहे थे, जिसके कारण फ्रांस को अनाश्यक रूप से यूरोप के कई युद्धों में भाग लेना पड़ता था।

इन युद्धों में राज्य का काफी धन खर्च होता था। दूसरी तरफ सम्राट अपने वश पर अत्यधिक धन खर्च कर देता था। इस धन की पूर्ति करने के लिये जनता पर अधिक से अधिक कर लगाये जाते थे। जनता इन बढते हुए करा के भार से तग हो चुकी थी।

(vii) फ्रांस की विदेश नीति की असफलता—फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवें ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी विदेश नीति पूरणरूप से सफल रही। उसके समय फ्रांस की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढी। लुई चौदहवें की मृत्यु के पश्चात् उसके दुबल उत्तराधिकारियों के शासन काल में फ्रांस का साम्राज्य घटने लगा। इसलिये सम्राट की जनता में बहुत बदनामी हुई। जनता ने उन अयोग्य सम्राटों का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया।

(viii) स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध—फ्रांस की जनता को भाषण, विचार, लेखन प्रकट करने और धर्म की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। इसलिये जनता के सामने क्रान्ति के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं था। जनता सम्राट की निरकुशता के

विरुद्ध किसी प्रकार की आवाज नहीं उठा सकती थी, इसलिये जनता में भयकर असन्तोष व्याप्त था। यह असन्तोष क्रांति के रूप में प्रकट हुआ।

यदि फ्रांस में लोगों की विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होती तो संभव था कि क्रांति कुछ समय के लिए टल जाती। लोग निरकुश शासन के विरुद्ध अपने विचार प्रकट कर अपने गुस्से को शांत कर लेते। फ्रांस के लोगों का न तो राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी और न ही धार्मिक स्वतन्त्रता। उस समय फ्रांस का राज धर्म कथोलिक था, इसलिये प्रोटेस्टेंट धर्मावलम्बियों पर भयकर अत्याचार किये जाते थे। उनको कठोर से कठोर मजायें दी जाती थी। यदि कोई व्यक्ति फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्म में विश्वास रखता था तो उसे धर्म छोड़ी घोषित कर मौत की सजा दी जाती थी। उस समय राजा के कृपापात्रों को यह अधिकार था कि वे जिस व्यक्ति को चाहते बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार कर सकते थे और उस इच्छानुसार सजा दे सकते थे।

फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन से स्पष्ट है कि क्रांति से पूर्व सम्पूर्ण फ्रांसीसी साम्राज्य में अराजकता एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। उसी स्थिति में क्रांति होना स्वाभाविक सी बात थी। प्राकटनवी ने उस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'विशेषाधिकार, रियासत विमुक्ति, कानून नहीं, फ्रांसीसी समाज के आधार थे। उनके शासकों की नीति इच्छानुबूल थी सिद्धांत नहीं। इसलिये कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि क्रांतिकारियों की सबसे पहली मांग संविधान के नियमों थी, जिससे उनका अभिप्राय था कि देश में कुछ व्यवस्था, कुछ संगठन हो।

(2) सामाजिक कारण—फ्रांस की राज्य क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण कारण सामाजिक था। "1789 की क्रांति स्वच्छाचारी एवं दमनपूर्ण शासन पद्धति के विरुद्ध युद्ध होने की अपेक्षा फ्रांसीसी समाज की असमानता के विरुद्ध एक महान संघर्ष था।" फ्रांस में सामाजिक असमानता ने सामाजिक अत्याय और बगवानों को जन्म दिया। पुरातन व्यवस्था के अनुसार फ्रांस का समाज तीन भागों में बंटा हुआ था।

(i) प्रथम इस्टेट—पादरी वर्ग

(ii) द्वितीय इस्टेट—कृषीन वर्ग

(iii) तृतीय इस्टेट—साधारण जनता, कृषक, और दाम आदि।

(i) पादरी वर्ग—प्रथम वर्ग धर्माधिकारियों या पादरियों का था, जिनका समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था। इन धर्माधिकारियों को कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। पादरी किसी भी व्यक्ति को चूक से निकाल सकते थे। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार समझा जाता था। पादरी ही सामाजिक नस्कारों का सम्पन्न करवाते थे। इन धर्माधिकारियों के पास अपार धन सम्पत्ति थी और फ्रांस

की विनाश भूमि पर उठाया अधिकार था। इसविषे न्त वास्तवों ने विनाश जीवा व्यतीत करवा प्रारम्भ पर किया था। अरु तत्रा तत्रिण तात प्रा गया था। इसविषे सुधार आं । न्त प्रारम्भ हुआ।

(ii) कृसीत वग—प्राग का दगग वग कृ सीत धरिषा का था कई प्रार के विनेपाधिकार प्रात थ। प्राग की ताग भूमि के एत थी पर कुनात वग का अधिकार था। उहें गामता व अधिकार प्रात थ, अपन अधिकारों का उपभाग करत थ और का व्या को पाता करता भूत गामता विमाता न कई प्रार ग अगा नता था। अग नामत विमान निय प्रात विगसता था। विमाता का गामता को शक्य व विन धगूर व मक्षण व निय अपन पनु दन पते थे। इस व अधिकार विमाता ग कागार टवग नम व टवग और भूमि टका जाति भां किया जाता था। यदि को अपनी भूमि दधाता ता उत भूमि ग प्रात घन का पांच व भाग उत साम देना पटा था।

सामंत कर्म कर्म पर साधारण जाता था अपमान करत थ। कृ सामाजिक उत्थगया म आगे नहीं बटा किया जाता था क्याकि आगे साम थ। कृपक साम त की रवीकृति व पश्चात ही अती ग तात का विवाह का था। कृपता व पुत्रा का समाज व गाय व उच व पर नियुक्त रही विप था। फिर भा जाता मध्य युग म सामता व दन वि पाधिकारा को दमति कर रहा थी क्याकि ये उनकी रक्षा करत थ।

जम-जम राजाशा व शक्ति म वद्धि हाता ग वस-वस सामता व की रक्षा करत व कत य स मुक्ति मिल गई। अब उनके लिये अधिकारा भोग करना उचित नहीं था। इस युग म साम ता का जाता स सम्पद दम गया क्याकि व अपनी जागीर को छांवर साम्राट के दरवार म रहा लगे। साम त फवल अपन अधिकारा का उपभोग करते थ और अपना कत य भू थे। इसनिय जाता उह अपना शोषक सम्पन लगी। जाता न उ ट पर तरह श्रद्धा और सम्मान देना छाट दिया। मरियट न लिखा है कि 1789 प्राप्त की राय प्राति पूणतया प्रत्य रप स वहां व सामता के अत्याच विरुद्ध थी।

(iii) साधारण वग—तीसरा वग साधारण वग था। जिनकी दश शोचनीय थी। इस वग म किसान शमिक, शिल्पकार और मध्यम वग के सम्मिलित थे।

(iv) कृपक तथा मजदूर की दशा—सामंत और पादरी वग किसान मजदूर का शोषण कर रहे थे। इस वग के लोग का धर्माधिकारियो साम राजा को अनक प्रकार के कर दन पडते थे। इस प्रकार एव किसान अपनी क

80 प्रतिशत भाग करो के रूप में चुका देता था और बचाया 20 प्रतिशत से वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। इस प्रकार इस वग की दशा बहुत दयनीय थी।

(घ) मध्यम वग का उत्थान—आधुनिक काल में यूरोप के कई देशों में मध्यम वग अथवा बुर्जुआ वग का उत्थान हुआ। फ्रांस में लगभग 2½ लाख व्यक्ति मध्यम वग के थे। इस वग ने काफी उन्नति कर ली थी और में लोग शिक्षित और बुद्धिमान थे। उनका समाज में अच्छा प्रभाव था। इन वग में व्यापारी, डाक्टर, वकील, प्राध्यापक वगैरे के अधिकारी जग और सभी शिक्षित लोग आते थे।

मध्यम वग के लोग शिक्षित और बुद्धिमान थे उनके पाम धन का अभाव नहीं था। समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, फिर भी उन्हें कुलीन वग की भांति राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और न ही कुलीन जसा सम्मान प्राप्त था। मध्यम वग के असंतोष का एक अन्य कारण यह भी था कि इस वग के लोग याग्य थे। फिर भी उनको राज्य के उच्च पदा पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इसलिए मध्यम वग ने शासन में जनता के अधिकारों की मांग का लेकर प्राप्ति को प्रारम्भ कर दिया। इस प्राप्ति का नेतृत्व मध्यम वग के द्वारा किया गया और सर्वाधिक लाभ भी इसी वग को प्राप्त हुआ।

(3) आर्थिक कारण—[1] फ्रांस की दुबल आर्थिक स्थिति—फ्रांस की प्राप्ति के समय आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई चौदहवें ने बहुत से युद्धों में भाग लिया। जिसके कारण बहुत अधिक धन खर्च हुआ जिससे राजकीय कोष खाली हो गया था। इतना ही नहीं लुई चौदहवां ने वधव और भोग विलास पर अत्यधिक धन का अपव्यय कर राज्य की आर्थिक दशा को शोचनीय बना दिया।

लुई पंद्रहवें ने भी फ्रांस की आर्थिक दशा में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने भी कई युद्धों में भाग लिया जिसके कारण अपार धन खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त उसने अपना महल और रक्षकों पर धन का बहुत अधिक अपव्यय किया। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था शोचनीय हो गई।

इतिहासकार बन फिगर ने लिखा है कि फ्रांस की राज्य प्राप्ति से पूर्व तक फ्रांस का धन सम्पत्ति पर घर्माधिकारियों और सामन्तों का अधिकार था। लुई चौदहवां पंद्रहवां और लुई सोलहवें के शासनकाल में जन साधारण की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय हो गई। साधारण वग के मनुष्यों के पाम बहुत कम भूमि थी। उनके साथ सामान होने वाले पशुओं की भांति व्यवहार किया जाता था।

जब लुई सोलहवां फ्रांस का सम्राट बना। तब फ्रांस आर्थिक दृष्टि से दिवा लिया हुआ चुका था। उसने फ्रांस की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए टरगा और

नेकर जस योग्य अथ शास्त्रियो को मंत्री के पद पर नियुक्त किया। लेकिन आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हो सका। इसलिये लुई सोलहवें ने विवश होकर 1789 ई. में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, जो क्रान्ति का कारण सिद्ध हुई।

(ii) सम्राट का अत्यधिक खर्चा—फ्रांस के शासक व सामन्त विलासिता पूर्ण जीवन बिता रहे थे। लुई चौदहवें के समय से ही फ्रांसीसी सम्राटों ने अपने वंश प्रदर्शन और भाग विलास पर धन का बहुत अधिक अपव्यय किया। लुई पंद्रहवें ने भी अपने महलों और रखला पर राज्य का बहुत अधिक धन अपव्यय किया। एक तरफ राज्य की आर्थिक दशा शौचनीय थी दूसरी तरफ फ्रांसीसी सम्राट ऐश्वर्य पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिये फ्रांसीसी जनता में सम्राट के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था। फ्रांस के सम्राट अपने का सुखी बनाने के लिये जनता से नाना प्रकार के कर वसूल करते थे और वह धन अपने ऐश आराम पर खर्च करते थे। इस प्रकार सम्राटों के द्वारा धन का बहुत अधिक अपव्यय करने के कारण राज्य का कोष खाली हो चुका था।

(iii) करों में असमानता—फ्रांस की कर प्रणाली में असमानता थी। कुलीन वर्ग के व्यक्तियों को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। राजा, सामन्त और पादरी तीनों ही कृषकों से कर वसूल करते थे। सामन्त कृषकों से मनमाना कर वसूल करता था। केन्द्रीय सरकार कृषकों से टक्स ठेकेदारों के माध्यम से वसूल करती थी। ठेकेदार कर की निश्चित रकम राज कोष में जमा करा देते थे। इससे पश्चात् के जनता से मनमाना रूप से कर वसूल करते थे। इससे जनता में असंतोष व्याप्त था परन्तु ठेकेदार राज्य कोष में उतना पसा जमा नहीं करवाते थे जितना कि राज्य को मिलना चाहिये।

प्रोफेसर हेज ने लिखा है कि फ्रांस का कृषक राज्य सामन्त व पादरियों को कर चुकाता था। इसके पश्चात् उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचता था जिससे कि वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का निर्वाह कर पाता था। कर प्रणाली की असमानता ने कृषकों और मध्यम वर्ग के लोगों को विद्रोह करने के लिये प्रेरित किया।

(iv) करों का अत्यधिक बोझ—कृषकों पर करों का अत्यधिक बोझ था। उन्हें राजा सामन्त और पादरी तीनों को ही कर देने पड़ते थे। फ्रांस में भूमि कर निश्चित नहीं था। इसलिये प्रांतीय शासक किसानों से अपनी इच्छानुसार कर वसूल करता था। यह भूमि कर प्रांतीय टक्स कहलाता था। प्रांतीय शासक किसानों से मनमाना कर वसूल करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रतिवर्ष अपनी आय का 20 प्रतिशत कर के रूप में देना पड़ता था।

प्रत्येक फ्रांसीसी कृषक के लिये यह आवश्यक था कि वह सरकार से दस गुनी कीमत पर सात पींड नमक प्रतिवर्ष खरीये। प्रत्येक किसान सामन्तों की भूमि का

किराया देना था। इसके अतिरिक्त अपनी रक्षा के बदले किसान एक निश्चित राशि सामंत को अदा करता था। सामंत किसान से एक सप्ताह में तीन बार बेगार ले सकता था। कृषक की मृत्यु के पश्चात् सामंत उसके पुत्र से एक बार भूमि का दोगुना किराया लेता था। यदि कोई कृषक अपनी भूमि बेचता था तो उस भूमि का जो मूल्य प्राप्त होता था, उसका पाचवा भाग उसे सामंत को देना पड़ता था। कृषक प्रतिवर्ष अपनी आय का बारहवा भाग चर्च को देता था। इस प्रकार कृषक अपनी आय का 4/5 भाग कर के रूप में दे देता था। इसके पश्चात् उसके पास सिर्फ इतना धन बचता था जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।

(4) सैनिक असंतोष—सैनिकों में मध्यम असंतोष भी फ्रांस की राज्य क्रान्ति का मुख्य कारण बना। उस समय किसानों को भी सेना में भर्ती किया जाता था। जिनकी स्थिति काफी दयनीय थी। कठोर अनुशासन, कम वेतन और खराब भोजन आदि असुविधाओं के कारण सैनिकों के असंतोष में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। सेना में कुलीन वर्ग का लड़का अयोग्य होते हुए भी उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता था, जबकि साधारण वर्ग के सैनिकों के योग्य होते हुए भी उन्हें उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। सेना में उच्च पदों पर अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होने से सैनिकों के मन में उनका प्रति कोई सम्मान नहीं था। फ्रांस के सैनिक रूसों के विचारों का अध्ययन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त फ्रांस की सेना में प्रजातन्त्रवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार हो रहा था।

(5) वैदेशिक घटनाएँ—(i) इंग्लैंड का प्रभाव—फ्रांस का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी इंग्लैंड था। इंग्लैंड में कुछ वर्षों पूर्व ही जनता के प्रयासों से वधानिक सरकार की स्थापना हो चुकी थी। इंग्लैंड का सम्राट को बाध्य होकर जनता की भाग को स्वीकार करनी पड़ी। वहाँ द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। जिसके अनुसार राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई। अपने पड़ोसी देश की भांति फ्रांसीसी जनता ने भी राजा की नीति के विरुद्ध क्रान्ति करने का निश्चय किया।

(ii) आयरलैंड का प्रभाव—आयरलैंड की जनता पर वहाँ का सम्राट एक शताब्दी से अधिक समय तक अत्याचार करता रहा। परिणामस्वरूप वहाँ की जनता ने 1779-1782 निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया। जिसके कारण उन्हें काफी सुविधाएँ प्राप्त हुईं। इस घटना ने फ्रांस को भी अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिये आंदोलन करने के लिये प्रेरित किया।

(iii) सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव—सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को बुरी तरह से पराजित किया था। जिसके कारण फ्रांस का साम्राज्य घटा। उसकी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा बनी हुई थी उसे काफी धक्का पहुँचा और युद्ध में

काफी धन गच हुआ। इसलिये फ्रांस की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। इस युद्ध में फ्रांस की असफलता ने फ्रांस की दुबलता को स्पष्ट कर दिया। इतना ही नहीं इसमें विश्व के सामन भी फ्रांस की शक्ति भी स्पष्ट हो गई। युद्ध में पराजय का कारण फ्रांसीसी जनता में शासक की अयोग्यता को माना और उन्हें सिंहासन से हटाने का निश्चय किया।

(iv) अमेरिका की क्रांति का प्रभाव—अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम ने भी फ्रांस को क्रांति करने की प्रेरणा दी। उत्तरी अमेरिका पर इंग्लैंड का अधिकार था। यहाँ पर इंग्लैंड द्वारा भयंकर अत्याचार किये जा रहे थे और वहाँ की जनता का शोषण किया जा रहा था। इसलिये उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों ने ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिये विद्रोह कर दिया। अक्टूबर 1787 ई० में अमेरिका ने ब्रिटिश दासता से स्वतंत्रता प्राप्त की।

फ्रांस इंग्लैंड से सप्नवर्षीय युद्ध की पराजय का बदला लेना चाहता था, इसलिये फ्रांस के शासक ने हारो सैनिकों और स्वयं सेवकों को अमेरिका की स्वतंत्रता में सहायता देने के लिये भेजे थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर लौटे हुए सैनिकों ने फ्रांस की जनता को क्रांति करने की प्रेरणा दी। क्योंकि उन पर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का काफी प्रभाव पड़ा था। लौटते हुए फ्रेंच सैनिकों ने कहा कि जब वे लोग अमेरिका को दासता से स्वतंत्र करवा सकते हैं तो अपने देश में भी गणतंत्र का विरोध निश्चय रूप से कर सकते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पर फ्रांस की सरकार का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जिसके कारण फ्रांस का राजकोष खाली हो गया। मन्त्रिमंडल ने आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। अब फ्रांसीसी जनता के सामने क्रांति का सिवाय अथवा कोई विकल्प नहीं था।

(6) बौद्धिक क्रांति—फ्रांस की जनता में अपरोक्त कारणों से भयंकर असंतोष याप्त था। उस समय के फ्रांस के विचारकों और लेखकों ने उस व्याप्त असंतोष को अपने लेखों में प्रकाशित कर जनता को क्रांति करने के लिये प्रोत्साहित किया। केटलवी ने लिखा है कि “फ्रांस के लेखकों ने वहाँ की जनता को क्रांति करने के लिये प्रोत्साहित किया। इस काल में ऐसे साहित्य का सृजन हुआ, जो गोल्ला वारुद के समान राज्य को नष्ट कर सकता था। इसमें पूरे क्रांति इतनी शक्ति और सूत्रों से कभी सृजित नहीं हुई थी।

फ्रांस के तत्कालीन विचारकों में मास्तेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो और दिदरो का नाम उल्लेखनीय है।

(1) मास्तेस्क्यू (1689-1755 ई०)—मास्तेस्क्यू 1689 ई० में एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। वह कानून द्वारा सबसत्ता में विश्वास करता था। वह राजा के अतिक्रमण का विरोधी था। उसने कहा था कि राजा ईश्वर

कृति नहीं होकर आवश्यकता की उपज है। यह फ्रांस की शासन व्यवस्था विरोधी था। उसे इंग्लैण्ड की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी लगी।

माटेस्वू ने "विधि की आत्मा" (The Spirit of law) नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने वैधानिक शासन की स्थापना पर अधिक जोर दिया। उसका यह मानना था कि कायपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर बलम-अलग व्यक्तियों का नियंत्रण होना चाहिये। यदि इन तीनों पर एक ही व्यक्ति का अधिकार रहेगा, तो उससे शासन व्यवस्था नष्ट हो जायेगी। इस ग्रन्थ में उसने राजा के दैविक अधिकारों की कटु आलोचना की और जनता को राजा के निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिये क्रांति करने के लिये प्रोत्साहित किया।

(ii) वाल्टेयर (1694-1778)—वाल्टेयर उस समय का महान लेखक, कवि एवं प्रसिद्ध विचारक था। उसका जन्म मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। उसकी शैली व्यंग्यात्मक थी। वह प्रजातन्त्र का समर्थक नहीं था। उसने निरंकुश शासन और चर्च में व्याप्त सुराश्या का विरोध किया। परिणामस्वरूप उसे फ्रांस छोड़कर इंग्लैण्ड जाना पड़ा। इसके चले जाने के पश्चात् भी उसका विचारों का प्रसार फ्रांस में होता रहा। उसका मानना था कि पुराने जमाने को मिटाने के पश्चात् ही नवीन युग की आधार शिला रखी जा सकेगी।

(iii) रूसो (1712-1778 ई०)—क्रांति की भावना का प्रादुर्भाव करने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। यह शासक वर्ग की आलोचना करते हुए जनसाधारण के समक्ष नवीन युग का चित्र भी प्रस्तुत करता था। उसका जन्म 1712 ई० में एक घड़ी साज के घर में हुआ। वाल्टेयर बुद्धि प्रधान लेख लिखता था, जबकि रूसो भावना प्रधान। वह एक नवीन समाज का गठन करना चाहता था।

रूसो ने 1762 में "सामाजिक सन्धि (Social Contract) नामक ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ ने राजतन्त्र को धराशायी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह ग्रन्थ उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ। रूसो ने ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा है कि "मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होते हैं पर वे सबल जजीरों से जकड़े हुए पाये जाते हैं। कुछ लोग अपने को दूसरों का मालिक समझते हैं, पर वस्तुतः वे दूसरों की अपेक्षा अधिक गुलाम होते हैं।"

रूसो ने अपनी पुस्तक में निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का विरोध किया। उसका यह मानना था कि जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, इसलिये शासन की सम्पूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथ में न होकर सम्पूर्ण जनता के हाथ में होनी चाहिये। उसके अनुसार सावभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित होती है। रूसो ने इन विचारों को "सामान्य इच्छा" (General will) की संज्ञा दी।

रूस के अनुसार मूल सविदा वह थी जिसके द्वारा राज्य का प्रादुर्भाव हुआ था। समाज के सभी व्यक्तियों को मिलाकर एक समझौता किया था। उस समझौते के अनुसार एक व्यक्ति को राजा बनाया गया था। जिसने जनहित में शासन संचालन करने की प्रतिज्ञा की थी। अब राजा ने इस मौलिक समझौते का उल्लंघन कर निरंकुश रूप से शासन करना प्रारम्भ कर दिया, जिसे अब जनता स्वीकार नहीं कर सकती थी।

रूसों के इन विचारों ने जनता को प्रेरित करने के लिये प्रोत्साहित किया। उसके विचारों के कारण फ्रांस की राज्य क्रांति में नव धेतना जाग्रत हुई। समानता, स्वतन्त्रता और विश्व-बंधुत्व की भावना ही फ्रांस की राज्य क्रांति के मूल आधार थे। इसलिये नेपोलियन ने कहा था कि 'यदि रूसों का अविर्भाव नहीं होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति कभी नहीं होती।'

(iv) दिदरो (1713-1784)—फ्रांस की राज्य क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करने में दिदरो ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिदरो ने एक विशाल विश्व कोष (इनसाइक्लोपीडिया) नामक ग्रंथ लिखा, जो 1750-1760 के बीच प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में उसने विश्व प्रसिद्ध विद्वानों एवं वैज्ञानिकों की जीवनीयों का वर्णन किया। फ्रांसीसी जनता ने इस विश्व-कोष में सकलित महानपुरुषों की जीवनीयों पढ़ी तो जनता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। अब फ्रांसीसी जनता ने विश्व कोष में सकलित महापुरुषों के उच्च आदर्शों पर चलने का प्रयास किया। उन राजनीतिक विचारकों के विचारों से फ्रांसीसी जनता में क्रांति की भावना प्रस्फुटित हो रही थी। यही कारण था कि फ्रांसीसी सरकार ने दिदरो को जेल में डाल दिया, परन्तु उसका विश्व कोष जनसाधारण को क्रांति की ओर अपसर करता रहा।

(v) अर्थशास्त्रियों का योगदान—उस समय क्वेसने और तुर्जो आदि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने सरकार की आर्थिक नीति की कटु आलोचना की और जनता को क्रांति करने के लिये उत्तेजित किया। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने व्यापार पर सरकारी नियंत्रण हटाने की अपील की और मुक्त व्यापार नीति को राज्य के हित में बताया।

(7) तत्कालीन कारण—यद्यपि 1789 ई० में फ्रांस में क्रांति के लिये वातावरण तयार हो चुका था, फिर भी यह सत्य है कि कोई भी बग क्रांति करने के लिये तयार नहीं था। फ्रांस की राज्य क्रांति किसी निश्चित योजना का परिणाम नहीं थी, अपितु कुछ तात्कालिक कारणों से यह क्रांति प्रस्फुटित हो गई थी। ये तात्कालिक कारण निम्नलिखित थे—

(1) लुई सोलहवें की अदूरदर्शिता—फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई सोलहवें के मूर्खतापूर्ण कार्यों ने क्रांति को अनिवार्य बना दिया। यदि लुई दूरदर्शी और

फ्रांस की राज्य क्रांति

बुद्धिमान होता तो क्रांति को कुछ समय के लिये टाला जा सकता था। डी-टोन्गुविले ने लिखा है कि "इस रक्त रजित क्रांति का गमस्त उत्तरदायित्व लुई चौदहवें पर था। युद्ध में वह दृष्टता और समझदारी से काम लेता तो क्रांति नहीं होती।"

वास्तव में लुई की अयोग्यता, अनुभवहीनता तथा विलासिता न 1789 में ही क्रांति को अवश्यम्भावी बना दिया। क्रांति के लिये वातावरण पहले से तयार हो चुका था। लुई में शासन करने की योग्यता का अभाव था। शासन कार्यों में वह रुचि नहीं लेता था। वह भीरु स्वभाव और अस्थिर प्रकृति का व्यक्ति था। लुई 'खाओ पीओ और मौज उड़ाओ' के सिद्धांत के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था।

(ii) एतवायनेत का प्रशासन में हस्तक्षेप—लुई के जीवन पर उसकी रानी एतवायनेत का बहुत अधिक प्रभाव था। लुई एतवायनेत के ईशारा पर ताचता था। रानी राज्य के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप करती थी। एतवायनेत का राज्य प्रबंध पर पूर्ण नियंत्रण था। साम्राज्य के कमचारियों की नियुक्ति तथा उनकी तबदीली उसकी अनुमति से की जाती थी। उन्हें उन्नत पद दान, पदच्युत करन तथा पुन उदासीन करने में भी रानी का हाथ रहता था। रानी का फिज़ूल खर्चा बहुत अधिक था। वह बहुमूल्य वस्तुएँ खरीदने में और अपन मित्रों को उपहार देने में सरकार का पसा पानी की तरह खर्च करती थी।

फ्रांस की जनता की निगाह में सारी बुराइयों की जड़ रानी एतवायनेत थी। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, सुधार याजनाओं की असफलता और बरा का भारी बोझ आदि के लिये जनता ने उस दायी माना। यदि इसी समय एतवायनेत को बजाय कोई दूसरी रानी होती तो क्रांति भी कुछ समय के लिये टल जाती। जनता में पहले से भयकर असंतोष व्याप्त था। एतवायनेत ने इस असंतोष का पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया। जिसके फलस्वरूप क्रांति प्रारम्भ हो गई।

(iii) शौचनीय आर्थिक दशा—फ्रांस की क्रांति का एक अन्य तात्कालिक कारण देश की शौचनीय आर्थिक दशा थी। लुई सानह्वे के समय राज्य की आर्थिक दशा बहुत शौचनीय थी। 1788 ई० में राज्य पर इतना बर्जा हो गया था कि उसकी आमदनी से भी अधिक पसा ब्याज का देना पड़ता था। लुई चौदहवें ने अपने समय में कई युद्ध लड़े, जिसमें अपार धन खर्च हुआ। उसने समय फ्रांस पर वार्षिक आमदनी का 16 गुना बर्जा हो गया था। लुई पन्द्रहवें ने सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा को और शौचनीय बना दिया। इसके अतिरिक्त कई उपनिवेश फ्रांस की अधीनता में स्वतंत्र हो गए। इस लिये अब फ्रांस के लिये एक कठिन समस्या पदा हो गई कि वह क्षति पूर्ति कहाँ से करे। परिणामस्वरूप फ्रांस पर बर्जा निरन्तर बढ़ता रहा। लुई सोलहवें ने अमेरिका के स्वतंत्रता संधाम में भाग लिया। उस संधाम में फ्रांस का अपार धन व्यय हुआ।

इस प्रकार लुई सोलहवें ने आर्थिक सकट में और बढ़ि की, और फ्रांस का राजकोष रिक्त हो गया। बहा की सरकार दिवालिया हो गई और सरकार को ऋण मिलना बंद हो गया।

(iv) सुधारों की ओर ध्यान न देना - लुई सोलहवें ने देश की आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिये पहले अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की लेकिन बाद में उन योजनाओं को छोड़ दिया। जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। वेदतबी ने लिखा है कि लुई सोलहवें ने पहले सुधार करने की चेष्टा की किन्तु जब उसे इस काय में असफलता मिली तो त्राति अवश्यम्भावी हो गई।

लुई सोलहवें पर चापलूस दरबारियों और उसकी रानी का अत्यधिक प्रभाव था। वह इही से परामश लेकर शासन का संचालन कर रहा था। इनका परामश जनहित के अनुकूल नहीं था। इसलिये लुई एक के बाद एक गलतियाँ करता रहा। लुई ने शासक बनते ही तुर्जों नामक प्रसिद्ध जय शास्त्री को वित्तमन्त्री बनाया था। जिसने 20 महीने के अल्प समय में फ्रांस की आर्थिक दशा में अनेक सुधार कर जनसाधारण का विश्वास प्राप्त कर लिया। लेकिन दरबारियों और अपनी रानी के प्रभाव में आकर लुई ने तुर्जों को मन्त्री पद से हटा दिया।

इसके पश्चात् लुई ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नेकर का अर्थ मन्त्री के पद पर नियुक्त किया। उसने भी तुर्जों की भाँति अनेक सुधार किये। 1781 ई० में उसने राज्य के आय-व्यय का विवरण समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दिया। जब जनता ने इस विवरण को पढ़ा तो उसे राजमहल के फिजूलखर्चों का पता चल गया। इस पर लुई सोलहवें ने अपने दरबारियों के प्रभाव में आकर नेकर को भी अर्थ मन्त्री के पद से पदच्युत कर दिया। नेकर के हटते ही सुधारों का काल समाप्त हो गया और जनता के लिये त्राति का भाग प्रशस्त हो गया।

नेकर के पश्चात् लुई सोलहवें ने केलोन को अर्थ मन्त्री के पद पर नियुक्त किया। उसने यह प्रस्ताव रखा कि बजट के घाटे की पूर्ति करने के लिये सम्पूर्ण फ्रांसीसी जनता पर सामान्य कर लगाया जाये। इस पर कुलीन वर्ग के व्यक्तियों ने इस कर का विरोध किया क्योंकि यह वर्ग सभी प्रकार के करों से मुक्त था। केलोन ने राजा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि विशिष्ट व्यक्तियों की बँठक बुलाई जाय, ताकि सभी व्यक्तियों से समान कर वसूल कर देश की आर्थिक दशा में सुधार किया जा सके। राज्य-व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये यह आवश्यक था कि इस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाय। इस पर केलोन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

इस्टेट्स जनरल एक ससदीय सस्था थी। 1302 ई० में इस सस्था की स्थापना हुई थी। इस सस्था का मुख्य काय राजा को सलाह देना था। यह राजा की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो इसकी बँठक बुलाये या न बुलाये। 1610

ई० तक नियमित अनियमित रूप से राजा इस सस्या की बठक बुलाता रहा, लेकिन उसके बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई भीटिंग नही बुलाई गई। अत यह सस्या मृतप्राय हो चुकी थी। 1788 ई० म इस सस्या के अधिवेशन बुलाने की माग इतनी प्रबल रूप से उठी कि अय राजा के लिये टालना असम्भव था।

लुई सोलहवें ने क्लोन क पश्चात सिपन को अय मन्त्री के पद पर नियुक्त किया। इसने वजट के घाटे की पूति करन क लिये कुछ नये कर लगाने का मुझाव लिया। किंतु पेरिस की पार्लेमा ने इन नये करों का विरोध किया एव इन करों को अपने रजिस्टर म दज करने से मना कर दिया। पार्लेमा न यह तक दिया कि बिना इस्टेट्स जनरल की अनुमति के राजा को नये कर लगाने का अधिकार नही है। इस पर राजा न पार्लेमा को भग कर दिया किंतु जनता द्वारा पार्लेमा का समथन किया गया। फलस्वरूप राजा को पार्लेमा का दुबारा आमन्त्रित करना पडा। पार्लेमा ने फिर अपनी पुरानी माग को दोहरा दिया। प्रांतों की पार्लेमाओं न भी पेरिस की पार्लेमा का समथन किया। अत मे राजा को बाध्य होकर 1788 ई० मे इम्प्टम जनरल का अधिवेशन बुलाने की माग स्वीकार करनी पडी।

जनवरी 1789 ई० म उक्तें जनापूण वातावरण में इस्टेट्स जनरल के चुनाव बरघाय गये। 5 मई 1789 ई० में बर्सय के महल मे इस सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। यही से फ्रांस की राज्य शक्ति प्रारम्भ होती है। इस अधिवेशन से फ्रांस के इतिहास में एक ऐसा अध्याय प्रारम्भ हुआ, जिसकी कोई कल्पना नही कर सकता था। इस समय नेकर को पुन मन्त्रि परिषद के प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया और आगामी बठक की तैयारी की जाने लगी।

क्रान्ति की मुख्य घटनायें— लुई सोलहवें ने राज्य की आयिक दशा मे सुधार करने के लिये टरगो व नेकर को अय मन्त्री के पद पर नियुक्त किया था। 5 मई 1789 ई० को आर्थिक परिस्थितियों से विवश होकर लुई को स्टेट्स जनरल की बठक बुलानी पडी। इस सस्या की पिछले 175 वर्षों म कोई बठक नही बुलाई गई थी। लुई सालहवें का यह मानना था कि स्टेट्स जनरल राज्य द्वारा लगाये गये नये करों पर अपनी अनुमति दे देगे और शातिपूर्वक इसका अधिवेशन समाप्त हो जायेगा।

(1) स्टेट्स जनरल का अधिवेशन— इस सभा के अधिवेशन न फ्रांस की राय को एक नई प्ररणा दी। 5 मई 1789 ई० को स्टेट्स जनरल का प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। इस सभा मे तीन सदन थे। पहला कुलीन वर्ग दूसरा पुनोहित वर्ग और तीसरा साधारण सदन था। इस सभा क अधिवेशन में लुई सोलहवें ने यह आदेश दिया कि तीनों सदन पृथक-पृथक रूप से काय करें। इस पर साधारण सदन के सदस्यों ने यह माग की कि तीनों सदनों के सदस्य एक साथ बठकर

बहुमत से निणय करें, परन्तु प्रथम (सामान्य) और द्वितीय (पुरोहित या पादरी बग) सदन के सदस्यों ने इस मांग का विरोध किया।

17 जून 1789 ई० को साधारण सदन के सदस्यों ने अपन आपकी राष्ट्र का प्रतिनिधि घोषित करते हुए एक नया सदन 'राष्ट्रीय महासभा' का निर्माण किया। 19 जून को दूसरे सदन के सदस्यों (पादरी बग) ने बहुमत से राष्ट्रीय महासभा में मिलने का निश्चय किया। 20 जून को लुई सोलहवें ने राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों को स्टेटस जनरल में निकाल दिया। इस पर राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों ने टेनिस कोर्ट के मैदान में यह प्रतिज्ञा की कि राष्ट्र में बर्धानिक सरकार की स्थापना होने तक हम डटे रहेंगे। सम्राट ने स्टेटस जनरल को अधिवेशन स्थगित करने का आदेश दिया। इस पर राष्ट्रीय महासभा के नेता काउण्ट मिराबो ने कहा कि "हम यहाँ जनता की इच्छा से हैं। जब तक हम बंदूक के बुन्दों से नहीं हटाया जायेगा, हम नहीं हटेंगे।" विवश होकर लुई सोलहवें का महासभा का निणय स्वीकार करना पड़ा और पीनो सदनो का समुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा। जनता की राजा के विरुद्ध यह प्रथम विजय थी।

(11) बेस्टाइल के कारागृह का पतन जुलाई 1789—महासभा की कार्यवाही से पब्लिकर राजा ने अपनी सुरक्षा के लिये विदेशी सैनिकों को नियुक्त किया। इस समय जनता में यह अफवाह फैली कि राजा क्रांति का दमन करने के लिये विदेशी सैनिकों की सहायता ले रहा है। इस अफवाह के फलने ही भूखी नगी और निहत्थी बेस्टाइल की जनता ने वहाँ के प्राचीन किले को नष्ट करने का निश्चय किया। अब जनता किले की आर बढ़ी। सैनिक दृष्टिकोण से इस किले का कोई महत्व नहीं था, परन्तु जेल के रूप में इस किले की काफी बदनामी हो चुकी थी। इसे जनता अत्याचार का प्रतीक समझती थी। यह जेल उस समय बुरों वश के निरंकुश शासन का प्रतीक बनी हुई थी, इसलिये क्रांतिकारी लोग इस किले पर हमला करने के लिये निहत्थे खाना लिये। किले के रक्षकों ने तोपों से बारूद के गोले बरसाये, परन्तु जनता ने क्रुद्ध होकर बेस्टाइल की ईंट से ईंट उखाड़ दी और राजनतिक कदियों को रिहा कर दिया। बेस्टाइल के कारागृह का पतन राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखता था। यह जनता की दूसरी विजय थी।

इतिहासकार फिशर ने इस स्वतंत्रता के नूतन प्रात काल की सभा दी है। इस कारागृह के पतन के पश्चात् पेरिस और सम्पूर्ण फ्रांस में क्रांति प्रारम्भ हो गई। बेस्टाइल के पतन के साथ ही फ्रांस में निरंकुश शासन का प्रतीक सुहृद दुग नष्ट हो गया। फ्रांस में इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन (14 जुलाई) सावजनिक अवकाश रखा जाता है। इस प्रकार इस घटना का फ्रांस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब संविधान सभा अधिक शक्तिशाली हो गई और क्रांति का नेतृत्व पेरिस के हाथ में आ गया।

क्रान्ति की प्रगति—प्राप्ति का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता ही रहा। इस क्रान्ति में कृपक बग न भी भाग लिया। किमानो ने बदले की भावना से प्रेरित होकर सामन्तों के घर लूट लिये और उनके दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। जनता की भारी भीड़ न घुड़ होकर टक्स बसूल करने वाले व्यक्तियों को पानी में डुबो दिया। इस प्रकार के अशान्ति वातावरण में 4 अगस्त को राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन बुलाया गया। यह अधिवेशन फ्रांस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित किये गये। सामन्तों व धर्माधिकारियों के विरोध अधिकार समाप्त कर दिये गये। सामन्त लोगो ने अपनी जान बचाने के लिये विदेश में शरण ली। देश में आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय रक्षा निर्युक्त किये गये। लफायत नामक व्यक्ति को राष्ट्रीय रक्षक दल का नेता बनाया गया, जो कि अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर चुका था। पेरिस का प्रबन्ध नागरिक सभा को सौंप दिया गया।

(1) सम्राट को पेरिस आने के लिये बाध्य करना—वेस्टाइल जैन का पतन होने के पश्चात् भी जब लुई सोलहवा पेरिस में नहीं आया तो जनता को यह सदेह होने लगा कि कहीं वह बर्साय में नया पदपत्र तो नहीं रख रहा है, इसलिये 5 अक्टूबर 1789 ई० को दस हजार स्त्रियों का एक दल राजा के महल की ओर रवाना हुआ। जिसका उद्देश्य राजा को सपरिवार पेरिस की जनता के सामने लाना था। स्त्रियों के इस दल में बर्साय के शीशमहल को घेर लिया, जिसमें राजा अपने परिवार सहित रहता था। 6 अक्टूबर को स्त्रियों का यह दल राजा, रानी और राजकुमार को पकड़ कर पेरिस ले आया। जब लुई सोलहवें को यह दल पेरिस ला रहा था, तो उस समय जनता प्रसन्नता से चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि “हमारे पाम खाना पकाने वाला, पकाने वाले की स्त्री है और छोटा बकरची लडका भी, उन हमको रोटी मिलेगी।”

(ii) जनता के मौलिक अधिकारों की घोषणा—अगस्त महीने में राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर निष्पत्ति लिये गये। कुलीन बग और पादरी बग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये। धार्मिक कर तथा छेती की उपज का कर समाप्त कर दिया गया। शिवार सम्बन्धी कानून हटा दिया गया। इसके पश्चात् महासभा ने मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की। जनता को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये। जनता की प्रमुखता को मान्यता दी गई।

इस घोषणा पत्र के अनुसार सभी मनुष्यों को स्वतन्त्रता प्रदान की गई। इस तरह की व्यवस्था की गई थी यदि एक मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग करे तो उसके दूसरे मनुष्य की स्वतन्त्रता में किसी तरह की बाधा उपस्थित न हो। प्रत्येक व्यक्ति की भाषण और लेखन की स्वतन्त्रता प्रदान की गई। यह कानून द्वारा

निश्चित सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। अब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से वन्द नहीं किया जा सकता था।

इस घोषणा पत्र में 17 धाराएँ थीं। इन धाराओं पर अमेरिकन संविधान का बहुत अधिक प्रभाव था। इस घोषणा पत्र में जनता की प्रभुसत्ता को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। इस प्रकार इस घोषणा पत्र ने शक्ति का वास्तविक उद्देश्य प्रस्तुत कर दिया। ग्रांट एव टेम्परले ने लिखा है कि 'यह घोषणा शक्ति के उज्ज्वल रूप का परिचालक है, इसके बिना यह यूरोपीय इतिहास की इतनी बड़ी घटना नहीं होती।'

इस घोषणा पत्र में उन सिद्धांतों का वर्णन था, जिसके आधार राष्ट्रीय महासभा फ्रांसीसी शासन व्यवस्था में सुधार कर सकती थी। इस पत्र में केवल मानव के अधिकारों की घोषणा की गई थी, वस्तुओं की नहीं। इसमें नई भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके अतिरिक्त एक अच्छी शासन प्रणाली के राजनीतिक, सवधानिक तथा सामाजिक अधिकारों का वर्णन किया गया था।

इस घोषणा पत्र में मानव के ऐसे अधिकारों की घोषणा की गई थी जिसे दुनिया के किसी भी कोन में लागू किया जा सकता था। वही भी निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था या सामंतों के विरोधाधिकारों से मुक्त होने के लिये इस घोषणा पत्र का प्रयोग किया जा सकता था। इसमें नागरिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया था। फ्रांस के इस घोषणा पत्र ने अन्य यूरोपीय देशों को एक भयंकर चुनौती दी। 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों तक इस घोषणा पत्र को 'उदारता का चादर' समझा जाता रहा।

(iii) राजा द्वारा भागने का प्रयास—6 अक्टूबर 1789 ई० का मग्राट लुई को बन्दी बनाकर लुईलरी के महल में रखा गया था। 1791 ई० तक नये संविधान का निर्माण हो चुका था। इस नये शासन विधान में राजा के अधिकार बहुत कम कर दिये गये, जिस लुई सालहवें ने विवश होकर स्वीकार कर लिया। अब राष्ट्रीय महासभा अपना शासन विधान फ्रांस में कठोरता से लागू करना चाहती थी।

इस समय राजा के परिवार के लोगों ने एक योजना बनाई कि फ्रांस के बाहर शक्ति विरोधी लोगों से सहायता प्राप्त की जाय, फिर एक सेना का निर्माण कर नई ससदीय सरकार को समाप्त कर दिया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 1791 ई० में लुई अपनी पत्नी और राजकुमार के साथ भेष बदल कर रात्रि में लुईलरी महल से भाग निकला। वह फ्रांस की सीमा को छोड़कर भागना चाहता था कि वरेनीज नामक स्थान पर उसे किसी ने पहचान लिया। उसे गिरफ्तार कर पेरिस लाया गया। अब उसकी स्थिति नजरबन्द कदी जैसी हो गई थी। जनता का राजा के प्रति विश्वास समाप्त हो चुका था। इस घटना ने शक्ति को एक नया मोड़

दिया। अब फ्रांस में प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करके प्रयास प्रारम्भ हुए।

(iv) व्यवस्थापिका सभा का पतन—नये संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन हुआ। 1 अक्टूबर 1791 को नई व्यवस्थापिका सभा की बैठक बुलाई गई। इस समय व्यवस्थापिका सभा को विदेश के साथ युद्ध में उलझ जाना पड़ा। यूरोप के शासक फ्रांस की शक्ति का कुचलन के लिए लुई को सहायता देने के लिए प्रयास कर रहे थे। आस्ट्रिया और प्रशा ने फ्रांस से भागे हुए कुलीनों की पूरी सहायता की। इस समय कुछ घटनाओं से प्रचार घटी कि इनसे फ्रांस और आस्ट्रिया में युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्ध में प्रशा ने आस्ट्रिया को सहायता दी। फलस्वरूप जगह जगह पर फ्रांसीसी शक्तिकारी सेनाओं की पराजय हाथ लगी।

इस युद्ध के दौरान प्रशा के सभापति 1 फ्रांसीसी शक्तिकारी नेता के नेता की चेतावनी दी कि यदि लुई सोलहवें को कुछ हो गया तो पेरिस का नामोनिशान मिटा दिया जायगा। इसमें फ्रांसीसी जनता को यह पता चल गया कि हमारा राजा दुश्मनों में मिला हुआ है और शक्ति को कुचलकर फिर से निरंकुश राजतन्त्र कायम करना चाहता है। अब शक्तिकारी नेताओं ने फ्रांस की रक्षा के लिये लुई सोलहवें को हटाने का निश्चय कर लिया। अब फ्रांस में व्यवस्थापिका सभा के स्थान पर व्यवस्थापिका के आधार राष्ट्र पर शासन का क्वेशन का निर्वाचन हुआ। इस निर्वाचन के कारण शक्ति न एक नये युग में प्रवेश किया।

(v) नेशनल क्वेशन का अधिवेशन—नेशनल क्वेशन में 782 सदस्य थे। इसमें उपवासियों और गणतन्त्र के समर्थक सदस्यों का बहुमत था। 21 सितम्बर 1792 ई० में नेशनल क्वेशन का पहला अधिवेशन बुलाया गया।

नेशनल क्वेशन के मामलों लुई सोलहवें ने भविष्य पर नियम लेना, देश की गृह युद्ध एवं विदेशी आक्रमण से रक्षा करना आदि कई समस्याएँ थीं। क्वेशन ने अपने प्रथम अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण नियम लिए। फ्रांस में निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त करके गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई। लुई पर देशद्रोह का अभियोग लगाकर नेशनल क्वेशन ने बहुमत से यह नियम लिया कि लुई को मृत्यु दण्ड दिया जाय। 21 जनवरी 1793 ई० में लुई का गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया और उगवा सिर घड़ से झलक कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस राजतन्त्र का अन्तिम अवरोध भी समाप्त हो गया और गणतन्त्र की स्थापना हुई।

(vi) फ्रांस में तानाशाही राज्य—नवम्बर 1792 ई० में फ्रांस के शक्ति कारियों ने गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की घोषणा की और यह प्रचार किया कि यह गणतन्त्र स्वतन्त्रता, समता एवं विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। फ्रांस के शक्तिकारियों ने कहा कि गणतन्त्र के इन सिद्धांतों का प्रचार करना के

अपना वक्तव्य समझते हैं। आस्ट्रिया और प्रशा व सम्राट्टा न लुई का पुन फ्रांस का सम्राट बनाने के लिये 1792 ई० म फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। इससे फ्रांस की जनता म प्रतिराघ की ज्वाला भडक उठी और शान्तिकारियों ने राजा के समयका को मौन के घाट उतार दिया।

अब शान्तिकारी परिपल इस निणय पर पहुँची कि राजा और रानी के जीवित रहते हुए फ्रांस म सवधानिक शासन सफल नहीं हो सकता। 1792 ई० म राष्ट्रीय विधान सभा ने फ्रांस में गणतन्त्र की स्थापना की घोषणा की। इसके पश्चात एक तरफ तो सम्राट लुई सोलहवें पर दश द्रोह का अभियोग लगाकर 21 जनवरी 1793 ई० म उसको फाँसी पर लटका दिया गया। उसके कुछ महिों पश्चात उसकी रानी एतवायनत को भी फाँसी पर चढ़ा दिया गया और दूसरी तरफ फ्रांस न आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर लिया। इस युद्ध म फ्रांस के शान्तिकारियों न आस्ट्रिया और प्रशा की समुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। इस समय फ्रांस म आतंक राज्य आरम्भ हुआ। इस आतंक राज्य के प्रधान दाते और रोस पियर थे।

दाते—फ्रांस म राजतन्त्र की समाप्ति के पश्चात भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने राजतन्त्र को पुन कायम रखने के लिये हर सम्भव प्रयास किये। इसी समय फ्रांस म एक नया रिपब्लिक दल का उत्कप हुआ इस दल का नेता दाते था। दाते का जन्म फ्रांस के मध्यम वर्ग के परिवार म हुआ था। वह श्रमिक वर्ग के हिता का समर्थक था। दाते भाषण देने की कला म प्रवीण था। इसलिये जेकोबिन दल को नतृत्व प्रदान कर सवा। इसक जोड़स्वी भाषणों से जनता बहुत प्रभावित थी। इसने अपने भाषणों के माध्यम से प्रजातन्त्र व पक्ष म भारी समयन प्राप्त कर लिया।

22 जून 1792 को पेरिस की जनता ने दाते के नेतृत्व में सम्राट के महल को घेरा था। उस दिन जनता ने राजा के विरुद्ध सिर्फ नारे लगाये और कोई हिंसात्मक घटना नहीं घटी। जनता न राजा को नीचे आन के लिये बाध्य किया। परिणामस्वरूप राजा को शान्ति की प्रतीक लाल टोपी पहन कर जनता के सामने आना पडा। उसन ऐसा करके बाध्य होकर शान्ति को भा यता प्रदान की पर उसके हृदय म शान्ति को कुचलने की प्रबल इच्छा थी।

25 जुलाई 1792 ई० को ड्यूक जाफ बुसविक ने शान्तिकारी जनता को भयभीत करने के लिये राजा के समयन मे यह घोषणा की कि जो शक्ति राजा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेगा, उससे ऐसा बदला लिया जायेगा कि वह जिन्दगी भर नहीं भूल सकेगा। ड्यूक की इस घोषणा से जनता ने उत्तेजित होकर 10 अगस्त 1792 ई० म राजा के महल पर पुन हमला कर दिया। इस वार भी वेदित जनता का नतृत्व दाते कर रहा था। जनता हिंसात्मक काय पर उतर आई

और उसने राजा के स्विस अग रक्षकों की मौत के घाट उतार दिया। परिणामस्वरूप राजा सभा भवन में जाकर छिप गया। इस वार जनता ने महल का लूटा। इस लूट में दान की राजा के कमरे में एक लोहे का सड़क मिठा। इस सड़क में प्राप्त पत्रों के आधार पर ही दात ने नेशनल कन्वेंशन में राजा पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध कर दिया और उसे फाँसी पर लटकवा दिया था। महल की लूट के पश्चात् चारों तरफ अराजकता फैल गई थी। जनता ने राजा के समयको का भारी सभ्या में कल किया। यह घटना सितम्बर के महीने में घटित हुई। दाते अराजकता का लाभ उठा कर तानाशाह बन गया था। उसने कहा था कि साहस के द्वारा ही सम्राट के समय का को भयभीत करके युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। दान की इस नीति पर चलते हुये जनता ने भारी सभ्या में राजा के समयक लोगो को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 22 सितम्बर का फ्रांस में गणतन्त्र की स्थापना की घोषणा की गई।

दान के उपरोक्त कार्यों की समीक्षा करते हुए कई इतिहासकारों ने उसे 'रक्त पिपासु' की सजा दी है। यदि हम गम्भीरता से उसके कार्यों का परीक्षण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह रक्त-पिपासु नहीं था, अपितु वह तो फ्रांस का एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था, जिसने कठिना परिस्थितियों में फ्रांस की सुरक्षा की। अतः उस भी आतंक राज्य का शिकार बनना पड़ा।

रोससपियर—स सपियर का जन्म 6 मई 1752 ई० का जारानगर में हुआ था। क्रांति से पूर्व वह कालात् का काम करता था। यह रुमो के विचारों से प्रभावित होकर उग्र विचारों का समयक बन गया था। 1789 ई० में यह तीसरे सदन का सदस्य चुना गया। इसके बाद यह जन सभ्य समिति का सदस्य बना और अपने उग्र विचारों का प्रसार करता रहा। दाते को मृत्यु दण्ड देकर वह तानाशाह बन गया था। यद्यपि यह जेकोबिन दल का सदस्य था परन्तु उग्र विचारों का होने के कारण राजतन्त्र का भी समयक था। इसका मानना था कि यदि क्रांति के समय में शासन लोकहित पर आधारित होना है तो क्रांति के समय में जनहित और आतंक दोनों पर ही आधारित होना चाहिये। उसका यह भी धारणा थी कि यदि शामक तक के आधार पर अपनी जनता पर शासन करता है तो शत्रु को भय के माध्यम में शासित करना चाहिये।

यद्यपि धर्म के क्षेत्र में वह नास्तिक नहीं था परन्तु चर्च का अनुयायी भी नहीं था। उसका राजनीतिक जीवन बड़ा भ्रष्ट था। गणराज्य और आतंक राज्य की सफलता के लिये वह सदाचार को आवश्यक समझता था। 1793 ई० में जब नेशनल कन्वेंशन का तीन गुटों से विभाजन हो गया तो इसका लाभ उठाकर उसने कम्प्यून के गुट को समाप्त कर दिया। इस कार्य में उस दाते ने सहयोग किया था।

जब इस काय मे उसे सफ़ाता मिल गई तो उमन दाने और उमके समथका पर देश द्रोह का अपराध लगाकर मौत के घाट उतार दिया ।

रोसपियर अप्रैल 1794 म जुलाई 1794 ई० तक फ्रांस पर तानाशाह की तरह शासन करता रहा । इस अल्पकाल म उसने हजारो व्यक्तियों को मौत के घाट उतरवा दिया । 8 जून का उसन परम पुरुष भगवान की प्रतिष्ठा की । इस अवसर पर उसने कहा कि यदि ईश्वर इस मगर म विद्यमान नही है ता उसका आविष्कार करना पडेगा । उसने 10 जून को एक ऐसा कानून बनाया जिसस क्वेशन के बिसी भी सदस्य का क्वेरी बनाया जा सनना था । जब रोसपियर ने क्वेशन के सदस्या को बन्दी बनाता छुहू किया तो इससे क्वेशन के सदस्या म हतचल मई गई । इस पर क्वेशन क सदस्यो न रोसपियर का राज्य की रक्षा के भार से बचित कर दिया और उस पर हमला कर लिया । इस आक्रमण म रोसपियर क जबड़े म गोली लग गई और 28 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई । इस प्रकार रोसपियर का भी वसा ही अंत हुआ जसा कि उसन दाते का किया था । रोसपियर को खुद की प्रणसा बहुत अच्छी लगती थी ।

भारा—फ्रांस की राज्य क्रांति के समय मारा राजतंत्र का समर्थक था । इसीलिय उसकी सम्राट लुई मालहवें के प्रति पूण निष्ठा थी । जब सम्राट को फ्रासी पर चढा दिया गया तो वह गणतंत्र का समर्थक बन गया । वह अगले समय का प्रसिद्ध पत्रकार था । उसन लोकप्रिय (The Friend of the People) नामक समाचार पत्र निकाला । जिसने शीघ्र ही जनसाधारण म लोकप्रियता प्राप्त कर ली । वह रोसपियर के उग्र विचारों का समर्थक थी । उसने लोकप्रिय पत्र क माध्यम से उग्र विचारों का प्रसार किया । माटेस्क्यू की भांति वह भी फ्रांस म इंग्लण्ड जसी शासन व्यवस्था स्थापित करने का पक्षपाती था । उमन इमने लिय फ्रासीमिया को परामश दिया । उसका यह मानना था कि जब तक जनसाधारण म समानता की भावना नही आयेगी तब तक कोई सुधार सम्भव नगी है। सक्ता । उसन जनता को क्रांति पूण काय करने के लिये प्रोत्साहित किया ।

वह राजनीतिज्ञ व रिपब्लिकन दल का नेता ही नही था, वरने बहुत बडा विद्वान भी था । वह अग्रेजी स्पनिश जमन तथा इटालियन भाषाओं का विद्वान था । इंग्लैंड म रह कर उमने एम० पी० की उपाधि प्राप्त की । कानानिक विषय पर उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी । वह अगले समय का प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री भी था । उसने साहित्यिक एवं कानानिक जीवन म बराबर लेटर राजनीति मे प्रवेश किया था । निर्मलीय होन हुय भी उमने जन साधारण म बहुत लोकप्रियता प्राप्त की । 1792 ई० म फ्रांस का शासक बन उस पर नाराज हो गया और 1793 ई० म एक लडकी न उसका कत्ल कर दिया ।

(vii) डाइरेक्टरी (1796-1799)—आतंक राज्य स फ्रांस की जनता परेशान हो चुकी थी । 1794 ई० म फ्रांस म एक नय सविधान का निर्माण किया

गया जिसके द्वारा शासन संचालन का भार प्रोड आण्ट डाइरेक्टर्स के हाथ में सौंप दिया गया। इसमें पांच व्यक्तियों की एक संस्था थी जिसे डाइरेक्टरी कहते थे। डाइरेक्टरी के शासन काल की अधिकांश इतिहासकारों ने कटु आलोचना की है।

एच० जी० वेल्स ने लिखा है कि डाइरेक्टरी प्रशासन स्वतन्त्र कठोर था कि उम देखकर ऐसा लगता था कि जैसे फ्रांस में कोई क्रांति ही नहीं हुई। डाइरेक्टरी ने चार वर्ष तक शासन किया। इस काल को पन्थम काल के नाम से पुकारा जाता है। डाइरेक्टरी के शासन काल में नपॉलियन बोनापार्ट का उत्तर हुआ। नवम्बर, 1799 ई० में नैपोलियन के नाटकीय ढंग से डाइरेक्टरी का पतन हो गया और फ्रांस के शासन की बागडोर उसने अपने हाथ में ले ली। प्लट जीन और डूमड ने लिखा है कि 'नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति का उपयोग सनिर तानाशाही की स्थापना के लिये किया।'¹

फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम—फ्रांस की राज्य क्रांति का यूरोप के इतिहास में नहीं बरन ससारा के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति से मध्यकालीन व्यवस्था की समाप्ति हुई और आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। इतिहासकार डब्लिस ने लिखा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति का 1917 की रूसी क्रांति के पूर्व और उसके बाद भी ससारा की अधिकांश महत्वपूर्ण इतिहासिक घटनाओं पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस क्रांति के प्रमुख परिणाम निम्न लिखित थे—

(1) **राष्ट्रीयता का विकास—**इस क्रांति से पूर्व फ्रांस वाली राजतंत्र और सामंतवाद में बुरी तरह जकड़े हुए थे। इस क्रांति के कारण फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की यह भावना केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही बरन जैसे-जैसे क्रांति का विस्तार होता गया वैसे-वैसे यूरोप के अन्य देशों में भी इस भावना का प्रसार होता गया। यही कारण था कि फ्रांस में 1830 व 1848 में क्रांति हुई और इनका सम्पूर्ण यूरोप पर प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांतियों से प्रभावित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतियों की। इटली, जर्मनी और रूस में क्रांतियाँ हुईं और वे सफल रही। यद्यपि 1789 ई० की क्रांति का फ्रांस में पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त हुई फिर भी इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रांस की इस क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों को क्रांति करने के लिये प्रोत्साहित किया।

(2) **तानाशाही शासन की समाप्ति—**अब राजाओं का युग समाप्त हो गया उनके स्थान पर जनता के प्रतिनिधियों का युग आरम्भ हुआ। क्रांति से पूर्व फ्रांस निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का सुन्दर गढ़ था, लेकिन इस क्रांति ने

उसे धराशाही कर दिया। अब जन साधारण न देश की राजनीति में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। इससे जनता में आत्म विश्वास की एक नई भावना का संचार हुआ। इस समय फ्रांस में विशाल पमाने पर राजनीतिक दला का उत्कथ हुआ।

(3) सामन्तवाद की समाप्ति—मध्य युगीन सामन्ती प्रथा की समाप्ति फ्रांस की राज्य शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण देन है। शक्ति से पूर्व समाज में समानता विद्यमान थी और समाज में सामन्तता का वचस्व कायम था। ये सामन्त कृषकों का शोषण करते थे तथा उनसे वगार लेते थे। इस प्रकार शक्ति से पूर्व सन्धियों तक कृषक वग और मध्यम वग के करोड़ा यक्तियों का सामन्तों द्वारा शोषण किया जाता रहा, इसलिए कृषक वग और मध्यम वग की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय हो गई थी।

इसके अतिरिक्त शक्ति से पूर्व सामान्य व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था। फ्रांस की शक्ति ने सामन्ती प्रथा का अन्त कर दिया और समानता के सिद्धांत का लागू किया। इस शक्ति में प्रभावित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी शक्तियों की और सामन्तवाद को जड़ से उखाड़ फेंका।

(4) धार्मिक सहिष्णुता का प्राबुध्ति—इस शक्ति के कारण धर्म के क्षेत्र में उदारता की भावनाएँ विकसित हुईं। फ्रांसीसी शक्ति के कारण यूरोप के अन्य देशों में धार्मिक सहिष्णुता की विचारधारा का विकास हुआ और लोगों को धार्मिक उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान की गई। मध्यकालीन युग में जिस धर्म का राजा मानता था, उसी धर्म को मानने के लिये वह अपनी प्रजा को बाध्य करता था। राजा की इच्छा के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्म की उपासना करता था तो वह उसे कठोर से कठोर दण्ड देता था। इस प्रकार शक्ति ने धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना का माग प्रशस्त कर दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धर्म की उपासना कर सकता था।

(5) प्रजातन्त्र का उदय—शक्ति से पूर्व फ्रांस निरकुश राजतन्त्र का सुदृढ़ गढ़ था लेकिन इस शक्ति ने इस गढ़ को धराशायी कर दिया। यह सत्य है कि जातक राज्य टाइरेक्टरी और नेपोलियन ने प्रजातन्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। उस समय फ्रांस की दशा निरकुश राजतन्त्र से भी अधिक शोचनीय हो गई थी। अन्त में फ्रांस में गणतन्त्र की स्थापना हुई। फ्रांसीसी शक्ति के मुख्य सिद्धांत स्वतन्त्रता समानता और विश्व बंधुत्व की भावना आदि थे। इससे विश्व में सभी स्थानों पर समानता के अधिकार की माग की जाने लगी। इसमें समाज में समानता स्थापित हुई। स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार माना गया और प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई। अब मनुष्यों को भाषण, लेखन प्रेम की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। मनुष्य अपने विचार

प्रकट करन के लिये स्वतन्त्र था। म्याम के समक्ष सभी लोगो को एक समान समझा गया और मतवर्जित पदा पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की गईं।

इस श्रान्ति ने विश्व वाङ्मय की भावना पर अधिक जोर दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार सत्कार का प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का भाई है। इसलिये उसे परस्पर सहयोग, प्रेम और महानुभूति का व्यवहार करना चाहिये। इस श्रान्ति के सिद्धान्तों से लोगो में राजनीतिक व सामाजिक समानता की भावनाएँ विकसित हुईं। इससे आगे चलकर सत्कार में प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत हो गईं।

(6) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विकास—इस श्रान्ति ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानव ने अधिपतियों की घोषणा एवं समानता तथा स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। जिसके कारण सामान्य व्यक्ति की गरिमा में भी वृद्धि हुई। श्रान्ति से पूर्व सामान्य व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था। श्रान्ति के पश्चात् सामान्य व्यक्ति का महत्व कायम हुआ। अब राज्य की सर्वोच्च सत्ता जन प्रतिनिधि के हाथों में केन्द्रित थी तथा शासन का स्वरूप जन प्रतिनिधियों की इच्छा पर निर्भर था।

(7) 'याय एव कानून के समक्ष समानता— फ्रांस की श्रान्ति के समानता के सिद्धान्त ने कानून एवं 'याय के समक्ष अमीरों और गरीबों का समानता प्रदान की। अब कानून के समक्ष सभी समान थे। कोई छोटा और बड़ा नहीं था। राजतन्त्र के समय फ्रांस के कानून में असमानता विद्यमान थी। उस समय फ्राँस में सामन्त, पादरियों मध्यमवर्ग और कृषक वर्ग के लिये अलग अलग कानून थे और एक ही अपराध के लिये अलग अलग सजाय दी जाती थी। अब इस श्रान्ति के पश्चात् सामन्त और चर्चों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये। सामन्त किमानो से जिनना रपया मागता था उसे माफ कर दिया गया। दाम प्रथा को समाप्त कर दिया। गिरजाघरों ने जनता से किसी भी प्रकार का कर न लेने का वायदा किया। इस प्रकार सामन्तवाद का अन्त विशेषाधिकारों की समाप्ति और चर्च की शक्ति का पतन हो जाने से समाजवादी शासन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो गया।

(8) सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सुधार—नेशनल एसेम्बली और नेशनल कन्वेंशन ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किये, जिससे फ्रांस में एक नया युग आरम्भ हुआ। इससे दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कजदारों को जेल में बंद करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। त्रिपत्या को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किये गये। पहले ज्येष्ठ पुत्र ही पिता की सम्पत्ति का भालिक होता था किन्तु अब एक पिता की सभी सत्ताओं को सम्पत्ति का बराबर बँटवारा किया जाता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस की राज्य श्रान्ति ने फ्रांस में कई महत्वपूर्ण और जनोपयोगी सुधार किये।

(9) फ्रांस की श्रान्ति का अन्य देशों पर प्रभाव—फ्रांस की राज्य श्रान्ति

के कारण जब निरकुश राजतंत्र घराशाही हो गया तो पड़ोसी देशों के निरकुश शासक घबरा गए। इसलिये इंग्लैण्ड जैसे देश ने अपने तथा म फ्रांसीसी शक्ति व प्रभाव को रोकने के लिय सरल कानून पास किये। फ्रांसीसीयों ने इस समय घोषणा की कि जो देश निरकुश राजतंत्र के विरुद्ध शक्ति करेगा उसे फ्रांस सहायता देगा। इस घोषणा के कारण फ्रांस के कई पड़ोसी देशों में निरकुश राजतंत्र घराशाही हो गया और उसके स्थान पर प्रजातन्त्र शासन व्यवस्था की स्थापना हुई।

फ्रांस की शक्ति का महत्व फ्रांस की राज्य शक्ति अपने ढंग का झूठा प्रयास थी। यह पहला अवसर था जब कि जनता ने राजा को समाप्त करने के लिय खुले रूप से शक्ति की। इंग्लैण्ड की जनता ने राजतंत्र के विरुद्ध नहीं बरन तत्कालीन राजाओं के विरुद्ध शक्ति की थी। अमेरिका की जनता ने अंग्रेजों की दासता से मुक्ति प्राप्त करने के लिय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। फ्रांस की राज्य शक्ति व एतिहासिक महत्व के विषय में इतिहासकारों ने अलग-अलग मत प्रकट किये हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांस की राज्य शक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। उसने केवल हिंसा और बदले की भावना को ही प्रोत्साहित किया परंतु यह बात पूर्णतया से सत्य प्रतीत नहीं होती। वास्तव में फ्रांस की राज्य शक्ति ने सोलहवीं शताब्दी के पुनर्जागरण के अधूरे काम को पूरा कर दिया।

प्राक्सर व्यवस्था लिखा है कि फ्रांस की राज्य शक्ति ने मध्य युगीन परम्पराओं को समाप्त कर लिया। डेविस ने लिखा है कि फ्रांस की राज्य शक्ति के कारण मानव सभ्यता के इतिहास में एक अध्याय प्रारम्भ हुआ। इस शक्ति के द्वारा जन साधारण में स्वतंत्रता व प्रेम की भावना पैदा की गई थी। यदि इंग्लैण्ड और अमेरिका की शक्तियों ने स्वतंत्रता का बीजारोपण किया तो फ्रांस की राज्य शक्ति के द्वारा उस बीज का विकास किया गया।

निम्नलिखित दो सौ वर्षों में विद्वान स्वतंत्रता समानता और विश्व वास्तव के सिद्धांतों की स्थापना पर जोर दे रहे थे। फ्रांस की राज्य शक्ति ने इन सिद्धांतों का प्रचार किया। फ्रांस की जनता ने विश्व के सामने यह उदाहरण रखा कि यदि राजा स्वतंत्रता प्राप्त करेगा तो उस शक्ति को हटा दिया जाना चाहिये। इस उदाहरण का यूरोप के स्वेच्छाचारी शासकों पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब बहुत से निरकुश शासकों ने जनहित के लिये काम करना प्रारम्भ कर दिया।

इंग्लैण्ड की राज्य शक्ति का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित था, जबकि फ्रांस की राज्य शक्ति का राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इस काल में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। वायरा तथा एन जसे महान् दार्शनिक व्यक्तित्व स्वतंत्रता के समर्थक बन

गये। फ्रांस की राज्य क्रांति यूनान, पालण्ड, जर्मनी, इटली और रूस आदि देशों की जनता के लिये मार्ग दर्शाकर बन गई।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रांति के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यद्यपि क्रांति समाप्त हो गई परंतु समस्त यूरोप में प्रजातान्त्रिक विचारों का प्रसार हो गया। प्रोफेसर गृच ने लिखा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने सम्पूर्ण विश्व में मानव के विचारों और कार्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया। हेजल वून ने लिखा है कि "यूरोप में राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र बहुत कुछ फ्रांस से ही विकसित हुए हैं।"

फ्रांस की राज्य क्रांति अमानवीय कार्यों के विरुद्ध हुई थी। इस क्रांति ने मध्य युगीन व्यवस्था को नष्ट कर दिया और एक नये समाज की आधार शिला रखी। मेकार्डन ने लिखा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को फ्रांस की राज्य क्रांति से जोड़ना गलत है।

प्रस्तावित सदस्य पाठ्य पुस्तकें

- 1—प्लेट और जीन ड्रमंड—विश्व का इतिहास
- 2—मवाइन—ए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन
- 3—नेहरू—जवाहरलाल—विश्व इतिहास की भूलक
- 4—बेल्स, एच० जी०—टी आउट लाईन ऑफ हिस्ट्री।

नेपोलियन बोनापार्ट

1 (नवम्बर 1799 से जून 1815 ई० तक)

सेवाइन ने लिखा है कि "नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के सबसे अधिक टिप्पणी किये जाने वाले आदमिया में से हैं।"¹

नेपोलियन का आरम्भिक जीवन—नेपोलियन का जन्म 1769 ई० में इटली के नजदीक कोसिका नामक द्वीप के एक छोटे से नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम कार्लोमेरिया बोनापार्ट था, जो एक साधारण वकील थे। उसकी माता का नाम लोर्टोशिया था, जो बठोर परिश्रमी महिला थी। नेपोलियन की मातृ भाषा इटालियन थी उसके तीन बहनें और चार भाई थे। जब नेपोलियन 10 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिये फ्रांस के स्कूल में भेजा गया। इसके पश्चात् नेपोलियन ने ब्रिगना और परिस के सैनिक स्कूलों में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उसे फ्रांस की सेना में मेलेस शहर के द्वितीय तोपची के पद पर नियुक्त किया गया। नेपोलियन रूसो के विचारों से बहुत प्रभावित था, इसलिये उसने फ्रान्सि के प्रारम्भ में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया और इस समय वह अपने परिवार को लेकर फ्रांस में आ गया। इसके पश्चात् वह फ्रान्सिकारी सेना में भर्ती हो गया।

नेपोलियन के कार्यों से प्रभावित होकर 1793 ई० में उसे तुलोन शहर के मुख्य तोपची के पद पर नियुक्त किया गया। महासभा की वठक इसी नगर में हो रही थी। इस समय तुलोन में उपद्रव प्रारम्भ हो गया। उपद्रवकारियों ने महासभा के भवन पर हमला कर दिया। ऐसे कठिन अवसर पर नेपोलियन ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया और भीड़ पर नियन्त्रण स्थापित करने में सफल हुआ। इस प्रकार उसने महासभा के सदस्या की जान बचाई। आतंक राज्यकाल में नेपोलियन पर फ्रान्सि विरोधी होने का अभियोग लगा कर उसे जेल में डाल दिया

1 सेवाइन—ए हिस्ट्री आफ वरल्ड सिविलीजेशन पृष्ठ 493

गया। उसने अपने जीवन की पच्चासवीं वषर्गांठ जेल में घ्यतीत की। इसके बाद उसे जेल से मुक्त कर दिया गया।

डाईरेक्ट्री की स्थापना, पेरिस की नागरिक सभा और जनता द्वारा आन्दोलन करना आदि बातों ने नेपोलियन को एमा मुनहरत मौका दिया जब कि वह अपनी योग्यता एवं सैनिक प्रतिभा का परिचय दे सका। 5 अक्टूबर 1795 ई० में उपद्रव कारिया ने चारों ओर अराजकता का वातावरण पैदा कर दिया। इस समय राष्ट्रीय ससद के सन्स्था की जाँ को खतरा हो गया। एस अवसर राष्ट्रीय ससद ने नेपोलियन को उपद्रव शांति करने का काम सौंपा। इस काय में उस सफलता मिली। उसकी इस सफलता से प्रभावित होकर फ्रांस के युद्ध मंत्री बार्नो ने उसे इटली भेजे जाने वाले अभियान के मुख्य सेनापति के पद पर नियुक्त किया। मँबनेन बनस ने लिया है कि इटली में उसकी प्रबल सफलता ने उसे राष्ट्रीय नायक का स्थान दिला दिया। हर जवान पर उसका नाम था और राजनीतिक नेता उससे डरने लगे।¹² नेपोलियन की उन्नति में उसकी पत्नी जोस फाणन ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इसका कारण यह था कि वह प्रभावशाली महिना थी और अनेक बड़े सरकारी अधिकारी उसके दोस्त थे।

नेपोलियन के युद्ध—इटली अभियान में नेपोलियन ने अपने शत्रुओं का पराजित करने के लिये नये नये तरीकों का प्रयोग किया और अपने शेष जीवन में उही तरीकों से अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। वह शत्रु पर घचानक आक्रमण करता था। यदि शत्रु की सेना छोटी होती, तब भी वह अपनी सम्पूर्ण सेना को युद्ध के मदान में उतार देता था। यदि युद्ध के दौरान शत्रु पीछे हटने लगता तो वह उस समय तक शत्रु का पीछा करता था, जब तक कि वह हथियार नहीं डाल दे या वह अपने पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दे। उसे इटली अभियान में भारी सफलता मिली। साडीनिया ने फ्रांस को नीस तथा सवाय के प्रदेश दिए। आस्ट्रिया ने उसे नीदरलैंड का प्रदेश दिया। इसके अतिरिक्त आस्ट्रिया ने यह भी स्वीकार कर लिया कि फ्रांस उत्तरी इटली के गणराज्या का संरक्षण बना रहेगा।

नेपोलियन अपनी विजयों की सूचनाएँ समय समय पर फ्रांस भिजवाता रहता था ताकि जनता का उसकी विजयों के बारे में जानकारी मिल सके। इसलिये जब नेपोलियन फ्रांस लौटा तो फ्रांस की जनता ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। फ्रांस में उसकी जय जयकार से वायुमंडल गूँज उठा। उस समय फ्रांस में उसकी वीरता की कई कहानियाँ प्रचलित हुईं, जिनमें वास्तविकता कम और अतिशयोक्ति अधिक थी।

अब नेपोलियन को मिश्र विजय करने का काम सौंपा गया। 1798 ई० में नेपोलियन एक शक्तिशाली सेना के साथ मिश्र को विजय करने के लिये रवाना हुआ। उसने मिश्र पहुँचते ही वहाँ के प्रसिद्ध बन्दरगाह अलक्जेंड्रिया पर अधिकार कर लिया। यह तो नेपोलियन का सौभाग्य था कि अंग्रेज जल सेनानायक नेलसन ने उसकी तलाश करने के लिए तीन दिन पहले अलक्जेंड्रिया छोड़ दिया था। यदि रास्ते में नेपोलियन की नेलसन से मुठभेड़ हो जाती तो आज का इतिहास ही शायद दूसरा होता।

1 अगस्त 1798 ई० में नेलसन और नेपोलियन के बीच नील नदी के पास निर्णायक युद्ध हुआ। जिसमें नेलसन ने फ्रांस के जहाजी बेडों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया और नेपोलियन का फ्रांस से सम्बंध विच्छेद कर दिया। नेपोलियन न साहस से काम लेते हुए सीरिया पर आक्रमण कर दिया। प्रारम्भ में उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई। उसको जाका नगर पर अधिकार करने में सफलता मिली परन्तु बाद में उसकी स्थिति निरन्तर बिगड़ती रही। इसलिए उसने एफर नगर को घेर लिया लेकिन उसको अधिकार करने में उसे सफलता नहीं मिली। इस समय उसकी सेना में महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था और गोला बारूद भी समाप्त हो गया था। 25 जुलाई 1799 ई० में उसका अक्कर की खाड़ी में तुर्की सेना से युद्ध हुआ। जिसमें उसने तुर्की सेना का बुरी तरह से पराजित किया। इस अभियान की उसकी यह अन्तिम विजय थी।

21 अगस्त 1799 ई० में उसने अपनी सेना को वहाँ छोड़ दिया और अपने कुछ चुने हुए साथियों को लेकर वह फ्रांस के लिये रवाना हो गया क्योंकि इस समय उसे यह सूचना मिली थी कि फ्रांस में डाइरेक्टरी का पतन नजदीक है। 9 अक्टूबर को नेपोलियन फ्रांस पहुँच गया। लोगों ने उमका भव्य स्वागत किया। नेपोलियन ने इस समय जनता के सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह फ्रांस का मुक्ति दाता हो। उसने अपने एक मित्र से उस समय यह कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भरा इतजार कर रहा था यदि मैं तनिक पहले आता तो वह ठीक न होता और यदि मैं बाद में आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ।

इसके बाद नेपोलियन ने तत्कालीन सरकार का तटता पलटने के लिये एक पञ्चमूर्त रचा। नेपोलियन के समर्थकों ने नियम निर्मात्री सभा के सदस्यों को चारों ओर से घेर लिया और उनको प्रशासन की बागडोर नेपोलियन के हाथ में सौंपने के लिए बाध्य किया। विरोधी सदस्यों को बंदूक की नाक पर भवन से बाहर निकाल दिया गया। शेष सदस्यों ने प्रशासन व्यवस्था का संचालन तीन कौंसिलों के हाथ में सौंप दिया। नेपोलियन को प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार गैर कानूनी तरीके से नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता पर अधिकार कर लिया।

सेवाइन ने लिखा है कि "एक मामूली पतल परदे की आड़ में तानाशाही स्थापित हो गयी।"²

नेपोलियन का कोस्यूलेट काल (1799-1804)—इस काल में उसकी सैनिक विजयों और प्रशासनिक सुधारों के कारण लोकप्रियता में वृद्धि हुई। 1800 ई. में नेपोलियन ने इटली में स्थित आस्ट्रिया की सेना को युद्ध में पराजित किया। 1802 ई. में उसने अपने शक्तिशाली शत्रु इंग्लैंड का अपनी इच्छानुकूल शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। नेपोलियन एक कुशल सेनापति था। सेबाइन ने लिखा है कि "संसार के अधिकांश विद्वान् सेनानी के विनाश के लिये वह सिकन्दर महान का प्रतिद्वन्दी है।"²

नेपोलियन एक महान योद्धा होने के साथ-साथ एक कुशल प्रशासक भी था। जिसने युद्धों में व्यस्त रहते हुए भी फ्रांस के प्रशासन में कई महत्वपूर्ण सुधार किये। जिन समस्याओं की उसने स्थापना की उसी आधार पर आधुनिक समस्याओं का निर्माण किया गया। इसलिए नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसने अपने सुधारों में यथासम्भव यह प्रयास किया कि क्रांति के सिद्धांतों का पालन हो सके। उसने केंद्र को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया।

प्रोफेसर डेविस ने लिखा है कि नेपोलियन लुई चौदहवें की भांति निरकुश था, परन्तु फ्रांस की जनता ने नेपोलियन की निरकुशता को इसलिए सहन किया क्योंकि वह नेपोलियन की असाधारण सैनिक विजयों से बहुत प्रभावित थी और वह फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों का विदेश में प्रचार कर रहा था।

नेपोलियन के शासन सम्बन्धी सुधार

उसने शासन के क्षेत्र में निम्न सुधार किये—

1 प्रशासनसम्बन्धी सुधार

नेपोलियन ने केंद्र का सुदृढ़ बनाने के लिए प्रांतीय और जिला का विभाजन किया। उसने उन लोगों का प्रांतीय जिला और तहसीला में शासन करने के लिए नियुक्त किया जो उसकी कृपा पर निर्भर करने दें। जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था। उन अफसरों को त्रमश प्रोफेक्टर, मजिस्ट्रेट तथा मेयर्स कहा जाता था। नेपोलियन द्वारा किया गया प्रांतीय और जिला का विभाजन आज भी फ्रांसीसी शासन व्यवस्था का आधार बना हुआ है।

नेपोलियन ने अनन्त क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार किये परन्तु यह केंद्रीय सरकार के अधिकारों का कम करने के पक्ष में नहीं था। प्रांतीय अधिकारियों का

1 सेबाइन—"हिस्ट्री ऑफ़ द लॉ मिबिलीनेशन, पृष्ठ 494

नियुक्ति वह स्वयं करता था और प्रान्तीय अधिकारी कर्म्यून के अधिकारियों को नियुक्त करता था। फ्रांस में सभी प्रकार के मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति नेपोलियन के द्वारा की जाती थी। नेपोलियन केन्द्रीय सत्ता का सुदृढ़ कर फ्रांस में अशान्ति और अव्यवस्था को समाप्त कर शांति स्थापित करने में सफल हुआ। इस प्रकार नेपोलियन ने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की।

उसने सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिये उसने पुराने मतभेद दलदल और झगडा को समाप्त करने के लिये सभी वर्गों एवं दलों का एक समान अधिकार प्रदान दिया। क्रांति के कारण देश से भागे हुए बुलीना एवं सामंतों को नेपोलियन ने पुनः फ्रांस में आने के लिये आमंत्रित किया। इस प्रकार उसने क्रांति के कार्यों को ठोस रूप प्रदान किया।

(2) आर्थिक क्षेत्र में सुधार—क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक दशा खराब थी। पिछले दस वर्षों में हो रहे युद्ध ने उसकी आर्थिक दशा को दयनीय बना दिया था। क्रांति के उथल-पुथल के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा निरंतर बिगड़ती जा रही थी। वहाँ पर उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो चुके थे। राज्य के कर नियमित रूप से वसूल नहीं हो पा रहे थे जिससे राज्य की आय में भारी कमी हो गई थी। नेपोलियन ने फ्रांस की इस बिगड़ती हुई आर्थिक दशा में सुधार करने के लिये निम्न प्रयास किये—

(i) नेपोलियन ने राज्य की कर प्रणाली में सुधार किया, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। उसने केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कर वसूल करने का अधिकार दिया। व्यापार को हानि पहुँचाने वाली वस्तुओं पर राज्य कर कम कर दिया। यदि कोई सरकारी कर्मचारी कर वसूल करने के पश्चात् राजकोष में जमा नहीं करवाता था अथवा घूस लेकर कम लगान व चुगी वसूल करता था तो उसे बड़ी-बड़ी सजा दी जाती थी। इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय में वृद्धि हुई।

(ii) नेपोलियन ने फ्रांस का आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करने के लिये 1800 ई० में फ्रांसीसी बैंक की स्थापना की। कुछ ही समय में फ्रांस के प्रमुख नगरों में उसकी शाखाएँ खोली गईं। इस बैंक का उसने मुद्रा प्रचलन एवं नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया।

(iii) उसने कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये। कई दसदलों को सुखाकर कृषि योग्य बनाया गया। कृषि के नये तरीकों का प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। उसने सिंचाई के लिए अनेक नई नहरों का निर्माण कराया तथा पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। नेपोलियन द्वारा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के कारण उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।

(iv) उसने व्यापार और व्यवसाय का प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाये। व्यापार के विकास के लिये "राष्ट्रीय उद्योग निगम" की स्थापना की। खाद्य सामग्री के वितरण के लिये समुचित व्यवस्था की और दशमलव प्रणाली को लागू किया गया। इंग्लैण्ड के नए नए औद्योगिक तरीके को फ्रांस के उद्योगपतियों ने अपना कर उत्पादन में बढ़ि की। इंग्लैण्ड के माल पर आयात कर में भारी मात्रा में बढ़ि की गई ताकि जनता फ्रांस की बनी हुई वस्तुएँ ही अधिक मात्रा में खरीदे और फ्रांसीसी वस्तुओं के मुकाबल में इंग्लैण्ड की वस्तुएँ सस्ती नहीं पड़े। व्यापार में बढ़ि करने के लिये उसने यातायात के साधना का विकास किया। उसने विदेशी व्यापारियों की सुविधा के लिए कई वास्तवशाहा का विकास किया।

इन सुधारों के फलस्वरूप फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई थी।

(3) पोप के साथ सम्बन्ध—नेपोलियन धर्म के क्षेत्र में तटस्थ था, परन्तु उसने धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किया। फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कथोलिक धर्म में विश्वास करती थी। त्रांति से पूर्व फ्रांसीसी जनता में रोमन चर्च के प्रति प्रगाढ श्रद्धा थी। त्रांति के पश्चात् पादरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और बर्धनिक पादरी वर्ग की स्थापना की गई। त्रांति काल में चर्च की जागीरें जब्त करली गई। इन कार्यों से फ्रांस की कथोलिक जनता में असंतोष विद्यमान था। पोप भी अपनी शक्ति नष्ट हो जाने के कारण त्रांति का विरोधी था।

नेपोलियन ने इस धार्मिक समस्या का राजनैतिक दृष्टिकोण से समाधान किया। उसने कथोलिक जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिये जेल में पड़े हुए पादरियों को रिहा कर दिया। रविवार का दिन फिर से महत्त्वपूर्ण दिन घोषित किया। इसके पश्चात् नेपोलियन ने पोप के साथ 1810 ई० में एक संधि की जो "कांकाहॉट" के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के अनुसार निम्न शर्तें निश्चित की गई —

- (i) इस संधि के अनुसार नेपोलियन ने कथोलिक धर्म को फ्रांस में राज्य धर्म घोषित कर दिया। इसके बदले में पोप ने त्रांति काल में राज्य द्वारा छीनी गई चर्च की जागीरों पर से अपना अधिकार त्याग दिया।
- (ii) फ्रांस की सरकार पादरियों की नियुक्ति के लिए एक सूची पाप को देगी। पोप उस सूची में अंकित व्यक्तियों को ही पादरी के पद पर नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार पोप अब बिना राज्य की इच्छा से अपने मनमाने ढंग से पादरियों को नियुक्त नहीं कर सकता था।
- (iii) पादरियों पर राज्य का नियंत्रण रखने के लिये उन्हें राज्य की ओर से वतन दिया जाना सगा। अब प्रत्येक पादरी को फ्रांस के संविधान के प्रति शक्ति

की शपथ लनी पड़ती थी। इस प्रकार नपोलियन ने रोमन कपोलिन घम के अनुयाइयाँ का समयन प्राप्त कर लिया। उसन सभी ब्यक्तियाँ को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदाती थी।

(4) शिक्षा के क्षेत्र में विकास—नपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास के नियम विनियम प्रयास किये। उसन शिक्षा का तीन भागों में विभाजित कर दिया। 1 प्रारम्भिक 2 उच्च माध्यमिक और 3 विश्वविद्यालय। उसन समय में प्रत्येक नगर में प्राईमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्ध का भार नपोलियन ने प्रभावशाली ब्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया। इसी प्रकार प्राईमरी शिक्षा का प्रबन्ध उसन सम्पूर्ण क हाथों में सौंप दिया। प्राईमरी और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर विश्वविद्यालय का नियन्त्रण था। उसन कई नगरों में राज्य के नियन्त्रण में सैनिक और व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना की।

1808 में नपोलियन ने फ्रांस में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय का समस्त देश की शिक्षा सस्याओं पर नियन्त्रण था। यही विश्वविद्यालय स्कूलों का पाठ्यक्रम निर्धारित करता था और वहाँ अध्यापकों की नियुक्तियाँ करता था। विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र देने के बाद कोई भी नया विद्यालय खोला जा सकता था। इस विश्व विद्यालय के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति नपोलियन के द्वारा की जाती थी। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। दश के सभी उच्च विद्यालयों को विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्धित कर दिया गया।

शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक शिक्षक विद्यालय की स्थापना की गई। नपोलियन ने गरीब और योग्य छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की। शोध कार्य के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई। जिसने कला और साहित्य के विकास का प्रोत्साहन दिया। उसने फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम घोषित किया।

(5) प्रजा हितकारी कार्य—नेपोलियन ने जनहित के निम्न कार्य किये—

(i) सड़कें—नेपोलियन ने युद्ध में व्यस्त रहने के बावजूद भी सड़कों का निर्माण करवाया। 1811 ई० तक फ्रांस में 229 चौड़ी सड़कों का जाल बिछा दिया उसने पेरिस का देश के हर कोन से जोड़ दिया। पेरिस से रोम, ब्रिजियन, स्विटजरलैण्ड, राइन प्रदेश और नेपल्स तक सड़कों का निर्माण करवाया। सड़कों के अतिरिक्त नेपोलियन ने नहरों और पुलों का निर्माण करवाया।

(ii) सिंचाई प्रबन्ध—नेपोलियन ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सिंचाई प्रबन्ध की व्यवस्था की। उसने अनेक नई नहरों का निर्माण करवाया और पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई।

(iii) पेरिस के सौंदर्य में वृद्धि—नेपोलियन ने पेरिस के सौंदर्य में वृद्धि

कर विश्व का सबसे सुन्दर और आकर्षक नगर बना दिया। उसने पेरिस में चौड़ी सड़क का निर्माण करवाया। इसका अतिरिक्त उसने अनेक स्मारक और सुन्दर भवना का निर्माण करवाया। पेरिस में उसने सुन्दर बाग बगीचे और फव्वारा का निर्माण करवाकर उनके सौंदर्य में वृद्धि की। वह देश देशांतरों से कलाकृतियाँ उठा लाता था और उस लाकर वे संग्रहालय में रख देता था। परिणामस्वरूप पेरिस का लाबेर संग्रहालय विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ बन गया। नेपोलियन ने 1804 ई० से लेकर 1813 ई० तक एक अरब फ्रैंक प्रजाहितकारी कार्यों पर खर्च किया।

संसार में निर्यात है कि विश्व विख्यात पेरिस नगर अपनी चौड़ी सड़क, पेडा की बतारा से सजी सड़क, स्मारक और सुन्दर भवना सहित उसकी महानता का सबूत है।¹ उसने नीन नदी पर बहुत सुन्दर और स्थायी पुल का निर्माण करवाया। नेपोलियन कला का प्रशंसक था। उसने प्राचीन कला के आधार पर पेरिस में "बच ऑफ मिडिलियानी" नामक विशाल व्यापार भवन का निर्माण करवाया। जो प्रायः वही उस समय की भवन निर्माण कला का सुन्दर नमूना है।

(6) विधि संहिता—नेपोलियन की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी विधि संहिता है। उसने एक बार कहा था कि 'विधान संहिता का निर्माण उसकी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि है, जिसका महत्व उसकी सभी विजयों से अधिक है।' नेपोलियन का यह कथन सत्य प्रतीत होता है। वास्तव में उसकी विधि संहिता सम्पूर्ण मानव समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। प्रायः वही एक सगठित कानून की आवश्यकता थी जिसे नेपोलियन ने पूरा किया।

प्रायः से पूर्व प्रायः में कानूनों की समानता नहीं थी। अलग-अलग प्रायः में अलग-अलग कानून प्रचलित थे। प्रायः काल में यह प्रयास किया गया कि सम्पूर्ण प्रायः में अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था का लागू किया जाय परन्तु इसमें विरोध सफलता प्राप्त नहीं हुई। नेपोलियन ने प्रायः में इस अधूरे कार्य को पूरा किया। उसने निम्न पाँच विधानों का निर्माण किया—1-नागरिक कानून 2-जायदाद सम्बन्धी कानून, 3-नागरिक नियम पद्धति 4-कौशलकारी कानून, 5-आपाधिक कानून।

नेपोलियन ने 1804 ई० में सम्पूर्ण प्रायः में इस विधि संहिता को लागू कर दिया। इस विधि संहिता के बाद प्रायः में एक जमी कानून व्यवस्था की स्थापना हुई। नेपोलियन की विधि संहिता पर प्रायः की वर्तमान जाय व्यवस्था आधारित है। यद्यपि इसमें आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि नेपोलियन ने प्रायः में मुख्यतः व्यवस्था और मुख्यव्यवस्था समाज की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की व्यवस्था थी। उसने प्रायः की

1—सेवाहन—ए हिस्ट्री ऑफ़ बरुड निवलीजेन्स, पृष्ठ 498

जनता की इच्छानुकूल देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना की और बिना किसी बाधा के यूरोपियन देशों में शांति के आदर्शों का प्रचार किया।

नेपोलियन की नीति (1804-1814)—नेपोलियन पडयत्र रचने में कुशल था। 1802 ई० में वह आजीवन भर के लिए कोससल बन गया। फरवरी 1804 ई० में कुछ लोगों ने नेपोलियन की हत्या का पडयत्र रचा। यद्यपि यह पडयत्र असफल रहा। परंतु नेपोलियन के मन में सम्राट बनने की अभिलाषा जाग्रत हुई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने फिर पडयत्र रचा। उसके प्रयासों से ट्रिब्यूनेट में यह प्रस्ताव रखा गया कि जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय और नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया जाय।

ट्रिब्यून ने इस प्रस्ताव पर जनमत संग्रह करवाया। 35 लाख मतों के बहुमत में जनता ने नेपोलियन को सम्राट बनाना स्वीकार कर लिया। अब तक यह परम्परा थी कि फ्रांस के सम्राट को राजमुकुट पोप पहनाता था परंतु नेपोलियन ने इस परम्परा का उल्लंघन करते हुए स्वयं ने अपना मुकुट धारण किया। एलिस और जोन ने लिखा है कि "2 दिसम्बर 1804 ई० को नोट्रेडेम कपेड्रल में अभिमानी नेपोलियन ने इस समारोह के लिये रोम से आए हुए पोप के हाथों से ताज लेकर अपने सिर पर रख लिया।"¹

इस प्रकार जिस राजतन्त्र को समाप्त करने के लिए फ्रांसीसी जनता ने शांति की थी। उसी राजतन्त्र को नेपोलियन ने सम्राट बनाकर फिर से फ्रांस में स्थापित कर दिया। जनता द्वारा नेपोलियन को सम्राट के पद पर चुनने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

- 1—नेपोलियन द्वारा सामाजिक समानता स्थापित करना
- 2—नेपोलियन की सुदृढ़ शासन व्यवस्था
- 3—उसकी असाधारण सैनिक विजय
- 4—उसकी सफल धार्मिक नीति
- 5—उसका असाधारण व्यक्तित्व

2 दिसम्बर 1804 ई० को बड़ी धूमधाम के साथ उसका राज्याभिषेक समारोह मनाया गया। उसने अपने राज्याभिषेक के समय बड़े शब्दों से कहा था कि "मैंने फ्रांस के ताज को जमीन पर पड़ा पाया और अपनी तलवार से उठा लिया।"²

यूरोप पर प्रभुत्व का प्रयास—सम्राट बनने के पश्चात् नेपोलियन ने सम्पूर्ण यूरोप पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। फ्रांस की राज्य शांति के कारण

1 एलिस और जोन—संसार का इतिहास पृष्ठ 344

2 ए हिस्ट्री आफ ब्रिटिश सिविलिजेशन, पृष्ठ 494

यूरोप के सभी देश चिंतित थे। उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाकर उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। नेपोलियन ने इंग्लैंड के अतिरिक्त अ्य सभी देशों को समय समय पर युद्धों में पराजित किया और उनके गुटों को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। उसको विवश होकर इंग्लैंड के साथ आर्मीस की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार यह निश्चित हुआ कि इंग्लैंड माल्टा द्वीप खाली कर देगा। जब उसने द्वीप खाली नहीं किया तो नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध तीसरी बार गुट का निर्माण किया। इस गुट में इंग्लैंड के साथ आस्ट्रिया, रूस और स्वीडन आदि देश थे। नेपोलियन का इस समय हनोवर पर अधिकार करने में सफलता मिली।

1805 ई० में ट्रेफलगर नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड के सेनापति नेलसन ने फ्रांस तथा स्पेन के समुक्त जहाजी बेड़े को बुरी तरह पराजित किया। स्वयं नेलसन भी इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ। थल युद्ध में आस्ट्रियन नामक स्थान पर नेपोलियन ने आस्ट्रिया की सेना को बुरी तरह परास्त किया। विवश होकर आस्ट्रिया को इंग्लैंड के गुट से अलग होना पड़ा तथा नेपोलियन के साथ प्रेंस युग की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के अनुसार राइन राज्य संध की स्थापना की गई और पवित्र रोमन सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया।

जब नेपोलियन ने जर्मनी के अठारह प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर राइन राज्य की स्थापना की तो प्रशा नेपोलियन का इस काम से बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि नेपोलियन राइन राज्य संध का माध्यम से प्रशा के मामले में हस्तक्षेप कर रहा था। इसलिए प्रशा ने अप्रसन्न होकर नेपोलियन का विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नेपोलियन ने उसे युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रशा को बाध्य किया। अब नेपोलियन को रूस से निपटना बाकी था। 14 जून 1807 ई० को फ्रीडलैंड के युद्ध में नेपोलियन ने रूस को बुरी तरह पराजित किया और उसे हिलसिंट की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि नेपोलियन का उत्कथ की चरम सीमा थी।

नेपोलियन पतन की ओर टिलसिंट की संधि तक नेपोलियन अधिकांश कार्यों में सफलता प्राप्त कर चुका था परंतु इसके बाद इसका भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। अततागत्वा उसका पतन हो गया। उसको पतन की ओर ल जाने में निम्न घटनाओं का योगदान रहा—

1. महाद्वीपीय प्रणाली—टिलसिंट की संधि का कारण नेपोलियन की शक्ति सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच गई थी। इस समय तक उसने इंग्लैंड के सिवाय यूरोप के सभी महत्वपूर्ण देशों को युद्धों में पराजित कर लिया था लेकिन उसकी साम्राज्यवादी लालसा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वह इंग्लैंड पर भी विजय प्राप्त करना

जनता की इच्छानुकूल देश में शांति और सु-व्यवस्था की स्थापना की और बिना किसी बाधा के यूरोपियन देशों में शान्ति के आदर्शों का प्रचार किया।

नेपोलियन की नीति (1804-1814)—नेपोलियन पढ्यत्र रचने में कुशल था। 1802 ई० में वह आजीवन भर के लिए कोस्तल बन गया। फरवरी 1804 ई० में कुछ लोगों ने नेपोलियन की हत्या का पढ्यत्र रचा। यद्यपि यह पढ्यत्र असफल रहा। परंतु नेपोलियन के मन में सम्राट बनने की अभिलाषा जाग्रत हुई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने फिर पढ्यत्र रचा। उसके प्रयासों से ट्रिब्यूनट में यह प्रस्ताव रखा गया कि 'जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय और नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया जाय।

ट्रिब्यून ने इस प्रस्ताव पर जनमत संग्रह करवाया। 35 लाख मतों के बहुमत से जनता ने नेपोलियन को सम्राट बनाना स्वीकार कर लिया। अब तक यह परम्परा थी कि फ्रांस के सम्राट को राजमुकुट पोप पहनाता था परंतु नेपोलियन ने इस परम्परा का उल्लंघन करते हुए स्वयं अपना मुकुट धारण किया। एलिस और जोन ने लिखा है कि "2 दिसम्बर 1804 ई० को नोट्टडेम कयेड्रल में अभिमानि नेपोलियन ने इस समारोह के लिये रोम से आए हुए पोप के हाथों से ताज लेकर अपने सिर पर रख लिया।"¹

इस प्रकार जिस राजतन्त्र को समाप्त करने के लिए फ्रांसीसी जनता ने शान्ति की थी। उसी राजतन्त्र को नेपोलियन ने सम्राट बनाकर फिर से फ्रांस में स्थापित कर दिया। जनता द्वारा नेपोलियन को सम्राट के पद पर चुनने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

- 1—नेपोलियन द्वारा सामाजिक समानता स्थापित करना
- 2—नेपोलियन की सुदृढ शासन व्यवस्था
- 3—उसकी असाधारण सैनिक विजय
- 4—उसकी सफल धार्मिक नीति
- 5—उसका असाधारण व्यक्तित्व

2 दिसम्बर 1804 ई० को बड़ी धूमधाम के साथ उसका राज्याभिषेक समारोह मनाया गया। उसने अपने राज्याभिषेक के समय बड़े गव से कहा था कि "मैंने फ्रांस के ताज की जमीन पर पड़ा पाया और अपनी तलवार से उठा लिया।"

यूरोप पर प्रभुत्व का प्रयास—सम्राट बनने के पश्चात् नेपोलियन ने सम्पूर्ण यूरोप पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। फ्रांस की राज्य शान्ति के कारण

1 एलिस और जोन—संसार का इतिहास पृष्ठ 344

2 ए हिस्ट्री आफ़ वरल्ड सिविलिजेशन, पृष्ठ 494

यूरोप के सभी देश चिंतित थे। उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाकर उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। नेपोलियन ने इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य सभी देशों को समय समय पर युद्धों में पराजित किया और उनके गुटों को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। उसको विवश होकर इंग्लैंड के साथ आर्मीस की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार यह निश्चित हुआ कि इंग्लैंड माल्टा द्वीप खाली कर देगा। जब उसने द्वीप खाली नहीं किया तो नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध तीसरी बार गुट का निर्माण किया। इस गुट में इंग्लैंड के साथ आस्ट्रिया, रूस और स्वीडन आदि देश थे। नेपोलियन का इस समय हनोवर पर अधिकार करने में सफलता मिली।

1805 ई० में ट्रेफालगार नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड के सेनापति नेलसन ने फ्रांस तथा स्पेन के संयुक्त जहाजी बंडे का बुरी तरह पराजित किया। स्वयं नेलसन भी इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ। थल युद्ध में आस्टेरलिज नामक स्थान पर नेपोलियन ने आस्ट्रिया की सेना को बुरी तरह परास्त किया। विवश होकर आस्ट्रिया को इंग्लैंड के गुट से अलग होना पड़ा तथा नेपोलियन के साथ प्रेस बुर्ग की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के अनुसार राइन राज्य संधि की स्थापना की गई और पवित्र रोमन सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया।

जब नेपोलियन ने जर्मनी के अठारह प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर राइन राज्य की स्थापना की तो प्रशा नेपोलियन के इस कार्य से बहुत प्रोथित हुआ, क्योंकि नेपोलियन राइन राज्य संधि के माध्यम से प्रशा के मामले में हस्तक्षेप कर रहा था। इसलिए प्रशा ने अप्रसन्न होकर नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध घोषित कर लिया। नेपोलियन ने उस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रशा को बाध्य किया। अब नेपोलियन को रूस से निपटना बाकी था। 14 जून 1807 ई० को फ्रीडलैंड के युद्ध में नेपोलियन ने रूस को बुरी तरह पराजित किया और उसे हिलासिट की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि नेपोलियन के उत्कृष्ट की चरम सीमा थी।

नेपोलियन पतन की ओर टिलसिट की संधि तक नेपोलियन अधिकांश कार्यों में सफलता प्राप्त कर चुका था परंतु इसके बाद इसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। अन्ततोगत्वा उसका पतन हो गया। उसके पतन की ओर ल जाने में निम्न घटनाओं का योगदान रहा—

1. महाद्वीपीय प्रणाली—टिलसिट की संधि के कारण नेपोलियन की शक्ति सर्वोच्च बिंदु पर पहुँच गई थी। इस समय तक उसने इंग्लैंड के सिवाय यूरोप के सभी महत्वपूर्ण देशों को युद्धों में पराजित कर दिया था लेकिन उसकी साम्राज्यवादी लालसा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वह इंग्लैंड पर भी विजय प्राप्त करना

चाहता था। उसका यह मानना था कि यूरोप पर प्रभुसत्ता बनाये रखने के लिए इंग्लण्ड को पराजित करना आवश्यक है।

ट्रेफलगर के युद्ध से नेपोलियन यह समझ चुका था कि इंग्लण्ड को परास्त करना कोई आसान काम नहीं है। इंग्लण्ड की नेपोलियन के विरुद्ध सफलता का मुख्य कारण यह था कि उसका सामुद्रिक बड़ा बहुत शक्तिशाली था। इसलिये नेपोलियन इंग्लिश चैनल का पार कर इंग्लण्ड पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पा रहा था। अतः नेपोलियन ने इंग्लण्ड को चुकाने के लिये एक नई नीति का प्रयोग किया। जिसे यापार बहिष्कार भीति जयन्ता महाद्वीपीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है।

नेपोलियन ने सोचा कि यदि इंग्लण्ड के यापार को नष्ट कर दिया जाय तो वह शीघ्र ही हथियार डाल देगा। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये उसने इंग्लण्ड के विरुद्ध 'यापारिक सघप प्रारम्भ कर दिया और उससे 'यापार को नष्ट करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया। यह 'यापारिक सघप ही इतिहास में महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध है।

व्यवस्था को क्रियायत करने का तरीका —

(1) बर्लिन की आजाप्ति—नेपोलियन इंग्लण्ड का एक व्यापारिक देश समझता था। इसलिये उसने इंग्लण्ड के यापार का सम प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया। नेपोलियन चाहता था कि इंग्लण्ड का माल यूरोप का कोई देश नहीं खरीदे और उसे कोई दश बच्चा माल दे। 1806 में नेपोलियन ने बर्लिन में जा घोषणाएँ की वह इतिहास में बर्लिन की आजाप्ति के नाम से प्रसिद्ध है।

इस आजाप्ति के अनुसार नेपोलियन ने सभी यूरोपियन देशों को आदेश दिया कि वे इंग्लण्ड के जहाजों को उनके बंदरगाहों पर नहीं आने देंगे और न ही इंग्लण्ड के साथ किसी प्रकार का व्यापार करेंगे। इस प्रकार नेपोलियन ने यूरोप के सभी बंदरगाह इंग्लण्ड के जहाजों के लिये बंद करवा दिये। यदि यूरोप के किसी भी बंदरगाह पर इंग्लण्ड का यापारी दिखाई देता तो उसे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया जाता था और उसका भान भी जप्त कर लिया जाता था। नेपोलियन ने यूरोपियन देशों का यह भी आदेश दिया कि जो वस्तुएँ पहले ब्रिटेन से मँगवाई जाती थीं। उनका उत्पादन यूरोप में प्रारम्भ किया जाय अथवा वे वस्तुएँ संयुक्त राष्ट्र या तटस्थ राष्ट्रों से आयात की जाय। नेपोलियन का बर्लिन आदेश इंग्लण्ड के लिये एक भयंकर चुनौती था। इस प्रकार नेपोलियन से इंग्लण्ड को पराजित करने के लिये सम्पूर्ण यूरोप को फ्रांस के इंग्लण्ड के आधिकारिक युद्ध में झोक दिया।

(11) ओट्स आफ कोर्गसल—ब्रिटेन की सरकार ने बर्लिन आदेश के विरोध में आर्टिनेस आफ कोर्गसल पास किया। वहाँ की सरकार ने जनवरी से नवम्बर 1807

इ० के बीच कई आदेश जारी किये। जिसके अनुसार यह घोषणा की गई थी कि यदि कोई भी तटस्थ राष्ट्र फ्रान्स और उसके अधीन देशों से व्यापार करता हुआ पाया जायेगा तो ब्रिटेन उसका माल जब्त कर लेगा। ब्रिटेन ने तटस्थ राष्ट्रां को भी यह आदेश दिया कि अफ्रीकी बंदरगाहों पर रिपोर्ट करने के पश्चात् ही उनका जहाज यूरोपियन तटों के लिये रवाना होंगे। इस आदेश के पीछे ब्रिटेन का मुख्य उद्देश्य यह था कि तटस्थ राष्ट्रों के जहाज फ्रांस और अन्य यूरोपियन देशों का मान नहीं पहुँचा सकें।

(iii) वारसा मिलान, फ्राउटैन ब्लू की घोषणा—आइसलैंड की वीसिल के विरोध में नेपोलियन ने जनवरी 1807 में वारसा में घोषणा की कि यदि किसी भी देश का जहाज ब्रिटेन के बंदरगाहों पर रिपोर्ट करने के लिये जायेगा तो फ्रान्स उसके जहाजों को जब्त कर लेगा।

इसके पश्चात् नेपोलियन ने फ्राउटैन ब्लू की घोषणा में यह आदेश जारी किया कि यदि किसी भी देश में इंग्लैंड का माल पाया गया तो फ्रान्स उसे जब्त कर लेगा। नेपोलियन को यह आदेश इसलिये जारी करना पड़ा, क्योंकि पिछले तीन वर्षों में कई यूरोपियन देश इंग्लैंड से गुप्त रूप से माल मँगवाने लग गये थे।

महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम—महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की अशुभतम सृष्टि का परिणाम थी। इस व्यवस्था के माध्यम में नेपोलियन यह चाहता था कि इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त कर फ्रांस को यूरोप का व्यापारिक केन्द्र बना दिया जाय। नेपोलियन का अपना उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। अतः यह नीति फ्रान्स के लिये घातक सिद्ध हुई। यूरोपियन देशों का अपना उपनिवेशों से सम्बन्ध विच्छेद होने के कारण माल आना रुक गया। परिणामस्वरूप वस्तुओं का भाव बढ़ी हुई और वस्तुओं का बाला बाजार रुक गया। इससे जनसाधारण बहुत दुखी हो गया और बर्लिन में दश गुल्लक के इंग्लैंड में सामान मँगवाने लगे।

इस व्यवस्था से फ्रान्स का व्यापार अवरुद्ध हो गया और इससे फ्रान्स और इंग्लैंड दोनों ही देशों की आर्थिक व्यवस्था का प्रभावित किया। इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों में माल नहीं मगवाने लगा परन्तु अन्य देशों का उसका मान निरंतर जाता रहा। जबकि फ्रान्स अपना मान अन्य देशों को नहीं भज सका। इसका परिणाम फ्रान्स के लिये घातक सिद्ध हुआ। अन्त में अतिरिक्त फ्रान्स के अन्तर्गत के व्यापार का हानि होने के कारण वे भी फ्रान्स में नाराज हो गये। इसलिये नेपोलियन का पतन सम्भव हुआ। यूरोप का अन्तर्गत चौकट हो गया। इंग्लैंड का मान यूरोप में नहीं आने में वस्तुओं का दाम बहुत अधिक बढ़ गया। जनसाधारण का अर्थिक उपयोग का वस्तुओं में मिलान के कारण उनमें उपनिवेशों की कामना शुरू कर

दिया। यूरोप के देश धीरे धीरे इस महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध करने लगे और इस व्यवस्था से अपने को मुक्त करने का प्रयास करने लगे।

जब स्वीडन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने से इन्कार कर दिया तो नपोलियन ने वहा के शासक को हटा दिया। उसके स्थान पर अपने सेनापति को वहा का शासक नियुक्त कर दिया। हालण्ड पर उस समय नेपोलियन का भाई लुई बोनापाट शासन कर रहा था। जब उसने भी इस नीति का पालन करने से इन्कार किया तो नेपोलियन ने उस भी शासक पद से हटा दिया और हालैण्ड को फ्रांस में मिला लिया। पोप ने भी नेपोलियन की इस नीति का विरोध किया। इसलिये नेपोलियन ने पोप का भी राज्य छीन लिया और उसे जेल के सीखचो में बन्द कर दिया। पुतगाल ने भी इस नीति का विरोध किया। परिणामस्वरूप नेपोलियन ने पुतगाल को फ्रांस में मिला लिया। इस प्रकार नेपोलियन ने अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के प्रश्न को लेकर अपने सभी मित्रों में असंतोष पैदा कर दिया।

प्रोफसर मायस ने लिखा है कि इंग्लण्ड को ध्वंस करने की नेपोलियन की यह नीति एक आत्म हत्या की नीति थी। इस नीति से उसके साम्राज्य को भयकर आघात पहुँचा। इंग्लण्ड की नौ सैनिक शक्ति के कारण उसकी यह नीति असफल रही।

इस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण कुछ देश नेपोलियन के मित्र बन गये क्योंकि वे इंग्लण्ड के ओडस आफ कौंसिल का पालन करने के लिये तयार नहीं थे। उदाहरण के लिये हम डेनमार्क को ले सकते हैं। जो इंग्लण्ड का मित्र था लेकिन ओडस आफ कौंसिल का विरोधी होने के कारण उसकी फ्रांस से मित्रता सम्भव हो गई। नेपोलियन की बर्लिन आज्ञापति के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपियन दशा को माल भेजना प्रारम्भ कर दिया था। फलस्वरूप उसके इंग्लण्ड के साथ सम्बन्ध कटु हो गये। इसलिए आगे चलकर 1812 ई० में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। जिसके परिणाम फ्रांस को भी भोगने पड़े। इस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण फ्रांस का व्यापार चौपट हो गया। उसे कई देशों के साथ युद्ध करने पड़े जिसके कारण फ्रांस का राजकोष खाली हो गया। परिणामस्वरूप फ्रांस में भ्रष्टाचार बढ़ा और उसकी आर्थिक दशा बहुत शोचनीय हो गई।

(2) नेपोलियन का पोप के साथ सम्बन्ध—कोन्स्यूलेट बनने के पश्चात् नेपोलियन ने अपनी स्थिति का दृढ़ करने के लिये पोप के साथ समझौता कर लिया था, जिससे उस कथोचिक जनता का सम्बन्ध मिल गया। कई वर्षों तक नेपोलियन इस सम्झौते का पालन करता रहा परन्तु जब पोप ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध किया तो नेपोलियन उस पर बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने पोप का राज्य छीन लिया। इस पर पोप ने नेपोलियन को चर्च से निकाल दिया। इस

समय नेपोलियन न पोप को गिरफ्तार कर जेल के सीखचो में बंद कर दिया। इसका पश्चात् उसने पोप का राज्य फ्रांस के साम्राज्य में मिला लिया। नेपोलियन के इस कार्य से सम्पूर्ण यूरोप की कथोलिक जनता उसकी शत्रु बन गई।

(3) स्पेन से सघर्ष—स्पेन का शासक नेपोलियन का घनिष्ठ मित्र था। उसने नेपोलियन की युद्धों में बहुत महत्वपूर्ण सहायता दिया था। जब नेपोलियन युद्धों में व्यस्त था तब स्पेन के शासक ने उसे जन, धन और सामग्री आदि में सहायता पहुँचाई थी, परन्तु नेपोलियन स्पेन को हथपना चाहता था, इसलिये वहाँ का शासक उसका बहुत शत्रु बन गया।

नेपोलियन ने स्पेन के राजवंश के सगड़े का लाभ उठाकर वहाँ का शासक चार्ल्स चतुर्थ को गिरफ्तार कर दिया और उसके उत्तराधिकारी युवराज फर्डिनेण्ड को गिरफ्तार कर लिया। इसका पश्चात् उसने अपने भाई जोसफ बोनापाट को स्पेन का सभ्यत नियुक्त किया। नेपोलियन के इस कार्य से स्पेनिश जनता में भयकर असंतोष फैला। वहाँ की जनता ने नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।

1808 ई० में स्पेनिश जनता ने खोलोन नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। परिणामस्वरूप जोसफ बोनापाट स्पेन से भाग गया। इस समय इंग्लैण्ड ने आन्तिकारी स्पेनिश जनता की सहायता के लिये आर्चिबिशप वेल्लेजरी के नेतृत्व में एक मना भेजी। इंग्लैण्ड का सेनापति आर्चर वेल्लेजरी जो आगे चलकर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उसने अगस्त, 1808 ई० में बिस्को नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और पुतगाल को फ्रांसीसी अधिपत्य में स्वतन्त्र कराने में सफल हुआ। इसलिये नेपोलियन स्पेन आया और उसने स्पेनिश जनता को कई म्यानों पर युद्धों में बुरी तरह से परास्त किया। इसका पश्चात् उसने अपने भाई जोसफ बोनापाट को पुनः स्पेन का शासक बना दिया। इस समय उसने अग्रेजी सेना से युद्ध करने का निश्चय किया परन्तु आस्ट्रिया द्वारा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने से उसे अपना निश्चय बदलना पड़ा। नेपोलियन स्पेन में सेना का उत्तरदायित्व भागन सार को सौंपकर स्वयं फ्रांस के लिये रवाना हुआ।

फ्रांसीसी सेनापति माशल सार और ब्रिटेन के सेनापति मूर के बीच कोल्ला नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मूर ने माशल सार को बुरी तरह हराया। इन घटनाओं ने स्पेन के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रोत्साहित किया। नेपोलियन ने मेसीना के नेतृत्व में एक विमान सना स्पेन में भेजी। ब्रिटेन के सेनापति आर्चर वेल्लेजरी ने मेसीना को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया परन्तु वह उस स्पेन के बाहर नहीं घुस सका। इस प्रकार नेपोलियन ने स्पेन को हथपकर एक भयकर घण्टी की।

वह मास्को से रवाना हुआ उसके पीछे से रुमिया ने उसकी सेना पर जोरदार आक्रमण किया। नेपोलियन के हजारों सैनिक मर रहे थे और जो बचे हुए थे उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिल रहा था। इस प्रकार नेपोलियन बहुत कठिनाईयों का सामना करता हुआ अपनी विशाल सेना में से केवल 20 हजार सैनिकों का साथ प्राप्त होट सका। इस में नेपोलियन की असफलता न यूरोप के अन्य देशों को पुनः नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रेरित किया।

(5) राष्ट्रों का युद्ध—नेपोलियन की मास्को में असफलता के पश्चात् इंग्लैण्ड प्रशा, रूस और आस्ट्रिया आदि देशों ने नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया। इंग्लैण्ड के सेनापति ड्यूक आफ वेलिंगटन ने स्पेन में प्राप्त की सहायता का युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। इसके पश्चात् वह स्पेन की राजधानी मद्रिड पर अधिकार करने में सफल हुआ। जोसफ को स्पेन छोड़कर भागना पड़ा। उधर अक्टूबर 1813 ई० में नेपोलियन का प्रशिया, आस्ट्रिया और रूस की सेनाओं में लाइपज़िग नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में इन तीनों देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित किया और उसे राइन नदी के इस पार तक घेरे दिया। यह युद्ध चार दिन तक चलता रहा। इस युद्ध को इतिहास में 'राष्ट्रों का युद्ध' का नाम से जाना जाता है। इसके बाद भी इस गुट के सदस्यों ने नेपोलियन का समझौता करने के लिये विवश किया परन्तु नेपोलियन ने समझौता करने से इंकार कर दिया। इस पर प्रशा और रूस की सेनाओं ने पेरिस में प्रवेश किया और नेपोलियन का बंदी बनाकर इटली के पास एल्बा द्वीप में भेज दिया गया।

6 वाटरलू का युद्ध (18 जून 1815)—नेपोलियन को एल्बा द्वीप में भेजने के पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने बूर्वी वंश के लुई अठारहवें को फ्रांस का सम्राट बनाया। इस पश्चात् उन्होंने फ्रांस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। अब मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि यूरोप की प्रादेशिक व्यवस्था के बारे में विचार करने के लिए आस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्रित हुए। वियना में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने यूरोप की प्रादेशिक व्यवस्था के बारे में अनबिणय लिए। इस सम्मेलन की कार्यवाही अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नेपोलियन फरवरी 1815 ई० में एल्बा द्वीप में भागकर फ्रांस पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही सेना और जनता ने उसका साथ दिया। इस पर नेपोलियन ने लुई अठारहवें का शासक पद से हटा दिया और स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। लुई अठारहवाँ फ्रांस में बर्लिन नामक भाग गया।

अब मित्र राष्ट्रों ने वियना कांग्रेस की कार्यवाही का बीच में ही बंद कर नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। अंग्रेज सेनापति वेलिंगटन और प्रशियन सेनापति ब्लूचर ने 18 जून 1815 ई० को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह पराजित किया। नेपोलियन युद्ध का मदान छोड़कर पेरिस पहुँचा।

इस बार जनता ने उसका साथ नहीं दिया। वह अमेरिका भागने का प्रयास कर रहा था कि अंग्रेज सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। इसके पश्चात् उसे बन्दी बनाकर सेन्ट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया। 6 वर्ष तक बन्दी के रूप में जीवन व्यतीत करने के पश्चात् 1821 ई० में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेपोलियन की गिनती आधुनिक सत्तार के महान विजेताओं और रण कुशल सेना नायकों में की जाती है। उसकी मृत्यु के साथ ही फ्रांसीसी जाति का अध्याय भी समाप्त हो गया।

वाटरलू के युद्ध का महत्व— (1) वाटरलू के युद्ध का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस युद्ध में पराजय के पश्चात् नेपोलियन के भाग्य का मितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। उसे अपना शेष जीवन बन्दी के रूप में व्यतीत करना पड़ा और लुई अठारहवें को पुनः फ्रांस का सम्राट बनाया गया।

(2) फ्रांस की राज्य शक्ति निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध हुई थी, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् फ्रांस में लुई अठारहवें को शासक बनाकर फिर से निरंकुश राजतंत्र को स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस युद्ध ने फ्रांस की राज्य शक्ति को असफल बना दिया। इस युद्ध से यह भी स्पष्ट हो गया कि सैनिक अधिनायक के रूप में अधिक समय तक शासन नहीं कर सकता और राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवाद के संघर्ष में किसी विजय होती है।

(3) इस युद्ध ने हमें प्रशासिक आस्ट्रिया और फ्रांस को एकता के मूल में बाध दिया। जो काफी वर्षों तक इस मूल में बर्ध रहे। इन देशों ने वियना कांग्रेस के माध्यम से यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया।

(4) वाटरलू के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने अपनी असाधारण सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। उसने नेपोलियन के दो भाग सैनिकों को इस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड की सैनिक शक्ति की धार यूरोप पर पुनः जम गई।

(5) इस युद्ध में नेपोलियन का पतन हुआ और यूरोप में पुनर्निर्माण का युग प्रारम्भ हुआ। इस दृष्टि से यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है।

नेपोलियन के पतन के कारण नेपोलियन एक सामान्य सैनिक पद से उन्नति करता हुआ फ्रांस का सम्राट बन गया था। जिसने इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप के सभी देशों को युद्ध में पराजित किया। जिस तेजी से नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ उतनी ही तेजी से उसका पतन हुआ। उमट पतन के प्रमुख कारण निम्न लिखित थे—

1 असमीमित महत्वाकांक्षा—नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएँ असमीमित थीं। वह सम्पूर्ण यूरोप पर अधिकार करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अनेक युद्ध लड़े और कुछ सीमा तक उस सफलता भी प्राप्त हुई। परन्तु आगिर वह भी एक मनुष्य ही था। जस-जसे उसकी उम्र चलनी जा रही थी, वस

बसे उमकी काय क्षमता भी कम होती जा रही थी। वह अधिक मोटा तथा विलास प्रिय हो गया था, इसलिए अब उसमें पहले जम स्फूर्ति नहीं रही।

2 अत्यधिक केन्द्रित शासन—नेपोलियन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। शासन की समस्त क्षमियाँ उसके हाथ में केन्द्रित थीं। वह शक्तियों के विकेंद्रीकरण का पक्षपाती नहीं था और न ही साम्राज्य के किसी भी अधिकारी को अधिक अधिकार देना पसंद करता था। नेपोलियन प्रशासन काय में किसी से भी परामश नहीं लेता था। वह नहीं चाहता था कि उसके अलावा अ्य व्यक्ति प्रजा में उम जस लोकप्रियता प्राप्त करे। इसलिए उसका पतन अवश्य म्भावी था।

3 सैनिक दुबलता—सैनिक दुबलता उमके पतन का कारण सिद्ध हुई। उसकी सेना में निम्नलिखित दोष आ गये थे -

(1) नेपोलियन ने अपने असाधारण व्यक्तित्व और सैनिक शक्ति के आधार पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उमका यह साम्राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित था। जब तक नेपोलियन के व्यक्तित्व में प्रतिभा विद्यमान रही तब तक फ्रांस तथा अ्य देश उसकी इच्छा का पालन करत रहे, परंतु जैसे ही उसकी प्रतिभा क्षीण हुई लोगों ने उमका साथ छोड़ दिया। सैनिक शक्ति पर आधारित राज्य उस समय तक शक्तिशाली रहता है जब तक कि शक्ति मौजूद हो। जब ही शक्ति नष्ट हो जाती है साम्राज्य छिन भिन्न हो जाता है। प्रारम्भ में नेपोलियन की सेना के सामने त्रांति के मिद्धान्तों के प्रचार करने का आन्श था। इसलिए वह स्वतंत्रता, समानता और विश्व वधुत्व के लिए लड़ रही थी परंतु जब नेपोलियन ने इन आदर्शों की अवहेलना कर साम्राज्यवादी नीति का पालन किया, तो उसकी सेना में पहले जैसा जोश नहीं रहा।

(ii) प्रारम्भ में नेपोलियन की सेना राष्ट्रीय भावना में ओतप्रोत थी। इसलिए दूसरे देशों की जनता यह चाहती थी कि नेपोलियन सना सहित उनके देश में आकर उनकी निरंकुश शासन में मुक्ति लाय। जब नेपोलियन ने अपनी सेना को दूसरे देशों में रखना प्रारम्भ कर दिया और सेना का व्यय भी उन देशों से वसूल करने लगा तो वहाँ की जनता नेपोलियन के विरुद्ध हो गई।

(iii) प्रारम्भ में नेपोलियन की सेना में राष्ट्रीयता की प्रबल भावनाएँ विद्यमान थीं। जब उसने अपनी सेना में दूसरे देशों के लोगों को भर्ती करना प्रारम्भ कर दिया तो इसका परिणाम यह हुआ कि सेना में राष्ट्रीय भावना का क्षोभ होता गया।

(iv) नेपोलियन का प्रारम्भ म उसके नये अस्त्रा शस्त्रा तथा समर नीति के कारण आश्चर्यजनक सफलतायें मिली । धीरे धीरे अ य श्शान भी उसकी युद्ध प्रणाली को अपना लिया । परिणामस्वरूप उसकी श्रेष्ठता का अत हो गया ।

(v) नेपोलियन ने इतने अधिक युद्ध लडे थे कि उनके अधिकांश अनुभववी जीर योग्य सनिक उन युद्धा म मारे गये थे । वह जिन सनिको के सहारे वाटरलू के युद्ध मे अपन भान्य को आजमा रहा था उनकी आयु 14 या 15 वष से अधिक नही थी । इस प्रकार उसकी सनिक निवलता उसके पतन का प्रमुख कारण सिद्ध हुई ।

4 जन प्रतिनिधित्व को महत्व नहीं देना—नेपोलियन ने शासन व्यवस्था मे जनप्रतिनिधित्व को विशेष महत्व नहीं दिया था । इससे फ्रांस की जनता म भयकर असंतोष विद्यमान था । नेपोलियन ने जनता को केवल सामाजिक समानता ही प्रदान की । लाकमत और स्थानीय स्वशासन के अभाव मे उसके साम्राज्य की जडे खोलली हो चुकी थी । प्रारम्भ म नेपोलियन न योग्य यक्तियों को ही राजकीय पदो पर नियुक्त किया था, परंतु धीरे धीरे उसने यह प्रथा समाप्त कर दी और अपने सम्बन्धियों को राज्य के उच्च पदा पर नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया । फ्रांस की राज्य क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र और सामंतो की शक्ति को समाप्त कर दिया था । परंतु नेपोलियन ने एक नये सिरे से फ्रांस म निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की । इससे जनता मे असंतोष फैलना स्वाभाविक ही था ।

5 इ गलैण्ड की सुदृढ सामुद्रिक शक्ति—इ गलैण्ड की सुदृढ सामुद्रिक शक्ति नेपोलियन के पतन का कारण बनी । नेपोलियन ने यूरोप क सभी देशो को पराजित किया परंतु इ गलैण्ड की सुदृढ सामुद्रिक शक्ति के कारण उसको पराजित करने मे असफल रहा । यही कारण था कि इ गलैण्ड नेपोलियन का लगातार मुकाबला करता रहा । फ्रांस की नौ शक्ति की निवलता के कारण नेपोलियन इ गलैण्ड की सामुद्रिक शक्ति नष्ट नहीं कर सका ।

नेपोलियन कहता था कि यदि छ घण्टे के लिये उसका इ गलैण्ड चनल पर अधिकार हो जाये ता वह इ गलैण्ड म अपनी सेनायें उतार सकता है और उसे युद्ध मे पराजित कर सकता है । यूरोप के देशो को उसने बार बार पराजित किया लेकिन इ गलैण्ड को पराजित करने म असफल रहा इ गलैण्ड निरंतर उसका विरोध करता रहा और उसके शत्रु देश की सहायता करता रहा । अंत म नेपोलियन ने इ गलैण्ड को पराजित करने क लिय महाद्विपीय व्यवस्था को अपनाया । नेपोलियन का यह नीति भी असफल रही । इ गलैण्ड की प्रबल सामुद्रिक शक्ति ने उसकी हर योजना को धूल म मिला दिया । इस प्रकार नेपोलियन का पतन हो गया ।

5 महाद्वीपीय व्यवस्था—महाद्वीपीय व्यवस्था व कारण यूरोप के सभी देशों ने नेपोलियन का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। उसकी इस नीति के कारण कई मित्र देश उसके कट्टर शत्रु बन गये। इस नीति का पालन करने व लिये उसे अनेक युद्ध लड़ने पड़े। इसी के कारण स्पेन और पुतगाल ने नेपोलियन व विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस युद्ध को प्रायद्वीप का युद्ध कहा जाता है। नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति के कारण उसका मित्र देश रूस भी उसका कट्टर शत्रु बन गया।

प्रायद्वीप के युद्धों के कारण नेपोलियन की मनिक शक्ति को बड़ा आघात पहुँचा। नेपोलियन ने कहा था कि स्पेन का युद्ध एक बढ़ते हुए धाव की तरह है, जिसने मुझे छा लिया है। प्रायद्वीप के युद्ध ने इंग्लण्ड को अवसर दिया कि वह नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन और पुतगाल में अपनी सेना भेजे। इंग्लण्ड ने अपनी सेना इन दोनों देशों की सहायता करने के लिये भेजी। उसने नेपोलियन को स्पेन और पुतगाल में असफल कर दिया। इससे उत्साहित होकर रूस ने भी युद्ध किया। वहाँ पर भी नेपोलियन को असफलता मिली। इस प्रकार निरंतर असफलताओं के कारण उसका पतन अवश्यम्भावी हो गया।

6 रूस का अभियान—नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर एक भयंकर गलती की थी। इस युद्ध में उसकी सेना नष्ट हो गई थी। नेपोलियन 6 लाख सैनिकों में से केवल 20 हजार सैनिक बचाकर फ्रांस ले गया था। पाँच लाख अस्सी हजार सैनिक भूख, सर्दियों के और रूसी सेना के पीछे से अचानक आक्रमण करने के कारण मारे जा चुके थे। रूस में नेपोलियन की असफलता ने यूरोपियन देशों के इस सदेह को दूर कर दिया कि नेपोलियन अजेय है। इससे पश्चात् नेपोलियन यूरोप में फिर अपनी सैनिक शक्ति की छाक नहीं जमा सका।

7 पोप से झगड़ा—पोप ने नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली को लागू करने में इंकार कर दिया इस पर नेपोलियन ने पोप का राज्य छीन लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। पोप ने उस चर्च में बहिष्कृत कर दिया। इस पर नेपोलियन ने पोप को बंदी बनाकर जेल के सीखचों में बंद कर दिया। नेपोलियन के इस काम से सम्पूर्ण यूरोप की कथोलिक जनता उसके विरुद्ध हो गई। इस बहुसंख्यक जनता ने सशक्त के समय नेपोलियन को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। इस प्रकार नेपोलियन का पोप से झगड़ा आगे चलकर उसके पतन का कारण सिद्ध हुआ।

उपरोक्त सभी कारणों से नेपोलियन अपने साम्राज्य से हाथ धो बैठा उसने 6 वर्ष तक एक निर्वासित बंदी के रूप में सेंट हेलेना में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। मार्शल फोच ने लिखा है कि “नेपोलियन इन बातों को भूल गया कि मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता। वह भूल गया कि राष्ट्र ध्यक्ति से तथा चार्तिक

नियम मानवता से उच्च है। वह भूल गया कि युद्ध ही गर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, क्याकि शांति युद्ध से वही अधिक उच्च है।”

नेपोलियन का स्थान—नेपोलियन जम व्यक्ति विश्व के इतिहास में बहुत कम हुए हैं। उसने 20 वर्ष तक यूरोपियन देशों के साथ अनेक युद्ध लड़े और उनमें अपनी असाधारण सैनिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्थल युद्धों में उमने सामने किसी भी देश की सेना का टिकना मुश्किल था। उसने आस्ट्रिया प्रशा और रूस आदि देशों की सेनाओं को कई बार युद्धों में परास्त किया। वह एक बहादुर सेनापति होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उसमें साहस कूट कूट कर भरा हुआ होने के कारण कठिनाइयों का सामना करने से वह हिचकता नहीं था। नेपोलियन के शब्दकोष में ‘असम्भव’ शब्द के लिए कोई स्थान नहीं था। वह घोर परिश्रम करने में समर्थ था। मेकनेल बनस ने लिखा है कि यह दुर्भाग्य है कि नेपोलियन की अधिकांश सैनिक सफलताओं को दी जाती है एक राजनीतिज्ञ के रूप में उसके काम बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे।¹

फ्रांसीसी राज्य प्राप्ति की अमूल्य देन नेपोलियन बोनापार्ट था। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रखर मानसिक बुद्धि, रणकौशल तथा शासक कला आदि गुण कुलीन वर्ग के अलावा साधारण वर्ग के व्यक्ति में भी हो सकते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस और यूरोप को महत्वपूर्ण देन दी है। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और पेरिस को यूरोपीय राजनीति का केन्द्र बना दिया। पेरिस को एक सुन्दर और आकर्षक नगर बना दिया। जो अपनी समृद्धि तथा सौंदर्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध हो गया। उसने फ्रांस की जनता को धार्मिक उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान की। फ्रांसीसी जनता को सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान की और प्रान्ति के द्वारा भूमि व्यवस्था में जो भी परिवर्तन हुए थे, उसको उसने बनाए रखा।

नेपोलियन महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। यद्यपि उसने फ्रांस में पुनः निरंकुश राजतंत्र कायम कर दिया था लेकिन उसने जनहित के लिये अनेक कार्य किये। उसने फ्रांसीसी जनता को सुखी समृद्ध बनाने के लिये अनेक सुधार किये। सरकारी पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया। फ्रांस में सुव्यवस्थित शासन की स्थापना नेपोलियन की सबसे बड़ी देन थी।

नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किये। उसने पेरिस के विश्वविद्यालय को यूरोप का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना दिया और विधि संहिता के द्वारा सम्पूर्ण फ्रांस में एक जसी कानूनी व्यवस्था स्थापित की। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन ने फ्रांस को अमूल्य देन दी।

फ्रांस ही नहीं अपितु सारा ससार नेपोलियन का ऋणी है। नेपोलियन ने फ्रांस के अग्रदूत का काम किया। उसने यूरोपियन दशा में फ्रांस के सिद्धांतों का प्रचार किया और यूरोपियन देशों ने इन सिद्धांतों का प्रचार ससार के अन्य देशों में किया। नेपोलियन पहला व्यक्ति था, जिसने आधुनिक स्वेज नहर के निर्माण की योजना बनाई थी। मिश्र की प्राचीन सभ्यता की छोज नेपोलियन ने की थी।

नेपोलियन यूरोप में जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने फ्रांस के स्वतंत्रता समानता और विश्व में धुलक के सिद्धांतों का प्रसार किया। विजित क्षेत्रों में उसने निरंकुश शासन व्यवस्था एवं दाम प्रथा एवं सामन्तवाद को समाप्त किया और वहाँ की जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसने यूरोपियन देशों में सामाजिक समानता एवं जनतांत्रिक विशारधारा का प्रचार किया। नेपोलियन के शत्रु देशों ने भी उसकी इस नवीन पद्यति को अपनाया प्रारम्भ कर दिया।

नेपोलियन की सबसे महत्वपूर्ण दम राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना था। इस भावना का उसने जो तरह से विकास किया। पोलण्ड जैसे देश में उसने जान बूझकर राष्ट्रीयता की भावना को उभारा। स्पेन और जर्मनी में उसने निरंकुश शासन की स्थापना कर वहाँ की जनता में राष्ट्रीयता की भावनाएँ जाग्रत की। जर्मनी और इटली में उसने अग्रदूत रूप में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसीलिए नेपोलियन को आधुनिक राष्ट्रीयता का निमाता कहा जाता है।

प्रस्तावित सन्दर्भ पाठ्य पुस्तकें

- 1 प्लेट जीन और ड्रमट-विश्व का इतिहास
- 2 एलिस और जोन-ससार का इतिहास
- 3 वल्स, एच० जी०-दी आउट लाइन आफ हिस्ट्री
- 4 मेयाइन-ए हिस्ट्री आफ वल्ड सिवलीजेशन
- 5 मनवेल्स वनस-वैस्टन सिवलीजेशन

औद्योगिक क्रान्ति

औद्योगिक क्रान्ति एक आकस्मिक घटना नहीं है। इस घटना का सूत्रपात अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही चुका था। धीरे-धीरे यह क्रान्ति विक्रम के माग पर चलती रही। प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि औद्योगिक क्रान्ति एक आकस्मिक घटना नहीं है अपितु यह क्रान्ति आज से कई वर्षों पहले प्रारम्भ हो चुकी थी। इसके पश्चात् ही यह शान-शान विकास माग पर चल रही है। इस क्रान्ति ने अपना उग्र रूप उन्नीसवीं शताब्दी में धारण किया परन्तु आज भी यह क्रान्ति चल रही है और विश्व के देशों को प्रभावित कर रही है। सामान्यतः इस क्रान्ति का कायकाल 1770 ई० से 1870 ई० तक का माना जाता है।

क्रान्ति से पूर्व यूरोप की स्थिति

औद्योगिक क्रान्ति आरम्भ होने से पूर्व यूरोप के देशों में सामन्तवादी शासन व्यवस्था विद्यमान थी। भूमि पर सामन्तों का अधिकार था। वे कृषकों को खेती करने के लिए भूमि देते थे और उनसे अपनी इच्छानुसार कर वसूल करते थे। सामन्तों का जपन किमानो तथा दासों पर पूरा अधिकार था। कृषक एवं दास अपने स्वामी की सेवा करते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। सामन्त किसानों से बेगार भी लेते थे। बिना सामन्तों की इजाजत के किसान दूसरी जगह जाकर नहीं बस सकता था।

क्रान्ति से पूर्व गृह उद्योग घरों का काफी विकास हो चुका था। ये मनुष्य की आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। बरोजगारी की समस्या नहीं थी। जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होने के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे थे जिससे वस्तुएँ काफी महंगी होती जा रही थी। उत्पादन आवश्यकता से कम हो रहा था। जीवन स्तर के उन्नत होने के कारण मनुष्य की आवश्यकताओं में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी। शिक्षा के विकास से मनुष्य का मस्तिष्क वैज्ञानिक बनता जा रहा था। यूरोपियन देशों में साम्राज्यवाद के क्षेत्र में होड़ लगी हुई थी। यूरोपियन देश अपने-अपने उपनिवेशों में वास्तुओं का निर्यात करते थे। उपनिवेशों में सामान

औद्योगिक क्रांति

भेजने के लिये एक उत्पादन के साधना में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहे थे। इस समय मध्यम वग व्यापार को विवक्षित करना चाहता था। इस वक के लोग के पास काफी धन सम्पत्ति थी। इसलिए इस समय यवनाय के क्षेत्र में गिल्ड पद्धति का प्रचलन हुआ। और व्यापार पर गिल्ड्स (सभा का नियन्त्रण था। प्रत्येक उद्योग का अलग अलग गिल्ड होता था और उस गध के सदस्यों को ही उग धन को करने की इजाजत दी जाती थी।

प्रत्येक व्यक्ति को आठ दस वष तक बिसी दश कारीगर के पास रह कर औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करनी पडती थी। उसे अपने गिदाव के गाघ वाम करना पडता था। समेप में यक्तियां को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी। यूरोपियन देशों के उपनिवेश दूर दूर स्थित थे। उनको वहा मामान भेजने में काफी कठिनाई का सामना करना पडता था। इसलिये यूरोपियन देश यातायात के साधनों का विकास करना चाहते थे। इससे स्पष्ट है कि उम समय की परिस्थितियों में औद्योगिक क्रांति को अनिवाय बना दिया।

पास की राज्य क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य क्रांति से पूव फ्रांस यूरोप में व्यापार का केन्द्र बना हुआ था। क्रांति के समय नेपालियन की अदूरदर्शिता का कारण फ्रांस में उद्योग घघे चौपट हो गये। राज्य क्रांति का फ्रांस के पड़ोसी देशों पर भी गहरा प्रभाव पडा और उनके उद्योग घघे भी चौपट हो गये। किंतु इस क्रांति के कारण डगनलण्ड को अपने उद्योग घघों के विकास करने का एक अच्छा अवसर हाय लगा। इसलिए औद्योगिक क्रांति का फ्रांस सबसे प्रथम इगलण्ड में हुआ। इस समय इगलैण्ड में कृषि क्रांति हुई व उसके उपनिवशों का विस्तार हुआ और व्यापार का भी विकास हुआ।

औद्योगिक क्रांति का अर्थ—
भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने औद्योगिक क्रांति की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ दी हैं। एलिस और जीन ने औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताते हुए लिखा है कि "औद्योगिक क्रांति क्या थी? यह हाय से काम लेने के बजाय मशीन से काम लेने का परिवर्तन था। यह धरेलू प्रणाली से यानी घर में बैठकर चीज बनाने से फैक्ट्री प्रणाली का परिवर्तन भी था।"

डा० बी०पी० सक्सेना ने लिखा है कि उत्पादन के साधना में परिवर्तन की ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। सी० डी० हेजन ने लिखा है कि यह उद्योगों की प्रेषणा कारखानों में उत्पादन करने की पद्धति को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। एच जी वेल्स ने लिखा है कि 'सामाजिक आर्थिक विकास को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। वैसे आम तौर पर यांत्रिक क्रांति को इतिहासकार औद्योगिक क्रांति

मान लेते हैं कि तु रोना म अन्तर है। प्राचीन रोमन गणराज्य का प्रभाव पुनः सजीव हुआ और मजदूरों का समूह बड़ी बड़ा जमीरों मुफ्त कृषि और पूँजी की उपलब्धि ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया।¹ मैकनल बनस न लिखा है कि 'औद्योगिक क्रांति केवल व्यापार का उत्पादन विकास ही नहीं था बल्कि उत्पादन के क्षेत्र में भी आशा से अधिक प्रगति थी। यह क्रांति उद्योग और मशीनीकरण उद्योग में शक्ति के प्रयोग से कारखानों को 'यावसायिक तरीके' के निर्माण से एक सनसनी पदा करने वाले मातायात के माध्यमों के विकास से सफल हुई थी। प्लेट जीन और ड्रमंड न लिखा है कि अनेक पूँजीपतियों ने बहुत बढ़िया मान बनाने के लिए जिसमें कि उन्हें अधिक ध्यान मिले। अत्यन्त कठोर परिश्रम किया। नयी मशीनायत करने के लिये निरन्तर सतक रहें। जो नये औद्योगिक संगठन इस युग में बने। उनसे व्यापार और पूँजी का विकास हुआ वही औद्योगिक क्रांति है।² डार्ल्यू एन बीच न लिखा है कि मनुष्य की लालच और भौतिकवादी भ्रूल को शांत कर सके, मशीनों की सहायता से उत्पादन बढ़ा सके और मशीनों को राजगार दे सकें वही व्यापारिक क्रांति है। औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार के अमूल परिवर्तन लाने वाली यह औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास में अपना अलग महत्त्व रखती है।³ प्रोफसर डविस ने लिखा है कि औद्योगिक क्रांति का मतलब उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह सम्भव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के पुराने उपायों को छोड़कर बड़ी मात्रा में कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एक अन्य इतिहासकार ने इस क्रांति की परिभाषा निम्न प्रकार दी है 'उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हो जाने का नाम औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति परिवर्तन की उस स्थिति का द्योतक है जिसकी वजह से प्राचीन काल के सीमित गृह उद्योगों की अपेक्षा वाष्प या विद्युत् यंत्रों की सहायता से कारखानों में बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है।'

सन्धिप में हम औद्योगिक क्रांति की परिभाषा निम्न प्रकार से दे सकते हैं। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हो जाने को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब गृह उद्योगों की अपेक्षा वाष्प या विद्युत् यंत्रों की सहायता से कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा। किसानों ने घेती का काम छोड़कर कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। इससे सामाजिक जीवन और प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इन सभी परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति के नाम से

- 1 वेल्स एच जी—दी आउट लाइन आफ हिस्ट्री पृष्ठ 955
- 2 मैकनल बनस—वेस्टन सिविलीजेशन—पृष्ठ 570
- 3 प्लेट जीन और ड्रमंड—विश्व का इतिहास पृष्ठ 498
- 4 बीच डार्ल्यू एन—हिस्ट्री आफ नी वल्ड पृष्ठ 717

जाना जाता है। इस क्रांति में श्रम का लाभ श्रमिकों को नहीं अपितु पूँजी लगाने वाले बड़े पूँजीपतियों को ही मिला।

औद्योगिक क्रांति का प्रारम्भ हुई और इसका विकास काल क्या रहा। इस प्रश्न पर विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किये हैं। किन्तु अधिकांश इतिहासकारों ने इस क्रांति का विकास काल 1770 ई० से 1870 ई० तक माना है। औद्योगिक क्रांति का कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह काफी समय से चली आ रही थी और आज भी यह क्रांति शन शन चल रही है। यूरोप में सबसे पहले यह क्रांति इंग्लैंड में प्रारम्भ हुई। इसका पश्चत् अर्थ यूरोपियन देशों में इसका प्रसार हुआ। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई? प्रश्न यह पड़ा होता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों प्रारम्भ हुई? क्या देशों में क्या नहीं हुई। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1 भौगोलिक स्थिति

इंग्लैंड के चारों ओर पानी होने के कारण इस पर बाहरी आक्रमण नहीं हो सके। नेपालियन भी इंग्लैंड पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड बिना किसी बाधा के अपना आन्तरिक विकास करता रहा जबकि यूरोप के देश युद्धों में अस्तित्व के कारण अपना आन्तरिक विकास नहीं कर सके। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके पास बहुत अच्छे बन्दरगाह थे और वह सत्सत् के प्रमुख 'वाणिज्य' मार्गों पर बसा हुआ था।

2 इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति—इंग्लैंड उस समय विश्व की सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक शक्ति था। इस शक्ति के सहारे ही वह 'वाणिज्य' करता था। नेपालियन फ्रांस की दुबला सामुद्रिक शक्ति के कारण ही इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं कर सका। इंग्लैंड की सरकार व्यापार को प्रोत्साहन दे रही थी। यहां के 'वाणिज्यियों' का यह विश्वास था कि उनकी सरकार उनके व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा कर सकेगी। इसलिए यहां औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ और इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता बन गया।

3 प्राकृतिक साधन

इंग्लैंड प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न देश था। यहां पर लाहा, कोयला तथा जल शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। इसलिये उद्योगों का विकास बहुत शीघ्रता से हुआ।

4 पूँजी

इंग्लैंड में पूँजी का अभाव नहीं था। कृषि क्रांति में यहां के व्यापारियों ने काफी धन अर्जित किया था। इंग्लैंड में बैंक की स्थापना से व्यापार में काफी सुविधा हो गई थी। इसलिए इंग्लैंड के धनी लोग बड़े-बड़े कारखाने स्थापित करने के पक्ष में थे।

5 मजदूरों का उपलब्ध होना

इंग्लैण्ड म मजदूर प्राप्ति की कोई समस्या नहीं थी। यहाँ की जनसंख्या म तीव्र गति से वृद्धि हानी जा रही थी। अठारहवीं शताब्दी तक इंग्लैण्ड की जनसंख्या दुगुनी हो गई थी। जनसंख्या म वृद्धि हान क कारण इंग्लैण्ड म मजदूर आसानी स उपलब्ध हो जात थे। इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड म हुई कृषि प्राप्ति के कारण गाव क बहुत से किसान बेरोजगार हो गये। अत वे रोजगार की तलाश मे शहरो म भटकने लगे। ये बेरोजगार लोग फक्ट्री म काम करने को तयार थे। इसलिये इंग्लैण्ड के उद्योगपतिया क सामन मजदूर प्राप्ति की कोई समस्या नहीं थी।

6 इंग्लैण्ड की औपनिवेशिक नीति

इंग्लैण्ड न साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करती थी। वह अपने उपनिवेशो स कच्चा माल मगवाता था और वहाँ पर अपने तयार माल को बेचता था। अपने उपनिवेशो की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इंग्लैण्ड ने उत्पादन म वृद्धि करना प्रारम्भ किया। जिसके फलस्वरूप उसका उत्पादन निरन्तर बढ़ता ही गया।

(7) राजनीतिक दशा—सोलहवीं शताब्दी म इंग्लैण्ड के व्यापारिया न व्यापार का विकास करके काफी धन सम्पत्ति अर्जित करली थी। इंग्लैण्ड की राजनीतिक दशा यूरोप क अन्य देशो से बहुत अच्छी थी। वहाँ शांति और सुयवस्था विद्यमान थी। यहाँ पर इस समय न तो आन्तरिक विद्रोह हो रहा था और न ही किसी देश का बाहरी आक्रमण। इसलिये यहाँ का व्यापार, दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा। नेपोलियन ने यूरोप के सभी देशो से युद्ध लडे। उस समय फ्रांस के अलावा सभी यूरोपियन देश इंग्लैण्ड से युद्ध सामग्री का आयात करते थे। फलस्वरूप इंग्लैण्ड सम्पूर्ण यूरोप का कारखाना बन गया। इससे इंग्लैण्ड के उद्योग धंधे तीव्र गति से विकसित हुए।

(8) आर्थिक स्वतंत्रता का सूत्रपात—अठारहवीं शताब्दी के अंत मे इंग्लैण्ड म एक भयंकर महामारी फली जिसे "बाली मृत्यु" कहा जाता है। इस महामारी के कारण वहाँ लाखो लोग मारे गये। इसके कारण इंग्लैण्ड मे किसानो और मजदूरों का अभाव हो गया। इसलिये भू स्वामियो ने किसानो के साथ उदारता का व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया। फिर भी, हजारो किसानो ने गाँवो को छोड़ दिया और रोजी की तलाश म शहरो म इधर-उधर भटकने लगे। इसस नगरो मे मजदूरों की प्राप्ति की कोई समस्या नहीं रही, क्योंकि भारी संख्या मे बेरोजगार व्यक्ति रोजगार की तलाश म इधर उधर भटक रहे थे। इन बेरोजगार व्यक्तियों ने अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार उद्योग धंधा म काम करना प्रारम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप शहरो म, उद्योग पर गिल्ड पद्धति का नियंत्रण ढीला हो गया। इसका लाभ उठाकर नये प्रशिक्षित कारीगरों ने अपने स्वतंत्र उद्योग स्थापित

करने प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार इंग्लण्ड में आर्थिक स्वतन्त्रता का प्रादुर्भाव हुआ। जिसके कारण वहाँ औद्योगिक विकास सम्भव हो सका।

औद्योगिक क्रान्ति के कारण—

औद्योगिक क्रान्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(1) राजनीतिक स्थिति— फ्रांस की राज्य क्रान्ति ने यूरोप की राजनीतिक स्थिति में काफी परिवर्तन कर दिया था। एक तरफ सत्राट साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए अपने उपनिवेशों में वृद्धि कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ यूरोपियन जनता अधिकारों की प्राप्ति के लिये सघन कर रही थी। इस समय राजाओं के लिये यह आवश्यक हो गया कि वे जशात जनता पर नियन्त्रण स्थापित करा व लिये विकास की ओर ध्यान दे। व्यापार में विनास, श्रमिकों को रोजगार देकर जनता को यस्त, सुखी एवं समृद्ध बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार राजाओं ने जनता को सन्तुष्ट करने के लिये उपनिवेशों पर सफल शासन चलाने और अन्य देशों से प्रगति में आगे बढ़ने के लिये प्रयास करने प्रारम्भ कर दिए। इससे यूरोप में औद्योगिक विकास को बलवा मिला।

इस समय इंग्लण्ड, फ्रांस, हालण्ड और स्पेन जादि देशों में विशाल औपनिवेशिक साम्राज्यों की स्थापना का। दूर दूर स्थित उपनिवेशों पर सफल रूप से शासन मचालने के लिये यह आवश्यक था कि यातायात के साधनों का विकास किया जाए। इसके अतिरिक्त जनता पर नियन्त्रण बनाय रखने के लिये भी यातायात के साधनों का विकास किया गया। इस कारण यूरोप में बणिमानी ने जलपोत का आविष्कार किया। इस प्रकार गणतन्त्र और साम्राज्यवाद की मिश्रित भावना ने औद्योगिक क्रान्ति को अवश्यम्भावी बना दिया।

(2) फ्रांस की राज्य क्रान्ति का योगदान— फ्रांस की राज्य क्रान्ति ने औद्योगिक क्रान्ति के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। क्रान्ति के पश्चात् नेपोलियन ने सम्पूर्ण यूरोप का युद्ध में उलझाएँ रखा। इस उलझन को इंग्लण्ड ने सुलझाया। इंग्लण्ड ने अपने समयक देशों की सैनिक सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके लिये उसे उत्पादन में वृद्धि करने के लिये नये तरीकों की खोज करनी पड़ी।

नेपोलियन ने इंग्लण्ड के व्यापार का नष्ट करने के लिये बर्लिन की आज्ञा और मिलान की आज्ञा की घोषणा की। इसके अनुसार उसने अपने अधीन राज्यों को यह आदेश दिया कि वे इंग्लण्ड से सामान नहीं मँगवायेंगे। इससे यूरोप के राज्यों में इंग्लण्ड का माल जाना बन्द हो गया। इसका फलस्वरूप इंग्लण्ड ने यूरोपियन देशों में अपना माल बेचने के लिये व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। इससे उगता औद्योगिक विकास हुआ।

युद्ध समाप्ति के पश्चात् इंग्लैण्ड में बेरोजगारी की समस्या उठ खड़ी हुई। इस समस्या का समाधान करने के लिये उद्योग धंधों का विकास किया गया। जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। अब अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिये और बच्चे माल की प्राप्ति के लिये नये नये उपनिवेश स्थापित किये गये। इस प्रकार उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नए आविष्कार किये गए।

(3) व्यापार का विकास—इस समय व्यापार का क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा था। साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ व्यापार का क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा था। इंग्लैण्ड और फ्रांस ने साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। इन उपनिवेशों में इंग्लैण्ड और फ्रांस न स्पान-स्थान पर अपनी व्यापारिक कम्पनियों की स्थापना की और इन देशों से व्यापार प्रारम्भ कर दिया। ये शक्तिशाली यूरोपियन देश अपने उपनिवेशों से सस्ती दरों पर कच्चा माल मँगवाते थे और वहाँ पर दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएँ मँहगी दरों पर बेचते थे। इस व्यवसाय के कारण व्यापारिक वर्ग धनी बनता जा रहा था। उपनिवेशों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण वस्तुओं की माँग में ताल गति से वृद्धि हो रही थी। इस बढ़ती हुई माँग की पूर्ति करने के लिये उत्पादन में वृद्धि करने के लिये नवीन तकनीक साधनों का आश्रय लिया। फलस्वरूप अनेक नये यंत्रों का आविष्कार हुआ। इस प्रकार निरंतर व्यापार का विकास ने औद्योगिक क्रांति को अनिवार्य बना दिया।

(4) शिक्षा का प्रसार—मध्य कालीन यूरोप में शिक्षा पर धर्म का नियंत्रण था और शिक्षा धर्म पर आधारित थी। लेकिन पुनजागरण के कारण यूरोप में शिक्षा का तीव्र गति में विकास हुआ। इस समय वैज्ञानिक खोजें प्रारम्भ हुईं। छापाखाने के आविष्कार के कारण शिक्षा का प्रचार और तीव्र गति से होने लगा। छापाखाने के कारण पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं। समाचार पत्र निकलने लगे। इन समाचार पत्रों के माध्यम से यूरॉपियों को दूर-दूर के देशों का स्थिति एवं दूसरे देशों के निवासियों के बारे में पता लगने लगा। समाचार पत्रों का लाभ उठाकर यूरोपियन देशों ने पिछड़े हुए राज्यों में अपने औपनिवेशिक राज्यों की स्थापना की। इस प्रकार शिक्षा के विकास के कारण विज्ञान में प्रगति की। विज्ञान की प्रगति के कारण नये नये आविष्कारों ने विश्व को एक बनाने का प्रयास किया तथा सुगम साधन उपलब्ध कराये। इस प्रकार शिक्षा के विकास ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग दर्शन किया।

(5) कोयले की उपलब्धि—कोयले की उपलब्धि के अभाव में लोहा, लकड़ी की भट्टियाँ पर गलाया जाता था। इसलिये अच्छी भट्टीयों का निर्माण करना सम्भव नहीं था। लकड़ी की भट्टियों पर लोहा गलाने का काम बहुत धीमी गति से होता था। इसमें समय बहुत अधिक लगता था। जब पत्थर का कोयला पर्याप्त

मात्रा में उपन्यास होने लग गया तो लोहे को पत्थर व कोयले की भट्टियाँ पर गलाया जाता था। जिसमें बहुत कम समय लगता था। इसलिये अब बड़ी-बड़ी मशीनों का निर्माण किया जान लगा। इन मशीनों के प्रसार से औद्योगिक क्रान्ति को महान सहयोग मिला।

(6) जनसङ्ख्या में वृद्धि—जनसङ्ख्या में वृद्धि ने भी औद्योगिक क्रान्ति को अनिवार्य कर दिया। जैसे जैसे यूरोप की जनसङ्ख्या में वृद्धि होती गई वेम-वस जीवीकोपाजन की समस्या भी बढ़ती गई। उस समय यह सम्भव नहीं था कि कृषि व द्वारा सभी को राजी रोटी दी जा सके। इसलिये लोगों ने उद्योग घरों के विकास की ओर ध्यान दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जनसङ्ख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण दैनिक जीवन की वस्तुओं की माग भी तीव्र गति से बढ़ रही थी। इस बढ़ती हुई माग की पूर्ति करने के लिये औद्योगिक विकास करना आवश्यक था। इसलिये उद्योग घरों का तीव्र गति से विकास प्रारम्भ हुआ।

(7) जीवनस्तर में वृद्धि—जैसे जैसे मनुष्य को सुविधाएँ प्राप्त होती गई, वैसे वैसे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती गई। इससे आवश्यकताएँ बढ़ी और बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया। अब भोग विलास की अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। अधिकांश लोग अपने रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करने के लिये अत्यधिक मात्रा में धन और विलास की वस्तुएँ खरीदने लगे। धीरे धीरे भोग विलास की वस्तुओं की माग बढ़ती गई। इस बढ़ती हुई माग के कारण औद्योगिक विकास भी होता गया।

(8) राष्ट्रीयता की भावना—राष्ट्रीयता की भावना ने औद्योगिक क्रान्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय प्रत्येक देश के निवासी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। वे यही चाहते थे कि उनका देश उन्नति करे एवं साम्राज्य का विस्तार हो। परन्तु इन सब के लिये उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक था। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुई। इस लड़ाई में वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता था, जो अधिक उत्पादन करने में समर्थ था। इंग्लैंड ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी सफलता का मुख्य कारण यह था कि वह अधिक उत्पादन करने में समर्थ था।

(9) साम्राज्यवादी भावनाओं का विकास—यूरोप में धीरे धीरे साम्राज्यवादी भावनाएँ विकसित होती जा रही थी। अब यूरोपियन देशों ने साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए एशिया, अफ्रीका और अमेरिका आदि देशों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों से यूरोपियन देश कच्चा माल मँगवाते थे और अपना माल इन उपनिवेशों में बेचते थे। अब यूरोपियन देशों को कच्चा माल उपनिवेशों से पर्याप्त मात्रा में मिल जाना था। उन्हें अपना माल बेचने के लिये बाजारों

की तलाश करने की चिन्ता नहीं थी क्योंकि वे अपने उपनिवेशों में अपना माल बेच देते थे। इसलिये अब यूरोपियन देश विज्ञान पगाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने लगे और उसे अपने उपनिवेशों में बचाने लगे।

(10) **वैज्ञानिक आविष्कार**—18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मशीनें बहुत कम थीं। ये मशीनें घाड़े या बला द्वारा चलाने जाती थीं। इसमें काम बहुत धीमी गति से होता था लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक आविष्कार करते गये। यूरोपवासियों ने पूर्वी देशों से बुतुबनुमा और बारूद का प्रयोग करना सीखा। हमने वे दूर-दूर के देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर सकते थे। इन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण यातायात व साधनों के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। इंग्लैण्ड में वस्त्र उद्योग व क्षेत्र में फ्लाईंग शटल और स्पिनिंग जनी का आविष्कार हुआ। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी अनेक आविष्कार हुए। जिसके कारण कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए 1769 ई० में जेम्सवाट ने भाप से चलाने वाले इंजिन का आविष्कार किया। बारूद से डायनामा का निर्माण किया गया। इन सब के कारण औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिसने औद्योगिक क्षेत्र की राया ही पलट दी। सबाइन ने लिखा है कि यह विज्ञान ही था जिसने औद्योगिक क्रांति को संभव बना दिया।¹ प्लेट जीन और डेमड ने लिखा है कि शक्ति चार्जित मशीनों द्वारा किये गए इन भारी परिवर्तनों को कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति कहा जाता है।

औद्योगिक क्रांति का विकास अधिनाश इतिहासकारों ने औद्योगिक क्रांति का काल 1770 ई० में 1870 ई० तक माना है। इतिहासकार हेज ने भी इसी मत का समर्थन किया है। 1770 ई० से 1830 ई० तक के काल में कुछ विशिष्ट बातों से ही क्रांति का चिह्न प्रदर्शित किये परन्तु 1830 ई० से लेकर 1870 ई० तक के समय में इस क्रांति में जाश्चरजनक प्रगति थी। प्रसिद्ध इतिहासकार हेज ने लिखा है कि 1870 ई० के पश्चात् उसको क्रांति की मजा नहीं दी जा सकती क्योंकि 1830 ई० से 1870 ई० तक जो प्रभाव इसके विश्व पर पड़े थे। वे 1870 ई० के पश्चात् नहीं पड़े।

यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में प्रारम्भ हुई। इसके पश्चात् यूरोप के अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ। 1870 ई० के पश्चात् सम्पूर्ण विश्व पर इस क्रांति का प्रभाव स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। औद्योगिक क्रांति का विकास निम्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है—

(1) **कृषि के क्षेत्र में विकास**—औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैण्ड में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अठारहवीं शताब्दी से पूर्व इंग्लैण्ड के

1—सेबाइन—ए हिस्ट्री आफ बल्ड सिवलीजेशन पृष्ठ 479

2—प्लेट जीन और डेमड—विश्व का इतिहास पृष्ठ 475

अधिकांश व्यक्ति कृषि का काम करते थे। कृषि करने के लिये वे प्राचीन साधनों का सहारा लेते थे। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वाह्न में वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिये नये-नये वैज्ञानिक साधनों की खोज की, ताकि कम कीमत पर अधिक अन्न पैदा किया जा सके।

सबप्रथम जैय रोटल (1674-1740 ई०) ने कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों की खोज की। उसने यह मत व्यक्त किया कि बार-बार भूमि जोतने के बाद बीज बोने में अधिक उपज होती है। उसने एक बीज व पत्र (बोने का यंत्र) का आविष्कार किया। जिसके द्वारा समान रूप से बीज बोये जा सकते थे। किसानों ने इस यंत्र से खेतों में बीज बोना प्रारम्भ किया। इससे किसानों का समय भी बचा और हाथ से बीज बोने के काम से भी उनको मुक्ति मिली। रोटल ने दूसरा सुझाव यह दिया कि कृषक (पट्टेला) यंत्र के द्वारा किसानों को अपनी भूमि को नरम बनाना चाहिये। यह यंत्र घोड़ों की सहायता से चलाया जाता था।

टाउन शौल्ड (1674-1738) ई० ने यह सुझाव दिया कि यदि खेत में बार-बार फसल बदल-बदल कर बोई जाय तो इससे उपज अधिक होती है। फसलों की अदला-बदली से भूमि की उर्वरता बनी रहती है। जस्टस वीन लीविंग ने भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया। इससे पहले भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए खाद्य का ही प्रयोग किया जाता था।

राबर्ट बैकवेल (1725-1795) ने जानवरों की नस्ल सुधारने के तरीके की खोज की। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड में 1800 ई० तक भेड़ों की संख्या तिगुनी और गाय, बैल आदि की संख्या पहले से दुगुनी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने 1793 ई० में एक कृषि बोर्ड स्थापित किया। आयर यंग (1740-1820) ने अनेक शोध लेख लिखे। उनके माध्यम से उसने कृषि को उन्नत बनाने का प्रयास किया।

अमेरिका में भी कृषि के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण यंत्रों का निर्माण किया। 1834 ई० में साइरस मैककौमिक ने फसल काट नामक मशीन का आविष्कार किया। इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। धीरे-धीरे इस्पात से बने हुए औजारों को घेनी के काम में लिया जाने लगा। इसके पश्चात् हत्तों को वाष्प चालित मशीनों से चलाया जाने लगा। इस समय बहुत से देशों में कृषि विभाग, कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान शालाओं की स्थापना की गई। इनमें कृषि के क्षेत्र में नई-नई खोजें हुईं। जिससे कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।

2. वस्त्र उद्योग में क्रांति

औद्योगिक क्रांति का सबप्रथम प्रभाव वस्त्र उद्योग में दृष्टिगोचर होता है। दिनो-दिन सूती वस्त्र की मांग बढ़ने लगी। इस समय सूती वस्त्र की मांग इतनी बढ़ गई थी कि पुराने ढंग के चर्खे उस मांग को पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिये

इस क्षेत्र में नये नये आविष्कार हुए ।

सब प्रथम जान के न 1733 ई० में प्लाइवुड शटल (उड़ान डरकी) का आविष्कार किया । यह मशीन एक आदमी के द्वारा चलाई जाती थी । इससे कपड़ा तीव्र गति से बुना जाने लगा । इस मशीन के द्वारा काने हुए सूत की मांग निरंतर बढ़ने लगी । 1748 ई० में वाल तथा वाट ने रोलर स्पिनिंग नामक मशीन का आविष्कार किया । इससे सूत अच्छा व बढ़िया काता जाता था । इन दोनों मशीनों से सूत पर्याप्त मात्रा में काता जाने लगा । इससे कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई । जेम्स हार्वीज ने 1764 ई० में स्पिनिंग जनी का आविष्कार किया । यह एक ऐसा चरखा था जिसमें एक पहिये को घुमाने से आठ तक हुए धूमते थे । इससे वस्त्र उद्योग में क्षेत्र में काफी उन्नति हुई, परंतु इन मशीनों को हाथ से चलाना पड़ता था ।

1769 ई० में जॉस्टन निवामी रिचर्ड आकराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया । यह एक ऐसा चरखा था जो हाथ की जगह जल शक्ति से चलाया जाता था । 1779 ई० में सेमुअल वाटसन ने म्यूल नामक यंत्र का आविष्कार किया । उसने यह यंत्र जनी और वाटर फ्रेम को मिलाकर बनाया था । यह मशीन अच्छा सूत कानने लगी और साथ ही साथ उस कपड़े में भी परिणित करने लगी । इस मशीन के द्वारा बढ़िया, घारीय और सस्ता कपड़ा बुना जाता था । इसमें लगभग 200 सूत कातने वाली मशीनों के बराबर शक्ति थी ।

1785 ई० में एडमण्ड काट राइट ने पावर लूम (शक्ति संचालित करघा) का आविष्कार किया । पावरलूम को जल और भाप दोनों शक्तियों से चलाया जा सकता था । इस मशीन में बारीक और सुन्दर कपड़ा बुना जाता था । इसमें एक बानक दस कारीगरों का काम करता था । परिणामस्वरूप इंग्लैंड के अनेक जुलाहे इस आविष्कार का विरोध करते हुए देश को छोड़ कर चले गये थे । इन आविष्कारों के कारण रूई की कमी पड़ने लगी । इस कमी का पूरी करने के प्रयास प्रारम्भ किये गये । परिणामस्वरूप एक अमरीकी शिक्षक एनीविलेन ने 1793 ई० में काटन जीन का आविष्कार किया । यह मशीन रूई घाटने का काम करती थी । इस आविष्कार के कारण रूई उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए । यह मशीन 50 कारीगरों का काम कर देती थी । इससे रूई की खेती को प्रोत्साहन मिला ।

इस प्रकार इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की । इस प्रगति के आधार पर ही वह सौ वर्षों तक सम्पूर्ण यूरोप का औद्योगिक केन्द्र बना रहा ।

3 लोहा और धातु शक्ति

वस्त्र उद्योग की भांति लोहा और धातु शक्ति के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक विकास हुआ । क्रांति के पूर्व लोहा लकड़ी और कोयले में गलाया जाता था । 1750 ई० में इंग्लैंड में पत्थर का कोयला उपलब्ध हो गया । इसलिए अब लोहा

पत्थर के कोयलो म गलाया जान लगा । इन कोयला की भट्टी से लोहा सरती दरो पर उपलब्ध हान लगा । परिणामस्वरूप लोहे के जोजार और बारखाना का निर्माण होने लगा । पत्थर के कोयले न ईंधन की समस्या का समाधान कर दिया ।

हेनरी वाटन न लोह को पिपलाकर नई मशीन बनाने की विधि का आविष्कार किया । अब लोहे के स्थान पर इस्पात की मशीना का निर्माण होने लगा । शुरू म इस्पात बहुत महंगा था किन्तु 1856 ई० म हनरी वैसलमर न फौलाद बनान की एक सस्ती और अच्छी विधि का आविष्कार किया । इसने इतना अधिक इस्पात बनने लगा कि इतिहासकारा न 19वीं शताब्दी का मशीन और इस्पात युग के नाम से पुकारा । इससे विशाल पैमान पर मशीना का निर्माण किया जान लगा । मशीना की वृद्धि से उद्योग धंधा का काफी विकास हुआ ।

इंग्लैण्ड म 1760 ई० से लोह युग प्रारम्भ हुआ । 1817 ई० म इंग्लैण्ड ने लोह के प्रथम पुल का निर्माण किया । इससे पश्चात् इंग्लैण्ड यूरोप मे लोह के व्यापार का केन्द्र बन गया । कोयले की उपलब्धि के पश्चात् बैनानिका ने उसकी सहायता से वाष्प शक्ति का आविष्कार किया । 1769 ई० म स्काटलैण्ड निवासी जेम्सवाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया । 1814 ई० म जाज स्टीफनसन न रल के इंजन (लौको मोटिव इंजन) का आविष्कार किया । यह इंजन वाष्प शक्ति की सहायता से चलता था । आग चलकर इसी इंजन को पानी के जहाजो म लगा दिया गया । जिससे आने जान म सुविधा हो गई और जल यात्रा म समय कम लगता था । 1811 ई० मे छापेखाने म वाष्प शक्ति का प्रयोग किया गया । धीरे धीरे पानी के जहाज भी लोह क बनने लग । इस प्रकार वाष्प शक्ति न औद्योगिक श्रान्ति के विकास को एक नई दिशा की प्रार अग्रसर किया ।

4 परिवहन तथा संचार

औद्योगिक श्रान्ति के कारण परिवहन तथा संचार साधनो के क्षेत्र म भी आवश्यकजनक विवास हुआ ।

(1) सड़के

अब कच्ची सड़को के स्थान पर मिट्टी और पत्थर से समतल पक्की सड़का का निर्माण किया जान लगा । बाद म तारकाल का भी प्रयोग किया जान लगा । उस समय सड़का के निर्माण म मैकएडम, टेलफोड ब्रिडजे, और रैनी जैसे विशेषज्ञो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया । इससे सड़को के निर्माण को प्रोत्साहन मिला और इंग्लैण्ड म सड़का मील लम्बी सड़का का निर्माण किया गया ।

(ii) नहरें

इस समय हजारों मील लम्बी नहर बनने लगी । इंग्लैण्ड म सबसे प्रथम प्रथम नहर का निर्माण ड्यूक आफ ब्रिजवाटर नामन व्यक्ति ने किया । ब्रह्मपट्टी नहर 1761 ई० म बामली से मैनचस्टर तक बनवाई गई थी । इस नहर का निर्माण के

पश्चात् इंग्लण्ड में 1830 ई० तक 4 हजार मील लम्बी नहरों का निर्माण करवाया गया। फ्रांस में भी 1830 ई० तक 7500 मील लम्बी नहरों का निर्माण हो चुका था। 1869 ई० फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड लेसेसेस ने स्वयं नहर का निर्माण करवाया। यह नहर भूमध्यसागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण के पश्चात् यूरोप और भारत के बीच भाग की एक तिहाई दूरी कम हो गई है। अमेरिका के न्यूयार्क शहर में 1810 ई० से 1837 ई० तक बहुत अधिक नहरों का निर्माण करवाया गया। इन नहरों का उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ा।

(iii) यातायात के साधनों का विकास

1812 ई० में पहला जलपोत पानी में उतरा जिसका नाम कामेट था। वाष्प नौकाओं के निर्माण से यात्रा में समय की बचत होने लगी। 1807 ई० में अमेरिकी राबर्ट फुल्टन ने सर्वप्रथम एक जहाज या नौका का निर्माण किया जो वाष्प शक्ति से चलता था। इंग्लैण्ड में जेम्सवाट ने भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। यह इंजन लोहे की पटरियों पर चलता था। इससे रेल की पटरियों का निर्माण होने लगा। 1822 ई० में जाज स्टीफेन्सन ने लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया। तीन साल बाद पहली सवारी गाड़ी 15 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चली। 1830 ई० में जाज स्टीफेन्सन ने 'राकेट इंजन' का आविष्कार किया। यह इंजन माल से भरे डिब्बों को लेकर 19 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चला। जाज स्टीफेन्सन की 1848 ई० में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से पहले इंग्लैण्ड में 6000 मील लम्बी रेलवे लाइन का निर्माण हो चुका था। जाज स्टीफेन्सन निरक्षर था। 1838 ई० में सीरियस और ग्रेट वेस्टन ने स्टीमर का पहला जहाज बनाया, जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया। मोटर के आविष्कारों के कारण यातायात के साधनों के क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन हुये परन्तु वायुयान के आविष्कार ने स्थानों की दूरियों को ओर कम कर दिया।

(iv) संचार के साधनों का विकास

यातायात के साधनों के साथ साथ संचार के साधनों के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक विकास हुआ। रोलेण्ड हिल ने आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव रखी। 1874 ई० में अंतर्राष्ट्रीय डाक संधि की स्थापना हुई। इस डाक संधि के माध्यम से एक देश के पत्र मनीआर्डर समाचार पत्र और पासल आदि दूसरे देश में आने जाने लगे। 1844 ई० में सेमुअल मास ने तार यंत्र की खोज की। इस तार यंत्र के द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से भेजा जा सकता था। इससे कुछ ही समय में सारे संसार में तारों का जाल बिछा दिया गया। 1851 ई० में इंग्लिश चैनल में तार बिछा दिया गया। 1866 ई० में एटलांटिक सागर में तार बिछा दिया गया। इससे विश्व के देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। इस तार यंत्र के कारण व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। 1876 ई० में ग्राहम बेल

ने टेलीफोन का आविष्कार कर संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया।

5 प्रकाश के क्षेत्र में विकास

हाम्फ्री डेवी ने 1815 ई० में सेप्टी लम्प की खोज की। इसी आधार पर डेवी ने 1821 ई० में बिजली का आविष्कार किया। इसके पश्चात् 1879 ई० में एडिसन ने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया।

6 औद्योगिक नीति

औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक नीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। क्रांति से पूर्व व्यापार पर सरकार का एकाधिकार था लेकिन क्रांति के पश्चात् उद्योगों के विकास के कारण एक नये वर्ग का विकास हुआ। जो पूँजीपति वर्ग कहलाया। इस वर्ग ने सरकार से व्यापार पर से सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। पूँजीपति वर्ग ने सरकार से यह आग्रह किया कि वह व्यापार में हस्तक्षेप न करें। इस प्रकार एक नई नीति का विकास हुआ जिसे 'अहस्तक्षेप की नीति' अथवा 'उत्तुक्त व्यापार की नीति' कहा जाता है। उस समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का उस समय बहुत ख्याति मिली। इसमें उसने नये आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसकी पुस्तक को पढ़कर जनता बहुत प्रभावित हुई। इस प्रकार उस समय कई देशों ने स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति हुई।

औद्योगिक क्रांति के कारण नये नये सामुद्रिक मार्गों की खोज हुई। नई-नई व्यापारिक तथा बीमा कंपनियों का स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के कारण अलग अलग क्षेत्रों में आश्चर्यजनक विकास हुआ। इस क्रांति के द्वारा आधुनिक समाज की नींव रखी गई।

औद्योगिक क्रांति का प्रसार— इंग्लैंड ने 40 वर्षों में आश्चर्यजनक विकास किया। वहाँ पर वस्तुएँ अब हाथ के स्थान पर मशीनों से बनाई जाने लगीं। कोयला और लोहा की उपलब्धि के कारण विशाल पैमाने पर मशीनों का निर्माण हुआ। इन मशीनों को वाष्प शक्ति की सहायता से चलाया जाता था। इससे सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। रेल, तार और जहाज के आविष्कार ने समय और दूरी को कम कर दिया। छापेखाने के आविष्कार के कारण शिक्षा का विकास और ज्ञान का प्रचार हुआ। अगले 40 वर्षों में यह क्रांति सम्पूर्ण यूरोप में फैल गई। प्रारम्भ में इंग्लैंड की सरकार ने मशीनों को बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगा रखा था परन्तु 1825 ई० में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। परिणाम स्वरूप 1830 ई० से 1870 ई० के बीच पश्चिमी यूरोप का मशीनीकरण हो गया।

इ गलण्ड के पश्चिम फ्रांस वेल्जियम और जर्मनी आदि देशों में भी औद्योगिक क्रांति हुई। वेल्जियम ने अपना औद्योगिक विकास करते हुए सबसे पहले यूरोप में रेल का प्रयोग प्रारम्भ किया। कुछ ही समय में वेल्जियम यूरोप का व्यापारिक केंद्र बन गया। फ्रांस में नेपोलियन और लुई फिलिप के प्रयासों से औद्योगिक विकास हुआ। फ्रांस में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण विशाल पैमाने पर मशीनों का निर्माण होने लगा। 1842 ई० से फ्रांस में रेलवे लाइन विद्यमान प्रारम्भ हुई। जर्मनी में भी औद्योगिक विकास हुआ और वहाँ 1839 ई० में ड्रेसडन से लिपज़िग तक पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इस प्रकार जर्मनी में भी औद्योगिक क्रांति हुई। इसके पश्चात् अमेरिका और एशिया में जापान तथा भारत में भी इस क्रांति का प्रसार हुआ। हमारे देश में तो यह क्रांति आज तक चल रही है। इस क्रांति से जापान ने इतना अधिक व्यापारिक और औद्योगिक विकास कर लिया कि उसकी गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक देशों में की जाती है।

औद्योगिक क्रांति के परिणाम—औद्योगिक क्रांति के प्रमुख परिणाम निम्न लिखित हुए —

1. सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव —

(1) **नये समाज का अन्वय—**औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप समाज में प्रचलित रीति रिवाजों रहन सहन का स्तर खान पान, धार्मिक विश्वास, विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने समाज की काया ही पलट दी और अब एक नये समाज का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक समाज की नींव रखी। इस क्रांति के कारण भारत जसा देश भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। हमारे देश में बहुजातिय एवं अस्पृश्यता के क्षेत्र में भी इस क्रांति के कारण बहुत सुधार हुआ है।

(ii) **मानव जीवन की सुख-सुविधा में वृद्धि—**औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन की सुख सुविधा में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज तक भटक-ऐश्वर्य आराम और विलासिता पूर्ण वस्तुओं की मांग में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। बढ़िया कपड़ा, सुगन्धित तेल, पाऊडर, अच्छा फर्नीचर, यातायात के आरामदायक साधन और मनोरंजन के साधन आदि का निर्माण औद्योगिक क्रांति के कारण सम्भव हुआ है। अब इनकी मांग में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अमीर-व्यक्तियों ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये वभव और ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारम्भ किया। इसका जन साधारण पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और उसमें भी जीवन स्तर में वृद्धि करने की भावनाएँ जाग्रत हुईं।

(iii) **मानव समाज का नतिक पतन—**औद्योगिक क्रांति का बुरा प्रभाव यह पटा कि इससे समाज का नतिक पतन प्रारम्भ हो गया। इस क्रांति के कारण संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई और उसके स्थान पर स्वतन्त्र छोटे छोटे परि

बारा का विकास आया। इन छोटे छोटे परिवारों में प्रेम भिन्न पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित होता था। परिणामस्वरूप पारस्परिक प्रेम का स्रोत सूखने लग गया। अब नारी का भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसे भी पुरुषों के समान अधिकार मिले। अब नारी पुरुष पर आश्रित नहीं रही। इस प्रकार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त हुआ। उस समय मजदूर कारखानों में 14 घंटे काम करते थे। इससे पश्चात् वे सायकाल बुरी तरह म थक जाते थे। उस समय पता चल गया कि साधन नहीं होने के कारण मजदूर अपनी थकान को दूर करने के लिये शराब पीते थे और जुआ खेलते थे। इतना ही नहीं वे अपने मनोरंजन के लिये दशयात्रा के पास भी जाते थे। इसी प्रकार कारखाना में काम करने वाली स्त्रियाँ भी चरित्र में गिर जाती थीं। इससे समाज का नैतिक पतन शुरू हो गया।

(iv) मध्यम वर्ग का विकास—इस क्रांति के परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग का तर्जो से विकास हुआ। औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक था कि कारखानों की स्थापना की जाय और इनकी स्थापना के लिये पूँजी तथा व्यावसायिक बुद्धि की आवश्यकता थी। मध्ययुगीन सामंतों के पास पूँजी तो बहुत अधिक थी परंतु उच्च व्यावसायिक बुद्धि का अभाव था। इसके अतिरिक्त वे व्यवसाय को निम्न श्रेणी का काम समझते थे। इसलिये उनकी व्यवसाय के प्रति कोई रुचि नहीं थी। मध्यम वर्ग के पास पूँजी और व्यावसायिक बुद्धि दोनों ही थीं। उनकी व्यवसाय के क्षेत्र में भी काफी रुचि थी। इसलिये उन्होंने अपनी पूँजी से अनेक नये कारखानों की स्थापना की। इससे औद्योगिक विकास भी हुआ और मध्यम वर्ग के लिए दिन प्रतिदिन धनवान् होते चल गये। कुछ ही समय में मध्यम वर्ग का आर्थिक स्थिति पर प्रभाव स्थापित हो गया और वे शहरी समाज के नेता बन गये।

(v) श्रमिकों की शोचनीय दशा—औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा बहुत शोचनीय हो गई। उस समय यंत्रियाँ या कारखानों में काम तो मिल गया परंतु उन्हें श्रम की तुलना में मजदूरी कम दी जाती थी। उन्हें कारखानों में 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था। कारखानों में काम करते हुए यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती थी। उस समय मजदूरों के जीवन की कोई सुरक्षा नहीं थी। स्त्रियाँ और बच्चे भी कारखानों में काम करते थे।

कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को नगर के गंदे मकानों में जानवरों की भाँति रहना पड़ता था। यदि किसी कारणवश कारखाना बन्द हो जाता तो उसमें काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो जाते थे। श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। दुष्टनाग्रस्त श्रमिकों के लिये मिल भाँतिव की तरफ से चिकित्सा भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय श्रमिकों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। उनमें आपसी एकता नहीं थी, क्योंकि उनमें अधिकांश

श्रमिक गांव व भोले भाले विमान थे, जो पहली बार रोमी रोटी की तलाश में शहर में जीवन व्यतीत कर रहे थे।

2 आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव—

(iii) आवश्यक वस्तुओं का सस्ता होना—त्राति से पूर्व आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन गृह उद्योग घघों के द्वारा किया जाता था। ये वस्तुएँ बहुत महंगी होती थी क्योंकि उत्पादन सीमित और कम मात्रा में होता था। जमे-जस जनसंख्या में वृद्धि होती गई वस-वस वस्तुओं की मांग बढ़ती गई। गृह उद्योग घघे इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने में असमर्थ थे। औद्योगिक त्राति के कारण कारखानों में विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा। कारखाना में उत्पादित वस्तुएँ गृह उद्योग घघा द्वारा निर्मित वस्तुओं से सस्ती होती थी। परिणामस्वरूप दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएँ सस्ती मिलने लगी।

(ii) जीवन स्तर में वृद्धि—औद्योगिक त्राति के परिणामस्वरूप मानव जीवन के स्तर में वृद्धि हुई। इस त्राति में ऐसी-ऐसी वस्तुओं का निर्माण हुआ जिन्होंने मानव जीवन के स्वरूप में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। आज यातायात के सुगम साधन उपलब्ध हैं जस मोटर रेल और वायुयान आदि न दुनिया के देशों की दूरी को कम कर दिया है। हम टेलीफोन से दूर-दूर के व्यक्तियों से आसानी से बात कर सकते हैं। आज हर रोग के विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध है। मानव के जीवन स्तर के उन्नत होने का एक प्रमाण यह भी है कि आज मृत्यु दर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है।

(iii) पूँजीवाद का उदय—औद्योगिक त्राति के फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व पूँजीवाद और साम्यवाद दो गुणों में विभाजित हो गया है। कारखानों के स्वामी मजदूरों का शोषण कर पूँजी एकत्रित कर रहे। ज्यों-ज्यों कारखानों का उत्पादन में वृद्धि हुई त्यों-त्यों मिल मालिकों की पूँजी में भी वृद्धि होने लगी। इस त्राति से पूर्व पूँजीपति वर्ग का समाज में नामोनिशान भी नहीं था परंतु आज यह वर्ग समाज में सबसे अधिक प्रभावशाली वर्ग है।

(iv) वर्ग संघर्ष का जन्म—औद्योगिक त्राति के परिणामस्वरूप समाज में नई समस्या वर्ग संघर्ष का प्रादुर्भाव हुआ। इस औद्योगिक त्राति ने मानव समाज को उद्योग के क्षेत्र में दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। एक वर्ग में कारखाना के मालिक आते हैं जबकि दूसरे वर्ग में खून पसीना बहाकर उत्पादन करने वाले मजदूर आते हैं। पूँजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण कर अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, जबकि आज का संगठित मजदूर वर्ग शोषित नहीं होना चाहता और अपने अधिकारों की मांग करता है। दोनों ही वर्ग अपने-अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास में व्यस्त है। यह संघर्ष दिन प्रतिदिन प्रबल होता जा रहा है।

(v) नवोन औद्योगिक नगरों का प्रादुर्भाव—औद्योगिक प्रगति के परिणाम स्वरूप कई नये औद्योगिक नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। कृषि प्रगति के कारण बहुत से किसान रोजी रोटी की तलाश में शहरों में आ गये। इससे गावों की जनसंख्या में कमी हुई और औद्योगिक केंद्रों की आबादी में वृद्धि हुई क्योंकि गावों में आये हुए किसान औद्योगिक केंद्रों के आसपास अपने-अपने मकान बनाकर रहने लगे। इनके अतिरिक्त कई छोटे-मोटे व्यापारियों ने भी रोजी रोटी की तलाश में वही जाकर बसना प्रारम्भ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक नगरों की आबादी में वृद्धि हुई और उनके आसपास कई नये नगरों का विकास संभव हो सका। इस प्रगति के कारण नीवरपूल, लकाशायर और मैनचेस्टर आदि नगर इंग्लैण्ड के प्रमुख औद्योगिक नगर बन गये।

(vi) गृह उद्योग धंधों की समाप्ति—औद्योगिक प्रगति के परिणामस्वरूप गृह उद्योग धंधे पतन की ओर अग्रसर होने लगे। प्रगति में पूर्व दैनिक जीवन की वस्तुओं का उत्पादन इन गृह उद्योग धंधों के द्वारा किया जाता था। इन गृह उद्योग धंधों में मनुष्य काम करते थे। इनके द्वारा निर्मित वस्तुएँ सीमित व कम मात्रा में होती थीं और बाजार में बहुत महंगी मिलती थीं। प्रगति के पश्चात् इन वस्तुओं का कारखानों में विशाल पैमाने पर उत्पादन होना लगा। कारखानों में उत्पादित वस्तुएँ घरेलू उद्योगों में निर्मित वस्तुओं से सस्ती व सुन्दर होती थीं। परिणामस्वरूप जनसाधारण ने मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदना प्रारम्भ कर दिया। इसका विनाशकारी प्रभाव घरेलू उद्योग धंधों पर पड़ा। ये घरेलू उद्योग धंधे पतन की ओर अग्रसर होने लगे।

(vii) बेरोजगारी की समस्या—औद्योगिक प्रगति के कारण एक ओर जहाँ रोजगार की आवश्यकता, वहाँ दूसरी ओर हजारों लोग बेरोजगार हो गये। यदि एक कारखाना हजार मजदूरों को रोजगार देता है तो लाखों का रोजगार छीन लेता है। एक मशीन कई व्यक्तियों का काम कर सकती है। इस प्रकार यदि मशीन में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो कई व्यक्ति बेरोजगार भी हो जाते हैं। मशीनीकरण के कारण गृह उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गये। इसका अनिश्चित मजदूरों की संख्या अधिक होने से उन्हें मजदूरी भी कम दी जाने लगी।

(viii) बाजार पर नियंत्रण—औद्योगिक प्रगति के कारण विकसित देश अपने राष्ट्र के उत्पादन की महत्व देने के लिए राष्ट्रीय बाजार पर नियंत्रण रखने लगे। प्रत्येक विकसित देश यही चाहता था कि उसकी जनता दूसरे देशों की अपेक्षा अपने देश में बनी हुई वस्तुएँ ही खरीदे। इसलिये विकसित देशों ने दूसरे राष्ट्रों में बनी हुई वस्तुओं पर भारी शुल्क कर लगा दिया, ताकि वे स्वदेशी वस्तुओं के मुकाबले में काफी मजंगी बिके। इसका परिणाम यह हुआ कि विकसित देशों को

जनता न दूररे राष्ट्र की वस्तुएँ जो महंगी होती थी उनके स्थान पर स्वदेश में बनी हुई वस्तुएँ खरीदना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु जत्र उत्पादित मान की अपने देश में खपाना असम्भव हो गया तो नये बाजारों की खोज प्रारम्भ हुई। उपनिवेशों के साथ व्यापारिक नियमों को भी बँटोर बना लिया गया।

(1x) देशों का एक दूसरे पर निर्भर होना—औद्योगिक विकास के कारण सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हो गये। त्राति से पूरा प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था। उस समय यातायात के माध्यम इतने विकसित नहीं थे कि दूर-दूर के देशों में सामान आसानी से पहुँचाया जा सके। त्राति के पश्चात् यातायात एवं संचार साधनों में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। जिससे सत्तार के सभी बाजारों को एक दूसरे से जोड़ दिया। आज यदि यूयाक में चांदी का भाव बढ़ता है तो भारत में भी इसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक देश बच्चे मान के नियम पिछड़े देशों पर निर्भर हो गये जबकि पिछड़े देश मशीनों तथा तयार माल के लिये औद्योगिक देशों पर निर्भर हो गये। इस प्रकार सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हो गये।

3 राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव—

(1) मध्यम वर्ग का प्रशासन में हस्तक्षेप—त्राति से पूरा सामंत धनवान और राजवंश के लोग ही प्रशासन में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे परन्तु त्राति के परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग ने काफी उन्नति कर ली थी। शिक्षा और धन की दृष्टि से यह वर्ग बुलीन वर्ग के व्यक्तियों से काफी आगे निकल चुका था। परन्तु इसको किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस वर्ग से राज्य का काफी आय प्राप्त होती थी। इसने बुलीन वर्ग के समान अधिकार प्राप्त करने के लिये प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इतना ही नहीं इस वर्ग के व्यक्ति प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग के व्यक्ति चुनावों में चुने जाने लगे। 1832 ई० में मध्यम वर्ग के व्यक्ति प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करने में सफल हुए। उदारवादी दल की सरकार ने प्रथम सुधार बिल पास किया। जो व्यक्ति मजदूरों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन देता था और उनकी मांगों को पूरी करवाने का वायदा करता था मजदूर वर्ग उसी व्यक्ति को अपना मत देते थे। इस प्रकार वह व्यक्ति चुनाव में विजय प्राप्त करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि मजदूर और आम जनता न प्रशासन में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। इतना ही नहीं चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति मतदाताओं को प्रसन्न करने का भी प्रयास करने लगे।

(2) साम्राज्यवाद की प्रोत्साहन—औद्योगिक त्राति के फलस्वरूप कारखानों में विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इसलिये यूरोपियन देश अपने

माल को बचने के लिये एवं कच्चे माल को प्राप्त करने के लिये नये बाजारों की खोज करने लगे। यूरोपियन देशों ने उपनिवेश बनाने शुरू किये और इस प्रवृत्ति ने साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहन दिया। परिणामस्वरूप यूरोपियन देशों में अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ प्रारम्भ हुई। प्रत्येक देश इस होड़ में आगे निकल जाना चाहता था।

इंग्लण्ड इस औपनिवेशिक होड़ में सबसे आगे निकल गया। उसने एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की। इंग्लण्ड के अतिरिक्त फ्रांस, रूस, हालण्ड, स्पेन, बेल्जियम और पुर्तगाल आदि देशों ने अपने-अपने उपनिवेश स्थापित किये। इस औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में एक देश के दूसरे देश के साथ सम्बन्ध बटु हो गया। परिणामस्वरूप उपनिवेशों के प्रश्न को लेकर, चीन, भारत, ईरान, मिस्र, अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपियन देशों के अनेक युद्ध हुए।

इस औपनिवेशिक होड़ में कुछ देश बहुत आगे निकल गये थे, जबकि कुछ बहुत पीछे रह गये थे। जैसे इंग्लण्ड, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल आदि देशों के पास बहुत उपनिवेश थे जबकि जर्मनी और इटली आदि देशों के पास एक भी उपनिवेश नहीं था। इसलिये जर्मनी और इटली भी इंग्लण्ड और फ्रांस की भाँति विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अतः जर्मनी और इटली में विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य वाले देशों के प्रति मनमुटाव की भावना थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा की चिन्ता लगी हुई थी। इस समय यूरोपियन देशों ने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिये अपने विरोधी देशों के विरुद्ध अपने-अपने मित्र देशों से सैनिक सन्धिग्रहण कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण सप्तराज्य, दो परस्पर विरोधी युद्धों में विभाजित हो गया। जिसके फलस्वरूप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े गये।

(111) सरकार द्वारा मजदूरों की दशा में सुधार—क्रान्ति के प्रारम्भ में मजदूरों की दशा बहुत शोचनीय थी। उन्हें कारखानों में चौदह घंटे तक काम करना पड़ता था। मजदूरों के मुँहवाले में उन्हें कम वेतन दिया जाता था। इसलिये श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिये सघन करना प्रारम्भ किया। रोबर्ट ओवन ने सबसे प्रथम मजदूरों की दशा में सुधार करने की माँग की। अतः में सरकार ने मजदूरों की दशा में सुधार करने के लिये समय-समय पर विभिन्न कानून बनाये।

1802 ई० में सरकार ने एक कानून पास किया। जिसके अनुसार निम्न एव अनाथ बच्चा से एक सप्ताह में 62 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता था। 1809 ई० के कानून द्वारा नौ बघ के बच्चे से बारह घण्टा प्रतिदिन काम करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 1822 ई० में एक और कानून पास किया गया। जिसके द्वारा बालकों के काम करने के घण्टे और कम कर दिये गये। अब

स्त्रियों के कोयले की खानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त कारखानों के मजदूरों के प्रतिदिन काम करने के आठ घंटे निश्चित किये गये।

मजदूरों को रहने के लिये कारखानों के पास स्वच्छ मकान दिये गये। उनके बच्चा की शिक्षा के लिए कारखानों के समीप ही स्कूल खोले गये। इतना ही नहीं मित्र मालिकों द्वारा उनकी बस्ती में ही उनके इलाज के लिए अस्पताल खोले गये। अब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन की सुरक्षा के लिये सरकार ने कानून बनाये। सरकार ने उन्हें उचित वेतन और बोनस दिलाने की भी व्यवस्था की। यदि मजदूर हड़ताल करें तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती थी। इस प्रकार सरकार ने फक्ट्री नियमों के द्वारा हड़ताल का अवध घोषित कर दिया।

सरकार के द्वारा बनाये गये कानूनों से मजदूरों में जाग्रति पैदा हुई। उनमें आत्मबल भी बढ़ा। अब मजदूरों ने अपने अधिकारों की मांग के लिये ट्रेड यूनियनों का संगठन किया। यह संघ मजदूरों के अधिकारों के लिये संघर्ष करता रहा है। इंग्लण्ड ने 1771 ई० में और फ्रांस में 1884 ई० में अपनी-अपनी देश में मजदूर संघों को मान्यता प्रदान कर दी। इसके पश्चात् एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ नामक संस्था का गठन किया गया। 1830 ई० में मजदूरों की जिस प्रकार उपेक्षा की जाती थी वह अब सम्भव नहीं रही। मजदूरों को राजनतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये कुछ समय और इंतजार करना पड़ा।

(14) समाजवाद—औद्योगिक क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन समाजवाद है। मजदूरों की दशा सुधारने के लिये जो आंदोलन प्रारम्भ हुआ। उससे जागे चलकर समाजवाद विकसित हुआ। समाजवाद का अर्थ है समाज में आर्थिक और राजनीतिक समानता की स्थापना करना। राबर्ट ओबन (1771-1858) ने सबसे पहले मजदूरों की दशा में सुधार करने के लिये मांग की। उसके प्रयासों के फलस्वरूप मजदूरों को उचित वेतन, आमोद प्रमोद और रहने सहने की सुविधाएँ प्राप्त हुईं।

इसके बाद काल मानव को यह श्रेय दिया जा सकता है कि उसने समाजवादी विचारधारा को अमर बना दिया। काल मार्क्स ने श्रमिकों में अपने समाजवादी विचारों का प्रसार किया। मार्क्स का यह कहना था कि सत्ता पर किसान और मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए और शक्ति उन्हीं के हाथ में निहित होनी चाहिए। जब राज्य की शक्ति जनता के हाथ में रहेगी और भूमि तथा पूँजी पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा एवं सभी व्यक्ति काम करेंगे तो स्वयं एक वग बिहीन समाज की स्थापना हो जायेगी। जिसमें कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकेगा। मार्क्स का यह मानना था कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक

अधिकार होना चाहिये। इस प्रकार औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न कठिनाइयां ने समाजवाद का जन्म दिया।

प्रस्तावित सभ्य पाठ्य पुस्तकें —

- 1 सेवान्—ए हिस्ट्री आफ वर्ल्ड सिवलीजेशन
- 2 टायनबी—ए स्टडी आफ हिस्ट्री
- 3 मैकनल बनस—वेस्टन सिवलीजेशन
- 4 डेविस—वर्ल्ड हिस्ट्री
- 5 प्लट, जॉन और ड्रमंड—विश्व का इतिहास
- 6 वेल्स, एच० जी०—दी वाउट लाइन आफ हिस्ट्री
- 7 एलिस और जॉन—संसार का इतिहास
- 8 वीच, डब्ल्यू० एन०—हिस्ट्री आफ दी वर्ल्ड

राष्ट्रवाद जर्मनी और इटली का एकीकरण

उन्नीसवीं शताब्दी राष्ट्रियता के विकास की शताब्दी मानी जाती है। इस शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रियता की भावना का तीव्र गति से विकास हुआ। राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को ही 'राष्ट्रवाद' अथवा 'राष्ट्रियता' कहा जाता है। जिस देश के मनुष्यों में राष्ट्रियता की भावना विद्यमान होती है उस देश के मनुष्य अपने देश को सत्कार का सयश्रेष्ठ देश मानते हैं और उसके विकास के लिये हृदय से प्रयास करते हैं। उस देश के व्यक्ति सब से ये कहते हैं कि मैं इस देश का निवासी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने देश की रक्षा करना अपना धर्म समझने है और उत्पत्ति के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। जब किसी देश के मनुष्यों में ऐसी भावनाएँ पैदा हो जाती हैं तो उसका यह अर्थ निकाला जाता है कि उस देश के मनुष्यों में राष्ट्रियता की भावना विद्यमान है।

जोसफ ने लिखा है कि "राष्ट्रवाद" व्यक्तिगत मनुष्य तथा मानव समाज रूपी श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली बन्दी है। 'प्लेट, जीन और डूमण्ड ने लिखा है कि अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को गीत करना राष्ट्रवाद या राष्ट्रियता कहलाती है। राष्ट्रियता, व्यक्तियों को एक-एक समूह के साथ आत्मीयता की एक भावना प्रदान करती है जिसमें उन सबके आदर्श परम्पराएँ और संस्कृति समाप्त होती है।¹ मकनल वनस ने लिखा है कि 'स्वदेश की प्रगति या जाग्रति के विचारों को ही राष्ट्रियता कहते हैं। कुछ लोग एक जाति, एक भाषा, एक धर्म या एक ही संस्कृति के तत्वों के सम्बन्ध को राष्ट्रियता कहते हैं। आरम्भ में यह विचार पवित्र और अच्छा था क्योंकि देश की आजादी के लिये लड़ाई होती थी। किन्तु धीरे-धीरे इसमें बुराई बढ़ती गई और राष्ट्रियता की अभिव्यक्ति, दूसरों पर प्रभुत्व जमाना, सैनिकवाद और राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा मात्र रह गई।"²

1 प्लेट जीन और डूमण्ड—विश्व का इतिहास—पृष्ठ 435

2 मकनल वनस—वस्टन सिविलीजेशन—पृष्ठ 612

इस प्रकार राष्ट्रीयता वह एक भावना है जिसमें मनुष्य अपने देश के हितों को सर्वोपरि ममता है और आवश्यक होने पर रक्षा तथा विकास के लिये अपने हितों का बलिदान कर देता है। कुछ जय इतिहासकार एक जाति, एक धर्म, एक भाषा और एक देश को राष्ट्रीयता का आवश्यक गुण मानते हैं। उन्होंने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है "राष्ट्रीयता उस अर्थ का श्रावक है जिसके अनुकूल एक जाति, एक भाषा एक देश सस्कृति, एक ही प्रकार के रहन महन और परम्परा का पालन करने वाले सभी लोगों का इस प्रकार का संगठन हो, कि शासन व दृष्टिकोण में उनकी इकाई बन जायें।"

अधिकांश विद्वान राष्ट्रीयता के लिये एक जाति, एक भाषा एक धर्म और एक देश को आवश्यक मानते हैं लेकिन प्रत्येक देश के लिये यह बात लागू नहीं होती है। जैसे कि भारत में विभिन्न जातियाँ व विभिन्न धर्म मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं, फिर भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना विद्यमान है। इसलिये राष्ट्रीयता का अर्थ राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना और अपने राष्ट्र-हित के लिये अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान कर देना है।

इतिहासकारों का यह मानना है कि राष्ट्रीयता फ्रांस की राज्य प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण घटना है। आस्ट्रिया और प्रशा ने जब फ्रांस पर आक्रमण किया तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये इस भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता के कारण साम्राज्यवाद का उदय हुआ। जब साम्राज्यवाद ने उग्र राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लिया तो विनाशकारी युद्ध लड़े गए। फ्रांस की राज्य प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता, गरिबी और राष्ट्रीयता के सिद्धांतों का बहुत अधिक प्रचार हुआ। जोसेफ ने लिखा है कि 'फ्रांस की प्राप्ति में लोगों में जनतन्त्रात्मक, राष्ट्रवाद, मातृभूमि शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीयता, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय विद्वानों के प्रति अपूर्व प्रेम हिलारों मारने लगा।' इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता में व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को अधिक महत्व दिया जाता है और राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होता है।

राष्ट्रीयता का विकास यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना का उदय यूनान के अगर राज्यों में हुआ। उसके पश्चात रोमन साम्राज्य में यह भावना विद्यमान थी। रोमवासी अपने साम्राज्य की रक्षा के लिये अपनी जान तक देने का तयार थे। इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते थे। मध्यकाल में सामंतवाद के समय भी राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। सामंत अपने राज्य की रक्षा के लिये मर चुक चुकाने कर सकते थे। इसने पश्चात पुनर्जागरण और प्रथम सुधार आन्दोलन के समय राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रारम्भ हुआ। स्पेन के विरुद्ध दत्ता का स्वतंत्रता संग्राम और अमेरिकन उपनिवेशों में इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्रीयता की भावना का माग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण सहायता दिया।

फ्रांस की राज्य क्रांति न प्रगतिशील राष्ट्रीयता की भावना का जन्म दिया। जिसका आधुनिक युग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। नागरिका के हृदय में अपने देश की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय भावना को भरने में क्रांति न अद्वितीय योगदान दिया। जब फ्रांस की राज्य क्रांति को कुचलने के लिये विदेशी शासकों ने फ्रांस पर आक्रमण किये तो मार्सेलीस के देश भक्त एक उत्साहवद्ध क गीत गाते हुए देश की रक्षा के लिये आगे बढ़ते रहे। इस गीत में राष्ट्रीयता और देश भक्ति की भावनाएँ विद्यमान थीं। वही गीत आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। नेपोलियन ने क्रांति के स्वतंत्रता समानता और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार किया। फ्रांस की राज्य क्रांति ने सभी यूरोपीय राज्यों में एकता संगठन और राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया।

नेपोलियन तथा राष्ट्रीयता—19वीं शताब्दी राष्ट्रीयता की शताब्दी मानी जाती है। इस शताब्दी में सम्पूर्ण सभ्यता में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार हो गया था। 179२ से 1814 ई० तक नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को यूरोपीय राजनीति का केन्द्र बनाये रखा। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी नेपोलियन अपनी बसाधारण सैनिक सफलताओं के कारण फ्रांस का सम्राट बन गया। फ्रांस की राज्य क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का उसने सम्पूर्ण यूरोप में प्रचार किया। नेपोलियन की यूरोप को एक महत्वपूर्ण देन थी राष्ट्रीयता की भावना।

नेपोलियन ने पोलण्ड में जानबूझकर राष्ट्रीयता की भावना को उभाड़ा जबकि स्पेन और जर्मनी में उसके विरोध के कारण इस भावना का विकास हुआ। इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने अनजाने में ही इस भावना की नींव रख दी थी। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जर्मनी 300 से भी अधिक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। ये राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र थे तथा नाम मात्र के लिये रोमन सम्राट के प्रति वफादार थे। नेपोलियन ने इन छोटे छोटे राज्यों को मिनाकर 39 राज्यों का एक सघ बना दिया। जिस राईन राज्य सघ के नाम से जाना जाता है। इस सघ का निर्माण कर नेपोलियन ने जर्मनी में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन की नींव रख दी। इस समय नेपोलियन ने जर्मनी में पवित्र रोमन सम्राट के शासन का अन्त कर दिया था। नेपोलियन की अधीनता से मुक्त होने के लिये जर्मनी के लोगों ने स्वतंत्रता सघप आरम्भ कर दिया। यही में जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना ने उग्र रूप धारण कर लिया।

नेपोलियन ने जर्मनी के अतिरिक्त इटली में भी राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया। उसने इटली के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर गगन नीर "राष्ट्रीय राज्य" की स्थापना की। इसके बाद उसने 'इटली का राज्य' निर्मित किया। 1811 ई० में उसने अपने पुत्र नेपोलियन II को वहाँ का शासक नियुक्त किया। इटली को एक

राज्य का रूप देकर उसने एक समान शासन व्यवस्था को लागू कर राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। नेपोलियन का इटली में प्रत्यक्ष शासन था और जर्मनी के गार्डेन राज्य मय का वह संरक्षक था। उसने स्पेन के शासक को हटा दिया और उसके स्थान पर अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इससे स्पेन में राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र गति से विकास हुआ। स्पेन ने नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। यही राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना नेपोलियन के पतन का कारण सिद्ध हुई।

वियना कांग्रेस तथा राष्ट्रीयता—फ्रांस की राज्य प्राप्ति के कारण प्रजातन्त्र राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता आदि विचारों का यूरोप में प्रसार हुआ। नेपोलियन के पतन के पश्चात् यूरोपीय राष्ट्रीयता में सफलता की भावना बहुत प्रबल हो गई और यूरोपीय राष्ट्रीयता न आस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप की प्रादेशिक व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर हस्ताक्षर किये। इस विषय में कांग्रेस में टर्की के अतिरिक्त सभी यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस कांग्रेस में आस्ट्रिया प्रशासक और इंग्लैंड का बालबोरो था। आस्ट्रिया का चांसलर मेटर्निक इस कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसने इसकी सारी कार्यवाही का संचालन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति और एकता स्थापित करना था।

वियना कांग्रेस का प्रमुख सूत्रधार मेटर्निक था। वह राष्ट्रीयता और गणतन्त्र के सिद्धांतों को कुचलकर पुरातन व्यवस्था का फिर से स्थापित करना चाहता था। इसलिये मेटर्निक और उसके समर्थकों ने वियना कांग्रेस में जनतन्त्र और राष्ट्रीयता का अंत कर दिया परंतु उसके प्रयास अफसस रहे।

राष्ट्रीयता का विकास (1815-1848)—नेपोलियन ने फ्रांस को राज्य प्राप्ति के स्वतंत्रता, समानता और विषय-वस्तु के सिद्धांत का सम्पूर्ण यूरोप में प्रचार किया था। उसके पतन के पश्चात् वियना सम्मेलन में प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने इन सिद्धांतों का अंत कर पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया। इस समय तक यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार हो चुका था। इसलिये हर देश में वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था का विरोध प्रारम्भ हुआ और अंत में मेटर्निक को भागना पड़ा।

1830 ई० में फ्रांस में दूसरी प्राप्ति हुई। यद्यपि इस प्राप्ति को पूर्णरूप में सफलता प्राप्त नहीं हुई परंतु इससे प्रभावित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी प्राप्ति हुई। 1830 ई० की प्राप्ति से 1848 की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके पश्चात् फ्रांस में 1848 ई० में तीसरी प्राप्ति हुई। इस प्राप्ति से यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार तीव्र गति से होने लगा। इससे अन्य यूरोपीय देशों पर भी प्रभाव पड़ा और वहाँ पर भी प्राप्ति हुई। अंत में फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल, ग्रीस और स्विट्जरलैंड आदि देश स्वतंत्रता

(2) वियना कांग्रेस और इटली—नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ई० में वियना कांग्रेस ने इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार नेपोलियन द्वारा स्थापित व्यवस्था को समप्त कर दिया गया और इटली के राज्यों में पुनः निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। वियना कांग्रेस ने इटली को 8 भागों में विभाजित किया था। लोम्बार्डी 2 वेनेशिया 3 नेपल्स 4 सिसली 5 परमा 6 टस्कनी 7 मोडेना 8 सार्डीनिया पिडमाण्ट।

इटली के लाम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश आस्ट्रिया को दे दिये गए। पोप का राज्य पुनः उसे दे दिया गया और वह अपने राज्य का स्वतंत्र शासक बन गया। नेपल्स का राज्य फ्रांस के वूवों राजवंश के सप्तम फर्डिनेण्ड को दे दिया गया। टस्कनी और मोडेना में फिर से राजतन्त्र की स्थापना कर दी गई। परमा का राज्य मेरिया लुईसा को दे दिया। मेरिया लुईसा नेपोलियन की पत्नी थी जो आस्ट्रिया की राजकुमारी थी। पिडमाण्ट का राज्य और जेनोआ का गणराज्य सार्डीनिया को दे दिया गया। इस प्रकार वियना कांग्रेस ने दक्षिणपूर्व में फ्रांस के आक्रमण को रोकने के लिए सार्डीनिया को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया।

वियना कांग्रेस ने इटली का विभाजन कर उसका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त कर दिया। विभाजन के प्रकार से किना गया कि इटली में एकात्मता की भावना उत्पन्न नहीं हो सके। इटली में पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया और वहाँ आस्ट्रिया का प्राधान्य पुनः स्थापित किया गया। वियना कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से इटली के एकीकरण का भाग प्रशस्त कर दिया। सार्डीनिया को इस कांग्रेस ने एक शक्तिशाली राज्य बना दिया था, जिसने आगे चलकर इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया।

(3) कार्बोनरी संस्थाएँ वियना कांग्रेस के प्रबंध में इटली की जनता में भयंकर असंतोष था। यहाँ की जनता ने यह निश्चय किया कि एकीकरण के लिए सघन प्रारम्भ कर दिया जाय। इसलिए इटली के अनेक भागों में कार्बोनरी समिति और राष्ट्रवादी नेतृत्व के लिए कार्यवाही की, जिसे कार्बोनरी और ग्रामा में गुप्त नाम से जाना जाता है।

इटली	बठर एक	में आयोजित
की गई थी, 1	कार्बोनरी	बड़े बड़े शहरों
में कार्बोनरी	इस मर	मुख्य उद्देश्य
इटली का एक	रूप	यह समस्या
राजनीतिक हल		करना
चाहता थी।		संस्था
न इटली के स्व		

(4) 1820-21 का असफल विद्रोह — बार्जोनरी सस्था के सदस्यों ने 1820 ई० में नपल्स में और 1821 में पिडमोंट में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विद्रोह कर दिया, परन्तु यह विद्रोह अमफल रहा क्योंकि मेटरनिक ने आस्ट्रिया की सेना को भेजकर इस विद्रोह को कुचल दिया।

(5) 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव — 1830 ई० की फ्रांसीसी क्रांति से इटली में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार हुआ। इस क्रांति में प्रभावित होकर इटली के परमा मोडेना और पोप के राज्यों में विद्रोह प्रारम्भ हुए। मोडेना के शासक का बहा की जनता ने राज्य में बाहर निकाल दिया और परमा की शासिका को आस्ट्रिया भाग जाने के लिए विवश किया, परन्तु आस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने आस्ट्रियन सेना को भेजकर मोडेना, परमा और पोप के राज्य में विद्रोहियों को बुरी तरह से कुचल दिया। इन राज्यों में हुई असफल क्रांतियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इटली के एकीकरण के माग में सबसे बड़ी बाधा आस्ट्रिया है, और स्थानीय विद्रोहों से उसकी शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

(6) इटली के राजनीतिक दल — इटली के राजनीतिक दल तीन भागों में विभाजित थे।

(i) प्रजातन्त्रवाद — मेजिनी व उसके अनुयायी यह चाहते थे कि एकीकरण के पश्चात् इटली में प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की जाय।

(ii) सघोष व्यवस्था — दूसरा दल सघवादियों का था। इस दल का नेता रोमन कैथोलिक पादरी था, जिसका नाम था जिब्रावर्ती। जिब्रावर्ती सघ को मानव कल्याण की धुरी मानता था। इस दल के सदस्य यह चाहते थे कि इटली के सभी राज्यों का एक सघ बनाकर पोप को उसका अध्यक्ष बनाया जाय।

(iii) संवैधानिक राजतन्त्र — तीसरा दल एकीकरण के पश्चात् संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इस दल के सदस्य यह चाहते थे कि पिडमोंट सार्डीनिया के राजा को सम्पूर्ण इटली का शासक बनाकर संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित किया जाय। उस समय पिडमोंट-सार्डीनिया एक शक्तिशाली राज्य था। वहाँ का राजा चार्ल्स एल्जट इटली के एकीकरण के लिये प्रयास कर रहा था। वह चाहता था कि एकीकरण के सघ का पिडमोंट नेतृत्व करे। पिडमोंट एक शक्तिशाली राज्य था जो आस्ट्रिया का मुकाबला करने में समर्थ था। बावजूद में इस दल का समर्थन किया।

(7) मेजिनी (1805-72) — इटली की स्वतंत्रता का पहला प्रभावशाली नेता मेजिनी था। मेजिनी में राष्ट्रीय भावनाएँ कूट-कूट कर भरती हुई थीं। उसका जन्म 1805 ई० में जिनेवा में हुआ था। उसके पिता एक डाक्टर थे।

नवोरा का युद्ध (1849) 1849 ई० सार्डीनिया के राजा एल्बर्ट ने एक बार पुनः आस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिये युद्ध प्रारम्भ कर दिया। आस्ट्रिया सना और सार्डीनिया का सना के बीच 1849 ई० में नवोरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में आस्ट्रिया ने एल्बर्ट का बुरी तरह पराजित किया। इसके पश्चात् उसने राज्य से त्याग पत्र दमर जपन पुत्र विक्टर एमेनुअल II को सार्डीनिया का शासक बना दिया। उसे विवश होकर आस्ट्रिया के साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार निम्न शर्तें निश्चित की गईं।

(1) सार्डीनिया ने लोवार्डी का क्षेत्र खाली कर आस्ट्रिया को देना स्वीकार कर लिया।

(11) सार्डीनिया को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक करोड़ पीछे आस्ट्रिया को देना पड़े।

इस प्रकार 1848 ई० की प्राप्ति की असफलता के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। यद्यपि कर्टोजा और नवोरा के युद्धों में सार्डीनिया पराजित हुआ परन्तु इन युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इटली के एकीकरण का नतृत्व पीन्मोण्ट-राज्य ही कर सकता है। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता पमी उसके झण्डे के नीचे एकत्रित होने लगे।

काबूर और इटली का एकीकरण —उपरोक्त असफलताओं के बावजूद भी इटली के नेताओं ने हिम्मत नहीं हारी और एकीकरण के लिये प्रयास करते रहे। एकीकरण का सर्वाधिक श्रेय काबूर को दिया जाता है। उसका जन्म 1810 ई० में हुआ था। प्रारम्भ में वह उदार विचारों वाला था परन्तु कुछ समय पश्चात् वह अधराजतंत्र का समर्थक बन गया। 1852 ई० में पिन्मोण्ट-सार्डीनिया के राजा विक्टर एमेनुअल ने उस प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया।

काबूर की नीति —काबूर की नीति का मुख्य उद्देश्य 'स्वाधीन तथा सयुक्त इटली का निर्माण करना था। काबूर के अनुसार इटली के एकीकरण के लिए निम्न दो बातें आवश्यक थी—

I—पीन्मोण्ट और सार्डीनिया के नतृत्व में इटली का एकीकरण किया जाय। इसके लिये आवश्यक था कि सार्डीनिया को एक आदर्श, शक्तिशाली तथा सम्पन्न राज्य बनाया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने निम्न कार्य किये —

(1) सार्डीनिया के व्यापार का विकास किया गया।

(11) उद्योग धंधा के लिये सरकारी सहायता दी गई।

(111) यातायात के साधनों को सुगम बनाने के लिये सड़क का निर्माण करवाया और रेलों का जाल बिछा दिया।

(iv) कृषि के विकास के लिए उसने कृषकों को ऋण दिये मिबाई की सुविधा के लिये नहरों का निर्माण करवाया। दलदल को साफ कर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। इसके अनिश्चित उजड़े हुए प्रदेशों को खेती योग्य बनाया गया।

(v) उसने सेना का पुनर्गठन किया। सेना को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित कर सैनिक शक्ति में वृद्धि की।

2—दूसरा, काबूर ने यह अनुभव किया कि जब तक आस्ट्रिया का प्रभाव इटली से समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इसलिये काबूर चाहता था कि आस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिये यूरोपियन देशों का सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। काबूर यह जानता था कि विदेशी सहयोग के बिना आस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना असम्भव है। आस्ट्रिया के विरुद्ध केवल फ्रांस का ही सहयोग मिल सकता था। काबूर ने एक बार कहा भी था "हम चाहे या न चाहे, हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है।

काबूर ने पीडमांट और सार्डीनिया को सुदृढ़ तथा समृद्धिशाली राज्य बनाने के लिये इटली में आस्ट्रिया को बाहर निकालने का निश्चय किया। उसने इटली के राज्यों में एकता पनपाने का प्रयास किया। काबूर ने इटली की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बनाने के लिये निम्न कार्य किये —

(1) सार्डीनिया का युद्ध —काबूर ने आस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया। 1854 ई० में रूस और टर्की के बीच सार्डीनिया का युद्ध प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस की बढ़ती हुई शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए टर्की का साथ दिया। काबूर ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। उसने इंग्लैंड तथा फ्रांस की मित्रता प्राप्त करने के लिये 17 हजार सैनिक इस युद्ध में टर्की की सहायता करने के लिये भेजे इस युद्ध में रूस पराजित हुआ और इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के सैनिकों के कारण टर्की को शानदार विजय प्राप्त हुई। सार्डीनिया के सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस बहुत प्रभावित हुए।

(2) पेरिस शान्ति सम्मेलन (1856) —युद्ध की समाप्ति के पश्चात् 1856 ई० में पेरिस में शान्ति सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस, आस्ट्रिया और रूस आदि देशों ने भाग लिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने आस्ट्रिया के विरोध के बावजूद भी सार्डीनिया का प्रतिनिधि को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया। इस पर काबूर ने सार्डीनिया की ओर से इस सम्मेलन में भाग लिया। काबूर ने यूरोपियन राष्ट्रों के सम्मुख इटली के एकीकरण का प्रश्न रखा। उसने अपने भाषण में कहा कि आस्ट्रिया इटली के एकीकरण का सबसे

बड़ा शत्रु है। ब्रिटिश विदेश मन्त्री ने काबूर की माग का समयन किया। इस प्रकार काबूर ने आस्ट्रिया के विरोध के बावजूद भी इंग्लैंड और फ्रांस का नतिक समयन प्राप्त कर लिया। उसने इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया।¹ इसीलिये एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि 'श्रीमिया के बीचड स नवीन इटली का निर्माण हुआ।

(3) नेपोलियन से समझौता होने के कारण —काबूर ने फ्रांस के शासक नपोलियन तृतीय से मित्रता कर ली। उसने आस्ट्रिया के विरुद्ध इटली को सहायता देना स्वीकार कर लिया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(i) काबूर के श्रीमिया के युद्ध में सैनिक भेजकर फ्रांस को सैनिक सहायता दी थी।

(ii) नेपोलियन तृतीय 1815 ई० की वियना कांग्रेस की व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहता था।

(iii) नेपोलियन वानापाट की भांति वह यत्न प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने इटली को स्वतन्त्रता दिलाने में सहायता देना स्वीकार कर लिया।

(4) प्लोम्बियस समझौता (1858)—फ्रांस के सम्राट नपोलियन तृतीय और काबूर के बीच प्लोम्बियस नामक स्थान पर एक गुप्त समझौता हुआ जिसमें निम्नलिखित बातें निश्चित की गई—

(i) नेपोलियन ने यह वायदा किया कि यदि आस्ट्रिया और सार्डीनिया के बीच युद्ध होगा तो वह आस्ट्रिया के विरुद्ध सार्डीनिया को दो लाख सैनिकों की सहायता देगा।

(ii) सार्डीनिया ने इस सहायता के बदले नीस और सेवाय के प्रदेश फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया।

(iii) आस्ट्रिया की पराजय के पश्चात् लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रांतों का सार्डीनिया में विलय कर दिया जायेगा।

(iv) जेरोम के नेतृत्व में इटली के राज्यों का एक संघ बनाया जायेगा।

(v) विक्टर एमेनुअल अपनी लड़की का विवाह नपोलियन के भाई प्रिंस जेरोम से करेगा।

इस प्रकार काबूर आस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस की सहायता प्राप्त करने में सफल हुआ परंतु इस सहायता के बदले में उसे महान् त्याग करना पड़ा। सेवाय सार्डीनिया के शासक की तथा नीस गेरी वाल्डी की जन्म भूमि थी परंतु इटली के

एकीकरण के लिए काबूर न यह प्रदेश नेपालियन तृतीय को देना स्वीकार कर लिया था ।

एकीकरण की पहली सीढ़ी (लोम्बार्डों का विलय)—नेपोलियन तृतीय स समझौता हो जाने के बाद काबूर आस्ट्रिया पर आक्रमण करने का भ्रवसर दूढ़न लगा । काबूर यह चाहता था कि युद्ध आस्ट्रिया के द्वारा प्रारम्भ किया जाए, ताकि यूरोपियन देशों की महानुभूति मार्लिनिया के प्रति बनी रहे । अतः सार्डीनिया व समाचार पत्रों में आस्ट्रिया की लोम्बार्डों व वेनिसिया के प्रति नीति की बटु आलोचना की जाने लगी । मार्लिनिया अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने लगा । उसने लोम्बार्डों की सीमा पर मोचाबंदी करना प्रारम्भ कर दिया । इतना ही नहीं काबूर ने आस्ट्रिया अधिष्टत श्रेष्ठ मस्सा और फ्रांस में विद्रोह करवा दिया । इन प्रदेशों में आस्ट्रिया के विरुद्ध आन्दोलन न उग्र रूप धारण कर लिया । इस पर आस्ट्रिया ने सार्डीनिया को चेतावनी दी कि यदि उसने तीन दिन में अपनी सैनिक शक्ति कम नहीं की तो उस पर आक्रमण कर दिया जायेगा । सार्डीनिया न इस अल्टीमेटम को जानबूझ कर ठुकरा दिया । यह तो चाहता था कि आस्ट्रिया उस पर आक्रमण कर । परिणाम स्वरूप 19 अप्रैल 1859 ई० में आस्ट्रिया न सार्डीनिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । इस समय काबूर ने ध्यवस्थापिका में भाषण देते हुए कहा कि "यह पालियामेंट की अंतिम बैठक है । इसके बाद सम्पूर्ण इटली की बैठक होगी तब इतिहास का निर्माण होगा ।"

जैसे ही आस्ट्रिया ने सार्डीनिया पर आक्रमण किया, वैसे ही फ्रांस ने दो लाख सैनिक सार्डीनिया की सहायता के लिए भेज दिए । फ्रांस और सार्डीनिया की संयुक्त सेना न आस्ट्रिया को मगन्ता और साल्फेरिनो के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया । साल्फेरिनो का युद्ध जो कि 24 जून 1859 ई० को हुआ था, उसकी गिनती 19वीं शताब्दी के भीषणतम युद्धों में की जाती है । इस युद्ध में दोनों ओर से ढाई लाख से भी अधिक सैनिक न भाग लिया । इसमें दोनों ओर के लगभग 40 हजार सैनिक युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए । इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् सार्डीनिया न समूचे लोम्बार्डों पर अधिकार कर लिया ।

नेपोलियन के युद्ध से प्रयत्न होने के कारण—जब मार्लिनिया न लोम्बार्डों पर अधिकार कर लिया तब नेपालियन ने बिना उससे परामर्श लिये आस्ट्रिया के साथ समझौता कर लिया । इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) नेपालियन बचल उत्तरी इटली को एकता की समर्थक था । वह सम्पूर्ण इटली की एकता का विरोधी था । वह यह नहीं चाहता था कि फ्रांस की सीमा पर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो ।

(2) इटली की जनता रामन कैथोलिक धर्म में विश्वास करती थी । कंधा लिव धर्म का गुरु पाप भी रोम में विश्वास करता था । इसलिए फ्रांस की जनता युद्ध

जारी रखने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि इससे पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाने की संभावना थी।

(III) आस्ट्रिया के पराजय के बाद उसकी स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा था और उसे पूर्ण रूप से पराजित करना असंभव सा लग रहा था।

(IV) नेपोलियन तृतीय को यह भय था कि वही प्रशा आस्ट्रिया का पत्र लेकर युद्ध में सम्मिलित न हो जाय।

इन सब कारणों से नेपोलियन ने युद्ध बंद करने का निश्चय किया और वह आस्ट्रियन सम्राट से विलाफ्रैंका नामक स्थान पर मिला। इस समय नेपोलियन ने कुछ शर्तों के साथ युद्ध बंद करने का प्रस्ताव रखा जिसे आस्ट्रिया ने सहप स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नेपोलियन ने युद्ध से अपने को अलग कर लिया।

(5) विलाफ्रैंका की संधि (1859) —नेपोलियन तृतीय ने आस्ट्रिया के सम्राट के साथ बिना सार्डीनिया की सलाह के 11 जुलाई 1859 को एक संधि कर ली, जिसे विलाफ्रैंका की संधि कहा जाता है। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्न लिखित थी —

- (1) आस्ट्रिया का लोम्बार्डी का प्राप्त सार्डीनिया को देना पडा।
- (II) वेनिसिया के प्रान्त पर आस्ट्रिया का अधिकार रखा गया।
- (III) यह निश्चय किया गया कि इटली के राज्यों का एक संघ बनाया जायगा जिसका अध्यक्ष पोप होगा।
- (IV) टस्कनी और मोडेना के ड्यूक पुनः शासक नियुक्त कर दिये गये।
- (V) नेपोलियन ने नीस और सेवाय के प्रदेशों को बजाय केवल युद्ध का खर्च लेना स्वीकार कर लिया।

अब नेपोलियन ने आस्ट्रिया के साथ विलाफ्रैंका की संधि कर ली, ता सार्डीनिया के राजा विक्टर एमनुअल की भी बाध्य होकर आस्ट्रिया के साथ ज्यूरिच की संधि करनी पडी। इस संधि पर दोना देश ने 10 नवम्बर 1859 ई० को हस्ताक्षर कर दिये। काबूर इस संधि के पक्ष में नहीं था। इसलिये उसने प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। इस संधि से सार्डीनिया को लोम्बार्डी का प्रदेश प्राप्त हुआ। यह एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इससे एकीकरण का पहला चरण पूरा हो गया।

एकीकरण की दूसरी सीढ़ी (मध्य इटली के राज्यों का विलय) —आस्ट्रिया की पराजय में इटालियन जनता के उत्साह में वृद्धि हुई। इससे उत्साहित होकर मध्य इटली के टस्कनी, परमा, मोडेना, और बोमासा राज्यों की जनता ने अपने शासकों को हटा दिया और सार्डीनिया में मिलने की घोषणा कर दी। इंग्लैण्ड के विदेश मंत्री पामस्टन ने इन राज्यों की कायवाही का समर्थन किया इसलिये आस्ट्रिया और फ्रांस चाहते हुए भी इन राज्यों की आति को कुचलने के लिये सन्निक हस्तक्षेप नहीं कर सके।

राष्ट्रवाद जर्मनी और इटली का एकीकरण

उधर काबूर पुन प्रधान मंत्री बन चुका था। उसमें इन राज्यों की शासन व्यवस्था का मचालन करने के दिव्य आन अधिकारी भेज लिए। इनके अतिरिक्त काबूर ने नपोलियन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह मध्य इटली के राज्यों को जनमत के आधार पर सार्डीनिया में मिलान की बात का समयन करेगा, तो काबूर उसे नीस तथा सेवाय का प्रदेश देगा। नपोलियन ने काबूर के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1860 ई० में मध्य इटली के टस्कनी, मोडेना परमा और रोमाग्ना प्रादि राज्यों को जनमत के आधार पर सार्डीनिया में मिला दिया। इसके पश्चान् काबूर ने नीस तथा सेवाय के प्रदेश फ्रांस का दे दिये। अब उत्तरी तथा मध्य इटली एकता के सूत्र में बंध गये। इस प्रकार एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हो गया।

एकीकरण की तीसरी सोढ़ी और गेरीबाल्डी (सिसली तथा नेपल्स का विलय—जोसेफ गेरीबाल्डी (1807-1882) का जन्म नीस नगर के एक साधारण परिवार में हुआ था। इसके पिता उसे पादरी बनाना चाहते थे, परंतु वह पादरी नहीं बनना चाहता था। इसलिये वह नीस से भागकर सार्डीनिया आ गया। वहाँ आकर जलसना में शर्ती हो गया। उसने स्वतन्त्रता सघप में भाग लिया। परिणाम स्वरूप 1834 में उसे मृत्यु दण्ड दिया गया। वह जेल से किसी प्रकार भाग कर दक्षिणी अमेरिका जा पहुँचा। वहाँ उसने स्पेन के उपनिवेशों की स्वतन्त्रता के लिये सघप में भाग लिया। इसमें उसने असाधारण सनिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके कारण उसे एक धीरे पुरुष समझा जान लगा।

गेरीबाल्डी ने सनिक दल का गठन किया। इस दल के सन्स्थापक "लाल कमीज" पहनते थे। इसलिये यह दल "लाल कुर्ती दल" के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1848 ई० की क्रान्ति के समय गेरीबाल्डी और मेजिनी ने पोप की रोम से भगा दिया और रोम पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् मेजिनी के नेतृत्व में रोम में गणतन्त्रात्मक शासन की स्थापना की गई। कुछ समय पश्चात् ही नेपोलियन तृतीय की सहायता से पोप पायस नवम ने रोम पर फिर से अधिकार कर लिया। परिणामस्वरूप मेजिनी इंग्लण्ड और गेरीबाल्डी अमेरिका भाग गया। गेरीबाल्डी काबूर की कूटनीति की आलोचना करता था। फिर भी, उसने जब 1860 ई० में सिसली पर आक्रमण किया, तो काबूर ने उसका समयन किया।

गेरीबाल्डी को दक्षिणी इटली के राज्यों में त्रांति की भावना पैदा करने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई। नेपल्स तथा सिसली के शासक जनता पर स्वेच्छा-चारी तरीके से शासन कर रहे थे और राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र की विचार धारा का दमन कर रहे थे। इन दोनों राज्यों की जनता में शासकों के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था। उत्तरी इटली तथा मध्य इटली के जन आंदोलन की सफलता ने सिसली

कि पड्य व और विद्रोहा से इटली का एकीकरण नहीं हो सकता । हम चाहे या न चाहें इटली का भाग्य फ्रांस पर निर्भर है ।

काबूर ने कूटनीति से काम लेने हुए प्रीमिया के युद्ध में सार्डीनिया के 17 हजार सैनिक इंग्लैण्ड और फ्रांस की सहायता के लिये भेजे । इसमें वह इंग्लैण्ड और फ्रांस का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गया । इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना लिया । काबूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ प्लाम्बियस का गुप्त समझौता कर अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया । यद्यपि इस समझौते का उसे भारी मूल्य चुकाना पड़ा, परन्तु राष्ट्रहित को देखते हुए उसने इसे चुकाना स्वीकार कर लिया । जब नेपोलियन ने काबूर के साथ विश्वासघात कर बीच में ही युद्ध बंद कर लिया तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, कि तु कुछ ही समय पश्चात् उम पुनः प्रधानमंत्री बनना पड़ा ।

यद्यपि काबूर घट राजतन्त्र का समर्थक था, परन्तु एकीकरण में क्रांति कारियों का सहयोग भी प्राप्त करने का निश्चय किया । उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'मैं इटली का निर्माण दक्षिण की ओर से क्रांति के द्वारा करूँगा ।' उसने गरीबाल्डी की सिसली विजय का समर्थन किया । जब गरीबाल्डी ने रोम पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया तो काबूर ने विक्टर एमेनुअल को भेजकर नेपल्स और सिसली पर सार्डीनिया का शासन कायम करवाया । इसके अतिरिक्त गरीबाल्डी के रोम अभियान को असफल बनाकर इटली को फ्रांस तथा आस्ट्रिया के साथ होने वाले युद्धों से बचाया ।

इतिहासकार फिलिप्स ने लिखा है कि उसने राष्ट्रीय मुक्ति के काम की दलीय भावनाओं से दूर और निष्पल काल्पनिक स्वर्गों की दुनियाँ से दूर रखा, विचारहीन पड्यत्वों से उसकी रक्षा की और क्रांति तथा प्रतिक्रांति की चट्टानों के बीच से उसकी मौका को खेकर उसे सगठित शक्ति ध्वजा शासन और विदेश मित्र प्रदान किये । मेरियट ने लिखा है कि 'मेजिनी की प्रेरणा, गरीबाल्डी की तलवार क्रांति कारियों का जोश तथा नेपोलियन के होसले का एक साथ एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयोग करना काबूर का ही काम था ।

यह सत्य है कि यदि काबूर का सहयोग नहीं मिला होता तो इटली का एकीकरण कुछ समय के लिये आगे टल सकता था ।

(4) एकीकरण की अंतिम सीढ़ी और विक्टर एमेनुअल—(वेनेशिया और रोम का विलय)—वेनेशिया और रोम के अलावा सभी प्रदेश सार्डीनिया में मिला दिय गये थे । 1861 ई० में काबूर की मृत्यु के पश्चात् एकीकरण का उत्तरदायित्व सार्डीनिया के सम्राट विक्टर एमेनुअल पर आ पड़ा ।

पराधीनता और इटली का एकीकरण

(i) वेनेशिया पर अधिकार (1866 ई०) — 1866 ई० में आस्ट्रिया और प्रशासक युद्ध हुआ। आस्ट्रिया को मितहीन बनाने के लिये विस्माक ने रुस, फ्रांस और इटली आदि देशों से कूचीतिक संधिया की। इटली से हुई संधि में यह निश्चित किया गया था कि जब प्रशासक और आस्ट्रिया के बीच युद्ध होगा तो उस समय इटली जर्मनी की सहायता के लिये आस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा। युद्ध में जर्मनी की विजय होने पर वह आस्ट्रिया से वेनेशिया का प्रदेश इटली को दिनवा देगा।

1866 ई० में आस्ट्रिया और प्रशासक युद्ध प्रारम्भ हो गया तो पूर्व में ए समझौते के अनुसार इटली ने आस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। आस्ट्रिया की अनायास इटली का युद्ध मयुरी तरह पराजित किया परन्तु प्रशासक ने सेडोवा के युद्ध में आस्ट्रिया को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और उसे संधि करने के लिये बाध्य किया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् 23 अगस्त 1866 ई० को आस्ट्रिया और प्रशासक के बीच संधि हुई। इस संधि के अनुसार प्रशासक ने वेनेशिया का प्रदेश आस्ट्रिया से इटली को दिनवा दिया। अब केवल रोम को छोड़कर सम्पूर्ण इटली का एकीकरण हो चुका था। रोम पर कथोलिक धर्म गुरु पोप का अधिकार था और पोप की रक्षा के लिये फ्रांस के सम्राट नपोलियन तृतीय ने फ्रांसीसी सेना को तैनात कर रखा था।

(ii) रोम पर अधिकार (1870 ई०) — 1870 ई० में फ्रांस और प्रशासक के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पूर्व विस्माक ने इटली से एक समझौता किया जिसके अनुसार इटली युद्ध में तटस्थ रहेगा। उमर बढ़ने में विस्माक ने उम रोम पर अधिकार करने की मोन स्वीकृति दे दी। 1870 ई० में जब फ्रांस और प्रशासक के बीच युद्ध प्रारम्भ हुआ तो नेपोलियन ने अपनी सेना रोम से बुलाई। फ्रांस की सेना ने रोम छोड़ते ही विक्टर एमेनुअल ने 20 सितम्बर 1870 ई० को रोम पर अधिकार कर लिया। जनता के बहुमत के आधार पर रोम को इटली में विलय कर दिया गया। इस प्रकार 1871 ई० में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया।

2, जून 1871 ई० को विक्टर एमेनुअल ने एक विशाल जुलूस के साथ रोम में प्रवेश किया। इसके पश्चात् उसने घोषणा की कि "हम रोम का पहलू हैं और यही रहेंगे।" इस प्रकार वह इटली जैसे, 1815 ई० में वियना कांग्रेस में भौगोलिक चिह्नमात्र कहा था, अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित हुआ।

1871 ई० में इटली की संसद ने एक कानून पास किया— जिसे 'ला ऑफ पेपाल गारंटीज' कहते हैं। इस कानून से पोप के साथ समझौता हो गया, उभे पेपाल देन की व्यवस्था की गई। इस कानून के अनुसार यह निश्चित किया गया कि—

- (i) पोप के निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र पर उसका अधिकार मान लिया गया। इस क्षेत्र में पोप की सर्वोच्च सत्ता रहेगी।
- (ii) इस क्षेत्र में पोप एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन करेगा। वहाँ इटली की सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होगा और पोप की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
- (iii) पोप विदेशों में अपने राजदूत भेज सकेगा और विदेशी राजदूत पोप के दरबार में रह सकेंगे। फिर भी पोप ने इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और वह अपने आपको नजरबन्द कर्मी समझता रहा। इस प्रकार एक लम्बे समय के पश्चात् मैजिनी के नतिक बल गरीबाल्डी की तलवार, विक्टर काबूर की कूटनीति, विक्टर एमनुअल की मूढवृत्त तथा हजारों देश भक्तों के बलिदान से इटली का एकीकरण का बाय पूरा हुआ। इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूरोप के रमंच पर प्रकट हुआ। इटली के एकीकरण के बारे में मेरियट ने लिखा है कि मैजिनी ने इटली की आत्मा, काबूर ने मस्तिष्क गरीबाल्डी ने तलवार और एमनुअल ने शरीर बनकर राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य को पूरा किया और उसकी दासता की बेडिया काट डाली।

जमनी का एकीकरण—विश्व इतिहास में जमनी का उदय और पतन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जमनी जाति ने प्राचीन यूरोप का विशाल रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था और इसके पश्चात् इंग्लैण्ड फ्रांस, जमनी स्पेन और इटली आदि देशों पर अधिकार कर लिया था। धीरे धीरे जमनी जाति का राजनीतिक प्रभाव समाप्त होता गया और स्वयं जमनी का अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजन हो गया।

फ्रांस की राज्य शक्ति से पूर्व जमनी भी इटली की भाँति दो सौ से अधिक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में से कुछ पर विदेशी शासकों का अधिकार था। जैसे कि हनोवर पर इंग्लैण्ड का श्लेसविग पर डेनमार्क का, उत्तर जमनी राज्यों पर आस्ट्रिया का और दक्षिणी जमनी राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव था। फ्रांस की राज्य शक्ति का जमनी पर भी प्रभाव पड़ा और वहाँ राष्ट्रीयता की भावनाएँ जाग्रत हुईं। अब जमनी की जनता राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने के पक्ष में थी।

नेपोलियन और जमनी—नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कार्यों से जमनी के एकीकरण का भाग प्रशस्त किया। 1806 ई० में उसने जमनी में पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त कर दिया। इसके पश्चात् जमनी के छोटे छोटे राज्यों को मिला कर 'राइन राज्य सघ' का निर्माण किया। सभी राज्यों में एक जसी शासन व्यवस्था लागू की। इस प्रकार नेपोलियन ने अपने कार्यों से अप्रत्यक्ष रूप से जमनी

के एकीकरण का माग प्रशस्त कर दिया। इसलिये उसको जमनी के एकीकरण का पथ प्रदर्शक कहा जाता है।

वियना कांग्रेस और जमनी —नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ई० में वियना में विजयी राष्‍ट्रा का एक सम्मेलन हुआ जिस वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में जमनी को 39 राज्या में विभाजित कर एक शिथिल सभ का निर्माण किया गया जिसमें जमनी परिसभ कहा जाता है। आस्ट्रिया के सम्राट को इस परिसभ का अध्यक्ष एवं प्रशासक सम्राट को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस परिसभ की एक ससद बनाई गई। जिसके सदस्य जमनी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि हाने थे। यह सघीय व्यवस्थापिका (Diet) बंधक राजाओं का प्रतिनिधित्व करता थी, जनता का नहीं। इस ससद के प्रतिनिधियों को एक जस अधिकार प्राप्त नहीं था। बड़े राज्या के प्रतिनिधियों को अधिक अधिकार दिये गये थे जबकि छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों को कम।

सघीय सभा में साधारण विषया पर बहुमत से निर्णय लिया जाता था, जबकि मुख्य विषयों पर दो तिहाई बहुमत से। सभी राज्या एक दूसरे से स्वतंत्र थे। सभ के सदस्य राज्या एवं दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। सभ पर आक्रमण हाने की दशा में सभी राज्या मिलकर सामना करते थे। वैसे सभ का प्रत्येक सदस्य अपने-अपने राज्या में पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। इस सभ के द्वारा आस्ट्रिया जमनी के राज्यों पर नियंत्रण रखता था। इसका मुख्य उद्देश्य जमनी में राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना था।

वियना सम्मेलन ने श्लेस्विग और होलस्टीन को डेनमार्क के अधीन कर लिया। अल्सास व सारेन के प्रदेश पर फ्रांस को अधिकार दे दिया। इस प्रकार जमनी के कुछ भाग पर डेनमार्क का, कुछ भाग पर फ्रांस का और कुछ भाग पर आस्ट्रिया का अधिकार हुआ गया। वियना सम्मेलन ने जमनी में तीन विदेशी शक्तियों का शासन स्थापित कर दिया। इस प्रकार वियना कांग्रेस के निर्णय ने जमनी राष्ट्रवादियों की आकांक्षा पर भयंकर कुठाराघात किया।

जमनी के एकीकरण का माग में कठिनाइया —

(1) धार्मिक भिन्नता —जमनी में अनेक राजनीतिक दल थे, जो सुधारों के विषय में एकमत नहीं थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि जमनी के राज्या में भिन्न भिन्न शासन प्रणालियाँ विद्यमान थीं। जमनी के जिन प्रदेशों में आस्ट्रिया का प्रभाव था, वहाँ पर निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कुछ नगरों में स्थानीय सस्थाएँ शासन का संचालन कर रही थीं।

जमनी के कुछ राज्या यह चाहते थे कि जमनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रशासक करें। कुछ सामन्तवादी विचार धारा के समर्थक थे। कुछ राज्य एकीकरण के

पश्चात् जर्मनी, म-गणतन्त्र कायम करना चाहते थे, उसे कुछ हस्त-वग-वशान्ते नगुत्व-में जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे।

10. इसके अतिरिक्त जर्मनी की आंतरिक समस्याएँ बड़ी जटिल थीं। इन समस्याओं पर विभिन्न दल आपस में भगड़ते रहते थे। जर्मनी के कुछ दल फ्रांस की राज्य-शक्ति से प्रभावित थे जो कुछ शान्तिकारी योजनाओं का विरोध कर रहे थे। जर्मनी में राज्यों और राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद थे। इसीलिए जर्मनी में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ।

11. (ii) विदेशी प्रभुत्व — इटली की भाँति जर्मनी में भी विदेशी राज्य-वशों, कुल-शासन था, जो जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। जर्मनी की अलस्विग-मौट-होलस्टीन की डचियों पर हेनमाक का अधिकार था। हेनमाक पर इंग्लैंड का अधिकार एक आस्ट्रिया का जर्मनी पर प्रभुत्व था, इसलिये आस्ट्रिया और हेनमाक जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। फ्रांस भी जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो।

12. (iii) प्रतिक्रियावादी नीति — विना कांग्रेस के नियमों में जर्मनी के एकीकरण का माँग अवरुद्ध कर दिया। आस्ट्रिया का जर्मनी पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी नीति का समर्थक था जो प्रगतिशील तथा राष्ट्रीयता के विचारों का कट्टर शत्रु था। उसने इन विचारों को कुचलन में कोई कसर नहीं रखी। मेटरनिक ने जर्मनी में घोर प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई।

जर्मनी में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार वहाँ के विश्वविद्यालयों के द्वारा किया गया। जेना इस आन्दोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। धीरे-धीरे सम्पूर्ण जर्मन राज्यों में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता का आन्दोलन बढ़ता ही गया। मेटरनिक ने इस आन्दोलन को कुचलन के लिये सघीय शासकों को आदेश दिया। उसने काल्सबाद में जर्मन संसद की बैठक बुलाई। इसमें उसने जर्मनी के राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिये कई नियम बनाए जिन्हें 'काल्सबाद के आदेश' के नाम से जाना जाता है। इन आदेशों के अनुसार यह निश्चित किया गया कि —

(i) प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग अपना एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। जो इस बात को देखेगा कि विश्वविद्यालय सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा है।

(ii) विश्वविद्यालयों और पाठ्यक्रम पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कहीं विश्वविद्यालय राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार तो नहीं कर रहा है।

(iii) बीस मुद्रित पृष्ठों से अधिक लेखों को सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही प्रकाशित किया जा सकता था।

राष्ट्रवादी जर्मनी और इटली का एकीकरण

जिसे इन दमनकारी कानूनों के कारण जर्मनी में 30 वर्ष तक राष्ट्रियता की भावना का विकास नहीं हो सका। इस प्रकार 1848 ई० तक आस्ट्रिया जर्मनी पर निरंकुश रूप से शासन करता रहा। जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के प्रयास (1815-1850 ई०) —

1. बुद्धि आंदोलन - जर्मनी व दार्शनिका, लेखना, कविया जोर इतिहासकार न जनता म राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया। गेट, शिलर, हीगल और पिकर आदि विद्वान न अपनी रचनाओं के माध्यम में जनता म बौद्धिक जागरण को। इस जर्मनी में बौद्धिक आ लिन प्रारम्भ हुआ। ये विद्वान गुप्त रूप स जनता म राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करते रहे।

2. आर्थिक संघ की स्थापना - जर्मनी क राज्या को विभाजित हानि से रापार म बठिगाई का सामना करना पडता था और व्यापारी को प्रत्येक राज्य म चूगी देनी पडती थी। इस व्यापारिक अशुविधा को दूर करने के लिए 1834 ई० म 18 जर्मन राज्या को मित्रावर प्रशा के नगत्व मे एक आर्थिक संघ की स्थापना की गई। यह संघ एक प्रचार ना चूगी संघ या जिसे 'जोलेवरिन' के नाम म भी पुकारा जाना था। इस संघ के सदस्य राज्या न यह निश्चय किया कि वे एक दूसरे के माल पर, चूगी कर नहीं लेंगे। इस प्रकार इस के सदस्य राज्यों को स्वतंत्र रूप से, रापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। 1850 ई० तक जर्मनी के सभी राज्या इस संघ के सदस्य बन गये। प्रशा इस आर्थिक संगठन के माध्यम स अपनी शक्ति म वृद्धि कर रहा था। भेटरनिक चाहते हुए भी इस संघ के विराघ म कुछ नहीं कर सका।

इस संघ की स्थापना से अधिक दृष्टि से सारा जर्मनी एक हो गया। एक ही राय क लागू दूसरे राज्य मे व्यापार के लिए धान जान लगे। इस जनता म ही राष्ट्रियता की भावना का काफी विकास हुआ। इस आर्थिक संघ की स्थापना से ही प्रशा जर्मन राज्या का नेता बन गया। इसम यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का वास्ते चलाने प्रशा के नतुत्तर म एकीकरण ही होगा। केटलवी ने लिखा है कि 'जोलेवरिन' के निर्माण ने भविष्य म प्रशा व नतुत्त्व म जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का माग तयार कर लिया।

1830 की फ्रांस की प्रभाव - 1830 की फ्रांस की दूसरी क्रांति म प्रभावित होकर जर्मन जनता न स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। परंतु जर्मन राजाओं ने भेटरनिक की सहायता स इस आंदोलन का दमन कर दिया। ए हिस्ट्री ऑफ मोडर्न टाइम्स, पृ 175

4—1848 ई० की क्रान्ति का प्रभाव —1848 ई० में फ्रांस में तीसरी क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति ने जर्मनी को बहुत अधिक प्रभावित किया। इससे प्रोत्साहित होकर प्रशा, वेवेरिया, सक्सनी हेनोवर वेडेन आदि राज्यों की जनता ने वहाँ के निरंकुश शासकों के विरुद्ध आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। इससे कुछ शासकों ने उदारवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की। परंतु जर्मन शासकों ने मेटर्निख की सहायता से इस आंदोलन का दमन कर दिया और फिर से प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी।

फ्रैंकफर्ट की ससद ने दस माह के प्रयासों से सघीय संसदात्मक राजतन्त्रीय संविधान का निर्माण किया। इस सघ का अध्यक्ष प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को बनाया गया। इस समय ससद ने प्रशा के सम्राट से अनुरोध किया कि वह ताज पहन ले परंतु उसने पहनने से इसलिये इन्कार किया क्योंकि इससे आस्ट्रिया के साथ युद्ध की सम्भावना थी। इस सघ में आस्ट्रिया के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए प्रशा का शासक जानता था कि आस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ेगा और प्रशा युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इसके जलावा इस सघ का अध्यक्ष बनने से प्रशा के अस्तित्व के समाप्त होने की सम्भावना थी।

प्रशा का राजा नहीं चाहता था कि वह फ्रैंकफर्ट एसेम्बली की इच्छा से राजा बन। यह संविधान क्रान्ति पर आधारित था और वह नहीं चाहता था कि वह क्रान्ति का दास बन। प्रशा का शासक विशुद्ध जर्मन राज्यों का एकीकरण करना चाहता था। इस प्रकार फ्रैंकफर्ट ससद के कार्य असफल रहे। इस पश्चात् प्रशा के सम्राट ने कुछ सुधार किये।

इस समय सेक्सनी, वूटम्बर्ग हेनोवर और वेवेरिया के राज्य एक सघ का निर्माण करना चाहते थे, परंतु आस्ट्रिया के विरोध के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। 1850 ई० में प्रशा ने आस्ट्रिया के भय से घबराकर सुधार वापस ले लिए और पुनः प्रतिक्रियावादी शासन लागू कर दिया। इन घटनाओं से निम्न दो बातें स्पष्ट हो गईं —

(1) आस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त कर बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकेगा।

(2) जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में होगा।

जर्मनी का एकीकरण (1862-1871) — विलियम प्रथम (1861-1888) — 1861 ई० में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के पश्चात् विलियम प्रथम प्रशा का सम्राट बना। वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम प्रथम योग्य स्थिर बुद्धि और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। हेज़न ने लिखा है कि विलियम प्रथम में सम्भव एवं असम्भव के निगम एवं मानव चरित्र के अन्त स्तल तक पहुँचने की श्रद्धालु क्षमता थी। विलियम प्रथम यह जानता था

कि एकीकरण के लिए आस्ट्रिया के साथ युद्ध होगा। इसलिये वह कहा करता था कि प्रशा का भविष्य सैनिक शक्ति पर निर्भर करता है। उसने सैनिक शक्ति में वृद्धि करने का निश्चय किया और प्रशा के सैनिकों की संख्या युद्ध काल में 4½ लाख और शान्ति काल में 2 लाख निश्चित कर दी परन्तु संसद ने सैनिक वृद्धि के लिए खर्चा स्वीकार नहीं किया। जर्मनी में उदारवादी लोग जनमत के आधार पर एकीकरण करने के समर्थक थे। वे तत्काल से जर्मनी का एकीकरण नहीं करना चाहते थे।

इस पर विलियम प्रथम ने संसद का भंग कर दिया और नये चुनाव करवाये। नया चुनाव सैनिक वृद्धि के लिये खर्चा देने का प्रश्न को लेकर रूढ़िवादी बनाया गया। नये चुनाव में उदारवादियों को बहुमत प्राप्त हो गया। अब सम्राट को यह भय लगने लगा कि कहीं संसद सेना का खर्च बढ़ न कर दे अथवा सेना को कम करने का प्रस्ताव नहीं रखे। इस संकट से बचने के लिये युद्ध में वी वाउण्ट वान रुन ने विलियम प्रथम का यह सलाह दी कि विस्माक को प्रधानमंत्री बना दिया जाय। अब विलियम प्रथम ने 23 सितम्बर 1862 ई० का दिन विस्माक का प्रशा का चांसलर (प्रधानमंत्री) नियुक्त किया, उस समय सम्राट जोर प्रतिनिधि सभा में सैनिक खर्च का प्रश्न को लेकर भगड़ा चल रहा था। विस्माक ने सम्राट को यह आश्वासन दिया कि "श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा पर संसद के साथ संधि में आपका साथ नहीं छाड़ूंगा।"

विस्माक - विस्माक अपने समय का यूरोप का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। उसका जन्म 1815 ई० में ब्रेडनबर्ग के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उसका पिता कुलीन परिवार का था और उसका शाही घराने से सम्बन्ध था। प्रशा में कुलीन को 'ज़कर' के नाम से पुकारा जाता था। कुलीन लोग कई पौडियों में सेना में काम कर रहे थे। ये लोग राजा के प्रति बफादार होते थे। विस्माक भी एक पक्का जकर था।

विस्माक की अध्ययन के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी। फिर भी उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। वह अपने विद्यार्थी जीवन में ही द्वन्द्व युद्ध, सदाइ झगड़ा करने और बीयर पीने में प्रसिद्ध हो गया। वह सरकारी नौकरी से घणा करता था। इसलिये कुछ समय नौकरी करने के पश्चात् उसने छोड़ दी। इसके बाद उसने यूरोपियन दक्षा का यात्रा किया। विस्माक का पालन-पोषण प्रतिप्रियावादी मानावरण में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में वह गणतंत्र का समर्थक बन गया था। इसके पश्चात् बर्लिन के प्रतिप्रियावादी दल के प्रमुख लोगों के सम्पर्क में आकर वह पुनः कट्टर प्रतिप्रियावादी बन गया और जीवन भर ऐसा ही बना रहा। 1847 ई० में वह राज्य सभा का सदस्य बना। परन्तु जगले दस वर्षों में उसने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। वह जीवन भर शान्ति विरोधी और कट्टर प्रतिप्रियावादी बना रहा।

विस्मार्क निरक्षुण राजनता का प्रबल समर्थक था। वह प्रशासनिक प्रशासन व्यवस्था की आलोचना करता रहता था। विस्मार्क सविधान की घणा की दृष्टि से दयता था और उसे वाग्य का टुकड़ा मन्त्र मानता था। वह प्रशासनिक नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करता चाहता था। फिर भी 1848 ई० में उसने जर्मनी का एकीकरण प्रयास का विरोध किया। उसका यह मानना था कि जर्मनी का एकीकरण राजाशाह द्वारा किया जाना चाहिये जनता द्वारा नहीं। विस्मार्क का यह अफराध मानना था। प्रशासनिक मानना की उसने सिय सयमे महान् धारणा था। विस्मार्क आस्ट्रिया का घोर विराधी था। यह जानना था कि आस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो के पश्चात् ही जर्मनी में प्रशासनिक गवर्नरना स्थापित हो सकेगी है। विस्मार्क 1851 ई० से 1858 ई० तक क्रॉफ्ट स्थित जर्मन सभ की सभा का प्रशासनिक ओर सभास्य बना रहा। इस अवधि में उसने आस्ट्रिया का नाच सिंघान का हर सभ्य प्रयास किया। राजा विलियम यह नहीं चाहता था कि आस्ट्रिया को नाराज किया जाय इसलिये उसने 1859 ई० में विस्मार्क को सभ्य सभ में वापस बुला लिया।

विस्मार्क राजदूत के रूप में (1859-1862)—प्रशासनिक सम्राट विलियम प्रथम ने 1859 ई० में विस्मार्क को इस में राजदूत के रूप में नियुक्त किया। विस्मार्क अपनी योग्यता के कारण इस के शासक जार से व्यक्तिगत मैत्री स्थापित करने में सफल हुआ। जार और तुर्की के बीच जब प्रीमिया का युद्ध चल रहा था, तब प्रशासनिक इस के विरुद्ध युद्ध घोषित करने की मांग की गई लेकिन विस्मार्क के कारण प्रशासनिक युद्ध में तटस्थ रहा। इसमें जार अलवाण्डर विस्मार्क का पत्रिष्ठ मित्र बन गया। विलियम प्रथम ने विस्मार्क को 1861 ई० में पेरिस में राजदूत बना कर भेजा।

प्रधानमन्त्री के रूप में (1862-1890)—प्रशासनिक सम्राट विलियम प्रथम ने 1862 ई० में विस्मार्क को पेरिस से बुलवाया और प्रशासनिक चांसलर के पद पर नियुक्त कर दिया। विस्मार्क ने 1862-1890 ई० तक चांसलर के रूप में काम किया।

विस्मार्क की रक्त और लोह नीति—विस्मार्क चाहता था कि प्रशासनिक सैनिक शक्ति में वृद्धि की जाय और प्रशासनिक नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया जाय। उसका मानना था कि भाषण तथा वाग्यी प्रस्तावों से आस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर नहीं निकाला जा सकता अपितु रक्त और लोह की नीति से ही आस्ट्रिया को जर्मनी से भगाया जा सकता है। इसलिये विस्मार्क ने कहा था कि जर्मनी की समस्याएँ भाषण और वाग्यी प्रस्तावों से नहीं अपितु 'रक्त और लोह' नीति से हल की जा सकती हैं। विस्मार्क प्रशासनिक राजा को सम्पूर्ण जर्मनी का सम्राट बनाना चाहता था। उसने अनेक प्रधानमन्त्री बनने से पहले इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री डिजरेली

स कहा था कि यदि मैं जर्मनी प्रशासक प्रधानमंत्री बना तो प्रशासकीय शक्ति को मजबूत करूँगा और आस्ट्रिया को परास्त करके प्रशासकीय नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करूँगा।

बिस्मार्क ने चांसलर बनने के पश्चात् सैनिक शक्ति में वृद्धि की। समुद्र के विरोध के बावजूद भी सैनिक शक्ति की पूर्ति के लिए व्यय करना शुरू कर दिया। जर्मन युद्धमंत्री हून और मेनापिन पान गाल्टेरी की सहायता से एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। इस प्रकार बिस्मार्क ने प्रशासकीय सेना को यूरोप की सर्वश्रेष्ठ सेना बना लिया। जब समुद्र में उसकी सैनिक नीति का विरोध किया ता उसने अपना एक भाषण में कहा था कि 'समुद्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का निपटारा भाषणों और बहुमत के आधार पर नहीं रहित रहत और 'ब्लड और Iron Policy) से होता है।

बिस्मार्क की नीति से निम्न दो बातें स्पष्ट हुई —

- (1) जर्मनी का एकीकरण प्रशासकीय नेतृत्व में किया जायेगा।
- (2) आस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर निवालेना।

बिस्मार्क यह जानता था कि आस्ट्रिया को पराजित करने के पश्चात् ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो सकेगा है। आस्ट्रिया जैसी महान शक्ति को पराजित करना बहुत कठिन काम था, क्योंकि एक तो आस्ट्रिया स्वयं शक्तिशाली देश था और दूसरा उसे यूरोपियन देशों का समर्थन प्राप्त था। इसलिये बिस्मार्क ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये आस्ट्रिया को महान शक्तियों से सहयोग में बंधित किया तथा प्रशासकीय नेतृत्व में महान शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया।

बिस्मार्क द्वारा रूस से मित्रता—बिस्मार्क ने रूस के शासक को अपना मित्र बना लिया। पोलैंड पर रूस का अधिकार था। 1863 ई० में पोलैंड की जनता ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये रूस के शासक के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस और आस्ट्रिया आदि देशों ने रूस पर पोलैंड में उदार मन्विधान लागू करने के लिये बाव डाला, परन्तु रूस इनके विषये तयार नहीं था। उसने शक्ति से आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया। इस समय सम्पूर्ण यूरोप की महाभूमि पोलैंड लोगों के साथ थी। जिससे उत्साहित होकर पोलैंड की जनता ने आन्दोलन तेज कर दिया। इससे रूस के सामने एक विपत्ति समस्या पड़ी ही गई। परन्तु ऐसे समय में बिस्मार्क ने रूस को सैनिक सहायता दी। जिसकी सहायता से रूस ने पोलैंड लोगों के स्वतंत्रता आन्दोलन का दमन कर दिया। यद्यपि बिस्मार्क के इस कार्य की सम्पूर्ण यूरोप के द्वारा निन्दा की गई परन्तु उसके इस कार्य से रूस प्रशासकीय घनिष्ठ मित्र बन गया। जर्मनी के एकीकरण के लिये रूसी मंत्री बहुत लाभदायक मित्र हुई। इससे पूरे रूस आस्ट्रिया का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन अब वह प्रशासकीय घनिष्ठ मित्र बन चुका था।

बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण—बिस्मार्क ने लोह और रक्त की नीति पर चलते हुए तीन युद्धों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा किया। प्रशा का पहला युद्ध डेनमार्क के साथ 1864 ई० में दूसरा युद्ध आस्ट्रिया के साथ 1866 ई० में और तीसरा युद्ध फ्रांस के साथ 1870 ई० में हुआ। इन तीनों महान युद्धों में बिस्मार्क का विजय मिली और उसने जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा किया।

(1) डेनमार्क से युद्ध (1864)—श्लेस्विग और होल्स्टाइन की डचिया डेनमार्क और प्रशा के बीच युद्ध का कारण थी। ये दोनों डचिया जर्मनी और डेनमार्क के बीच में स्थित थीं। होल्स्टाइन की लगभग सम्पूर्ण जनता जर्मन जाति की थी, जबकि श्लेस्विग की आधी जनता जर्मन जाति की थी और आधी डेन जाति की। इन दोनों डचिया पर कई शताब्दियों में डेनमार्क का अधिकार था। डेनमार्क का राजा स्वयं 'ड्यूक' कहलाता था। डेनमार्क की जनता यह चाहती थी कि इन दोनों डचिया को डेनमार्क में मिला दिया जाए, जबकि इन डचिया में अधिकांश जनता जर्मन जाति की थी। ये यह चाहती थी कि इन डचियों का विषय जर्मन संघीय राज्य में कर लिया जाए।

विषय सम्मेलन में डेनमार्क का इन दोनों डचिया का संरक्षण का दिया गया था। होल्स्टाइन तो 1815 ई० से ही जर्मन परिषद का सदस्य बन चुका था। इन दोनों डचिया में राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र गति से विकास हो रहा था इसलिए डेनमार्क से इनके संबंधों में बंटूता आने लगी। 1848 ई० में इन डचिया की जनता ने जर्मनी में विलय के लिए प्रयास प्रारम्भ किया। डेनमार्क के राजा ने इन डचिया को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशा तथा अन्य जर्मन राज्यों के विरोध के कारण डेनमार्क को सफलता नहीं मिल सकी।

1852 ई० में इन डचिया की समस्या को हल करना के लिये तदन में एक सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें यह निश्चित किया गया कि डेनमार्क इन डचिया को अपने राज्य में नहीं मिलायगा। 1863 ई० में तदन संघि का उल्लंघन करते हुए डेनमार्क के शासक ने एक नये संविधान की घोषणा कर श्लेस्विग को अपने राज्य में मिला दिया। फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु के पश्चात् त्रिशिचिन नवम डेनमार्क का शासक बना। उसने भी अपने पूर्वज की नीति का ही पालन किया। जर्मनी ने श्लेस्विग को डेनमार्क में मिलाने का विरोध किया, तब बिस्मार्क ने आस्ट्रिया को भी अपने पक्ष में कर लिया।

बिस्मार्क ने आस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क के शासक से यह मांग की कि वह नये संविधान को 48 घंटे के अंदर वापस ले ले। इंग्लैण्ड के आश्वामन पर डेनमार्क ने संविधान को वापस नहीं लिया इसलिए आस्ट्रिया और प्रशा की सलाहों ने संयुक्त रूप से 1864 ई० में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। इस का शासक बिस्मार्क का मित्र होने से युद्ध में तटस्थ रहा। इंग्लैण्ड केवल विरोध प्रदर्शित

करके रह गया। फ्रांस मक्खिमकी की समस्या में उलझा हुआ था, इसलिये इस ओर ध्यान नहीं दे सका। परिणामस्वरूप आस्ट्रिया और प्रशा की सन्धि में डेनमार्क को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया।

वियना की संधि—(30 अक्टूबर, 1864) —डेनमार्क ने आस्ट्रिया और प्रशा के साथ विवाद होकर वियना की संधि पर 30 अक्टूबर 1864 ई० को हस्ताक्षर कर दिये। इस संधि के अनुसार —

- (i) डेनमार्क को श्लेसविग और हालेस्टाइन दोनों उच्चिया आस्ट्रिया और प्रशा को सौंप दी।
- (ii) डेनमार्क ने इन उच्चिया में मिला हुआ नाएन बग का प्रशा भी आस्ट्रिया और प्रशा का सौंप दिया।
- (iii) डेनमार्क ने यह स्वीकार कर लिया कि इन उच्चियों पर आस्ट्रिया और प्रशा जा भी निणय लेंगे वह उस स्वीकार होगा।

गस्टाइन का समझौता (14 अगस्त 1865)—वियना संधि के पश्चात् उच्चियों के प्रश्न को लेकर आस्ट्रिया और प्रशा के बीच मतभेद पैदा हो गया। इस मतभेद को सुलझाने के लिये दोनों के बीच 14 अगस्त 1865 ई० को गेस्टाइन का समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार आस्ट्रिया और प्रशा ने विजित प्रदेशों को निम्न प्रकार बांट लिया—

- (i) प्रशा ने लाएनबग का प्रदेश आस्ट्रिया से कीमत देकर खरीद लिया।
- (ii) श्लेसविग पर प्रशा का अधिकार मान लिया गया।
- (iii) हालेस्टाइन पर प्रशा ने आस्ट्रिया का अधिकार मान लिया।

इस विभाजन से प्रशा को अधिक लाभ मिला। श्लेसविग और लाएनबग पर प्रशा का अधिकार हो जाने से उसका कील बन्दरगाह पर नियंत्रण स्थापित हो गया। इससे प्रशा की सैनिक शक्ति में वृद्धि हुई। इस समझौते से आस्ट्रिया की प्रतिष्ठा को घटका पहुँचा।

लाज तथा हान ने लिखा है कि “गेस्टाइन का समझौता बिस्मार्क की एक महान कूटनीतिक विजय थी। यह समझौता आलमुत्स में प्रशा का जो अपमान हुआ था उसका प्रतिपाद्य था। ग्राट एव टेम्परल ने लिखा है कि ‘इस युद्ध से प्रशा राज्य का विस्तार हुआ। बिस्मार्क को फ्रांस तथा इंग्लैण्ड की दुबलता का ज्ञान हुआ तथा फ्रांस ने इंग्लैण्ड को तथा इन दोनों ने यूरोप को असफल बना दिया।’

2—आस्ट्रिया से युद्ध (1866)

सबोवों का युद्ध—गेस्टाइन की संधि ने आस्ट्रिया प्रशा संधि का अनिवाय कर दिया। इस संधि के मुख्य दो कारण थे —

- (i) आस्ट्रिया ने प्रशा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिये डचिया का शासन आगस्टन वुग के सम्राट के हाथ में दे दिया। बिस्माक ने आस्ट्रिया की इस कायवाही का विरोध किया। आस्ट्रिया जर्मनी को कमजोर और विभाजित रखना चाहता था। वह एकीकरण का कट्टर विरोधी था, जबकि प्रशा जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था।
- (ii) सघप का दूसरा कारण यह था कि बिस्माक न जर्मन राज्य सघप के संविधान को भंग कर दिया था और नये संविधान को लागू करने की मांग की। इस नये संविधान में बिस्माक आस्ट्रिया को कोई स्थान नहीं देना चाहता था। इससे आस्ट्रिया को दुःख हुआ। इससे आगे चलकर सघप का मांग प्रशस्त हुआ।

आस्ट्रिया को मित्रहीन बनाना—बिस्माक यह जानता था कि आस्ट्रिया को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित करने से पूर्व बिस्माक न प्रशा के लिये यूरोप की महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त किया तथा आस्ट्रिया को महाशक्तियों के सहयोग से बर्चित करने के लिये कई काय किये, ताकि जब प्रशा और आस्ट्रिया के बीच युद्ध हो तो कोई भी यूरोपियन राष्ट्र उसकी सहायता नहीं करे। दूसरे ५५ में बिस्माक न ५५ दशक की तटस्थता प्राप्त करने का निश्चय किया। आस्ट्रिया का महान शक्तियों का सहायता से बर्चित करने के लिये बिस्माक न निम्न काय किये —

(1) रूस—क्रीमिया के युद्ध में आस्ट्रिया तटस्थ रहा। जिसके कारण रूस उसका शत्रु बन गया था। जबकि 1863 ई० में पोलण्ड के विद्रोह को कुचलने में बिस्माक ने रूस की सख्त सहायता दी। परिणामस्वरूप बिस्माक न रूस के शासक की सहानुभूति प्राप्त कर ली। इस प्रकार बिस्माक न अपने काय में रूस के शासक अलेक्जेंडर द्वितीय को अपना मित्र बना लिया।

(2) फ्रांस—1865 ई० में बिस्माक ने फ्रांस का सहयोग प्राप्त करने के लिये फ्रांस के शासक नपोलियन तृतीय से वियारिटस नामक स्थान पर भेट की। यहाँ पर दोनों के बीच में समझौता हो गया। नपोलियन न यह आश्वासन दिया कि आस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध होने पर फ्रांस तटस्थ रहेगा और उत्तरी जर्मनी के राज्यों के एकीकरण का विरोध नहीं करेगा। नपोलियन न यह आश्वासन इसलिये दिया था क्योंकि —

- (i) बिस्माक ने नपोलियन तृतीय से यह वायदा किया था कि युद्ध में तटस्थ रहने पर वह फ्रांस को राइन का प्रदेश देगा।
- (ii) नपोलियन तृतीय 1815 ई० की वियना कांग्रेस की व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था।

- (iii) नेपोलियन इस समय मक्सिका की समस्या में उलझा हुआ था। उसे इतना समय नहीं था कि वह इस युद्ध की ओर अपना ध्यान दे सके।
- (iv) नेपोलियन प्रशा की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ था। उसे यह विश्वास था कि युद्ध में आस्ट्रिया ही विजय प्राप्त करेगा। इसलिये उसने असली सौदा आस्ट्रिया के साथ तय किया था।
- (v) नेपोलियन का यह मानना था कि दोनों के बीच सघर्ष लम्बे समय तक चलेगा। दोनों ही युद्ध से जब कमजोर हो जायेंगे, तब वह जर्मनी की राजनीति में हस्तक्षेप कर फ्रांस के प्रभाव में वृद्धि कर लेगा।

(3) इटली—विस्माक ने 8 अप्रैल 1866 ई० में इटली के साथ एक समझौता किया। जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि जब आस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध होगा तो इटली आस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा। इसके बदले में आस्ट्रिया के पराजित होने पर विस्माक इटली को आस्ट्रिया से वनेशिया का प्रदेश निश्चय देगा।

(4) इंग्लैंड—इंग्लैंड इस समय अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ था। इसलिये उसकी तरफ से कोई विशेष चिन्ता नहीं थी।

इस प्रकार विस्माक ने इंग्लैंड फ्रांस, रूस और इटली के मित्रता स्थापित कर ली। अब आस्ट्रिया मिन विहीन था। इस अवसर का लाभ उठाकर विस्माक ने आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

सेडोवा का युद्ध (1866)—11 जून 1866 ई० को आस्ट्रिया ने जर्मन समक्ष से प्रशा के विरुद्ध वायवाही करने का अनुरोध किया। संसद ने आस्ट्रिया के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। विस्माक ने संधि को समाप्त कर आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इस प्रकार युद्ध प्रारम्भ हो गया।

इस युद्ध में एक ओर प्रशा के दूमरी ओर आस्ट्रिया था। प्रशा का जर्मनी छोटे छोटे राज्यों और इटली के साथ दिया। जयन्ति आस्ट्रिया का जर्मनी के ववरिया यून्ग्वग, सक्सानी, हनावर नास, वेडेन और ह्स्मकासेल आदि राज्यों के साथ किया। युद्ध का प्रारम्भ होने के तीन दिन की अवधि में प्रशा ने इन सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध 16 जून 1866 ई० में प्रारम्भ हुआ और अगस्त 1866 ई० में समाप्त हुआ। इस युद्ध का सारा सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से गृहयुद्ध था। जुलाई 1866 ई० में आस्ट्रिया ने इटली को बुरी तरह से युद्ध में पराजित किया लेकिन सेडोवा के युद्ध में प्रशा ने आस्ट्रिया को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया।

पराजित आस्ट्रिया की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। प्रशा का राजा विनियम प्रथम यह चाहता था कि आस्ट्रिया की राजधानी वियना पर आक्रमण कर

लिया जाये परन्तु विस्माक ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह युद्ध बंद करने के पक्ष में था।

विस्माक द्वारा युद्ध बंद करने के कारण— विस्माक द्वारा आस्ट्रिया के साथ युद्ध बंद करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

1 विस्माक यह जानता था कि वही ऐसा न हो कि फ्रांस का सम्राट नपोलियन तृतीय सार्डीनिया पीडमण्ट व शासक के साथ गमभीरता कर ले और इसके पश्चात् राइन नदी की सीमा पर आक्रमण कर दे।

2 विस्माक जानता था कि यदि प्रशा ने वियना पर आक्रमण किया तो यूरोपियन देशों की सहानुभूति आस्ट्रिया के साथ हो जायेगी और वे उसकी सहायता के लिये हस्तक्षेप करेंगे। इससे जर्मनी के एकीकरण का मार्ग अवरोध होने की संभावना थी।

3 इस समय प्रशा की सेना के पाम तोपखान का वारुद समाप्त हो चुका था एवं सैनिकों में बीमारी फैल रही थी। इसलिये युद्ध बंद करने व सिवाय विस्माक के सामने अन्य कोई विकल्प नहीं था।

4 विस्माक आस्ट्रिया के सहयोग से फ्रांस को पराजित करना चाहता था। इसलिये उसने आस्ट्रिया का कम से कम रक्त बहाया। इतना ही नहीं युद्ध समाप्त के पश्चात् विस्माक ने संधि में उदार शर्तें रखकर उसका समयन प्राप्त कर लिया। विस्माक ने उस समय कहा था कि हमको पुन आस्ट्रिया की मित्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये।

प्राग की संधि (23 अगस्त 1866 ई०)—23 अगस्त 1866 ई० का विस्माक ने आस्ट्रिया से प्राग की संधि कर ली। विस्माक ने कूटनीति का परिचय देते हुए संधि की उदार शर्तें रखी। इस प्रकार वह आस्ट्रिया को अपना मित्र बनाने में सफल हुआ। प्राग की संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी—

- (1) श्लेसविग और होल्स्टाइन की डचिया प्रशा को दे दी गई।
- (2) आस्ट्रिया ने वनेशिया का प्रदेश इटला को देना स्वीकार कर लिया।
- (3) आस्ट्रिया को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पौंड प्रशा का देने पड़े।
- (4) 1815 ई० में वियना कांग्रेस के द्वारा निर्मित जर्मन परिषद की समाप्ति कर दी गई। आस्ट्रिया ने यह आश्वासन दिया कि अब वह जर्मनी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(5) प्रशा के उत्तर में उत्तरी जर्मन संध का निर्माण किया गया। इस संध में आस्ट्रिया के लिये कोई स्थान नहीं था। इसमें हेनोवर हेस्से कसल, श्लेसविग होलेटाइन आदि उत्तरी जर्मनी के राज्य सम्मिलित किये गये थे। इससे अतिरिक्त उत्तरी जर्मनी के 16 राज्य इसके सदस्य थे। 21 राज्यों के उत्तर जर्मन राज्य संध

राष्ट्रवाद जमनी और इटली का एकीकरण

का अध्यक्ष प्रशा के सम्राट को बनाया गया। इस राज्य सघ के निमाण से उत्तरी जमनी का एकीकरण पूरा हो गया। अभी दक्षिण जमनी के बेडेन, ववरिया, हेस्से तथा यूटमबग आदि राज्य स्वतंत्र थे। इन राज्यों के विलय के पश्चात् ही सम्पूर्ण जमनी का एकीकरण हो सकता था। दक्षिणी जमनी के इन राज्यों पर फ्रांस का अत्यधिक प्रभाव था। इसलिये इन राज्यों के विलय के लिये फ्रांस स युद्ध होना अनिवार्य था।

आस्ट्रिया व प्रशा युद्ध के परिणाम—आस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हुए—

1 प्राग की संधि स प्रशा को नवीन प्रदेश मिले। जिससे उसके राज्य का विस्तार हुआ। अब प्रशा व राज्य की सीमायें राइन नदी से बाल्टिक सागर तक पहुँच गई। नवीन प्रदेशों के सम्मिलित हो जाने से प्रशा की जनसंख्या में 50 लाख और क्षेत्रफल में 2500 वर्ग मील की वृद्धि हुई।

2 आस्ट्रिया का जमन राज्यों से प्रभाव समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रशा शक्तिशाली देश हो गया और वह अपने नेतृत्व में जमनी का एकीकरण करने में सफल हो सका।

3 प्रशा का कील बंदरगाह पर अधिकार हो जाने से जल सेना तथा व्यापार के क्षेत्र में भी विकास हुआ।

4 इस युद्ध ने जमनी के एकीकरण की नींव रखी। इसमें विजय प्राप्ति के पश्चात् उत्तरी जमन राज्यों का एक सघ बनाया गया, जिसका अध्यक्ष प्रशा के सम्राट को बनाया गया।

5 इस युद्ध में प्रशा की विजय होने के कारण बिस्माक ने बाहरी शत्रुओं को पराजित करने के साथ-साथ आंतरिक शत्रुओं को भी समाप्त कर दिया। इस युद्ध से पूर्व जमनी में उदारवादी स्वशासन की मांग कर रहे थे, लेकिन युद्ध में बिस्माक की सफलता के कारण इन उदारवादियों का प्रभाव समाप्त हो गया। अब उन्होंने जमनी के एकीकरण का समयन करना प्रारम्भ कर दिया। इन उदारवादियों ने राष्ट्रीय उदारवादी दल की स्थापना की। यह दल बिस्माक के वार्यों का समयन करता रहा।

6 इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् प्रशा मध्य यूरोप का एक शक्तिशाली देश बन गया।

7 इस युद्ध ने इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण सहायता दी। सार्डीनिया का राजा अभी तक आस्ट्रिया से वेनिसिया का प्रदेश प्राप्त नहीं कर सका था। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् बिस्माक ने आस्ट्रिया से वेनिसिया का प्रदेश इटली को दिलवा दिया। इससे इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ।

8 इस युद्ध का आस्ट्रिया पर घातक प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप—

- (i) आस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी के राज्या में समाप्त हो गया।
- (ii) आस्ट्रिया का साम्राज्य कम हुआ गया। इसके पश्चात् 1867 ई० में उस हंगरी को भी स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार करना पड़ा।
- (iii) इस युद्ध के पश्चात् आस्ट्रिया ने प्रतिनियतावादी नीति को छोड़कर उदारवादी नीति का पालन करना शुरू कर दिया। जब आस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने आस्ट्रिया में बसने वाली विभिन्न जातियों की भाग के अनुसार शासन में सुधार करना प्रारम्भ किया।
- (iv) आस्ट्रिया की यूरोप में अब वह प्रतिष्ठा नहीं रही जो कि इस युद्ध के पूर्व थी।
- (v) आस्ट्रिया का प्रभाव इटली के राज्यों में भी समाप्त हो गया।
- (vi) आस्ट्रिया अब यूरोप का एक शक्तिशाली देश नहीं रहा।

(9) फ्रांस—इस युद्ध का फ्रांस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय का युद्ध के पश्चात् अपनी भूल का पान हुआ। इस युद्ध में जर्मनी की विजय से फ्रांस की सीमा पर जर्मनी एक शक्तिशाली देश हो गया जो फ्रांस के लिये सिर दब बन गया। इस विजय ने नेपोलियन की आशाओं को धून में मिला दिया। उसका यह मानना था कि युद्ध लम्बा चलेगा तथा उसे मध्यस्थता करने का अवसर प्राप्त होगा। इस अतिरिक्त बिस्माक ने उम राईन का प्रदेश देने का वायदा किया था पर तु नेपोलियन को न तो मध्यस्थता करने का अवसर मिला और न ही विजय के बाद उसे राईन का प्रदेश मिला। उसकी विदेश नीति की असफलता से जनता में उसके प्रति असंतोष बढ़ने लगा। इस असंतोष को दूर करने के लिये नेपोलियन ने 1870 ई० में जर्मनी से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में जर्मनी ही विनाश को आमंत्रित किया।

(3) फ्रांस प्रशा युद्ध [सडान का युद्ध] (1870-71)—सेडान का युद्ध में आस्ट्रिया को नहीं बल्कि फ्रांस की पराजय हुई थी। नेपोलियन तृतीय ने यह सोचा था कि जब आस्ट्रिया और प्रशा युद्ध करते-करते कमजोर हो जायेंगे तब वह मध्यस्थ का काम करेगा पर तु बिस्माक ने उसे मध्यस्थता करने का मौका ही नहीं दिया। आस्ट्रिया को पराजित करने के पश्चात् प्राग सम्मेलन में बिस्माक ने नेपोलियन को न बुलाकर उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाया। इसने अतिरिक्त बिस्माक ने आस्ट्रिया के साथ संधि की उदार शर्तें रख कर उसे अपना मित्र बना दिया। इससे नेपोलियन की आशाओं पर पानी फिर गया। प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण से नेपोलियन भयभीत हो गया। क्योंकि उसकी सीमा पर एक शक्तिशाली राष्ट्र का उत्थान हो रहा था जिस वह वर्दास्ति नहीं कर सकता था।

नेपोलियन और फ्रांसासी जनता ने सेडान की पराजय को अपनी पराजय

राष्ट्रवाज जर्मनी और इटली का एकीकरण

माना। फ्रांस में यह विचारधारा तेजी से फैली कि नेपोलियन ने आस्ट्रिया प्रशासक म तटस्थ रहकर एक भयंकर भूल की है। फ्रांस की जनता यह मांग करने लगी कि "सडावा की पराजय का बदला लिया जाय" इससे फ्रांस और प्रशासक के सम्बन्ध निरन्तर बढ़ते गये। जिसने परिणामस्वरूप 1870 ई० में फ्रांस और प्रशासक के बीच भयंकर संघर्ष हुआ।

युद्ध के कारण—दूसरे युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(1) फ्रांस जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। आस्ट्रिया को पराजित करने के पश्चात् प्रशासक की गिनती यूरोप के शक्तिशाली देशों में की जाने लगी। इस युद्ध में प्रशासक की विजय से फ्रांस की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो गया था, जिसे फ्रांस अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस प्रकार फ्रांस प्रशासक की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत था।

(2) विस्माक ने नेपोलियन का यह आश्वासन दिया था कि यदि वह आस्ट्रिया प्रशासक म तटस्थ रहेगा तो उसे प्रशासक की राईन का प्रदेश देगा परन्तु युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् विस्माक ने उसे राईन का प्रदेश नहीं दिया।

(3) नेपोलियन तृतीय हीनरिच से सबसे कम बचक का प्रदेश खरीदना चाहता था परन्तु विस्माक ने उसकी योजना को अस्वीकार कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा।

(4) नेपोलियन तृतीय ने अमेरिका में मक्सिको की समस्या में हस्तक्षेप किया। इसका कारण यह था कि अमेरिका इस समय गृह युद्ध में उत्तम हुआ था। इसलिये नेपोलियन तृतीय को यह आशा थी कि वह इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे सकेगा। इसके अतिरिक्त जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को देख कर अपने खोये हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिये राज्य विस्तार के उद्देश्य से उसने मक्सिको की समस्या में हस्तक्षेप किया। नेपोलियन तृतीय ने मक्सिको में प्रजातन्त्र को मजबूत कर मक्सिमिलियन को वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया। इस समय मक्सिमिलियन की हत्या हो जाने से फ्रांस का काफी धक्का लगा। इसलिये नेपोलियन तृतीय के सामने अपनी छोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिये प्रशासक के साथ युद्ध करने का अभाव अन्य कोई विकल्प नहीं था।

(5) उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति विस्माक के अनुकूल थी। फ्रांस ने हीनरिच के प्रांतिकारियों का समर्थन किया था। इसलिये फ्रांस से नाराज था। ग्रीसिया के युद्ध में भी फ्रांस ने हमारे विरुद्ध टर्की का साथ दिया था। इसलिये फ्रांस का शत्रु बन चुका था। विस्माक ने हीनरिच के विद्रोह का दमन करने के लिये फ्रांस को सैनिक सहायता दी। इससे फ्रांस प्रशासक का घनिष्ठ मित्र बन चुका था। फ्रांस ने आस्ट्रिया प्रशासक म प्रशासक का साथ दिया। इससे फ्रांस आगे बढ़ता ही गया। इस समय फ्रांस निरक्षर विहीन था और विस्माक का फ्रांस, आस्ट्रिया, इंग्लैंड

और इटली (विस्माक ने इटली को वनशिया का प्रदेश दिनवाया था) आदि दशों की मित्रता प्राप्त थी। इंग्लिय विस्माक ने प्राप्त पर आक्रमण करने का यह उपयुक्त अवसर समझा।

(6) आस्ट्रिया प्रशा सघष स पूव फ्रास जास्ट्रिया का मित्र था। लेकिन 1866 ई० म जास्ट्रिया प्रशा सघष म नपोलियन तटस्थ रहा। जिसके कारण आस्ट्रिया की युद्ध मे पराजय हुई। इसलिए आस्ट्रिया फ्रास का शत्रु हो गया जबकि दूसरी तरफ विस्माक न आस्ट्रिया न साथ सधि म उदार शर्तें रखकर उसे अपना मित्र बना लिया। सेडोवा के युद्ध के बाद नपोलियन तृतीय फ्रास की जनता म अप्रिय होता जा रहा था। सेडोवा क युद्ध पर दीयस न प्रवस्थापिक सभा म यह कहा था कि 'सेडोवा के युद्ध म आस्ट्रिया की नही बरन फ्रास की पराजय हुई।'¹

यदि आस्ट्रिया सेडोवा के युद्ध म पराजित नही होता तो प्रशा फ्रास का भी पराजित नही कर पाता। फ्रास की जनता सेडोवा की पराजय का बदला लेना चाहती थी। नपोलियन भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त करना चाहता था। इसके लिये प्रशा स युद्ध करना अनिवार्य था। बटलमी ने लिखा है कि 'नेपोलियन ने इस युद्ध को दश की हानि और आत्मा प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति का अंतिम साधन बनाया।'

(7) दक्षिणी जर्मनी क चार राज्य बवेरिया वडेन व्यूटम्बर्ग और हेसम जमन राज्य सघष की उपक्षा कर रहे थे। दक्षिणी जर्मनी क इन राज्या पर फ्रास का बहुत अधिक प्रभाव था। विस्माक इन राज्या को अपने सघष म मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा करना चाहता था, परंतु फ्रास इसका विरोध कर रहा था। इसलिये युद्ध क अतिरिक्त अन्य कोई माग नही था।

(8) तत्कालीन कारण (स्पेन का विद्रोह) — स्पेन के विद्रोह ने फ्रास और प्रशा के बीच युद्ध अनिवार्य कर लिया। स्पेन की प्राति से फ्रास और प्रशा के सम्बन्ध इनने बटु हा चुने थे कि युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई माग नही बचा था। 1868 ई० मे स्पेन की जनता ने बहा की निरकुश शासिका रानी ईसाबेला द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस पर रानी स्पेन छोड कर भाग गई। इसके बाद स्पेन का शासक किसका बनाया जाय इस पर विवाद चलता रहा। अंत मे स्पेन की प्रातिकारी जनता ने दक्षिणी जर्मनी के राजकुमार लियोपोल्ड को स्पेन का शासक बना दिया। लियोपोल्ड प्रशा के राजवंश होहेन जोलन वंश से सम्बन्धित था। प्रशा और स्पेन के इस मिशन का नेपोलियन तृतीय ने विरोध किया।

नेपोलियन न प्रशा के शासक म यह माग की कि लियोपोल्ड को स्पेन का शासक नही बनाया जाय। जिसे उसने स्वीकार कर लिया। नेपोलियन तृतीय की यह प्रथम कूटनीतिक विजय थी परंतु वह इससे स तुष्ट नही हुआ। उसने पुन प्रशा के शासक को लिखा कि यह 'स बात का वायना करे कि भविष्य मे प्रशा के

राजवंश के किसी भी धर्मात्त को स्पन्द का शासक नहीं बनाया जायगा। विलियम प्रथम ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया। उस पर फ्रांस के राजदूत ने प्रशा के सम्राट् न 'एम्म' नामक स्थान पर बैठे की और इस विषय में चर्चा की।

विलियम प्रथम ने एम्म में विस्माक को एक तार भेजा जिसमें उसने फ्रांसीसी राजदूत को वार्ता का यौरा दिया। विस्माक उस तार का पटकर क्रुद्ध हो उठा। उसने इस श्रवण का लाभ उठाने का निश्चय किया। विस्माक ने तार का कोई शब्द न बदलने हुये सतिप्त करने समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। तार के इस सक्षिप्त रूप को पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माना फ्रांस के राजदूत ने प्रशा के सम्राट् का धार अपमान किया है। दूसरा तरफ फ्रांस की जनता को ऐसा आभास हो रहा था कि प्रशा के सम्राट् ने फ्रांस के राजदूत का धार अपमान किया है। विस्माक की इस चाल से दोनों देशों की जनता भड़क उठी और युद्ध की मांग करने लगी। फ्रांसीसी जनता का सहावा की पराजय का बदला लेना चाहती थी। इसलिये नपोलियन तृतीय ने 1⁹ जुलाई 1870 को प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

युद्ध की घटनाएँ — युद्ध की घोषणा हात ही दक्षिणी जर्मनी के चारों राज्यों ने प्रशा का साथ देने का निश्चय किया। इसमें प्रशा की भविष्य शक्ति में वृद्धि हुई। दूसरा ओर फ्रांस अकेला था। उसका साथ न लेने दक्षिणी जर्मनी के राज्यों ने और न यूरोप के किसी देश ने दिया। आस्ट्रिया फ्रांस-प्रशा युद्ध में इस लिये तटस्थ रहा क्योंकि आस्ट्रिया-प्रशा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहा था। दूसरा कारण यह था कि विस्माक ने संधि की उदार शर्तें रख कर आस्ट्रिया को अपना मित्र बना लिया।

फ्रांस बिना किसी तयारी के युद्ध में कूद पड़ा था। इसलिए प्रशा की सनाओ ने फ्रांस का कई बार पराजित किया। विस्माक ने 2 सितम्बर 1870 ई० को मेडान के युद्ध में फ्रांसीसी सनाओं का निर्णायक रूप से पराजित किया। इस समय नपोलियन को 80 000 सैनिकों के साथ आत्म समर्पण करना पड़ा। विस्माक ने नपोलियन को बन्दी बना लिया। जैसे ही फ्रांस की पराजय का सूचना परिशत में पहुँची, वहाँ शान्ति हो गई। इस शान्ति के फलस्वरूप द्वितीय साम्राज्य का अन्त हुआ और फ्रांस में गेम्बेट्टा के नेतृत्व में तृतीय गणतन्त्र की स्थापना की गई। गेम्बेट्टा ने युद्ध जारी रखा। अन्त में विस्माक की सनाओं के सामने पैरिस को भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। एक इतिहासकार ने फ्रांस-प्रशा युद्ध के बारे में लिखा है कि— यदि यूरोप के इतिहास में कोई युद्ध निरर्थक कहा जा सकता है तो वह युद्ध फ्रांस के प्रशा के मध्य हुआ, जो 1870 ई० में लड़ा गया था।

18 जनवरी, 1871 में विस्माक ने वर्साय के शीश महल में जर्मन साम्राज्य के संविधान की घोषणा की। प्रशा के सम्राट् विलियम प्रथम का जर्मन साम्राज्य

का सम्राट बनाया गया। दक्षिणी जर्मनी के राज्यों के उत्तर जर्मन संधि में सम्मिलित हो जाने से जर्मनी के एकीकरण का वायं पूरा हो गया। नवीन जर्मन साम्राज्य की राजधानी बर्लिन बनाई गई। बिस्माक को नये साम्राज्य का प्रथम चांसलर बनाया गया। इस प्रकार बिस्माक ने जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा कर दिया।

फ्रेंचफट की संधि (1871 ई०) — युद्ध की समाप्ति के पश्चात् फ्रांस और जर्मनी के बीच 10 मई 1871 को फ्रेंचफट की संधि का मुख्य शर्तें निम्न लिखित थी —

- (1) फ्रांस को अल्सास और लोरेन के प्रदेश एवं स्ट्रासबर्ग के सामरिक महत्व के किले प्रशा को देने पड़े।
- (2) फ्रांस ने युद्ध क्षति पूर्ति के रूप में 20 बिलियन फ्रांको की अवधि में प्रशा को दान स्वीकार कर लिया।
- (3) क्षति पूर्ति की रकम वसूल होने तक जर्मनी अपना सना उत्तरी फ्रांस में बनाये रखेगा जिसका खर्च फ्रांस को उठाना पड़ेगा।

फ्रांस-प्रशा युद्ध के परिणाम — इस युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में फ्रांस की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। इतिहासकार हनशा ने इस युद्ध के महत्व के बारे में लिखा है कि— 'संसार के इतिहास में बहुत कम ऐसी घटनाएँ हुईं जिनके तत्कालीन परिणाम इतने महत्वपूर्ण हुए हों, जितने की सीडान की रणभूमि में फ्रांस की पराजय से हुए।'¹

इस युद्ध का फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस पर विदोष रूप से प्रभाव पड़ा।

1—जर्मनी पर प्रभाव —

- (i) इस युद्ध में प्रशा की विजय होने से दक्षिणी जर्मन राज्यों को उत्तर जर्मन राज्य संधि में मिला दिया गया। जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया।
- (ii) अब जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में यूरोपीय रणमंच पर प्रकट हुआ।
- (iii) जर्मनी को अल्सास के लोरेन के प्रदेश मिल जाने से उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और साम्राज्य का भी विस्तार हुआ क्योंकि ये दोनों प्रदेश लोहे के कोयले के प्रमुख केन्द्र थे।
- (iv) फ्रांस को पराजित करने के पश्चात् बिस्माक यूरोपीय राजनीति का केन्द्र बिन्दु बन गया। केटलबी ने लिखा है कि— 'फ्रांस और प्रशा

के युद्ध ने जर्मनी का यूरोप की मालकिन और बिस्माक को जर्मनी का स्वामी बना दिया।

2—फ्रांस पर प्रभाव —

- (1) इस युद्ध में फ्रांस के पराजित हो जाने से यूरोपीय राजनीति में उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई।
- (ii) फ्रांस को विवश होकर फ्रैंकफर्ट जैसी अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े।
- (iii) फ्रांस को अपने लोहे और कोयले के प्रमुख केंद्र अल्सास और लोरेन के प्रदेशों को प्रशासकों को देने पड़े।
- (iv) नेपोलियन तृतीय का पतन हो गया।
- (v) इस युद्ध में फ्रांस के पराजित होने से पेरिस में त्रासित हुई। जिसके फलस्वरूप गेम्बेटा के नेतृत्व में फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना की गई।

3—प्रथम महायुद्ध का कारण — इस युद्ध के परिणामस्वरूप शक्ति सन्तुलन विगड़ गया। जिसके कारण आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी और इटली दो शक्तिशाली राष्ट्र यूरोपीय खगमच पर प्रकट हुए। फ्रांस अपनी इस पराजय को कभी नहीं भूल सका और बदला लेने का अवसर ढूँढता रहा। फ्रांस को इस अवसर में वंचित रखने के लिए बिस्माक ने कूटनीतिक संधियाँ काताना बुना। जिनके कारण यूरोप परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गया और अन्ततः प्रथम विश्व युद्ध का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार फ्रांस-प्रशासक युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के बीज निहित थे।

4—इटली पर प्रभाव — इस युद्ध से इटली का एकीकरण पूरा हो गया। जब फ्रांस और प्रशासक युद्ध प्रारम्भ हुआ तो नेपोलियन तृतीय ने रोम से फ्रांसीसी सेना बुला ली। फ्रांसीसी सेना के रोम छोड़ते ही विक्टर एमैन्युअल द्वितीय ने रोम पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हो गया। इटली ने रोम को अपनी राजधानी घोषित किया।

5—रूस पर प्रभाव — इस युद्ध का रूस पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। रूस ने फ्रांस और प्रशासक युद्ध का लाभ उठा कर बाल्टिक सागर पर अधिकार कर लिया।

नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी का एकीकरण का माग प्रशस्त कर दिया था। उसे बिस्माक ने 1870 ई० में पूरा कर दिखाया। बिस्माक ने जर्मनी के एकीकरण का काम किया। इतना ही नहीं उनके प्रयासों से जर्मनी यूरोप का एक शक्तिशाली देश बन गया। बिस्माक अपने युग का एक महान कूटनीतिज्ञ और

अवसरवादी राजनीति का था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि "राष्ट्र का जन्म युद्ध भूमि में होता है ।¹

इटली और जर्मनी का एकीकरण एक ही समय में पूरा हुआ । इन दोनों ही देशों में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण ही एकीकरण सम्भव हो सका था ।

जर्मनी और इटली के एकीकरण में असमानताएँ — यद्यपि जर्मनी और इटली का एकीकरण एक ही समय में पूरा हुआ परन्तु इसके आधारभूत सिद्धांत में अन्तर था । जर्मनी और इटली के एकीकरण में प्रमुख असमानताएँ निम्नलिखित थी —

- (1) बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण "रक्त और लौह नीति पर चलते हुए सैनिक शक्ति के आधार पर किया जबकि इटली के एकीकरण के लिए अनेक देश भक्ता ने बलिदान दिए थे और जनतंत्र प्रणाली पर इटली का एकीकरण किया गया था ।
- (2) जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क अकेले ने पूरा कर दिया जबकि इटली का एकीकरण मजिगा काबूर गरीबाल्डी और विक्टर एमेनुअल और अन्य कई देश भक्ता के बलिदान से पूरा हुआ ।
- (3) इटली में जनमत संग्रह के द्वारा पीडमोण्ट - सार्डीनिया राज्य में विभिन्न राज्यों का विलय किया गया जबकि प्रशासन जर्मनी के विभिन्न राज्य बिना जनमत संग्रह के मिला दिये गए ।
- (4) इटली का एकीकरण विदेशी सहायता के कारण सम्भव हो सका । काबूर ने फ्रांस की सहायता से आस्ट्रिया को पराजित किया था और फिर प्रशा की सहायता से इटली आस्ट्रिया अधिभूत वंशजिया का प्रदेश प्राप्त कर सका था परन्तु बिस्मार्क ने बिना किसी प्रकार की विदेशी सहायता के जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिखाया ।
- (5) एकीकरण के समय पीडमोण्ट — सार्डीनिया राज्य को इटली में विलय कर दिया गया परन्तु जर्मनी में एकीकरण के समय प्रशासन जर्मनी में नहीं मिला वरन् जर्मनी के अन्य प्रदेशों का प्रशासन विलय कर दिया गया ।

1— Nations are seldom born except on the battle

प्रस्तावित सप्तम पाठ्य पुस्तकें —

- 1—प्लेट जीन और डूमड—विश्व का इतिहास
 - 2—मैकनल वास—वैस्टन सिवलीजेशन
 - 3—सबाइन—ए हिस्ट्री आफ वर्ल्ड सिवलीजेशन
 - 4—कटलबी ए हिस्ट्री आफ माडर्न टाइम्स
 - 5—हेज़न—आधुनिक यूरोप का इतिहास
 - 6 पाट एण्ड टेम्परले यूरोप का इतिहास—उनीसवीं और बीसवीं शताब्दी में ।
-

साम्राज्यवाद

पन्द्रहवीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों के परिणामस्वरूप यूरोपियन देशों ने अमेरिका में अपने-अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे तथा पूर्वी दशा से भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। इस समय यूरोपियन देशों का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों से व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात् विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा तथा अच्छे माल की आवश्यकता होने लगी तो ब्रिटेन और फ्रांस आदि साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने लगे। साम्राज्यवादी देशों के द्वारा उपनिवेशों के आर्थिक शोषण को ही आर्थिक साम्राज्यवाद का नाम से पुकारा जाता है।

अमेरिकन उपनिवेशों ने साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक शोषण की नीति का विरोध किया। फलस्वरूप 19 वीं शताब्दी तक उन्होंने साम्राज्यवादी देशों के आधिपत्य से स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। 1870 ई० के पश्चात् नवीन साम्राज्यवाद का उत्कर्ष हुआ। यूरोपियन देशों ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिये उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई और कुछ ही समय में इन देशों ने अफ्रीका को बांट लिया। इसके अतिरिक्त यूरोपियन देशों ने एशिया और प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित किये।

इस उपनिवेश की होड़ में फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन सबसे आगे थे किन्तु छोटे-छोटे यूरोपियन देशों ने भी अपने-अपने उपनिवेश स्थापित कर लिये थे। पुराने साम्राज्यवाद के समय यूरोपियन देशों का मुख्य उद्देश्य राजनतिक प्रभुसत्ता और व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था परन्तु 19 वीं शताब्दी के नवीन साम्राज्य में यूरोपियन देशों का मुख्य उद्देश्य अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना था।

साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण

1—आर्थिक कारण —

(1) विशाल पैमाने पर उत्पादन — औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड

की भाँति फ्रांस, जर्मनी, और इटली आदि देशों का भी औद्योगिक विकास हुआ। इन देशों में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा। इसलिए इस अतिरिक्त उत्पादन का खाने के लिए यूरोपियन देशों ने बाजारों की खोज प्रारम्भ की और नव-नव उपनिवेशों की स्थापना का प्रयास किया।

यूरोपियन देशों ने सस्ते विदेशी माल से अपने व्यवसायों की रक्षा करने के लिये मुक्त व्यापार की नीति को त्याग कर संरक्षण की नीति लागू की। इतना ही नहीं यूरोपियन देशों ने बाहर से आने वाले माल पर इतने भारी चुँगी कर लगा दिये कि वह स्वदेश के माल से काफी महंगा हो गया। इस प्रकार यूरोपियन देशों ने अपने अतिरिक्त उत्पादन को खाने के लिये उपनिवेशों की खोज प्रारम्भ कर दी।

(ii) पूँजी की अधिकता — औद्योगिक क्रान्ति के कारण कई देशों के पास बहुत अधिक पूँजी एकत्रित हो चुकी थी। क्रान्ति से पूर्व अमेरिका और स्पेन जैसे पूँजीपति देश पिछड़े देशों को ऋण दिया करते थे। इसमें उनकी काफी पूँजी नष्ट हो जाती थी क्योंकि पिछड़े देश उस ऋण को नहीं चुकाते थे। इसलिये पूँजीपतियों ने यह निश्चय किया कि वे अपने देश के उपनिवेशों में रेल, धान और व्यापार आदि से पूँजी लगायेंगे। जिसमें उन्हें लाभ भी अधिक मिलेगा और पूँजी भी नष्ट नहीं होगी।

पूँजीपतियों ने यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया कि यदि अफ्रीका के नए लोगों में कपड़े पहनने की रुचि पैदा कर दी जाय तो उद्योग में भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इस प्रकार उद्योगपतियों और व्यापारियों को भारी मुनाफा प्राप्त होने की आशा थी। इसलिए व्यावसायिक वर्ग ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वह उपनिवेशों की स्थापना करें अथवा पिछड़े हुए देशों पर अधिकार करें ताकि वे अपने माल को इन देशों के बाजारों में बेचकर भारी मुनाफा कमा सकें। पूँजीपतियों का यह भी विश्वास था कि उन देशों में मजदूरी मस्ती है और प्रति योगिता भी कम है। इसलिए वे मनचाहा मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे।

(iii) यातायात के साधनों का विकास — औद्योगिक क्रान्ति के कारण यातायात के साधनों के क्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास हुआ। सामुद्रिक यातायात के विकास के कारण अथ शीघ्रता के साथ सस्ती दरों पर कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता था और अपना तैयार माल बेचा जा सकता था। भाप से चलने वाले जहाजों तथा सामुद्रिक तार के आविष्कार ने देशों की आपसी दूरी को बहुत कम कर दिया।

(iv) कच्चे माल की आवश्यकता — औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् यूरोपियन देशों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। जैसे-जैसे औद्योगिक विकास

होता गया, वैसे वैसे कच्चे माल की माग बढ़न लगी। यह कच्चा माल उपनिवेशों से अथवा पिछड़े हुए देशों में प्राप्त हो सकता था।

साईजिल और मोन्ग बनाते के लिए रवड की आवश्यकता थी। पन्ड्री और मिला की स्थापना के लिए लोह की आवश्यकता थी। कपड़े तयार करने के लिए कच्ची रूई और ऊन की आवश्यकता थी। ये सारी चीजें पिछड़े और अविश्वसित देशों से बड़ी सस्ती दरों पर मिल सकती थीं। इस प्रकार उपनिवेशों के धर्म और खनिज सम्पत्तियों में यूरॉपियन देशों को आर्थिक दृष्टि से मशरूत बना दिया।

साम्राज्य के विकास के कारण अन्न की माग भी बढ़ने लगी। जर्मनी और जापान की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। इस वृद्धि हुई जनसंख्या के जीवन निर्वाह के लिये अन्न की आवश्यकता थी। इनके अतिरिक्त जो यूरॉपियन देश सिर्फ औद्योगिक विकास करते रहे वहाँ अन्न की उपज कम हो गई। अनाज की माग की पूर्ति सिर्फ पिछड़े हुए देश ही कर सकते थे। इसलिये यूरॉपियन देशों ने यहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित करने प्रारम्भ कर दिये इस नये साम्राज्यवाद का आधार आर्थिक था। इसलिये इस आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहा जा सकता है।

2—सामाजिक कारण—इंग्लैण्ड और जर्मनी में औद्योगिक विकास पूणता प्राप्त कर चुका था। इन देशों के बुत्तीन परिवारों तथा महत्वाकांक्षी युवकों ने यह देखा कि हम अपने देश में शीघ्रता से उन्नति करने के अवसर प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इसलिये उन्होंने उपनिवेशों की सेनाओं एवं प्रशासकीय सेवाओं में भर्ती होना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि वहाँ पर उन्नति के अवसर आसानी से मिल सकते थे। अतः साहसी युवकों ने नौकरी और व्यवसाय के लिये उपनिवेशों में जाकर स्वीकार कर लिया।

3—राजनतिक कारण —

(1) सामरिक महत्त्व के स्थानों पर अधिकार—यूरॉपियन देश अपना साम्राज्य का विस्तार एवं व्यापार की सुरक्षा करना चाहते थे। इसलिये इन देशों ने नौसेना के अङ्गु स्थापित किये और सामरिक महत्त्व के स्थानों पर अधिकार करने के प्रयास किये ताकि उनकी शक्ति में वृद्धि हो और उनकी राजनीतिक स्थिति सशक्त हो सके।

फ्रांस ने अफ्रीका में सब प्रथम साइप्रस और केप के प्रदेश पर अधिकार किया। इसके पश्चात् इटली ने लीबिया के प्रदेश पर अधिकार किया। सामुद्रिक मार्गों की खोज हाने से यूरॉपियन राष्ट्रों ने उन स्थानों पर अधिकार करने का प्रयास किया, जहाँ उनका जहाज कोयला और पानी ले सकते थे और विश्राम कर सकते थे। इसलिये यूरॉपियन देशों ने समुद्र तटों और माग में पडन वाले द्वीपों पर अधिकार कर लिया।

साम्राज्यवाद

(ii) अस्तव्यवस्था में वृद्धि—औद्योगिक शक्ति के कारण सभी देशों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। यह बढ़ती हुई जनसंख्या को बर्सा के लिए यूरोपियन देश नये उपनिवेशों की तलाश करने लगे। जहाँ जमीन यूरोपियनों के लिए उपलब्ध न थी वहाँ-वहाँ साम्राज्यवाद की स्थापना आगामी महोत्सव के लिए। 1971 ई० के बाद छ माघ जमान का भी अभाव और ब्राजील में जाकर उस समय। यह समय यूरोपियन देशों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। "गतिमान यूरोपियन" न भ्रमन देशों में लानेवाला गया के बर्सा पर रोष लगायी। उदाहरणार्थ—मध्य राज्य अमेरिका और कनाडा न चीनियों और जापानियों के बर्सा पर प्रतिवृत्त लगा दिया। "यूरोपीयन" आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों न भी चीनियों और जापानियों के बर्सा पर रोष लगाने। इस तरह यूरोपियनों की शक्ति में निरंतर वृद्धि रह।

(iii) धार्मिक मतभेदों का योग—यूरोपियन देशों में साम्राज्यवाद के प्रसारण के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहा। यूरोप के पाश्चिमी विच्छेद हुए देशों में और विच्छेदी हुई जातियों में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जात थे। यह विच्छेद हुए लोगों को ईसाई बनाकर अपनी महत्त्वात्ता और महत्त्व का प्रचार करने के लिए प्रचार प्रसारण करने के लिए गये। कुछ पादरियों ने तो अपने देशों की सेवा की परन्तु अधिकांश अपने उद्देश्य को भूल गये।

अधिकांश पाश्चिमी न पहले विच्छेद हुए देशों और विच्छेदी हुई जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इनके परभाव यूरोपियन राज्यों को यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी। यह पादरी अपना देश की सरकार से रक्षा करने के बहाने उन विच्छेद हुए प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए अनुग्रह करते थे। पादरी नये नये उपनिवेशों की स्थापना में इंग्लिश प्रयत्न रहते थे क्योंकि उन्हें इन प्रदेशों में ईसाई धर्म का प्रचार करना का अवसर प्राप्त हो जाना था। पादरियों के माध्यम से विच्छेद देशों में यूरोपियन मूल की धारणा होनी थी इसलिए यूरोपियन इन पादरियों की बहुत सहायता करते थे। अनेक ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि पादरियों ने प्रत्यक्ष रूप में साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करने में अपना सहयोग प्रदान किया। डॉ० लिथिंगटन ने ब्रिटिश सरकार को अफ्रीका में साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सके। जमान पादरी की बरी ने साम्राज्यवाद की आरंभ अधिक लोगों को झुकाया।

(iv) उग्र राष्ट्रीयता—यूरोपियन देशों की राष्ट्रीयता की भावना न साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। प्रोवेन्सर हॉ और बोल ने कहा है कि उग्र राष्ट्रीयता ने नवीन साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र जर्मनी और इटली की उग्र राष्ट्रीयता के पक्ष में चले रहा था। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य के स्वामी थे तो दूसरी तरफ इटली

और जमनी के पास एक भी उपनिवेश नहीं था। इसलिये जमनी और इटली में भी उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई। जमनी और इटली भी ब्रिटेन और हालैण्ड की भाँति विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना चाहत थे। यहाँ की जनता राष्ट्र के गौरव और अभिमान की रक्षा के लिये अपनी अपनी सरकारों पर उपनिवेशों की स्थापना के लिये दबाव डाल रही थी।

फ्रांस प्रशा के हाथों से हुई अपनी पराजय की क्षतिपूर्ति करने के लिये नये नये उपनिवेशों की स्थापना कर अपने साम्राज्य में वृद्धि करना चाहता था। इंग्लण्ड अवसर का लाभ उठाकर साम्राज्य में और वृद्धि करना चाहता था। 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में यूरोपियन देशों में उपनिवेशों की स्थापना को लेकर होड़ प्रारम्भ हुई।

(v) असभ्य लोगों को सभ्य बनाना—यूरोपियन देशों में यह भावना विद्यमान थी कि उनकी सभ्यता और सस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इस भावना ने यूरोपियन देशों में साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। यूरोपियन देशों में इस विचारधारा का प्रसार हुआ कि असभ्य एवं पिछड़ी हुई जातियाँ और अशिक्षित लोगों में अपनी सभ्यता और सस्कृति के प्रचार द्वारा उनका सभ्य बनाना और उनका विकास करना प्रमुख कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पालन के लिए यूरोपियन देशों ने प्रचार प्रारम्भ कर दिये। उदाहरणार्थ रूडवाड ने इस बात का प्रचार किया कि काल लाना को सभ्य बनाना गोरों लोगों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की ओर जनता तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यूरोपियन विद्वानों ने अनेक ग्रन्थ लिखीं। इन प्रयासों के कारण साम्राज्य विस्तार की भावना को बड़ा बल मिला।

उपरोक्त सभी कारणों से 1870 ई० बाद यूरोपियन देशों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना को लेकर होड़ प्रारम्भ हुई। इसलिये यूरोपियन देशों में उत्तरी अफ्रीका, मध्य और सुदूरपूर्व के प्रदेशों में अपने-अपने उपनिवेश स्थापित किये और वहाँ अपनी-अपनी सस्थाओं की स्थापना की। इस प्रकार यूरोपियन देशों में उपनिवेशों के आर्थिक साधनों का लाभ उठाया। दूर-दूर तक उपनिवेश स्थापित करने और साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया।

अफ्रीका का विभाजन—19वीं शताब्दी की सबसे विशिष्ट उल्लेखनीय घटना अफ्रीका की खोज एवं यूरोपियन देशों द्वारा उसका विभाजन करना था। मेरियट ने लिखा है कि यूरोपियन देशों द्वारा अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना आधुनिक साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अफ्रीका को 'अध महाद्वीप' भी कहा जाता था। यहाँ पर कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता था। यह महाद्वीप यूरोप से नजदीक होते हुए भी यूरोपियन देशों का ध्यान इसकी ओर सबसे बाद में गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियन देशों ने सामुद्रिक मार्ग की खोज की और भारत व चीन में अपने-अपने

उपनिवेश स्थापित किये । इस समय यूरोप के बड़े-बड़े राज्य उपनिवेशों की स्थापना में उत्साह में इतना लगे हुए थे कि उनका मानना था कि जिस प्रकार पत्र पत्र ही पड़ सके अलग हो जाता है उसी प्रकार उपनिवेशों का विकास होते ही व उनके साम्राज्य से अलग हो जायेंगे । औद्योगिक क्रांति के पश्चात् यूरोपियन देशों की विचार धारा में परिवर्तन हुआ । इस क्रांति के कारण विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा । इसलिये इस अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए एक अच्छे माल की प्राप्ति के लिए यूरोपियन देशों को नये-नये बाजार खोजने पड़े । फलस्वरूप नवीन साम्राज्यवाद औपनिवेशिक विकास के रूप में प्रकट हुआ ।

फरीन लिखा है कि जिन देशों के पास अनिरीक्त पूँजी है और निर्मित माल को बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता है । उन्हीं देशों के लिये औपनिवेशिक साम्राज्य लाभदायक होता है । रेम्जेम्पूर ने लिखा है कि यह नवीन साम्राज्यवाद आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक व सांस्कृतिक रूप में विश्व पर छाया गया ।

मध्य अफ्रीका की खोज—1869 ई० में स्वेज नहर के निर्माण के पश्चात् अफ्रीका का महत्व बढ़ा यूरोपियन देशों के कुछ साहसी नाविकों ने अफ्रीका के तटीय भागों की खोज की परन्तु अफ्रीका की खोज में सबसे अधिक योगदान लिविंग्स्टन और स्टेनलिन का रहा । वेल्जियम के शासक लियोपोल्ड ने अफ्रीका की खोज करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की । इस संस्था ने अफ्रीका की खोज में बहुत सहायता की । मुनरो सिद्धांत के अनुसार अमेरिका में साम्राज्यवाद को प्रसार करना संभव नहीं रहा तो यूरोपियन देशों की दृष्टि में अफ्रीका का महत्व और अधिक बढ़ गया ।

1878 ई० के बर्लिन सम्मेलन में यूरोपियन देशों ने अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर अधिकार करने के बारे में बातचीत की । 1882 ई० की बारडो मधि के पश्चात् यूरोपियन देशों में अफ्रीका के विभाजन को लेकर होड़ प्रारम्भ हुई । वेल्जियम में स्थापित संस्था ने कांगो प्रदेश की खोज की । शीघ्र ही यूरोपियन देश इस पर अधिकार करने के लिये लूट खसोट करने लगे ।

अफ्रीका का शांतिपूर्वक विभाजन करने के लिए 1884 ई० में यूरोपियन देशों का बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भाग लिया । इसमें सभी यूरोपियन देशों को समान रूप में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए । इस प्रकार व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया । इस सम्मेलन में यह भी निश्चित किया गया कि अफ्रीका के किसी भी प्रदेश पर किसी भी यूरोपियन देश का अधिकार नहीं माना जायगा जबकि यह उस प्रदेश पर अधिकार करने के पश्चात् अन्य यूरोपियन देशों को सूचित करे । इस प्रकार बर्लिन सम्मेलन के बाद सभी यूरोपियन देशों ने अफ्रीका के अधिक से अधिक प्रदेशों पर अधिकार करने का प्रयास किया ।

और जमनी के पास एक भी उपनिवेश नहीं था। इसलिये जमनी और इटली में भी उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई। जमनी और इटली भी ब्रिटेन और हाल्लैण्ड की भाँति विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यहाँ की जनता राष्ट्र के गौरव और अभिमान की रक्षा के लिये अपनी अपनी सरकारों पर उपनिवेशों की स्थापना के लिये दबाव डाल रही थी।

फ्रांस प्रशासकों के हाथों से हुई अपनी पराजय की क्षतिपूर्ति करने के लिये नये नये उपनिवेशों की स्थापना कर अपने साम्राज्य में वृद्धि करना चाहता था। इंग्लैंड अबसर का लाभ उठाकर साम्राज्य में और वृद्धि करना चाहता था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यूरोपियन देशों में उपनिवेशों की स्थापना का लेकर हाड़ प्रारम्भ हुई।

(v) असभ्य लोगों को सभ्य बनाना—यूरोपियन देशों में यह भावना विद्यमान थी कि उनकी सभ्यता और सस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इस भावना ने यूरोपियन देशों में साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। यूरोपियन देशों में इस विचारधारा का प्रसार हुआ कि असभ्य एवं पिछड़ी हुई जातियाँ और अविश्वसित लोगों में अपनी सभ्यता और सस्कृति के प्रचार द्वारा उनकी सभ्य बनाना और उनका विकास करना प्रमुख कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पालन के लिए यूरोपियन देशों ने प्रचार प्रारम्भ कर दिये। उदाहरणार्थ रूडवाड ने इस बात का प्रचार किया कि काल लोगों को सभ्य बनाना और लोगों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की ओर जनता तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यूरोपियन विद्वानों ने अनेक ग्रन्थ लिखीं। इन प्रयासों के कारण साम्राज्य विस्तार की भावना को बड़ा बल मिला।

उपरोक्त सभी कारणों से 1870 ई० बाद यूरोपियन देशों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना को लेकर होड़ प्रारम्भ हुई। इसलिये यूरोपियन देशों में उत्तराफ्रीका, मिश्र और सुदूरपूर्व के प्रदेशों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किये और वहाँ अपनी-अपनी संस्थाओं की स्थापना की। इस प्रकार यूरोपियन देशों में उपनिवेशों के आर्थिक साधनों का लाभ उठाया। दूर दूर तक उपनिवेश स्थापित करने और साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया।

अफ्रीका का विभाजन—19वीं शताब्दी की सबसे विशिष्ट उल्लेखनीय घटना अफ्रीका की खोज एवं यूरोपियन देशों द्वारा उसका विभाजन करना था। मेरियट ने लिखा है कि यूरोपियन देशों द्वारा अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना आधुनिक साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अफ्रीका को अधःमहाद्वीप भी कहा जाता था। यहाँ पर कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में पदा होता था। यह महाद्वीप यूरोप से नजदीक होते हुए भी यूरोपियन देशों का ध्यान इसकी ओर सबसे बाद में गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियन देशों ने सामुद्रिक मार्ग की खोज की और भारत व चीन में अपने अपने

उपनिवेश स्थापित किये। इस समय यूरोप के बड़े-बड़े राज्य उपनिवेशों की स्थापना में उत्साह में इसलिए भाग नहीं ले रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि जिस प्रकार फल पकत ही पेड़ से अलग हो जाता है उसी प्रकार उपनिवेशों का विकास होते ही व उनके साम्राज्य से अलग हो जायेंगे। औद्योगिक क्रांति के पश्चात् यूरोपियन देशों की विचार धारा में परिवर्तन हुआ। इस क्रांति के कारण विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इसलिये इस अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए एक अच्छे माल की प्राप्ति के लिए यूरोपियन देशों को नये-नये बाजार खोजने पड़े। फलस्वरूप नवीन साम्राज्यवाद औपनिवेशिक विचारों के रूप में प्रकट हुआ।

फेरी ने लिखा है कि जिन देशों के पास अनिश्चित पूँजी है और निश्चित माल की बचत के निश्चित बाजारों की आवश्यकता है। उन्हीं देशों के लिये औपनिवेशिक साम्राज्य लाभदायक होता है। रोजेम्बूर ने लिखा है कि यह नवीन साम्राज्यवाद आर्थिक राजनीतिक सैनिक व सांस्कृतिक रूप में विश्व पर छा गया।

मध्य अफ्रीका की खोज—1869 ई० में स्वेज नहर के निर्माण के पश्चात् अफ्रीका का महत्व बढ़ा यूरोपियन देशों के कुछ साहसी नाविकों ने अफ्रीका के तटीय भागों की खोज की परन्तु अफ्रीका की खोज में सबसे अधिक योगदान लिविंग्स्टन और स्टैनलिन का रहा। वेल्जियम के शासक लियोपोल्ड ने अफ्रीका की खोज करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने अफ्रीका की खोज में बहुत सहायता की। मुनरो सिद्धांत के अनुसार अमेरिका में साम्राज्यवाद को प्रसार करना संभव नहीं रहा तो यूरोपियन देशों की दृष्टि में अफ्रीका का महत्व और अधिक बढ़ गया।

1878 ई० के बर्लिन सम्मेलन में यूरोपियन देशों ने अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर अधिकार करने के बारे में बातचीत की। 1882 ई० की बारडो संधि के पश्चात् यूरोपियन देशों में अफ्रीका के विभाजन को लेकर होड़ प्रारम्भ हुई। वेल्जियम में स्थापित संस्था ने कांगो प्रदेश की खोज की। शीघ्र ही यूरोपियन देश इस पर अधिकार करने के लिये लूट खसोट करने लगे।

अफ्रीका का शान्तिपूर्वक विभाजन करने के लिए 1884 ई० में यूरोपियन देशों का बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भाग लिया। इसमें सभी यूरोपियन देशों को समान रूप से व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। इस सम्मेलन में यह भी निश्चित किया गया कि अफ्रीका के किसी भी प्रदेश पर किसी भी यूरोपियन देश का अधिकार तभी माना जायेगा जबकि वह उस प्रदेश पर अधिकार करने के पश्चात् अन्य यूरोपियन देशों का सूचित करे। इस प्रकार बर्लिन सम्मेलन के बाद सभी यूरोपियन देशों ने अफ्रीका के अधिक से अधिक प्रदेशों पर अधिकार करने का प्रयास किया।

आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े महाद्वीप का विभाजन बहुत कम समय में हुआ गया। इसके विभाजन को लेकर विभिन्न देशों में तनावपूर्ण सम्बन्ध घबराव रहे परन्तु जैसा एशिया व अमेरिका में युद्ध हुआ वसा अफ्रीका के विभाजन के लिए कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। जब जब भी युद्ध की सम्भावनाएँ पैदा हुईं तो कूटनीति के आधार पर उम समस्या का हल ढर दिया गया। उस प्रकार यूरोपीयन देशों में बहुत कम वर्षों में अफ्रीका का विभाजन पूरा कर लिया।

1 जर्मनी और अफ्रीका—जर्मनी औपनिवेशिक साम्राज्य की दौड़ में दर से सम्मिलित हुआ। बिस्मार्क की उपनिवेशों में रुचि नहीं थी। वह तो जर्मनी को सिर्फ महाद्वीपीय शक्ति बनाये रखना चाहता था परन्तु 1890 में बिस्मार्क का पतन के बाद जर्मनी भी उपनिवेश की दौड़ में शामिल हो गया। इसका कारण यह था कि जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय 'विश्व नीति' का पालन कर रहा था और उपनिवेशों में उसकी काफी रुचि थी।

जब बेल्जियम ने कांगो के प्रदेश पर अधिकार कर लिया तो जर्मनी के उद्योगपतियों और धर्म प्रचारकों का ध्यान अफ्रीका की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने जर्मन सरकार पर यह दवाव डाला कि वह भी अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करे। इसलिये जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने अनेक जर्मन व्यक्तियों को अफ्रीका के सरदारों के पास संधियाँ करने के लिये भेजा। काल पीटर जर्मनी का पहला व्यक्ति था, जिसने पूर्वी अफ्रीका में 60 हजार वर्ग मील का भू-भाग प्राप्त किया और अफ्रीका में जर्मनी की ईस्ट अफ्रीका कम्पनी की स्थापना की। इस कम्पनी में तीन चार वर्षों में दो लाख वर्ग मील भू-भाग पर अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र का नाम टेमानिका रखा गया। इसी प्रकार जर्मनी ने 1883 ई० में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में एक टयूनिंस की स्थापना की। जर्मनी की सरकार ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की। जर्मनी ने अफ्रीका में कम्बोस टोगालण्ड जादि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया।

2 फ्रांस अफ्रीका—फ्रांस भी इस उपनिवेशित साम्राज्य की दौड़ में शामिल हो गया। उससे उत्तरी अफ्रीका और अल्जीरिया में अपने उपनिवेश स्थापित किये। वह मिश्र में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था परन्तु अंग्रेजों के विरोध के कारण उसे सफलता नहीं मिली। फ्रांस ने 1857 ई० में पूर्वी अफ्रीका में सोमा लीलण्ड के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। 1869 ई० में एक फ्रांसीसी ने स्वेज नहर का निर्माण किया और उसके बहुत शेयर खरील लिये। स्वेज नहर के प्रश्न पर इंग्लण्ड और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। इटली के विरोध के बावजूद भी फ्रांस ने 1881 ई० में टयूनिंस के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। मोरक्को में गार्सकर का द्वीप सूडान व कांगो नदी के तटीय प्रदेशों के लिये फ्रांस और ब्रिटेन में झगड़े हुए परन्तु इन प्रदेशों का अधिकांश भाग फ्रांस को मिला।

3 इटली और अफ्रीका—इटली का एकीकरण 1871 ई० में हुआ। उसका

साम्राज्यवाद

भी यह च्छा थी कि अफ्रीका में अपन उपनिवेश स्थापित करे। उत्तरी अफ्रीका से इटली का सम्बन्ध प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। प्राचीन काल में उत्तरी अफ्रीका के भागों पर रोमन साम्राज्य का अधिकार था। इसलिये इटली एकीकरण के परवाह अपन प्राचीन गौरव को पुन प्राप्त करने के लिये उत्तरी अफ्रीका के इन हिस्सा पर अधिकार करना चाहता था। इटली के उपनिवेशों की लौह में शामिल हान से पहले ही यूरोपियन देश उत्तरी अफ्रीका के अनन्य भागों पर अधिकार करने लगे।

इटली ट्युनिशिया के प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था। जब फ्रांस ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया तो वह निराश हो गया। इससे क्षुब्ध होकर इटली फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुट संधि में सम्मिलित हो गया। अतः इटली ने मध्य हीन प्रदेशों पर अधिकार करने का निश्चय किया। इटली ने 1870 ई० में इरिट्रिया पर और 1889 ई० में सोमाली लण्ड के एक भाग पर अधिकार कर लिया। 1889 ई० में एबीसीनिया पर अधिकार करने के लिये आक्रमण किया परन्तु उसे असफलता ही हाथ लगी। 1912 ई० की संधि के अनुसार ट्रिपोली लीबिया और सिरैनाका के प्रदेशों पर इटली का अधिकार हो गया।

4 पुतगाल और अफ्रीका—1870 ई० से पूर्व पुतगाल पूर्व-पश्चिमी अफ्रीका की कुछ वस्तियाँ पर अधिकार कर चुका था। इस क्षेत्र में कुछ ही समय में उसने अंगोला नामक प्रांत पर भी अधिकार कर लिया। पुतगाल अपने साम्राज्य की सीमाओं में मिलने हुए अफ्रीकन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था परन्तु उसे सफलता नहीं मिली।

5 स्पेन और अफ्रीका—स्पेन भी औपनिवेशिक साम्राज्य की दौड़ में शामिल हुआ। उसने अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में छोटे छोटे भू-भागों पर अधिकार कर लिया।

6 बेल्जियम और अफ्रीका—बेल्जियम ने भी अफ्रीका में कांगोबेसिन के उपनिवेशों में अधिकार कर लिया था। इसने अनिश्चित उसने अन्य कई उपनिवेश स्थापित किये।

7 इंग्लैण्ड और अफ्रीका—ब्रिटेन को विश्व में विशाल साम्राज्य का निमाण करने में सफलता मिली। प्रोटेक्टर एजेंसी केन्द्रों के लिये ही कि विश्व के भिन्न भिन्न भागों में ब्रिटिश साम्राज्य बहुत तीव्र गति से फैला।

अफ्रीका में सबसे ज्यादा उपनिवेश इंग्लैण्ड के पास थे। प्रारम्भ में इंग्लैण्ड का अफ्रीका में कोई उपनिवेश नहीं था, परन्तु जब हालैण्ड ने ब्रिटेन को बर्नबोलीनी का प्रांत दिया तब से इंग्लैण्ड ने यहाँ औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना में दृष्टि सेना प्रारम्भ कर दिया। दक्षिणी अफ्रीका में 40 लाख वर्ग मील के भू-भाग पर अफ्रीका का अधिकार हुआ गया। बाइर मुल्द के फ्लोरेंस इंग्लैण्ड का ट्रांसवाल, बोरेन्ज, प्रोटेक्टर, नटाल तथा कुछ अन्य छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार हुआ गया।

इंग्लैण्ड ने अफ्रीका में मिश्र के प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। इसका कारण यह था कि नेपालियन के मिश्र आक्रमण के कारण अंग्रेज भावघान हो गये थे और भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिये मिश्र का बहुत अधिक महत्व था। डिजरेली के समय इंग्लैण्ड ने स्वेज नहर के बहुत से शेयरस खरीये। 1882 ई० में जब मिश्र का लागा न विदेशिया के विरुद्ध विद्रोह किया तो इंग्लैण्ड ने अकेले ही इस विद्रोह को कुचल लिया। परिणामस्वरूप मिश्र पर उसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया।

इसके पश्चात् इंग्लैण्ड ने सूडान के प्रदेश पर अधिकार करने का निश्चय किया। यह प्रदेश मिश्र के दक्षिण में स्थित है। इसका अधिकांश भाग रेगिस्तान है। सूडान पर मिश्र के शासन का अधिकार था। 1885 ई० में सूडान के लोगों ने मिश्र के विरुद्ध विद्रोह कर लिया। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने खारतूम नामक स्थान पर अंग्रेज सेनापति जनरल गाल्डन की भी हत्या करनी। इसको बहाता बना कर अंग्रेज सरकार ने 1898 ई० में सूडान पर अधिकार कर लिया।

अफ्रीका में अंग्रेज व्यापारियों द्वारा स्थापित कम्पनियां न भी नये नये उपनिवेशों की स्थापना की। कुछ ही समय में अंग्रेजों का अफ्रीका के नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट और गेम्बिया आदि प्रदेशों पर अधिकार हो गया। पूर्वी अफ्रीका में अंग्रेजों ने युगांडा, जजीबार और मोमाली लैण्ड के प्रदेशों तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। नॉर्म रोड नामक व्यक्ति ने उत्तरी और दक्षिणी रोडेसिया पर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार स्थापित करवा दिया।

इस प्रकार अंग्रेजों ने अफ्रीका में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अफ्रीका के चौथे हिस्से पर अंग्रेजों का अधिकार था। इसलिए अफ्रीका को तृतीय अंग्रेज साम्राज्य के नाम से पुकारा गया।

इस तरह यूरोपियन देशों ने अपने अपने ढंग से अफ्रीका का विभाजन पूरा कर लिया। अफ्रीका के सबसे ज्यादा भाग पर ब्रिटेन और फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। आश्चर्य की बात यह थी कि इतने बड़े महाद्वीप के विभाजन को लेकर यूरोपियन देशों में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। यूरोपियन देशों में इस विभाजन को लेकर मतभेद अवश्य हो गये थे। उन मतभेदों का समाधान के माध्यम से सुलझा लिया गया।

एशिया में साम्राज्यवाद

1। अफ्रीका और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में आधुनिक साम्राज्यवाद का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इससे पहले यूरोपियन देश इन दोनों क्षेत्रों पर इतना अधिक प्रभाव स्थापित नहीं कर सके थे। 1870 ई० से 1914 ई० तक के बीच यूरोपियन देशों ने इन दोनों क्षेत्रों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर अपना सिक्का जमा लिया।

1. इंग्लैण्ड और एशिया—भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अंग्रेजी राज्य की स्थापना की। इस कम्पनी के गवर्नर बर्माईव न प्लासी के युद्ध (1757) में बंगाल के नवाब गिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। 1757 ई० से 1857 ई० तक तो यहाँ के समय में इस कम्पनी ने सम्पूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध अमनोप व्याप्त था। इसलिए उन्होंने 1857 ई० में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रारम्भ कर दिया।

यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीयों के इस स्वतन्त्रता प्राप्ति के विद्रोह का बुरी तरह से कुचल दिया परन्तु इस समय की समाप्ति के पश्चात् भारत में कम्पनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर शासन का काम ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। 1877 ई० में ब्रिटेन की सरकार ने स्वयं नहर कम्पनी के बहुत बड़े शेयर खरीद कर भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा करी।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बर्मा एक स्वतन्त्र राज्य था। उस पर आठ वर्षों का शासन शासन कर रहे थे। यूरोपियन व्यापारियों ने बर्मा के समुद्री तटों पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। 1824 ई० में बर्मा और अंग्रेजों के बीच प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और बर्मा को बाध्य होकर संधि करने पड़ी। इस संधि के अनुसार बर्मा को अराकन और तनेसरिम के प्रदेश अंग्रेजों को देने पड़े। 1852 ई० में अंग्रेजों और बर्मा के बीच द्वितीय युद्ध हुआ। जिसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई। इस विजय के फलस्वरूप दक्षिणी बर्मा पर उनका अधिकार हो गया। 1885-86 ई० तक सम्पूर्ण बर्मा अंग्रेजों के अधीन हो गया और बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। अंग्रेजों ने सामारिक महत्त्व के कारण रगूम के बन्दरगाह पर अपना सैनिक अड्डा स्थापित किया।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन को यू. गाइना तथा योर्निफो द्वीप के अधिकांश भाग पर अधिकार करने में सफलता मिली। 1824 ई० में अंग्रेजों ने मलाया के साथ एक संधि की। इस संधि के अनुसार मलाया प्रदेश पर उनका अधिकार मान लिया गया।

अंग्रेजों ने चीन में अपना साम्राज्य प्रसार करने का प्रयास प्रारम्भ कर लिया था। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम युद्ध 1839-42 ई० तक लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने चीन को बुरी तरह से पराजित कर संधि करने के लिये विवश किया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् चीन और ब्रिटेन के बीच नानकिंग की संधि हुई। इस संधि के अनुसार चीन को अपने पाँच बन्दरगाहों में अंग्रेजों को व्यापार करने की सुविधाएँ देनी पड़ी। इसके बाद भी ब्रिटेन कोई न कोई बहाना बनाकर चीन से युद्ध करता रहा और वहाँ व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करता रहा।

(2) फ्रांस और एशिया—फ्रांसीसी यात्रारियो न 1863 ई० मे इंडो चाइना मे फ्रांसीसी साम्राज्य की नींव रखी। धीरे धीरे सम्पूर्ण इंडोचाइना पर फ्रान्च न अधिकार कर लिया। 1862 65 ई० के बीच फ्रांस ने चीन म अपने साम्राज्य का प्रसार किया और वहा पर व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त की।

(3) जमनी और एशिया—विलियम द्वितीय ने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। 1900 ई० तक जमनी न चीन के शा तुंग प्रान्ठ पर अधिकार कर लिया था तथा प्रशांत महासागर के कुछ टापुओ पर भी जमनी का अधिकार हो गया था।

(4) हालण्ड और एशिया—हालण्ड के डचो न मालाबार लका, मलक्क, बोर्नियो और श्याम जादि द्वीपो पर अधिकार कर लिया। कालांतर म मालाबार और लका का द्वीप अंग्रेजो ने अधिहृत कर लिया। 19वीं शतादी म ईस्ट इण्डीज (आधुनिक इंडोनेशिया) पर भी हालण्ड क डचो न अधिकार कर लिया था।

(5) पुतगाल और एशिया—पुतगाल न पूर्वी द्वीप समूह क निम्नो द्वीप के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। पुतगालियो न भारत की सीमा पर गोआ दमन और ड्यू मे अपनी व्यापारिक कोटिया स्थापित की। 16वीं शता दी म पुत गालियो न मकाओ द्वीप म भी अपनी वस्तिया स्थापित कर दी थी, जिसक फलस्वरूप चीन के साथ उनका व्यापार प्रारम्भ हो गया। धीरे धीरे पुतगाली चीन म अपना प्रभाव बढाने का प्रयास करते रह।

(6) स्पेन और एशिया—फिलिपाइन द्वीप समूह म सबसे पहले पुतगाल ने अपनी वस्तिया स्थापित की थी पर तु स्पेन पहला दश था जिम फिलिपाइन द्वीप समूह पर अधिकार करने म सफलता मिली। स्पेन ने 1571 ई० मे फिलिपाइन पर अधिकार किया और वह 1898 ई० तक इस द्वीप समूह पर शासन करता रहा। इसक पश्चात संयुक्त रा य अमरिका ने इस द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया।

(7) रूस की साम्राज्यवादी नीति—18वीं शता दी मे रूस ने साइबेरिया में प्रसार प्रारम्भ किया। 19वीं शतादी के मध्य तक वह सम्पूर्ण साइबेरिया पर अधिकार करने म सफल हुआ। 1858 ई० म रूस ने आमूर नदी क उत्तर क चीनी भाग, प्रशांत महासागर और युसुरी नदी के बीच क भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1880 ई० म रूस ने तुर्किस्तान और आर्मेनिया पर अधिकार कर लिया। 1898 ई० मे रूस ने चीन से पोर्ट आथर का बंदरगाह प्राप्त किया। 1904 ई० म उसने कारिया और मचूरिया म प्रसार करने का निश्चय किया। जिसके फलस्वरूप जापान स उसका युद्ध हुआ। युद्ध मे जापान ने रूस को बुरी तरह पराजित किया आर अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया। रूस की हार ने उसका साम्राज्य प्रसार मुद्दू पूव म रोक दिया।

(8) जापान की साम्राज्यवादी नीति—एशिया म कबल जापान ही एक

साम्राज्यवाद

ऐसा देश था, जिसने पश्चिमी देशों से सम्पर्क स्थापित कर पश्चिमी ढंग में अपना देश का विकास किया। 1894-95 ई० में जापान और चीन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में जापान ने चीन को बुरी तरह पराजित किया और सधि करने के लिये शीमोनोस्की की सधि पर हस्ताक्षर किये। इस सधि के अनुसार चीन ने कोरिया को स्वतंत्र कर दिया और उसे जापान को वारपूसा, पेन्काडोस द्वीप तथा लियाओ तुंग का प्रदेश देना पड़ा। इसके पश्चात् जापान ने कोरिया और मचूरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारम्भ किया। रूस भी इसी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। इसलिये 1894-95 ई० में रूस और जापान में युद्ध हुआ। जिसमें जापान की विजय हुई। उसके पश्चात् रूस और जापान के बीच 1905 ई० में पोर्ट्स माउथ की सधि हुई। इस सधि के अनुसार दक्षिणी सारवालीन और लिओ तुंग का प्रदेश रूस को दिया गया और पोर्ट आयर का बन्दरगाह जापान को दिया गया। कोरिया में जापानी प्रभाव रूस ने स्वीकार कर लिया और मचूरिया से रूस ने अपनी पौर्जे हटाली। 1910 ई० तक जापान ने सम्पूर्ण कोरिया पर अधिकार कर लिया और उसमें अपना साम्राज्य मिला लिया।

साम्राज्यवाद के परिणाम —

उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपियन देशों ने विश्व के विभिन्न भागों में अपने साम्राज्यों की स्थापना की। यूरोपियन देशों की सम्पत्ता और संस्कृति का उन देशों की जनता पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवाद के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हुए —

(1) उपनिवेशों का विकास — साम्राज्यवादी देशों ने एशिया और अफ्रीका के अविकसित देशों का विकास करने का हर सम्भव प्रयास किया। जिसके कारण अविकसित देशों का आर्थिक विकास हुआ। साम्राज्यवादी देशों ने इन अविकसित देशों का इसलिये विकास किया क्योंकि वे अधिक से अधिक मुताफा कमाना चाहते थे।

ब्रिटिश सरकार ने भी भारत में कई फैक्ट्रियों और मिलों की स्थापना की। यद्यपि यह सत्य है कि साम्राज्यवादी देश अपने हितों की पूर्ति के लिये उन अविकसित देशों का विकास कर रहे थे और न ही इतनी तीव्र गति से विकास किया जा रहा था जितना कि स्वतंत्र शासन में सम्भव था परन्तु फिर भी अंग्रेजों ने नये-नये यंत्रों का उपयोग कर भारत का आर्थिक विकास किया। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल भंगवाने के लिये मातायात के साधनों का विकास किया। उन्होंने सारे देश में सड़कों और रेलों का जाल बिछा दिया। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ पद्धति को लागू कर उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने उपनि-

वेशो में जनता को सतुष्ट करने के लिये शासन सम्बन्धी सुधार किये। सम्पूर्ण देश में एक समान कानून और एक समान शासन व्यवस्था की स्थापना की गई।

साम्राज्यवादी देशों के अधीन लोगों को पश्चिमी वस्तुओं का उपयोग करना प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त पश्चिमी धर्म और मनोरंजन की अनेक बातें उठोने अपना लीं। कुछ साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधिकृत देशों के समाज में 'याप्त सती' प्रथा दास प्रथा और नर मांस भक्षण जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार यूरोपियन देशों ने अपने अधिकृत देशों का विकास करने के साथ-साथ उनमें अपनी सभ्यता एवं सस्कृति का भी प्रचार किया। धीरे-धीरे अधिकृत देश प्रगति करने लगे। उन्होंने भी पश्चिमी वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास का लाभ उठाना प्रारम्भ कर दिया।

(2) राष्ट्रीय भावनाओं की जाग्रति—साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधिकृत प्रदेशों में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। जिसके फलस्वरूप उन देशों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ। अधिकृत देशों ने साम्राज्यवादी देशों के अधिपत्य से मुक्त होने के लिये 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारम्भ कर दिए। इन आंदोलनों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये प्रयास प्रारम्भ कर दिए। आंदोलनों के फलस्वरूप पिछले 32 वर्षों में भारत, ब्रह्मा मिस्र सूडान, हिन्देशिया और अफ्रीका के कई देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधिकृत जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की है वे देश भी इसका लिये प्रयास कर रहे हैं तथा उन्हें शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जायेगी।

(3) आर्थिक शोषण—साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधिकृत प्रदेशों का आर्थिक शोषण किया। वे अपने अधिकृत प्रदेशों से कच्चा माल कम से कम दरों पर प्राप्त करते थे और अपने उत्पादित माल को मनमानी दरों पर वचते थे। उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड ने अपने उद्योगों का विकास करने के लिये भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। इंग्लैण्ड की सरकार ने चीनी लोगों में अफीम खाने की सत लगाकर अपने राजनीतिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति की। साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधिकृत देशों का आर्थिक विकास अवरुद्ध कर दिया क्योंकि वे अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण अपने हितों को दृष्टिगत रखते हुए करते थे। इस आर्थिक शोषण के परिणामस्वरूप एशिया और अफ्रीका के देश दिन प्रतिदिन गरीब होते गए।

(4) उपनिवेशों की जनता पर अत्याचार—साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधिकृत प्रदेशों में अपनी सत्ता बनाय रखने के लिये जनता पर अमानुषिक अत्याचार किये। उन्होंने जनता को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। इस प्रकार के शासन में जनता अपना विकास नहीं कर सकी। इंग्लैण्ड ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिये अमानवीय अत्याचार किये। फ्रांस ने भी मोरक्को और अल्जी

रिया के राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिये वहा की जनता पर भयङ्कर अत्याचार किए। पुनर्गालिया ने अपने उपनिवेशों में अपना शासन बनाये रखने के लिये भयङ्कर राजनीतिक प्रत्याचारों का सहारा लिया।

(5) उग्र राष्ट्रीयता की भावना—साम्राज्यवाद के परिणामस्वरूप उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसलिये एक देश दूसरे देश के साथ समसाम्यो पर समभौता बनने में अपना अपमान समझा लगा।

(6) सशक्तिकरण में वृद्धि—यूरोपियन देशों ने अपने उपनिवेशों की रक्षा करने के लिये सशक्तिकरण में वृद्धि करना प्रारम्भ किया। बहुत से यूरोपियन राज्यों ने अनिवाय सैनिक शिक्षा लागू कर दी। इससे यूरोपियन देशों में शस्त्रीकरण की होड़ प्रारम्भ हुई। इस प्रकार सैनिक प्रतिस्पर्धा ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया।

(7) यूरोपियन देशों के तनावपूर्ण सम्बन्ध—यूरोपियन देशों की उपनिवेशों और साम्राज्यों की स्थापित करने के प्रश्न को लेकर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। इस प्रतिस्पर्धा में एक देश का स्वायत्त दूसरे देश के स्वायत्त से टकराया। फलस्वरूप यूरोपियन देशों के आपसी सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये।

जर्मनी और इटली इस औपनिवेशिक साम्राज्य की दौड़ में बहुत दूर तक शामिल हुए थे। ये दोनों देश भी उपनिवेशों की स्थापना करना चाहते थे। इस समय तक इंग्लैण्ड और फ्रांस विशाल साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे। इसलिये जर्मनी और इटली भी इनकी तुलना में उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। इंग्लैण्ड के पास कनाडा, मिश्र और मोरक्को को लेकर कट्टर सम्बन्ध हो गये थे। रूस के इंग्लैण्ड के साथ मध्य एशिया में अधिकार के प्रश्न को लेकर तनावपूर्ण सम्बन्ध हो गये थे। जर्मनी के टर्की में बढ़ते हुए प्रभाव और उसकी नई सैनिक शक्ति में वृद्धि में इंग्लैण्ड चिन्तित था। इस समय सभी को एक दूसरे से खतरा था। इस खतरे से अपनी रक्षा करने के लिये राष्ट्रों ने गुटबन्धियों का सहारा लिया। सबसे पहले बिस्मार्क ने जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली के साथ मिलकर एक गुट का निर्माण किया। इसके प्रत्युत्तर में फ्रांस ने रूस और इंग्लैण्ड के साथ मिलकर एक गुट का निर्माण किया। जापान फ्रांस के गुट का समर्थक था तो टर्की जर्मन गुट का समर्थक कर रहा था। इस प्रकार इन गुटबन्धियों के कारण सम्पूर्ण यूरोप दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गया जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा हो गया।

प्रस्तावित सबसे पुस्तकें

- 1—हेजल-आधुनिक यूरोप का इतिहास
- 2—वेरस, एच० जी०-दो आउट लाइन आफ हिस्ट्री
- 3—ग्रांट एण्ड टेम्परले-यूरोप का इतिहास उन्नीसवीं और 20वीं शताब्दी में।
- 4—गूच, जी० पी०-आधुनिक यूरोप का इतिहास
- 5—बेटलबी-ए हिस्ट्री ऑफ माडर्न टाइम्स

प्रथम विश्व युद्ध

'फ्रेंच प्रशियन युद्ध (1871) से लेकर प्रथम महायुद्ध का काल सशस्त्र शांति का युग है।'

बिस्माक ने रक्त और लोह की नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया था परन्तु एकीकरण के पश्चात् यह शांति का समर्थक बन गया। वह यूरोप की यथास्थिति को बनाये रखना चाहता था, ताकि नवनिर्मित जर्मनी अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। बिस्माक ने 1870 ई० में सीडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था। युद्ध समाप्ति के पश्चात् इसने फ्रांस के अल्सास और लोरेन दो महत्वपूर्ण प्रांत छीन लिये थे। यह फ्रांस का राष्ट्रीय अपमान था। बिस्माक यह भी जानता था कि फ्रांस को अवसर मिलते ही वह अपनी पराजय का बदला निश्चित रूप से लेगा। इसलिये उसे फ्रांस की ओर स हमेशा आक्रमण की चिन्ता लगी रहती थी। राइकर ने ठीक ही लिखा है कि बिस्माक जानता था कि फ्रांस अपनी पराजय का बदला अवश्य लेगा परन्तु उसे यह भी मानना था कि जब तक फ्रांस मित्रविहीन रहेगा, तब तक वह जर्मनी पर आक्रमण नहीं कर सकेगा किन्तु फ्रांस को अ य देशों से मित्रता स्थापित होत ही वह जर्मनी पर आक्रमण करेगा।

बिस्माक की विदेश नीति—1871 ई० में बिस्माक की विदेश नीति के दो मुख्य आधार थे —

- (1) बिस्माक यूरोप की राजनीति में फ्रांस को एकाकी बनाये रखना चाहता था अर्थात् फ्रांस को मित्रविहीन रखा जाये। यदि फ्रांस अ य यूरोपियन देशों से मित्रता स्थापित करे तो उसे रोका जाय। बिस्माक का मानना था कि यूरोप में शांति तभी स्थापित रह सकती थी जबकि फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध गुट का निर्माण न कर सके। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि फ्रांस अकला जर्मनी पर आक्रमण नहीं कर सकता। इसलिये बिस्माक ने यूरोपियन शक्तियों से मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने रूस,

आस्ट्रिया व इटली आदि देशों से संधिया की और इंग्लैंड के साथ भी मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखे।

(11) विस्माक यूरोप की यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में था।

(1) तीन सम्राटों के संध की स्थापना (1873)—विस्माक ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये तीन सम्राटों के संध की स्थापना की। इस संध में जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस के शासक थे। इन तीनों ही देशों के शासकों के बीच एक समझौता 1873 ई० में हुआ जो कि तीन सम्राटों के संध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते के अनुसार तीनों ही देशों के शासकों ने यह वायदा किया कि वे यूरोप में शांति बनाये रखने का प्रयास करेंगे तथा वार्ता द्वारा आपसी झगड़ों का हल निकालेंगे। विस्माक आस्ट्रिया और रूस दोनों से एक साथ संधि करने में सफल हुआ। परन्तु वह जानता था कि बाल्कन प्रदेश में दोनों के आपसी हित टकराते हैं, इसलिए उनमें अधिक समय मित्रता नहीं रह सकती।

1875 ई० में ऐसा लगन लगा कि फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध प्रारम्भ हो जायेगा। उस समय रूस ने जर्मनी की भूमिका का प्रदर्शन नहीं किया तो विस्माक ने आस्ट्रिया के साथ अपने सम्बन्ध और दृढ़ बनाने का निश्चय किया गया।

1877-1878 ई० में रूस और टर्की के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्ध में रूस विजयी हुआ और उसने टर्की को सन स्टीफनो की संधि करने के लिये विवश किया। इस संधि में रूस को टर्की के कई प्रदेश प्राप्त हुए। इंग्लैंड और आस्ट्रिया ने इस संधि का विरोध किया। इसलिये इस संधि की शर्तों पर पुन विचार करने के लिये बर्लिन में एक सम्मेलन 1878 ई० में बुलाया गया। यह सम्मेलन बर्लिन कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता विस्माक ने की। यद्यपि विस्माक ने कहा था कि मने ईमादार दलाल के रूप में अपनी भूमिका निभाई है परन्तु उसने इस सम्मेलन में रूस के विरुद्ध आस्ट्रिया के हितों की रक्षा की। इसमें रूस जर्मनी ने नाराज हो गया, क्योंकि बर्लिन कांग्रेस में उसने स्टीफनो संधि द्वारा प्राप्त कई प्रदेशों से वंचित कर दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप तीन सम्राटों का संध प्रभावहीन हो गया।

द्वि गुट संधि (1879 ई०)—बर्लिन संधि में विस्माक ने आस्ट्रिया के हितों की रक्षा कर उसे अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया था। इसलिये 1879 ई० में जर्मनी और आस्ट्रिया के बीच एक संधि हुई जो द्वि गुट संधि के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक गुप्त सैनिक संधि थी। इस संधि के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि यदि रूस आक्रमण करेगा तो दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि दोनों देशों में से कोई भी देश रूस के अलावा किसी अन्य देश से युद्ध करेगा तो दूसरा घटस्थ रहेगा। यदि रूस शत्रु की सहायता करेगा

तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस संधि से बिस्माक की रूस के साथ मित्रता समाप्त हो गई।

त्रिगुट का निर्माण (1882 ई०) — 1882 ई० में फ्रांस और इटली के बीच ट्यूनिंस के प्रदेश को लेकर मनमुटाव हो गया था। इटली ट्यूनिंस के प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था। जब फ्रांस ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया तो इटली फ्रांस से भयकर नाराज हुआ। बिस्माक ने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने गुट में शामिल कर लिया। 1822 ई० में जमनी आस्ट्रिया और इटली के बीच एक संधि हुई जिसे त्रिगुट की संधि कहा जाता है। यह संधि पाच वर्ष के लिए की गई थी परंतु समय समय इस की अवधि बढ़ती रही और इस प्रकार यह संधि 1914 के प्रारम्भ तक चलती रही।

तीन सम्राटों के संधि की पुनर्स्थापना — त्रिगुट के निर्माण से पूर्व बिस्माक ने जून 1881 ई० में तीन सम्राटों के संधि की पुनर्स्थापना की और रूस को फिर से अपना मित्र बना लिया था।

पुनरुत्थापन संधि — बिस्माक ने 1887 ई० में रूस के साथ एक सुरक्षात्मक संधि की, जो इतिहास में पुनरुत्थापन संधि (रि० इन्स्योरेम ट्रीटी) के नाम से प्रसिद्ध है।

बिस्माक की औपनिवेशिक नीति — बिस्माक ने फ्रांस का ध्यान यूरोप से हटाने के लिये उसे औपनिवेशिक साम्राज्य की दौड़ में भाग लेने के लिये प्रेरित किया। बिस्माक यह जानता था कि यदि फ्रांस उपनिवेशों के निर्माण में लग जायगा, तो वह अपनी 1870 ई० की पराजय का बदला लेना भूल जायेगा। इस औपनिवेशिक दौड़ में भाग लेने से उसके इंग्लैंड के साथ सम्बन्ध निश्चित रूप से कटू हो जायेंगे।

इंग्लैंड के साथ सम्बन्ध — बिस्माक ने इंग्लैंड के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये। उसने इंग्लैंड को लुप्त करने के लिये जर्मनी की नाविक शक्ति का विकास नहीं किया और औपनिवेशिक दौड़ में भाग नहीं लिया। बिस्माक ने स्वयं एक बार यह कहा था कि इंग्लैंड समुद्री चूहा है और जर्मनी जमीन का चूहा है। इसलिये दोनों के बीच कभी युद्ध नहीं हो सकता।

बिस्माक एक उच्चकोटि का राजनीतिज्ञ था। वह एक ऐसा जादूगर था जो पांच गेंदों से एक साथ खेलता था, जिसमें से दो हमेशा हवा में उछलती रहती थी और आवश्यकता पड़ने पर इनको भी अपने हाथों में रख सकता था। ये पांच गेंदें थी—आस्ट्रिया, रूस, प्रशा, इंग्लैंड और इटली। उसने अपनी कूटनीति से जर्मनी की सुरक्षा की थी। जर्मनी पर रूस के आक्रमण के समय आस्ट्रिया की सहायता आस्ट्रिया के आक्रमण करने पर रूस की सहायता, फ्रांस के आक्रमण होने पर इटली की सहायता, फ्रांस और रूस का संयुक्त आक्रमण होने पर आस्ट्रिया

और इटली की संयुक्त सहायता का आश्वासन प्राप्त कर लिया था। इससे यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसी गुत्थीदार व्यवस्था थी, जिसका संचालन कबन बिस्माक ही कर सकता था।

विलियम द्वितीय की 'विश्व नीति' — बिस्माक की विदेश नीति बहुत पेचीला थी। उसका उत्तराधिकारी इस व्यवस्था को नहीं चला सके। परिणामस्वरूप 1890 ई० में उसके पतन के साथ-साथ उसकी व्यवस्था भी समाप्त हो गई। 1888 ई० में कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी का शासक बना। वह राजा कदविक अधिकार में विश्वास रखता था। इसीलिए 1890 ई० तक उसने राज्य की शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उसके शासनकाल में मित्रता की स्थिति क्लिकों के समान हो गई। यह शासन कायम किसी से परामर्श नहीं करता था। उसने 1890 ई० में बिस्माक को हटा दिया था। विलियम द्वितीय बहुत महत्वावासी शासक था। वह जर्मनी को विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। उसकी इस नीति के कारण जर्मनी की इस मित्रता समाप्त हो गई और रूस ने फ्रांस से मित्रता कर ली।

बिस्माक ने रूस के साथ रिइन्स्योरेम ट्रीटी की थी। इस संधि के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि यदि जर्मनी पर फ्रांस आक्रमण करेगा तो रूस तटस्थ रहेगा। इसके बदले में जर्मनी बाल्कन प्रायद्वीप में उसके हितों का विरोध नहीं करेगा। इस संधि की अवधि 1890 ई० में समाप्त हो गई और कैसर विलियम द्वितीय ने इसे दुहराने से इन्कार कर लिया। वास्तविकता यह थी कि बाल्कन प्रायद्वीप में रूस और आस्ट्रिया दोनों के हित टकराते थे, इसीलिए जर्मनी के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह एक ही समय में अपने दोनों मित्रों के हितों की रक्षा कर सके।

कैसर विलियम द्वितीय ने जब रिइन्स्योरेम ट्रीटी को दुहराने से इन्कार कर दिया तो रूस अबेला पड़ गया। उसने नया मित्र की खोज प्रारम्भ की। इसका एक कारण यह भी था कि रूस को अपने औद्योगिक एवं मनिक विकास के लिये एक बड़ी धन राशि की आवश्यकता थी। जर्मनी ने रूस को कर्ज देने से इन्कार कर लिया था। उधर फ्रांस के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह किसी भी कीमत पर अपना एकाकीपन समाप्त करना चाहता था। इसलिये वह मित्र की खोज कर रहा था। उधर रूस भी मित्र की खोज कर रहा था। रूस ने फ्रांस से मित्रता की बातचीत प्रारम्भ की। परिणामस्वरूप 1894 ई० में रूस और फ्रांस में एक मनिक संधि हो गई। इस संधि के अनुसार यह निश्चित किया गया कि यदि दोनों पर जर्मनी या उसकी सहायता से अन्य कोई देश आक्रमण करेगा तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस संधि में लगभग 23 वर्षों का फ्रांस रूस के

मित्रता करके अपना एकाकीपन समाप्त करके मगपत हुआ। इसने बिस्माक का व्यवस्था को पगु बना दिया।

बैसर विलियम द्वितीय की नीति के कारण इंग्लैंड ने जर्मन जमनी का विरोधी बन गया अगिनु उसका विरोधी गुट का मत्स्य बनने के लिए बाध्य हो गया। बैसर विलियम ने जमनी को नोमना का विकास करके विपट टिरपिज को नोमना का सचिव नियुक्त किया। उगत 1898 ई० में तथा 1900 ई० में नोमना के विकास के लिए विशेष कानून पास किए। बगर के द्वारा नाविक शक्ति के विकास के कारण इंग्लैंड जमनी से दूर होता गया। अर शिप्टेन ने फ्रांस से मित्रता करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया।

बगर ने टर्की में इगाजत सगर बास्फोरस से बगनाद जोर पारम की घाटी तक एक रेलवे माग का निर्माण कराना प्रारम्भ किया। इस यात्रा में स्वज नहर और भारत की सुरक्षा को खतरा पदा हो गया। इससे जमनी के सम्बन्ध इंग्लैंड के साथ और बटु बन गए। इस समय दक्षिण अफ्रीका के वाशर मुद्ध में बगर ने इंग्लैंड के विरुद्ध वाशर का समर्थन किया। परिणामस्वरूप दोनों देशों के सम्बन्धों में और बटुता आ गई। इस समय इंग्लैंड ने जपान को प्रकला पाया। इस अरुत्पन को दूर करने के लिये उगत 1902 ई० में जापान के साथ संधि की।

इसके पश्चात् इंग्लैंड ने 1904 ई० में फ्रांस के साथ संधि कर ली। फ्रांस ने मिश्र में इंग्लैंड के विशयाधिकारों को स्वीकार कर लिया। इसके बन्ने में इंग्लैंड ने मोरक्को में फ्रांसीसी प्रभाव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सदिया के शत्रु इंग्लैंड और फ्रांस मित्रता के सूत्र में बंध गए। फ्रांस इंग्लैंड और रूस दोनों का मित्र था। उसके प्रयासों से 1907 ई० में तीनों राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच एक संधि हो गई जो कि राष्ट्र मंत्री के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार बगर की नाति के कारण बिस्माक के त्रिगुट के विरुद्ध विराट्ट मैत्री गुट का निमाण हो गया। बगर की नीति के अन्तर्गत दोना गुटा में तनाव बढ़ा। जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घटन — बिस्माक की सन्धि संधियों के कारण यूरोप में शस्त्रीकरण की होड प्रारम्भ हो गई। इन संधियों के कारण प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे को सन्देह और अविश्वास की दृष्टि से देखने लगा। 1906 ई० तक सम्पूर्ण यूरोप दो सम्पन्न शिविरों में विभाजित हो गया था। राष्ट्रों में तनावपूर्ण सम्बन्ध थे। कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव युद्ध प्रारम्भ कर सकता था। 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कई बार ऐसा लगा कि युद्ध प्रारम्भ हो जायगा परन्तु राजनीतिक सौदेबाजी के द्वारा युद्ध को टाउट लिया गया। उस समय घटित घटनाओं के कारण राष्ट्रों के आपसी मनमुटाव में वृद्धि हुई और वे अपने शस्त्रों में वृद्धि करने लगे। 1905

ई० स 1913 ई० तक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों का उत्पन्न हुये जिसके कारण कई बार युद्ध हुए। इन घटनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है —

1—मोरक्को सन्ध (1905 ई०) — फ्रांस का अफ्रीका के मारक्को प्रदेश में भारी व्यापारिक स्वाम्य था। 1904 ई० की डिराष्ट्र मैत्री के अनुसार ब्रिटेन ने मारक्को में फ्रांस के प्रभाव को स्वीकार कर लिया। अब फ्रांस ने मारक्को में अपनी स्थिति को मजबूत करना प्रारम्भ किया। जर्मनी का भी मोरक्को में भारी व्यापारिक स्वाम्य था। इसलिये बँसर विलियम द्वितीय ने फ्रांस के बढ़ते हुए प्रभाव का विरोध किया। 1904 ई० में बँसर ट्रेजियर की यात्रा पर गया। वहाँ पहुँच कर उसने मोरक्को की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। इस समय मोरक्को के प्रश्न को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की माँग की गई। बँसर ने फ्रांस (मोरक्को की राजधानी) के सम्राट को यह वचन दिया था कि यदि फ्रांस सम्मेलन बुलाने का विरोध करेगा तो वह उसे सैनिक सहायता देगा।

बँसर के इस वाय स फ्रांस में बड़ा रोष फना, परन्तु इस समय फ्रांस का मित्र रूस, जापान द्वारा पराजित कर दिया गया था। इसलिये फ्रांस युद्ध का खतरा माल नहीं लेना चाहता था। अतः उसे विवश होकर सम्मेलन बुलाने की माँग स्वीकार करनी पड़ी। 1906 ई० में अल्जेसिराज में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में रूस इटली आस्ट्रिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने भाग लिया। आस्ट्रिया और इटली ने जर्मनी का समर्थन किया, परन्तु ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ने फ्रांस का जोरदार शर्तों में समर्थन किया। परिणामस्वरूप मोरक्को में फ्रांसीसी प्रभाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया गया और जर्मनी को मुह की छानो पड़ी। इस सन्ध ने इंग्लैंड और फ्रांस को घनिष्ठ मित्र बना दिया। यद्यपि युद्ध टल गया, परन्तु जर्मनी ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा में बढि करने के लिए सैनिक शक्ति में वृद्धि करना प्रारम्भ किया।

मोरक्को सन्ध (1911 ई०) — 1908 ई० में मोरक्को सन्ध फिर से प्रारम्भ हुआ। इस समय कसाब्लिका में स्थित जर्मन दूतावास में कुछ फ्रांसीसी सैनिकों को अपने दूतावास में आश्रय दे दिया। इस पर फ्रांसीसी सना ने जर्मन दूतावास पर हमला कर दिया। इसमें युद्ध का वातावरण उपस्थित हो गया। इस मामले को हेग न्यायालय में भेज दिया गया। इससे यह सन्ध टल गया। 1909 ई० में जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस के प्रभाव को स्वीकार कर लिया। इसके बदले में फ्रांस ने जर्मनी को मोरक्को में कुछ व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान की।

1911 ई० में मारक्को में पुन सन्ध उठ खड़ा हुआ। इस समय घद्दा के राष्ट्रवादियों ने फ्रांस के त्रिभूद आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। फ्रांस ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिये अपनी सेना को मोरक्को में भेजा। फ्रांसीसिया की रक्षा करने के लिये मोरक्को की राजधानी फज पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने फ्रांस

की इस कायदाही का विरोध किया। उसने कहा कि फ्रांस न मोरक्को में सेना भेज कर अल्जिरिया सम्मलन के निणयो का उल्लंघन किया है। जर्मनी ने अपने व्यापारिक हिता की रक्षा के लिए 'पेर' नामक एक युद्धपोत को मारक्का के अगादीर बंदरगाह पर भेजा। फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी की इस कायदाही का विरोध किया। ब्रिटेन ने जर्मनी से कहा कि यदि उसने अपनी इस कायदाही को नहीं रोका तो वह उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा। ब्रिटेन की युद्ध की घमकी के आगे जर्मनी को झुकना पड़ा। नवम्बर में एक समझौता हुआ। जिसके अनुसार जर्मनी ने सम्पूर्ण मोरक्को में फ्रांस के प्रभाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इसके बदले में फ्रांस ने फ्रेंच कांगो के आस पास के कुछ क्षेत्र पर जर्मनी को अधिकार दे दिया।

2—बाल्कन कूट — 1878 ई० की बर्लिन संधि के अनुसार हर्जगोबिना और बोस्निया के प्रदेशों पर आस्ट्रिया को शासन करने का अधिकार दिया था। 1908 ई० में आस्ट्रिया ने इन दोनों प्रदेशों को अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया। इससे सर्बिया भयंकर नाराज हो गया। इन दोनों प्रान्तों में सर्बोंकी की आबादी अधिक थी। इसलिये सर्बिया इन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था। रूस सर्बिया का समर्थन कर रहा था जबकि जर्मनी आस्ट्रिया का। रूस की सहायता पाकर सर्बिया ने युद्ध की तयारी करनी प्रारम्भ कर दी। दूसरी तरफ जर्मनी ने आस्ट्रिया की कायदाही को उचित ठहराया। उसने रूस को चेतावनी दी कि यदि वह आस्ट्रिया के विरुद्ध सर्बिया की सहायता करेगा तो जर्मनी को बाध्य होकर आस्ट्रिया के पक्ष में युद्ध में भाग लेना पड़ेगा। रूस युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह युद्ध के लिये तैयार नहीं था। 1904-5 ई० की पराजय के बाद वह अपनी सैनिक शक्ति में सुधार नहीं कर सका था। इस समय वह इस स्थिति में नहीं था कि जर्मनी और आस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं से युद्ध कर सके। इसलिये बोस्निया सकट टल गया। यह आस्ट्रिया और जर्मनी की कूटनीतिक विजय थी और फ्रांस रूस और इंग्लैंड गुट की कूटनीतिक पराजय थी। यद्यपि यह सकट टल गया परंतु इस बार रूस में जर्मनी के विरुद्ध भयंकर असंतोष फैलने लगा।

3—बाल्कन युद्ध (i) प्रथम बाल्कन युद्ध (1912 ई०) — एक समय वह था जबकि सम्पूर्ण बाल्कन प्रायद्वीप टर्की के अधीन था। परंतु धीरे धीरे अधिकांश प्रदेश स्वतंत्र होते गये। जो प्रदेश बच गये थे, उस पर भी बाल्कन के छोटे छोटे राज्यों की आँखें लगी हुई थी। इन राज्यों ने 1912 ई० में बाल्कन संधि की स्थापना की। सर्बिया, मांटनीग्रो, बुल्गेरिया तथा यूनान आदि राज्य बाल्कन संधि के सदस्य थे। इस संधि का निर्माण टर्की के विरुद्ध सम्भावित युद्ध के लिये हुआ था।

1912 ई० में रूस के प्रोत्साहित करने पर बाल्कन संधि के सदस्यों ने टर्की

के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इसे प्रथम बाल्कन युद्ध कहते हैं। टर्की ने बाल्कन सघ के सदस्यों का युद्ध में डटकर मुकाबला किया परंतु बहुत कम अवधि में बाल्कन सघ के सदस्यां न टर्की को युद्ध में पराजित कर दिया। इस प्रथम बाल्कन युद्ध में बाल्कन सघ के सदस्यों की शानदार विजय हुई। बाल्कन युद्ध में विजय का फलस्वरूप सर्बिया की शक्ति में वृद्धि हुई। उसे कुछ प्रदेश भी प्राप्त हुये थे।

आस्ट्रिया सर्बिया के विक्रम को बर्दास्त नहीं कर सकता था क्योंकि उसे यह आशंका थी कि यदि सर्बिया एक शक्तिशाली देश बन गया तो वह एजिप्टन सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकेगा। इससे अतिरिक्त आस्ट्रिया को यह भी भय था कि उसे दक्षिण के प्रदेशों में रहने वाले स्लाव जाति के लोग सर्बिया में मिलने की मांग न करने लगे। इससे आस्ट्रियन साम्राज्य के विघटन की सम्भावनाएँ थी। इसलिए आस्ट्रिया और सर्बिया के बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध हो गया। विजित प्रदेशों के घटवारे का प्रश्न को लेकर बाल्कन सघ के देशों में मतभेद प्रारम्भ हो गया। आस्ट्रिया ने इस मतभेद को अधिक बढ़ाने में सहायता दी। प्रथम बाल्कन युद्ध की समाप्ति सम्मेलन के द्वारा ही सम्भव हो सकी। इस समय अल्बानिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

द्वितीय बाल्कन युद्ध (1913 ई०) — प्रथम बाल्कन युद्ध के बाद लन्दन में बुलाय गया सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के आपसी मतभेद स्पष्ट नजर आने लगे थे। सर्बिया स्वतंत्र अल्बानिया के निर्माण से नाराज था, इसलिये वह मेसोडोनिया पर अधिकार करना चाहता था। बुल्गेरिया ने सर्बिया की इस मांग को अस्वीकार कर दिया और सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार मेसोडोनिया पर अधिकार करने के प्रश्न को लेकर सर्बिया और बुल्गेरिया के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। इसे द्वितीय बाल्कन युद्ध कहते हैं।

बुल्गेरिया के सर्बिया पर आक्रमण करते ही रूमानिया और यूनान ने भी बुल्गेरिया पर समुक्त रूप से आक्रमण कर दिया। टर्की बाल्कन राज्यों का इस आपसी सघर्ष का लाभ उठाकर अपने छाये हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार करना चाहता था। इसलिये उसने भी बुल्गेरिया पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय बाल्कन युद्ध में बुल्गेरिया की पराजय हुई और सर्बिया तथा उसके समर्थक ग्रेस यूनान और रूमानिया की शानदार विजय हुई। इस युद्ध में सर्बिया की विजय होने के कारण बुल्गेरिया को मेसोडोनिया का अधिकांश हिस्सा उसका देना पड़ा। इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण तैयार कर दिया।

आस्ट्रिया के युवराज की हत्या और प्रथम विश्व युद्ध का खतरा—द्वितीय बाल्कन युद्ध में सर्बिया की विजय से आस्ट्रिया अप्रसन्न था। उसने सर्बिया की शक्ति को कुचलने के लिये योजनाएँ बनाना प्रारम्भ कर दिया था। आस्ट्रिया के अधिकृत

बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के प्रदेशों में रहने वाले सब जाति के लोगों ने सर्बिया में मिलने के लिये आंदोलन और तेज कर दिया था। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में 28 जून 1914 ई० को आस्ट्रिया के युवराज आर्कड्युक फ्रांसिस फर्दिनैंड की सार्वजनिक हत्या बोस्निया की राजधानी सिराजेवो में कर दी गई। इस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध को प्रारम्भ कर दिया।

प्रथम विश्व युद्ध के कारण — 19 वीं और 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये उपयुक्त वातावरण था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिये अनेक योजनाएँ भी तयार की गईं। बौद्धिक वर्ग को युद्ध की सम्भावनाएँ दिन प्रतिदिन कम लग रही थीं। 1871 ई० से 1914 ई० के बीच यूरोपियन देशों में आपस में कोई युद्ध नहीं हुआ था। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधि आये, जिसका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर युद्ध को टाल दिया गया। यदि उस समय कोई भी देश युद्ध करना चाहता तो उसका मित्र दल उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता था। आस्ट्रिया की विस्तारवादी नीति पर जर्मनी ने नियंत्रण रखा। रूस की निकटपूर्व में विस्तारवादी नीति पर इंग्लैंड और फ्रांस ने जकड़ लगाया। इसलिये बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यूरोपियन राजनेताओं और बौद्धिक वर्ग ने युद्ध को रोकने का हर सम्भव प्रयास किया। फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि 1914 ई० में ही महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। इसके प्रारम्भ होने के अनेक मौलिक कारण थे।

इतिहासकारों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को पांच भागों में बाटा है जो निम्नलिखित हैं —

- 1—उग्र राष्ट्रीयता,
- 2—आर्थिक साम्राज्यवाद
- 3—सैनिकवाद
- 4—गुप्त सैनिक सन्धियाँ
- 5—समाचार पत्रों का योगदान।

1—उग्र राष्ट्रीयता — शीपिरो ने लिखा है कि 'राष्ट्रीयता एक नवीन धर्म था जिसने मानव जाति की गम्भीर समस्याओं का उत्तेजित किया।'

फ्रांस को राज्य शक्ति ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया। इस भावना के कारण 19 वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण इसने महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसी भावना के कारण एकीकरण के पश्चात् जर्मनी और इटली भी उपनिवेशों का निर्माण करना चाहते थे। जिसने फलस्वरूप यूरोपियन देशों में उपनिवेशों की स्थापना को लेकर होड़ प्रारम्भ हुई। जर्मनी और इटली इस दौड़ में बहुत देर से शामिल हुए थे। उनके पास उपनिवेश नहीं होने से वे असंतुष्ट थे। उपनिवेशों

की स्थापना को लेकर यूरोपियन देश दो भागों में विभाजित हो गये। एक भाग में ताब दश आते थे, जो विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य व स्वामी थे जमे इंग्लैंड और फ्रांस। दूसरे भाग में वे देश आते थे, जिनके पास उपनिवेश नहीं थे, जैसे जर्मनी और इटली। इसलिये जर्मनी और इटली बड़े राष्ट्रों के मुकाबले में उपनिवेशों की स्थापना करना चाहते थे।

1890 ई० के पश्चात् जर्मन सम्राट कसर विलियम द्वितीय ने औपनिवेशिक विस्तार को अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य बनाया। इस नीति के कारण जर्मनी के सम्बन्ध इंग्लैंड के साथ कटु हो गये और जर्मनी के लिए आस्ट्रिया से समझौता बनाय रखना आवश्यक हो गया। इस सङ्घर्षित राष्ट्रियता के कारण अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशों की स्थापना का लेकर अनेक बार तनावपूर्ण वातावरण पैदा हो गया। प्रत्येक घटना के बाद राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध बिगड़ते गये। इसी राष्ट्रीयता के नाम पर बाल्कन युद्ध लड़ा गया और सिराजेवो का हत्या काण्ड हुआ। इन घटनाओं से प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया।

(2) आर्थिक साम्राज्यवाद— औद्योगिक क्रांति के पश्चात् यूरोपियन देश साम्राज्यवादी नीति पर चल रहे थे। इन क्रांति के कारण उद्योगों का विकास हुआ और विशाल पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा। इसलिये यूरोपियन देशों ने अपने माल को बेचने के लिये और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिये उपनिवेशों की खोज करने प्रारम्भ कर दी। अतः सभी यूरोपियन देशों में उपनिवेशों के निर्माण की होड़ लग गई। इस दौड़ में इंग्लैंड और फ्रांस सबसे आगे निकल गये। ये विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य के स्वामी बन गये जबकि दूसरी तरफ इटली और जर्मनी के पास कोई उपनिवेश नहीं होने से वे नवीन उपनिवेश चाहते थे। प्रत्येक राष्ट्र में उपनिवेशों की स्थापना की होड़ लगी हुई थी। इस होड़ में प्रत्येक देश एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता था।

जर्मनी की औपनिवेशिक नीति के कारण इंग्लैंड के साथ उत्तक सम्बन्ध कटु हो गये। यूरोपियन देशों ने उपनिवेशों के निर्माण को लेकर परस्पर गुटबन्दिता की। जिसके फलस्वरूप 1905 ई० में 1914 ई० तक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मकट आय। इस काल को 'दुर्घटनाओं का काल' कहा जाता है। गुटबन्धियों के कारण ही 1905 व 1911 का मोरक्का मकट एवं 1908, 1912 व 1913 का बाल्कन मकट पैदा हुआ। यद्यपि यूरोपियन देश न कूटनीति से काम लेते हुए इन मकटों को टाल लिया, जिससे यूरोपियन शांति भंग नहीं हो सकी परन्तु, प्रत्येक मकट ने इन राष्ट्राँ में भय आपसी द्वेष और आपसी मनमुटाव में वृद्धि की। जिसके फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया।

(3) सैनिक शक्ति—प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण कारण सैनिक

वाद था। इतिहासकार फे ने लिखा है कि सैनिकवाद शब्द का प्रयोग दा अर्थों में किया गया।

(1) शस्त्रों का निर्माण किया जाय।

(ii) एक ऐसे बग का प्रभुत्व स्थापित किया जाय, जो प्रत्येक समस्या को युद्ध के माध्यम से ही हल करने का प्रयास करे।

1870 ई० में बिस्माक ने फ्रांस को सीडान युद्ध में पराजित कर 200 वर्षों की रजनीति को बदल दिया। जर्मनी ने सैनिक शक्ति के द्वारा ही अपना विकास किया था और वह यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली देश बन गया था। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करने लगा। 1870 ई० के पश्चात् फ्रांस 23 वर्षों तक एकाकी रहा। बिस्माक के प्रयासों के कारण वह किसी भी यूरोपियन देशों को अपना मित्र नहीं बना सका। इसलिये उसने अपनी 1870 ई० की पराजय का बदला लेने के लिये जोर शोर के साथ शस्त्रीकरण प्रारम्भ कर दिया। दूसरी तरफ कसर जर्मनी को विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था, इसलिये उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति में वृद्धि करना प्रारम्भ कर दिया। कसर ने नौसना के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने कहा था कि "जर्मनी का नौ सैनिक बड़ा इतना शक्तिशाली होगा कि यदि सबसे अधिक बलशाली, नौ सैनिक शक्ति भी उससे सघष करेगी, तो उसकी महानता के लिये खतरा उत्पन्न हो जायेगा।"

जर्मनी द्वारा नौसैनिक शक्ति में वृद्धि करने पर ब्रिटेन उससे दूर होता गया और उसने भी अपनी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि करनी प्रारम्भ कर दी। अब जर्मनी का अनुसरण करते हुए विभिन्न यूरोपियन देशों ने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करना प्रारम्भ कर दिया। जर्मनी की भाँति अन्य देशों ने अपने यहाँ अनिवाय सैनिक संवा लागू कर दी। सभी देशों ने अपने शस्त्रों में तीव्र गति से वृद्धि करनी प्रारम्भ कर दी। प्रत्येक दश यह कहता था कि वह अपनी सुरक्षा के लिये शस्त्रीकरण कर रहा है परन्तु वास्तव में एक दूसरे के प्रति घणा और युद्ध का आशका के कारण यह होड़ लगी हुई थी। प्रत्येक देश अपने पड़ोसी देश की सैन्य वृद्धि को शका की दृष्टि से देखता था। इसके परिणामस्वरूप वह भी अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना प्रारम्भ कर देता था। शस्त्रीकरण की होड़ ने यूरोप के वातावरण को विपात बना दिया और प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण तयार कर दिया। प्रत्येक बड़े देश को अपनी सैनिक शक्ति पर गव था। इसलिये वह दूसरे राष्ट्र से संधि करने में और उसका सामने झुकने में अपना अपमान समझता था। ब्रेलिसफोर्ड ने लिखा है कि इस शस्त्रीकरण की होड़ से युद्ध प्रारम्भ हो गया।

शस्त्रीकरण की होड़ को समाप्त करने के लिये नि शस्त्रीकरण के सारे प्रयास असफल रहे। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के प्रयासों से 1899 ई० में हेग में एक सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें यूरोप के 36 देशों ने भाग लिया, परन्तु

इ गलपड और फ्रांस के विरोध के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। इसी प्रकार 1907 ई० में हेग में यूरोपियन राष्ट्रों का दूसरा सम्मेलन बुलाया गया, परंतु यह सम्मेलन भी असफल रहा। असफलता का कारण यह था कि इ गलपड अपनी नौ सैनिक शक्ति में कमी नहीं करना चाहता था। जर्मनी भी अपनी सैनिक शक्ति में कमी करने के लिये तयार नहीं था। इसलिये जब जब भी शस्त्रों की होड़ को कम करने के लिय प्रयास किये गये, तब-तब राष्ट्रों ने अपने शस्त्रों में और अधिक वृद्धि की। इसलिये नि शस्त्रीकरण के प्रयासों ने युद्ध को रोकने के बजाय इसने लिये उपयुक्त वातावरण बनाया। बेस ने लिखा है कि इस सैनिकवाद ने चार तरीकों से युद्ध प्रारम्भ करने में सहायता दी—

(i) सैनिकवाद ने राष्ट्रों में भय, आपसी द्वेष, सदेह और मनमुटाव में वृद्धि की।

(ii) प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सैनिक शक्ति पर गव था, इसलिये वह दूसरे राष्ट्र के साथ समझौता करने में अपना अपमान स्मझता था। आपसी हिंसा के समझौते भी अब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बनने लगे।

(iii) जर्मनी सभी समस्याओं को युद्ध के माध्यम से हल करना चाहता था।

(iv) शस्त्रीकरण के कारण एक नये वग के निर्माताओं का जन्म हुआ। यह वग शस्त्र में निरन्तर वृद्धि करना चाहता था। इसलिये इस वग ने सैनिक वृद्धि का वातावरण बनाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि इन शस्त्र निर्माताओं ने अपने प्रयासों से नि शस्त्रीकरण के सम्मेलनों को असफल बना दिया। उन्होंने अपने-अपने देशों में नि शस्त्रीकरण के विरुद्ध वातावरण तयार किया एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं को उभारने का प्रयास किया। इन निर्माताओं के प्रयासों के कारण ही हेग सम्मेलन असफल हो गया।

(4) गुप्त सैनिक संधियाँ—इतिहासकारों ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में गठित विभिन्न सैनिक समझौतों के कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। फ्रांस और प्रशा युद्ध से गुप्त संधियों की शुरुआत हुई। बिस्माक ने फ्रांस को मित्रहीन बनाये रखने के लिये यूरोपियन देशों के साथ सैनिक समझौते किये। 1879 ई० में बिस्माक ने ट्रिगुट संधि की। इस संधि के कारण आस्ट्रिया जर्मनी का मित्र हो गया। 1882 ई० में इटली के इस ट्रिगुट में शामिल हो जाने से यह त्रिगुट सगठन में परिणित हो गया। इससे इटली आस्ट्रिया व जर्मनी का मित्र बन गया।

बिस्माक के पतन के बाद फ्रांस ने 23 वर्ष बाद अपने एकाकीपन को समाप्त किया और 1894 ई० में उसने रूस के साथ एक संधि की। जिसे द्वि मंत्री संधि

कहा जाता है। 1904 ई० म फ्रांस ने इंग्लण्ड से संधि कर उसे अपना मित्र बना लिया। इस संधि के अनुसार दोनों ने एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया। 1907 ई० म रूस भी इंग्लण्ड और फ्रांस के गुट में सम्मिलित हो गया। इससे त्रिराष्ट्र मंत्री का निर्माण हो गया। अब इंग्लण्ड और फ्रांस को रूस सहयोगी के रूप में मिल गया। इस प्रकार 1907 ई० तक इन गुप्त सैनिक संधियों के कारण सम्पूर्ण यूरोप दो सशस्त्र शिविरों में बँट गया। बिस्माक द्वारा निर्मित त्रिगुट में जर्मनी आस्ट्रिया और इटली आदि देश थे। फ्रांस ने बिस्माक के इस गुट के विरुद्ध एक त्रिवर्गीय मंत्री गुट का निर्माण किया। जिसके सदस्य फ्रांस, रूस और इंग्लण्ड आदि देश थे। इन दोनों गुटों में परस्पर प्रतिस्पर्धा थी।

इतिहासकार बेन्स ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सम्पूर्ण यूरोप दो सशस्त्र सैनिक शिविरों में विभाजित हो गया था। ये दोनों ही गुट सैनिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली और बहुत महत्वाकांक्षी थे। इन संधियों के कारण यूरोप दो गुटों में बँट गया था। ये दोनों ही गुट आपस में प्रतिस्पर्धा रखते थे और एक दूसरे को सन्नेह और भय की दृष्टि से देखते थे। इन गुटों ने युद्ध के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिया था। इन संधियों के कारण यूरोपियन देशों में तनाव बढ़ गया।

यह सारी संधियाँ रक्षात्मक थीं परन्तु धीरे-धीरे इनका रूप आक्रामक हो गया था। इन संधियों में शांति स्थापना में भी महत्वपूर्ण सहायता थी। सगठन के एक देश को दूसरे देश की महत्वाकांक्षाओं पर अकुश लगाने में कई बार सफलता मिली। जैसे कि आस्ट्रिया की आक्रामक बाल्कन नीति को जर्मनी ने हमेशा नियंत्रण में रखा। इसी प्रकार फ्रांस और इंग्लण्ड ने रूस की महत्वाकांक्षाओं पर अकुश लगाया। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रत्येक गुट के सदस्य को एक दूसरे के मामलों में सही या गलत बात होना पर भी समझना करना पड़ता था, क्योंकि वे संधि के अनुसार ऐसा करने के लिये वचनबद्ध थे। यद्यपि यह सत्य है कि ऐसे समझना में गुट के सदस्य राष्ट्रों का अपना कोई स्वायत्त नहीं होता था परन्तु सगठन को मजबूत बनाय रखने के लिये वे इस प्रकार का समझना करते थे। उदाहरणार्थ, जर्मनी बाल्कन राजनीति में आस्ट्रिया का समझना इसलिये करता था, क्योंकि यह उसके गुट का सदस्य था। इसी तरह फ्रांस रूस की सहायता के लिये वचनबद्ध था। जर्मनी और फ्रांस दोनों का बाल्कन राजनीति में प्रत्यक्ष कोई स्वायत्त नहीं था। वे ने लिखा है कि इंग्लण्ड के सामने फ्रांस और रूस के समझना के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था।

इन गुप्त संधियों ने यूरोप के वातावरण को विपाक बना दिया। अब प्रत्येक यूरोपियन देश शस्त्रों में वृद्धि करने लगा। इसलिये युद्ध की सम्भावनाएँ दिन प्रति दिन बढ़ती गईं। कुछ देशों ने तो ये संधियाँ आक्रामक रूप प्रदान करने के लिये ही

की थीं। प्रीमम ने कहा है कि इटली और आस्ट्रिया ने सधि सगठन आक्रामक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से ही किया।

सबिया के प्रश्न से जर्मनी का कोई लेना देना नहीं था। आस्ट्रिया उसके गुट का सदस्य था, इसलिये उसे युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। जर्मनी आस्ट्रिया का समर्थन कर रहा था। इसलिये फ्रांस न सबिया का समर्थन किया। फ्रांस को यह विश्वास था कि उसके गुट का सदस्य इंग्लैण्ड उसका समयन निश्चित रूप से करेगा। यदि हम गम्भीरता से सबिया के काय का अध्ययन करें तो पता चलता है कि यह कोई ऐसा काय नहीं था कि जिसमें युद्ध होने की नीवत घ्रा जाये। इसके आतरित सबिया ने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया था। इतना ही नहीं आस्ट्रिया द्वारा रखी गई अपमानजनक शर्तों को भी स्वीकार कर लिया था। परंतु जर्मनी चाहता कि युद्ध हो। इसलिए उसने आस्ट्रिया को सबिया पर आक्रमण करने के लिये प्रोत्साहित किया। उसने आस्ट्रिया को नीचा दिखाने के लिये युद्ध की घोषणा कर दी। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह युद्ध आस्ट्रिया और सबिया के बीच न होकर त्रिगुट और त्रिराष्ट्र मंत्री के बीच लड़ा जा रहा था। हेरजिमरमा ने ब्रिटिश राजदूत से कहा था कि यह (युद्ध) गुटबंदी प्रणाली के कारण हुआ है जो आधुनिक युग का अभिशाप है।"

(5) समाचार पत्रों का योगदान—ग्राफेसर फे ने लिखा है कि समाचार पत्र और साहित्य ने यूरोप में कटु वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण सहायता दी। जिसके कारण प्रथम विश्वयुद्ध का वातावरण तयार हो गया। सभी यूरोपियन देशों के समाचार पत्रों ने खोवमत को विपाक्त बना दिया। कुछ यूरोपियन समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय भावनाओं को उमाड़ा। दूसरे देशों के बारे में गलत प्रचार किया और शांति कायम करने वाली बातों का विरोध किया। इस समय कई देश युद्ध चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान कर लिया जाए। परंतु समाचार पत्रों के कारण सफलता नहीं मिली।

इंग्लैण्ड और जर्मनी के सम्बन्धों को सुधारने के लिये अनेक प्रयास किये गये परंतु समाचार पत्रों के कारण ये प्रयास असफल रहे। जर्मनी के समाचार पत्रों ने सैनिक शक्ति को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। 1914 ई० में आस्ट्रिया के युवराज की हत्या की समस्या इसलिए शांतिपूर्वक हल नहीं हो सकी क्योंकि आस्ट्रिया और सबिया के समाचार पत्रों ने वातावरण को विपाक्त बना दिया था।

6—अन्य कारण—

(1) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सङ्कट—प्रथम महत्वपूर्ण सङ्कट 1905 ई० में मोरक्को में उपस्थित हुआ। इस सङ्कट के कारण इंग्लैण्ड और फ्रांस ने साथ जर्मनी के सम्बन्ध कटु हो गये। 1911 ई० में मोरक्को सङ्कट पुनः उठ खड़ा हुआ। इस समय जर्मनी ने मोरक्को में हस्तक्षेप किया परंतु इंग्लैण्ड और फ्रांस के सामने उसे

झुकना पड़ा। इससे जमनी के इंग्लण्ड और फ्रांस के साथ सम्बन्ध और अधिक कटु हो गए।

दूसरा महत्वपूर्ण सक्कट बाल्कन प्रायद्वीप में पैदा हुआ। आस्ट्रिया ने बल्गिया का उल्लंघन करते हुए 1908 ई० में बोस्निया और हर्जोगोविना पर अधिकार कर अपन साम्राज्य में मिला लिया। सर्बिया ने इसका विरोध किया परन्तु जमनी के हस्तक्षेप के कारण यह सक्कट टल गया। बोस्निया सक्कट के कारण आस्ट्रिया और जमनी के सम्बन्ध फ्रांस रूस और इंग्लण्ड के साथ कटु हो गये।

तीसरा महत्वपूर्ण सक्कट 1912-1913 के दो बाल्कन युद्धों से उत्पन्न हुआ। पहला बाल्कन 1912 ई० में हुआ। जिसमें टर्की के विरुद्ध बाल्कन राज्यों की विजय हुई। विजित प्रदेशों के बँटवारे के प्रश्न को लेकर बाल्कन राज्यों में 1913 ई० में द्वितीय बाल्कन युद्ध हुआ। इन युद्धों से आस्ट्रिया के सर्बिया के साथ सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये। इन घटनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध का माग प्रशस्त कर दिया।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय सन्धियों का अभाव—उस समय युद्ध की सम्भावनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी किंतु ऐसी कोई सन्धि नहीं थी जो युद्ध को रोक सके और समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर सके। यद्यपि रूस ने इस ओर प्रयास किया था, परन्तु असफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभाव के कारण सभी राष्ट्र स्वैच्छाचारी बनते जा रहे थे। इसलिये युद्ध को रोक जाना असम्भव था।

(iii) तत्कालीन कारण—1914 के पूर्व युद्ध के लिये वातावरण तैयार हो चुका था, केवल चिंगारी की आवश्यकता थी, जो इस युद्ध को प्रारम्भ कर सके। इस समय आस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेण्ड की अप्रत्याशित हत्या 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सिराजेवो में सर्बियन क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई। इस घटना ने चिंगारी का काम किया, जिसके कारण विस्फोट हो गया। जांच से यह पता चला कि हत्या करने वाला व्यक्ति आस्ट्रिया का नागरिक था और बोस्निया का निवासी था। फिर भी आस्ट्रिया ने राजकुमार की हत्या के लिये सर्बिया को दोषी ठहराया और उसे हत्यारों के राष्ट्र की सजा दी।

डेरी और जमनी ने लिखा है कि यह सारा हत्याकाण्ड आज भी एक रहस्य है। एक दिन में दो बार राजकुमार की हत्या का प्रयास किया परन्तु फिर भी उसकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की गई। उसकी अत्येष्टी क्रिया में विदेशी राजदूतों को शामिल नहीं होने दिया गया। आस्ट्रिया ने इस सारी घटना की जांच की। उसे इस हत्याकाण्ड में सर्बिया का हाथ नजर नहीं आ रहा था, परन्तु आस्ट्रिया तो सर्बिया से बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा में था। इसलिये उसने यह अवसर उपयुक्त समझा। आस्ट्रिया को यह भय था कि नहीं रूस सर्बिया की सहायता न करे।

इसलिये जर्मने जमनी से पहले पूछा कि यदि रूस सर्बिया की सहायता करेगा तो जमनी आस्ट्रिया को सहायता देगा या नहीं। जमनी ने आस्ट्रिया को सहायता देने का आश्वासन दिया। इससे पश्चात् 23 जुलाई 1914 ई० को आस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी देते हुए एक पत्र लिखा। जिसमें हत्याकांड का सारा उत्तरदायित्व उम पर डाला गया। आस्ट्रिय, न सर्बिया को पत्र में उल्लिखित सारी मांगों को 48 घंटे में स्वीकार करने के लिये कहा। पत्र की शैली और उसकी शर्तें इतनी कठोर थी कि कोई भी स्वाभिमानो राष्ट्र उसे स्वीकार नहीं कर सकता था। हेजेन न लिखा है कि आस्ट्रिया ने पत्र की भाषा कठोर थी और मांगों को अधिनायकवाद की तरह स्वीकार करने के लिये सर्बिया को बाध्य किया गया था।

रूस, इंग्लैण्ड और फ्रांस ने अवधि बढ़ाने के लिये प्रयास किया परंतु यह सफलता नहीं मिली। इसलिये उन्होंने सर्बिया को लिखा कि वह आस्ट्रिया के पत्र का उत्तर शांतिपूर्वक और समझौतावादी तरीके से लिखे। इंग्लैण्ड ने रूस में महाशक्तियों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा परंतु जमनी के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली।

सर्बिया ने आस्ट्रिया की एक मांग के अलावा अन्य सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। अस्वीकार की जाने वाली मांग यह थी कि जब सर्बिया की अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया जायेगा तो सर्बिया के न्यायालय में इस हत्याकांड की जांच के लिये आस्ट्रिया के अधिकारी भी न्यायाधीश के रूप में बैठेंगे। सर्बिया इस बात के लिये तैयार था कि यदि आस्ट्रिया चाहे तो इस मामले को हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में या महान शक्तियों के समक्ष रख दे परंतु वह तो युद्ध चाहता था। इसलिये उसने 28 जुलाई 1914 ई० को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। रूस ने अपनी सेनाओं को सर्बिया की सहायता के लिये भेज दिया और अपने सैनिक अभियान भी प्रारम्भ कर दिये।

जमनी ने रूस को चेतावनी दी कि वह अपनी सनातें जर्मन मोर्चा से हटाने परंतु रूस ने इस चेतावनी को अस्वीकार कर लिया। इसलिये जर्मनी ने पहली अगस्त 1914 को रूस पर आक्रमण कर लिया। रूस और फ्रांस की संधि के अनुसार फ्रांस ने रूस की सहायता करने का निश्चय किया। इसलिये जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर लिया।

अभी तक इंग्लैण्ड युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। जर्मनी बेल्जियम के मांग से फ्रांस पर आक्रमण करना चाहता था। बेल्जियम फ्रांस और जमनी के बीच स्थित था। इसलिये जमनी ने बेल्जियम से मांग की कि वह उसकी सेनाओं को जाने के लिए मांग दे। बेल्जियम ने जर्मनी की इस मांग को अस्वीकार कर लिया। इस पर जर्मन सेनाओं ने जबरन बेल्जियम में प्रवेश किया। अतः उसने इंग्लैण्ड से सहायता करने की अपील की।

इ गलण्ड की सुहानुभूति फ्रांस और रूस के साथ थी परन्तु वह उनकी सहायता करने के लिये बाध्य नहीं था। इ गलण्ड के इस युद्ध में भाग लेने की कोई सभावना नहीं थी क्योंकि सर्बिया के प्रश्न से उसना कोई लेना देना नहीं था। जब 4 अगस्त 1914 ई० को जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो इ गलण्ड ने उसी दिन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर लिया। इ गलण्ड द्वारा युद्ध में भाग लेने का मुख्य कारण यह था कि 1839 ई० की मद्रि क अनुमति बेल्जियम की स्वतंत्रता की रक्षा का वचन दे चुका था। जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तो बेल्जियम ने इ गलण्ड से सहायता की अपील की। इसलिये इ गलण्ड को बेल्जियम की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये युद्ध में भाग लेना पड़ा। इसके अतिरिक्त वह जर्मनी की नौ सैनिक शक्ति से भी चिंतित था। इसलिये इ गलण्ड ने जर्मनी का बेल्जियम की सीमा से सना हटाने की चेतावनी दी। जर्मनी ने अस्वीकार करने पर इ गलण्ड ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। कुछ दिनों बाद टर्की और बुल्गेरिया ने जर्मनी का पक्ष लेकर युद्ध प्रारम्भ कर दिया। जापान ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध प्रारम्भ कर दिया। 1917 ई० में अमेरिका ने भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध छेड़ लिया। इटली ने अपने गुट के सदस्यों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। इस प्रकार यह युद्ध विश्व-व्यापी बन गया।

प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व — वर्साय की संधि की धारा 231 के अनुसार मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी को युद्ध के लिये दोषी ठहराया और सारी जिम्मेदारी उसके सिर पर डाल दी। प्रत्येक देश ने युद्ध का उत्तरदायित्व एक दूसरे पर डालने का प्रयास किया। युद्ध के प्रारम्भ होने के समय जर्मनी ने वाइट बुक प्रकाशित की। इसमें 27 तारा को उद्धृत करते हुए उसने यह स्पष्ट किया कि रूस के आक्रमण से अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये उसे युद्ध में भाग लेना पड़ा।

इसी प्रकार इ गलण्ड ने 6 अगस्त को ब्लू बुक निकाली। जिसमें यह दर्शाया गया था कि उनके विदेशमंत्री प्रे ने युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया परन्तु आस्ट्रिया और जर्मनी के कारण शांति के प्रयास असफल रहे और उस युद्ध में भाग लेना पड़ा। इस पुस्तक में अपने मत की पुष्टि के लिये उसने 150 से अधिक पत्रों को उद्धृत किया। इसी प्रकार रूस ने ओरेंज फ्रांस ने यलो, आस्ट्रिया ने लाल बुक प्रकाशित कर यह स्पष्ट किया कि युद्ध की जिम्मेदारी उसकी न होकर उस देश की है जिसके विरुद्ध वह युद्ध कर रहा है।

वास्तव में इसके लिये प्रत्येक देश दोषी था। सर्बिया इस युद्ध के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार था। आस्ट्रिया के युवराज की हत्या में सर्बिया के कुछ अधिकारियों का हाथ था। एव सर्बिया का सरकार इस बात को जानती थी। इस प्रकार सर्बियों ने युद्धका माग प्रशस्त कर दिया। आस्ट्रिया का यह दाव था कि उस सर्बिया के उत्तर से स तोप नहीं हुआ और उस पर आक्रमण कर दिया। इससे रूस को भी सर्बिया

प्रथम विश्व युद्ध

की सहायता करने का अवसर मिल गया। रूस ने आस्ट्रिया और जर्मनी के विरुद्ध सैनिक तयारी करके युद्ध के क्षेत्र को विस्तृत बना दिया। उसकी रूस कायदाहीन समझौते के द्वारा बंद हो गये।

इस युद्ध के लिये सबसे अधिक श्रेणी जर्मनी या उसका पहला दोष तो यह था कि उसने बिना सोचे समझे आस्ट्रिया को सहायता करने का आश्वासन दे दिया। उसने इंग्लैण्ड, फ्रांस और इटली आदि देशों की प्रतिश्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया और युद्ध करने की योजना तैयार कर ली। इस प्रकार जर्मनी ने आस्ट्रिया का सहायता का आश्वासन केवल रूस को उगाड़ने का काम किया। बस बिलय की विश्व नीति भी युद्ध के लिये उत्तरदायी थी। उसने इस नीति पर चलते हुए जर्मनी की नैतिक शक्ति का तर्जो से विकाम किया। उसने इस नीति के कारण मारकोव मकदमों द्वारा। उसने बर्लिन वगैरह रेलवे का निर्माण काय प्रारम्भ किया। उसके तयारी से जो राष्ट्र एक दूसरे के कण्टर शत्रु थे, वे अब मित्रता में मूढ हो गये। अंतर की नीति के कारण विस्माक द्वारा निर्मित त्रिगुट का पतन हो गया और त्रिदोष मंत्री संधि का उदय हुआ। इसलिये जर्मनी को इस युद्ध के लिये सबसे बड़ा दोषी माना जा सकता है। फिर, भी उसने आस्ट्रिया और सर्बिया के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों को सीमित करने का प्रयास अवश्य किया।

इंग्लैण्ड ने इस युद्ध को टालने तथा समस्या का शांति पूरा ढंग में समाधान करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। फ्रांस ने रूस को इसलिये सहायता देने का निश्चय किया क्योंकि उस पुनर्स्थापना की आशा थी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जर्मनी यकीन विधेय या किसी एक देश पर युद्ध का उत्तरदायित्व नहीं ढाला जा सकता। इनके लिये सभी देश दोषी थे।

क्या यह युद्ध टाला जा सकता था?—यूरोपियन देशों को 1914 ई० का युद्ध अप्रत्याशित लगा। यूरोप का कोई भी देश न तो विश्व युद्ध के लिए तयार था और न ही किसी देश का यह आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध हो जायेगा। युद्ध प्रारम्भ होने के अन्तिम समय तक जर्मनी ने युद्ध को सीमित रखने का प्रयास किया।

जर्मनी ने इंग्लैण्ड के द्वारा किये गये प्रयासों का इसलिये विरोध किया क्योंकि वह अपने मित्र आस्ट्रिया का स्पष्ट रूप से समर्थन देना चाहता था। रूस किसी बड़े युद्ध के लिये तयार नहीं था। उसे तो फ्रांस से सहायता मिलने की ही आशा नहीं थी। इंग्लैण्ड ने युद्ध का टालने का हर सम्भव प्रयास किया। उसी के प्रयासों से सर्बिया ने आस्ट्रिया की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया था। इस समय यूरोपियन देशों को यह उम्मीद नहीं थी कि आस्ट्रिया के युवराज की हत्या को लेकर प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो जायेगा। इस समय यूरोपियन

देशों में परस्पर, भय आगका और मनमुटाव इतना हो गया था कि वे एक दूसरे की इच्छाओं को सही रूप से नहीं समझ पा रहे थे। उस समय यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था होती तो शांति पूरा ढंग से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। उस प्रकार की न तो कोई संस्था थी और न ही शांतिविरण।

निष्कर्ष — यूरोपियन देशों की सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि युद्ध को आगे टाला जा सकता था, उस एक दम रोहना सम्भव नहीं था। उग्र राष्ट्रीयता की भावना, गुप्त सैनिक सन्धियाँ और शस्त्रों की होड़ आदि ने प्रथम विश्व युद्ध का माग प्रशस्त कर दिया।

महायुद्ध की घटनाएँ — 1914 ई० में विश्व युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व सम्पूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। मित्र राष्ट्र (Allied Powers) इस गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूमानिया, यूनान, चीन, क्यूबा, पनामा और ब्राजील आदि देश थे।

(11) केन्द्रीय शक्तियाँ (Axis Powers) — इस गुट में जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गेरिया आदि देश थे।

युद्ध के शुरू में जर्मनी तथा उसके साथी देशों को शानदार विजय प्राप्त हुई। 1917 ई० में जर्मनी ने रूस को पराजित कर दिया और उसको ब्रेस्ट लिटी-वस्क की संधि पर हस्ताक्षर के लिये विवश किया। रूस में इस समय बोल्शेविक शक्ति हाँचुकी थी। जिसके नेता युद्ध से अलग होकर शान्तिपूर्वक रूस का विकास करना चाहते थे। इसलिये 15 दिसम्बर, 1917 को रूस तथा जर्मनी के बीच युद्ध बन्द हो गया।

इस समय जर्मनी ने अमेरिका के जहाज डूबो दिये। जिसमें कई अमेरिकन मारे गये। जर्मनी की इस कायवाही में क्रोध होकर अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने 6 अप्रैल, 1917 ई० को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। अमेरिका द्वारा मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध घोषित करने से उनका पलड़ा भारी हो गया। मित्र राष्ट्रों ने घुरी राष्ट्रों की इस प्रकार से नाके बंदी की कि उन्हें कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सका। उनके सभी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया। अन्त में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी व उसके साथी देशों को युद्ध में पराजित कर दिया। इस प्रकार मित्र राष्ट्रों की शानदार विजय हुई।

29 सितम्बर, 1918 को बुल्गेरिया ने, 31 अक्टोबर को तुर्की ने और 3 नवम्बर को आस्ट्रिया ने आत्म समर्पण कर दिया। 9 नवम्बर, 1918 को जर्मन सम्राट कर्नर विलियम द्वितीय ने सिंहासन छोड़ दिया। 10 नवम्बर, 1918 को जर्मनी में गणतन्त्र शासन व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के 14 सिद्धांतों से सहमत होकर जर्मनी ने 10 नवम्बर 1918 ई० को आत्म समर्पण कर दिया। 11 नवम्बर, 1918 ई० को

प्रातः 11 बजे युद्ध विराम हो गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इस युद्ध काल की मुख्य घटना रूस की बोल्शेविक क्रांति थी। जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायेगा।

विल्सन के चौदह सिद्धान्त — जर्मनी के विल्सन के चौदह सिद्धान्तों पर आत्मसमर्पण किया था। उसे यह आश्वासन दिया गया था कि यदि करते समय इन सिद्धान्तों का पालन किया जावेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन न भविष्य में युद्ध को रोकने के लिये तथा शांति स्थापित करने के लिये 8 जनवरी, 1918 को कांग्रेस के भाषण में अपने निम्न 14 सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था —

- 1—गुप्त समझौते नहीं होने चाहिए। शांति की परिपक्व होने के लिये होनी चाहिए।
- 2—युद्ध और शांति के समय राष्ट्रीय सीमा के बाहर समुद्र में जहाजों की यातायात की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाय।
- 3—जहाँ तक सम्भव हो आघात कर हटा दिये जायें और व्यापारिक परिस्थितियों में समानता स्थापित करने के लिये प्रयास किये जायें।
- 4—राष्ट्रीय शस्त्रोत्पत्ति केवल आंतरिक सुरक्षा तक ही सीमित रखा जाय।
- 5—उपनिवेशों का बटवारा आत्म नियंत्रण के सिद्धान्त के आधार पर किया जाय।
- 6—रूस के इलाके से जर्मनी अपनी फौजें हटा लेगा और सभी देश उसकी विकास का अवसर देंगे।
- 7—बेल्जियम को स्वतंत्रता दी जाय।
- 8—जर्मनी अल्सास व लोरेन के प्रदेश प्राप्त कर लौटा दे।
- 9—इटली की सीमाओं का निर्धारण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के आधार पर किया जाय।
- 10—ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य की जनता को विकास के लिए स्वतंत्रता व पूर्ण अवसर दिये जायें।
- 11—सर्बिया, रूमानिया, भाटनीयो से सन्तानें हटायी जायें और उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाय। सर्बिया को समुद्र तक जान का स्वतंत्रता माग दिया जाय और बाल्कन समुद्र की सीमाओं का निर्धारण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर किया जाय तथा उनकी आर्थिक सुखी की जाय।
- 12—तुर्की साम्राज्य को अपने वास्तविक भू भाग पर बना रहने दिया जाय परंतु तुर्की में रहने वाली अल्प जातियों को स्वतंत्र राष्ट्रीय विकास

के पूरा अवसर दिये जायें। डाडेनल्स में सभी राष्ट्रों का व्यापार के लिये सुविधायें दी जायें।

13—राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर फिर से स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण किया जाय तथा उसको समुद्र तक जाने का रास्ता दिया जाय।

14—राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के आधार पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जाय जो छोटे बड़े राज्यों को स्वतंत्रता और सुरक्षा का विश्वास दिला सक।

विल्सन के जिन सिद्धांतों पर जर्मनी ने आरम्भ समझौता किया था, वरसाय की संधि में उनका पालन नहीं किया गया। लैगसम ने निश्चय है कि विल्सन के चौदह सिद्धांतों में से पांच, संख्या 7, 8, 11, 13, 14 का पालन किया गया। और चार संख्या 5, 6, 9, 10 का पालन इस प्रकार में हुआ कि उससे मित्र राष्ट्रों को लाभ पहुंचा एवं चार संख्या 1, 2, 3, 4, 12 का उपक्षेप की गई।¹

यद्यपि विल्सन की कुछ शर्तों का पालन नहीं किया गया, पर तु वसम कोई संदेह नहीं कि उसके सिद्धांतों का वरसाय की संधि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यदि विल्सन न होता तो यह संधि और कठोर एवं अत्यायुष्ण होती।

पेरिस शांति सम्मेलन — प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् यूरोप के मानचित्र का नये सिरे से निर्माण करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का 18 जनवरी 1919 ई० को पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में रूस को नहीं बुलाया गया क्योंकि उसने 1917 ई० में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि कर युद्ध बंद कर लिया था। जिससे मित्र राष्ट्रों की स्थिति नाजुक हो गई थी। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधान मंत्री डेविड जोज, फ्रांस के प्रधान मंत्री क्लीमैणो का प्रभाव छाया रहा। मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों को निम्न संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया।

1—जर्मनी के साथ वरसाय की संधि 28 जून, 1919

2—आस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मा की संधि 10 सितम्बर, 1919,

3—हंगरी के साथ त्रिआनो की संधि 4 जून, 1920,

4—बल्गेरिया के साथ युदली की संधि 27 नवम्बर, 1919,

5—तुर्की के साथ सत्र की संधि 10 जगस्त 1920।

1919 ई० में भी गई वसाय की संधि से लेकर तुर्की के साथ सत्र की

सन्धि तक उपरोक्त सभी सन्धियां संयुक्त रूप से "शांति समझौते" के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

वर्साय की सन्धि — वेरिस शांति सम्मेलन में जितनी भी सन्धियां की गईं, उनमें वर्साय की सन्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो 28 जून 1919 ई० को जर्मनी के साथ की गई । इस सन्धि का मसविदा इंग्लिश तथा फ्रेंच भाषाओं में बनाया गया । इसमें 80 000 शब्द, 15 अध्याय और 439 धाराएँ थीं । इस सन्धि में कुछ छोटे-मोटे सशोधन करके जर्मनी के प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया । अतः 28 जून 1919 ई० को विवश होकर जर्मन प्रतिनिधियों को इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े ।

सन्धि की व्यवस्थाएँ — वर्साय की सन्धि की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न लिखित थीं —

1—**प्रादेशिक व्यवस्थाएँ** — वर्साय की सन्धि की प्रादेशिक व्यवस्थाएँ निम्नलिखित थीं —

(i) अल्सास व लोरेन का प्रदेश जर्मनी ने फ्रांस को लौटा दिया ।

(ii) जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र सार के कोपले का खानो पर 15 वर्ष के लिए फ्रांस को अधिकार दिया गया और उसके बाद जनमत द्वारा इस पर निर्णय लेने का निश्चय किया गया ।

(iii) जर्मनी को मासनेट यूपेन तथा मल्मेडी के प्रदेश हजति व रूप में बेल्जियम को देने पड़े ।

(iv) स्लेस्विग की डची डैनमार्क को दी गई ।

(v) पूर्वी साइलेशिया पश्चिमी प्रशा और पोसेन आदि पोलैंड को दिये गये । डार्नाजिग नगर को राष्ट्रसंघ के संरक्षण में मित्र राष्ट्रों ने अपने अधिकार में रखा ।

(vi) मेमेल नामक बंदरगाह मित्र राष्ट्रों ने अपने अधिकार में रखा, जो 1923 ई० में लिथुनिया को दे दिया गया ।

(vii) बेल्जियम व लक्जमबर्ग की सटस्थता समाप्त कर दी गई ।

(viii) जर्मनी के चीन तथा प्रशांत महासागर के उपनिवेशों पर जापान को अधिकार दिया गया और उसके अफ्रीका में स्थित उपनिवेशों को ब्रिटेन और बेल्जियम ने राष्ट्रसंघ द्वारा घरोहूर व्यवस्था में डाल कर उन पर अपना अधिकार बनाये रखा ।

2—**सैनिक व्यवस्थाएँ** — वर्साय की सन्धि के द्वारा जर्मनी को सैनिक शक्ति से धुंसा देने के लिए निम्न प्रतिबंध लगाये गये —

(i) जर्मनी का पण्य रूपेण शिशस्त्रीकरण किया गया ।

- (ii) जमनी की अनिवाय सैनिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई।
- (iii) स्थल सेना की सदस्या एक लाख निश्चित की गई।
- (iv) जमनी के युद्ध सामग्री के उत्पादन तथा आयात करने पर रोक लगा दी गई।
- (v) जमनी की नौ सैनिक शक्ति बहुत कम कर दी गई और उस अपना जहाजी बेडा मित्र राष्ट्रों का सौंपन के लिये बाध्य किया गया।
- (vi) राइन नदी के 31 मील व भू भाग पर अमेनिकीकरण कर दिया गया तथा बहा मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को रखा गया, ताकि जमनी सैनिक तयारी नहीं कर सकें।
- (vii) जमनी की सैनिक शक्ति नियंत्रित रखन के लिए मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। ये आयोग 1925 व बाद घीरे घीरे समाप्त कर दिये गये।

3—आर्थिक व्यवस्थाएँ — आर्थिक दृष्टि से जमनी पर निम्न कठोर शर्तें लादी गई —

- (i) एक क्षतिपूर्ति आयोग की स्थापना की गई जिस क्षतिपूर्ति की रकम निश्चित करन का काम सौंपा गया।
- (ii) आयोग की सिफारिशों के आने तक यानी मई 1921 ई० तक जमनी को 5 अरब डालर क्षतिपूर्ति की रकम के रूप में चुकाना ही कहा गया।
- (iii) जमनी को बाध्य किया गया कि वह 70 लाख टन कोयला फ्रांस को 80-80 लाख टन ब्रिटेन व बेल्जियम को देगा।

4 - कानूनी व्यवस्थाएँ - वर्साय की संधि के द्वारा जमनी को युद्ध आरम्भ करन का दोषी माना गया और जमन सम्राट कसर विलियम II पर गम्भीर आरोप लगाये गये। मित्र राष्ट्रों ने सैनिक न्यायालयों की स्थापना की ताकि युद्ध के नियमों का उल्लंघन करन वाले जमनी पर अभियोग चलाये जा सकें और उन्हें दण्ड दिया जा सके। मित्र राष्ट्रों के सैनिक न्यायालयों में 12 व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये।

वर्साय की संधि के द्वारा राष्ट्र सभ की स्थापना की गई, ताकि यूरोप में शांति और सुरक्षा बनी रह सके। इसकी प्रथम 25 धाराओं राष्ट्र सभ के सविधान से सम्बंधित थी। इस संधि के द्वारा पोलण्ड, बेल्जियम यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार वर्साय की संधि का जमनी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।

लगसम न वर्साय की संधि का जमन पर प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'दससे यूरोप में जमन प्रवेश का आठवा भाग और 70 लाख व्यक्ति कम हो

गये। उसके सारे उपनिवेश, 15 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि 12 प्रतिशत पशु, 10 प्रतिशत कारखाने छिन गये। उसके व्यापारिक जहाज 57 लाख टन से घटकर केवल पाच लाख टन रह गये। ब्रिटेन की नौ सेना से स्पर्धा करने वाली उसकी नौसक्ति बिल्कुल नष्ट कर दी गई और घल सेना की अधिकतम मर्या एक लाख निश्चित कर दी गई। उसे अपने कोयले के 2/5 भाग से, लोहे के 2/3 भाग से, जस्ते के 7/10 भाग से तथा आग्ने से अधिक शोरों से हाथ धोना पडा। उपनिवेशों के छिन जाने से रबड एव तल की भारी कमी हो गई। बर्साय की प्रादेशिक व्यवस्थाओं ने उसके उद्योग धर्मों और व्यापार को एकदम चौपट कर दिया। क्षतिपूर्ति के लिय उसने कौरे चक्र पर हस्ताक्षर कर दिये।”¹

बर्साय की सधि की आलोचना—बर्साय की सधि की शर्तों का पालन करना किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिये असम्भव था। इस सधि का जन्मदाता और हस्ताक्षरकर्ता दोनों ही इससे असंतुष्ट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि “मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे। वे मांस का पाँड ही नहीं चाहते थे बल्कि जमनी के अद्ध मृत शरीर से खून की आतिरी बूद तक ले लेना चाहते थे।” इस सधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित थे—

(1) आरोपित सधि—बर्साय की सधि एक आरोपित सधि थी। यह सधि जमनी पर थोपी गई थी। इस सधि में जमन प्रतिनिधियों की स्थिति बर्दियो के समान थी। उह विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं दिया गया। जमन प्रतिनिधियों को इस सधि पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया गया। जमनी ने इस सधि को स्वेच्छा नहीं अपितु बाध्य होकर स्वीकार किया था।

(2) कठोर सिद्धांतों पर आधारित सधि—जमनी को आधिक दृष्टि से पशु बनान के लिये बर्साय की सधि की शर्तें जान बूसकर कठोर बनाई गई थीं। वास्तव में इस सधि के निर्माता जमनी को सबक सिखाना चाहते थे। इस की कठोर तथा अपमानजनक शर्तों का कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र एक लम्बे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था।

(3) एक पक्षीय शर्तें—इस सधि की शर्तें एक पक्षीय थीं। पराजित पक्ष पर तो अनेक शर्तें लाद दी गईं, जबकि विजित राष्ट्रों को उनसे पूणत मुक्त रखा गया। इस सधि के अनुसार जमनी का पूणरूपेण निःशस्त्रीकरण कर दिया गया परंतु मित्र राष्ट्रों ने अपना निःशस्त्रीकरण नहीं किया। जमनी तथा तुर्की के उपनिवेश छिन लिये गये लेकिन मित्र राष्ट्रों के उपनिवेश नहीं छिने गए। युद्ध के अन्त में दोना पक्षों को आर से हुए थे लेकिन अभियोग केवल जमन व्यक्तियों पर ही चलाये गये। मित्र राष्ट्रों के दोषी व्यक्तियों पर अभियोग नहीं चलाये गये।

(4) पराजित राष्ट्रों में जबरन प्रजातंत्र की स्थापना—मित्र राष्ट्रों ने युद्ध की समाप्ति के पश्चात् जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गेरिया आदि पराजित राष्ट्रों में जबरन गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी एवं इन राज्यों में एकतंत्र की समाप्ति कर दिया गया। जर्मन जनता एकतंत्र की अभ्यस्त थी। इसलिये कुछ समय पश्चात् ही हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में फिर तानाशाही का उदय हो गया।

(5) नये राज्यों का निर्माण इस संधि में चेकोस्लोवाकिया, लिथुनिया लैटविया, और फिनलैण्ड आदि अनेक छोटे छोटे नये राज्यों का निर्माण सम्भव हो सका।

(6) विल्सन के सिद्धांतों की अंगहेलना (विंसा के जिन चीन्ह सिद्धांतों पर जर्मनी ने आत्म-समर्पण किया था) वर्साय की संधि में उनका पूर्णरूप से पालन नहीं किया गया। जिसका कारण हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं।

(7) द्वितीय विश्व युद्ध का कारण— वर्साय की संधि की अपमानजनक शर्तों को जर्मनी जसा स्वाभिमानी राष्ट्र एक लम्बे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे जैसे जर्मनी को मौका मिलता गया वैसे-वैसे वह संधि की शर्तों का उल्लंघन करता गया। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों से प्रतिशोध लेने के लिये ऐसे कार्य किये, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया।

वर्साय की संधि के द्वारा पोलैण्ड का स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह संधि 1918 ई० में की गई ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के मुकाबले में कम कठोर थी। जर्मनी ने रूस के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से जसा अपमानजनक व्यवहार किया था, वैसे-वैसे मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी के साथ नहीं किया। इस प्रकार वर्साय की संधि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के मुकाबले में कम अत्यायपूर्ण थी। यदि जर्मनी को इसमें भाग लेने दिया जाता और उसकी बात को सुना जाता तो यह संधि और अत्यायपूर्ण हो सकती थी।

निष्पत्ति—इतना सब कुछ होते हुए भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस संधि के द्वारा भविष्य में युद्ध टालने के लिये तथा शांति स्थापित करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संधि की स्थापना की गई थी। यद्यपि राष्ट्रसंधि अपने कार्यों में सफल नहीं हो सका। फिर भी इस संधि के द्वारा यूरोप में लगभग 20 वर्ष तक शांति स्थापित रही। इस कार्य के लिये उसे श्रेय मिलना ही चाहिये। साउथगेट ने लिखा है कि वर्साय की संधि संधि के इतिहास में एक नये माग का सूचक थी।¹

प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम — प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के 36 भाग लिये गए थे। उनमें से 32 राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के साथ थे और केवल 4 राष्ट्र केन्द्रिय शक्तियों के साथ थे। इस युद्ध में यूरोपियन देशों के अतिरिक्त मध्यकालीन अमेरिका और एशिया के देशों ने भी भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध लगभग सवा चार वर्ष तक चला। इस युद्ध में जन धन की अपार हानि हुई थी। इसका परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं —

(1) जन धन की अपार हानि — इस युद्ध में जन और धन की अपार हानि हुई। इसमें दोनों पक्षों की ओर से कुल 6¹ करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था। जिसमें से एक करोड़ तीस लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ 20 लाख सैनिक घायल हुए। जिनमें से 70 लाख व्यक्ति तो एक दम पशु और बेकार हो गए थे। युद्ध के तुरंत पश्चात् महामारी पड़ी। जिसके कारण 40 लाख व्यक्ति बालक प्रायः बने। इस तरह अपार जन क्षति के कारण कई यूरोपियन देशों में पुरुषों की भी कमी हो गई। अथ शास्त्रियों का मानना है कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 खरब 70 अरब डालर रुपया खर्च हुआ था।

(2) आर्थिक असंतुलन — युद्ध के दौरान प्रत्येक देश की उत्पादन शक्ति युद्ध कार्यों में लगी दी गई। जिससे आर्थिक संगठन को गहरा आघात लगा। युद्ध के दौरान फसलें नष्ट हो गईं। रेल मार्ग छिन्न भिन्न कर दिए गए। बम्बारी हानियों से जेतनों की श्रम शक्ति नष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त कारखाने एवं मकान नष्ट हो गए। जिससे आर्थिक संगठन को भारी धक्का लगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् पुनर्वास की समस्या और कारखानों के नष्ट हो जाने के कारण श्रमिकों की समस्या पैदा हो गई। इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्री के अभाव वस्तुओं के भाव भी आकाश को छूने लगे।

3—एकतन्त्र शासन की समाप्ति — इस महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी आस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बुल्गेरिया में एकतन्त्र शासन व्यवस्था को समाप्त कर गणतन्त्र शासन व्यवस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया, लिथुनिया लैटविया, एस्टोनिया और फिनलैंड आदि नववर्धित राज्यों में भी गणतन्त्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् यूरोप में प्रजातन्त्र की बाढ़ आ गई।

4—सोवियत के सिद्धांतों की उपेक्षा — यद्यपि मित्र राष्ट्रों ने प्रजातन्त्र के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए युद्ध सहाया किन्तु यह दूसरे देशों को आकर्षित करने का साधन मात्र था। युद्ध के आरम्भ में ईंग्लैंड की सरकार ने यह वचन दिया था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भारत को स्वतन्त्र कर दिया जायेगा

परन्तु ब्रिटेन की सरकार ने अपना वायदा नहीं निभाया और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिए रालेट एक्ट पास किया। इस एक्ट के अनुसार 13 अप्रैल, 1920 ई० को जनरल डायर न पनाव के जलियावाला बाग में निहत्थे भारतवासियों को गोली से मृतवा दिया। इस प्रकार इंग्लैण्ड प्रजातंत्र का समर्थक होते हुए भी उसने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने में कोई बसर नहीं उठा रहीं। पेरिस के शान्ति सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों के साथ जो संधियाँ की गई थी उसमें लोकतंत्र के सिद्धांतों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई थी।

5—नवीन वादा का उदय — प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 ई० में रूस में बोलशेविक क्रांति हुई। जिसका फलस्वरूप वहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। इससे पूँजीवादी दशा की नीच हारम हो गई। बर्साय की संधि में जर्मनी और इटली के साथ अत्याय हुआ था। इसलिए युद्ध समाप्ति के पश्चात् इन दोनों देशों में हमशा अशांति बनी रही। जिसके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद और इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्टवाद का जन्म हुआ। यदि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् जर्मनी के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं किया जाता तो शायद जर्मनी में नाजीवाद का विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् यूरोप में जर्मनी में नाजावाद इटली में फासिस्टवाद का जन्म हुआ। इसके कारण यूरोप में फिर सैनिकवाद प्रारम्भ हो गया।

6—बेरोजगारी की समस्या — युद्ध के दौरान कारखाने उद्योग धंधे आदि नष्ट हो गये। जिसका फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई। बेरोजगारी की इस समस्या के कारण प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था डगमगाने लगी।

7—नये राज्यों का अभ्युदय — इस युद्ध के फलस्वरूप पोलैण्ड को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। लिथुनिया, लटविया और फिनलैण्ड आदि नये राज्यों का अभ्युदय हुआ। आस्ट्रिया को जर्मनी से अलग करके एक छोटा सा राज्य बना दिया गया। चेकोस्लोवाकिया को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया। सर्बिया का नाम बदल कर यूगोस्लाविया नामक एक नये राज्य का निर्माण किया गया।

8—स्त्रियों की दशा में सुधार — प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी कार्यालयों में कमचारियों का अभाव हो गया। क्योंकि अधिकांश नवयुवक युद्ध में भाग लेने चले गये थे। इससे राजकीय कार्यालयों का काम ठप्प होने लगा। ऐसी स्थिति में स्त्रियों ने सरकारी कार्यालयों में काम करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस विश्व युद्ध के कारण स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। अब वे घर की चार दीवारी से निकल कर पुरुषों की भाँति कार्यालयों में काम करने लगीं।

9—संधि संधि —युद्ध के पश्चात् मजदूर बग दिन प्रतिदिन संगठित होता जा रहा था। इसलिए संधि संधि तेजी के साथ प्रारम्भ हुआ। अब कारखानों के पूँजीपतियों व शोषण व विरुद्ध मजदूरों ने संधि प्रारम्भ कर दिया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् मजदूर बग अत्याचार सहन करने के लिये तैयार नहीं था, क्योंकि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका था और उसने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संधि प्रारम्भ कर दिया था।

10—शक्ति सन्तुलन - युद्ध से पूर्व विश्व का नेतृत्व ब्रिटेन के हाथ में था। युद्ध के पश्चात् शक्ति सन्तुलन का स्थानांतरण कुछ समय के लिये अमेरिका को ओर हो गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् पेरिस शान्ति सम्मेलन में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

11—साम्राज्यवाद की प्रोत्साहन—इस युद्ध ने साम्राज्यवाद की प्रोत्साहन किया। इटली ने एडियाटिक सागर पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने मैडेण्ट व्यवस्था के अंतर्गत अपने उपनिवेशों में और मध्यपूर्व में अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की। जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रकट हुआ। वह अपने आपको सुदूरपूर्व की सर्वोच्च शक्ति मानने लगा।

12—राष्ट्रीयता की भावना का विकास—इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। हमन अरबों के स्वतंत्रता आन्दोलन में नया जोश फैला दिया। भारत में भी इस युद्ध के पश्चात् स्वतंत्रता आन्दोलन तेज हो गया।

13—अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि—यह पहला अवसर था जबकि अमेरिका ने यूरोप के मामले में हस्तक्षेप किया। इस युद्ध में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और अमनी तथा उनके साथी देशों को पराजित कर विश्व में अपनी सैनिक शक्ति की धार जमा दी। अमेरिका ने युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को गोला बारूक और हथियार आदि दिए। इसके अतिरिक्त युद्ध की समाप्ति के पश्चात् यूरोपियन देशों को आर्थिक दशा सुधारने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी। अब अमेरिका विश्व का एक प्रतिष्ठित साहूकार माना जाने लगा। उसने विश्व के बहुत से राष्ट्रों का बज दिया। युद्ध के पश्चात् उसने व्यापार वाणिज्य के माध्यम से धन कमाना प्रारम्भ किया। इस प्रकार इस युद्ध के कारण अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हुई।

14 राष्ट्रसंधि की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भविष्य में युद्ध सम्बंधों को समाप्त करने के लिए और शान्ति स्थापित करने के लिए अमेरिका ने राष्ट्रपति विल्सन ने 1919 ई० में राष्ट्रसंधि की स्थापना की। यद्यपि राष्ट्र संधि अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। फिर, भी विश्व शान्ति को बनाये रखने के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रयास किए। हम संधि ने मानव समाज के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये।

15— शस्त्रीकरण की होड़—युद्ध के बाद नि शस्त्रीकरण के लिए कई धार प्रयास किये गये, परन्तु शस्त्रीकरण की होड़ न रक सकी। यूरोप के सभी देश अपना सैनिक शक्ति और युद्ध सामग्री बढ़ाने में लगे रहे। इससे यूरोपियन दशा में फिर शस्त्रीकरण की होड़ प्रारम्भ हुई। इस होड़ ने द्वितीय विश्व युद्ध का माग प्रशस्त कर दिया।

प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही एक युग की समाप्ति हुई। फिर, भा मनुष्य ने युद्ध के परिणाम से कोई शिक्षा नहीं ली। जिसके फलस्वरूप 20 वर्षों बाद ही पहले से भी अधिक विनाशकारी महायुद्ध हुआ।

प्रस्ताविक सन्दर्भ पाठ्य पुस्तकें —

- 1—फे—दी ओरिजिन आफ दी वर्ल्ड वार
- 2—हेजन—आधुनिक यूरोप का इतिहास
- 3—लैंगसम—दी वर्ल्ड सिंस 1919
- 4—कैटलबी—ए हिस्ट्री आफ माडर्न टाइम्स
- 5—घाट एण्ड टेम्परले—यूरोप का इतिहास—उनीसवीं और बीसवीं शताब्दी में
- 6—गूच, जी० पी०—आधुनिक यूरोप का इतिहास
- 7—गेयोन और हार्डी—ए हिस्ट्री आफ इन्टरनेशनल अफेयर्स

रूस की क्रांति

1917 ई० की रूसी क्रांति का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति के पश्चात् रूस में साम्यवाद की शासन व्यवस्था स्थापित हुई। जिसमें सामन्ती शोषण को समाप्त कर दिया गया। इसके फलस्वरूप रूस में जनसाधारण का महत्व बढ़ा। इस प्रकार यदि फ्रांस की राज्य क्रांति न जनतात्मिक युग की शुरुआत की तो रूस की इस क्रांति ने समाजवादी युग की। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रूस एशियाई शक्ति था। पीटर पहला व्यक्ति था, जिसने मध्यवीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की तरह रूस का विकास करने का प्रयास किया। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में क्यारोल्स महान ने रूस का अत्यधिक विकास किया, जिसके कारण यूरोप में रूस का महत्व बढ़ने लगा। 19 वीं शताब्दी में रूस की आन्तरिक दशा में सुधार करने के लिए प्रयास प्रारम्भ हुए। इसी समय रूस की जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गई। गूच ने लिखा है कि— "क्रान्ति की पहली मजिद आगा से बहुत कम भयकर सिद्ध हुई, क्योंकि राज्य का पुराना जजर ढाँचा बिना किसी प्रतिरोध के ढह गया।"¹

क्रान्ति से पूर्व रूस की दशा—एच० जी० वेन्स ने लिखा है कि—'बीसवीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्षों में समार में लगभग दस लाख ऐसे व्यक्ति थे, जो यह मानते थे कि श्रमजीवी की तानाशाही से एक नयी और अधिक अच्छी सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी।'² रूस की क्रांति जनता, मजदूरों और किसानों की क्रांति थी। क्रांति से पूर्व रूस की दशा बहुत शोचनीय थी। रूस का शासक अन्वर्जेंडर जनता पर निरंकुश रूप से शासन कर रहा था। जागीरदार जनता पर अत्याचार

1—गूच जी० पी०—आधुनिक यूरोप का इतिहास, पृष्ठ 560

2—वेन्स, एच० जी०—दी आउट लाइन थाफ हिस्ट्री, पृष्ठ 116

कर रहे थे। पूजीपति धर्मिका का शोषण कर रहे थे। रूसी जनता को किसी भी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। रूस की मेना जनता के विद्रोह का बुचलने में गव का अनुभव करती थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में जीवोगिक श्रान्ति के प्रसार के कारण रूस में अनेक कारखाना की स्थापना हो चुकी थी परन्तु पूजीपति मजदूर वर्ग का शोषण कर रहे थे। जिसके कारण मजदूरों में असंतोष व्याप्त था। जनता में रूसी शासक एलेक्जेंडर तृतीय के अत्याचारा के कारण असंतोष था। इसलिए एनक्जेंडर तृतीय ने कुछ सुधार किये जसे शिक्षा का विवास एवं यातायात के साधना का विकास, परन्तु जनता पर इन सुधारों का कोई प्रभाव नहीं पडा। निकोलस द्वितीय ने भी जनता में व्याप्त असंतोष को दूर करने का प्रयास किया परन्तु उस भी सफलता नहीं मिली। 1905 ई० में जापान ने रूस को पराजित कर दिया ता इससे निकोलस व उसकी सरकार की बड़ी बदनामी हुई। रूस की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा कम हो गई। जापान के साथ साथ युद्ध में रूस के हारों निर्दोष सैनिक मार गये। रूस की इस पराजय के कारण जनता में जार निकोलस II के विरुद्ध असंतोष बढ़ा और जनता के मन में रूसी मनाजा का भय समाप्त हो गया।

जार निकोलस II के असंतोष के विरुद्ध रूस में 1905 ई० में क्रांति हुई, लेकिन वह धसपन रही। रूस में सामन्त जनता पर अत्याचार कर रहे थे। निकोलस द्वितीय पर उसकी रानी का अत्यधिक प्रभाव था। इस कारण वह जनता के लिये सन्तोषप्रद सुधार नहीं कर सका। ऐसे वातावरण में 1914 ई० में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्ध में रूस न मित्त राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया था। युद्ध के प्रारम्भ में रूस को शानदार सफलता मिली। इसके पश्चात् रूस की सेनायें निरन्तर हारती गई। जिससे देश में भुखमरी, गरीबी, आंतरिक अशांति, अयवस्था और असंतोष फला। युद्ध के वातावरण से परेशान होकर रूसी जनता ने 1917 ई० में अपनी सरकार के विरुद्ध क्रांति कर दी।

क्रांति के कारण—1917 ई० की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्न लिखित थे—

(1) शासकों की निरकुशता—रूसी शासक निरकुश और स्वच्छाचारी थे। वे मध्य कालीन शासकों की भांति निरकुश रूप से शासन कर रहे थे। वे देवी सिद्धान्त के अनुसार अपनी प्रजा पर शासन करने में विश्वास करते थे। उनकी इच्छा ही कानून थी और उसका विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं था। जार शासकों ने अपनी जनता को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं द रखे थे। प्रशासन की समस्त शक्तियां कुलीन वर्ग के व्यक्ति का हाथ में निहित थीं। जिनकी प्रजा हित वायों में विलुप्त रूचि नहीं थी।

रूस की जाति

इस समय प्रशासन के प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार फला हुआ था। चारों तरफ भ्रष्टाचार और वैईमानी का बोलबाला था। जनता को 'पाय नहीं मिल रहा था। इसलिये जनता में रूसी शासकों के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था। जनता ने शासकों से मुधार करने की माग की लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीमिया ने युद्ध के पश्चात् रूस में कुछ मुधार किये गए परंतु एलेक्जेंडर द्वितीय (1855-1881 ई०) ने इस मुधारवादी नीति को समाप्त कर दिया। जनता ने जार से रूस में संवैधानिक शासन लागू करने की माग की लेकिन जार ने इस माग को अस्वीकार किया। इस पर 13 मार्च 1881 ई० को बम्ब फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई।

एलेक्जेंडर तृतीय (1881-1894) — 1881 ई० में एलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। इस पश्चात् उसका पुत्र एलेक्जेंडर तृतीय रूस का शासक बना। इस समय उसकी आयु 36 वर्ष थी। एलेक्जेंडर तृतीय सद्गुण मस्तिष्क और जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उन सभी व्यक्तियों का बंधन करवा दिया, जिन्होंने उसके पिता की हत्या के पड़वत्त में भाग लिया था। एलेक्जेंडर तृतीय ने जनता की स्वतंत्रता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिये। उसने सारे देश में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। एवं भाषण व लेखन की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया। विश्वविद्यालय में वही पाठ्यक्रम पढाया जाता था, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता था। अध्यापकों और छात्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिये गये। पश्चात्त्य शिक्षा पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार एलेक्जेंडर तृतीय ने रूस को बौद्धिक विकास के माग को अवरुद्ध कर दिया।

एलेक्जेंडर ने गर रूसी जातियों पर भी अमानवीय अत्याचार किया। रूस में रहने वाली जर्मन, पोल आदि अरूसी जातियों पर भी रूसी कानून लाद दिये गये। रूसी भाषा सबके लिये अनिवार्य कर दी गई। एलेक्जेंडर ने यहूदियों पर भी घोर अत्याचार किये। उसने 1882 ई० में कानून बनाया। जिसके अनुसार यहूतियों के अचल सम्पत्ति खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शिक्षण संस्थाओं में यहूदियों के प्रवेश पाने की संख्या 3 प्रतिशत निश्चित कर दी गई। अनेक यहूदियों को सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। इन अत्याचारों से परेशान होकर 3 लाख यहूदी रूस छोड़कर चले गये। जार के इन अत्याचारों से रूस का सम्पूर्ण यहूदी समाज उसका कट्टर शत्रु बन गया।

एलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक बना। इस समय उसकी आयु 26 वर्ष की थी। वह अपने पिता की भांति स्वेच्छाचारी और निरकुश था। अत्याचार करने में तो उसने अपने पिता की भी पीछे छोड़ दिया था। उसने निरकुश नीति को जारी रखा। अपने शासन काल में उसने जनता और गर रूसियों पर घोर अत्याचार किए। उसने प्रतिनिधायवादी

नीति को अधिक शक्ति के साथ लागू किया एक जनता की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। समाचार पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। विश्वविद्यालयों में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया। उसके शासन काल में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये बन्दी बनाया जा सकता था, उसे जेल में रखा जा सकता था या देश से निर्वासित किया जा सकता था।

निकोलस द्वितीय जनता पर अत्याचार कर रहा था। उसने सैनिक छत्र को पूरा करने के लिये किसानों से नये-नये कर वसूल करना प्रारम्भ किया। करों के बढ़ते हुए बोझ के कारण जनता में जार के विरुद्ध असंतोष फैल रहा था। निकोलस द्वितीय ने 1899 ई० में फिनलैंड में संवैधानिक शासन को समाप्त करके वहाँ पर निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना की। फिनलैंड की सेना को रूसी सेना के अधीन कर दिया गया और वहाँ उच्च पदों पर रूसी अधिकारियों की नियुक्तियाँ की गईं। जार के इन कार्यों से फिनलैंड की जनता में उसके विरुद्ध असंतोष प्रारम्भ हो गया।

रूस में कुलीन वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्तियों पर अत्याचार कर रहे थे। निकोलस द्वितीय ने प्लेह्वे को अपना गृहमंत्री नियुक्त किया। जिसने जनता पर घोर अत्याचार किए। निकोलस द्वितीय के विरुद्ध 1905 में रूस में एक क्रांति हुई जो असफल रही। इसके पश्चात् उसने पुनः निरंकुश रूप में शासन करना प्रारम्भ कर दिया। 1907 ई० में चुनाव कानून को सीमित कर दिया गया। क्रांतिकारियों को कुचलन के नियमों के अन्तर्गत कानून का उपयोग किया गया और रूस में कई सैनिक-यात्रालयों की स्थापना की गईं। स्टोलीपिन को मन्त्रीमण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिसने क्रांतिकारियों को या तो आजम कारावास की सजा दे दी या देश से निर्वासित कर दिया या मौत की घाट उतार दिया। रूस में बढ़ती हुई यहूदी घोर अत्याचार किये गये। इन्होंने भी जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध जनता को क्रांति करने के लिये उत्तेजित किया। 1907-1911 ई० के बीच स्टोलीपिन ने 300 व्यक्तियों को फाँसी पर लटका दिया और हजारों व्यक्तियों को साइबेरिया के शीत प्रदेशों में निर्वासित कर दिया। स्टोलीपिन की अत्याचारपूर्ण नीति के विरुद्ध जनता में तेजी से असंतोष फैला। परिणामस्वरूप 14 सितम्बर 1911 ई० को क्रांतिकारियों ने स्टोलीपिन को मार डाला। फिर भी जार ने निरंकुशता की नीति को नहीं छोड़ा।

1911 से 1916 तक जार ने फादर रासपुटिन की सहायता से शासन संचालन किया। फादर रासपुटिन नामक व्यक्ति वैसे तो साधु था परन्तु उसके कार्यों से उसे धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। रासपुटिन का जार के दरबार में काफी प्रभाव बढ़ चुका था। जार निकोलस द्वितीय और उसकी रानी पर रासपुटिन का इतना अधिक प्रभाव था कि वे उससे बिना परामर्श लिये शासन का एक भी कार्य नहीं

करते थे। इस प्रकार जार और त्रारीना दोनों रासपुटिन के हाथों की कठपुतली बन चुके थे। उसी के परामर्श पर मन्त्रियों की नियुक्ति और हटाना निभर था। इसके प्रभाव में आकर जार ने एक बार गुप्त समझौता करने का भी प्रयत्न किया। उसके कहने के अनुसार जार ने थोड़े स समय में 4 प्रधानमन्त्रियों, 6 गृह मन्त्रियों, 4 युद्ध मन्त्रियों और 3 विदेश मन्त्रियों नियुक्त किये थे। राजपुटिन के प्रभाव के कारण जनता में असंतोष फल रहा था। राज्य में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला था। क्रांतिकारियों ने इस अव्यवस्था और अत्याचार की जड़ रासपुटिन को समझा। इसलिये उन्होंने जार से माग की कि रासपुटिन को दरबार से बाहर निकाल लिया जाय, परन्तु सम्राट ने इस माग को अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप जार के कुटुम्ब के एक सदस्य ने राजपुटिन को हत्या कर दी। प्लैट जीन और ड्रमड ने लिखा है कि "1916 में सम्राट के एक गुट ने जो उसे जार सरकार की दुबलता, असमत्ता और भ्रष्टाचार का दोषी मानता था, रासपुटिन की हत्या कर दी।" इससे भी जार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिये क्रांति का होना असाध्यम्भावी हो गया था। लिप्सन का मानना है कि "जार की अधीन सरकार ने जमाने को नहीं पहचाना और मौका हाथ में छोड़ दिया। जिससे सुधार आन्दोलन ने क्रांति का रूप धारण कर लिया। इस क्रांति ने राज सत्ता का ही नहीं रूसी समाज के आकाश प्रकार का ही अन्त कर दिया।"

(2) सामाजिक कारण—क्रांति का दूसरा मुख्य कारण सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त असमानता थी। इस समय समाज तीन वर्गों में विभाजित था —

- (i) कुलीन वर्ग
- (ii) मध्यम वर्ग
- (iii) निम्न वर्ग

(i) कुलीन वर्ग—कुलीन वर्ग में जागीरदार, धर्माधिकारी और धनी व्यक्ति आते थे। इस वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। रूस की अधिकांश भूमि पर इस वर्ग के लोगों का अधिकार था। शासन व्यवस्था का संचालन इसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। इस वर्ग के व्यक्ति भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, और निम्न वर्ग के व्यक्तियों पर अत्याचार करने थे।

(ii) मध्यम वर्ग—इस वर्ग की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। औद्योगिक विभाज्य के कारण इस वर्ग का विकास हो चुका था परन्तु इस वर्ग के व्यक्तियों को कुलीन वर्ग की भांति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। इस वर्ग के व्यक्ति मार्क्स के समाजवादी विचारों से प्रभावित होते जा रहे थे। इसलिये इस वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व किया।

(11) निम्न वग निम्न वग म कियान जोर मजदूर आते थे। रूप की अधिकांश जनता कृषि का काय करती थी। इस समय कृषकों की दशा बहुत शोचनीय थी। कृषकों का जमीन पर अधिकार नहीं था। जमीन पर बुलीन वग का अधिकार था। यह वग किसानों पर नाना प्रकार के अत्याचार करता था। कृषकों की आय का अधिकांश भाग कर के रूप में चना जाता था। फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। कृषक दास प्रथा समाप्ति के पूर्व भूमिपति लोग अपनी भूमि के साथ दासों का भी वेच देते थे। वे दासों से बेगार लेते थे। भूमिपति दासों को कृषि के अतिरिक्त भाड़े पर कारखाने में काम करने के लिये भेज सकते थे। 1861 ई० में दास प्रथा की समाप्ति के लिये एक कानून बनाया गया जिसमें सामाजिक और आर्थिक द्वाित प्रारम्भ हुई। इसके पश्चात् रूस का पश्चिमीकरण होना प्रारम्भ हो गया।

दास मुक्ति कानून से रूसी किसानों को जमींदारों से मुक्ति मिल गई लेकिन अभी तक उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिल सकी थी। किसानों के पास भूमि खरीदने के लिये पैसा नहीं था, इसलिये उन्होंने भूमिपतियों से अधिक व्याज पर रुपया उधार लिया। जब किसान अपना कर्ज नहीं चुका सक तो इन भूमिपतियों ने उनके खेत और घर नीलाम करवा दिये। इससे किसानों की दशा बहुत शोचनीय हो गई। इस कारण किसानों में तीव्र गति से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार हुआ। अब उन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और भूमि की मांग करने लगे।

(3) आर्थिक कारण आर्थिक दृष्टि से रूस एक पिछड़ा हुआ देश था। रूस की अधिकांश जनता कृषि का काय करती थी। अभी तक कृषि पुराने ढंग से की जाती थी। वनानिक आविष्कारों का उपयोग कृषि के क्षेत्र में प्रारम्भ नहीं हुआ था। किसानों के पास जमीन नहीं थी। उनको अपनी आय का अधिकांश भाग कर के रूप में चुकाना पड़ता था। इस प्रकार किसानों की दशा शोचनीय थी। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में किसान खेतों को छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे थे। किसान भूख और भूमि से पीड़ित थे। डब्ल्यू० एन० बीच ने लिखा है कि 'किसान भूमि भूख से पीड़ित थे। पचास वर्ष पहले वे दास मात्र थे और अब वे आजाद थे किंतु फिर भी बुरी तरह गरीब थे। वे अपनी शक्ति व्यर्थ गंवाने को तयार नहीं थे और गाँवों में अपनी जमीनों छीन लेने के लिये तयार थे।'¹ किसान अपनी भूमि प्राप्त करने के लिये हिंसात्मक तरीका अपनाने को तयार था। ऐसा वातावरण क्रांति के लिये उपयुक्त था। औद्योगिक प्रसार रूस में भी हुआ। इसके पश्चात् रूस का औद्योगिक विकास प्रारम्भ हुआ। 1871 ई० के पश्चात् रूस में कोयला और लोहा

का उत्पादन बढा और वहाँ अनका नये कारखाना की स्थापना की गई। औद्योगिक विकास होने के कारण मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। जिससे औद्योगिक नगरों की जनसंख्या बढी क्योंकि इन कारखानों में काम करने के लिये लाखों मजदूरों ने गाँवों से आकर शहरों में रहना प्रारम्भ कर दिया था।

कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी उन्हीं कारखानों में 14 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था लेकिन वेतन कम दिया जाता था। मिल मालिक मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूरों को सड़क बनाने का अधिकार नहीं था। कारखानों में इतनी खराब व्यवस्था थी कि आधे दिन मजदूर मशीनों से बच जाते थे। वे गंदी बस्तियों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके बच्चों के लिये कारखानों के पास शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। कारखानों के पास न तो अस्पताल था और न ही मनोरंजन के साधन। कारखाना में काम करने वाली स्त्रियाँ नैतिक चरित्र में गिर जाती थीं। मजदूरों के मनोरंजन में मुख्य साधन वसा वृत्ति, जुआँ और शराब आदि थे। मजदूरों में पूँजीपतियों के शोषण के कारण असंतोष व्याप्त था। वे शोषण में बचने के लिये सड़क का निर्माण करना चाहते थे। औद्योगिक शक्ति के कारण रूस में मध्यम वर्ग का विकास हुआ। इस वर्ग के लोगों ने समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। 1905 ई० की शक्ति में एक लाख माठ हजार मजदूरों ने भाग लिया था। मजदूरों ने अपना असंतोष प्रकट करने के लिये हड़ताल और दंगा का सहारा लिया।

(4) रूस-जापान युद्ध (1904-1905) — रूस एशिया में विस्तार करना चाहता था। जापान ने इसे रोक दिया। पोर्ट आर्थर बंदरगाह पर अधिकार करने में प्रश्न को लेकर 1904-1905 ई० में रूस और जापान के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्ध में जापान जिस छोटे से देश ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को बुरी तरह से पराजित किया। युद्ध में जापान की विजय होने से रूस को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य होना पड़ा। इस संधि के अनुसार रूस में कोरिया में जापानी प्रभाव स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त पोर्ट आर्थर का पट्टा भी जापान के नाम कर दिया।

इस युद्ध में रूस की पराजय से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई और जापान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। रूस की जनता ने इस पराजय के लिये सरकार को दोषी माना। इस युद्ध के कारण रूस की आर्थिक दशा और खराब हो गई। इस पराजय से रूसी जनता में सरकार के विरुद्ध असंतोष और तीव्र गति में फैला। अब जनता ने सम्राट् को मुद्दारा करने की माँग की।

(5) 1905 ई० की शक्ति — रूसी शासक की निरकुशता नीति के कारण जनता में पहले से ही असंतोष व्याप्त था। अब रूस की पराजय के कारण यह असंतोष और भी तीव्र हो गया। अब जनता ने निकोलस के अत्याचारों से परेशान

होकर हिंसात्मक तरीके अपनाने प्रारम्भ कर लिए। रूस में शून्यवाद का भी विकास हो रहा था। रूस का बौद्धिक वर्ग पश्चिमी यूरोप के दशन को पढ़कर जारशाही सरकार का विरोधी बन चुका था। उस समय अराजकतावादियों ने यह नारा लगाया प्रारम्भ कर दिया था कि सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। रूस में काल-मावस के सिद्धांतों का तजी से प्रचार हो रहा था।

1898 ई० में रूस में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण हुआ। मजदूर और किसान भारी संख्या में इस दल के सदस्य बने। इस दल ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिये अनेक प्रयास किये। इन्होंने माग रखी कि मजदूरों के काम के घंटे सीमित कर दिये जाय और उनके वेतन में वृद्धि की जाय। इन पार्टी का यह मानना था कि केवल मजदूर ही प्राप्ति कर सकते हैं। 1907 ई० तक किसानों ने सात हजार बार विद्रोह किया। 1910 से 1914 ई० के बीच 13 हजार बार किसानों ने आन्दोलन किया। मजदूरों ने जार निकोलस से यह माग की कि उन्हें ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाय परन्तु उसने इस माग को अस्वीकार कर दिया। उसने रूस में हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यदि वही हड़ताल होती तो हड़तालियों को गद्दर घोषित कर गोली से उड़ा दिया जाता था। मजदूरों ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये आन्दोलन करना प्रारम्भ कर दिया।

1903 ई० में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक दल में मतभेद प्रारम्भ हो गया। जिसके कारण यह दल दो भागों में विभाजित हो गया। बोल्शेविक दल और मेनशेविक दल। बोल्शेविक दल के सदस्य उग्रवादी और क्रांतिकारी विचारों के थे। इस दल के सदस्य बहुत अधिक थे। इस दल का नेतृत्व लेनिन और ट्राट्स्की के हाथ में था। दूसरा दल मेनशेविक था जिसके सदस्य उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। इस दल के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इन दोनों ही दलों ने श्रमिकों के संसोधन का प्रारम्भ किया। रूस में क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार होने लगा। जनता ने सरकार से भाषण लेखन और धार्मिक स्वतंत्रता देने की माग की। उस समय रूस का महामंत्री वानप्लेह्वे था जिसने जनता पर घोर अत्याचार किये। उसने मजदूरों की हड़तालों को कुचल दिया। इस पर क्रांतिकारियों ने क्रुद्ध होकर जुलाई 1904 में बम फेंक कर वानप्लेह्वे की हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त सरकार के अग्र कई अधिकारियों को बम फेंक कर मार डाला।

इस समय सभी शहरों की सड़कों पर यह नारे लगाये जाने लगे कि 'निरंकुश शासन का अन्त हो'। रूस की जनता सवधानिक शासन की माग करने लगी। 22 जनवरी 1905 ई० रविवार के दिन मजदूरों का एक विशाल जुलूस पान्तर गैरन के नेतृत्व में जार निकोलस द्वितीय को अपील करने के लिये शाही महलों की ओर खाना हुआ। ज्योंही यह जुलूस शाही महलों के पास पहुँचा त्योंही जार ने

रूस की क्रांति

निशस्त्र मजदूरों की भीड़ पर रैंकों को गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने निशस्त्र भीड़ पर गोली चलाई। जिससे फ़ारर गेपन के साथ हजारों यति मारे गये और दो हजार से अधिक व्यक्ति घायल हुए। जिससे शाही महल के आगे लाशा का ढेर लग गया और सेंट पीटर्स बर्ग की सड़क पर खून की नदी बह निकली। इस अत्याचार के विरुद्ध सारे देश में यही नारा लगाया जा रहा था कि "जार को हिंसात्मक तरीके से जवाब दिया जाये।" यही स रूस की प्रथम क्रांति प्रारम्भ हुई। किसानों ने भूमिपतियों से बदला लेने के लिये उनके महलों में आग लगवा दी। सरकार ने पौजी कानून का सहारा लेकर क्रांतिकारियों को बेरहमी में कुचलना प्रारम्भ किया। इसका जवाब क्रांतिकारियों ने पुलिस अधिकारियों और अ्य बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या करने दिया। इस अराजकता के वातावरण में क्रांतिकारियों ने जार के भ्रात्रा को मार डाला।

इस अराजकता के वातावरण से परेशान होकर जार ने 1905 म शासन सुधारों की घोषणा की। उसने जनता को यह आश्वासन दिया कि एक ड्यूमा का निर्माण किया जायेगा। जिस कानून बनाने का अधिकार होगा और जिसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। वास्तव में सुधारों की घोषणा कर जार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था परंतु उसने एक आदेश और निकाला, जिसके अनुसार उसने ड्यूमा को विधान सभा का प्रथम सदन माना, और साम्राज्य परिषद के नाम से एक दूसरे सदन का निर्माण कर सुधारों की घोषणा का प्रभाव कम कर दिया। साम्राज्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जार द्वारा की जाती थी। जार ने यह घोषणा कर दी कि ड्यूमा से पास किये हुए बिल पर साम्राज्य परिषद की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। साम्राज्य परिषद की स्वीकृति के पश्चात् ही बिल जार की अनुमति के नियम भेजा जायेगा। इस प्रकार ड्यूमा नाम मात्र की सस्था रह गई क्याकि उमके द्वारा पास किये हुए बिल को साम्राज्य परिषद अस्वीकृत कर संकती थी। इस प्रकार स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

क्रान्ति की असफलता के कारण—रूस की प्रथम क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

- (i) रूस एक विशाल देश है। वहाँ यातायात एवं संचार साधना के पून विकास के अभाव में क्रांतिकारी एक दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके। इसलिये रूस में सभी स्थानों पर एक साथ क्रांति नहीं हुई।
- (ii) उस समय जार ने जापान के साथ मघि करली थी और रूसी सैनिकों युद्ध में लौट कर आ चुके थे। उहलिये जार पद की रक्षा के लिये क्रांति

का बरहमी स दमन किया। सेना के निदयी बायीं स रूस मे चारा ओर भय का आतक का वातावरण उपस्थित हो गया।

(iii) प्रातिकारियो म केन्द्रीय यवस्था का अभाव था, इमलिये वे सगठित रूप स प्राति नही कर सके। इस प्राति को कुचलने क लिये रूम क शासक जार को यूरोपियन देशो ने काफी सहायता दी। फ्रान ने इस प्राति को कुचलने के लिये रूस को बहुत अधिक धन दिया। इ गणपड, जमनी ओर आस्ट्रिया की सहानुभूति भी जार के साथ थी। यूरोप क इन दशा न प्रातिकारिया को ब दी घना कर रूस को सुपुन करना प्रारम्भ किया।

(iv) प्रातिकारियो की आपसी फूट भी प्राति की असफलता का कारण बनी। उनकी आपसी फूट के कारण क सगठित रूप से जार का विराध नही कर सके। किसान बग बिल्कुल अमगठित था। इसक अतिरिक्त इस प्राति का क्षेत्र केवल शहरो तक ही सीमित था। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की हत्याकांड नाति स जनता मे आतक छा गया और उसन इस दल का साथ देना छोड दिया। प्रातिकारियो के पास जार को हटाकर शासन यवस्था स्थापित करने की कोई योजना नही थी। इतिहासकार बंस ने लिखा है कि इस प्राति से रूस मे सवधा निक शासन की स्थापना नही हो सकी और 1905 ई० के पूव की जार शाही कायम रही।

(6) ड्यूमा की समाप्ति—अक्टूबर, 1905 ई० मे जार ने शासन सुधारा की घोषणा की जिसके अनुसार एक ड्यूमा की स्थापना का जायगी। जिसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और जिसे कानून बनाने का अधिकार होगा। इस घोषणा का बोल्शेविक दल के अतिरिक्त सभी दलो ने स्वागत किया।

प्रथम ड्यूमा—1905 ई० मे जार न प्रथम ड्यूमा का निर्माण किया। 1906 मे इसके सदस्यो के चुनाव हुए, जिसमे सुधारको को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। ड्यूमा के सदस्यो ने कायकारिणी पर क कुष लगान की माग की। इस पर जार ने ड्यूमा का कमजोर बनाने के लिय साम्राज्य परिषद की स्थापना का। अब ड्यूमा प्रथम सदन और साम्राज्य परिषद को दूसरा सदन घोषित किया गया। साम्राज्य परिषद को ड्यूमा के बराबर अधिकार दिये गये। साम्राज्य परिषद के आधे सदस्यो को जार मनोनीत करता था और आधे सदस्यो को निर्वाचित किया जाता था। ड्यूमा द्वारा पास किये हुए बिल को परिषद अस्वीकृत कर सकती थी। इस प्रकार ड्यूमा को अधिकार हीन सस्था बना दिया गया। फिर भी ड्यूमा के सदस्यो ने जार शाही पर नियन्त्रण लगाने का हर सभव प्रयास किया और जार

सरकार की कटु बालोचना की। फलस्वरूप जनता भी सरकार विरोधी होती जा रही थी। इसलिये जार ने 22 जुलाई 1906 ई० को पहली ड्यूमा भंग कर ली।

दूसरी ड्यूमा—जार ने 5 मार्च 1907 ई० को दूसरी ड्यूमा का निर्वाचन कराया। रूस के प्रधानमंत्री स्टोलीपिन ने जनता के असतोष और विद्रोह को दबाने के लिये घोर अत्याचार किये। उसने हजारों व्यक्तियों को या तो देश से बाहर निकाल दिया या जेलों में बंद कर दिया। प्रतिनिधियों और जार के बीच संघर्ष चलता रहा। इसलिये जार ने समाजवादियों पर पड्यन्त्र का आरोप लगाकर 16 जून 1907 ई० को दूसरी ड्यूमा भंग कर दिया। परिणामस्वरूप तेजी से आंदोलन प्रारम्भ हुआ। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिये दमन चक्र चलाया। इसलिये जार ने मताधिकार को सीमित करने के लिये प्रयास किया।

तीसरी ड्यूमा—इस ड्यूमा के निर्माण से पूर्व जार ने सितम्बर 1907 में चुनाव सम्बन्धी कानूनों में संशोधन किया। जिसके अनुसार मताधिकार को सीमित कर दिया। अब मतदान का अधिकार केवल जमींदार, जागीरदार और बुलीन वर्ग के व्यक्तियों को दिया गया। इसलिये जब 1907 ई० में तीसरी ड्यूमा के सदस्यों का चुनाव हुआ तो अधिकांश सदस्य जमींदार चुनकर आये, जो प्रतिश्रियावादी नीति के समर्थक थे। य सस्था जार के सलाहकार समिति के रूप में थी। जार ने इस सस्था की सहायता से फिर से निरंकुश रूप से शासन करना प्रारम्भ किया। यह सस्था नाम मात्र की थी, जिसके सुधारों का कोई मूल्य नहीं था। जनता को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जनता ने अधिकारों की पुन मांग की इसलिये जार ने 1911 ई० में तृतीय ड्यूमा को भंग कर दिया। 1911 ई० में एक बार पुन मताधिकार को सीमित कर दिया गया।

चौथी ड्यूमा—चौथी ड्यूमा का चुनाव 1912 ई० में हुआ। इस बार पूजा पति, बुलीन वर्ग और जमींदार वर्ग के लोग इसके सदस्य चुन गये। य सदस्य जार के समर्थक थे। इसलिये जार ने पुन निरंकुश रूप से शासन करना प्रारम्भ कर दिया।

मजदूरों और किसानों ने अपना असतोष व्यक्त करने के लिये हड़ताल का सहारा लिया। बाल्शेविक दल ने इन हड़तालों का समर्थन किया। कृषकों ने हड़तालों में हिंसात्मक कार्य करने शुरू कर दिये। जिससे सारे देश में अराजकता एवं अशांति व्याप्त हो गई।

7- पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभाव—पीटर ने अपने शासनकाल में रूस का पश्चिमी देशों की तरह विकास करना प्रारम्भ कर दिया। रूस जब पश्चिमी देश के सम्पर्क में आया तो उस पर उनके विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। रूसवासियों ने देखा कि पश्चिमी राष्ट्रों में प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था है तो इसमें प्रभावित

होकर उ हाने भी सरकार से रूस में प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने की माग की। 1789 से 1917 ई० के बीच फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, इंग्लण्ड, ग्रीस, इटली जर्मनी और पोण्ड आदि देशों में क्रान्तियाँ हुईं और वह सफल रही। बाल्कन देश भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रयास में लगे हुए थे। यूरोपियन देशों के प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर रूसी जनता ने अपने देश में भी एक सवहारा वर्ग की सरकार स्थापित करने की माग की।

8 - रूस का बौद्धिक जागरण एवं योग्य नेताओं का योगदान - इस समय रूस में बौद्धिक क्षेत्र में काफी विकास कर लिया था। रूसी लेखकों और विचारकों ने जनता में राष्ट्रीय चेतना की भावनाएँ जाग्रत की और जनता का क्रान्ति करने के लिये प्रोत्साहित किया। विद्वानों ने जनता को यह समझाया कि वह सरकार से अपनी स्वतन्त्रता, समानता और मौलिक अधिकारों की माग करे। यूरोप की अनेक क्रान्तिकारी पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद किया गया। जब जनता ने उन पुस्तकों को पढ़ा तो उनमें राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हुई और उसने क्रान्ति करने का निश्चय कर लिया। टाल्स्टाय, तुगनेव, दातोविस्की आदि विद्वानों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को क्रान्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में जार शाही सरकार की कटु आलोचना की। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षित वर्ग ने सुधारों की माग करना प्रारम्भ कर लिया। इस समय क्रान्ति का नेतृत्व लेनिन ने किया। उसने किसानों, और मजदूरों को संगठित कर आन्दोलन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार लेनिन, स्टालिन, टाल्स्की ने इस क्रान्ति को पूर्ण कर दिखाया।

9 - जनता का अधिकारों के प्रति जागरूक होना - रूसी जनता की अधिकारों के प्रति जाग्रति भी क्रान्ति का प्रमुख कारण था। जार ने अपनी सैनिक शक्ति से 1905 ई० की क्रान्ति को कुचल कर असफल कर दिया था। इस क्रान्ति की असफलता के पश्चात् जनता जागरूक हो गई। उसने उन एक नई प्रेरणा दी। इसलिए 1905 ई० की क्रान्ति के पश्चात् जनता ने अपने अधिकारों की माग करना प्रारम्भ कर दिया। ड्यूमा की स्थापना से जनता मताधिकार के प्रयोग से परिचित हो चुकी थी। इसलिये रूसी जनता ने प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना के लिये आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस के साम्यवादी दल ने राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। साम्यवादी दल ने साम्यवादी विचार धारा का प्रचार किया। इन विचारों से मजदूर वर्ग बहुत अधिक प्रभावित हुआ। साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं ने गुप्त रूप से साम्यवादी साहित्य मजदूरों तक पहुँचाना प्रारम्भ किया। अब मजदूर नेता साम्यवादी विचारों का अध्ययन करने लगे। धीरे-धीरे रूसी मजदूर साम्यवादी शासन व्यवस्था के अनुयाई बन गये। अब उन्होंने निरंकुश जार शाही को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया।

10—प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव—

(i) युद्ध में रूस की पराजय - प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया। युद्ध के प्रारम्भ में रूस की शानदार सफलताएँ मिलीं। इसके जनता का ध्यान युद्ध की विजय की ओर गया और रूस में शांति स्थापित हो गई। परन्तु कुछ समय पश्चात् ही जर्मनी ने रूस की सेनाओं को स्थान-स्थान पर घुरी तरह से पराजित किया। रूस की पराजय से जनता में जादू के विपक्ष अमतीप और तीव्र हो गया। जनता ने इस युद्ध में रूस की पराजय का कारण जार शाही सरकार को माना। युद्ध में हजारों रूसी सैनिकों के अनावश्यक मारे जाने से जनता में असंतोष व्याप्त था। इस समय ड्यूमा के मन्त्रियों ने जार से उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल नियुक्त करने की मांग की जिसे जर्मन अस्वीकार कर लिया।

(ii) रूस में अकाल (1916-17)—एक तरफ रूसी सेनाएँ युद्ध में घुरी तरह हार रही थीं तो दूसरी तरफ 1916-17 में रूस में अकाल पड़ गया। युद्ध प्रारम्भ होते ही सरकार ने किसानों को बहुत अधिक सस्या में सेना में भर्ती कर लिया। किसानों के युद्ध क्षेत्र में चले जाने से वेतों में काम करने वाले व्यक्तियों का अभाव हो गया। पशुस्वल्प खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम हो गया। जिसके कारण वस्तुओं के भाव बहुत अधिक बढ़ गए।

यातायात के साधनों का पूर्ण रूप में विकास नहीं होने के कारण गाँवों में जो बाढ़ा बहुत उत्पादन हुआ था, उसे शहरों तक नहीं पहुँचाया जा सका। इस लिए रूस के नगरों में अकाल पड़ गया। वस्तुओं के भाव इतने बढ़ गये कि गरीबों के लिए जीवन निर्वाह करना असम्भव हो गया। लेकिन सामान्य और दरबारी अपना विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे। उन्होंने जनता के कष्टों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। जार की सरकार इस अकाल की समस्या को हल करने में असफल रही। यह वातावरण क्रांति के लिए उपयुक्त था। इसलिए 7 मार्च, 1917 ई० का क्रांति प्रारम्भ हो गई।

(iii) सेना में असंतोष—प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया। रूस के सैनिक युद्ध के मोर्चे पर भेजे जा रहे थे। जार ने युद्ध के प्रारम्भिक तीन वर्षों में एक लाख पचास हजार सैनिक मोर्चे पर भेज लिये लेकिन सन्ना के पास खाद्यान्न व युद्ध सामग्री का अभाव होने के कारण रूसी सेना युद्ध में स्थान-स्थान पर घुरी तरह पराजित हुई। इस युद्ध में 20 लाख सैनिक मारे गए और 50 लाख घायल हुए। इस सैनिक विनाश के पशुस्वल्प रूसी फौज

म असंतोष फैल गया। इस समय खाद्यान्न व युद्ध सामग्री के अभाव में हजारों मनुष्य मारे जा रहे थे और जार महानों में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। इन घटनाओं से सैनिक असंतुष्ट हो गये जिसमें फ्रांस के स्पष्ट सकेत प्रकट होने लगे। असंतुष्ट मनुष्य फौजों में भागन लगे। उन्होंने किसानों और मजदूरों की हड़तालों का समर्थन किया। जिससे फनम्बरूप फ्रांस स्पष्ट रूप में शक्तिशाली होने लगी।

फ्रान्स का विकास—रूस की फ्रांस का फरवरी 1917 ई० से नवम्बर 1917 ई० तक तीन चरणों में विकसित हुआ। ये तीन चरण निम्नलिखित हैं—

- 1—माच 1917 ई० की फ्रांस और जार शाही का अन्त
- 2—अक्टूबर 1917 ई० की समाजवादी फ्रान्सि,
- 3—बोल्शेविक फ्रांसि, नवम्बर, 1917।

1 माच, 1917 ई० की फ्रान्सि और जार शाही का अन्त—फ्रांस की फ्रांसि की तरह रूस की फ्रान्सि तीन परिस्थितियों से होकर गुजरी। रूस में पहली फ्रांसि माच, 1917 ई० में हुई। 1916 ई० तक रूसी जनता अधिकारियों और ड्यूमा के सदस्यों में जार के विरुद्ध भयंकर असंतोष व्याप्त हो गया था। 1916-17 तक हड़तालों ने फ्रांसि का रूप धारण करना प्रारम्भ किया। चारों तरफ सुधारों की मांग की गयी परन्तु जार ने इसको अस्वीकार कर दिया। नवम्बर, 1916 ई० में प्रगतिशील दल के नेता मिल्यू कोव ने महल पर दायरे चर कर जार को हटाने का प्रयास किया, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली।

इसके पश्चात् सेनापति गुर्को ने ड्यूमा को भग कर सैनिक शासन स्थापित करने का प्रयास किया। अब जार के विरुद्ध जनता में भयंकर असंतोष व्याप्त था। फ्रान्सिवाहियों ने क्रुद्ध होकर जार के सलाहकार रामपुटिन की 1916 ई० में हत्या कर दी। चारों तरफ अराजकता और अशांति का वातावरण पैदा होने लगा। इससे दगे फर्मान और हड़तालों ज्यादा होने लगी। 1917 ई० में रूस की राजधानी पेटोग्राड में अप्रत्यक्ष रूप में फ्रांसि हो गई। हेन ने लिखा है कि इस समय रूस में फ्रांसि करने के लिए कोई भी तयार नहीं था। खूनी रविवार की जयंति के दिन मास्को में दो हजार मजदूरों ने एक विशाल जुलूस निकाला। इनका मुख्य नारा यह था कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाय। रूस में चारों ओर जार शाही के विरुद्ध आवाजें उठन लगी।

7 माच को भूख से 'याकुव' मजदूरों ने पेटोग्राड में एक जुलूस निकाला। उनका मुख्य नारा 'रोटी' था। उन्होंने लूटमार करना प्रारम्भ कर दिया। 8 माच को कपड़े के कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों ने हड़ताल कर दी।

रूस की क्रांति

उनकी मांग थी कि उन्हें भर पेट रोटी चाहिये। उनके समयन में मजदूरों ने हड़ताल कर एक विशाल जुलूम निकाला। उनका नारा यह था कि युद्ध को समाप्त किया जाय और सभी को लिए भर पेट भोजन की व्यवस्था की जाय। जार ने मजदूर आन्दोलन को बुचलाने के लिये सेना को गोली चलान का आदेश दिया, लेकिन सेना न गोली चलान से इंकार कर दिया। सेना में क्रान्ति की भावना का विकास होने लगा। इसलिये सेना मजदूरों से जाकर मिल गई।

मजदूर हड़ताल न जार पकड़ा। 10 माच को पेट्रोघ्राड के सभी कारखानों के मजदूर हड़ताल पर रहे। जिससे कारखाने बंद हो गये। पेट्रोघ्राड के मजदूरों के समयन में रूस के प्रमुख नगरों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। 10 माच को सारे देश के मजदूर हड़ताल पर रहे। जार ने सैनिकों को हड़ताल का दमन करने के लिये भेजा परन्तु सेना मजदूरों से जाकर मिल गई। 11 माच को जार ने ड्यूमा भंग कर दी और हड़ताली कमचारियों को यह चेतावनी दी कि वे काम पर नौट आयें लेकिन मजदूरों ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया। इसके अनिश्चित ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने अपने पद से हटने के लिए इंकार कर दिया। इससे 14 माच 1917 ई० को जार तबोव को नेतृत्व में एक अस्थायी उदारवादी सरकार की स्थापना कर दी गई। हेज ने लिखा है कि जार ने चुपचाप 15 माच, 1917 ई० को सिंहासन छोड़ दिया और किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इस प्रकार माच की क्रांति में रूस में जार शाही का अंत हो गया और एक उदारवादी सरकार की स्थापना हुई। इस अस्थायी उदारवादी में समाजवादी उदारवादी मेथेविक आदि सभी दलों का प्रतिनिधित्व था।

उदारवादी सरकार का कार्य — प्रिंस लवोव के नेतृत्व में बनी अस्थायी सरकार के अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग के थे। यद्यपि क्रांति मजदूरों की थी परन्तु उन्हें शासन में कोई स्थान नहीं दिया गया। इस क्रांति में पेट्रोघ्राड में बड़ी भूमिका आना की जो पेरिस में फ्रांस की राज्य क्रांति में की थी। इसमें भी पेरिस की तरह क्रांति मजदूरों के द्वारा की गई, परन्तु सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई। लिप्सन ने लिखा है कि शासन सत्ता मध्यम वर्ग को सौंपन का कारण यह था कि वे शक्ति अपने पास रखने में असमर्थ थे।

मिश्र राष्ट्रों ने इस नई उदारवादी अस्थायी सरकार को मायता प्रदान कर दी। इस सरकार ने निम्न कार्य किये—

- 1—राजनीतिक कारणों से बनाये गये बन्धियों का रिहा कर दिया गया।
- 2—रूस में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई।

- 3—जनता को भाषण लेखन व प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई ।
- 4—जार द्वारा रूस से निकाले गये लोगो को पुन रूस में आने की अनुमति दे दी गई ।
- 5—यूनानी खज के विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई ।
- 6—मृत्यु दण्ड की सजा समाप्त कर दी गई ।
- 7—यहूदियों पर लाद गये विभिन्न कानूनों को समाप्त कर लिया गया ।
- 8—रूस में वयस्क मताधिकार के आधार पर नया शासन विधान बनाने की घोषणा की गई ।
- 9—पोलण्ड को स्वायत्त शासन देने का आश्वासन दिया गया ।
- 10—रूस की नई उदारवादी सरकार ने अपनी विदेशी नीति निर्धारित करते हुए कहा कि सरकार अपनी मातृभूमि व अधिकारों की सुरक्षा करेगी और उसके साथ ही मित्र राष्ट्रों से किये गये समझौतों का पालन करेगी । इस प्रकार नई सरकार ने यह घोषणा की कि युद्ध को जारी रखा जायेगा । मित्र राष्ट्रों ने इस घोषणा का स्वागत किया ।

2 — अक्टूबर 1917 ई० की समाजवादी क्रांति

उदारवादी सरकार के सुधार भी किसानों मजदूरों और महिला में असंतोष को दूर करने में असफल रहे । फलस्वरूप रूस में किसानों और मजदूरों ने अपने अपने संगठन बनाये । ये संगठन सोवियत सभ के नाम से प्रसिद्ध हुए । सनिक भी इस सभ के सदस्य बन गये । अराजकता के वातावरण में सभ ने सरकार के कार्य करने प्रारम्भ कर दिये । इस सभ में बोल्शेविकों का घेन बाला था सरकार और सोवियत सभ में आपस में मत भेद था क्योंकि नई सरकार में इस सभ के सदस्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया था । नई अस्थाई सरकार के अधिकारियों ने भी आन्दोलनों को बेरहमी से कुचलना प्रारम्भ किया । फलस्वरूप रूस नई सरकार व विरुद्ध जनता में असन्तोष व्याप्त था ।

इस समय तक अनेक निवासित साम्यवादी नेता लेनिन ट्राट्स्की और स्टालिन आदि रूस लौट आये थे । लेनिन ने उदारवादी सरकार से माग की कि युद्ध को बंद कर दिया जाय और रोजी रोटी की समस्या को हल किया जाय । उदारवादी सरकार ने युद्ध जारी रखने की घोषणा की इसलिये उसके विरुद्ध जनता में असन्तोष बढ़ा । लेनिन ने भी युद्ध जारी रखने का विरोध किया अत रूस में पुन विद्रोह प्रारम्भ हो गये । एक तरफ तो रूसी स्थान-स्थान पर हार रहे थे और दूसरी तरफ जनता में असन्तोष बढ़ता जा रहा था । इसलिये त्रिस ल्वोव और उसके समर्थकों ने उदारवादी सरकार से इस्तीफा दे दिया । 15 जुलाई 1917 को केरेसकी के नेतृत्व में समाजवादियों की नई सरकार बनी । केरेसकी को प्रधानमंत्री बनाया गया ।

करेसकी सरकार मजदूरों, सैनिकों और किसानों का असंतोष दूर करने में असफल रही। फलस्वरूप इनमें असन्तोष और अधिक बढ़ा। करेसकी ने भी युद्ध जारी रखने की घोषणा की परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था कि लेनिन युद्ध बंद करने का पक्षपाती था। वह रूस में शांति स्थापित करना चाहता था। जब रूसी सेनाएँ मोर्चों पर हारने लगीं, तब असंतुष्टों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किये। बोल्शेविक दल ने इन प्रदर्शनकारियों का नतुत्व किया। करेसकी इस विगड़ती हुई परिस्थिति का सामना नहीं कर सका और उसने 6 नवम्बर 1917 को सरकार में स्वीकारा दे दिया।

3—बोल्शेविक क्रांति (नवम्बर 1917) —

नवम्बर 1917 ई० में लेनिन ने नतुत्व में रूस में दूसरी राज्य क्रांति हुई, जिस पूर्ण रूप से सफलता मिली। यह क्रांति विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति की मुख्य विशेषता यह थी कि यह एक रक्तहीन क्रांति थी। लेनिन बोल्शेविक दल का नेता और संस्थापक था। सेबाइन ने लिखा है कि “इतिहास में ऐसे अनेक ध्यक्विकों का उदाहरण कम देखने को मिलता है जिनका घटनाओं की गति पर इतना सीधा प्रभाव हो और इससे भी अधिक ऐसे कम लोग होंगे जो लेनिन के समान बाधाओं की बाढ़ का नाश करने में सफल हुए हैं।”

मार्च 1917 ई० में लेनिन को रूस से निर्वासित कर लिया गया था। उसने बाहर रहकर भी क्रांति का वातावरण तैयार किया। अप्रैल, 1917 ई० को वह पेट्रोपाड पहुँचा और उसने बोल्शेविक दल के समस्याओं में मुख्य क्रांतिकारी विचार रखे। लेनिन को ट्राटस्की का सहयोग प्राप्त हो जाने से बोल्शेविक दल अधिक शक्तिशाली बन गया। ट्राटस्की का पेट्रोपाड स्थित सोवियत सभ का प्रधान बना दिया गया। जब बोल्शेविक दल ने मत्ता हथियाने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये। बोल्शेविक दल के पास 25 000 सशस्त्र मजदूर थे, जिन्हें ‘रेड गार्ड’ के नाम से पुकारा जाता था। पेट्रोपाड में स्थित रूसी मत्ता भी रेड गार्ड में जाकर मिल गई क्योंकि उन्हें यह भय था कि कहीं उन्हें युद्ध के मोर्चों पर न भेज दें।

5 नवम्बर 1917 ई० को करेसकी ने बोल्शेविक दल के नेताओं को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये लेकिन इस समय तक क्रांति की पूरी तैयारी हो चुकी थी, इसलिए उनके आदेशों का पालन नहीं हुआ। 6-7 नवम्बर की रात्रि को बोल्शेविक सैनिक टुकड़ियाँ न पेट्रोपाड के रेलवे स्टेशन स्टेशन, स्टेट बैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, डाक घर और अन्य सरकारी भवनों पर बरतना कर लिया। 7 नवम्बर 1917 को करेसकी राज्य सत्ता छोड़कर भाग गया। सरकार के अन्य सदस्यों को बोल्शेविक सैनिक टुकड़ियाँ न गिरफ्तार कर लिया। रूप की शासन सत्ता पर बोल्शेविकों का अधिकार हो गया। उन्होंने पेट्रोपाड के शरद भवन पर लाल पता फहरा दिया। इस क्रांति का नतुत्व लेनिन ने किया था और उसे ट्राटस्की और स्टालिन ने

अपना पूरा सहयोग किया था। इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति बिना किसी एक खून की बूंद बहाये सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गई। बोल्शेविक दल ने लेनिन को प्रधान मंत्री और ट्राट्स्की को युद्ध मंत्री के पद पर नियुक्त किया।

लेनिन के पास निश्चित कार्यक्रम थे। युद्ध बंद करके संधि करना भूमि मित्रों का भूमि पर से अधिकार बिना मुआवजा लिये समाप्त करना भूमि किसानों में बांटना उद्योग घरों पर श्रमिकों का नियंत्रण रखना, नगरों में अनाज पहुँचाने की व्यवस्था करना व्यक्तिगत सम्पत्ति को जब्त करना निजी कारखाना बंदों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना आदि। लेनिन के प्रधान मंत्री बनने के पश्चात् 8 जनवरी 1918 ई. को जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर रूस को युद्ध से अलग कर लिया। यूरोपियन इतिहास में यह संधि सर्वाधिक अपमानजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण संधि थी, परंतु लेनिन किसी भी कीमत पर युद्ध बंद करना चाहता था ताकि शांति स्थापित कर रोजी रोटी की समस्या को हल किया जा सके। इस संधि से मित्र राष्ट्र रूस के विरुद्ध हो गये परंतु रूस के समक्ष आंतरिक विकास के लिये संधि के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था।

बोल्शेविक क्रांति के पश्चात् रूस ने जर्मनी के साथ संधि कर युद्ध बंद कर मित्र राष्ट्रों के साथ विश्वासघात किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी की शक्ति में वृद्धि हुई। इस लिये मित्र राष्ट्रों ने बोल्शेविक क्रांति को एक चुनौती समझकर इस कुचलन के लिये रूस का घेरा बाल दिया क्रांति के विरोधियों का पश्चिमी राष्ट्रों ने सहायता दी। जिससे रूस में क्रांति के विरुद्ध आंदोलन प्रारम्भ हो गये। अब बोल्शेविक दल की लालसेना ने ट्राट्स्की के नेतृत्व में श्वेत सेना से युद्ध किया। इस युद्ध में बोल्शेविक दल की विजय हुई। इस दल ने घरेलू और बाहरी सभी शत्रुओं को परास्त करके खदेड़ दिया। 1920 ई० में इस संधि की समाप्ति हुई। अब रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था सुदृढ़ रूप से स्थापित हो गई। इस अवधि में रूस के हजार परिवार को यूराल पर्वत पर स्थिति इकेटिन बग में बंसी बनाकर रखा गया। जिसे 16 जुलाई 1918 को बोल्शेविक दल के अधिकारियों ने गोली से उड़ा दिया। इस प्रकार रोम नोव बर्ग के अंतिम शासक का अन्त हुआ।

क्रांति की सफलता के कारण—बोल्शेविक क्रांति की सफलता के प्रमुख कारण निम्न लिखित थे—

- (1) किसानों और मजदूरों का समर्थन—बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक दल ने किया था। किसान और मजदूर इस दल के सन्तुष्ट थे। इन दोनों ही वर्गों ने क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किसानों का यह मानना था कि क्रांति की सफलता के पश्चात् भूमि पर उनका अधिकार हो जायगा जबकि मजदूरों का यह मानना था कि क्रांति के पश्चात् उद्योग घरों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जायगा। यदि क्रांति

असफल हो जायेगी तो मजदूरों और किसानों का फिर से शोषण प्रारम्भ हो जायेगा। इसलिए बोल्शेविक क्रांति को सफल बनाने के लिये किसानों और मजदूरों को जो जान स बोल्शेविक दल का साथ दिया।

- (2) अस्थायी सरकार की असफलता - क्रांति के प्रारम्भ में जो अस्थायी सरकार बनी थी, उसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे। जिनमें परस्पर घृणा थी। उस प्रकार अस्थायी सरकार में संगठन का अभाव था और वह विभिन्न दलों की विचट्टी मात्र थी। अस्थायी सरकार ने युद्ध को जारी रखने की घोषणा की परन्तु वह रोजी रोटी की समस्या को हल नहीं कर सकी। युद्ध जारी रखने के कारण मित्र राष्ट्रों ने भी इस अस्थायी सरकार को सहयोग देने का निश्चय किया। मित्र राष्ट्र युद्ध के सम्मेलन करने के कारण थके हुए थे। रूस बहुत दूर होने के कारण बड़े पैमाने पर कोई आपवाही नहीं कर सका। बोल्शेविक शासन को उठाइए के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और जापान ने हर सम्भव प्रयास किया, परन्तु वे असफल रहे। जनता ने इस क्रांति के पश्चात् बोल्शेविकों के शासन को स्वीकार कर लिया। मित्र राष्ट्रों के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण बोल्शेविकों ने रूस में अपने पैर जमा लिए।
- (3) युद्ध बंदी की माँग—रूस क्रांति की सफलता का एक अन्य कारण बाल्कन क्षेत्रों द्वारा युद्ध बन्द करने की माँग करना था। रूस की जनता युद्ध से परेशान हो चुकी थी। युद्ध के लम्बे होने के कारण अन्धकार का क्षेत्र बढ़ता जा रहा था और वस्तुओं के भाव आसमान को छू रहे थे। जब अस्थायी सरकार ने युद्ध जारी रखने की घोषणा की तो बोल्शेविकों ने इसका विरोध किया। परिणामस्वरूप उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हो गया।
- (4) बाल्शेविकों का कार्यक्रम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप था—बोल्शेविक दल के कार्यक्रम जनता की इच्छा के अनुरूप थे। इस दल ने यह घोषणा की कि भूमि पर किसानों को अधिकार दे दिया जायेगा। उद्योग घरों और मजदूरों का नियंत्रण स्थापित कर दिया जायेगा। निजी कारखानों, बंकों और बीमा कंपनियों को सरकार अपने हाथ में ले लेगी। इस प्रकार बोल्शेविकों का सबहारा शासन और समाज की स्थापना करना चाहते थे। इस दल के कार्यक्रम जन कल्याण पर आधारित होने से यह दल कुछ समय में ही जनता में लोकप्रिय हो गया।
- (5) लेनिन का प्रभावशाली व्यक्तित्व—रूस क्रांति की सफलता का मुख्य कारण लेनिन का प्रभावशाली व्यक्तित्व होना था। उसी ने क्रांति का सफल नतीजा किया और किसानों और मजदूरों को बोल्शेविक दल के मण्डल के नीचे एकत्रित कर क्रांति करने के लिये प्रोत्साहित किया था।
- रूस की क्रांति में लेनिन का योगदान - रूसी क्रांति का सबसे प्रसिद्ध नेता लेनिन थे। उसका वास्तविक नाम व्लाडिमिर इलियच यूनियानोव था, परन्तु वह

इस क्षेत्र में बिलकुल भी रुचि नहीं थी। वह तो मार्क्स के विचारों का अध्ययन करने में व्यस्त रहता था। 1903 ई० में वह लेनिन का प्रथम अनुयायी बना। लैंगसम ने लिखा है कि स्टालिन निर्भीक तथा कम बोलने वाला व्यक्ति था परंतु वह भयंकर से भयंकर बठिनाई का सामना करने में नहीं घबराता था। उसकी मर्तौ वृत्ति किसी के आगे झुकने की नहीं थी। इसलिए उस लोह पुरुष के नाम से जाना जाता था।

लेनिन की मृत्यु के पश्चात् शासन सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिये लियोन ट्राट्स्की और जोसेफ स्टालिन के बीच सघष प्रारम्भ हो गया। इस सघष में स्टालिन को सफलता मिली। उसने 1929 ई० में ट्राट्स्की को पराजित कर लिया और रूस का तानाशाह बन गया। स्टालिन और ट्राट्स्की के बीच सिद्धांतों का भी सघष था। ट्राट्स्की साम्यवाद को अन्तर्राष्ट्रीय बनाने के पक्ष में था जबकि स्टालिन इसका विरोधी था। उसका यह कहना था कि दूसरे देशों में साम्यवाद का प्रसार करने की अपेक्षा पहले इस रूस में दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रूस को अपना आर्थिक विकास करना चाहिए। इसने विपरीत ट्राट्स्की सम्पूर्ण विश्व में साम्यवादी क्रांति लाना चाहता था।

स्टालिन यह चाहता था कि रूस कृषि और उद्योग के क्षेत्र में इतना अधिक विकास कर ले कि वह पूंजीपति देशों पर निर्भर न रहे। 1936 में स्टालिन ने एक नया संविधान बनाया। जिसके द्वारा लोगों को राजनीतिक और आजीविका पाने का अधिकार दिया गया। उसने रूस के आर्थिक विकास के लिए दो पंच वर्षीय योजनाएं लागू कीं। इससे सामंतों का प्रभाव समाप्त हो गया और रूस में उत्पादन बढ़ा। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्टालिन ने लेनिन के अधूरे कार्यों को पूरा कर क्रांति को पूर्ण कर दिखाया। 1953 ई० तक वह रूस का अधिनायक बना रहा। उसके समय में रूस में साम्यवाद दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो गया।

क्रांति के परिणाम—रूस का इस क्रांति का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति ने विश्व के सारे राष्ट्रों को प्रभावित किया। इससे रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। इस क्रांति के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हुए—

1— राजनीतिक परिणाम —

- (1) साम्यवादी शासन की स्थापना—इस क्रांति से रूस में तीन शताब्दों से चले आ रहे निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई और उसके स्थान पर साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। पूंजीपतियों का कठोरता से दमन किया गया। समाजवाद के विरोधियों को मौत के घाट उतार लिया गया। बड़े जागीरदार पूंजीपति, धर्माधिकारी

और जारशाही के अधिकारियों को या तो दश से निष्कासित कर दिया गया या जेल क सीखचा म बंद कर दिया गया ।

रूस को इस शान्ति स वग हीन समाज का उदय हुआ । जिसमें व्यक्ति की योग्यता और श्रम का पूरा मूल्यांकन किया जाता था । इसलिये विद्वानों का यह मानना है कि मार्च 1917 की शान्ति केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित रही जबकि नवम्बर 1917 ई० की शान्ति से राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । इस शान्ति से रूस में सामाजिक समानता स्थापित हुई । अब मजदूर किसान व पू जीपति में कोई अंतर नहीं रहा । कानून के समक्ष सभी समान थे । इसके अतिरिक्त सभी को अपनी योग्यतानुसार उन्नति का अवसर प्राप्त हुआ ।

(ii) पराधीन राष्ट्रों में नवचेतना का संचार—रूस की इस शान्ति का एशिया और अफ्रीका के पराधीन राष्ट्रों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । इससे उन पराधीन देशों की जनता में साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की नवचेतना का संचार हुआ । अब इन देशों की जनता ने अधिकारा और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन को और तेज कर दिया । इस शान्ति से प्रभावित होकर भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की गति और तज हो गई ।

(iii) रूस द्वारा साम्यवाद का प्रसार इस शान्ति के पश्चात् रूस ने विश्व के अनेक देशों में साम्यवाद का प्रचार किया । जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ । एशिया में चीन जसा विशाल देश भी साम्यवादी बन गया । इसके अतिरिक्त एशिया के कुछ अन्य देशों में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई । अन्य कई देशों में भी इस विचार धारा का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है ।

(iv) रूस के पश्चिमी राष्ट्रों में तनावपूर्ण सम्बन्ध—रूस और मित्र राष्ट्रों के बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध होने के तीन कारण थे—पहला कारण यह था कि रूस ने मित्र राष्ट्रों की सलाह लिये बिना युद्ध बन्द कर दिया और जर्मनी के साथ व्हेस्ट लिटोवस्क की संधि कर ली । मित्र राष्ट्र नहीं चाहते थे कि रूस जर्मनी से संधि करे । इसलिए वे उससे नाराज हो गये । दूसरा कारण यह था कि मित्र राष्ट्रों ने जार के समय रूस को कर्जा दिया था । उसे बोलोविक सरकार ने चुकाने से इनकार कर दिया । तीसरा कारण यह था कि साम्यवाद दिन प्रति दिन प्रबल होता जा रहा था । इसलिए इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका आदि पूँजीवादी देशों ने रूस में सैनिक हस्तक्षेप कर और कान्ति

विरोधी तत्वों की सहायता देकर त्राति को असफल बनाने का प्रयास किया, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली।

लेनिन और उसके साथी रूस में साम्यवादी को इड़तापूर्वक स्थापित कर विश्व के अन्य देशों में इसका प्रसार करना चाहते थे। जब बोलशेविक सरकार ने जार के समय की गुप्त संधियों को प्रकाशित करवाया तो इससे मित्र राष्ट्रों के साथ रूस के सम्बन्ध और कटू हो गये। जब मित्र राष्ट्रों को रूस की त्राति को विफल बनाने में सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने रूस का बहिष्कार करना प्रारम्भ कर दिया।

इसलिये युद्ध समाप्ति के पश्चात् पेरिस शान्ति सम्मेलन में रूस को नहीं बुलाया गया। युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था वे उनमें नहीं लौटाये गये। इसके बाद कई वर्षों तक उसे राष्ट्र सघ का सदस्य नहीं बनाया गया। रूस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये गये। रूस ने पश्चिमी देशों के विरोध का दृढ़ कर सामना किया। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, साम्यवादी गुट और पूँजीवादी गुट।

(v) यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय— पूँजीपति राष्ट्रों ने साम्यवादी को कुचलने का हर सम्भव प्रयास किया। रूस ने इसका दृढ़ कर सामना किया। इन दोनों के सघ के कारण यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ। जस जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद और इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्टवाद का उत्कर्ष हुआ। इन दोनों अधिनायकों ने साम्यवादी विरोधी प्रचार किया। फलस्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस ने इनके प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई। जिसके कारण तानाशाही शक्तियों का उदय सम्भव हो सका और ससार को द्वितीय महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम मुग्तान पड़ा।

2—सामाजिक परिणाम—

(1) नये समाज का जन्म—इस त्राति के फलस्वरूप रूस में सामाजिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। रूस की पुरानी सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो गई। भूमि और उद्योग सरकार ने अपने हाथ में ले लिये। कारखानों, बैंकों और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार के कार्यों से रूस में पूँजीपति, सामंत और कुलीन वर्ग के प्रभाव का अन्त हो गया। मकनल बनस न लिखा है कि 'कारखाने, छानने, रेल की पटरियाँ और जनता के प्रयोग की वस्तुएँ सबका स्वामी राज्य था। भण्डार या तो सरकारी थे या सहकारिता द्वारा चलाये जाते थे। कृषि का भी पूर्ण रूप से

सरकारी कारण हो गया था। देश की भूमि का दबवा भाग सरकार का था, चाकी सब सहकारिता द्वारा संचालित था। सामाजिक क्षेत्र, में भी कोई कम क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुये थे।¹² इस क्रांति से ग्रामों में मजदूरों और किसानों का प्रमुख स्थापित हो गया। अब रूस में मजदूरों की प्रतिष्ठा होने लगी। अब उनके शोषण की समस्या भी नहीं रही थी।

(ii) शिक्षा का विकास—क्रांति के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक विकास हुआ। सरकार ने शिक्षा का काम अपने हाथ में ले लिया। 1930 ई० तक रूस में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 1930 ई० तक रूस की 90 प्रतिशत जनता शिक्षित हो गई।

(iii) धर्म पर प्रभाव—इस क्रांति के कारण धर्म पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। साम्यवाद में धर्म के लिये कोई स्थान नहीं था। इसलिये रूस में धर्म या धार्मिक संस्थाएँ नहीं बन सहीं। रूस में चर्चों की संख्या कम कर दी गई। धर्म की भूमि और सम्पत्ति पर सरकार ने अधिकार कर लिया।

(iv) स्त्रियों की दशा में सुधार—रूस की स्त्रियों की दशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। अब उन्होंने घर की चार दिवारी से बाहर निकलकर कारखानों में, सेना में और राजकीय नौकरियों में काम करना प्रारम्भ कर दिया। यही कारण है कि आज रूस में 50 प्रतिशत स्त्रियाँ डाक्टर हैं। अनेक स्त्रियाँ सेना में जंवरन हैं और कारखानों में बगैरों स्त्रियाँ मजदूर एवं फीरभन का काम कर रही हैं।

3—आर्थिक परिणाम—

(1) रूस का औद्योगिक विकास—1917 ई० की क्रांति के बाद रूस में तीव्र गति में औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की। रूस की साम्यवादी सरकार ने कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और जमीन किसानों में बाँट दी। इससे किसानों की राहत मिली और पूँजीपति वर्ग समाप्त हो गया परन्तु रूस में उत्पादन घट गया। जिसके कारण 1921 ई० में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण 50 लाख व्यक्ति भूख से मर गये। इसलिये लेनिन ने 1921 ई० में नवीन 'आर्थिक नीति' अपनाई। जब स्टालिन रूस का प्रधान बना तो उसने रूस का औद्योगिक विकास करने के लिए दो पंच वर्षीय योजनाएँ लागू कीं।

इसमें उसे आश्चर्यजनक सफलता मिली। इन योजनाओं से रूस का औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। अब रूस आत्म निर्भर बन गया। इसके पश्चात् रूस निरन्तर विकास कर रहा है। अब रूस विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है।

(ii) श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि—इस क्रांति के पश्चात् पूंजीपति वर्ग का अन्त हो गया। सरकार ने कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्रांति से पूर्व पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता था। उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उनको मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, परन्तु आज रूस का मजदूर सर्वाधिक सुरक्षित है। उसके रहने के लिए आवास की अच्छी व्यवस्था है। कारखानों में विश्राम गृह और मनोरंजन कक्ष हैं। मनोरंजन के साधनों द्वारा श्रमिकों को स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है। वृद्धावस्था में पेंशन बीमारी का बीमा और सामाजिक बीमा की व्यवस्था भी है। सरकार बेरोजगारों को काम देना अपना कर्तव्य मानती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रूस की यह क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति थी जो विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे मजदूरों का शोषण समाप्त हो गया। इस क्रांति के पश्चात् रूस में किमाना और मजदूरों की सरकार स्थापित हुई, जो सोवियत रूस के नाम से प्रसिद्ध है। रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। लेनिन और स्टालिन जैसे योग्य नेताओं के नेतृत्व के कारण ही यह क्रांति सफल हो सकी। स्टालिन को रूस का तानाशाह कहा जाता है और उसकी बहुत अधिक आलोचना की जाती है। परन्तु उसने कठोर प्रशासन के द्वारा ही लेनिन के अधूरे कार्यों को पूरा कर इस क्रांति को सफलता में सम्पूर्ण किया।

प्रस्तावित सप्तम पाठ्य पुस्तकें—

- 1—सेवाइन—ए हिस्ट्री आफ वर्ल्ड सिवलीजेशन
- 2—बीच डब्ल्यू० एन०—हिस्ट्री आफ दी वर्ल्ड
- 3—लगसम—वर्ल्ड सिम, 1919
- 4—मकनल बनस—वस्टन सिवलीजेशन
- 5—जैट जीन और डूमड विश्व का इतिहास
- 6—गूथ, जी० पी०—आधुनिक यूरोप का इतिहास
- 7—वेल्स, एच० जी० दी आउट लाइन आफ हिस्ट्री

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भविष्य में युद्ध सम्बन्धी सभाषनाओं को रोकने के लिए तथा शांति स्थापित करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र सघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र सघ की स्थापना मनुष्य की शताब्दियाँ के प्रयास का फल था। इससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नई व्यवस्था प्रारम्भ हुई।

आदिकाल से मनुष्य शांति स्थापना के लिए प्रयास करता रहा है। मनुष्य को यह प्रवृत्ति रही है कि उसने मदा से युद्ध के पश्चात् शांति के प्रयास किये हैं और शांति के समय युद्ध की बात करता रहा है। राष्ट्र सघ की स्थापना एक नब्बी ऐतिहासिक प्रगति का परिणाम था। यो तो मध्यकाल से ही यूरोप के दायनिको ने शांति स्थापित करने के लिए और युद्धों की रोकने के लिए अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की थीं। 14 वीं शताब्दी में दोगे ने 'डिवाईन कामेडी' नामक पुस्तक लिखी। जिसमें उसने शांति स्थापित करने के बारे में सुझाव दिये थे। सातहवीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच शांति स्थापित करने सम्बन्धी अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं। परन्तु नेपोलियन के युद्धों से पूर्व इन योजनाओं को क्रियावित नहीं किया गया। य सिर्फ आदर्शवाणियों की कल्पना ही बनी रही। प्रायः प्रत्येक युद्ध की समाप्ति के पश्चात् शांति स्थापित करने के लिए प्रयास आरम्भ ही जाते हैं। नेपोलियन के भयानक युद्धों ने यूरोप की प्राचीन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया था। अब एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता थी, जो यूरोप का पुनः निर्माण कर सके। नेपोलियन के उल्लंघन के बाद यूरोपियन राष्ट्रों ने युद्ध की सभाषनाओं से भयभीत होकर शांति के लिए अनेक प्रयत्न किये थे, तथा से अन्तर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन की परम्परा प्रारम्भ हुई।

1815 ई० में पहली बार वियना काँग्रेस ने एक सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें सभी यूरोपियन देशों ने भाग लिया। यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का था। इसमें यूरोप की प्रादेशिक व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था को स्थायी बनाये

रखने के लिये 'यूरोपीय व्यवस्था' की स्थापना की गई। शांति स्थापित करने के लिये 'पवित्र सभ' की स्थापना की गई। इन प्रयासों में यूरोपियन राष्ट्रों ने अपनी समस्याओं को सुनझाने के लिए सम्मेलन बुलाने आरम्भ कर दिए। पेरिस शांति सम्मेलन (1856), वर्लिन कांग्रेस (1878), हेग सम्मेलन (1899 एवं 1907) आदि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाये रखने के लिये बुलाये गये थे। इन सम्मेलनों ने राष्ट्र सभ के निमाण का भाग प्रयुक्त कर दिया। यद्यपि इन सम्मेलनों की असफलता के कारण ही प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ था। जिसके परिणाम सभी को भुगतने पड़े थे।

राष्ट्रसभ का जन्म — प्रथम विश्व युद्ध के भयकर विनाशकारी परिणाम हुए। इसलिये भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों को रोकने के लिये एव युद्ध काल में ही शांति स्थापित करने के लिये विद्वानों ने अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की। परिणामस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्र सभ की स्थापना सम्भव हो सकी।

एच० जी० वेल्स ने लिखा है कि 'राष्ट्र सभ बोलत में बंद मानववादी एक मनुष्य था, जिससे यह आशा की जा रही थी कि वह समस्त कठिनाईयों को पार कर सत्तार पर राज्य करेगा।'¹

मकनेल बनस ने लिखा है कि 'युद्ध समाप्त करवा वाली' संघिया राष्ट्रसभ में सकलित कर दी गई। विश्व के छोटे और बड़े राज्यों के सहयोग से दीर्घ काल से इच्छित शांति के स्वप्न को पूरा करने के लिये राष्ट्रसभ की स्थापना की गई। जिस शांति के लिये अमेरिका को युद्ध में घसीटा गया उसी के राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रसभ को सजीव किया।'²

इसी प्रकार एन्ट और जीन ड्रनड ने लिखा है कि "एक राष्ट्रसभ बनाने का विचार लोगों के मन में शताब्दियों से था। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिकाओं ने राष्ट्रपति विल्सन के अलावा बहुत से व्यक्तियों को इस बात के लिये कटिबद्ध कर दिया कि एक राष्ट्रसभ ही बनाया जाए।"³

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रसभ की स्थापना की। विल्सन ने 8 जनवरी 1918 ई० को अपने 14 प्रसिद्ध सूत्रों की घोषणा में राष्ट्रसभ की स्थापना पर जोर दिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रसभ की रूपरेखा तयार करने के लिये एक समिति की स्थापना की गई। जिसने अध्यक्ष विल्सन थे। ब्रिटेन के लार्ड सेसिल और फिलीमोर तथा

1—वेल्स एच० जी०—दी आउट लाईन आफ हिस्ट्री—पृष्ठ 1105

2—मकनेल बनस—वेस्टन सिवनीजेस—पृष्ठ 752

3—एन्ट और जीन ड्रनड—विश्व का इतिहास—पृष्ठ 629

दक्षिणी अफ्रीका के जनरल समुद्रस इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने 3 फरवरी को राष्ट्रसघ का प्रारूप तैयार किया। जिसे 14 फरवरी 1919 को शांति सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। 28 फरवरी 1919 ई० को सम्मेलन की आम सभा ने इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया। इस प्रारूप में केवल 4000 शब्द थे। इस प्रकार 10 जनवरी, 1920 को राष्ट्रसघ ने बंधानिक दृष्टि में काय करना प्रारम्भ किया।

सँगसम न लिखा है कि 'इस सघ को वास्तव में युद्ध को समाप्त करने और शांति व्यवस्था बनाय रखने का काय सीपा गया था।'¹

राष्ट्रसघ को बर्साय को सधि का एक अंग बना दिया गया। इस सधि की प्रथम 26 धाराओं में राष्ट्र सघ के सविधान का बणन किया गया है। राष्ट्रसघ का प्रधान कार्यालय स्विटजरलण्ड के नगर जिनेवा में रखा गया। इस सघ की बैठक प्रति बय सितम्बर में बुलाई जाती थी, परंतु आवश्यक कारणवश इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती थी। इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन की महत्वपूर्ण देन राष्ट्रसघ की स्थापना करना था। यह पहला सगठन था, जिस बंधानिक मायता प्राप्त थी, और जिसका एक सविधान था। इसकी स्थापना को विश्व इतिहास में एक प्रान्तिकारी बिंदु कहा जा सकता है।

राष्ट्रसघ के उद्देश्य—हेजेन ने लिखा है कि "सघ के निर्माण के पीछे युद्ध को रोकना तथा शांति का बनाय रखने की प्रबल शक्ति थी और इस सस्था का यही उदघोषित उद्देश्य था।"²

राष्ट्रसघ की स्थापना विश्व में शांति स्थापित करन के लिय की गई थी। यह सघ अपन उद्देश्य में तभी सफल हो सकता था, जबकि सभी राष्ट्र युद्ध को घृणा का दृष्टि में देखें। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक शांति के लिय की गई सधियों का पासन करें। सधों में राष्ट्रसघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(1) इस सघ का मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति व्यवस्था बनाये रखना था। इसके अतिरिक्त इस सघ के सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा करना था। इसका प्रत्येक सदस्य यह शपथ लेता था कि वह अपने सदस्य राष्ट्रों की प्रान्तिक अघण्डता को बनाये रखेगा।

(2) राष्ट्रसघ युद्ध की सभावनाओं को कम करने के लिए अस्त्र शस्त्र की दौड़ को एक साम्राज्यवाद को सीमित करने का प्रयास करेगा।

(3) राज्यों के आपसी दिवादा का बिना युद्ध का सहारा लिये शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना।

1—सँगसम—दिक्कट सिम 1919—पृष्ठ 40

2—हेजेन आधुनिक यूरोप का इतिहास—पृष्ठ 601

(4) होने वाले युद्धों को मन्त्रीपूण ढंग से सम्मेलनों के द्वारा रोकने का प्रयास करना ।

(5) प्रत्येक वाय में सभी राष्ट्रों के हितों का ध्यान रखना ।

(6) सभी राष्ट्रों के विकास कार्यों में यथा सम्भव सहायता देना ।

(7) इस संधि का मुख्य उद्देश्य पेरिस शांति सम्मेलन में की गई संधियों का संवर्धित देशों में पालन करवाना था और पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था को बनाये रखना था । राष्ट्रसंघ को डार्नजिग नगर और सार्वभौम प्रशासन व्यवस्था का संचालन 15 वर्ष के लिये दे दिया था ।

(8) जन साधारण का कल्याण के लिये कार्य करना । जस दास प्रथा को समाप्त करना, महाभारिया को रोकने का प्रयास करना स्वास्थ्य सुधार के लिये प्रयास करना, स्त्रियों के श्रम बिक्रय पर प्रतिबंध लगाना और मानव जीवन को सुखी बनाने के लिये आर्थिक, सामाजिक और साहित्य के क्षेत्र में विकास करना ।

राष्ट्रसंघ की संख्या—प्रारम्भ में राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या 31 थी, जो 1928 ई० में बढ़कर 54 हो गई । भारत भी राष्ट्रसंघ का सदस्य था । राष्ट्रसंघ का यह दुर्भाग्य था कि कई बड़े-बड़े देश इसके सदस्य नहीं बने थे । जमे इस संधि का जन्मदाता विल्सन अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनवा सका था । प्रारम्भ में जर्मनी और रूस का इसका सदस्य नहीं बनाया गया ।

संधि के नियमों का पालन करने का आश्वासन देने पर कोई भी राष्ट्र इसका सदस्य बन सकता था । ऐमेम्बली का 2/3 बहुमत होने पर ही किसी भी राष्ट्र को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया जाता था । इसी प्रकार यदि कोई राष्ट्र इस संधि की सदस्यता छोड़ना चाहता, तो उस दो वर्ष पूर्व इसको सूचना देनी पड़ती थी । 1923 ई० में ब्राजील ने 1933 ई० में जर्मनी ने और जापान ने तथा 1937 ई० में इटली ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को छोड़ दिया । यदि कोई सदस्य राष्ट्रसंघ के नियमों का पालन नहीं करता तो ऐसे देश को कौन्सिल की सब सम्मति से राष्ट्रसंघ से बाहर निकाल दिया जाता था । 1939 ई० में रूस को इसी प्रकार राष्ट्रसंघ से बाहर निकाला गया था । इस प्रकार महाशक्तियों की उपेक्षा के कारण राष्ट्रसंघ निरंतर कमजोर होता गया ।

प्रधान कार्यालय—राष्ट्रसंघ का प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैण्ड की राजधानी जेनेवा में रखा गया । इस संधि का सचिवालय जिनवा में होने से यहीं संधि की बैठक बुलाई जाती थी । वैसे संधि की वार्षिक बैठक सितम्बर माह में बुलाई जा सकती थी ।

राष्ट्रसंघ के अंग—राष्ट्रसंघ की दूसरी धारा के अनुसार संधि के कार्य का संचालन करने के लिये निम्न तीन विभागों की स्थापना की गई ।

- 1 साधारण सभा (एसेम्बली)
- 2 परिषद (कौंसिल)
- 3 सचिवालय ।

इस अतिरिक्त राष्ट्रसभ के काम में सहयोग देने के लिये सरक्षण आयोग, सैनिक आयोग, परामशदाता आयोग आदि गठित किये गये थे । सभ के प्रमुख अंग का वर्णन निम्न प्रकार है —

(1) साधारण सभा (एसेम्बली)—राष्ट्रसभ का पहला अंग एसेम्बली था । इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि थे । एसेम्बली में छोटे और बड़े सभी राष्ट्रों को एक समान अधिकार प्राप्त थे । प्रत्येक राष्ट्र एसेम्बली में तीन प्रतिनिधि भेज सकता था । परन्तु उन्हें एक ही मत देने का अधिकार था ।

एसेम्बली 2/3 बहुमत से किसी भी राष्ट्र को इस सभ का सदस्य बना सकती थी । इस सभ की धारा 5 के अनुसार किसी भी राजनीतिक विषय पर निर्णय लेने के लिये बठक में उपस्थित सभी सदस्यों की संवत्सम्ति आवश्यक थी । यदि बठक में एक भी राष्ट्र उस निर्णय का विरोध करता, तो बहु निर्णय नहीं लिया जा सकता था ।

एसेम्बली का काम सचानन के लिये एक सभापति और एक उप सभापति होना था । इसकी बठक प्रतिवर्ष सितम्बर महीने में जिनवा में बुलाई जाती थी । इसके अतिरिक्त आवश्यक कारणवश इसकी विंग बठकें भी बुलाई जा सकती थी । इन सभा का काम छ सभितियों के द्वारा सम्पन्न किया जाता था । सभा के काम की देखभाल महासचिवी करता था ।

एसेम्बली सभ से सम्बन्धित किसी भी समस्या पर वाद विवाद कर सकती थी । जब राष्ट्र सभ के नये सदस्य बनाता, अग्यार्ई सदस्यों का चुनाव करना राष्ट्र सभ के बजट पर स्वीकृति देना, महामन्त्रिचव एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिये न्यायाधीशों को नियुक्त करना और राष्ट्र सभ के सचिवालय में सहायन करना आदि इसका काम थे ।

एसेम्बली धारा 3 के अनुसार विश्व शांति को खतरा पहुँचाने वाली सभी परिस्थितियों पर विचार कर सकती थी । लैंगसम न लिखा है कि ' विश्व शांति का प्रभावित करने वाला कोई भी मसला एसेम्बली के वाद विवाद का विषय था ।'¹

इसके सदस्य राष्ट्र अपनी शिवायतें महासभा में प्रस्तुत कर सकते थे । परन्तु महासभा के सदस्य को राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था । एसेम्बली का पहला अधिवेशन 15 नवम्बर 1920 ई० को और अंतिम

अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई० म बुलाया गया था। इस अधिवेशन म उपस्थित सदस्यों ने सवसम्मति स इस सध को समाप्त करन का प्रस्ताव पास किया था।

(2) कौंसिल (परिपद) — कौंसिल राष्ट्र सध की सबसे शक्तिशाली सस्था थी। इसम पाच स्थायी और चार अस्थायी सदस्य थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लण्ड फ्रांस जापान और इटली आदि दश इसक स्थायी सदस्य थ परंतु अमेरिका की सीनेट ने राष्ट्र सध का सदस्य बनन पर स्वीकृति नहीं दी। इसलिये अमेरिका ने अपनी सदस्यता का प्रारम्भ स ही उपयोग नहीं किया। कौंसिल क चार अस्थाई सदस्या का निर्वाचन एसम्बली क सदस्यों के द्वारा किया जाता था। 1920 ई० म ब्राजील बल्जियम, यूनान और स्पेन कौंसिल के अस्थाई सदस्य चुन गये थ। 1922 ई० म अस्थाई सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर दस कर दी गई। अस्थाई सदस्या की सख्या आवश्यकता अनुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती थी। 1939 ई० म स्याई सदस्य केवल तीन दश हस फ्रांस, और ब्रिटेन रह गये थ। जबकि अस्थाई सदस्यों की संख्या 11 थी।

कौंसिल की बैठक वष म तीन बार जनवरी, मई और सितम्बर माह म बुलाई जाती थी परंतु आवश्यक कारणवश उसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती थी। परिपद की कार्यवाही का सचालन सभापति करता था जिम्मा चुनाव फ्रांस की बणमाला के अनुसार किया जाता था। इसलिये परिपद क प्रत्येक सदस्य को एक बार सभापति बनन का अवसर अवश्य मिल जाता था। इसने स्थायी सत्स्यों का वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था। कौंसिल म प्रत्येक विषय पर निणय सवसम्मति स लिया जाता था। राष्ट्र सध की असफलता क लिये यह "यवस्था बहुत अधिक सीमा तक जिम्मेदार थी। कौंसिल क प्रमुख काम निम्नलिखित थे —

- (1) सार तथा डार्जिंग प्रदश की प्रशासन यवस्था का सचालन करना।
- (2) शासनादेश प्राप्त राज्या का वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना।
- (3) अल्प सख्यको की सुरक्षा के लिये कार्य करना।
- (4) युद्ध के खतरे को दूर रखने क लिये निःशस्त्रीकरण की योजनाएँ प्रस्तुत करना।
- (5) आश्रामन कार्यवाहियों को रोकने क लिय यथासम्भव प्रयास करना।
- (6) अंतर्राष्ट्रीय झगडों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना।
- (7) महासचिव की नियुक्ति पर स्वीकृति देना और सचिवालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- (8) सध के नियमों की अवहेलना करने वाले सदस्य राष्ट्रों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करना।
- (9) कौंसिल ऐसे किसी भी विषय पर विचार कर सकती थी, जिससे विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरा पदा होता हो।

राष्ट्र सभ

कौमिल की पहली बैठक 6 जनवरी 1920 ई० को एव अंतिम बैठक 14 सितम्बर 1938 ई० को बुलाई गई थी। कौंसिल और एसेम्बली ने सदस्यों को यह अवसर दिया कि वे अपनी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल कर लें।

(3) सचिवालय—राष्ट्र सभ का प्रशासकीय कार्यालय जिनवा में रखा गया, जिसे सचिवालय कहते थे। राष्ट्र सभ का प्रबंध, पत्र व्यवहार और व्यवस्था बाकि सभी काय इसी सचिवालय के माध्यम से होते थे। इसमें 750 कर्मचारी और अधिकारी काम करते थे। जिनकी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर महासचिव करता था।

सचिवालय का काम राष्ट्र सभ के प्रशासन की देखभाल करना था। इसका प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता था। जिसकी नियुक्ति कौंसिल एसेम्बली के परामर्श में करती थी। महासचिव के कार्यों में सहयोग देने के लिये दो सहकारी और दो उप सहकारी सचिव नियुक्त किये जाते थे। सचिवालय 11 भागों में विभाजित था। प्रत्येक विभाग का एक डाइरेक्टर होता था। सचिवालय परिषद् और सभी दोनों के लिये काय करता था। इसके प्रमुख काय निम्नलिखित थे—

- (i) एसेम्बली तथा कौंसिल में रखे जाने वाले विषयों की सूची तैयार करना।
- (ii) एसेम्बली और कौंसिल की बसों आयोजित करना उनकी व्यवस्था करना और बैठक की कायवाही का विवरण तैयार करना।
- (iii) पत्र व्यवहार करना सधियों का रिक्वाइड रखना आदि। इसके मुख्य काय थे।

राष्ट्र सभ की स्वायत्त सस्याएँ राष्ट्र सभ की निम्न दो स्वायत्त सस्याएँ थी—

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय 'यायालय
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सभ

(1) अन्तर्राष्ट्रीय 'यायालय—राष्ट्र सभ की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय सगडों को मिटाकर शांति स्थापित करने के लिये की गई थी। इसकी धारा 14 के अनुसार सितम्बर 1921 ई० में हालण्ड के हेग में अन्तर्राष्ट्रीय 'यायालय की स्थापना की गई थी। यह सभार का पहला अन्तर्राष्ट्रीय 'यायालय था, जिसका ज मदाता राष्ट्र सभ था। आरम्भ में इस 'यायालय में 'यायाधीशों की सस्या 11 और उप 'यायाधीशों की सख्या 4 निश्चित की गई थी परंतु काय भार बढ़ जाने से इसकी सख्या बढ़ाकर 15 कर ली गई। 'यायाधीश का कायकाल 9 वर्ष था। इसका वार्षिक बजट पाँच लाख डॉलर था। अन्तर्राष्ट्रीय 'यायालय के प्रमुख काय निम्नलिखित थे—

- (i) अंतर्राष्ट्रीय भण्डा का निणय करना ।
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करने वाले राष्ट्र व विरुद्ध कायवाही करना ।
- (iii) परिषद और एसेम्बली को परामर्श देना ।
- (iv) सविधान की धाराओं की व्याख्या करना ।
- (v) अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर विचार करना तथा क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित करना ।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी विषय पर निर्णय बहुमत से लिया जाता था । इसके फोरम की पूर्ति 9 न्यायाधीशों से होती थी ।

(2) अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संध—राष्ट्र संध की धारा 13 के अनुसार मजदूरों की दशा में सुधार करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संध की स्थापना की गई । श्रम संध का प्रधान कार्यालय जिनेवा में रखा गया । इस संध का मुख्य उद्देश्य मजदूरी करने वाली स्त्रियों पुरुषों और बच्चों की दशा में सुधार करने के लिये प्रयास करना था । संध के सार मजदूरों में समानता स्थापित करना और मजदूरों की सतुष्टी के लिये काय करना था । लगसम ने लिखा है कि 'इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संध का उद्देश्य मनुष्य के श्रम के लिये मानवीय परिस्थितियाँ प्राप्त कर उन्हें बनाये रखना था ताकि आदमी औरत और बच्चा का शोषण न हो सके' ।¹

विश्व का कोई भी राष्ट्र इस संध का सन्ध्य बन सकता था । समुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्र संध का सदस्य न होते हुए भी इस संध का सदस्य था । इस संध के निम्न तीन विभाग थे

- 1 साधारण सम्मेलन
- 2 प्रशासन विभाग
- 3 अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय

(1) साधारण सम्मेलन—प्रत्येक देश साधारण सम्मेलन में चार प्रतिनिधि भेज सकता था । जिनमें से एक मजदूरों के द्वारा दो सरकार के द्वारा और एक मिल मालिकों के द्वारा भेजा जाता था । इसका अधिवेशन वष में एक बार बुलाया जाता था । दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते थे । साधारण सम्मेलन मजदूरों की दशा में सुधार करने के लिये प्रस्ताव पारित करता था । 1939 ई० तक साधारण सम्मेलन ने 133 प्रस्ताव पारित किये । जिनके अनुसार धर्मियों के लिये एक सप्ताह में काम करने के 48 घंटे निश्चित किये गये । 14 वष से कम आयु वाले बच्चों के कारखाने में काम करने पर रोक लगा दी गई । महिला मजदूरों की सुविधा के लिये भी कई नियम बनाये गये ।

(2) प्रशासन विभाग—प्रशासन विभाग म 32 सदस्य होत थे । जिनको 3 वष के लिये निर्वाचित किया जाता था । इसम आठ मजदूरों के, 8 मिल मालिकों के और 16 विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते थे । इस सभा का मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सभ के कार्यालय क निर्देशक का चुनाव करना और उस पर नियंत्रण बनाये रखना था ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया था । इस कार्यालय का मुख्य काम श्रमिकों के कल्याण क लिये सामग्री एकत्रित करना था । साधारण सम्पन्न की बैठक क लिय यह श्रम कार्यालय विचारणीय विषयों की सूची तयार करता था । इसक अतिरिक्त श्रमिकों के लिये कल्याण का कार्य करने वाली मन्त्रालयों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करता था । श्रमिकों की रिपोर्ट और बुलटिन भी प्रकाशित करता था । इस श्रम कार्यालय का एक अध्यक्ष होता था जो 350 विशेषज्ञों की नियुक्ति करता था । ये विशेषज्ञ श्रमिकों के कल्याण क लिये सिफारिशें प्रस्तुत करते थे । इस रस्ते न श्रमिकों क कल्याण क लिये अनेक कार्य किए ।

मै-डेड प्रणाली—मै-डेड प्रणाली का सरक्षण प्रयास या अधिदेशीय आदेश व्यवस्था भी कहा जाता है । प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् परिम शांति सम्मेलन की मधिया क अनुसार जर्मनी तथा टर्की क उपनिवेशों को राष्ट्र सभ के अधीन कर लिया गया । राष्ट्र सभ न ब्रिटेन फ्रान्स बेल्जियम और जापान आदि देशों के इन उपनिवेशों पर प्रशासन करने का अधिकार लिया । ये देश राष्ट्र सभ की ओर न इन उपनिवेशों के प्रशासन की दखल बरतते थे । इन प्रकार विजयी राष्ट्रों ने राष्ट्र सभ के नाम पर इन उपनिवेशों पर शासन करना प्रारम्भ किया, क्योंकि राष्ट्रसभ न इन उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों के संरक्षण म छोड़ दिया था । सरक्षण मत्र राष्ट्र सभ के निर्देशानुसार इन उपनिवेशों पर शासन करते थे । उन्हें शासन प्रबंध की रिपोर्ट प्रति वष परिपद म प्रस्तुत करनी पड़ती थी । इन रिपोर्टों की जांच राष्ट्र सभ की कौमियर द्वारा नियुक्त संरक्षण आयोग करता था । इस व्यवस्था का मै-डेड व्यवस्था कहा जाता है ।

राष्ट्र सभ की मै-डेड व्यवस्था के अंतगत 14 क्षेत्र थे । इन क्षेत्रों का तीन भाग म विभाजित किया गया था । इन व्यवस्था के बावजूद भी सरणित प्रदेशों जर्मनी इच्छानुसार शासन करते रहे । अपने हितों को दृष्टिगत रखन हुए इन प्रदेशों का शोषण किया और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिय वहाँ की जनता पर नाना प्रकार के शोषण किए । इस प्रकार संरक्षण व्यवस्था के साम्यवादी अन्तर्भावों की समाप्ति नहीं किया जा सका । इस व्यवस्था से ब्रिटेन और फ्रान्स को बहुत अधिक लाभ पट्टा । संसद ने सिखा है कि 'राष्ट्र सभ की संरक्षण प्रणाली ने विश्व शांति की भावना को प्रोत्साहन दिया । पल्लव

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह प्रवस्था समुक्त राष्ट्र सभ में मिलती गई ।¹

राष्ट्र सभ की सफलताएँ—राष्ट्र सभ की सफलता के लिये हम उसके राजनीतिक कार्य और गर राजनीतिक कार्यों पर विचार करना पड़ेगा । सभ राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्णरूप से असफल सिद्ध हुआ परन्तु गर राजनीतिक कार्यों में उस काफ़ी सीमा तक सफलता प्राप्त हुई । लगसम ने लिखा है कि 'कदाचित् राष्ट्र सभ का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का प्रचार किया और निष्पक्षतात्मक रूप से उसके उद्देश्य और सिद्धान्त समुक्त राष्ट्र सभ में जा मिले जो हर बिन्दु और हर मोड़ पर राष्ट्र सभ का प्रतिबिम्ब है । सेवाइन ने राष्ट्रसभ के बारे में लिखा है कि राष्ट्रसभ ने युद्धोपरांत स्थिति में शान्ति बनाये रखने के लिये अथक परिश्रम किया । जरा इस प्रश्न पर रुक कर विचार कीजिये कि यदि राष्ट्र सभ न होता तो क्या होता ? दीधकालीन की तो बात छोड़िये कुछ समय के लिये भी शान्ति सुलभ नहीं होती ।² इतिहासकार प्लेट और जीन डमड ने लिखा है कि राष्ट्र सभ सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में अधिक सफल रहा । अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन द्वारा की गई सिफारिशों पर बच्चों से मजदूरी करवाने पर रोक आठ घंटे का कार्य दिवस और मजदूरों का अपना संगठन बनाने का अधिकार देना सभ की सफलताएँ थी ।³

राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएँ—राष्ट्र सभ के सचिवालय की धारा 10 से 17 के अनुसार राष्ट्र सभ आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना या युद्धों को रोकने और सामूहिक सुरक्षा के लिये उपायों की खोज करता था । यदि किसी राष्ट्र पर आक्रमण की सम्भावना हो तो वह राष्ट्र सभ से सहायता के लिए अपील कर सकता था । राष्ट्र सभ पहले दोना विवादों वाले राज्यों के मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने का प्रयास करता था । यदि आक्रमणकारी राष्ट्र राष्ट्र सभ की बात नहीं मानना तो वह उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाता था । इसके पश्चात् आवश्यक होने पर राष्ट्र सभ आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सामूहिक रूप से सैनिक कार्रवाही के आदेश दे सकता था ।

राष्ट्र सभ के पाम 20 वष की अवधि में 40 राजनीतिक विवाद आए । उसे छोटे छोटे राज्यों के विवादों को सुलझाने में सफलता मिली । स्थानीय युद्धों को ध्यापक रूप से धारण करने में रोक और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने में सफल हुआ किन्तु शक्तिशाली राष्ट्रों के विवादों को हल करने में उस सफलता नहीं मिली ।

1 लगसम—*दी वलड सि स* 1919 पृष्ठ 54

2 नैगनम—*दी वलड सि स*, 1919 पृष्ठ 55

3 सेवाइन—*ए हिस्ट्री आफ द वर्ल्ड सिविलीज़ेशन*—पृष्ठ 682

4 प्लेट और जीन डमड—*विश्व का इतिहास* पृष्ठ 630

बड़े राष्ट्रों न राष्ट्र सभ के आदेश का पालन नहीं किया। सभ को निम्नलिखित विवादा का हन करने में सफलता मिली —

(1) आर्लेण्ड द्वीप विवाद - फिनलैण्ड और स्वीडन दोनों ही देश बाल्टिक सागर के आर्लेण्ड द्वीप पर अधिकार करना चाहते थे। इसका लिये 1924 ई० में दोनों देशों में हस्ताक्षर प्रारम्भ हो गया। सभ ने फिनलैण्ड को आर्लेण्ड द्वीप पर अधिकार देकर इस विवाद का निपटाया। यह सभ की पहली महान सफलता थी।

(2) अल्बानिया का सीमा विवाद—1920 ई० में यूनान और यूगोस्लाविया में अल्बानिया पर अधिकार करने के प्रश्न को लेकर विवाद प्रारम्भ हो गया। राष्ट्र सभ ने अल्बानिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर दिया था। 1920 ई० में यह राष्ट्र सभ का मन्स्य भी बन गया था। 1921 ई० में यूगोस्लाविया और यूनान ने अल्बानिया पर अधिकार करने के लिये आक्रमण कर दिया। क्योंकि इस देश की सीमा राष्ट्र सभ ने निर्धारित नहीं की थी। सभ ने हस्तक्षेप कर इस मामले का निपटाया। उसके आदेश पर यूगोस्लाविया ने सेनाएँ हटा ली और राष्ट्र सभ ने अल्बानिया की सीमा को निर्धारित कर दिया। इस प्रकार बल्कन युद्ध का खतरा टल गया।

(3) मेसल विवाद—1923 ई० में लिथुआनिया ने मेसल पर अधिकार कर लिया। जब यह विवाद राष्ट्र सभ के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो राष्ट्र सभ ने यह निर्णय दिया कि बर्लिन के अतिरिक्त सम्पूर्ण मेसल प्रदेश पर लिथुआनिया का अधिकार रहेगा। मेसल की जनता का आन्तरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। मेसल का एक अन्तरराष्ट्रीय बन्दरगाह घोषित कर, वहाँ का शासन एक अन्तरराष्ट्रीय बोर्ड के हाथों में सौंप लिया गया।

(4) यूनान और बल्गेरिया का विवाद—1925 ई० में यूनान और बल्गेरिया के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध प्रारम्भ हो गया। यूनान ने बल्गेरिया को 70 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। इस पर बल्गेरिया ने राष्ट्र सभ से सहायता मांगी। राष्ट्र सभ के हस्तक्षेप से यह युद्ध बन्द हो गया और दोनों देशों ने अपनी-अपनी सेनाएँ हटा लीं। कौमिन ने यूनान को आक्रमणकारी घोषित किया और उसे बल्गेरिया को क्षतिपूर्ति देने के लिये कहा। मार्च 1926 ई० में यूनान ने बल्गेरिया को क्षतिपूर्ति की रकम चुका दी। इस प्रकार राष्ट्र सभ ने ग्रासानी से इस विवाद को निपटा दिया।

इसी प्रकार राष्ट्र सभ ने विलना विमना (1920-1922), ऊपरी साइलेशिया का विवाद, मोसुल का विवाद (1926), हंगरी रूमानिया का विवाद (1923-30) आदि विवादों को भी शान्तिपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक निपटा दिया। बार ने लिखा है कि "1924 ई० से 1930 ई० के काल की अवधि में राष्ट्र सभ उत्पत्ति एक प्रतिष्ठा के चरम शिखर पर था।"

गर-राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएँ—राष्ट्र सभ को राजनीतिक कार्यों में बहुत कम सफलता प्राप्त हुई परन्तु गर-राजनीतिक कार्यों में उस बहुत अधिक सफलताएँ प्राप्त हुई। उसने सामाजिक, आर्थिक और मानव कल्याण के लिये बहुत से ऐसे कार्य किये, जिसमें उस बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई। उसने निम्नलिखित गर राजनीतिक कार्य किये थे—

(1) आर्थिक सहायता—प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत से देशों की आर्थिक स्थिति शालनीय हो गई थी। राष्ट्र सभ ने इन देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। जैसे कि आस्ट्रिया हंगरी यूनान, बुल्गेरिया और डानजिग को राष्ट्र सभ ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी।

(2) युद्ध बंदियों और शरणार्थियों की सहायता—राष्ट्र सभ ने युद्ध में बंदी बनाये गये सैनिकों को छोड़कर वापस उनके देश में पहुँचाया। यह राष्ट्र सभ का कल्याणकारी कार्य था। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। इन सभ ने उन्हें वापस उनके देश में पहुँचाया।

राष्ट्र सभ ने शरणार्थियों को बसाने में भी महत्वपूर्ण सहायता दी। प्रथम विश्व युद्ध में शरणार्थियों को बसाने की एक गम्भीर समस्या उठ खड़ी हुई। युद्ध के समय लाखों रूसी तुर्क यूनानी और आर्मेनियन लोग बेघर हो गये। राष्ट्र सभ ने इनको बसाने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना की। जिसका अध्यक्ष डा० नानसेन का बनाया गया। यूनान के 15 लाख शरणार्थियों को बसाने के लिये राष्ट्र सभ ने 6 करोड़ डालर की सहायता प्रदान की। इसी प्रकार बुल्गेरिया के शरणार्थियों को बसाने के लिये उस विदेशों से ऋण दिलवाया।

राष्ट्र सभ ने अपनी समिति के माध्यम से केवल चार वर्ष के समय में दो लाख शरणार्थियों को बसाया। इन शरणार्थियों को शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की गईं। डा० नानसेन की मृत्यु के पश्चात् राष्ट्र सभ ने इस कार्य को हाथ में ले लिया।

(3) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य—राष्ट्र सभ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में प्रथमनीय कार्य किए। जन साधारण के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिये एक स्वास्थ्य सगठन की स्थापना की गई। इस सगठन के प्रयासों से मृत्यु दर में कमी हुई। युद्ध के पश्चात् रूस में टायफस बुखार की भयंकर महामारी फैल रही थी। राष्ट्रसभ ने इस महामारी को सीमित करने का प्रयास किया। स्वास्थ्य सगठन ने हैजा मलेरिया चक्रे और क्षय रोगों के इलाज ढूँढ निकाले।

(4) सामाजिक उत्थिति के लिये प्रयास—राष्ट्र सभ ने सामाजिक उत्थिति के लिये निम्न प्रयास किये—

(1) दास प्रथा पर रोक—राष्ट्रसभ ने दास प्रथा को समाप्त करने के लिये अनेक प्रस्ताव पारित किये। इस क्षेत्र में उसे अच्छी सफलता मिली।

(2) बच्चों व स्त्रियों की दशा में सुधार—राष्ट्रसघ न बच्चों व स्त्रियों के व्यापार को समाप्त करने का प्रयास किया। उसने बच्चा व स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अप्रत्याशित प्रवासियों को रोकने और वध्यावृत्ति को समाप्त करने का प्रयास किया। स्त्रियों के विवाह की आयु के बारे में भी विचार किया गया। बच्चों के कल्याण के लिये अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं। राष्ट्रसघ के सुधारों से प्रभावित होकर अनेक देशों ने इस सम्बन्ध में कई नियम बनाये।

(3) मादक वस्तुओं पर नियन्त्रण—राष्ट्रसघ ने मादक द्रव्यों जफीम, कोकीन के सर्वा पर प्रतिबंध लगाने के लिये और मादक वस्तुओं के व्यापार पर नियन्त्रण के लिये एक परामशदात्री आयोग की स्थापना की। राष्ट्रसघ को इस कार्य में भी आभासी सफलता मिली।

सम प्रथम राष्ट्रसघ को गैर राजनीतिक कार्यों में बहुत अधिक सफलताएँ प्राप्त हुईं। उसने जन साधारण के कल्याण के लिये कल्याणकारी समस्या की भाँति अनेक सराहनीय काम किए।

राष्ट्रसघ की असफलताएँ—छोटे छोटे राष्ट्रों के समझौते के निपटाने में राष्ट्रसघ सफल रहा परन्तु बड़े राष्ट्रों के विवादों की मुलज्ञान में यह असफल रहा।

1 राष्ट्रसघ की जापान के विरुद्ध असफलता—

(1) मंचूरिया सङ्घ (1931 ई०)—जापान ने राष्ट्रसघ का सदस्य होने का भी उसका सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए 1931 ई० में चीन के मंचूरिया प्रदेश पर अधिकार कर दिया। इस पर चीन ने राष्ट्रसघ से सहायता करने की अपील की। परिपक्ष में जापान का मंचूरिया में सेना हटाने का आदेश दिया लेकिन जापान ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इससे विपरीत उसने 1931 ई० तक सम्पूर्ण दक्षिणी मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। इसने राष्ट्रसघ की दुबलता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी।

1932 ई० में साधारण सभा ने जापान के काम की निंदा की। सघ ने मंचूरिया काट कर वापस करने के लिये लिटन कमिशन की नियुक्ति की। लिटन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में जापान को आक्रामक घोषित किया और उसे दोषी ठहराया परन्तु राष्ट्रसघ जापान के विरुद्ध कुछ भी कदम नहीं उठा सका। जापान ने सम्पूर्ण मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और 1933 ई० में राष्ट्रसघ की संस्यता त्याग दी। राष्ट्रसघ जापानी आक्रमण में चीन की रक्षा नहीं कर सका। इससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रसघ बड़े राष्ट्रों के आक्रमणों से छोटे राज्यों की रक्षा करने में असमर्थ है।

(ii) चीन जापान युद्ध (1937-45 ई०)—जापान ने 1937 ई० में एक सामान्य बात को लेकर बिना युद्ध की घोषणा किए चीन के प्रदेशों पर अधिकार

करना प्रारम्भ कर दिया। चीन ने दुबारा राष्ट्रसंघ से सहायता की अपील की और जापान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की लेकिन राष्ट्रसंघ के सदस्य जापान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते थे। इसलिये जापान चीन के प्रदेशों पर अधिकार करते हुए आगे बढ़ता गया। 1941 ई० में चीन जापान युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में परिणित हो गया। चीन के प्रतिनिधि वलिंग्टन क्लू ने उस अवसर पर सत्य ही कहा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रसंघ मिश्र की ममी की तरह मूक बनकर सिर्फ तमाशा ही देखता रहा।

(2) राष्ट्रसंघ की पोलण्ड के विरुद्ध असफलता—बिना नगर पोलण्ड और लिथुआनिया के बीच में स्थित था। वर्साय की संधि के द्वारा विलना नगर पर लिथुआनिया को अधिकार दे दिया गया था परन्तु पोलण्ड ने बलपूर्वक विलना पर अधिकार कर लिया। लिथुआनिया ने राष्ट्रसंघ में पोलण्ड के विरुद्ध शिकायत की। पोलण्ड को फ्रांस का समर्थन प्राप्त होने के कारण राष्ट्रसंघ उसके विरुद्ध कुछ भी कायवाही नहीं कर सका। इस प्रकार राष्ट्रसंघ का आक्रमणकारी को सजा देने में सफलता नहीं मिल सकी। वह दोनों पक्षा में समझौता नहीं रख सका। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ ने इस विवाद को निपटाने के लिये जो हल प्रस्तुत किया, वह वर्साय की संधि के विरुद्ध था।

3 राष्ट्रसंघ की इटली के विरुद्ध असफलता—

(1) कोफू द्वीप पर अधिकार (1923 ई०)—1923 ई० में यूनान में कुछ इटालियन लोगों की हत्या कर दी गई। इस पर मुसोलिनी ने यूनान के कोफू द्वीप पर अधिकार कर लिया। यूनान ने राष्ट्रसंघ से इटली के विरुद्ध शिकायत की परन्तु वह इटली के विरुद्ध कुछ भी कायवाही नहीं कर सका। इस प्रकार राष्ट्रसंघ की असमर्थता प्रकट हो गई और बड़ी शक्तियों को आश्रय कायवाहियों के लिये प्रोत्साहन मिला।

(2) इटली को एबीसीनिया पर विजय—जापान के विरुद्ध राष्ट्रसंघ की असफलता से उत्साहित होकर इटली के अधिनायक मुसोलिनी ने 1935-36 ई० में संघ के सदस्य राष्ट्र एबीसीनिया पर हमला कर दिया। बहा के सम्राट हेले सेनासी ने राष्ट्रसंघ में उपस्थित होकर इटली के विरुद्ध शिकायत की। उसने इटली की सेनाओं को एबीसीनिया से बाहर निकालने की मांग की। राष्ट्रसंघ ने इटली को आश्रय मानते हुए उसके विरुद्ध 18 नवम्बर 1935 ई० को कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाये। जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के कारण राष्ट्रसंघ का यह कदम अमफल रहा। फ्रांस और इंग्लैंड भी इटली को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिये मुसोलिनी ने एबीसीनिया पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रसंघ के आदेशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की। इससे यह स्पष्ट हो गया

राष्ट्रसघ

कि राष्ट्रसघ बड़े देश का आक्रमण होना पर छोटे राष्ट्रों की सुरक्षा नहीं कर सकता है।

(4) राष्ट्रसघ की स्पेन के विरुद्ध असफलता—स्पेन के मामले को निपटाने में भी राष्ट्रसघ असफल रहा। स्पेन में गणतन्त्रीय सरकार के विरुद्ध 1937 ई० में जनरल फ्रांको ने गृहयुद्ध प्रारम्भ कर दिया। जनरल फ्रांको गणतन्त्र को समाप्त कर स्पेन में राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। जर्मनी और इटली ने अपनी सेना जनरल फ्रांको की सहायता के लिये भेजी। इस पर स्पेन की गणतन्त्रीय सरकार ने राष्ट्रसघ से सहायता की अपील की। राष्ट्रसघ की साधारण सभा ने जर्मनी और इटली को स्पेन से सेनाएँ हटाने का आदेश दिया लेकिन दोनों राष्ट्रों ने इस आदेश का पालन करने में इन्कार कर दिया। राष्ट्रसघ इनके विरुद्ध कुछ भी बायबाही नहीं कर सका। गृह-युद्ध में जनरल फ्रांको विजयी हुआ। राष्ट्रसघ के कई मददगार न उसकी सरकार को मायता भी प्रदान कर दी। यह राष्ट्रसघ की एक महान असफलता थी।

(5) राष्ट्रसघ की रूस के विरुद्ध असफलता—रूस और फिनलैण्ड के युद्ध ने राष्ट्रसघ को मृतप्राय बना दिया। हिटलर की आक्रामक बायबाही से भयभीत होकर रूस ने आत्म रक्षा के लिये 30 नवम्बर 1939 ई० में फिनलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। फिनलैण्ड ने राष्ट्रसघ से रक्षा करने की अपील की। राष्ट्रसघ ने रूस को सघ से निष्वासित कर दिया परन्तु इसमें फिनलैण्ड को कोई लाभ नहीं पहुँचा और रूस आगे बढ़ता ही रहा। 12 मार्च 1940 ई० को फिनलैण्ड ने रूस व सामन हथियार डाल दिये। जर्मनी जापान और इटली ने राष्ट्रसघ के आदेशों की अवहेलना की थी परन्तु उन्हें सघ से निष्वासित नहीं किया गया था। रूस को निष्वासित करने का कारण यह था कि राष्ट्रसघ व अधिकांश सदस्य साम्यवाद के विरोधी थे। राष्ट्रसघ फिनलैण्ड की रक्षा करने में असफल रहा।

(6) राष्ट्रसघ की जर्मनी के विरुद्ध असफलता—जब राष्ट्रसघ इटली को एबीसीनिमा पर अधिकार करने से नहीं रोक सका तो यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रसघ बड़ी शक्तियों से छोटे देशों की रक्षा करने में और युद्ध को रोकने में असमर्थ है। जर्मनी 1926 ई० में राष्ट्रसघ का सन्ध्य बन चुका था। 1935 ई० में जर्मनी के अधिनायक हिटलर ने वेरसि शांति समझौते के विरुद्ध जर्मनी में अनिवाय मन्तिक सेवा लागू कर दी। जिसमें चित्त होकर दूसरे राष्ट्रों ने भी अपने शस्त्रों में वृद्धि करना प्रारम्भ कर दिया। 1936 ई० में हिटलर ने बर्साय की संधि के विरुद्ध राइनलैण्ड में सेनाएँ भेजी और उस पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रसघ हिटलर के विरुद्ध कुछ भी बायबाही नहीं कर सका। इसमें हिटलर का उत्साह बढ़ा और उसने 1938 ई० में चेकोस्लोवाकिया के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात् उसने आस्ट्रिया पर

अधिकार कर लिया। राष्ट्रमण्डल के विच्छेद कुछ न कर सका। अंत में हिटलर ने सितम्बर १९३९ ई० में पोलैंड का वार्साग्राह डानजिग पर आक्रमण कर दिया। जिससे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। राष्ट्रमण्डल द्वितीय विश्व-युद्ध को सुकदशक की तरह देखता रहा और उसे रोकने के लिये कुछ भी नहीं कर सका।

४ अप्रैल १९४६ ई० में राष्ट्रमण्डल का अंतिम अधिवेशन जिनवा में बुलाया गया था। इसमें ३४ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। १९ अप्रैल १९४६ ई० का एसेम्बली ने सत्रसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रमण्डल का विघटन कर दिया।

राष्ट्रमण्डल की असफलता के कारण—राष्ट्रमण्डल से लोगों को घड़ी आशाएँ थीं। लोगों को यह विश्वास हो गया था कि अब राष्ट्रमण्डल भविष्य में युद्ध नहीं होने देगा और विश्व में शांति बनाय रखेगा। परन्तु जनता की यह आशाएँ शीघ्र ही निराशाओं में बदल गईं। इसकी स्थापना के २० वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया, जिसके विनाशकारी परिणाम सत्तार को भुगतने पड़े। राष्ट्रमण्डल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में और विश्व में शांति स्थापित करने में असफल रहा। राष्ट्रमण्डल की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(१) वर्साय की संधि का एक अंग—राष्ट्रमण्डल का जग बर्माय की संधि का द्वारा हुआ था। इस संधि की प्रथम २६ धाराओं में राष्ट्रमण्डल के संविधान का वर्णन किया गया था। विल्सन ने यह प्रावधान रखा था कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रमण्डल इन संधियों में संशोधन कर सकेगा परन्तु भारत के नेतृत्व में एक गुट ने संशोधन का विरोध किया।

राष्ट्रमण्डल का वर्साय की संधि से सम्बंध होने के कारण पराजित राष्ट्र इसके विजेताओं का एक सच मानते थे और उस घणा की दृष्टि से देखते थे। राष्ट्रमण्डल का काम वर्साय की संधि की व्यवस्थाओं की बनाय रखना था। संसलिय, पराजित राष्ट्र यह मानते थे कि यह विजित, राष्ट्रों के स्वायत्त सिद्धि का यन्त्र है। इस प्रकार राष्ट्रमण्डल की वर्साय की संधि का एक जग बनाना दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। नामक वेदविच ने कहा है कि 'राष्ट्रमण्डल एक मुद्दयात्। माता की कुप्रतिष्ठित पुत्री थी।'।

(२) संयुक्त राज्य अमेरिका का सदस्य न बनना—संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन राष्ट्रमण्डल का जग मंदाता थे। विल्सन सनेट के विरोध के कारण अमेरिका को राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं बनना सक्त था। सनेट 'संधि का सदस्य बन कर यूरोपियन मामलों में नहीं उल्लंघना चाहती थी'। अमेरिका के सदस्य न बनने से संधि की शक्ति कमजोर हो गई। अमेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र था जो यूरोपीय मामलों में निष्पक्ष फायदाही कर सकता था। 'उसके सदस्य न बनने से राष्ट्रमण्डल की नींव ही कमजोर हो गई।' इसलिये वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। मेघोन और हार्डी ने लिखा है कि 'एक बालक यूरोप का दरवाजे पर अनाथो

राष्ट्रसभ्य ३

की भांति छोड़ दिया गया। जिसके चेहरे मोहरे पर अमेरिकन पत्रकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी।

समुक्त राज्य अमेरिका के सत्स्य न बनने से सभ्य की नीव कमजोर हो गई। अब यदि राष्ट्रसभ्य किसी देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिवध लगाता तो वह देश अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ अमेरिका से खरीद सकता था। इसके अनिश्चित दूसरे राष्ट्रसभ्य का छोड़न की वारंवार धमकी देने लगे। जर्मनी और जापान ने तो राष्ट्रसभ्य को छोड़ भी दिया।

(3) सवधानिक प्रुटिया—राष्ट्रसभ्य निम्न सवैधानिक प्रुटिया के कारण असफल रहा—

(i) सदस्य राष्ट्र राष्ट्रसभ्य के आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य नहीं थे। इसका कारण यह था कि धरम परिषद का नियम उसके विरुद्ध होता तो वह देश राष्ट्रसभ्य की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता और राष्ट्रसभ्य उस देश के विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता था।

(ii) राष्ट्रसभ्य में किसी भी विषय पर नियम लेने के लिये परिषद के सदस्य का एकमत होना आवश्यक था। दूसरे शब्दों में सभ्यसम्मति से निर्णय लिया जाता था। यदि एक भी सदस्य राष्ट्र उस नियम का विरोध कर तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकता था। किसी भी अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिवध और सन्निक कार्रवाई करने के लिये कौनसल के सदस्यों का एकमत होना आवश्यक था। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और गुटबन्दी के युग में सभी राष्ट्रों का एकमत होना अत्यन्त कठिन काम था। यह बात भी सभ्य की असफलता का मुख्य कारण थी।

(iii) सभ्य के कार्य करने का तरीका बहुत जटिल था। किसी भी विषय पर बहस बहुत दिना तक चलती रहती थी। शीघ्रता में निर्णय नहीं लिया जा सकता था।

(iv) सभ्य के सवधान मायुद्ध को पूरा रूप से निषेध घोषित नहीं किया गया था। रक्षात्मक युद्ध को सभ्य न बध मान लिया था। इस कारण आलापन बड़े राष्ट्रों ने उठाया।

(4) सभ्य की सीमित सदस्यता—सभ्य की सीमित सदस्यता भी उसकी असफलता में सहायक सिद्ध हुई। विश्व के सभी राष्ट्र इस सभ्य के सदस्य नहीं थे। प्रारम्भ से ही समुक्त राज्य अमेरिका सीनट के विरोध के कारण इस सभ्य का सत्स्य नहीं बन सका। फ्रान्स की स्टैंडर्डी के कारण जर्मनी का एकलमने समय तक इस

सम का सदस्य नहीं बनाया गया। आस्ट्रिया और रूस को भी इसका सदस्य नहीं बनाया गया। इस प्रकार राष्ट्रमण्डल विश्व-व्यापी सस्था नहीं बन सकी, क्योंकि विश्व के अनेक राष्ट्र इसके सदस्य नहीं थे।

राष्ट्रमण्डल ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध कुछ भी कायवाही नहीं कर सकता था, जो उन्हा सदस्य नहीं हो चाहे वह राष्ट्रमण्डल के नियमों की अवहेलना ही क्यों न करे? यदि राष्ट्रमण्डल ऐसा राष्ट्र के विरुद्ध कुछ कायवाही करता तो भी वह राष्ट्रमण्डल की आज्ञा का पालन करने के लिये बाध्य नहीं था। इतना ही नहीं ये राष्ट्र अपराधी सदस्य राष्ट्र की महत्ता कर सब की कायवाही को असफल कर सकते थे।

सम का एक अन्य महत्वपूर्ण शोध यह था कि इसमें सदस्यता समाप्त करने की व्यवस्था भी की गई थी। कोई भी राष्ट्र दो वर्ष पूर्व नोटिस देकर इसकी सदस्यता को छोड़ सकता था। इसलिये समयानुसार जापान जर्मनी और इटली ने राष्ट्रमण्डल को छोड़ दिया। बड़े राष्ट्रों के अलग हो जाने में राष्ट्रमण्डल की शक्ति को काफी धक्का लगा।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय सेना का अभाव राष्ट्रमण्डल के पास अन्तर्राष्ट्रीय सेना का अभाव था। इसलिये उसके आदेशों की अवहेलना करने वाले देशों को वह दण्ड नहीं दे सका। राष्ट्रमण्डल आवश्यक होने पर सदस्य राष्ट्रों को सेना भेजन के लिये आदेश दे सकता था, परन्तु उसका पालन करने के लिये वे राष्ट्र बाध्य नहीं थे। यदि राष्ट्रमण्डल के पास अन्तर्राष्ट्रीय सेना होती तो वह शक्तिशाली राष्ट्रों को निबन राष्ट्रों पर अधिकार करने से रोक सकता था। बड़े राष्ट्रों ने खुले आम राष्ट्रमण्डल की अवहेलना की। इसलिये निबन देश उभे शांति बनाये रखने में असमर्थ समझने लगे। इस कारण सदस्य राष्ट्रों का राष्ट्रमण्डल से विश्वास उठने लगा।

(6) अधिनायकवाद का उदय—यूरोप में अधिनायकवाद के उदय से इस मण्डल को बड़ा धक्का लगा। राष्ट्रमण्डल की स्थापना विवादात्मक शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये की गई थी। 1930 ई० के बाद जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्टवाद और जापान में सनिकवाद के उदय ने इस मान्यता को समाप्त कर दिया। हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह और लोह नीति के आधार पर अपनी समस्याओं को हल करना चाहते थे। ये राष्ट्रमण्डल की परवाह न करने हुए अपनी मार्गें पूरा करवाने के लिये सैनिक शक्ति का महाराज्यत थे। राष्ट्रमण्डल हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही प्रवृत्ति पर अकुश नहीं लगा सका। ऐसे वानावरण में राष्ट्रमण्डल का असफल होना ध्वश्य भावी था।

(7) शस्त्रीकरण को सीमित करने में असफलता—राष्ट्रमण्डल ने धारा 8 के अनुसार शस्त्रीकरण को सीमित करने के लिये कई योजनाएँ बनाईं परन्तु सम्बन्धित राष्ट्रों की अनुमति के अभाव में ये योजनाएँ क्रियावत् नहीं की जा सकीं। 1930

ई० के बाद प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करता रहा परन्तु राष्ट्रसभ उस पर कोई अबुझ नहीं लगा सजा। जर्मनी ने अनिवाय सैनिक सेवा लागू कर ली। इससे प्रभावित होकर अथ यूरोपियन राष्ट्रा ने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार यूरोपियन राष्ट्रा में फिर से इस्त्रा की होठ प्रारम्भ हुई। जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव—राष्ट्रसभ के सदस्यों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था। सभी सदस्य राष्ट्र इस मध्य के माध्यम में अपनी स्वायत्त सिद्धि करना चाहते थे। इस कारण राष्ट्रसभ अपने उद्देश्य प्राप्ति में असफल रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि राष्ट्रसभ युद्ध के पूर्व की शक्ति स्थापित कर परन्तु वह किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता था। इस प्रकार इस सकीण दृष्टिकोण के कारण राष्ट्रसभ असफल रहा।

(9) राष्ट्रसभ के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर—सदस्य राष्ट्रा का राष्ट्रसभ के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर भी उसको असफलता का एक कारण बना। सभी सदस्य राष्ट्र इस मध्य के माध्यम से अपना अपना स्वायत्त सिद्धि करना चाहते थे। फ्रांस राष्ट्रसभ को बर्साय की संधि का पालन करवाने वाली मस्था मानता था। वह चाहता था कि मध्य जर्मनी पर नियन्त्रण बनाये रखे। ब्रिटेन इस मध्य के माध्यम से साम्यवाद का बुचलना चाहता था। इसलिये उसने मचूरिया पर जापानी आक्रमण का विरोध नहीं किया था। जिससे राष्ट्रसभ की प्रतिष्ठा को काफी घटका पहुँचा। फ्रांस और इंग्लैण्ड दोनों ही देश राष्ट्रसभ द्वारा शांति स्थापित करना चाहते थे, परन्तु वे अपने हितों का बलिदान करने के लिये तयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसभ के लिये शांति स्थापित करना असम्भव था। इन दोनों राष्ट्रा ने मुसालिनी के विरुद्ध राष्ट्रसभ के आदेशानुसार कार्यवाही इसलिये नहीं की, क्योंकि वे इटली से अपने सम्बन्ध खराब नहीं करना चाहते थे।

प्रारम्भ में जर्मनी के राष्ट्रसभ का सदस्य नहीं होने से उसकी मध्य के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। जर्मनी की दृष्टि में राष्ट्रसभ विजयी राष्ट्रा की एक मस्था थी। जिसका कार्य बर्साय की संधि का पालन करवाना था। 1926 ई० में जर्मनी राष्ट्रसभ का सदस्य बना। इसके पश्चात् उसने बर्साय की संधि का उल्लंघन करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार सदस्य राष्ट्रा के विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण राष्ट्रसभ असफल रहा।

(10) आर्थिक संकट—1930 ई० के आर्थिक संकट ने राष्ट्रसभ की असफलता में बहुत बड़ा सहयोग दिया। इस आर्थिक मदी के कारण सभी देशों की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। उन्होंने अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिये विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध, सीमा-बन्ध और सट कर लगाए। आर्थिक संकट के कारण सभी देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद की शक्तियाँ प्रबल हो उठीं। जिसके फलस्वरूप

जर्मनी में हिटलर के नरतन्त्र में नाजीवाद इटली में मुसोलिनी के तत्त्व में फासिस्ट वाद और जापान में सैनिकवाद का उत्पन्न हुआ। इन्होंने अपने साम्राज्य में बढि करने के लिये एव समस्याओं को हल करने के लिये सैनिक शक्ति का सहारा लिया। फलस्वरूप यूरोप में फिर से शस्त्रीकरण की हाड प्रारम्भ हो गई।

(11) ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति—राष्ट्रसंघ में अमेरिका के नूहोन के कारण ब्रिटेन और फ्रांस की गिनती महान राष्ट्रों में की जाती थी। ये दोनों देश साम्यवाद के विरोधी थे और उस दूर समय बुचलना चाहत थे। इसलिये उन्होंने जर्मनी, जापान और इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उनकी दृष्टि में हिटलर और मुसोलिनी से भी साम्यवाद ज्यादा खतरनाक था। फलस्वरूप जापान के मंचूरिया पर आक्रमण और इटली के एथीसिनिया पर आक्रमण के समय राष्ट्रसंघ उनके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सका। अतः ही हिटलर की साम्राज्यवादी क्षुधा का कारण द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हो गया।

(12) हमलावरों का सरक्षक—राष्ट्रसंघ की स्थापना समानता एवं 'याव के सिद्धांत' पर की गई थी। जब कभी छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों के आक्रमण पर राष्ट्रसंघ से शिकायत करते तो बड़ी शक्तियाँ का आकांक्षा को समर्थन मिलने के कारण राष्ट्रसंघ उनके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकता था। इस प्रकार राष्ट्रसंघ छोटे राष्ट्रों की बड़े राष्ट्रों से रक्षा करने में असमर्थ रहता था। परिणामस्वरूप छोटे राष्ट्र इस संधि की हमलावरों का सरक्षक समर्थने नग। धीरे-धीरे दुबले राष्ट्रों का इस संधि से विश्वास हटन लगा।

(13) राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों के प्रति अविश्वास—राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय इस प्रकार संस्था राष्ट्रों ने यह आश्वासन दिया था कि वे संधि की धारा 11, 11, 15 एवं 16 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दायित्व एवं सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्तों का पालन करेंगे। जब उत्तरदायित्वों के पालन का समय आया तो बड़े राष्ट्र पीछे हटने लगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बड़े राष्ट्रों का राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों में विश्वास नहीं है। वे यह मानने को तयार नहीं थे कि राष्ट्रसंघ विश्व में शांति को स्थापित करने में सफल हो सकता है। यद्यपि वे शांति की दुहाई देते रहे थे परंतु वे व्यावहारिक तौर पर कोई कदम उठाने के लिये तयार नहीं थे। बड़े बड़े राष्ट्र दुहरी नीति पर चल रहे थे। सिद्धांतिक रूप से राष्ट्रसंघ ने एथीसिनिया पर इटली का आक्रमण रोकने के लिये आधिक्य प्रतिबंध लगाए परंतु व्यावहारिक रूप में इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली का सहयोग कर इन आधिक्य प्रतिबंधों का प्रभावहीन बना दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐसी ही नीति जापान के मंचूरिया पर आक्रमण के समय अपनाई थी। जब राष्ट्रसंघ की बड़ी शक्तियाँ ही उनके साथ विश्वासघात कर रही थी तो यह संधि कैसे सफल हो सकता था। शून्य ने लिखा है कि 'संधि की सफलता के लिये यह आवश्यक था कि सदस्य राज्यों में इसके सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बुद्धिमत्ता और साहस होता किंतु इनमें इसका सबका अभाव था, अतः एक जिनेवा की शील'

राष्ट्र सघ

के तट पर एरियाना पाक में निर्मित उसका भव्य प्रासाद शीघ्र ही उसका सुन्दर समाधि स्थल बन गया।”¹

राष्ट्रसघ का मूल्यांकन—राष्ट्रसघ अपने उद्देश्यों में आंशिक रूप से सफलता प्राप्त कर सका। उसकी युद्ध को रोकने, निशास्त्रीकरण करने और शांति स्थापित करने में पूर्णतया सफलता नहीं मिली परन्तु गर राजनीतिक बायों में उसे आघातित सफलता मिली। राष्ट्रसघ ने पहली बार यह स्पष्ट कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित रह सकती है। वाल्टर ने लिखा है कि “राष्ट्रसघ की स्थापना इस रूप में क्रांतिकारी कदम था कि इसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में सद्भावित परिवर्तन आया।”

राष्ट्रसघ के प्रयासों से सभी देशों में युद्ध के प्रति घृणा की भावनाएँ विकसित हुईं। यद्यपि यह सघ आक्रमणों को रोकने में असफल रहा, तथापि आक्रमणों को रोकने के लिये सामूहिक प्रयास का मिश्रात व्यापक होने लगा। लैंगसम ने लिखा है कि ‘सघ की सबसे बड़ी देन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विचार को उन्नत करना था।’

सघ ने मदस्य राष्ट्रों में विवादों को हल करने के लिये बाद विवाद, कूटनीति और समझौते का माग अपनाने पर जोर दिया। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का वातावरण तैयार हुआ। इसलिये यह कहा जाता है कि यद्यपि राष्ट्रसघ असफल रहा तथापि उसने सयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। वाल्टर ने लिखा है कि “सयुक्त राष्ट्रसघ के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं और कार्यप्रणाली पर राष्ट्रसघ की स्पष्ट छाप है।”

प्रस्तावित सद्म पाठ्य पुस्तकें

- 1—शूमैन—इंटरनेशनल पोलिटिक्स
- 2—कैटलबी—ए हिस्ट्री ऑफ मॉडन टाइम्स
- 3—हेजन—आधुनिक यूरोप का इतिहास
- 4—मोरगैथॉ—पोलिटिक्स अमग नेशंस
- 5—गूच, जी० पी०—आधुनिक यूरोप का इतिहास
- 6—लगतम—दि वर्ल्ड सि०स, 1919
- 7—घाट एण्ड टेम्परले—यूरोप का इतिहास—उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में।
- 8—गेवोन और हार्डी—ए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स।

13

आधुनिक चीन

इतिहासकार थॉमसन का कहना है कि चीन का प्राचीन इतिहास बहुत अधिक जटिल है। चीन भी भारत की भाँति एक प्राचीन देश है। यहाँ 22 वंशों ने शासन किया। यहाँ का अंतिम मन्चू वंश का था जो 1912 ई० तक शासन करता रहा। चीन में सातवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक टांग वंश के शासकों ने शासन किया। डॉ० बी० आर० वेनर्जो का मानना है कि इस वंश के अधीन चीन ने काफी प्रगति की। मंगोल वंश का शासन भी चीन से प्रारम्भ होता है। मंगोल बहुत निरदयी और अत्याचारी थे। उनका नतीजा चंगेज खा अपनी क्रूरता और नश्वरता के लिये समस्त म प्रसिद्ध हो चुका था। उसके शासनकाल में भी चीन में प्रगति की। चंगेज खा के पश्चात् उसका पौत्र कुबलाई खा चीन का शासक बना। यह जनता में बहुत अधिक लोकप्रिय था। उसने पकिंग शहर को चीन की राजधानी बनाया। उसका शासनकाल में कला और साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ। उसने सभी घमों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। घोंघे के अनुयायियों के विद्रोह के कारण मंगोल वंश का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर 1368 ई० में मिंगवंश का शासन स्थापित हुआ।

मिंगवंश के शासनकाल में चीन में बहुत अधिक उन्नति की। इस वंश के शासकों ने ब्रिटेनिया के चीन में आन पर प्रतिबंध लगा दिया। 1644 ई० तक मिंगवंश के शासक चीन पर शासन करते रहे। 1644 ई० के पश्चात् मन्चू वंश ने चीन पर अधिकार कर लिया। मन्चू वंश के शासक असभ्य हाते हुए भी साहसी थे। इस वंश का दूसरा सम्राट काङ्गसि था। जिसने 1662 ई० से 1723 ई० तक चीन पर शासन किया। उसने साहित्य और कला को प्रोत्साहन दिया। इसलिये शासनकाल में कला और साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ। मन्चू वंश के शासकों ने 1912 ई० तक चीन पर राज्य किया। उनके शासन काल में चीन ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की, और साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। अठारहवीं शताब्दी में मन्चू वंश का पतन होने लगा।

आधुनिक चीन

इस प्रकार चीन में कई वंश के शासक ने शासन किया। चीन ने मंगोल और मंचू वंश के विजेताओं को अपने में मिला लिया। इस प्रकार चीन की प्राचीन सभ्यता अविच्छिन्न गति से चलती रही, परन्तु 20वीं शताब्दी में चीन पाश्चात्य सभ्यता से अपनी सभ्यता और सस्कृति की रक्षा करने में असफल रहा। स्पष्ट है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीन का आधुनिकीकरण आरम्भ हुआ। पाश्चात्य देशों के प्रभाव से चीन के रहन-सहन, खान-पान, चिन्तन और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होने लगे। इस परिवर्तन को चीन का आधुनिकीकरण कहा जाता है। चीन के आधुनिकीकरण से प्राचीन सस्कृति की परम्पराएँ टूटती लगी।

यहाँ पर सम्राट् दबी सिद्धांत के अनुसार शासन करता था। सम्राटो ने शासन की सुविधा के लिये चीन को कई प्रांतों में विभाजित कर रखा था। इन प्रांतों की सख्या घटती बढ़ती रहती थी। 19 वीं शताब्दी में इन प्रांतों की सख्या 18 थी। प्रांतों का शासन प्रबन्ध चाने के लिये सम्राट् राज्यायतन, कोषाध्यक्ष और 'यायाधीश' आदि अधिकारियों की नियुक्ति करता था। नागरिक प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षा प्रणाली के द्वारा होती थी। चीनी सम्राट् ने शासन के अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वंशों के अन्तर्गत रिकार्डों का बड़ा सम्मान करते थे। चीनी समाज में प्रशासन पर बहुत अधिक प्रभाव था। गाव, चीनी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। वृद्धपत्र गाव का शासन चलाते थे। चीनी शासन में विवेकीकरण अधिक होने से विदेशी आक्रमणकारियों की सफलता प्राप्त हुई।

चीनी समाज में कुटुम्ब का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके कुटुम्ब में जीवित सदस्यों के अतिरिक्त मृतकों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वंशों के अन्तर्गत रिकार्डों का बड़ा सम्मान करते थे। चीनी समाज में माता पिता का बहुत आदर किया जाता था। चीन में मृतकों के परिवार प्रणाली प्रचलित थी। स्त्रियों को समाज में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। पुत्रों के जन्म होने पर खुशिया मनाई जाती थी।

चीनी लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग रेशम के कपड़े बनाने का धंधा करते थे। समाज में विद्वान तथा कृषकों को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था। चीनी व्यापारी सभ्यता में बड़े हुए थे। विदेशों से व्यापार करते समय चीनी व्यापारी चांदी का प्रयोग भी किया करते थे। चीन में कागजी मुद्रा का प्रयोग भी किया गया। यहाँ सामान कृषकों से अत्यधिक मात्रा में कर वसूल करते थे। इन शोषण के कारण चीन में गरीबी की देशा बहुत शीघ्रता से हो गई।

चीनी लोग कन्फुशियस के नैतिक सिद्धांतों का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। यहाँ के नागरिक किसी एक धर्म को नहीं मानते थे और विभिन्न धर्मों में विश्वास करते थे। चीन के कुछ लोग ताओवाद में विश्वास करते थे; तो कुछ

बौद्ध धर्म की मूर्तियों की पूजा में विश्वास रखते थे। 19वीं शताब्दी में चीन में इस्लाम धर्म का प्रवेश भी हो चुका था। चीनी लोग परलोक में भी विश्वास करते थे। यहां के मुख्य देवता "यीन" (अधकार की देवी) और "याम" (प्रकाश, सत्य और याप देवता) आदि थे। चीन में कन्फ्यूशियस ताओ और बौद्ध धर्म के अनेक स्थानों पर मंदिर, मठ और बिहार बने हुए थे, जहां पुरोहित और बौद्ध भिग्नु रहते थे।

चीन में क्रेटन, फूचाऊ तथा टी-सटीन आदि क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती थी। इन सब भाषाओं को लिपि एक जसी थी। 19वीं शताब्दी तक चीन ने लिपी और भाषा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति कर ली थी परंतु शब्द जटिल और अधिक थे। चीनी विद्वानों ने कृषि तथा चिकित्सा शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखीं। यहां की शिक्षा में परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को राज्य और समाज में बड़ा सम्मान मिलता था। राज्य की नौकरियों के लिये भी परीक्षाएँ आयोजित की जाती थी और सफल अभ्यर्थी को राजकीय नौकरी में नियुक्ति दी जाती थी। चीन की सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती थी।

चीन में विदेशियों का आगमन—उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक पश्चिमी देशों को चीन में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था कि मचू वंश के शासकों ने पश्चिमी लोगों के चीन में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। मचू वंश के दुबल शासकों के समय अंग्रेज व्यापारियों ने चीन से व्यापारिक सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया। परंतु उन्हें अपमानित कर चीन से बाहर निकाल दिया गया। 1816 ई० में लाड एमहस्ट पेकिंग में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिये आया था परंतु उसे भी अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। चीनी सरकार ने उसे अपमानित कर निकाल दिया। इसी प्रकार 1834 ई० में लाड नपियर भी चीन आया परंतु उसे भी अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली।

अब अंग्रेजों ने चीन में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने चीन से अफीम का व्यापार शुरू किया। इस शीले व्यसन का प्रचार कर चीनी लोगों को अफीम खाने का आदि बना दिया। अब अंग्रेज चीन से सामान मँगवाने लगे और उसके बदले में भारत से अफीम ले जाकर उनको देने लगे।

प्रथम अफीम युद्ध (1839-42 ई०)—ब्लाइड ने लिखा है कि "चीन के लिये यह सैनिक पराजयों की शताब्दि का आरम्भ था।" अंग्रेज व्यापारी अफीम के व्यापार के द्वारा चीन का आर्थिक शोषण कर रहे थे। चीनी सरकार अफीम के बुरे परिणामों से चिन्तित हो उठी। उसने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया

और इसका व्यापार करने पर कठोर सत्रा देने की घोषणा की गई। अंग्रेजों ने इसको बहाना बनाकर 1839 ई० में चीन से युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इसे प्रथम ओपियम युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1839 ई० से 1842 ई० तक चला रहा। इस युद्ध में अंग्रेज सेना ने चीनी सेना को बुरी तरह से पराजित किया। हमें चीन के 20 हजार और अंग्रेज सेना के 500 सैनिक मारे गये। एम्पटीन न निष्ठा है कि "यस युद्ध में पश्चिम के अग्रगण्य व सम्य राज्यों की निरंतर शौर चीन के सामन्तवादी पिछड़े साम्राज्य की दुबलता का पता सारे सत्रा को चल गया।"¹

नानकिंग की संधि (1842 ई०)—प्रथम ओपियम युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई। इसलिये उसने 29 अगस्त, 1842 ई० को चीन की एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, जिसे नानकिंग की संधि कहा जाता है। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं—

- (1) हांगकांग का बन्दरगाह अंग्रेजों को दे दिया गया।
- (2) चीन ने अपने बाह्य बन्दरगाहों केटन, अमोय, क्वांग निगवा और स्याई में अंग्रेजों को व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। अंग्रेज सरकार इन बन्दरगाहों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती थी।
- (3) चीन ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 21 लाख डालर अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया।
- (4) चीन में रहने वाले अंग्रेजों को विद्यवाधिकार प्रदान किये गये। इस अधिकार के अनुसार अंग्रेजों के अधिभोग पर केवल अंग्रेजी न्यायाधीश ही नियुक्त किये जा सकते थे।

ब्रिटेन की विजय से प्रोत्साहित होकर अन्य पारस्वत्य देशों ने भी चीन के साथ व्यापारिक समझौते कर लिए। 1844 ई० में चीन और अमेरिका के बीच एक व्यापारिक संधि हुई। इस संधि के अनुसार चीन ने यह स्वीकार किया कि वहाँ रहने वाले अमेरिकन लोगों के अधिभोगों की मुनवाई का अधिकार अमेरिकन न्यायाधीशों को होगा। यह शर्त चीन के लिये अपमानजनक थी, परन्तु उस बाध्य होकर इस शर्त को स्वीकार करना पड़ा। शीघ्र ही फ्रान्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, प्रशा और पुर्तगाल ने चीन के पाँचों बन्दरगाहों पर अपनी अपनी व्यापारिक वाणिज्य स्थापित कर ली। अब चीन को बाध्य होकर अकेलेपन की नीति का परित्याग करना पड़ा तथा राजदूतों का आदान प्रदान करने के लिये दिवस होने लगे।

द्वितीय ओपियम युद्ध (1856-60 ई०)—नानकिंग की अपमानजनक संधि से चीनी मांग असंतुष्ट थे। वे अंग्रेजों का सुविधाएँ नहीं देना चाहते थे। परन्तु नानकिंग की संधि से बाध्य होकर सुविधाएँ देनी पड़ी। उधर अंग्रेज नानकिंग की

1—द्वन्द्ववाहल-एम्पटीन-फ्रेम ओपियम वार टू लिबरेशन पृष्ठ 5

संधि से प्राप्त सुविधाओं से सन्तुष्ट नहीं थे वे और अधिक सुविधायें प्राप्त करना चाहते थे। इसलिये 1853 ई० में दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये। 1856 ई० में चीनी सरकार ने एक फ्रेंच रोमन कथोलिक पादरी को मृत्युदण्ड दिया। इस समय अंग्रेजों ने विधोपाधिकारों को लेकर पुनः चीन से युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इसे द्वितीय अफीम युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 1856 से 1860 ई० तक चलता रहा। इस युद्ध में फ्रांस ने इंग्लण्ड का साथ दिया। इस प्रकार फ्रांस और इंग्लण्ड की संयुक्त सेना ने चीन को इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर संधि करने के लिये विवश किया। टिंसटीन की संधि (1858 ई०) —

- (1) चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटा लिया। अब अफीम का व्यापार खुल तौर पर हो सकता था।
- (2) चीन ने अपने 11 बन्दरगाहों में विदेशी व्यापारियों को व्यापारिक सुविधायें प्रदान कीं।
- (3) चीन में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतन्त्रता दी गई।
- (4) चीन में रहने वाले विदेशियों पर चीनी कानून लागू नहीं होगा।

इस युद्ध में फ्रांस को भी चीन में व्यापारिक सुविधायें प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त अमेरिका को भी चीन में व्यापारिक सुविधायें प्राप्त हुईं। अब चीन ने पश्चिमी शक्तियों के लिये अपने द्वार खोल दिये। हेराल्ड एम० विनाके ने लिखा है कि "तथ्य यही है कि नयी व्यवस्था को सहज रूप से स्वीकार न करने से सबसे अधिक अहित चीन का ही था, यद्यपि यह नयी व्यवस्था चीन पर थोपी गई थी।"¹

ताईपिंग विद्रोह— चीनी अंग्रेजी युद्धों के पश्चात् पश्चिमी देशों ने चीन में अपना साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया। यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। इससे चीनी कृषक बहुत अधिक प्रभावित हुए। चीन के कृषकों और ईसाईयों ने चीनी सम्राट की निरकुशता के विरुद्ध हुग शियु चुआन के नेतृत्व में ताईपिंग में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य चीन के आंतरिक मामलों में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप को समाप्त करना था। 1853 ई० में हुग शियु चुआन ने नानकिंग पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर एक नई सरकार की स्थापना की। जिस "महान् शांति का स्वर्गीय राज्य" कहा जाता है। इसे चीनी भाषा में 'ताईपिंग तिन कुओ' के नाम से जाना जाता है। 1850 ई० से लेकर 1865 ई० तक आतंककारियों की सरकार नानकिंग का शासन चलाती रही। इस अवधि में न तो चीनी सरकार नानकिंग पर अधिकार कर सकी और न ही आतंककारी पेंकिंग पर अधिकार कर सके। आतंककारियों ने मचू वंश के शासकों की

निरक्षुण्णता के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह का प्रभाव 1854-1865 ई० तक बना रहा।

क्रांतिकारी सरकार के सुधार - प्रान्तिकारी सरकार न निम्नलिखित सुधार किये —

(1) जमींदार और सामंत वर्ग का अन्त कर लिया और भूमि किसानों में बांट दी गई। इसके अतिरिक्त कृषकों को सामूहिक रूप से कृषि काय करने की शिक्षा दी गई। आगस्टस लिडले ने लिखा है कि 'आजाप के नीचे सारी भूमि, आजाप के नीचे रहने वालों द्वारा जोती जानी चाहिये। जब उन्हें मिलकर जोतना दो।'¹

(2) मजदूर गणतन्त्र के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये गये।

(3) अफीम का प्रयोग बन्द कर दिया गया। इसका प्रयोग करने पर कठोर सजा देने की घोषणा की गई।

(4) रक्तपात की दशा में सुधार करने के लिये कई प्रयास किये गये। स्त्रियों के बर्षावर्ति और लाह के जूते पहनने पर रोक लगा दी गई।

(5) मजदूरों की दशा में सुधार करने के लिये कई प्रयास किये गये। ऐम्प्लीन ने लिखा है कि 'ताईपिंग प्रान्तिकारी किसानों का युद्ध उन्नीसवीं शताब्दी का सबसे भयानक और साहसी युद्ध था। और मानव स्वतन्त्रता के लिये विश्व के सबसे महान युद्धों में से एक था।'

ताईपिंग राज्य में व्यापार के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई। चाय का निर्यात दुगुना हो गया। इतना सब कुछ हानि पर भी यह प्रान्त असफल रही। क्लाइड ने लिखा है कि "एक दफा जब ताईपिंग ने रास्ता तयार कर दिया तो चीन गणतन्त्र और ईसाई धर्म की भावना से, शिक्षित लोगों की शक्ति और व्यापारिक मेलजोल से प्रगति करता स्वतन्त्र होकर रहेगा।"² विनाके ने लिखा है कि "आन्दोलन के रचनात्मक नेतृत्व का सृजन नहीं किया, अधिपत्य योग्यता के लोगों ने आरम्भ में ही अपन प्राण होम दिये और चू कि अधिपत्य योग्यता और वट्टरपची नेनाओं का हृग पर प्रभाव रहा, इसलिये ताईपिंग अपनी ही कमजोरियों व कारण समाप्त हो गया।"⁴

चीनी जमींदारों ने 1858 ई० में हूग शियु चुआन का कत्ल करवा दिया। चुआन की मृत्यु के पश्चात् ताईपिंग सेना का संगठन कमजोर हो गया। ऐसे समय

1— आगस्टस लिडले—दी हिस्ट्री आफ ताईपिंग रेवोल्यूशन पृष्ठ-78

2— इजराइल एम्पटीन— फोम ओपियम वार टू लिबरेशन पृष्ठ 21

3— क्लाइड, पाल एच०—दी फार ईस्ट—पृष्ठ 143

4— विनाके, हेराल्ड एम०—यूव एशिया का आधुनिक इतिहास पृष्ठ 75

1899 ई० में यह आदान-प्रदान शांति-संधि से प्रारम्भ हुआ और धीरे-धीरे चीन के अन्य प्रदेशों में फैलने लगा। दश भक्ता न विदेशियों का बाहर निकालने के लिए लुटमार अग्निबाढ़ और हत्याएँ करना प्रारम्भ कर लिया। इस समय ईसाई धर्म प्रचारकों की भी हत्या की गई। विदेशियों की समुक्त सेना ने आन्दोलन को बुचलने का प्रयास किया। ऐसी परिस्थिति में चीन की सेना बोक्सस की सहायता के लिये आ गई। इसमें उत्साहित होकर बोक्सस ने जर्मनी तथा जापान के राजदूतों को मार डाला। इस पर जर्मनी, फ्रांस, रूस और जापान ने पेंकिंग स्थित अपने दूतावासों की रक्षा करने के लिए एक अन्तर्गण्टीय सेना भेजी। इस सेना ने 1900 की अगस्त में वाक्सर आन्दोलन का बुरी तरह से बुचल दिया गया और चीन के सम्राट को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया।

इस संधि के अनुसार चीन ने युद्ध का खर्चा देना स्वीकार कर लिया परन्तु चीनी सरकार खर्चा चुकान में असमर्थ थी। अतः विदेशी राष्ट्रों ने चीन से यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि वे चीन का विदेशी वस्तुओं का प्राप्ति प्राप्त करने वाली जाय लेंगे। इस प्रकार का अधिकार प्राप्त हो जाने से पाश्चात्य देशों को आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ। इस विभाजन के कारण चीन को पूरव का तरजूज भी कहा जाता है।

इस बोक्सर आन्दोलन के कारण चीनी साम्राज्यी रूपहीसी ने कुछ सुधार किये। इन सुधारों के अनुसार राज्य के उच्च पदा पर अब उही पत्तियों को नियुक्ति दी जाती थी जो पाश्चात्य विषय (जयशास्त्र राजनीति शास्त्र और रसायन शास्त्र) लेकर परीक्षा में सफल होने थे। इससे चीन के प्राचीन विषयों का महत्व कम होने लगा।

(5) इसी जापानी युद्ध (1904-1905)—वाक्सर अन्तिम चीन में नव चेतना का संचार हुआ। इसी बीच रूस और जापान के बीच 1904-5 ई० में युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्ध में जापान जैसे छोटे से देश ने रूस जैसे महान राष्ट्र को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में जापान की विजय से चीनवासी समझ गये कि जापान पाश्चात्य शस्त्रों के युद्ध प्रणाली के कारण रूस जैसे महान राष्ट्र को हराने में सफल हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भी पाश्चात्य देशों के आधार पर अपनी शिक्षा, शासन और औद्योगिककरण करने का निश्चय किया ताकि वह भी जापान के समान एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके।

(6) चीन की 1911 ई० की गणतन्त्रवादी क्रांति—1908 ई० में मन्चू सरकार ने शासन सम्बन्धी कई सुधार किये। मन्चू वंश के सम्राट ने नये ढंग से चीनी समाज का संगठन किया। सम्पूर्ण देश में कई विद्यालयों की स्थापना की गई। अफीम का प्रयोग गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सरकार ने जनता को यह आश्वासन दिया कि 1917 ई० में एक नया संविधान लागू किया जायेगा। सम्राट

के इन सुधारों का सामंती ने विरोध किया। इसलिए ये सुधार नियाचित नहीं किये जा सके। इससे जनता अंततुष्ट थी। चीनी जनता ने विदेशियों के बढ़ते हुये प्रभाव के लिए अपनी सरकार का जिम्मेदार माना। अतः 1911 ई० में चीन में प्रान्ति हुई। जिसके फलस्वरूप चीन में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कर दी गई। 8 नवम्बर 1911 ई० में वां चांग मू वंश के अंतिम सम्राट ने सिंहासन छोड़ दिया।

गणतन्त्रवादी प्रान्ति के कारण—इस प्रान्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) चीन की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही थी, 1885 ई० में चीन की जनसंख्या 37 करोड़ 70 लाख थी परन्तु 1911 ई० में यह बढ़कर 43 करोड़ हो गई। इस अनुपात में उत्पादन तथा पैदावार में वृद्धि नहीं हो रही थी। इसके अतिरिक्त चीन में लगभग हर साल अकाल पड़ता था, जिससे हजारों व्यक्ति मारे जाते थे। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये कुछ भी प्रयास नहीं किया, इसलिए जनता में सरकार के विरुद्ध असंतोष का व्याप्त होना स्वाभाविक ही था।

(2) छापखाने के आविष्कार, समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं रेलमार्गों का निर्माण के कारण दूर दूर के प्रांतों की दूरी को कम कर दिया। इसके अतिरिक्त आवागमन के साधनों का विकास होने के कारण प्रांतों के निवासी एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आये। समाचार पत्रों के द्वारा प्रान्तिकारी विचारों का प्रसार किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने सामूहिक रूप से निरंकुश शासन को समाप्त करने का प्रयास किया।

(3) चीनी जनता में विदेशियों के विशेषाधिकारों का प्रति भयंकर असंतोष व्याप्त था। इसलिए जनता ने विदेशियों का प्रभाव समाप्त करने के लिये सरकार को बदलना आवश्यक समझा।

(4) चीन के कई परिवार पश्चिमी देशों में जाकर बस गये थे। वहाँ उन्होंने देखा कि जनता किस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। इससे प्रभावित होकर उन्होंने चीन में प्रान्तिकारी भावनाओं का प्रचार किया। डॉ० सनयात सन ने एक प्रान्तिकारी दल की स्थापना की।

(5) केंद्र व प्रान्तीय सरकारों के बीच मतभेद भी प्रान्ति का कारण बना। उस समय चीन की केंद्रीय सरकार विदेशों की सहायता से चीन में रेलवे लाइन का निर्माण करवा रही थी। जिसका प्रान्तीय सरकारों ने विरोध किया। प्रान्तीय सरकार यह चाहती थी कि ये स्वयं रेलवे लाइन का निर्माण करवायें। केंद्र की सरकार ने विरोध किया।

(6) प्रान्ति का सत्वालीन कारण सना का विद्रोह था। 10 अक्टूबर 1911 ई०

1899 ई० में यह आंदोलन शांति से प्रारम्भ हुआ और धीरे-धीरे चीन के जय प्रदशो में फनने लगा। रूस भक्ता ने विदेशियों का बाहर निकालने के लिये लूटमार, जग्मिकाड और हत्याये करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय ईसाई धर्म प्रचारकों की भी हत्या की गई। विदेशियों की संयुक्त सेना ने आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। ऐसी परिस्थिति में चीन की सेना वाक्सस की सहायता के लिये आ गई। इससे उत्साहित होकर बोक्सस ने जर्मनी तथा जापान के राजदूतों को मार डाला। इस पर जर्मनी, फ्रांस रूस और जापान ने पेरिस स्थित अपने दूतावासों की रक्षा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजी। इस सेना ने 1900 की अगस्त में वाक्सस आन्दोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया और चीन के सम्राट को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया।

इस संधि के अनुसार चीन ने युद्ध का खर्चा देना स्वीकार कर लिया, पर तु चीनी सरकार खर्चा चुकान में अक्षम थी इसलिए विदेशी राष्ट्रों ने चीन से यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि वे चीन का नियंत्रण कर संप्रान्त रूप से कर सकें। इस प्रकार का अधिकार प्राप्त हो जाने से पश्चात्य देशों को आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ। इस विभाजन के कारण चीन को पूरव का तरबूज भी कहा जाता है।

इस बोक्सस आन्दोलन के कारण चीनी साम्राज्यी त्यूहीसी ने कुछ सुधार किये। इन सुधारों के अनुसार राज्य के उच्च पदा पर अब उही पक्तियों को नियुक्ति दी जाती थी जो पश्चात्य विषय (अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र और रसायन शास्त्र) लेकर परीक्षा में सफल होते थे। इसमें चीन के प्राचीन विषयों का महत्व कम होने लगा।

(5) रूसी जापानी युद्ध (1904-1905)—वाक्सस का तिस चीन में नव चेतना का मवार हुआ। इसी बीच रूस और जापान के बीच 1904-5 ई० में युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्ध में जापान जैसे छोटे से देश ने रूस जैसे महान राष्ट्र को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में जापान की विजय से चीनवासी समझ गये कि जापान पश्चात्य शस्त्रों व युद्ध प्रणाली के कारण रूस जैसे महान राष्ट्र को हरान में सफल हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भी पश्चात्य देशों के आधार पर अपनी शिक्षा, शासन और औद्योगिकरण करने का निश्चय किया ताकि वह भी जापान के समान एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके।

(6) चीन की 1911 ई० की गणतन्त्रवादी क्रांति—1908 ई० में मन्चू सरकार ने शासन सम्बन्धी कई सुधार किये। मन्चू वंश के सम्राट ने नये ढंग से चीनी सेवा का संगठन किया। सम्पूर्ण देश में कई विद्यालयों की स्थापना की गई। शपथ का प्रयोग कर कानूनी घोषित कर दिया गया। सरकार ने जनता को यह विश्वासन दिया कि 1917 ई० में एक नया संविधान लागू किया जायगा। सम्राट

के इन सुधारों का सामंता ने विरोध किया। इसलिए ये सुधार नियाचित नहीं किए जा सके। इसमें जनता अमनुष्य थी। चीनी जनता ने विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव के लिए अपनी सरकार को जिम्मेदार माना। जन 1911 ई० में चीन में श्रान्ति हुई। जिससे फलस्वरूप चीन में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कर दी गई। 8 नवम्बर 1911 ई० में का चीन के मू. वंश के अंतिम सम्राट ने सिंहासन छोड़ दिया।

गणतन्त्रवादी श्रान्ति के कारण—इस श्रान्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) चीन की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही थी 1885 ई० में चीन की जनसंख्या 37 करोड़ 70 लाख थी परन्तु 1911 ई० में यह बढ़कर 43 करोड़ हो गई। इस अनुपात में उत्पादन तथा पैदावार में वृद्धि नहीं हो रही थी। इसके अतिरिक्त चीन में लगभग हर साल अकाल पड़ता था, जिससे हजारों व्यक्ति मारे जाते थे। सरकार ने इस समस्या का हल करने के लिये कुछ भी प्रयास नहीं किया, इसलिये जनता में सरकार के विरुद्ध अमनोप का व्याप्त होना स्वाभाविक ही था।

(2) छापखाने के आविष्कार, समाचार पत्रों के प्रकाशन एवं रेलमार्गों के निर्माण के कारण दूर-दूर के प्रांतों की दूरी का कम हो गया। इसके अतिरिक्त आवागमन के साधनों का विकास होाने के कारण प्रांतों के निवासी एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आये। समाचार पत्रों के द्वारा श्रान्तिकारी विचारों का प्रसार किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने सामूहिक रूप से निरंकुश शासन को समाप्त करने का प्रयास किया।

(3) चीनी जनता में विदेशियों के विशेषाधिकार के प्रति असंतोष व्याप्त था। इसलिये जनता ने विदेशियों का प्रभाव समाप्त करने के लिये सरकार को बदलना आवश्यक समझा।

(4) चीन के कई परिवार पश्चिमी शक्तियों में जाकर बँध गये थे। वहाँ उन्होंने देखा कि जनता किस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। इससे प्रभावित होकर उन्होंने चीन में श्रान्तिकारी भावनाओं का प्रचार किया। डॉ० सनयात उन ने एक श्रान्तिकारी दल की स्थापना की।

(5) केन्द्रिय प्रान्तीय सरकारों के बीच मतभेद भी श्रान्ति का कारण बना। उस समय चीन की केन्द्रीय सरकार क्विन्सा की सहायता से चीन में रेलवे लाइन का निर्माण करवा रही थी। जिसका प्रांतीय सरकारों ने विरोध किया। प्रांतीय सरकार यह चाहती थी कि वे स्वयं रेलवे लाइन का निर्माण करवायें। इसका केन्द्रीय सरकार ने विरोध किया।

(6) श्रान्ति का तत्कालीन कारण सना का विद्रोह था। 10 अक्टूबर 1911 ई०

को बम विस्फोट की घटना घटित हुई। बम से पत्ने घाता मकान क्रांतिकारी व्यक्ति का था। जब सरकारी अधिकारियों ने इस मकान की तलाशी ली तो वहाँ काफी मात्रा में युद्ध की सामग्री प्राप्त हुई। इस पर सरकार ने क्रांतिकारियों को बन्नी बनाना प्रारम्भ किया। सैनिकों क्रांतिकारियों को मृत्यु दण्ड दिया गया। इन क्रांतिकारियों में घनेर सेना के उच्च पदाधिकारी थे जिनको भी मृत्यु दण्ड दिया गया था। फलस्वरूप चीन में सेना ने विद्रोह कर दिया और क्रांति प्रारम्भ हो गई।

बूचांग प्रान्त की सेनाओं ने 11 अक्टूबर 1911 ई० को ली-युआन हुंग के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जनता ने सेना को सहयोग दिया। परिणामस्वरूप बूचांग में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। वहीं सरकार ने इस क्रांति को कुचलने के लिए युआन शी-काई को बुलाया। वह शासन से अप्रसन्न था, क्योंकि कुछ समय पूर्व उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। इसलिए उसने क्रांति को दबाने में विशेष रुचि नहीं ली। जब सम्राट ने उस प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया, तो वह सेना लेकर क्रांति को कुचलने के लिए रवाना हुआ। इस समय तब क्रांतिकारियों ने नानकिंग को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था और वहाँ पर गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। 29 दिसम्बर 1911 ई० को डॉ० सनयात सेन को अस्थाई राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने 1 जनवरी 1912 ई० को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। युआन शी काई राजतंत्र का समर्थक और क्रांतिकारियों का बट्टर शत्रु था। इसलिए उसने प्रधान मंत्री बनने के बाद क्रांतिकारियों का कुचलना प्रारम्भ कर दिया। इस समय क्रांतिकारी डॉ० सनयातसेन के नेतृत्व में नानकिंग में एक सामयिक सरकार की स्थापना कर चुके थे परन्तु डॉ० सेन चीन में एक सरकार की नव चेतना में थे। परिणामस्वरूप 12 फरवरी 1912 ई० को युआन शी-काई म युद्ध प्रारम्भ के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार चीन के राष्ट्र को बुरी तरह से सिंहासन त्याग दिया। चीन में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समझ गये कि जापाई। 14 फरवरी 1912 को डॉ० सेन ने राष्ट्रपति पद से त्याग राष्ट्र को हाराने में सनकिंग की क्रांतिकारी समिति ने युआन शी काई को चीन का राजा बनाया। इस प्रकार डॉ० सेन ने चीन की एवता को बनाये रखने को भंग कर दिया।

की नजर

हुए प्रभाव

सनयात

आधुनिक चीन

डॉ० सनयात सेन हृदय से देश भक्त था। वह चीन का पाश्चात्य ढग से आधुनिकीकरण कर उसे विश्व का एक महान राष्ट्र बनाना चाहता था। इस काम में उसे उसकी पत्नी बिग लिंग ने बड़ा सहयोग दिया। डॉ० सेन को प्रजातांत्रिक चीन का निर्माता कहा जाता है।

डा० सेन का जन्म हिचांग शान के-टन बंदरगाह से 40 मील दूर गाव में एक कृषक के घर में हुआ था। इनका बड़ा भाई हवाई टापू में व्यापार करता था। इन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा हवाई द्वीप में प्राप्त की। यहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् डा० सेन चीन लौट आये। चीन में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया पर तु पुरातनवादियों ने इन्हें चीन से भागने के लिए विवश कर दिया। 1892 ई० में उन्होंने हांग कांग में डाक्टर की डिग्री प्राप्त की।

डा० सनयात सेन चीन के मन्चू राजवश के विरोधी थे। 1894-95 ई० के युद्ध में जब जापान ने चीन का बुरी तरह में पराजित कर दिया, तब इन्होंने के-टन में क्रांति की परन्तु उक्त सफलता नहीं मिली। क्रांति की असफलता के पश्चात् वे समुक्त राज्य अमेरिका भाग गये। अमेरिका जान से पूर्व उन्होंने एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य पाश्चात्य ढग से चीन का आधुनिकीकरण करना और मन्चू राजवश को उखाड़ फेंकना था। अमेरिका जाने के पश्चात् भी वे चीन के सम्राट के विरुद्ध क्रांतिकारी आन्दोलन का संचालन करते रहे। 1905 ई० में डॉ० सेन ने गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पर जाघारित युग मिग हुई" नामक दल की स्थापना की। प्रागे चलकर 1912 ई० में यही दल कुओमिन्ताग दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

1911 ई० में चीन की राज्य क्रांति के समय डा० सनयात सेन पुन चीन लौट आये। इन्होंने के-टन में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। क्रांतिकारी दल ने डा० सेन को 1912 ई० में के-टन का अस्थायी राष्ट्रपति बना लिया। डा० सेन ने चीन की एरना को ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने स्थान पर युआन शी-वाई को चीन का राष्ट्रपति बनाया। इन्होंने राष्ट्रीवादी दल का नाम कुओमिन्ताग रखा। नानकिंग की ससद में इस दल का बहुमत था। जिससे यह दल राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सका।

1913 ई० में युआन शी-वाई ने मन्चू वश की नीति का अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया। डॉ० सेन ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप युआन शी-वाई ने कुओमिन्ताग दल को अवैधानिक घोषित कर दिया और स्वयं का सम्राट घोषित करने के प्रयास में सग गया। इसमें चीन में आंतरिक विद्रोह प्रारम्भ हो गया। युआन ने विद्रोह को कुचल दिया और डा० सेन को विवश होकर जापान भागना पड़ा। उसने निरक्षाना पूर्वक शासन करना प्रारम्भ किया। चीन में राजतन्त्रात्मक

शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1916 ई० में युआन की मृत्यु के पश्चात् कुओमिन्तांग दल पुनः ताकतवर हो गया।

प्रथम विश्व युद्ध और चीन—प्रथम विश्व युद्ध के समय चीन तटस्थ रहा। जापान ने साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए जीन के कोरिया, मन्चूरिया और धाशातुंग प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं जापान ने चीन को "इक्कीस मागे" स्वीकार करने के लिये विवश किया। परिणामस्वरूप चीन को बाध्य होकर 21 मागे स्वीकार करनी पड़ी। 1916 ई० राष्ट्रपति युआन शी काई की मृत्यु होने के पश्चात् डॉ० सनयात सेन के नेतृत्व में कण्टन में सत्सदीय सरकार की स्थापना की गई। इस प्रकार चीन पुनः दो भागों में विभाजित हो गया।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् चीन में भी पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में चीन को उपेक्षा की गई। उसके विरोध के बावजूद भी शांतुंग प्रदेश पर जापान को अधिकार दे दिया गया। इस सूचना के चीन में पहुँचते ही सम्पूर्ण चीनी जनता ने जापान के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। सभी स्थानों पर जापानी माल का बहिष्कार किया जाने लगा। काफी प्रयासों के बाद इस विद्रोह को शांत किया जा सका।

वाशिंगटन सम्मेलन (1922 ई०)—चीन में जापान के बढ़ते हुए प्रभाव एवं अन्य समस्याओं को हल करने के लिए अमेरिका ने नवम्बर 1921 ई० में वाशिंगटन में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें चीन के सम्बन्ध में नौ राष्ट्रों की सधि की गई। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया।

चीनी गृह युद्ध में कुओमिन्तांग दल की शक्ति में वृद्धि—युआन शी काई की मृत्यु के पश्चात् चीन की आंतरिक दशा शोचनीय हो गई। देश में दो सरकारें काम कर रही थीं। एक कण्टन में और दूसरी पकिंग में। पकिंग की सरकार सैनिक नेताओं के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। ये सेना नायक आपस में लड़ते लड़ते रहते थे। इस प्रकार 1917 ई० के बाद चीन में पुनः गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया। 1921 ई० में डॉ० सेन ने कण्टन में प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। इस समय डॉ० सेन को चीन का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। उसने 1921 ई० में देश की एकता समृद्धि और शक्ति में वृद्धि करने के लिए निम्न तीन सिद्धांतों की घोषणा की—

- 1 जनता में राष्ट्रीय भावना जाग्रत करना।
- 2 प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना।
- 3 समाजवाद

ये तीनों सिद्धांत डॉ० सेन की बसीयत माने जाते हैं। विनाके ने लिखा है

कि "उनका वसूयतनामा" दल के लिए पवित्र सिद्धान्त बन गया और जनता के नीचे सिद्धान्त राष्ट्रपिता वादियों का धर्म ग्रन्थ हो गया।¹

राष्ट्रीयता के अन्तर्गत डॉ० सेन चीन के विदेशियों का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे और जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जाग्रत करना चाहते थे। प्रजातन्त्र के अन्तर्गत डॉ० सेन चीन में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। वह जनता को अधिकार देना चाहते थे ताकि जनता सविधान सभा के सदस्यों को चुनकर भेज सके। समाजवाद के अन्तर्गत सामाजिक धर्म अथवा जनता के मरण पीपण के साधनों को जुटाना था।

डॉ० सेन के सीना सिद्धान्त साम्यवादी विचारधारा के काफी निकट थे। इसलिए रूस ने कुओमिन्तांग दल की सहायता करने का निश्चय किया। डॉ० सेन ने च्यांग-काई शेख की रूस भेजा, ताकि रूस की सहायता प्राप्त की जा सके। तब रूस ने बोरोडीन को डॉ० सेन की सहायता करने के लिए चीन भेजा। बोरोडीन ने चीन में साम्यवादी दल की नींव रखी। अब चीन में साम्यवादी विचारों का तेजी से प्रसार हो रहा था। 1924 ई० में डॉ० सेन ने ब्रिटेन के पास चाम्पोआ में एक सैनिक संस्था की स्थापना की। यह संस्था प्रातिवारियों को सैनिक शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था का अध्यक्ष च्यांग रार्ड शेख था। धीरे धीरे कुओमिन्तांग दल ताकतवर बना गया और मास्को में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसमें हजारों चीनियों को साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। इन सब प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि कुओमिन्तांग दल चीन का एक शक्तिशाली दल बन गया। इस दल में दो वर्ग प्रभावशाली थे। एक राष्ट्रीय जनतन्त्रवादी और दूसरा साम्यवादी। इस प्रकार चीन में दो सरकारें काम कर रही थीं। चीन दो भागों में विभाजित था। डॉ० सेन देश की एकात्मता के लिए प्रयास करते हुए 12 मार्च 1925 ई० को मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात् भी चीन में उनके विचारों का प्रसार किया जाता रहा।

डॉ० सेन के द्वारा किये गये सुधार—डॉ० सेन ने अपने भ्रमणकालमें निम्न लिखित सुधार किये —

1. डॉ० सेन ने शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए काफी प्रयास किये। उसने शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने चीनी भाषा के 40 हजार सवतों के स्थान पर 13 हजार सवत रख दिये इससे चीनी भाषा सरल हो गई। परिणामस्वरूप जनसाधारण आसानी से शिक्षा ग्रहण करने लगा।

- 2 डा० सेन ने यूरोपियन साहित्य का चीनी भाषा में अनुबाद करवाया, ताकि जनसाधारण उम आसानी में पढ़ सकें। इसका अतिरिक्त समाचार पत्रों की प्रान्तसाहित्य किया गया।
- 3 अतः तब कपूगिदस के विचारों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। एसनिय स्कूला में अतः नवीन विचारों की पुस्तकें पढ़ाई जाने लगी।
- 4 चीन के नवीन धर्म द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार किया गया।
- 5 पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव का कारण चीन की संयुक्त परिवार प्रथा तथा अन्य प्राचीन रीति रिवाज समाप्त होने लगे। अब चीन में आधुनिक तरीके में शिक्षा होने लगी। इसका अतिरिक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का जीवन में भी महान परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा।
- 6 डॉ० सेन ने चीन में राष्ट्रीय उद्योगों के स्तान पर बड़े उद्योगों की प्रोत्साहन किया। इससे परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई।

इससे स्पष्ट है कि डॉ० मनपात सेन चीन का एक महान् क्रांतिकारी नेता और उच्चकोटि का सुधारक था। उनके सुधारों से चीन में एक नये युग का आरम्भ हुआ। इमलिय उसके शासनकाल की सनयात मेन काल के नाम से जाना जाता है। उसकी मृत्यु से चीनवासियों का काफी दुःख हुआ। इतिहासकार योमसन ने लिखा है कि डॉ० मनयात मेन अमान्यार था। वह एक गरीब व्यक्ति की तरह मर गया।

1911 ई० की क्रांति के परिणाम—एक क्रांति के प्रमुख परिणाम निम्न लिखित हुए —

- (i) चीन में राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की समाप्ति हो गई।
- (ii) क्रांति के पश्चात् चीन में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई।
- (iii) चीन पाश्चात्य देशों की अपेक्षा रूस की जोर अधिक झुकने लगा।
- (iv) चीन में साम्यवादी तल की स्थापना हो गई।
- (v) चीन में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन को सहायता देना बन्द कर दिया।

छाया काई शेख का आधुनिकीकरण में योगदान—छाया काई शेख डा० सेन यात मेन का विश्वास पात्र व्यक्ति था। छाया काई शेख को 1887 ई० में एक बौद्ध धर्म की अनुयाई स्त्री ने जन्म दिया था। उसने 1907 ई० से लेकर 1911 ई० तक जापान में सैनिक शिक्षा प्राप्त की। डा० सेन से उसका प्रथम सम्पर्क 1907 में हुआ था। वह 1911 ई० की क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। डा० सेन यात मेन ने उसे रूस में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा। इसलिये उस पर

आधुनिक चीन

साम्यवादी विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। 1925 ई० में उगने अपने भाषण में कहा था कि "यदि हमने अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है तो इस सफलता का श्रेय हमारे सोशियलिस्ट्स के साधियों को है। यदि चीनी शक्ति की विजय होती है तो वह विजय रूसी शक्ति की भी है।" परंतु बाद में च्यांग काई शेख साम्यवाद का विरोधी हो गया। 1926 ई० में उसे सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। उसके नेतृत्व में कुओमिन्तांग सेना ने सम्पूर्ण चीन को एक करने के लिये 1926 ई० में उत्तरी चीन पर आक्रमण कर दिया। 1927 ई० तक उस कार्य में सफलता मिली। चीन की एकता एक सरकार के नीचे सम्भव होने लगी।

1927 ई० में कुओमिन्तांग दल में मतभेद पड़ा हो गये और यह दल दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग च्यांग-काई शेख का समर्थक था तो दूसरा साम्यवादी-विचारधारा का। अब धीरे-धीरे चीन में साम्यवादी दल का प्रभाव बढ़ने लगा। ऐसे समय में च्यांग काई शेख ने श्रीमती सनयात सेन की बहिन से विवाह कर अपनी शक्ति में वृद्धि की। 1927 ई० में च्यांग ने नानकिंग पर अधिकार कर लिया और उसे चीन की राजधानी बना दिया। साम्यवादी दल ने उसका विरोध किया और उसने हानको में अपनी सरकार स्थापित की। च्यांग के पास सेना थी। उसे पश्चिमी देशों का सहयोग प्राप्त था। इसलिये उसने साम्यवादी दल की हानकी की सरकार को समाप्त कर दिया। च्यांग ने साम्यवादियों को कुचलकर 1928 ई० में पीकिंग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सम्पूर्ण चीन में एक सरकार का राज्य स्थापित हुआ। च्यांग ने 6 जुलाई 1928 को चीन में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। अब चीन की राजधानी नानकिंग बनाई गई तथा च्यांग की राष्ट्रपति बनाया गया।

चीनी जापानी युद्ध (1931 ई०) —

जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण—चीन में प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना के पश्चात् भी उसका एकीकरण नहीं हो सका। मंचूरिया में चांगत्सो लिन एक स्वतन्त्र शासक की तरह शासन कर रहा था। साम्यवादियों ने मई 1931 में क्वान्तुन में एक सरकार बनाई। इसके अतिरिक्त हेको तथा आसपास के प्रदेशों पर साम्यवादियों का अधिकार था। च्यांग की साम्यवादी विरोधी नीति के कारण पश्चिमी राष्ट्र उसे सहायता दे रहे थे। इतना ही नहीं उन्होंने च्यांग की सरकार को मान्यता भी दे दी थी। च्यांग ने पश्चिमी देशों के साथ कई संधियाँ कीं। उसने विदेशी सहायता प्राप्त कर चीन का एकीकरण करने का प्रयास किया। फलस्वरूप चीन में पुनः गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया। इसी समय जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया।

आक्रमण करने के कारण—जापान द्वारा चीन के मंचूरिया प्रदेश पर

आक्रमण करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) भौगोलिक कारण—

- (i) जापान मचूरिया के निकट स्थित है ।
- (ii) दोनों देशों की जलवायु अनुकूल है ।
- (iii) मचूरिया एक उपजाऊ प्रदेश है । जहाँ पर चावल, सोयाबीन व अन्य अनाज का उत्पादन काफी मात्रा में होता है । जापान ने व्यावसायिक उन्नति तो करली थी, परन्तु वहाँ अभी तक, खाद्य पदार्थों का उत्पादन आवश्यकता से कम होता था । जापान मचूरिया से कच्चा माल, ताँहा, कोयला और तेल सस्ती दरों पर प्राप्त कर सकता था और अपना अतिरिक्त उत्पादन वहाँ इच्छानुसार दूरों पर बेच सकता था । इस प्रकार मचूरिया जापान के लिये एक अच्छा बाजार भी था । जापान ने अपने औद्योगिक विकास के लिये इस प्रदेश पर अधिकार करने का निश्चय किया । जापान के लिये मचूरिया की सामरिक स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण थी । गेयोन हार्डी ने लिखा है कि “जापान के लिये मचूरिया का प्रतिरक्षा और आक्रमण की दृष्टि से सामरिक महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है ।”

(2) आर्थिक कारण—

- (i) जापान की जनसंख्या में 9 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि हो रही थी । इस बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिये जापान को जगह की आवश्यकता थी । 1924 ई० में अमेरिका ने जापानियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी । इसी प्रकार के प्रतिबंध आस्ट्रेलिया ने भी लगा दिये थे ।
- (ii) 1923 ई० में जापान में एक भयंकर भूकम्प आया । जिससे काफी क्षति हुई । उसके बाद बाढ़ों से भी काफी क्षति हुई । अतः जापान की आर्थिक व्यवस्था दयनीय हो गई थी ।
- (iii) 1930-31 के विश्व व्यापी आर्थिक संकट के कारण जापान की आर्थिक व्यवस्था काफी शोचनीय हो गई थी ।
- (iv) जापान मचूरिया से सस्ती दरों पर कच्चा माल प्राप्त कर सकता था और वहाँ इच्छानुसार दूरों पर अपना माल बेच सकता था ।
- (v) जापान ने कोरिया पर 1894 ई० में अधिकार कर चुका था । अब वह मचूरिया का अपने अधिकार में लाना चाहता था । जापान ने दक्षिणी मचूरिया में एक रेलवे लाइन का निर्माण करवाया । पट्टे के आधार पर उस पर जापान का अधिकार था । मचूरिया में जापानी पूंजीपतियों ने कई कारखानों की स्थापना की । 1931 ई० तक जापानी पूंजीपति एक मिलियन डॉलर पूंजी मचूरिया में लगा चुके

थे। जापानी पूँजीपतिषु को यह भय था कि वही राष्ट्रवादी चीन राष्ट्रियकरण कर उनकी सम्पत्ति को ज्वन न कर ले। अतः वे सरकार पर निरन्तर दबाव डाल रहे थे।

(3) सामरिक महत्व—

- (i) जापान मचूरिया पर अधिकार करने में पश्चात् ही चीन के दक्षिणी प्रदेशों में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता था।
- (ii) इस और जापान दोनों ही देश मचूरिया पर अधिकार करना चाहते थे, परन्तु इस समय इस अपनी आन्तरिक समस्याओं को हल करने में व्यस्त था। इसलिये अवसर का लाभ उठाकर जापान ने इस प्रदेश पर अधिकार करने का निश्चय किया।

(4) चीन और जापान की आन्तरिक स्थिति—

- (i) जापान ने वाशिंगटन सम्मेलन के द्वारा निश्चित नौबेड़े के निमाण की सीमाओं का पालन करने से इन्कार कर दिया। इस सम्मेलन में उसने चीन की अखण्डता का बचन लिया था। परन्तु जापान का राजनीतिक दल ने इसका विरोध किया। परिणामस्वरूप 1930 ई० में जापानी सरकार ने साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए मचूरिया पर अधिकार करने का निश्चय किया।
- (ii) चीन में 1912 ई० में राज्य प्राप्ति हुई परन्तु पिछले 18 वर्षों में आन्तरिक मतभेदों के कारण चीन किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका था। व्यापक कोई एक साम्यवादी दल से मतभेद चल रहा था। चीन में दो सम्कारें शासन चला रही थीं। एक कैंटन में और दूसरी नानकिंग में। उस समय ऐसी सम्भावना थी कि इन दोनों दलों में कभी भी समझौता हो सकता है।
- (iii) चीन में साम्यवादी दल माओ और जोन के नेतृत्व में राष्ट्रवादी दल का विरोध कर रहा था। फिर भी इस समय साम्यवादी दल ने जापान के विस्तार को रोकने के लिये एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने का सुझाव दिया। जिस व्यापक कोई एक ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह साम्यवाद को जापानिया में भी ज्यादा खतरनाक मानता था। फिर भी जापानियों को यह भय था कि वह संयुक्त मोर्चा कभी भी स्थापित हो सकता है।
- (iv) यद्यपि चीन के प्रमुख राजनीतिक और शासन जापान के प्रश्न पर एकमत नहीं थे, परन्तु चीनी जनता में जापान के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था। इसलिये नई प्रान्तों में जापानी माल का बहिष्कार किया

जा रहा था। जनता न सभी दलों को संगठित होकर जापान का मुकाबला करने की मांग की।

- (v) प्रारम्भ में मचूरिया के शासक च्यांग त्सोलिन ने जापान का विरोध नहीं किया। उसने 1928 ई० में च्यांग काई शेख से समझौता कर लिया परन्तु उसका पुत्र च्यांग लिआंग मचूरिया में जापानी प्रभाव समाप्त करना चाहता था। इससे भी जापान ने शीघ्र ही मचूरिया पर अधिकार करने का निश्चय किया।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जापान के अनुकूल थीं—

- (i) इस समय सभी देशों की आर्थिक स्थिति आर्थिक मंदी के कारण शोचनीय हो गई थी।
- (ii) चीन में 1931 ई० में बाढ़ों के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इसके अतिरिक्त इस समय चीन के सैनिक पदाधिकारी आपस में लड़ने में व्यस्त थे।
- (iii) जापान जानता था कि इंग्लैंड, फ्रांस व अमेरिकन साम्यवादी विरोधी होने से मचूरिया पर अधिकार करने का विरोध नहीं करेंगे। यदि उन्होंने विरोध किया तो जापान यह कह सकता था कि इस चीन दुबलता का लाभ उठाकर वहाँ मचूरिया पर अधिकार न कर ले। इसलिए वह मचूरिया पर अधिकार कर रहा है।

(6) आकस्मिक कारण—18 सितम्बर 1931 ई० की रात्रि को मचूरिया में मुकडेन के निकट जापानी रेल्व लाईन को कुछ व्यक्तियों ने बम से उड़ा दिया। जापान ने इसका लिये चीन को दोषी मानते हुए मुकडेन नगर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1932 ई० में जापानी सना ने सम्पूर्ण मचूरिया पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकार स्थापित कर दी। चीन की सरकार जापान को मचूरिया पर अधिकार करने से नहीं रोक सकी। राष्ट्रसंघ भी इस सबूध में काई ठोस कदम नहीं उठा सका। जब राष्ट्रसंघ ने जापान के विरुद्ध बाधवाही करने का निश्चय किया तो जापान ने राष्ट्रसंघ की सन्म्यता से त्यागपत्र दे दिया।

जापान ने मचूरिया पर अधिकार करने के पश्चात् चीन के अर्थ प्रदर्शों पर अधिकार करने का प्रयास किया। चीन की जनता ने जापान के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ कर लिया परन्तु चीन का राष्ट्रपति जापान के विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के स्थान पर साम्यवादियों के बुचलने में लगा हुआ था। साम्यवादी दल ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि राष्ट्रवादी सरकार जापान का मुकाबला करे तो वह सरकार के साथ समझौता करने के लिये तैयार है परन्तु च्यांग काई शेख ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया। 1936 ई० में जब च्यांग काई शेख शांसी प्रदेश

में साम्यवादियों का सफाया कर रहा था। तब सनिको ने इसका अग्रहरण कर लिया और उभ तभी मुक्त किया गया, जबकि उसने साम्यवादियों के साथ मिलकर जापान का विरोध करने का वायदा कर लिया।

1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। उस समय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये साम्यवादी दल और राष्ट्रवादी दल में समझौता हो गया। च्यांग काई शेख के नेतृत्व में दोनों दलों ने संयुक्त रूप में जापान का मुकाबला किया। जापान ने चीन के हीपैइ शांशी तथा शांतुंग प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। चीन और जापान का युद्ध द्वितीय महायुद्ध के अंत तक चलता रहा। यद्यपि चीन को जापान को पराजित करने में सफलता नहीं मिली फिर भी उसने बहादुरी के साथ जापान का सामना किया और अंतिम समय तक साहस नहीं छोड़ा।

चीन में साम्यवादी क्रांति (1949 ई०)—द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् चीन को जापान के आक्रमण से मुक्ति मिल गई परंतु इसके पश्चात् चीन में पुनः गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया। यद्यपि महायुद्ध के समय चीन के साम्यवादी और राष्ट्रवादी दल ने मिलकर जापान का मुकाबला किया था, परन्तु युद्ध के बाद दोनों दलों में पुनः गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस मध्य में साम्यवादियों की विजय हुई और च्यांग काई शेख को चीन से भागना पड़ा। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। इतिहासकार शूमा ने साम्यवादियों की सफलता के बारे में लिखा है कि 'द्वितीय महायुद्ध के विनाश तथा महार न मिलने तथा शत्रुओं की मूर्खता के साथ मिलकर चीन को साम्यवाद के हाथों सौंप दिया। अमेरिका के आंकड़ों ने चीन की क्रांति को 'रूसी पद्धति' अथवा 'वाशिंगटन में विश्वासघातियों के पडपन्ने' का किसी न किसी रूप में परिणाम बताया। चीन की लाल विजय बीसवीं शताब्दी में रूस की सबसे भारी विजय तथा अमेरिका की सबसे बड़ी पराजय होत हुए भी, न तो अमेरिका के योग का काय था और न रूसिया का, बरन चीनिया का ही काय था।'

पकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चिन तु सिङ ने अपनी पत्रिका "सिन चिंग जिन" के माध्यम से सब प्रथम चीनी जनता को साम्यवाद का संदेश पहुँचाया था। कुछ लोगों का ऐसी मान्यता है कि प्रोफेसर चिन तु सिङ ने 1921 ई० में चीन में साम्यवादी दल की स्थापना की। माओत्स तुंग, चाऊ एन लाई और चूतह आदि इस दल के सदस्य बन।

1922 ई० से 1927 ई० तक साम्यवादी दल और कुओमिन्ताग दल में आपसी सहयोग बना रहा परंतु उसके पश्चात् च्यांग काई शेख साम्यवादी दल का विरोधी बन गया। अब उसने साम्यवादियों का कुचलना प्रारम्भ किया। साम्यवादियों का केन्द्र दण्गो चीन था। जब च्यांग काई शेख की सेनाओं ने उन्हें दक्षिण में घेर लिया तो उन्होंने उत्तरी चीन की तरफ प्रयाण किया। दक्षिणी चीन से उत्तरी

चीन की दूरी तीन हजार बग मील थी साम्यवादियों को इस दूरी को पार करने में 8 महीने का समय लग गया और रास्ते में हजारों व्यक्ति मारे गये। इसे "एतिहासिक प्रयाण" के नाम से जाना जाता है। च्यांग ने काफी प्रयास किये परन्तु साम्यवादियों की प्रगति को रोकने में असफल रहा। साम्यवादियों ने गैंगी प्रांत में अपनी अलग सरकार बना ली। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक साम्यवादी दल ने जापान का मुकाबला करने के लिये राष्ट्रवादी दल को पूरा सहयोग दिया।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् चीन में पुनः गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया। उत्तरी चीन पर साम्यवादियों का अधिकार था और दक्षिण चीन पर च्यांग काई शेख का अधिकार था। च्यांग काई शेख को अमेरिका सहायता दे रहा था जबकि साम्यवादी दल को रूस सहायता दे रहा था। गृह युद्ध के दौरान समझौते के प्रयास असफल रहे। मार्च, 1947 में च्यांग काई शेख को भारी सफलता मिली। उसने साम्यवादियों के घनान मचूरिया और शातुंग प्रदेशों पर अधिकार कर लिया परन्तु शीघ्र ही साम्यवादियों ने उन्हें वहाँ से धकेल दिया। इसके पश्चात् साम्यवादी सेनाओं निरंतर आगे बढ़ती रही।

चीन में 1945 ई० से 1949 तक गृह-युद्ध चलता रहा। इस गृह-युद्ध में साम्यवादियों को सफलता प्राप्त हुई। 1 अक्टूबर 1949 ई० को चीन में साम्यवादी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। नई सरकार की राजधानी पकिंग बनाई गई। साम्यवादी दल ने नये गणतन्त्र का अध्यक्ष माओत्से तुंग को एवं प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई को बनाया। च्यांग काई शेख ने चीन से भाग कर फारमोसा द्वीप में शरण ली। वहाँ पर उसने अमेरिका की सहायता से राष्ट्रीय चीन की सरकार स्थापित की। इसमें प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। साम्यवादी चीन (लाल चीन) के नाम से जाना जाता है। जबकि च्यांग काई शेख का चीन राष्ट्रवादी चीन के नाम से प्रसिद्ध है। साम्यवाद की स्थापना के पश्चात् चीन ने बहुत उन्नति की। अब वह विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। इसके अतिरिक्त समुक्त राष्ट्रसंघ को सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से वह एक है। अब उसकी गिनती विश्व के पांच महान राष्ट्रों में की जाती है।

गृहयुद्ध की साम्यवादी दल की विजय के कारण—चीन के गृह युद्ध में साम्यवादी दल की विजय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(1) च्यांग काई शेख की नीति के कारण साम्यवादियों को सफलता मिली। उसकी पूँजीवादी नीति के कारण अमेरिका उसको सहायता दे रहा था। धीरे धीरे अमेरिका ने चीन में अपना आर्थिक विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप चीन के उद्योग धंधे ठप्प हो गये और लाखों मजदूर बेकार हो गये। इन मजदूरों ने कुओमिन्तांग दल के विरुद्ध साम्यवादी दल का समर्थन किया।

इहीं मजदूरो के सहयोग के कारण यह-युद्ध म साम्यवादी दल विजय प्राप्त कर सका ।

(2) क्यांग काई शेख सत्ता मे आते ही डॉ० सनयात सेन के सिद्धान्तो को भूल गया और उसने शासन को समस्त शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर गिरकुशता पूर्वक शासन करना प्रारम्भ कर दिया । उसने अपने विरोधियों का कठोरतापूर्वक दमन किया । इतना ही नहीं सरकार के प्रत्येक विभाग म अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को नियुक्त किया । नियुक्ति करते समय योग्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । उसने सेना के उच्च पदों पर अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को नियुक्त किया ।

(3) क्यांग काई शेख न देश म राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि शासन म अयवस्था फलने लगी और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा । चीन की आर्थिक दशा निरंतर दयनीय होती जा रही थी । चीनी सिक्के का मूल्य काफी गिर गया था । विदेशों मे चीन को जो आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी, उसे क्यांग के कृपा पात्र हजम कर जाते थे । सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उनम भी क्यांग के प्रति अमनोप था । शासन की दमनकारी नीति के कारण समाज का प्रत्येक वर्ग सरकार का विरोधी होता जा रहा था । बुद्धिजीवी वर्ग अधिकारों की तथा सुधारों की मांग कर रहा था, परंतु सरकार ने इस दिशा मे कोई कदम नहीं उठाया । क्यांग की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण उमकी लोक प्रियता धीरे धीरे कम होनी जा रही थी । जन साधारण में क्यांग के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था । इसलिये उसकी सरकार का पतन होना आवश्यकभावी था ।

इसके विपरीत साम्यवादी दल ने प्रारम्भ से ही देश शक्ति का परिचय दिया । जापान का विरोध करने म साम्यवादी दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । उन्होंने क्यांग काई शेख के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम आपस के मतभेद भुला कर जापान का मुकाबला करना चाहिये । परंतु क्यांग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह साम्यवाद को जापानियों से ज्यादा खतरनाक मानता था । इसलिये उमने अपनी सारी शक्ति साम्यवादियों को मुचलने में लगा दी । साम्यवादियों ने जनता के सामने अपने निम्न कार्यक्रम रखे —

- (1) इसके अनुसार चीन स विदेशियों का प्रभाव समाप्त किया जायेगा ।
- (2) देश के धन का दुरुपयोग करने वालों का दण्ड किया जायेगा ।
- (3) निधनों तथा बरोजगारों को सहायता दी जायेगी ।
- (4) जनता का मौलिक अधिकार रक्षित जायेगा और उसकी रक्षा भी की जायेगी ।
- (5) चीन की अक्षमता को बनाये रखा जायेगा ।
- (6) यदि साम्यवादी दल का शासन स्थापित हुआ तो जन-कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

चीन की दूरी तीन हजार वग भीत की साम्यवादियों को इस दूरी को पार करने में 8 महीने का समय लग गया और रास्ते में हजारों व्यक्ति मारे गये। इसे "एतिहासिक प्रयाण" के नाम से जाना जाता है। च्यांग काफ़ी प्रयास किये परन्तु साम्यवादियों की प्रगति को रोकने में असफल रहा। साम्यवादियों ने दक्षिणी प्रांत में अपनी असल सरकार बना ली। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक साम्यवादी दल ने जापान का मुकाबला करने के लिये राष्ट्रवादी दल को पूरा सहयोग दिया।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् चीन में पुनः गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया। उत्तरी चीन पर साम्यवादियों का अधिकार था और शेष चीन पर च्यांग काई शेख का अधिकार था। च्यांग काई शेख को अमेरिका सहायता दे रहा था जबकि साम्यवादी दल को रूस सहायता दे रहा था। गृह युद्ध के दौरान समझौते के प्रयास असफल रहे। मार्च, 1947 में च्यांग काई शेख को भारी सफलता मिली। उसने साम्यवादियों के येंगान मचूरिया और शांतुंग प्रान्तों पर अधिकार कर लिया परन्तु शीघ्र ही साम्यवादियों ने उन्हें वहाँ से धकेल दिया। इसने पश्चात् साम्यवादी सेनाओं निरन्तर आगे बढ़ती रही।

चीन में 1945 ई० से 1949 तक गृह-युद्ध चलता रहा। इस गृह-युद्ध में साम्यवादियों को सफलता प्राप्त हुई। 1 अक्टूबर 1949 ई० को चीन में साम्यवादी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। नई सरकार की राजधानी पकिंग बनाई गई। साम्यवादी दल के नये गणतन्त्र का अध्यक्ष माओत्स तुंग को एक प्रधानमंत्री काऊ एन लाई को बनाया। च्यांग काई शेख ने चीन के भाग कर पार सूसा द्वीप में शरण ली। वहाँ पर उसने अमेरिका की सहायता से राष्ट्रीय चीन की सरकार स्थापित की। इसमें प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। साम्यवादी चीन (लाल चीन) के नाम से जाना जाता है। जबकि च्यांग काई शेख का चीन राष्ट्रवादी चीन के नाम से प्रसिद्ध है। साम्यवाद की स्थापना के पश्चात् चीन में बहुत उन्नति की। अब वह विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। इसके अतिरिक्त समुक्त राष्ट्रमण्डल की सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों में से वह एक है। अब उसकी गिनती विश्व के पांच महान राष्ट्रों में की जाती है।

गृहयुद्ध की साम्यवादी दल की विजय के कारण — चीन में गृह युद्ध में साम्यवादी दल की विजय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

(1) च्यांग काई शेख की नीति के कारण साम्यवादियों को सफलता मिली। उसका पूँजीवादी नीति के कारण अमेरिका उसको सहायता दे रहा था। धीरे धीरे अमेरिका ने चीन में अपना आर्थिक विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप चीन में उद्योग धंधे ठप्प हो गये और लाखों मजदूर बेकार हो गये। इन मजदूरों ने कुओमिन्तांग दल के विरुद्ध साम्यवादी दल का समर्थन किया।

इन्हीं मजदूरों के सहयोग के कारण गृह-युद्ध में साम्यवादी दल विजय प्राप्त कर सका।

(2) च्यांग काई शेख मत्ता में आते ही डॉ० सनयात सेन के विद्वान्त्वों को भूल गया और उसी शासन की समस्त शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर निरकुशता पूर्वक शासन करना प्रारम्भ कर दिया। उसने अपने विरोधियों का कठोरतापूर्वक दमन किया। इतना ही नहीं सरकार के प्रत्येक विभाग में अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को नियुक्त किया। नियुक्ति करते समय योग्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसने सेना के उच्च पदों पर अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों का नियुक्त किया।

(3) च्यांग काई शेख ने देश में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि शासन में अयवस्था फैलन लगी और घ्रष्टाचार बढन लगा। चीन की आर्थिक दशा निरंतर दयनीय होती जा रही थी। चीनी सिक्के का मूल्य काफी गिर गया था। विदेशों से चीन को जो आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी, उसे च्यांग के वृषा पात्र हजम कर जाते थे। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उनमें भी च्यांग के प्रति असंतोष था। शासन की दमनकारी नीति के कारण समाज का प्रत्येक वर्ग सरकार का विरोधी होता जा रहा था। बुद्धिजीवी वर्ग अधिकारों की तथा सुधारों की मांग कर रहा था, परन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। च्यांग की अनिश्चिन्ता वाली नीति के कारण उसकी लोक प्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जनसाधारण में च्यांग के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था। इसलिये उसकी सरकार का पतन होना आवश्यकमानी था।

इसके विपरीत साम्यवादी दल ने प्रारम्भ से ही देश भक्ति का परिचय दिया। जापान का विरोध करने में साम्यवादी दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने च्यांग काई शेख के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम आपस के मतभेद भुलाकर जापान का मुकाबला करना चाहिये। परन्तु च्यांग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह साम्यवाद को जापानियों में ज्यादा खतरनाक मानता था। इसलिये उसने अपनी सारी शक्ति साम्यवादियों को कुचलने में लगा दी। साम्यवादियों ने जनता के सामने अपने निम्न कार्यक्रम रखे —

- (1) इसके अनुगार चीन से विदेशियों का प्रभाव समाप्त किया जायगा।
- (2) देश के धन का दुरुपयोग करने वालों को दण्ड दिया जायेगा।
- (3) निधना तथा बरोजगारी को सहायता दी जायेगी।
- (4) जनता को मौलिक अधिकार दिये जायेंगे और उनकी रक्षा भी की जायेगी।
- (5) चीन की अगण्डता को बनाय रखा जायेगा।
- (6) यदि साम्यवादी दल का शासन स्थापित हुआ तो जन-कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(7) रोजी रोटी की समस्या को हल किया जायेगा ।

साम्यवादी दल के इन कार्यक्रमों में उन्ने शीघ्र ही जनता का समर्थन प्राप्त हो गया । साम्यवादी जिस प्रश्न पर अधिकार करते थे, वही जमींदारों से भूमि छीन कर उसे किसानों में बांट देते थे । इस नीति के कारण साम्यवाद दल को किसानों का सहयोग प्राप्त हो गया ।

(4) साम्यवादी दल के सैनिक छापामार प्रणाली से युद्ध लड़ते थे । इस कारण उन्हें च्यांग काई कैच के विरुद्ध निरंतर सफलता प्राप्त होती रही । साम्यवादी दल के सेनानायक यांग थे । उनमें राष्ट्रीय भावनाएँ कूट-कूट कर भरी हुई थी । मेना में एषिया और अनुशासन था । इस प्रकार साम्यवादियों की सैन्य नीति और कुशल युद्ध संचालन के कारण उन्हें गृह युद्ध में सफलता प्राप्त हुई ।

चीनी शक्ति में माओत्से तुंग का योगदान—माओत्से तुंग को आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है । वह चीन के साम्यवादी दल के संस्थापकों में से एक था । 1893 ई० में यह हुनान प्रांत के एक कृषक परिवार में पैदा हुआ था । माओत्से तुंग की बचपन में ही शादी कर ली गई । शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वह पकिंग विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुआ । महा उसने मार्क्स के विचारों का अध्ययन किया ।

1919 ई० में माओत्से की चीन के प्रोफेसर चैन तु सिउ से मुलाकात हुई । वह उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ । इसलिये 1921 ई० में जब साम्यवादी दल की स्थापना की गई तो वह भी उसका सदस्य बन गया । माओत्से तुंग को हुनान प्रांत का सचिव बनाया गया । जहाँ उसने किसानों और मजदूरों को संगठित किया । 1923 ई० में उसे केन्द्रीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया । शघाई में मजदूरों की हड़ताल के समय माओत्से हुनान लौट आया । यहाँ आकर उसने भूमि को किसानों में वितरण करने की मांग की । 1927 ई० में माओत्से के नेतृत्व में हुनान के किसानों ने क्रांति की । जिसे सरकार ने कुचल दिया । परंतु माओ को हुनान तथा किंग्यासी के किसानों को संगठित करने में सफलता मिली । माओ ने चिंग कासान में एक साम्यवादी के दल की स्थापना की ।

इस समय चीन के साम्यवादी दल की स्थिति शीघ्रनीय थी । इस दल की शघाई शाखा ने माओत्से को हुनान के सचिव के पद से हटा दिया । 1928 ई० में चू तेह माओत्से के साथ आकर मिल गया । इससे माओ की स्थिति सुदृढ़ हो गई । माओत्से ने किंग्यासी, क्वांगतुंग और शेन्शी आदि प्रांतों में साम्यवादी केंद्र स्थापित करने की प्रेरणा दी । 1930 ई० में माओ के नेतृत्व में किंग्यासी प्रांत में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई । माओ ने चूतेह को प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया । उसने यहाँ पर भूमि सम्बन्धी सुधार किये । जिसके कारण उसे किसानों का समर्थन प्राप्त हो गया । 1931 ई० तक दल के अंतर्गत कई सदस्यों ने माओत्से को अपना नेता स्वीकार कर लिया ।

च्यांग वाई नेच ने किंग्यासी के द्र में साम्यवादियों की शक्ति को कुचलने के हर समब प्रयास किया परंतु माओत्से की छापा मार युद्ध प्रणाली के कारण उसे सफलता नहीं मिली। 1932 ई० में साम्यवादी सेना ने कुकियन, हुनान तथा बवांग तुंग आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इस पर अक्टूबर 1933 ई० में च्यांग वाई नेच ने साम्यवादियों का सफाया करने के लिये दस लाख सैनिक भेजे। जिन्होंने माओ को चारा ओर में घेर लिया। ऐसी स्थिति में माओत्से ने अपना 90 हजार सैनिकों के साथ किंग्यासी से शंसी की ओर प्रयाण किया। इस दूरी का पार करने में उसे 8 महीने लग गये। इस अभियान में उसने 60,000 सैनिक मारे गये। उसका यह प्रयाण "ऐतिहासिक प्रयाण" के नाम से प्रसिद्ध है। इस अभियान में माओत्से की सफलता मिली। अब उसने येंनान में एक नया केन्द्र स्थापित किया। इस केन्द्र को इस के निकट होने के कारण आशानी में रूसी सहायता प्राप्त हो सकती थी।

1935 ई० में माओत्से ने च्यांग वाई से छेक के समझ प्रस्ताव रखा कि साम्यवादी और बुद्धोपिठाग दल आपस के मतभेद भुलाकर समुक्त रूप से जापान का मुकाबला करें, परंतु च्यांग वाई से छेक न इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। च्यांग वाई से छेक साम्यवाद को जापान से अधिक खतरनाक समझता था। इसलिये उसने साम्यवादियों का सफाया करना प्रारम्भ कर दिया। परिस्थितियां से विवश होकर च्यांग वाई नेच को साम्यवादी दल से समझौता करना पड़ा। 1937 ई० में दोनों दलों ने समुक्त माचा बनाया। युद्धकाल में साम्यवादियों ने जापानी सेना का बटकर मुकाबला किया। उठाने जापान अधिभूत प्रदेशों पर अधिकार कर वहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित करनी प्रारम्भ कर दी। इन क्षेत्रों की जनता का समयन प्राप्त करने के लिये साम्यवादियों ने कई आर्थिक सुधार किये।

1940 ई० में माओत्से ने "नये जनतंत्र" नामक पुस्तक लिखी। इसमें उसने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुयारा का वर्णन किया। 1942-43 ई० में उसने साम्यवादी दल में कई सुधार किये। महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् माओत्से ने च्यांग वाई से छेक को पूरा रूप से पराजित कर चीन से भगा दिया। उसने साम्यवादी सेना में एकता और अनुशासन बनाये रखा और चीन में विदेशियों का प्रभाव समाप्त करने में साम्यवादी सेना ने माओत्से के नेतृत्व में शानदार सफलताएँ प्राप्त कीं।

प्रस्ताविक सन्दर्भ पाठ्य पुस्तकें —

- 1—बराइड, पाल० एच०—दी फार ईस्ट
- 2—ग्रिमरोड, ए० बिटनी—फार ईस्टन पालिमी आफ यूनाइटेड स्टेटस
- 3—इब्राहम ऐमटीन—श्रीम भोपियम वार टू तिबेटेशन
- 4—बिनावे, हैराल्ड एम—पूर्व एशिया का आधुनिक इतिहास
- 5—बागन्टम लिटले—ची हिस्ट्री आफ टार्डियंग रेवोल्यूशन

14

जापान का आधुनिकीकरण

जापान दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व तक एशिया में सबसे शक्तिशाली और विश्व की एक महान शक्ति बन चुका था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसने तीव्र गति से विकास किया और 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वह इंग्लैंड के समकक्ष हो गया। इतिहासकार यनेगा ने लिखा है कि 'जापान का उदय और अस्त उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार एक उल्का अपने तीव्र प्रकाश से सारी अंधेरी रात को प्रकाशमान कर थोड़ी ही देर में लुप्त हो जाती है।'¹

प्राचीन जापान— जापान का इतिहास बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। क्लाइड ने लिखा है कि 500 ई० पू० जब कन्फ्यूशियस इतिहास की महानतम चरित्र सवधी 'यारयाओं' में से एक का प्रतिपादन कर रहा था तो जापान का इतिहास गुरु भी नहीं हुआ था और इसके मैदान अमद्र और जंगली लोगों के युद्धस्थल मात्र थे।²

जापान 2500 मील लम्बे टापुओं का समूह है। वहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है इसलिये जापानी अपने देशों में 'निपोन' भी कहते हैं। जापानी भूगोल जाति के है। इनका रंग पीला कद छोटा और आँखें छोटी होती है। जापान के दक्षिणी भाग में रहने वाले लोग पोलोनेशियन जाति के हैं। यद्यपि जापान के टापुओं में पहाड़ी भाग अधिक है। फिर भी पहाड़ों की घाटियाँ और नदियों के मैदानों में कृषि योग्य भूमि होने से पदावार अच्छी होती है। यहाँ की मुख्य उपज चाय चावल और शहतूत आदि है। प्राचीन और मध्यकाल में जापानी लोगों का मुख्य व्यवसाय रेशम का कपड़ा बनाना था।

छठी शताब्दी के मध्य तक जापानियों की कोई लिखित भाषा नहीं थी।

1—यनेगा—जापान सिन्स परी पृष्ठ 7

2—क्लाइड, पाल० एच०- दी फार ईस्ट 58

550 ई० म बौद्ध भिदु कोरिया हाने हूय जापान म आयें । जहां जापानी जनता न उनका बहुत अच्छा स्वागत किया । जापानी लोग ने बौद्ध भिदुआ स चीनी भाषा सीखी और वे बौद्ध धर्म के अनुयाई बन गय । इन समय के जापानी शासन शातानु ने बौद्ध धर्म के भिदुता और राजकीय कानून का मकानन किया । बौद्ध धर्म के साथ जापानी लोग शिंटो धर्म म भी विश्वास करत रह । यह धर्म प्रकृति, पूर्वजों और सम्राट की पूजा पर अधिक जोर देता था ।

प्राचीन कथाका के अनुसार जापान का इतिहास बहुत पुराना है । पश्चिमी देश के सम्पर्क में आने से पहले जापान की राजनीतिक दशा गौचनीय थी । ऐसा माना जाता है कि 11 फरवरी 630 ई० पू० म जिम्मु नामक व्यक्ति न जापान के साम्राज्य की स्थापना की थी । जापानी सम्राट अपने का 'मूल पुत्र' कहते थे, क्योंकि जापान म सबसे पहले सूर्योदय होता था । यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी और मुद कला में दक्ष थे । यहाँ पर सामन्तवादी शासन-व्यवस्था विद्यमान थी ।

8वीं शताब्दी तक 12वीं शताब्दी तक राज्य की शक्ति सामन्तों के हाथों म केंद्रित थी । 12वीं शताब्दी म जापान क सम्राट न अपनी सहायता क लिये 'शोगुन' नियुक्त किया । शोगुन सम्राट का शासन सम्बन्धी शायों म सहयोग देते थे । शासन का प्रधान राजा था, लेकिन वह नाम मात्र का शासक था । उसके पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी । सम्राट कपोती के राजमहल में रहता था । राजकीय आय का एक निश्चित भाग उसके खर्च के लिये दिया जाता था । जापानी जनता सम्राट का ईश्वर तुल्य मानती थी । जन साधारण सम्राट में नहीं मिल सकता था ।

राज्य की वास्तविक शक्ति सम्राट क हाथ म न होकर शोगुन के हाथ म थी, जो जापान का प्रधानमंत्री होता था । सम्राट सामन्तों के नेता की शोगुन के पद पर नियुक्त करता था । धीरे धीरे प्रशासन म सामन्तों का प्रभाव बढ़ने लगा । जापानी शासन सामन्ती प्रथा पर आधारित था । शोगुन के नीचे छोटा सामन्त होता था, उसको 'डायमीओज' कहा जाता था । डायमीओज क अधीन जागीरदार होता था, उसको समुराई कहा जाता था । धीरे धीरे जापान म शोगुन का पद पतुव हा गया ।

1868 ई० के पश्चात् जापान न पाश्चात्य सम्पर्क के कारण आश्चर्यजनक प्रगति की । इसका परिणाम यह हुआ कि 1905 ई० म उसने रूस का बुरी तरह पराजित किया । इस प्रकार जापान एशिया का सब शक्तिशाली और विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया ।

जापान का पश्चिमी देशों से सम्पर्क—1542 ई० में पुतगाता सबप्रथम जापान पहुँचे । इसके पश्चात् 16वीं शताब्दी क अन्तिम वर्षों म स्पनिश, 17वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों म डच और अंग्रेज स्पनिश की आर से जापान पहुँचे । इन्होंने नागाराकी म अपना व्यापारिक वाठिया स्थापित की । प्रारम्भ म जापानियों

न इन विदेशी लोग का स्वागत किया परन्तु बाद में इनके पारम्परिक भगडा को देखकर जापानी लोग सतक हो गये। शोगुन इन विदेशियों को घणा की दृष्टि से दृग्ता था। इसलिये 1614 ई० म उसने एक आणा क द्वारा ईसाई धम प्रचारका के जापान म आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जापान म गिरजाघरा को नष्ट कर दिया गया। जिन जापानियों न ईसाई धम ग्रहण कर लिया था, उठ फिर स बौद्ध धम स्वीकार करवाया गया।

चीन न पाश्चात्य दशा के प्रभाव को सुगमता से स्वीकार कर लिया था। पर तु जापान की जनता पश्चिमी सभ्यता को घणा की दृष्टि से देखती थी। इसलिये जापान की सरकार न 1936 ई० म एक और कानून बनाया। जिक अनुमार —

- (1) जापान ने पश्चिमी दशा से अपन सभ्यघ स्थापित कर दिये।
- (2) स्पनिश पुनगाली और अग्रेज व्यापारिया क जापान म आने पर रोक लगा दी गई।
- (3) जापानियों का पश्चिमी राष्ट्रों के साथ व्यापार करना गैर कानूनी घोषित किया गया।
- (4) जापान म बस हुये विदेशियों को जापान से बाहर निकाल दिया गया।
- (5) सरकार न जापानियों के देश से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
- (6) डच व्यापारियों को नागामाकी म व्यापार करन की इजाजत दी गई।

इस प्रकार जापान की सरकार न पृथकीकरण की नीति अपनाई। जापान दो वष तक इस नीति पर चलता रहा, परन्तु इन प्रतिबन्धों के बावजूद भी जापान की सरकार पश्चिमी देशों के लोगों का अपन यहा आने स नही रोक सकी।

19वीं शताब्दी क प्रारम्भ म औद्योगिक शान्ति हुई। जिसके फलस्वरूप वाष्पचलित जहाज से लोग यात्रा करन लगे। प्रशांत महासागर म जहाजों के विद्यमान क पानी लेने के लिये जापान क बंदरगाह काफी लाभदायक सिद्ध हो सक्ते थ, परन्तु जापान ने विदेशियों क आगमन पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। अत इस प्रतिबन्ध को हटवाने की आवश्यकता थी। इस काम का नेतृत्व समुक्त राज्य अमेरिका ने किया।

1840 ई० म समुक्त राज्य अमेरिका न दो जहाज जापान के साथ राज नीतिक सम्पर्क स्थापित करन के लिये भजे परन्तु इसम उसे सफलता नही मिली। 1853 ई० म अमेरिका न दुवारा चार जहाज कोम्मोडोर परी के नेतृत्व म भजे। जापानियों के विरोध के बावजूद भी परी जापानी समुद्र तट पर पहुच गया। वहा पहुचकर उसने जापान के अधिकारियों का अमेरिका के राष्ट्रपति का पत्र दिया। और उनसे कहा कि वे यह पत्र जापान के सम्राट के पास पहुचा दें। उसने यह भी कहा कि वह एक वष बाद पुन उस पत्र का जवाब लेने के लिये जापान आयेगा।

जापान का आधुनिकीकरण

जापानी अधिकारियों ने पेरी का पत्र शोगुन के पास पहुँचा दिया। अब जापान के विषे पश्चिम वालों को राकना असम्भव लग रहा था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों न चीन के साथ जो जबरदस्ती की थी, उसमें भी वह विहित था।

1854 ई० में पेरी दुबारा 10 जहाजा और 2,000 सैनिकों के साथ जापान पहुँचा। जापानी शोगुन ने पेरी की सेना में भयभीत होकर 1854 ई० में मयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संधि कर ली। इस संधि के अनुसार जापान ने अपने तीन वादरगाह अमेरिका के स्थापना के लिये खोल दिये। इसके अतिरिक्त जापान न अमेरिका द्वारा इन वादरगाहों पर एक प्रतिनिधि रखने की शर्त को भी स्वीकार कर लिया। अब अमेरिकन जहाज जापानी वादरगाहों पर बोझला, पानी और रसद सामग्री ले सकते थे। इस प्रकार अमेरिका ने जापान की एकात्मता की नीति का भंग कर दिया। शूमा न अपनी पुस्तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में इस मत का समर्थन किया है। थोमसन ने लिखा है कि जापान न अमेरिका की सैनिक शक्ति से भयभीत होकर अपनी एकात्मता की नीति का परित्याग कर दिया। इसने अन्ततः जापान के पास अब कोई विकल्प नहीं था।

इसके पश्चात् जापान ने 1854 ई० में रूस के साथ सिमोडा की संधि, 1855 ई० में रूस के साथ शिमाडा की संधि और 1857 ई० में हान्गुट के साथ संधि की। जापान ने सभी विदेशियों के लिये नागासाकी वादरगाह के द्वार खोल दिये। जनता ने इन संधियों का विरोध किया परन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकला। जापान न पृथक्ता की नीति का परित्याग कर सभी विदेशियों के लिये अपना द्वार खोल दिया। फिर भी इन संधियों के कारण जापान अपना आंतरिक विकास करने में सफल हुआ।

सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना—जापानी जनता विदेशियों के विरुद्ध थी। इसलिए उसने उनके विरुद्ध आन्दोलन करना प्रारम्भ कर दिया। इस कारण सम्राट अपनी शक्ति की पुनः प्राप्ति करने में सफल हुआ। पश्चिमी देशों के साथ शागुन ने संधियाँ की थीं। इसलिए जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशियों को जापान में बाहर निकालना, शागुन को पद से हटाना और सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना करना था। इस आन्दोलन से पश्चिमी राष्ट्राँ न संधियों पर सम्राट के हस्तक्षेप करवाना आवश्यक समझा।

शोगुन के विरोधी सामन्तों ने सम्राट को उसके द्वारा की गई संधियों के विरुद्ध भड़काया। जापान में शोगुन के विरुद्ध विशाल पैमाने पर आन्दोलन प्रारम्भ हुआ गया। जापानी जनता 'सम्राट का भ्रष्ट करो, विदेशियों का भगा दो' के नारे लगाते लगीं। शागुन के विरोधियों ने ब्रिटिश तथा अमेरिकन दूतावास में आग लगा दी और अनेक बयेंजों का करल कर दिया। जब शागुन इन भ्रष्टाचारों को राकने में असफल रहा, तब विदेशियों ने समुक्त रूप से कायबाही कर आन्दोलनकारियों के

किलों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इन घटनाओं से शोगुन की प्रतिष्ठा घूल म मिल गई। 1866 ई० में पुराने शोगुन की मृत्यु हो गई।

इसके पश्चात् 'वेइकी' नामक युवक नया शोगुन बना। जिसमें देश भक्ति की भावनाएँ कूट कूटकर भरी हुई थीं। इस समय जापान का नया सम्राट मुत्सुहितो बना। उस समय उसकी आयु 24 वर्ष की थी। मुत्सुहितो कूटनीतिज्ञ और दरदशी शासक था। इतिहासकार हेज और मून ने लिखा है कि मुत्सुहितो उत्साही था एवं जापान का आधुनिकीकरण करना चाहता था। अब वह देश की वास्तविक शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करना चाहता था। इसलिये उसने शोगुन को अधिकारहीन बनाने का प्रयास किया। इस बात से जनता न शासक का समर्थक किया। नये शोगुन ने समय का पहचानते हुए 1867 ई० में पद त्याग दिया। इस प्रकार सदिया के पश्चात् सम्राट वास्तविक शासक बन पाया। अब जापान में शोगुन का प्रभाव समाप्त हो गया। शासन की वास्तविक शक्ति मुत्सुहितो के हाथ में आने के पश्चात् उसने शासन में कई नवीन प्रकार के सुधार किये। राजनीतिज्ञ शूमा ने लिखा है कि जापान ने शोगुन के प्रभाव की समाप्ति के पश्चात् ही आवश्यकजनक विकास किया और विश्व का एक महान् आधुनिक राष्ट्र बन गया।

सम्राट मुत्सुहितो ने अपने शासन का नाम मजी शासन रखा। जिसका अर्थ 'बुद्धिमत्तापूर्ण शासन' होता है। अब शासन की वास्तविक शक्ति सम्राट के हाथ में निहित थी। सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना को मजी पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है।

मेजी युग में जापान का विकास—मुत्सुहितो ने चीन के डा० सनयात सन की भाँति जापान का आधुनिकीकरण किया।

(1) राजनीतिक क्षेत्र में विकास जापान में सम्राट की पुनर्स्थापना एक क्रांतिकारी घटना थी। 1868 ई० में मुत्सुहितो ने अपनी राजधानी क्योटो सहटा कर य दो नगर को बनाइ। अब इस नगर का नाम टोकियो रखा गया। टोकियो ही सारे देश की राजधानी था। अब मुत्सुहितो ने शासन का केंद्रीयकरण करना प्रारम्भ किया। इस कार्य में साम तो प्रथा बाधक बना हुई थी। इसलिये सम्राट ने 1868 ई० में प्रत्येक जागीर में एक केंद्रीय अधिकारी का नियुक्त किया। 1871 ई० में मुत्सुहितो ने एक कानून बनाया। जिसके द्वारा साम तो प्रथा को समाप्त कर दिया गया। साम तो की भूमि के बदले उनको मुआवजा दे दिया गया और उस भूमि का किमानो में बांट दिया गया।

मुत्सुहितो ने पश्चात्य ढंग से जापान की सना का पुनर्गठन किया। उसने 1872 ई० में जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। परिणामस्वरूप सभी वर्गों के लोग सेना में भर्ती होने लग। इससे सेना में साम तो का प्रभाव समाप्त हो गया। यामागाता ने फ्रेंच और जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से जापानी सना का

पुनर्गठन किया। जापान ने इंग्लैंड का अनुसरण करते हुए अरबी जन सेना का विकास किया। इसके लिये ब्रिटिश विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की गई। मेना के सर्वोच्च अधिकारी सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। इसलिये अगले चतुर्दश वर्षों में जापान ने उग्र मजिबुतवादी का उदय हुआ।

शासन में जनता की प्रतिनिधित्व देने के लिये मुत्सुहितो ने 1874 ई० में सीनेट तथा केन्द्रीय न्यायालय की स्थापना की। 1878 ई० में उसने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। प्रांतीय शासन उनसे सलाह लेकर शासन करते थे। 1882 ई० में मुत्सुहितो ने कुछ राजनीतिज्ञों को पार्लियामेंट दलों में सविधानों का अध्ययन करने के लिये भेजा। काफी प्रयासों के बाद एक नया सविधान बनाया गया। जिसे 1889 ई० में लागू किया गया। इस नये सविधान में दिसदनात्मक मसद और जनता को मौलिक अधिकार दिये गये। इस प्रकार जापान का आधुनिकीकरण पूरा हुआ।

(ii) आर्थिक विकास—मुत्सुहितो ने जापान के औद्योगिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर कारखाने स्थापित किये। सरकार ने मशीनों का बाहर से आयात किया। उस समय लोह और बरत उद्योग के कारखाने भी स्थापित किये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि जापान में लोहा और कपड़े का विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा। कारखानों में नये-नये आविष्कारों और वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग किया गया। परिणामस्वरूप 1890 ई० तक जापान में 250 कारखानों का उत्पादन की सहायता में चलने लगे। इन कारखानों में कागज सीमेंट बरत, रेशम, लोहा और बरत आदि का उत्पादन विशाल पैमाने पर होने लगा। गांवों से किसान गेहूँ की खेती में औद्योगिक शहरों में आने लगे। जिनमें मजदूरों की समस्या नहीं रही। जापान में मजदूरों की दर सस्ती थी। अतः माल कम खर्च में तैयार हो जाता था।

जापान ने व्यापार के क्षेत्र में भी काफी उत्थिति की। 1873 ई० में बहा राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। 1879 ई० तक जापान में 151 बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। 1885 ई० में 'जापान बैंक' की स्थापना की गई, जिसे केन्द्रीय बैंक कहा जाता था। बचत बैंक को ही नोट छापने का अधिकार दिया गया। जिसमें मुद्रा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया।

जापान ने व्यावसायिक उत्थिति के लिये परिवहन तथा संचार साधनों का विकास किया। 1873 ई० में जापान में टोकियो से याकोहामा तक पहला रेल मार्ग बनाया गया। 1894 ई० तक जापान 2112 मील रेल मार्ग का निर्माण कर चुका था। जनता ने निष्ठा है कि 'पन्नी रेल्वे लाइन 1872 ई० में टोकियो से याकोहामा के बीच बनी और 1894 ई० तक जापान में रेलों का जाल बिछ गया और दो

हजार ए० सी अठारह मी० लम्बी रेन लाईन बन गई ।¹

1868 ई० में टेलीग्राफ खोला गया । फिर सारे देश में डाक घर स्थापित किये गये । 1877 ई० में जापान में टेलीफोन का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । इस समय तक जापान के बड़े बड़े बाष्प चलित जहाजों का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया था । इस प्रकार जापान ने पश्चात्य देशों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया । यनेगा ने लिखा है कि 'इन सुधारों से जापान का कायाकल्प हो गया ।' जापान ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक विकास कर लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसको अपने अतिरिक्त उत्पादन को खपाने के लिये और कच्चा माल प्राप्त करने के लिये बाजारों की तलाश करनी पड़ी ।

(111) सांस्कृतिक विकास—शोगुना ने अपने शासनकाल में जापानियों के विदेश जाने पर प्रतिबन्ध लगा रखा था । फिर भी डचों के सम्पर्क से जापानी लोग पश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के सम्पर्क में आये । शोगुनों के पतन के पश्चात् मुत्सुहिता ने विदेश यात्रा पर से प्रतिबन्ध हटा दिया । अब जापानी विदेशों में अध्ययन करने के लिये जाने लगे ।

मुत्सुहितो ने जापान में पश्चात्य ढंग पर आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू की । जापान में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी । इस शिक्षा के लिए अमेरिकन पद्धति का अनुसरण किया गया । जापान में अनेक नये स्कूल खोले गये । पाठ्यक्रम में देश भक्ति तथा सम्राट प्रति निष्ठा की भावना पर अधिक बल दिया जाता था । लड़कियों के पाठ्यक्रम में गृह कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता था । जापान की उच्च शिक्षा फ्रेंच पद्धति और विश्वविद्यालयी शिक्षा जर्मन पद्धति पर आधारित थी । 1877 ई० में टोकियो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । इस समय पश्चिमी देशों के ग्रन्थों का बड़ी मर्यादा में जापानी भाषा में अनुवाद किया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि जापान में एक नये बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किसी देश से पीछे नहीं था ।

मुत्सुहितो का योगदान—जापान के आधुनिकीकरण में मुत्सुहितो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया । जब वह जापान का सम्राट बना तब जापान सत्रमण काल से गुजर रहा था । पश्चिमी देशों के लोगों के जागमन के विरुद्ध सारे देश में आंदोलन चल रहा था । शागुन की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल चुकी थी । ऐसे समय में यदि वह जापान को सही दिशा नहीं देता तो उसका विनाश अवश्यम्भावी था ।

मुत्सुहितो यह जानता था कि पश्चिमी देशों से युद्ध करने का अर्थ था जापान के विनाश का जामन्त्रित करना । इसलिए उसने जापान का नय सिर से निर्माण करने

1—यनेगा—जापान सि० स० पैरी—पृष्ठ 98

2—यनेगा—जापान सि० स० पैरी—पृष्ठ 93

जापान का आधुनिकीकरण

का प्रयास किया। वह जापान को शक्ति सम्पन्न तथा समृद्ध देश बनाना चाहता था, ताकि जापान पश्चिमी राष्ट्रा का मुकाबला करने के योग्य बन सके। इसलिए उसने जापान में सामन्ती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने जापान में एक नया संविधान लागू किया, जिसमें जनता को मौलिक अधिकार दिये गये। जापान की राजधानी टोक्यो बनाई। उसने जापान का बहुत अधिक औद्योगिक विकास किया। जापानी लोगो को गान विज्ञान अर्जन करने के लिये विदेशों में भेजा जाने लगा। वहाँ पाश्चात्य ढंग पर आधारित शिक्षा प्रणाली लागू की गई। प्रारम्भिक शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य कर दी गई। जापान की सैनिक शक्ति को मजबूत बनाया गया। इस प्रकार मुक्तोद्दिता के कारणों के कारण जापान का आधुनिकीकरण हो गया।

जापान की साम्राज्यवादी नीति—जब जापान का आधुनिकीकरण हो गया तो उसने साम्राज्यवादी नीति का पालन करना प्रारम्भ कर लिया। दश नीति का पालन करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

- 1 जापान के आधुनिकीकरण के कारण उसकी सैनिक शक्ति सबन बन चुकी थी। वहाँ के सनापति अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए युद्ध की नीति पर चलना चाहते थे।
- 2 जापान की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए जगह की आवश्यकता थी।
- 3 जापान अपनी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर पा रहा था। खाद्यान्न अविश्वसित एवं पिछड़े हुए देशों से प्राप्त हो सकता था।
- 4 जापान को अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए एक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए बाजारों की आवश्यकता थी। बाजारों की स्थापना के लिये साम्राज्यवादी नीति का पालन करना अनिवार्य था।
- 5 जापान के आधुनिकीकरण के कारण उसकी विदेश नीति में परिवर्तन होना आवश्यक भावी था। वह पश्चिमी देशों के साथ कड़ी गई अपमानजनक संधियों में संशोधन चाहता था, क्योंकि इन संधियों के अनुसार उसे विदेशी नागरिकों के अभियोगों को सुनने का अधिकार नहीं था। इनके अनिश्चित वह व्यापार पर शुल्क निश्चित नहीं कर सकता था।

जापान ने 1858 ई० में कड़ी संधियों में संशोधन करने के लिये 1873 ई० में एक मिशन पश्चिमी देशों में भेजा। परन्तु उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। 1888 ई० में जापान ने दश सम्बन्ध में दुबारा प्रयास किया, परन्तु इस बार भी उसे असफलता का मुंह देवना पड़ा। अब जापान यह समझ गया कि शक्ति प्रदर्शन के द्वारा ही इन पुरानी संधियों को समाप्त किया जा सकता है। इसलिये अब वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा।

इन उपरोक्त कारणों से जापान ने 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में साम्राज्यवादी नीति पर चलने का निश्चय किया।

1 चीन जापान युद्ध (1849-95 ई०)—जब चीन पर पश्चिमी देश अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे तो जापान ने भी चीन में अपना साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। यनेगा ने लिखा है कि 'नजर के सामने कमजोर और असहाय चीन की समृद्ध दशा ने उन्हें (जापान) असहनीय प्रलोभन प्रदान किया।'¹

जापान ने साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुये 1894 ई० में फारमोसा और 1879 ई० में लू चू द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् उसने कोरिया पर अधिकार करने का प्रयास किया, ताकि उसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता रहे। कोरिया एक राजतंत्र था। उस पर अप्रत्यक्ष रूप से चीन का प्रभाव स्थापित था। जब जापान ने 1894 ई० में कोरिया पर अधिकार करने का प्रयास किया तो चीन जापान युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्ध में जापान की नयी शिक्षित व अनुशासित सेना ने चीन को बुरी तरह से पराजित किया और उसको एक अल्पमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया।

शिमोनोसकी की संधि (1895 ई०)—चीन और जापान के बीच 17 अप्रैल 1895 ई० को शिमोनोसकी की संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी—

- 1 चीन ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक अरब 75 करोड़ डालर जापान को देना स्वीकार कर लिया। क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने तक चीन के 'वे हाई वे' बन्दरगाह पर जापान का अधिकार रहेगा।
- 2 चीन ने कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कोरिया पर से चीनी प्रभाव समाप्त हो गया।
- 3 चीन ने लियाओतुंग प्रायद्वीप, फारमोसा तथा पेस्केडोस द्वीप पर जापान को अधिकार दे दिया।
- 4 चीन ने अपने चार बन्दरगाह जापान के व्यापार के लिए खोल दिये।

इस युद्ध में विजय से जापान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और कोरिया में उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस विजय के विषय में थोमसन ने लिखा है कि जापान की इस प्रथम विजय से जापानी बहुत प्रसन्न हुए। पाल० एच० क्लाइड ने लिखा है कि "जापान की सैनिक और नाविक विजय ने सुदूरपूर्व में एक नये युग का प्रारम्भ अंकित किया जिसका प्रभाव एशिया और यूरोप पर समान पड़ा।"²

1 यनेगा—जापान सिस परी—पृष्ठ 94

2 1 क्लाइड,—पाल० एच०—दी फार ईस्ट, पृष्ठ 302

इस युग में जापान की विजय में उसकी गणना विश्व की महान शक्तियाँ में होने लगी। उसका आंतरिक विकास हुआ। कोरिया पर जापान का अधिकार हो जाने से उसे कच्चा माल आसानी से सस्ती दरा पर प्राप्त होने लगा। इससे उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होने से उसके व्यापार में भी वृद्धि हुई।

चीन में जापान की विजय से रूस चिंतित हो उठा क्योंकि मंचूरिया में जापानी प्रभाव रूस के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था। इसलिए रूस ने फ्रांस और जर्मनी को इसमें हस्तक्षेप करने की अपील की। इस पर फ्रांस, जर्मनी और रूस ने जापान पर नियाओतुंग और पोटआवर बंदरगाह चीन का लौटाने के लिए दबाव डाला। जापान को बाध्य होकर यह प्रदेश चीन को लौटाने पड़े क्योंकि जापान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं था कि मित्र राष्ट्रों की मांग को टुंटा सके। जापान की इस विजय से प्रभावित होकर अमेरिका और इंग्लैंड ने पुर्गनी संधियाँ में मशाघन कर दिया। इस प्रकार जापान को उन अपमानजनक संधियों में मुक्ति मिली।

इंग्लैंड के साथ संधि (1902 ई०)—जापान ने चीन का युद्ध में पराजित कर लियाओतुंग का प्रदेश प्राप्त किया था परंतु महान शक्तियों के विरोध के कारण उसे यह प्रदेश पुनः चीन को लौटाना पड़ा था। जापान इस कूटनीतिक पराजय का बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसे एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता अनुभव हुई। उधर इंग्लैंड यूरोप में अकेला पड़ गया था। एक तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली का त्रिगुट बन चुका था और दूसरी तरफ फ्रांस एवं रूस में संधि हो चुकी थी। इंग्लैंड का इन दोनों ही गुटों से विरोध चल रहा था। इसलिये उसे अपने उपनिवेशों की रक्षा करने के लिए सुदूरपूर्व में मित्र की आवश्यकता अनुभव हुई। इंग्लैंड जापान की चीन विजय में बहुत प्रभावित था। उसका यह मानना था कि एशिया में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को जापान रोक सकता है। परिणामस्वरूप 1902 ई० में जापान और इंग्लैंड के बीच संधि हो गई जिसे आंग्ल-जापानी संधि कहा जाता है। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं—

1. दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे एक दूसरे के व्यापारिक हितों की रक्षा करेंगे।
2. दोनों ने चीन की शक्ति और सुरक्षा की रक्षा करने का आश्वासन दिया।
3. इंग्लैंड ने कोरिया में जापान के विशेषाधिकारों को स्वीकार कर लिया।
4. इंग्लैंड ने मंचूरिया में जापानी प्रभाव को स्वीकार कर लिया।

5 यदि दो या दो से अधिक शक्तियाँ चीन पर आक्रमण करेंगी तो दोनों मयुक्त रूप से उनका मुकाबला करेंगे।

यह संधि पाच वष के लिए की गई थी। इंग्लैण्ड जैसे विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र की जापान जस छोटे स राष्ट्र के साथ संधि को दखकर विश्व के तत्कालीन राजनीतिज्ञ आश्चर्य करन लग। इस संधि स जापान की प्रतिष्ठा म वृद्धि हुई। वह पाश्चात्य देशा की बराबरी का दम भरने लगा। इस संधि से रूस के विरुद्ध इंग्लैण्ड न जापान का समर्थन प्राप्त कर लिया था। इससे रूस सुदूरपूव म अकेला पड़ गया।

रूस के साथ युद्ध (1904-5)—19वीं शताब्दी म रूस एशिया का सब शक्तिशाली और विश्व का एक महान् राष्ट्र माना जाता था, परंतु 1905 ई० म जापान जसे छोटे से राष्ट्र ने उसे युद्ध म बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

- 1 जापान ने चीन को युद्ध म पराजित कर लियाओतु ग और पोर्ट आथर के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था परंतु रूस के प्रयासों से उसे ये प्रदेश चीन को पुन लौटाने पड़े। इसलिये जापान अपनी इस कूटनीतिक पराजय का रूस से बदला लेना चाहता था।
- 2 1902 ई० म जापान की ब्रिटेन के साथ संधि हो जाने के कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र म प्रतिष्ठा बढ़ी। अब वहाँ का सम्राट साम्राज्यवादी नीति पर चलना चाहता था।
- 3 रूस और जापान दोनों ही कोरिया और मंचूरिया पर अधिकार करना चाहते थे। जब रूस के विरोध के कारण जापान ने शिमोनो सबी संधि से प्राप्त प्रदेश पुन चीन को लौटा दिये तो रूस ने इन प्रदेशों में अपना प्रभाव बढाना शुरू किया। रूस ने 1898 ई० में पोर्ट आथर बंदरगाह पर और 1903 ई० म मंचूरिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। इसके पश्चात् उसने कोरिया में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया।

रूस जापान युद्ध—मंचूरिया तथा कोरिया म रूस का प्रसार जापान की सुरक्षा तथा प्रगति म बाधक था। जापान ने रूस के कोरिया और मंचूरिया म बढ़ते हुए प्रभाव का कडा विरोध किया। उसन रूस से मंचूरिया व कोरिया की सीमा से सेना हटाने के लिए कहा परंतु रूस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 1904 ई० म जापान न रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने पोर्ट आर्थर म स्थित रूसी बड़े का नष्ट कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् उसने कारिया म अपनी सेनायें भेज दी। इस युद्ध न फ्रांस और जर्मनी की सहानुभूति रूस के साथ थी। इंग्लैण्ड तथा अमेरिका न जा। र का आर्थिक सहायता प्रदान की।

यह युद्ध फरवरी 1904 ई० से सितम्बर 1905 ई० तक चलता रहा। इस युद्ध में जापान जैसे छोटे से राष्ट्र न रूस जैसे विशाल राष्ट्र को बुरी तरह सपराजित किया और उसने रूस को पोर्ट्स माउथ की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया।

पोर्ट्स माउथ की संधि (1905 ई०)—यह संधि 1905 ई० में जापान और रूस के बीच हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं।

- 1 रूस ने कारिया में जापानी प्रभाव को स्वीकार कर लिया।
- 2 जापान का लियाओतुंग व पोर्ट आयर बंदरगाह पर पुन अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त मन्चूरिया के रेबे का दक्षिणी हिस्सा एवं दक्षिणी सांगवालिन प्रदेश प्राप्त हुआ।
- 3 मन्चूरिया पर चीन का अधिकार मान लिया। जापान तथा रूस ने वहा से अपनी सेनाएँ हटाना स्वीकार कर लिया।
- 4 रूस ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जापान को 2 करोड़ 80 लाख पौण्ड देना स्वीकार कर लिया।

इसी जापानी युद्ध का महत्व—

1 इस युद्ध में जापान ने रूस जैसे विशाल राष्ट्र को पराजित किया था। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा बड़ी और वह एशिया का सब शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। अब जापान की गिनती विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में होने लगी। इस युद्ध के पश्चात् जापान ने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। 1910 ई० में उसने कोरिया पर अधिकार कर लिया। पश्चिमी राष्ट्र जापान की सैनिक शक्ति का लोहा मानने लगे क्योंकि रूस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित कराना कोई साधारण बात नहीं थी। अतः जापान में उग्र मन्दिवाद का उदय हुआ। जिससे जापान का विनाश अवश्यम्भावी हो गया। गुमान लिया है कि रूस को पराजित करने के पश्चात् जापान की गिनती विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में होने लगी। अब जापान के साम्राज्य विस्तार का भाग प्रशस्त हो गया।

2 यह युद्ध रूस के लिए घातक सिद्ध हुआ। रूस की पराजय होने से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई। इस पराजय के कारण रूस में सरकार विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इस युद्ध में बिना कारण रूस के डेढ़ लाख सैनिक मारे गए। रूस की जनता में पहल से जार के निरंकुश शासन के विरुद्ध असंतोष था। इस पराजय के कारण यह असंतोष और अधिक तीव्र हो गया। जनता ने युद्ध में रूस की पराजय के नियम सभ्राट को उत्तरदायी माना। जनवरी 1905 ई० में रूस में क्रान्ति हुई। यद्यपि जार ने क्रान्ति को बुचकन किया फिर भी उसने रूस के अन्तर्लेपन को दूर करने के लिये इंग्लैण्ड और फ्रांस के साथ संधि की।

3. अमेरिका चीन की सुरक्षा के लिये किसी भी देश को विशेषाधिकार देने के पक्ष में नहीं था परन्तु अमेरिका की मध्यस्थता से रूस और जापान के बीच पोट्सडाम संधि की संधि हुई थी, जिसके द्वारा अमेरिका ने जापान को चीन में विशेष अधिकार प्रदान कर दिये।

प्रथम विश्व युद्ध और जापान—1914 ई० में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। 1902 ई० की आंग्ल जापानी संधि के कारण जापान ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया। युद्धकाल में उसने प्रशान्त महासागर में जर्मनी की पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त चीन में जर्मनी अधिकृत शान्तुग प्रदेश पर अधिकार कर लिया।

युद्ध के दौरान जापान का वाणिज्य व्यापार तथा उद्योग धन्धों का जबरदस्त विकास हुआ। इस दौरान इंग्लैण्ड फ्रांस, जर्मनी तथा इटली एशिया में अपना माल नहीं पहुँचा सके। जापान ने इस अवसर का लाभ उठाकर एशिया के देशों में अपना माल पहुँचाया। युद्धकाल में जापान सारे एशिया का कारखाना बन गया इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने जापान की प्रगति का द्वार खोल दिया।

इक्कीस मांगे—जापान चीन को अपना आर्थिक उपनिवेश बनाना चाहता था। इसलिये उसने युद्ध के दौरान 18 जनवरी 1915 ई० को चीन के सामने 21 मांगे रखी और उसको स्वीकार करने के लिये विवश किया। उसकी ये इक्कीस मांगे पाँच भागों में विभाजित थी।

1. पहले खण्ड में जापान ने शान्तुग प्रदेश के बारे में चार शर्तें रखीं। इसके अनुसार शान्तुग प्रान्त पर जापान का अधिकार रहेगा। जापान को इस प्रदेश में राजनैतिक, व्यापार और रेल निर्माण करने के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा उसमें किसी भी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप वर्दाशत नहीं किया जायेगा।

2. दूसरे भाग में पोट्सडाम, मुकदमे तथा दक्षिणी मचूरिया के प्रदेश पर जापान को 99 के वर्ष के लिए पट्टा दिया जायेगा। जापान को मंगोलिया में भी व्यापारिक और रेल आदि बनाने के विशेषाधिकार होंगे।

3. तीसरे भाग में चीन में बड़े नगरों में जापान के लोहे के कारखाने स्थापित करने की इजाजत दी जायेगी। इसके अतिरिक्त चीन अन्य किसी देश को अपने यहां खानें खोदने का अधिकार नहीं देगा।

4. चौथे खण्ड में जापान ने वचन दिया कि वह चीन की सुरक्षा करेगा परन्तु चीन बिना जापान की स्वीकृति के अपना कोई भी बन्दरगाह या द्वीप किसी विदेशी को नहीं देगा।

5. पाचवें भाग में जापान ने सात शर्तें रखी थीं। इसके अनुसार जापान चीन में अपने सत्ताहकार रखेगा। वह चीन में जापानी स्कूल, चर्च, अस्पताल बनायेगा। चीन के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा जापान और चीन की पुलिस संयुक्त रूप से करेगी। जापान ने चीन से कहा कि वह विदेशी पूंजी का प्रयोग करने से

जापान का आधुनिकीकरण

ने उससे स्वीकृति लेगा। इसके अतिरिक्त चीन अपने युद्ध की 50 प्रतिशत सामग्री जापान से ही खरीदेगा।

ये 21 मांगे पांच भागों में जापान ने चीन के समक्ष रखी। चीन ने बाध्य होकर 25 मई 1915 ई० को इन अपमानजनक मांगों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जापान ने चीन पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया।

वेरिस शांति सम्मेलन और जापान—प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् विजित राष्ट्रों की पराजित राष्ट्रों के साथ संधियां करने के लिए वेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ। जापान ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में जापान की विश्व की पांच प्रमुख शक्तियों में स्थान मिला। जिससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। सम्मेलन में जापान की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

1. चीन में जापान की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाय।
 2. जर्मन उपनिवेशों पर उसके अधिकार को मान्यता दिलवाना।
- अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के विरोध के बावजूद भी चीन जर्मनी अधिकृत शान्त्युग प्रदेश जापान के अधिकार में दे दिया गया। चीन ने इसका विरोध किया, परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रशान्त महासागर में स्थित जर्मनी के कुछ उपनिवेश जापान को दे दिये गये। परन्तु जापान की अन्य मांगे स्वीकार नहीं की गईं। युद्ध के दौरान उसने चीन के जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, वहाँ से उसे अपनी सेनाएँ हटाने को कहा गया।

जापान को शांति सम्मेलन में आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई। वह वेरिस शांति सम्मेलन में विजे गये निर्णयों से असन्तुष्ट था। इटली की भाँति जापान ने यह माँवना पर करने लगी कि उसने युद्ध में जो कुछ जीता था, उसे संधि में खो दिया।

वाशिंगटन सम्मेलन (1922 ई०)—जापान निरन्तर प्रगति कर रहा था और चीन में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। चीन में जापान के विस्तार को रोकने के लिये और उसकी बढ़ती हुई शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये 12 नवम्बर, 1921 ई० को अमेरिका ने वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, हालैण्ड, चीन, जापान, और अमेरिका आदि नौ राष्ट्रों ने भाग लिया। इसमें प्रशान्त महासागर में नौसैनिक शक्ति कम करने तथा पूर्वी एशिया की स्थिति पर विचार किया गया।

वाशिंगटन सम्मेलन में प्रशान्त महासागर में सभी देशों के जहाजों की संख्या एवं उन पर नैविक और तोपों की संख्या भी निश्चित कर दी गई। इसमें तीन प्रकार की संधियाँ भी हुईं। समुद्री निरास्त्रीकरण की प्रमुख संधि—यह संयुक्त राज्य

अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली आदि पांच राष्ट्रों के बीच में हुई थी। इस संधि के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के जहाजों का अनुपात 5:5:3 निश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त इटली और फ्रांस के जहाजों का अनुपात 1.75 निश्चित किया गया। इसका तात्पर्य यह था कि यदि प्रशांत महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन पांच-पांच जहाज रख सकते थे तो जापान केवल तीन और इटली तथा फ्रांस केवल 1.75, 1.75 जहाज रख सकते थे। जापान इस सम्मेलन में विश्व की तीसरी नाविक शक्ति बन गया।

इस सम्मेलन में 1902 ई० की आंग्ल-जापानी संधि को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि इन चार राष्ट्रों में संधि हुई। इसे चार राष्ट्रों की संधि कहा जाता है। इस सम्मेलन में सभी नौ राष्ट्रों ने चीन की अखण्डता को बनाये रखने और उसकी सुरक्षा करने का आश्वासन दिया। सभी देशों को चीन में एक समान व्यापारिक अधिकार दिये गये। जापान ने चीन से चार करोड़ स्वर्ण मान लेकर उसका शान्तुग का प्रदेश लौटा दिया। क्लाइड ने लिखा है कि "1921-22 का वाशिंगटन सम्मेलन कई तरह से जापान के लिये एक दुःखदायी कूटनीतिक दस्तावेज था।"¹

वाशिंगटन सम्मेलन का महत्व :—

1. यद्यपि यह सम्मेलन राष्ट्रों का पूर्ण रूप से निःशस्त्रीकरण नहीं कर सका परन्तु इस बात को मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस सम्मेलन के कारण सुदूरपूर्व में 17 वर्षों तक शांति स्थापित रही।
2. इस सम्मेलन से जापान की ब्रिटेन से मित्रता समाप्त हो गई। इतिहासकार यनेगा ने लिखा है कि "जापान का तेईस वर्षों का किया हुआ काम समाप्त करने की विकल चेष्टा की गई। इस सम्मेलन से एक लाभ हुआ कि ब्रिटेन व जापान की दोस्ती टूट गई।"²
3. यह सम्मेलन जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिये तथा उसकी सैनिक शक्ति पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिये बुलाया गया था, परन्तु जापान ने इसके निर्णयों का पालन करने से इन्कार कर दिया। अब जापान साम्राज्यवादी नीति पर चलने लगा। इस कारण पश्चिमी राष्ट्रों से उसका मनमुटाव हो गया।

(4) इस सम्मेलन के बाद चीन की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब चीन सरकार स्वतन्त्रता का दावा करने लगी। इतिहासकार विनाके ने लिखा है कि "जिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वाशिंगटन सम्मेलन में समझौते

1—क्लाइड, पाल० एच०—दी फार ईस्ट—पृष्ठ 352

2—यनेगा—जापान सिन्स पैरी पृष्ठ 94

हए थे। उनसे सुदूरपूर्व की राजनीति में एक नये तत्व का उदय अवश्य हुआ। यह तत्व या चीनी सरकार द्वारा स्वतन्त्रता का दावा। सीमित रूप से इससे चीन की परराष्ट्र नीति को एक नई दिशा मिली।”

जापान द्वारा मंचूरिया पर अधिकार (1931 ई०) 1928 ई० में जापान में राजनैतिक शक्ति सैनिक वर्ग के हाथ में आ गई। इस नई सरकार ने पुनः साम्राज्यवादी नीति पर चलने का निश्चय किया। जापान के मंचूरिया पर आक्रमण करने के कई कारण थे, जिनका विस्तृत अध्ययन हम विछने अध्याय में कर चुके हैं। जापान ने मंचूरिया की खनिज सम्पदा से आकर्षित होकर और अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को वहाँ बसाने के लिए उस पर अधिकार करने का निश्चय किया। लैंगमन ने लिखा है कि “इस प्रकार मंचूरिया ने अपने अत्यधिक साधनों, अविकसित क्षेत्रों, भौगोलिक निकटता और महत्वपूर्ण स्थिति के कारण जापान को प्रलोभित किया।”¹

18 सितम्बर 1931 ई० की रात्रि में कुछ लोगों ने मुकडेन में बम में से जापानी रेलवे लाइन को उड़ा दिया। अतः इसको बहाना बनाकर जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। गेयोर्न और हार्डी ने लिखा है कि “18 सितम्बर 1931 ई० की रात को मुकडेन के निवासियों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद गोलियाँ चलाये जाने की आवाज आई और सवेरे देखा गया कि नगर जापानियों के बड़े में है।”²

चीन ने राष्ट्र संघ से इस सम्बन्ध में शिकायत की, परन्तु जापान मंचूरिया में निरन्तर आगे बढ़ता रहा। 1932 ई० के अन्त तक उसने सम्पूर्ण मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकार स्थापित कर दी। राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लिटन कमीशन ने जांच के दौरान जापान को दोषी पाया। इस पर राष्ट्र संघ ने जापान से अनुरोध किया कि वह मंचूरिया से अपनी सेना हटा ले। जापान ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और 24 फरवरी 1933 ई० को उसने राष्ट्र संघ से त्यागपत्र दे दिया। कारने लिखा है कि “जापान ने मार्च 1933 ई० में राष्ट्रसंघ को सदस्यता त्याग दी। जिससे सुदूरपूर्व में एक उनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। जापान ने शीघ्र ही मंचूरिया को जीतकर पूर्वी एशिया में अपनी स्थिति और अधिपत्य को सुदृढ़ कर लिया।”³

जब राष्ट्र संघ जापान के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सका तो इससे

1—लैंगमन—दो बल्डें सिन्स 1919, पृष्ठ 426

2—गेयोर्न और हार्डी—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ 266

3—कार, ई० एच०—इन्टरनेशनल रिलेशन्स बिट्विन दी टू बल्डें वास, पृष्ठ 242

जापान की साम्राज्यवादी तृष्णा और अधिक बढ़ी और उसने चीन के एक अन्य प्रान्त जेहोल पर भी अधिकार कर लिया। अब जापान ने यह नारा लगाया कि "एशिया एशियावासियों के लिए है।" लेटारिटू ने लिखा है कि "सही मायने में इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध का आरम्भ सितम्बर 1931 ई० की उस आधी रात को हो गया था, जब भोला फूटा था। वही विश्व युद्ध के आरम्भ की सूचना थी।"¹ इस प्रकार मंचूरिया कांड ने ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। कार ने लिखा है कि "जापानियों द्वारा मंचूरिया विजय प्रथम विश्व युद्ध के बाद इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है।"²

जापान की घोषणा (1934 ई०)—अप्रैल 1934 ई० में जापान की विदेश नीति में एक नया परिवर्तन हुआ। इस समय जापान ने यह घोषणा की कि "एशिया एशियावासियों के लिये है"। इसे एशिया के लिये नई व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके द्वारा जापान ने पश्चिमी राष्ट्रों को चीन से हटने की चेतावनी दी। इस घोषणा का अर्थ यह था कि यदि किसी भी पश्चिमी राष्ट्र ने एशिया के किसी भी मामले में हस्तक्षेप किया तो जापान उसे सहन नहीं करेगा। जापान की यह घोषणा अमेरिका के मुनरो सिद्धान्त के अनुकूल थी। इस प्रकार जापान समस्त पूर्वी एशिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था।

साम्यवाद विरोधी समझौता (1936 ई०)—1936 ई० में जापान की विदेश नीति में एक और नया मोड़ आया। इस सम्बन्ध में शूमा ने लिखा है कि "जब यह बात स्पष्ट हो गई कि साम्यवाद का विरोध, देश-भक्ति उभाड़ने तथा पश्चिमी प्रजातन्त्रों को भ्रमित करने के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकता है तो जापान के नीति निर्माताओं ने 25 नवम्बर 1936 ई० को एन्टी कमिन्टर्न पेक्ट पर हस्ताक्षर करने में नाजीदल का साथ दिया।"

जापान का साम्यवाद विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर करना वस्तुतः एक नया बदम था। इससे इटली और जर्मनी जापान के मित्र बन गये। इसके अतिरिक्त साम्यवाद विरोधी कार्यों में उसे इंग्लैण्ड, फ्रांस व अमेरिका का भी मौन समर्थन प्राप्त हो गया।

द्वितीय विश्व युद्ध और जापान—1937 ई० में जापान ने पुनः चीन पर आक्रमण कर दिया। चीन और जापान के बीच युद्ध चल रहा था कि द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया। द्वितीय विश्व-युद्ध में जापान ने जर्मनी और इटली का साथ

1—लेटारिटू—ए शोर्ट हिस्ट्री ऑफ दी फार ईस्ट पृष्ठ 576

2—कार, ई० एच०—इन्टरनेशनल रिलेशन्स विट्विन दी टू बल्डें वासं, पृष्ठ 171

जापान का आधुनिकीकरण

दिया और उनके पक्ष में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने शीघ्र ही फिलीपाइन द्वीप समूह, हिन्द चीन, मलाया, श्याम, हिन्देशिया, बर्मा आदि देशों पर अधिकार कर लिया। उसने दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात् भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1944 ई० तक जापान को युद्ध में शानदार सफलताएँ मिली परन्तु इसके पश्चात् जापान के पैर उखड़ने लगे।

1945 ई० में जापान के साथी देश जर्मनी तथा इटली ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया, परन्तु जापान ने युद्ध जारी रखा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर 6 अगस्त को एब नागासाकी नगर पर 9 अगस्त 1945 ई० को अणुबम गिराये। जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गये। इससे भय-भीत होकर ब 14 अगस्त 1945 ई० को जापान ने आत्म-समर्पण कर दिया। इस प्रकार जापानी साम्राज्य का पतन हो गया। जापान पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। 26 अप्रैल 1952 ई० को जापान को स्वतन्त्र देश घोषित कर दिया और वहाँ पर प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था स्थापित कर दी गई। सिर्फ 28 वर्षों में जापान ने इतना अधिक विकास कर लिया कि आज विश्व के प्रगतिशील और औद्योगिक देशों में उसकी गिनती की जाती है। हमें उसकी कार्य क्षमता से सबक लेना चाहिये।

प्रस्तावित सन्दर्भ पाठ्य पुस्तकें :—

- 1—ब्लाइट, पाल० एच०—दी फार ईस्ट
- 2—यनेगा—जापान सिन्स पैरी
- 3—विनाके, हैराल्ड एम०—पूर्व एशिया का आधुनिक इतिहास
- 4—प्रो० गोबिन्स—मैकिंग ऑफ मोडर्न जापान
- 5—कार, ई० एच०—इन्टरनेशनल रिलेशन्स विट्विन दी वर्ल्ड वास
- 6—लैंगसम—दी वर्ल्ड सिन्स 1919
- 7—गेयोर्न और हार्डी—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संक्षिप्त इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध

अधिनायकवाद का उदय अधिनायकवाद के उदय के बीज शान्ति समझौतों में निहित है। प्रोफेसर कार ने लिखा है कि 1919 ई० से लेकर 1939 ई० तक जितनी भी घटनाएँ घटित हुई हैं, उन सब पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्साय की संधि का प्रभाव पड़ा है। जापान और इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था, परन्तु पेरिस शान्ति सम्मेलन में उनकी सभी मांगें स्वीकार नहीं की गईं, इसलिये ये दोनों देश शान्ति संधियों से असंतुष्ट थे। सोवियत रूस को शान्ति समझौते में आमन्त्रित नहीं किया, इसलिये वह असंतुष्ट था।

पेरिस शान्ति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। जर्मनी ने विल्सन के 14 सिद्धान्तों पर हथियार डाल दिये थे, परन्तु पेरिस शान्ति सम्मेलन में जर्मनी के साथ की गई संधि में विल्सन के सिद्धान्तों का पूर्णरूप से पालन नहीं किया गया। उसके कई प्रदेश मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए। उसके प्रतिनिधियों को अपमानित कर दिया और उनको संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया गया। उसकी आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया तथा उस पर भारी जुर्माना लाद दिया गया। उसे राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित रखा गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में पेरिस शान्ति सम्मेलन में की गई संधियों के प्रति भयंकर असंतोष व्याप्त था। जर्मनी के नेता इन संधियों की शर्तों का उल्लंघन करना चाहते थे।

1919 ई० के शान्ति समझौते में यूरोप की आर्थिक दशा को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 1923 ई० तक जर्मनी की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। इसका प्रभाव यूरोपियन देशों पर भी पड़ा। 1919 ई० में नव-निर्मित दाल्कन राज्यों की आर्थिक दशा को सुधारने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 1931 ई० में सारे यूरोप में एक महान् आर्थिक संकट छा गया। इससे इटली और जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय हो गई। इस

द्वितीय विश्व युद्ध

कारण अधिनायकों का उत्कर्ष संभव हो सका। जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्टवाद की स्थापना हुई। इन तानाशाहों का उद्देश्य युद्ध के माध्यम से अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार करना था।

जापान ने औद्योगिक विकास के लिये साम्राज्यवादी नीति का पालन करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप वहाँ पर उग्र सैनिकवाद का उदय हुआ। पश्चिमी राष्ट्रों ने रूस की साम्यवादी शान्ति की बुचलने का प्रयाग किया था। इसलिये स्टालिन ने अपने देश में साम्यवादी अधिनायक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फासिस्टवाद, रूस में साम्यवाद और जापान में उग्र सैनिकवाद के उदय के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा। जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ।

इटली में फासिस्टवाद का उत्कर्ष—इटली में 1870 ई० में संवैधानिक राज-तन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। वहाँ कई राजनीतिक दल होने से विभिन्न दलों के संयुक्त मन्त्रीमण्डल बनते थे और विगड़ते थे। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध तक इटली में स्थायी सरकार नहीं बन सकी। जिसके कारण इटली का विकास नहीं हो सका और न ही इटली अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका।

इटली की सरकार का पोप से मतभेद चल रहा था। इसलिये इटली की कैथोलिक जनता सरकार से नाराज थी। उसने सरकार को अपना सक्रिय सहयोग कभी नहीं दिया। इटली सरकार की पोप विरोधी नीति के कारण कैथोलिक देश फ्रांस से भी उसकी मित्रता होना असंभव था। वहाँ के प्राकृतिक साधन सीमित होने के कारण वहाँ पर औद्योगिक शान्ति की प्रगति बहुत धीमी रही। इटली उपनिवेशों की दौड़ में बहुत देर से शामिल हुआ था, इसलिये उसके पास अफ्रीका में बहुत कम उपनिवेश थे।

प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक इटली एक सामान्य शक्ति था। वह 1882 ई० में विस्मार्क के "त्रिगुट" का सदस्य बन चुका था, परन्तु जब युद्ध आरम्भ हुआ तो उसने अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास किया। 1915 ई० में लंदन में एक गुप्त संधि की गई, जिसके द्वारा इटली को यह प्रलोभन दिया गया कि यदि उसने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी तो उसे युद्ध की समाप्ति के पश्चात् लंदन संधि में प्रस्तावित प्रादेशिक भाग पर अधिकार दे दिया जायेगा।

इटली ने लंदन की गुप्त संधि के तालच में आकर प्रथम विश्व-युद्ध में अपने विगुट के मित्र जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के दौरान जर्मनी ने सम्पूर्ण इटली पर अधिकार कर लिया। तब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से उसे छुटकारा दिलवाया। प्रथम विश्व-युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई।

युद्ध की समाप्ति के पश्चात् पेरिस शान्ति सम्मेलन में इटली के प्रधानमन्त्री और-लैंडों ने भाग लिया, परन्तु मित्त राष्ट्रों ने युद्ध से पूर्व किये गये वायदों को सम्मेलन में पूरा नहीं किया। इसलिये इटली की जनता ने पेरिस शान्ति सम्मेलन के विरुद्ध भयंकर असंतोष व्याप्त था। इसके लिये उसने अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ऐसी परिस्थितियों में मुसोलिनी का उत्कर्ष हुआ। उसने एक नया आंदोलन प्रारम्भ किया जिसे फासिस्टवाद कहा जाता है। मुसोलिनी के समर्थकों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। 1922 ई० में वह इटली का प्रधानमन्त्री बन गया। शीघ्र ही शासन की समस्त शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर इटली में ससदीय सरकार के स्थान पर तानाशाह शासन स्थापित कर दिया। इसके पश्चात् उसने तानाशाह की तरह शासन करना प्रारम्भ किया।

इटली में फासिस्टवाद के उदय के कारण—इटली में फासिस्टवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1. वर्साय की संधि से असन्तोष—प्रथम विश्व-युद्ध में इटली ने मित्त राष्ट्रों का साथ दिया था। युद्ध में इटली ने मित्त राष्ट्रों की विजय होने से इटली को यह आशा थी कि मित्त राष्ट्र अपने किये गये वायदों को पूरा करेंगे, जिससे इटली की स्थिति सुधर जायेगी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् इटली ने भी एक विजेता राष्ट्र के रूप में पेरिस शान्ति सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में मित्त राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की। इसमें इटली को उपनिवेश नहीं दिये गये। मित्त राष्ट्रों ने युद्ध के पूर्व किये गये प्रादेशिक वायदों को पूरा नहीं किया। इटली प्यूम बन्दरगाह पर अधिकार करना चाहता था, परन्तु इस विषय पर कोई निर्णय नहीं किया गया।

इस प्रकार पेरिस शान्ति सम्मेलन में उसकी समस्त आशाएँ धूल में मिल गईं। इटली की जनता ने पेरिस शान्ति सम्मेलन के विरुद्ध घोर असन्तोष और निराशा फैल गई। जनता ने इसके लिये अपनी दुर्बल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार इटली ने संसदीय सरकार के स्थान पर शक्तिशाली तानाशाही सरकार का मार्ग प्रशस्त हो गया।

2. इटली की शोचनीय आर्थिक दशा—प्रथम विश्व-युद्ध में भाग लेने के कारण इटली की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय हो गई थी। जैसे कि:—

- (i) युद्ध में भाग लेने के कारण इटली को जन तथा धन की अपार हानि हुई।
- (ii) युद्ध के कारण इटली का व्यापार और उद्योग घन्घे नष्ट हो चुके थे। उत्तरी इटली के कारखानों में उत्पादन कम होने के कारण आये दिन मजदूरों को निकाल दिया जाता था, जिससे वहाँ के मजदूर हड़ताल करते रहते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध

- (iii) युद्ध के दौरान जर्मनी की फौजों ने फसलों को नष्ट कर दिया था।
- (iv) इटली पर इस समय 12 लाख डालर ऋण था।
- (v) क्षतिपूर्ति की रकम उसे अभी तक नहीं मिल पाई थी।
- (vi) युद्ध के दौरान इटली की खानें बरबाद हो चुकी थी। इन खानों से पुनः कोयला और लोहा निकालने के लिये धन चाहिये था।
- (vii) मित्र राष्ट्रों की आर्थिक दशा खराब होने के कारण वे इटली को सहायता नहीं दे पा रहे थे।
- (viii) इटली सरकार के कोष में पैसा नहीं था।
- (ix) इस समय सरकार ने कर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिये थे। इस प्रकार इटली की दमनीय आर्थिक व्यवस्था के कारण अशान्ति और अव्यवस्था फैलने लगी। जिससे इटली में एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- (x) कारखानों में उत्पादन कम होने से खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं के भाव आसमान को छू रहे थे।

3. बेरोजगारी की समस्या—युद्ध के दौरान उद्योग धन्धे एवं कारखानों नष्ट हो चुके थे। इसलिये भारी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गये। इसके अतिरिक्त युद्ध से लौटे हुए सिपाहियों को सरकार नौकरी देने में असमर्थ थी। इसलिये सिपाही भी बेकार हो गये। इस प्रकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात् इटली में बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये बेरोजगार इटली की सरकार से असंतुष्ट थे, इसलिये मुसोलिनी की पार्टी के सदस्य बन गये थे।

4. साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव—एक ओर इटली में असन्तोष और निराशा फैल रही थी, तो दूसरी ओर उत्तरी इटली से औद्योगिक क्षेत्र में साम्यवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा था। मुसोलिनी ने साम्यवादी विरोधी संगठन बनाया, जिसके कारण उसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि पूंजीपति देशों का सहयोग प्राप्त हो गया।

5. इटली में राजनीतिक अस्थिरता—1919 से 1923 ई० तक इटली में कई मन्त्रिमण्डल बने और बिगड़े, लेकिन कोई भी दल स्याई सरकार नहीं बना सका। विभिन्न दलों के संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनते थे, जो चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिये लम्बे चौड़े वायदे करते थे परन्तु स्थायी सरकार बनाने में असमर्थ होने के कारण इन वायदों को पूरा करने में असमर्थ थे। इस कारण इस समय इटली का निरिक्त विकास नहीं हुआ और जनता में संसदीय सरकार के विरुद्ध असन्तोष गन्त था।

ऐसी परिस्थितियों में मुसोलिनी ने इटली में फासिस्टवाद दल की स्थापना की। इस दल के सदस्य "फेसियो" कहलाते थे। फेसियो शब्द की उत्पत्ति भेंटिन

मापा के "फायेज" शब्द से हुई है, जिसका अर्थ "कठोर और दण्ड" होता है। धीरे-धीरे इटली में फासिस्ट दल का प्रभाव बढ़ता गया।

6 बेनिटो मुसोलिनी मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट दल की स्थापना की। 1883 ई० में वह रोमेग्ना प्रान्त के एक क्रांतिकारी के घर में पैदा हुआ था। उसके पिता जुहार का काम करते थे, परन्तु समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। मुसोलिनी अपने पिता के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वह अध्यापक बन गया। शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उसका साम्यवादी दल से सम्पर्क हो गया। 1908 ई० में उसने सरकार विरोधी आन्दोलन में भाग लिया, जिसके कारण सरकार ने उसे जेल में बन्द कर दिया। जेल से मुक्त होने पर उसने "अवन्ती" नामक पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया।

प्रथम विश्व-युद्ध के समय मुसोलिनी चाहता था कि इटली युद्ध में भाग ले क्योंकि इससे इटली की आकांक्षा पूरी हो सकती थी। परन्तु साम्यवादी दल प्रथम विश्व-युद्ध में भाग लेने के पक्ष में नहीं था क्योंकि वह उसे पूंजीपतियों का युद्ध मानता था। इसलिए मुसोलिनी का साम्यवादी दल के साथ मतभेद हो गया। प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ होने पर मुसोलिनी इटली की सेना में भर्ती हुआ और 1915 ई० में युद्ध के दौरान उसने आईसोना नामक स्थान पर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। परिणामस्वरूप वह इटली जनता में लोकप्रिय हो गया।

(i) फासिस्ट दल का संगठन - प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् मार्च 1919 ई० में मोलान नामक नगर में मुसोलिनी ने फासिस्ट दल की नींव रखी। इस दल का संगठन बहुत मजबूत था। दल के प्रत्येक सदस्य को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। इस दल के प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उसे सब प्रकार के बलिदान के लिये तैयार किया जाता था। मुसोलिनी ने स्वयं सेवक दल की स्थापना की। ये काली कमीज पहनते थे। इसलिए इन्हें "काले कुर्ते वाले" कहा जाता था। इनका असल से झण्डा था। इस दल के लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही में विश्वास करते थे।

(ii) पार्टी का प्रोग्राम फासिस्ट दल का प्रोग्राम जनता की इच्छा के अनुकूल था। इस दल ने यह घोषणा की थी कि इटली के लिये उपनिवेश प्राप्त किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक, कृषि एवं यातायात के क्षेत्र में विकास किया जायेगा। राज्य के नियन्त्रण में एक ऐसी व्यवस्था कायम की जायेगी, जिससे सभी लोग सहयोग के साथ जीवित रह सकें। इस प्रकार पार्टी का घोषणा पत्र जनता की मनोभावनाओं के अनुकूल होने के कारण वह दल शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया।

(iii) मुसोलिनी का योग्य नेतृत्व—मुसोलिनी का योग्य एवं प्रभावशील नेतृत्व भी फासिस्टवाद के उदय का कारण बना। मुसोलिनी भाषण देने की कला में प्रवीण था। उसने अपने भाषणों के द्वारा फासिस्टवाद के सिद्धान्तों का बहुत अधिक

द्वितीय विरव युद्ध

प्रचार किया। उसमें जनता की मनोभावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता थी। उसने विपक्षियों के प्रति एक संगठित तथा सुनिश्चित नीति अपनाई।

7. आकस्मिक कारण—(1) 1919 ई० में मुसोलिनी ने फासिस्ट दल का संगठन किया। 1921 ई० के चुनाव में फासिस्ट दल के प्रतिनिधि बहुत अधिक संख्या में विजयी हुए। इस दल की शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती रही। इस समय मुसोलिनी ने यह घोषणा की कि यदि इटली की शासन सत्ता हमारे हाथों में नहीं आई तो हम रोम पर आक्रमण कर देंगे। इससे 1922 ई० में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया।

28 अक्टूबर, 1922 ई० में मुसोलिनी ने अपने पचास हजार स्वयं सेवकों के साथ रोम पर आक्रमण कर दिया। इस पर इटली के राजा विक्टर एमैन्युएल तृतीय में मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया। 31 अक्टूबर 1922 ई० को मुसोलिनी इटली का प्रधानमन्त्री बना। इसके कुछ महीनों पश्चात् ही उसने इटली में तानाशाही शासन स्थापित कर दिया।

प्रधानमन्त्री बनने के पश्चात् मुसोलिनी ने इटली में शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने 1924 ई० में चुनाव करवाये, जिसमें फासिस्ट दल को स्पष्ट-¹ बहुमत प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् उसने अपने विरोधियों का दमन करना प्रारम्भ किया। विरोधी दलों के नेताओं को बन्दी बना लिया गया और उन्हें जेल में भ्रमंकर यातनाएँ दी गईं। मुसोलिनी ने विरोधियों के समाचार पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया और उनकी सम्पत्ति पर सरकार ने कब्जा कर लिया। 1924-28 ई० को अवधि में बनाये गये कानूनों के अनुसार उन सभी राजकीय कर्मचारियों को राज्य सेवा से निकाल दिया गया, जो फासिस्ट दल के सदस्य नहीं थे। मुसोलिनी ने सभी राजकीय पदों पर फासिस्ट दल के सदस्यों को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त उसने सभी विरोधी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया। इस प्रकार मुसोलिनी इटली का तानाशाह बन गया।

फासिस्टवाद के सिद्धान्त—प्रो० लिप्सन ने लिखा है कि फासिस्टवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, साम्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति का विरोधी है। फासिस्टवाद के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:—

(1) फासिस्टवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विरोधी है। उसमें अन्य किसी राजनीतिक दल की स्वतन्त्रता के लिये कोई स्थान नहीं है।

(2) फासिस्ट दल प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का विरोधी है। मुसोलिनी का मानना था कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात् प्रजातन्त्र पद्धति के प्रयोग असफल रहे हैं। इसका कारण यह है कि प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में किसी भी प्रश्न पर जल्दी से निर्णय नहीं लिया जा सकता। मुसोलिनी कहता था कि 20वीं

गांधी प्रजापन्थ का नहीं अपितु तानाशाही का युग है। इसलिये उसने प्रजातन्त्र विरोधी विचारों का प्रचार किया। फासिस्ट दल एक नेता और एक शासन में विश्वास करता था। मुसोलिनी ने अपने दल के सदस्यों से कहा कि "विश्वास करो, आज्ञा मानो, और सड़ो।"

(3) साम्यवाद विरोधी—फासिस्टवाद साम्यवाद का विरोधी है। मुसोलिनी का मानना था कि राज्य के और व्यक्तियों के हित समान हैं। एक देश में सभी वर्गों के मनुष्य सह अस्तित्व की भावना से जी सकते हैं। वर्ग संघर्ष राजनीतिक तनावों के कारण होता है। मुसोलिनी के अनुसार यदि राज्य सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर नीति का निर्धारण करता है तो पूंजीपतियों और मजदूरों में सहयोग बना रह सकता है। इसके लिये साम्यवाद की आवश्यकता नहीं है। मद्यपि फासिस्टवाद साम्यवाद विरोधी था, तथापि व्यापार और उद्योग पर सरकार का नियंत्रण आवश्यक मानता था।

(4) शान्ति विरोधी—फासिस्टवाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शान्ति का विरोधी है। मुसोलिनी के अनुसार इटली शान्तिपूर्ण ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, लेकिन यदि कोई भी राज्य उसके विस्तार के मार्ग में बाधा उपस्थित करेगा, तो इटली युद्ध का आश्रय लेने से नहीं चूकेगा। मुसोलिनी का कहना था कि युद्ध अनादिबाल से होते चले आये हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। इसलिये यह कहना कि हम भविष्य में युद्धों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, यह बात इतिहास के निर्णय के विरुद्ध है। मुसोलिनी का कहना था कि "इटली का विस्तार उसके जीवन और मरण का प्रश्न है, इटली का विस्तार होना चाहिये, नहीं तो उसका विनाश हो जायेगा।"

इस प्रकार मुसोलिनी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिये साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसका कहना था कि बर्साय की संधि में इटली के साथ अन्याय किया गया है। इसलिये इटली को अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने चाहिये। मुसोलिनी ने एक भाषण में कहा था कि "हम भूमि के भूखे हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और हम ऐसा चाहते भी हैं।"

मुसोलिनी प्राचीन रोमन साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और भूमध्यसागर पर अधिकार करके उसे इटली की क्षील बनाना चाहता था। उसने कहा था कि प्राचीन काल में भूमध्य सागर पर हमारा अधिकार था और फिर शीघ्र अधिकार हो जायेगा।

(5) फासिस्टवाद शक्तिशाली राज्य का समर्थक था। मुसोलिनी ने कहा था कि "राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है।"

इस प्रकार फासिस्टवाद सैनिक शक्ति में विश्वास करता था। मुसोलिनी का यह मानना था कि बिना सैनिक शक्ति बढ़ाये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी बात को कोई नहीं मानेगा। यद्यपि इटली 1923 ई० में राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया था, परन्तु सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त में वह विश्वास नहीं करता था। इसलिये अबसर मिलते ही उसने राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया।

मुसोलिनी की विदेश नीति—मुसोलिनी शांति का विरोधी और युद्ध का समर्थक था। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद मिल राष्ट्रों ने पेरिस शांति सम्मेलन में इटली की मांगों को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए मुसोलिनी उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहता था। उसने इटली के लिये उपनिवेश स्थापित करने का निश्चय किया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसने कड़ी विदेश नीति का पालन करने का निश्चय किया। उसकी विदेश नीति से विश्व शांति के लिये संकट पैदा हो गया।

(1) यूनान-अल्बानिया सीमा विवाद—अल्बानिया और यूनान की सीमा विवाद की जांच करने के लिये राष्ट्रसंघ ने एक कमीशन नियुक्त किया था। इस कमीशन में इटली के मेम्बर भी थे। जब यह कमीशन सीमा विवाद के बारे में जांच कर रहा था, उस समय यूनान के कोप्यु द्वीप में 1923 ई० में इटालियन मेम्बरों की हत्या कर दी गई। इटली ने यूनान को भारी हर्जाने की रकम देने के लिये कहा। यूनान के विलम्ब करने पर मुसोलिनी ने कोप्यु नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस प्रश्न पर उसने राष्ट्र संघ का निर्णय मानने से इन्कार कर दिया। मुसोलिनी को चाहिये था कि वह इस मामले को राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत करता परन्तु उसने सीधी कार्रवाही कर मह स्पष्ट कर दिया कि इटली स्वयं शक्तिशाली है और उसे राष्ट्रसंघ के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। कोप्यु की घटना से दुनिया के देशों को यह पता चल गया कि दक्षिणी यूरोप में एक आशानक राष्ट्र का उत्कर्ष हुआ है।

(2) अल्बानिया पर अधिकार—पेरिस शांति सम्मेलन में बाल्कन क्षेत्र के अल्बानिया को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु यहाँ की अशिथिल तथा अनुभवहीन जनता का लाभ उठाकर अहमद जोगू नामक व्यक्ति अल्बानिया का शासक बन बैठा। अहमद ने अल्बानिया का आर्थिक विकास करने के लिये इटली से आर्थिक सहायता मांगी। तो मुसोलिनी ने तुरन्त अल्बानिया को आर्थिक सहायता प्रदान की। मुसोलिनो अल्बानिया पर अधिकार करना चाहता था। इसलिये उसने आर्थिक सहायता के साथ-साथ अल्बानिया पर सैनिक नियन्त्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। 1930 ई० में अहमद को इटालियन नीति का पता चला, परन्तु अब उसकी सतर्कता बेकार थी। 1939 ई० में मुसोलिनी ने अल्बानिया पर अधिकार कर लिया और उसे इटालियन साम्राज्य में मिला लिया।

(3) एबीसीनिया पर विजय—1934 ई० में मुसोलिनी ने एबीसीनिया राज्य को हड़पने का निश्चय किया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:—

- (i) एबीसीनिया प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न देश था। इटली यहाँ से खनिज पदार्थ, ऊन, रूई, और कच्चा माल आसानी से प्राप्त कर सकता था।
- (ii) इटली की बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिये जगह की आवश्यकता थी।
- (iii) एबीसीनिया के समीपस्थ प्रदेश इरिट्रिया और सोमालीलैण्ड पर इटली का पहले से ही अधिकार था। अब वह एबीसीनिया पर अधिकार करना चाहता था। 1935 ई० में एबीसीनिया की सीमा पर इटली के सैनिकों की एबीसीनिया के सैनिकों से मुठभेड़ हो गई। इस पर मुसोलिनी ने एबीसीनिया के सम्राट हेल सिलासी से सफाई मांगी। हेल सिलासी ने इस विवाद के बारे में राष्ट्रसंघ से अपील की। राष्ट्रसंघ ने दोनों ही देशों को शांतिपूर्ण तरीके से विवाद हल करने की सलाह दी परन्तु मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ की सलाह को मानने से इन्कार कर दिया। और 1935 ई० में एबीसीनिया पर हमला कर दिया। राष्ट्रसंघ ने इटली के इस कार्य की कटु आलोचना करते हुए 7 अक्टूबर 1935 ई० को उसको आक्रामक घोषित किया। 18 नवम्बर 1935 ई० को उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये गये। परन्तु इटली राष्ट्रसंघ के आदेश की अवहेलना करते हुए एबीसीनिया में आगे बढ़ता ही गया। 1936 ई० तक मुसोलिनी ने सम्पूर्ण एबीसीनिया पर अधिकार कर लिया और उसे इटलियन साम्राज्य में मिला लिया।

एबीसीनिया युद्ध के परिणाम—एबीसीनिया युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हुए:—

- (i) इस घटना ने राष्ट्रसंघ की दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया।
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की प्रतिष्ठा बढ़ी।
- (iii) इस घटना से इंग्लैण्ड और फ्रांस के सम्बन्ध फट्टु हो गये। इसका लाभ उठाकर अधिनायकों ने अपने साम्राज्य विस्तार की योजनाओं को पूर्ण करने का निश्चय किया।
- (iv) जब इटली एबीसीनिया पर अधिकार करने में लगा हुआ था तो राष्ट्रसंघ ने उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध के आदेश जारी किये, परन्तु जर्मनी ने राष्ट्रसंघ के आदेश की अवहेलना करते हुए इस समय इटली को शस्त्र तथा अन्य आवश्यक सहायता पहुंचाई। इसका परिणाम

द्वितीय विश्व युद्ध

यह हुआ कि जर्मनी और इटली पनिष्ठ मित्र बन गये। जिससे रोम बर्लिन टोकियो धुरी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया।

(v) रोम बर्लिन धुरी (1936 ई०)—1936 ई० में इटली और जर्मनी के बीच एक संधि हुई, जिससे रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ।

इस संधि के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे :—

(i) जर्मनी और इटली पेरिस शान्ति सम्मेलन की वसर्पा की संधि से असंतुष्ट थे।

(ii) हिटलर और मुसोलिनी साम्राज्य विस्तार करने की आक्रामक नीति का पालन कर रहे थे। दोनों ही देश संसार की सहानुभूति खो चुके थे। इसलिये अब दोनों के सामने दोस्ती करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था।

(iii) दोनों ही राष्ट्रों का इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस से युद्ध होना अनिवार्य था क्योंकि उनकी साम्राज्यवादी नीति में ये देश बाधक बन रहे थे।

(iv) 1936 ई० में स्पेन में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया था। मुसोलिनी ने राजतन्त्र के समर्थक जनरल फ्रैंको को सहायता पहुँचाने का निश्चय किया परन्तु अधिकांश यूरोपियन देशों की सहानुभूति फ्रैंको के विरोधी गणतन्त्र दल के साथ थी। ऐसे समय में हिटलर ने मुसोलिनी की सहायता की। जिसके फलस्वरूप 25 अक्टूबर 1936 ई० को दोनों देशों के बीच एक संधि हुई। इस संधि से दोनों ही देशों के अधिना-यक मित्रता के मूल में बँव गये। इस प्रकार रोम-बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ।

(5) राष्ट्रसंघ का परिस्थान मुसोलिनी की नीतियां राष्ट्रसंघ विरोधी थी। वह राष्ट्रसंघ के निर्णय और आदेशों का उल्लंघन करता रहा। एबीसीनिया पर अधिकार करने के पश्चात् 1936 ई० में व मुसोलिनी ने मुख्य होकर राष्ट्रसंघ का परिस्थान कर दिया।

(6) स्पेन का गृह-युद्ध (1936 ई०)—1936 ई० में स्पेन में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस समय स्पेन में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी इसके विरुद्ध राजतन्त्र के समर्थक जनरल फ्रैंको ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार स्पेन में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया। इंग्लैण्ड और फ्रांस ने स्पेन के किसी भी दल को सहायता नहीं दी, परन्तु मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को युद्धे आम सहायता पहुँचाई। हिटलर ने भी मुसोलिनी का साथ दिया। परिणामस्वरूप स्पेन के गृह-युद्ध में फ्रैंको सफल हुआ। उसने 1939 ई० तक सम्पूर्ण स्पेन पर अधिकार कर लिया। इस गृह युद्ध में जनरल फ्रैंको की सफलता ने पश्चिमी राष्ट्रों की दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया।

(7) द्वितीय विश्व-युद्ध और इटली—1939 ई० में हिटलर ने डॉनजिग समस्या को हल करने के लिये पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया। इटली ने जर्मनी का साथ दिया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की शानदार विजय हुई; महायुद्ध के अन्तिम दिनों में इटली के लोगों ने मुसोलिनी को मार डाला। उसकी मृत्यु के पश्चात् इटली में तानाशाही शासन की समाप्ति हो गई। द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् इटली में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई।

जर्मनी में नाजीदल का उदय—प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् जर्मनी में राजतन्त्र के स्थान पर गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। जर्मनी के गणतन्त्र को “वाइमर गणतन्त्र” भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी की लोकसभा का पहला अधिवेशन वीमर नगर में प्रारम्भ हुआ था। वर्साय की संधि को जर्मनी की जनता अपने राष्ट्र के लिये कलकपूर्ण दस्तावेज मानती थी। इस संधि को वाइमर गणतन्त्र की सरकार ने स्वीकार किया था। इसलिए जनता में सरकार के विरुद्ध असन्तोष व्याप्त था।

1930 ई० में विश्व-व्यापी आर्थिक संकट छा गया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति पहले से शीघ्रनीय थी, परन्तु इस आर्थिक संकट के कारण उसकी स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। इससे सरकार का दिवाला निकल गया। उद्योग घन्घे चौपट हो गये। बेरोजगारी की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया। वस्तुओं के भाव आसमान को छूने लगे। स्थान-स्थान पर हड़तालें और उपद्रव होने लगे। जर्मनी की प्रजातन्त्रीय सरकार इस आर्थिक स्थिति में सुधार करने में असफल रही, क्योंकि जर्मनी को विदेशों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसे समय हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल ने सरकार के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।

हिटलर का उत्कर्ष—नाजी दल के संस्थापक हिटलर का जन्म 20 अप्रैल, 1889 ई० को आस्ट्रिया के एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता चुंगी विभाग में नौकरी करते थे। प्रथम विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने के समय हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। उसने इस युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। जिसके फलस्वरूप जर्मनी की सरकार ने उसे “आइरन क्रॉस” नामक पुरस्कार प्रदान किया। प्रथम विश्व-युद्ध में जर्मनी की पराजय होने से मित्र राष्ट्रों ने उसे वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया। हिटलर ने प्रथम विश्व-युद्ध की पराजय और कलकित संधि का बदला लेने का निश्चय किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उसने नाजीदल पर राष्ट्रीय समाजवादी दल की स्थापना की।

हिटलर और उसका नाजीदल—जर्मनी में नाजीदल का जन्मदाता ड्रेक्सटर नामक ध्यक्ति था, जिसने 1919 ई० में इस दल की नींव रखी। कुछ ही समय में

द्वितीय विश्व युद्ध

मिक और कुशल कारीगर काफी संख्या में इस दल के सदस्य बन गये। धीरे-धीरे जर्मनी के अन्य नगरों में इसकी शाखाएँ खुलने लगी। हिटलर नामक श्रमिक भी इस दल का सदस्य बन गया। उसने 1920 ई० में इस दल के कार्यक्रमों की घोषणा की। दल के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित थे :—

- (i) वर्साय की संधि का अन्त करना।
- (ii) जर्मनी से छीने गये उपनिवेश पुनः प्राप्त करना।
- (iii) जर्मनी को एक सूत्र में बाँधकर एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना।

(iv) यहूदियों को जर्मनी से भगाना।

(v) जर्मनी में अनिवाय सैनिक सेवा लागू करना आदि लक्ष्य पार्यंते ने अपने सामने रखे। हिटलर भी इस दल का नेता बन गया। उसे इस दल का 'पयूरर' कहा जाता था।

1923 ई० में हिटलर ने लुन्डेडोर्फ के साथ मिलकर बवेरिया के गणतन्त्रीय सरकार के विरुद्ध असफल विद्रोह किया। सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया और उसे छः महीने के लिये जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उसने "Mein Kampf" (मेरा संपर्ण) नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने प्रोग्राम और सिद्धान्तों का वर्णन किया था।

1924 ई० के बाद हिटलर के दल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी। पहले नाजी दल का केन्द्र म्युनिक था। अब इस दल की शाखाएँ सम्पूर्ण जर्मनी के नगरों में खोली जाने लगी। 1924 ई० के चुनाव में इस दल के 24 सदस्य विजयी हुए, लेकिन बाद के चुनावों में इमे कोई विशेष मफलता नहीं मिली। 1930 ई० में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ टोयनबी जर्मनी की यात्रा पर गया, तब उसने कहा कि नाजी-दल का जर्मन की राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं है। लेकिन 1930 ई० के आर्थिक संकट के बाद नाजीदल की लोकप्रियता बढ़ने लगी।

हिटलर द्वारा सत्ता की प्राप्ति और अधिनायक बनना—1932 ई० में हिटलर तत्कालीन राष्ट्रपति हिण्डेन बर्ग के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिये खड़ा हुआ, परन्तु इस चुनाव में हिटलर की हार हुई और हिण्डेन बर्ग विजयी हुआ। इस चुनाव के परिणामस्वरूप हिटलर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा। इस समय रोस्टाग के चुनाव में 584 स्थानों में से 196 पर नाजी दल के सदस्य विजयी हुए। नाजीदल ने रोस्टाग में नेगनल कन्ज़रवेटिव दल से समझौता कर लिया था। इस तरह कुल मिलाकर 230 स्थान नाजियों को मिले।

हिण्डेन बर्ग ने हिटलर के स्थान पर दूसरे दल के नेता ग्लीबर को अपना वांसलर बनाया। राष्ट्रपति बनने के पश्चात् हिण्डेन बर्ग ने कहा था कि "मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह (हिटलर) वोहेमन सिपाही मेरे रहते कभी भी जर्मनी का चांसलर

नहीं बनेगा। मैं अधिक से अधिक उसे किसी उप नगरीय डाकखाने का पोस्ट मास्टर बना सकता हूँ।” परन्तु हिट्लर बर्ग की भविष्यवाणी गलत निकली, क्योंकि उसे 30 जनवरी 1933 ई० को हिट्लर को चांसलर के पद पर नियुक्त करना पड़ा। इसका कारण यह था कि उसके द्वारा नियुक्त चांसलर श्लीचर ने 8 माह में ही त्याग पत्र दे दिया था।

हिट्लर ने चांसलर बनने के बाद 27 फरवरी 1933 में चुनाव की घोषणा की। चुनाव से पूर्व नाजी सरकार ने अपने विरोधियों को कुचलना प्रारम्भ कर दिया। 1933 के चुनाव में 647 स्थानों में से 288 पर नाजी दल के सदस्य और 52 स्थानों पर इनके मित्र विजयी हुए। नई सरकार को 647 में से 340 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार नाजी दल की रीष्टाग में बहुमत प्राप्त था। रीष्टाग ने 1933 ई० में सविधान को स्वयं गत करके हिट्लर को तानाशाही अधिकार प्रदान कर दिये। अगस्त 1934 ई० को जर्मनी के राष्ट्रपति हिट्लर बर्ग की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात् हिट्लर ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को एक कर दिया और उसका नाम “राइक्स फूह्रर” रखा। हिट्लर ने इस पद को ग्रहण किया। इस कार्य के लिये हिट्लर ने जनमत का संग्रह करवाया। 90 प्रतिशत जनता ने हिट्लर के इस कार्य का समर्थन किया। इस प्रकार जर्मनी में प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त हुई और तानाशाही शासन का उदय हुआ। अब हिट्लर ने तानाशाही की तरह शासन करना प्रारम्भ कर दिया।

नाजी दल के उत्थान के कारण - नाजी दल के उत्थान के प्रमुख कारण निम्न लिखित थे :—

1. वर्साय की संधि का अन्वय—नाजी दल के उत्कर्ष का पहला कारण वर्साय की संधि का अन्वय था। वर्साय की संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार किया था। उसके उपनिवेश छीन लिये, निःशस्त्रीकरण कर दिया गया, उस पर युद्ध हर्जाने की भारी रकम लाद दी गई। इस संधि की अपमानजनक शर्तों को जर्मनी ने वाध्य होकर स्वीकार किया था। यह संधि जर्मनी के लिये कलंकपूर्ण दस्तावेज था। इससे उसकी राष्ट्रीय भावनाओं को गहरा आघात पहुँचा था। जर्मनी की जनता में इस संधि के विरुद्ध भयंकर असंतोष व्याप्त था। वाइमर गणतन्त्रीय सरकार वर्साय की संधि के अपमान को नहीं धो सकती। ऐसी स्थिति में हिट्लर ने जनता से यह वायदा किया कि यदि वह सत्ता में आया तो वर्साय की संधि को रद्द कर देगा और जर्मनी से छीने गये उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करेगा। लैगसम ने लिखा है कि नाजी दल के लोकप्रिय होने का मुख्य कारण 1930 ई० का आर्थिक संकट था, वर्साय की संधि नहीं थी। यदि यह सबसे मुख्य कारण होता तो नाजी दल अपने जन्म के समय से ही लोकप्रिय हो जाता।

2. प्रजातन्त्र विरोधी—जर्मनी की जनता सदा से प्रजातन्त्र विरोधी तथा

द्वितीय विश्व युद्ध

मैत्रिक प्रवृत्ति की थी। इसलिये प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् जर्मनी में स्थापित गण-तन्त्रात्मक शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जब वाइमर गणतन्त्र सरकार, वर्साय की संधि के अपमान का बदला लेने में असफल रही तो जनता ने हिटलर का स्वागत किया।

3. वाइमर गणतन्त्र की असफलता—इसकी असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे :—

(i) पराजय के समय उसका जन्म हुआ था।

(ii) वाइमर गणतन्त्र को जन्म के समय ही वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य होना पड़ा था। संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण जनता में गणतन्त्रीय सरकार के प्रति भयंकर असंतोष व्याप्त था।

(iii) प्रजातन्त्र के दलों में आपसी एकता का अभाव था। इसलिये जर्मनी में कभी स्थायी सरकार स्थापित नहीं हो सकी।

(iv) क्षतिपूर्ति और धन्य प्रश्नों पर किये गये समझौते के विरुद्ध जनता में असंतोष था।

(v) इसकी विदेश नीति कमजोर थी। इस कारण जर्मनी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित नहीं कर सका।

(vi) यह सरकार जर्मनी की अर्थ व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकी। बाविस योजना के बाद अमेरिका ने जर्मनी को ऋण दिया। इससे उसकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ परन्तु क्षतिपूर्ति की समस्या के कारण उसकी अर्थ व्यवस्था संभल नहीं पा रही थी।

4. 1930 की आर्थिक मंदी—1930-31 ई० में सारे विश्व में आर्थिक संकट मंडक छा गया। जर्मनी की आर्थिक दशा पहले से ही खराब थी। इस आर्थिक संकट के कारण उसकी आर्थिक दशा और अधिक शोचनीय हो गई। जर्मनी को इस समय विदेशों से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप उसके उद्योग धन्ये चौपट हो गये। जर्मनी में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ी। लाखों धर्मिक बेरोजगार हो गये। उनके मामले रोजी-रोटी की समस्या थी। ऐसे समय हिटलर ने मशी को रोजी-रोटी देने का वायदा किया। परिणामस्वरूप हिटलर का नाज़ीदल जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। गर्धान हार्डी तथा शुमैन का मानना है कि नाज़ीवाद के उदयान का सबसे महत्वपूर्ण कारण 1930-31 की आर्थिक मंदी है।

5. नाज़ीदल के धार्षिक कार्यक्रम—हिटलर ने अपनी पार्टी नेशनल सोशल-लिस्ट जर्मन सेबर पार्टी को जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम प्रदान किया। येगमम ने लिखा है कि हिटलर के धार्षिक कार्यक्रम से जनता बहुत

अधिक प्रभावित हुई। हिटलर ने अपनी पार्टी को निम्नलिखित कार्यक्रम प्रदान किए—

- (i) यहूदियों ने जनसाधारण को जो ऋण दिया था, उसे हिटलर ने माफ करने का वायदा किया। इससे जनता प्रसन्न थी।
- (ii) हिटलर ने कहा कि यह श्रमिकों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति दिलवायेगा।
- (iii) साम्यवाद का विरोध किया जायेगा।
- (iv) हिटलर पूंजीपतियों का समर्थक था।
- (v) उसने थोक व्यापारियों के लाभ को सीमित करने के लिये ऐसे प्रस्ताव रखे, जिससे छोटे दुकानदार बहुत अधिक प्रभावित हुए।
- (vi) हिटलर ने कहा कि बड़े-बड़े फार्मों की भूमि किसानों में बांट दी जायेगी। इससे किसान हिटलर के समर्थक बन गये।
- (vii) हिटलर ने क्षतिपूर्ति की राशि चुकाने का वायदा किया।

हिटलर ने अपने इन कार्यक्रमों का जोर-शोर के साथ प्रचार किया। इनमें जन साधारण बहुत अधिक सन्तुष्ट हुआ। परिणामस्वरूप हिटलर की लोकप्रियता बढ़ने लगी।

6. यहूदी विरोधी विचार—हिटलर यहूदियों का विरोधी था। इसलिये उसने उनके द्वारा जन साधारण को दिये गये ऋणों को माफ करने का वायदा कर लिया। इसके अतिरिक्त हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी से बाहर निवासने के लिये एक योजना रखी, जिसका जनता ने भारी स्वागत किया।

7. विशुद्ध आर्य रक्त का सिद्धान्त—हिटलर ने आर्यों का उद्गम जर्मनी बताया। उसके अनुसार केवल जर्मनी में रहने वाले व्यक्ति ही शुद्ध आर्य थे। जो व्यक्ति जर्मनी से बाहर चले गये थे, उसने उनको शुद्ध आर्य नहीं माना क्योंकि उन्होंने वहाँ के आदि निवासियों की लड़कियों से विवाह कर लिया था। इसलिये उनका रक्त अशुद्ध हो गया था। हिटलर यह मानता था कि आर्य जाति दुनियाँ की सर्वश्रेष्ठ जाति है और उसे शासन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। हिटलर जर्मन जाति को विश्व की महान शक्ति बनाना चाहता था।

8. नाजी दल का संगठन—प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट दल (नाजीदल) की स्थापना की। इस दल का प्रमुख कार्यालय म्युनिख में रखा गया। धीरे-धीरे इस दल की शाखाएँ जर्मनी के अन्य नगरों में भी खोली जाने लगी। नाजी दल के प्रत्येक सदस्य को सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उन्हें कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। इस दल के सदस्य अपने नेता के आदेशों का पालन आँख मूँद कर करते थे। नाजीदल के सदस्यों का चिन्ह स्वस्तिक (卐)

द्वितीय विश्व युद्ध

था। इस दल के सदस्यों को भूरे रंग की कमीज पहननी पड़नी थी। ये स्वयं सेवक थे। इनका काम दूसरे राजनीतिक दलों की सभाओं में गड़बड़ी पैदा करना था। हिटलर ने स्वयं सेवकों की रक्षा के लिए एक पुलिस दल का भी गठन किया। इस दल के सदस्य काले रंग की कमीज पहनते थे। ये काले रंग की कमीज पर सफेद खोपड़ी का चिन्ह लगाते थे। हिटलर ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम तथा सिद्धान्तों का अपनी पुस्तक "मेरा संघर्ष" में वर्णन किया है।

9. नाज़ी आन्दोलन के नये तरीके—नाज़ी दल के सदस्यों ने चुनाव में नये-नये तरीके अपनाये। हिटलर ने स्थान-स्थान पर भाषण दिये और अपनी पार्टी के कार्यक्रम का जोर-शोर के साथ प्रचार किया। सभी स्थानों पर पोस्टर लगाये गये, जिनमें नाज़ीदल के कार्यक्रमों का उल्लेख होता था। नाज़ी दल के सदस्य हथियार सहित प्रदर्शन करते थे। जिसमें विरोधी दल भयभीत हो गये।

10. चुनाव में सभी प्रकार के साधनों का उपयोग—नाज़ी दल के सदस्यों ने चुनाव में सभी प्रकार के तरीके अपनाए। इस दल के सदस्यों ने अपने विरोधियों को मोत के घाट उतार दिया अथवा उन्हें घायल कर दिया या उन्हें आतंकित कर दिया। नाज़ीदल ने मतदाताओं को भी आतंकित कर दिया और विरोधियों का मुँह बन्द कर दिया। इससे जनता को यह विश्वास हो गया कि नाज़ीदल वसर्था की संधि के अपमान का बदला लेने में समर्थ है और देश में शान्ति तथा समृद्धि लाने में सक्षम है।

11. हिटलर का असाधारण व्यक्तिगत—हिटलर के असाधारण व्यक्तित्व ने नाज़ीदल के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह राजनीति में चतुर तथा कूटनीतिज्ञ था। उसमें वे सभी गुण मौजूद थे, जो एक योग्य नेता में होने चाहिये। वह भाषण देने की कला में दक्ष था। उसने जोर-शोर के साथ अपने भाषणों में नाज़ी दल के प्रोग्राम और सिद्धान्तों का प्रचार किया। उसके कार्यक्रम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप थे। उसके भाषण को सुनने के लिये दूर-दूर से श्रोतागण आते थे और जो भी सुनता वह मुग्ध हो जाता था। हिटलर का प्रचार मन्त्री गोबुल्स कहा करता था कि "एक झूठ यदि सौ बार बोला जाय तो वह सच बन जाता है।"¹

12. साम्यवादी विरोधी—हिटलर और नाज़ीदल के उत्थान का कारण जर्मनी में साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव था। उसने साम्यवाद का विरोध किया। जिसके कारण इंग्लैण्ड और फ्रांस आदि पूंजीपति देशों का मोन समर्थन प्राप्त हो गया। पूंजीपति देशों ने नाज़ीदल के उत्थान का विरोध नहीं किया।

13. मुसोलिनी की सफलता—इटली में मुसोलिनी को तानाशाह शासक के रूप में सफलता प्राप्त हो चुकी थी। अतः जर्मनी के सामने मुसोलिनी का उदाहरण

1. "A lie told hundred times, becomes truth."

या । मुसोलिनी से प्रभावित होकर हिटलर ने भी जर्मनी में अघिनायक बनने का निश्चय किया ।

14. जर्मनी में उस समय अन्य कोई राजनीतिक दल इतना संगठित नहीं था ।

15. तत्कालीन कारण—1933 ई० में श्लीचर ने चांसलर के पद से त्यागपत्र दे दिया । तब राष्ट्रपति हिण्डेन बर्ग ने हिटलर को चांसलर के पद पर नियुक्त किया । हिटलर ने सत्ता का दुरुपयोग किया और आतंकवादी कार्य किये । जिसके कारण नये चुनावों में उसके दल के सदस्यों को साधारण बहुमत प्राप्त हुआ । रिप्टांग की हार के बाद भी हिटलर ने सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिये और जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित कर दिया ।

हिटलर ने तानाशाह बनने के पश्चात् सभी विरोधी दलों को भंग कर दिया । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई । सभा, भाषण, प्रेस, रेडियो, सिनेमा और शिक्षा आदि पर नियन्त्रण लगा दिया गया । हिटलर ने यहूदियों और अपने विरोधियों का दमन करने के लिये कुछ शिविरो की स्थापना की, जहाँ उन्हें कठोर यातनाएँ दी जाती थी । उसने अपने विरोधियों को मार डाला । हिटलर ने अपने गुप्तचर विभाग (गैस्टापो) के द्वारा जर्मनी में भय और आतंक का शासन स्थापित कर दिया । इस प्रकार हिटलर जर्मनी का सर्वोच्च बन गया ।

हिटलर की विदेश नीति—हिटलर की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

- (i) वर्साय की संधि को रद्द करना ।
- (ii) समस्त जर्मन जाति को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना करना ।
- (iii) जर्मनी की बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिये उपनिवेशों की स्थापना करना ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिये हिटलर ने जर्मनी की सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाया । इसके अतिरिक्त उसने आक्रामक कार्यों को प्रोत्साहन देने वाले मित्रों की खोज प्रारम्भ कर दी । इस प्रकार उसकी विदेश नीति सैनिक शक्ति एवं साम्राज्यवाद पर आधारित थी ।

2. राष्ट्रसंघ का परित्याग—हिटलर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिये जर्मनी की सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना आवश्यक समझा । उसने राष्ट्रसंघ द्वारा आयोजित निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लिया । इस सम्मेलन में हिटलर ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि सभी देशों ने अपने शस्त्रों में कमी नहीं की, तो जर्मनी भी शस्त्रों में वृद्धि करेगा । यूरोप की महान् शक्तियों ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं

निया। इस पर हिटलर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन से अलग हो गया और राष्ट्रसंघ की सदस्यता में त्यागपत्र दे दिया। हिटलर ने पश्चिमी राष्ट्रों को सन्तुष्ट करने के लिए अपनी दूसरी घोषणा में कहा कि जर्मनी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटायेंगा और शक्ति का आश्रय नहीं लेगा। इस घोषणा की पुष्टि में उसने पोलैण्ड के साथ 10 वर्ष के लिये अनाश्रमण समझौता कर लिया। इस समझौते के पीछे हिटलर का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह पोलैण्ड की तरफ से चिन्ना मुक्त होकर आस्ट्रिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। 1935 ई० में हिटलर ने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी।

2. आस्ट्रिया को हड़पने का असफल प्रयास—हिटलर आस्ट्रिया को हड़पना चाहता था। इसलिये उसने वहाँ के प्रधानमंत्री डॉल्फम का कत्ल करवा दिया। इसके पश्चात् उसने आस्ट्रिया के नाजियो से वहाँ की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करवा दिया। आस्ट्रिया की सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया। हिटलर आस्ट्रियन नाजियो की सहायता के लिये जर्मन सेना भेजना चाहता था परन्तु मुसोलिनी के विरोध के कारण नहीं भेज सका। इस समय मुसोलिनी ने आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए इटली की सेना भेजी। इसके अतिरिक्त उसने हिटलर को चेतावनी दी कि यदि उसने आस्ट्रिया पर अधिकार करने का प्रयास किया तो इटली उसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा। इसलिये हिटलर ने आस्ट्रिया के विरुद्ध कुछ भी कदम नहीं उठाया। इस प्रकार उसकी आस्ट्रिया पर अधिकार करने की योजना असफल रही परन्तु इस घटना ने हिटलर को मुसोलिनी की मित्रता का महत्व समझा दिया।

3. सार की प्राप्ति—1 मार्च, 1935 ई० में वर्साय की संधि की शर्तों के अनुसार सार प्रदेश में जनमत संग्रह किया गया। सार की अधिकांश जनता ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में मतदान किया। परिणामस्वरूप सार का प्रदेश पुनः जर्मनी में मिला लिया गया।

4. वर्साय की संधि की अवहेलना—16 मार्च, 1935 ई० को हिटलर ने घोषणा की कि जर्मनी वर्साय की संधि की सैनिक व्यवस्थाओं का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है। इसके पश्चात् उसने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी और जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि करने लगा। इस प्रकार हिटलर ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कर दिया।

5. ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नौ सेना संधि—सार पर अधिकार करने के पश्चात् हिटलर जर्मनी का शस्त्रीकरण करने लगा। इससे इंग्लैण्ड और फ्रांस चिन्तित हो उठे। ऐसे समय में हिटलर ने इंग्लैण्ड को भुलावे में रखने के लिये उसके सामने एंगलो-जर्मन नौ सैनिक समझौते का प्रस्ताव रखा। इंग्लैण्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों देशों के बीच 18 जून, 1935 ई० को नौ सेना संधि हो गई। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने जर्मनी को ब्रिटिश जल सेना के

था। मुसोलिनी से प्रभावित होकर हिटलर ने भी जर्मनी में अधिनायक बनने का निश्चय किया।

14. जर्मनी में उस समय अन्य कोई राजनीतिक दल इतना संगठित नहीं था।

15. तत्कालीन कारण—1933 ई० में श्लीचर ने चांसलर के पद से त्यागपत्र दे दिया। तब राष्ट्रपति हिण्डेन बर्ग ने हिटलर को चांसलर के पद पर नियुक्त किया। हिटलर ने सत्ता का दुरुपयोग किया और आतंकवादी कार्य किये। जिसके कारण नये चुनावों में उसके दल के सदस्यों को साधारण बहुमत प्राप्त हुआ। रीप्टांग की हार के बाद भी हिटलर ने सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिये और जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित कर दिया।

हिटलर ने तानाशाह बनने के पश्चात् सभी विरोधी दलों को भंग कर दिया। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई। सभा, भाषण, प्रेस, रेडियो, सिनेमा और शिक्षा आदि पर नियन्त्रण लगा दिया गया। हिटलर ने यहूदियों और अपने विरोधियों का दमन करने के लिये कुछ शिविरो की स्थापना की, जहाँ उन्हें कठोर यातनाएँ दी जाती थी। उसने अपने विरोधियों को मार डाला। हिटलर ने अपने गुप्तचर विभाग (गैस्टापो) के द्वारा जर्मनी में भय और आतंक का शासन स्थापित कर दिया। इस प्रकार हिटलर जर्मनी का सर्वोच्च बन गया।

हिटलर की विदेश नीति—हिटलर की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

- (i) वर्साय की संधि को रद्द करना।
- (ii) समस्त जर्मन जाति को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना करना।
- (iii) जर्मनी को बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिये उपनिवेशों की स्थापना करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिये हिटलर ने जर्मनी की सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाया। इसके अतिरिक्त उसने आक्रामक कार्यों को प्रोत्साहन देने वाले मित्रों की खोज प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार उसकी विदेश नीति सैनिक शक्ति एवं साम्राज्यवाद पर आधारित थी।

2. राष्ट्रसंघ का परिस्थान—हिटलर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिये जर्मनी की सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना आवश्यक समझा। उसने राष्ट्रसंघ द्वारा आयोजित निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में हिटलर ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि सभी देशों ने अपने शस्त्रों में कमी नहीं की, तो जर्मनी भी शस्त्रों में वृद्धि करेगा। यूरोप की महान् शक्तियों ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं

किया। इस पर हिटलर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन से अलग हो गया और राष्ट्रसंघ को सदस्यता से हटाकर दे दिया। हिटलर ने पश्चिमी राष्ट्रों को सन्तुष्ट करने के लिए अपनी दूसरी घोषणा में कहा कि जर्मनी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटायेगा और शक्ति का आश्रय नहीं लेगा। इस घोषणा की पृष्ठ में उमने पोलैण्ड के साथ 10 वर्ष के लिये अनाश्रयण समझौता कर लिया। इस समझौते के पीछे हिटलर का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह पोलैण्ड की तरफ से चिन्ता मुक्त होकर आस्ट्रिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। 1935 ई० में हिटलर ने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी।

2. आस्ट्रिया की हड़पने का असफल प्रयास—हिटलर आस्ट्रिया को हड़पना चाहता था। इसलिये उसने वहाँ के प्रधानमंत्री डाइफम का कत्ल करवा दिया। इसके पश्चात् उसने आस्ट्रिया के नाजियों से वहाँ की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करवा दिया। आस्ट्रिया की सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया। हिटलर आस्ट्रियन नाजियों की सहायता के लिये जर्मन सेना भेजना चाहता था परन्तु मुसोलिनी का विरोध के कारण नहीं भेज सका। इस समय मुसोलिनी ने आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए इटली की सेना भेजी। इसके अतिरिक्त उसने हिटलर को चेतावनी दी कि यदि उसने आस्ट्रिया पर अधिकार करने का प्रयास किया तो इटली उसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा। इसलिये हिटलर ने आस्ट्रिया के विरुद्ध कुछ भी कदम नहीं उठाया। इस प्रकार उसकी आस्ट्रिया पर अधिकार करने की योजना असफल रही परन्तु इस घटना ने हिटलर को मुसोलिनी की मित्रता का महत्व समझा दिया।

3. सार की प्राप्ति—1 मार्च, 1935 ई० में वर्साय की संधि की शर्तों के अनुसार सार प्रदेश में जनमत संग्रह किया गया। सार की अधिकांश जनता ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में मतदान किया। परिणामस्वरूप सार का प्रदेश पुनः जर्मनी में मिला लिया गया।

4. वर्साय की संधि की अवहेलना—16 मार्च, 1935 ई० को हिटलर ने घोषणा की कि जर्मनी वर्साय की संधि की सैनिक व्यवस्थाओं का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है। इसके पश्चात् उसने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी और जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि करने लगा। इस प्रकार हिटलर ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कर दिया।

5. ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नौ सेना संधि—सार पर अधिकार करने के पश्चात् हिटलर जर्मनी का शस्त्रीकरण करने लगा। इससे इंग्लैण्ड और फ्रांस चिन्तित हो उठे। ऐसे समय में हिटलर ने इंग्लैण्ड को भुलावे में रखने के लिये उसके सामने एंग्लो-जर्मन नौ सैनिक समझौते का प्रस्ताव रखा। इंग्लैण्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों देशों के बीच 18 जून, 1935 ई० को नौ सेना संधि हो गई। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने जर्मनी को ब्रिटिश जल सेना के

35 प्रतिशत अनुपात से जल सेना रखने की स्वीकृति दे दी। यह समझौता करके इंग्लैण्ड ने वर्साय की संधि को पंगु बना दिया।

6. राइन प्रदेश पर अधिकार करना—हिटलर लोकार्नों संधि की अवहेलना करके राइन प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था। इस समय फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया ने लोकार्नों की भावना के विरुद्ध रूस के साथ पारस्परिक सुरक्षा के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। हिटलर ने इस समझौते का विरोध किया। इसके प्रत्युत्तर में 2 मार्च, 1936 ई० को उसने राइन सैण्ड पर अधिकार कर लिया। संसार को भुलावे में रखने के लिये हिटलर ने यह वायदा किया कि राइन सैण्ड में शांति व्यवस्था स्थापित की जायेगी परन्तु उसने गुप्त रूप से इस प्रदेश में शस्त्रीकरण करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रदेश पर जर्मनी का अधिकार हो जाने से जर्मन सेना को आक्रमण करने का मार्ग मिल गया।

रोम-बर्लिन-टोकियो धुरी—हिटलर ने ऐसे मित्रों की तलाश प्रारम्भ कर दी थी, जो आक्रामक नीति पर चलते हों। उसने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इटली और जापान के साथ मित्रता करने का निश्चय किया।

हिटलर 1934 ई० में मुसोलिनी के विरोध के कारण आस्ट्रिया पर अधिकार नहीं कर सका था परन्तु जब मुसोलिनी ने एबीसीनिया पर आक्रमण किया तो यूरोप के अधिकांश देश इटली का विरोध कर रहे थे। ऐसे समय में हिटलर ने मुसोलिनी का विरोध करने के स्थान पर उसका साथ दिया। इतना ही नहीं हिटलर ने मुसोलिनी की एबीसीनिया की विजय को मान्यता भी दे दी। जब राष्ट्रमण्डल ने इटली को आक्रान्त घोषित कर उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये तो हिटलर ने राष्ट्रमण्डल के आदेश का उल्लंघन करते हुए इटली को सहायता पहुँचाई। हिटलर ने मुसोलिनी की एबीसीनिया विजय को उचित मानते हुए एबीसीनिया में मुसोलिनी की सरकार को मान्यता प्रदान की। हिटलर के इन उपकारों से प्रभावित होकर मुसोलिनी ने उससे मित्रता करने का निश्चय कर लिया। 1936 ई० में स्पेन के गृह युद्ध में हिटलर ने मुसोलिनी को खुश करने के लिये जनरल फ्रैंको की सहायता की।

इन उपकारों से मुसोलिनी हिटलर का मित्र बन गया। हिटलर और मुसोलिनी के बीच अक्टूबर 1936 ई० में एक गुप्त संधि हुई। जिससे रोम-बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। नवम्बर 1936 ई० में हिटलर ने जापान के साथ एन्टी कोमिन्टर्न पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिये। यह संधि साम्यवादी रूस का विरोध करने के लिये की गई थी। हिटलर के अनुरोध पर 6 नवम्बर 1937 ई० को मुसोलिनी ने भी इस पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिये। इस प्रकार रोम-बर्लिन-टोकियो धुरी का निर्माण हुआ और जर्मनी-जापान और इटली ये तीनों ही राष्ट्र धुरी-राष्ट्र बहलाये।

ये तीनों घुरी राष्ट्र साम्यवाद विरोधी समझौते की आड में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। साम्यवाद विरोधी समझौते के कारण उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों का मौन समर्थन प्राप्त हो गया, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्र साम्यवाद से बहुत भयभीत थे। घुरी राष्ट्रों का यह समझौता रूस के अलावा इंग्लैण्ड और फ्रांस के विरुद्ध भी था। इस समझौते के द्वारा हिटलर ने वर्साय की संधि के अपमान का बदला लेने का प्रयास किया। इस संधि के पश्चात् हिटलर ने आक्रामक नीति का पालन करना प्रारम्भ कर दिया।

7. आस्ट्रिया पर अधिकार—हिटलर ने इटली तथा जापान से समझौता करने के पश्चात् पुनः आस्ट्रिया को हड़पने का निश्चय किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने आस्ट्रिया में नाझीदल का संगठन किया। इस दल ने हिटलर के इगारे पर स्थान-स्थान पर विध्वंसकारक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। इससे आस्ट्रिया की आन्तरिक स्थिति बिगड़ गई। 11 मार्च, 1938 ई० को जर्मनी की सेना ने बिना किसी चेतावनी के आस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने आस्ट्रिया की मसद को भंग कर दिया। इसके पश्चात् जनमत संग्रह के आधार पर आस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने का निश्चय किया गया। हिटलर ने जनमत संग्रह करवाया। आस्ट्रिया की 88.65 प्रतिशत जनता ने जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में मतदान किया। हिटलर ने आस्ट्रिया को जर्मनी में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार उसने आस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया।

8. म्युनिख समझौता (29 सितम्बर 1938 ई०)—आस्ट्रिया पर अधिकार करने के पश्चात् हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने का निश्चय किया। इसका कारण यह था कि चेकोस्लोवाकिया में 32,31,600 व्यक्ति जर्मन जाति के थे। चेकोस्लोवाकिया के सूडेटनलैण्ड के क्षेत्र में जर्मन जाति के लोग बहुत अधिक संख्या में निवास करते थे। चेकोस्लोवाकिया के जर्मन नागरिकों ने सरकार के समक्ष ऐसी मांगें रखी, जिनको स्वीकार करना उसके लिये असम्भव था परन्तु हिटलर ने उनकी मांगों का समर्थन किया और चेकोस्लोवाकिया को सरकार को चेतावनी दी कि यदि जर्मन नागरिकों की मांगें स्वीकार नहीं की गईं तो जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर देगा।

अन्त में इस समस्या को हल करने के लिये म्युनिख में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी और इटली आदि देशों ने भाग लिया। परन्तु इस समस्या से सम्बन्धित देश चेकोस्लोवाकिया को और उसके समर्थक देश रूस को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि हिटलर की साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगा दिया परन्तु इंग्लैण्ड और फ्रांस ने इस सम्मेलन में हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। 29 सितम्बर

1938 ई० को म्युनिख में उपस्थित धारों देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किये, जिसे म्युनिख समझौता कहते हैं। इस समझौते में निम्नलिखित निर्णय लिये गये—

- (i) मूडेटन लैण्ड पर जर्मनी को अधिकार दे दिया गया।
- (ii) हिटलर ने आश्वासन दिया कि वह अब चेकोस्लोवाकिया के किसी भी भाग पर अधिकार नहीं करेगा।
- (iii) हिटलर ने चेम्बरलेन तथा दलादियर को यह वचन दिया कि मूडेटन-लैण्ड लेने के पश्चात् अन्य किसी प्रदेश पर अधिकार करने का प्रयास नहीं करेगा।

म्युनिख समझौता हिटलर की एक महान् कूटनीतिक विजय थी। इस समझौते से इंग्लैण्ड और फ्रांस की दुर्बलता स्पष्ट हो गई परन्तु हिटलर की साम्राज्यवादी लालसा शान्त न हुई और धीरे-धीरे उसने सम्पूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया।

9. मेमल पर अधिकार—हिटलर ने 21 मार्च 1939 ई० को लियुआनिया से मेमल प्रदेश देने की माग की। लियुआनिया ने पश्चिमी देशों की सहायता के अभाव में मेमल प्रदेश हिटलर को दे दिया। हिटलर को मेमल जैसा उपजाऊ प्रदेश प्राप्त हो गया।

10. रूस के साथ समझौता (23 अगस्त 1939)—अब हिटलर पोलैण्ड पर अधिकार करना चाहता था परन्तु उसे भय था कि रूस पोलैण्ड की सहायता कर सकता है। इसलिये उसने रूस से संधि वार्ता प्रारम्भ की। इस समय पश्चिमी देश भी जर्मनी के विरुद्ध रूस का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे परन्तु सफलता हिटलर को मिली। 23 अगस्त 1939 ई० में रूस और जर्मनी के बीच में अनाक्रमण संधि हुई। इसके अतिरिक्त हिटलर ने रूस के साथ एक गुप्त संधि भी की, जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि दोनों ही देश पूर्वी यूरोप पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् आपस में प्रदेश बांट लेंगे।

11. पोलैण्ड पर आक्रमण (1939 ई०)—रूस से समझौता करने के पश्चात् हिटलर ने 28 अप्रैल, 1939 ई० को पोलैण्ड से डाभिजग बन्दरगाह की माग की। इंग्लैण्ड और फ्रांस ने पोलैण्ड की सहायता करने का वचन दिया था, इसलिये उसने हिटलर की माग को टुकरा दिया। इस कारण (एक) सितम्बर 1939 ई० में हिटलर ने बिना चेतावनी दिये पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैण्ड और फ्रांस ने हिटलर को चेतावनी दी कि यदि उसने पोलैण्ड से अपनी सेनाएँ नहीं हटाई तो वे उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे। हिटलर ने पोलैण्ड से सेना हटाने में इन्कार कर दिया। अब इंग्लैण्ड और फ्रांस के समक्ष युद्ध के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। इसलिये उन्होने 3 सितम्बर 1939 ई० को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्ध के प्रारम्भ में

द्वितीय विश्व युद्ध

जर्मनी को शानदार सफलताएँ मिली परन्तु अन्त में उसकी पराजय हुई। हिटलर अपनी आंखों से जर्मनी की पराजय नहीं देखना चाहता था इसलिये उसने आत्महत्या कर ली। हिटलर की मृत्यु तथा जर्मनी की पराजय के साथ ही जर्मनी में तानाशाही शासन की समाप्ति हो गई।

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण—प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् पेरिस शांति सम्मेलन में मार्शल फोच ने यह भविष्यवाणी की थी कि वर्साय की संधि 20 वर्ष के लिये युद्ध-विराम संधि है। वास्तव में मार्शल फोच की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई और ठीक 20 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया और विश्व-शांति के सभी प्रयास अमफल रहे। मैकनेल बर्नस ने लिखा है कि "सितम्बर 1939 ई० में यूरोप पुनः एक अथाह छद्मे की सतह पर कूद पड़ा। 1919-1920 की संधि एक युद्ध विराम में परिणित हो गई और असंख्य लोग एक ऐसे संघर्ष में जकड़ गये जो पिछले सभी विनाशकारी युद्धों से भयानक था।" एलिस और जोन ने लिखा है कि "दुनिया अभी प्रथम महायुद्ध के राष्ट्रों से नहीं उमर पाई थी कि दूसरा विश्व-युद्ध शुरू हो गया। दुनिया की घटनाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये यह युद्ध अप्रत्याशित नहीं था। दरअसल जो घटनाएँ कई वर्षों से जमा होती आ रही थी उनके परिणामस्वरूप 1 सितम्बर, 1939 को प्रथम हमला शुरू हो गया।" 1 सितम्बर, 1939 को प्रारम्भ होने वाले द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे :—

1. वर्साय की संधि के प्रति असंतोष प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया। यह संधि जर्मनी के सिर पर बल्लक का टीका थी। इस संधि की अल्पमानजनक शर्तों का पालन करना जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए असम्भव था। मित्र राष्ट्रों ने पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया।

इस संधि पर हस्ताक्षर करते समय जर्मन प्रतिनिधियों के साथ अपराधियों की भांति व्यवहार किया गया। संधि की शर्तों एक पक्षीय थी। पराजित राष्ट्रों पर तो बहुत अधिक शर्तें लाद दी गईं किन्तु विजेताओं को उनसे मुक्त रखा गया। जर्मनी पर युद्ध हर्जनी की भारी राशि लाद दी गई, जिसको चुकाना उसके लिये असम्भव था। जर्मनी के सभी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया। उसका निरस्तरीकरण कर दिया गया। जर्मनी के सार के प्रदेश को छीनना, राइनलैण्ड में

1—मैकनेल बर्नस-बैस्टन सिविलीजेशनस पृष्ठ 805

2—एलिस और जोन—गंसार का इतिहास—पृष्ठ 542

मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ रखना और युद्ध के लिये जर्मनी को दोषी मानना आदि जर्मनी का प्रबल राष्ट्रीय अपमान था। जर्मनी की जनता इस अपमानजनक संधि का बदला लेना चाहती थी। जब हिटलर ने इस संधि को रद्द करने का आश्वासन दिया तो जनता ने उसका समर्थन किया। हिटलर ने चांसलर बनने के बाद यह घोषणा की थी कि "जर्मनी वर्साय की आरोपित संधि की किसी भी शर्त के अनुकूल कार्य करने के लिये बाध्य नहीं है।"

इस प्रकार हिटलर ने चांसलर बनने के बाद वर्साय की संधि की शर्तों का खुले आम उल्लंघन करना प्रारम्भ कर दिया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व-युद्ध के रूप में प्रकट हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन में जापान तथा जर्मनी की माँगें मित्र राष्ट्रों ने स्वीकार नहीं की। इसलिये ये दोनों देश भी इस सम्मेलन के निर्णयों से असंतुष्ट थे। परिणामस्वरूप इन दोनों देशों में अधिनायकवाद का जन्म हुआ।

2. राष्ट्रसंधि की असफलता—राष्ट्रसंधि की असफलता भी द्वितीय विश्व-युद्ध का कारण बनी। राष्ट्रसंधि की स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिये की गई थी परन्तु उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि अमेरिका जैसा बड़ा राष्ट्र इसका सदस्य नहीं था। इसके अतिरिक्त पराजित राष्ट्र जर्मनी और सोवियत संध को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। परिणामस्वरूप राष्ट्रसंधि केवल विजेता राष्ट्रों का संध बन गया जिसका एकमात्र उद्देश्य पेरिस शांति सम्मेलन में हुई संधियों का सम्बन्धित राष्ट्रों से पालन करवाना था।

इस प्रकार राष्ट्रसंधि लुटेरों और डाकुओं की एक ऐसी संस्था थी, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने व्यक्तिगत लाभ के पीछे था। राष्ट्रसंधि छोटे-छोटे राष्ट्रों के विवादों को सुलझाने में सफल रहा परन्तु बड़े राष्ट्रों के विवादों को सुलझाने में उसे सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था कि उसके पास अन्तर्राष्ट्रीय सेना का अभाव था। इसलिये वह जापान द्वारा मंचूरिया पर किये गये आक्रमण को इटली द्वारा एथीसी-निया पर किये गये आक्रमण को एव हिटलर द्वारा वर्साय की संधि को रद्द करने के लिये उठाये गये कदम को रोकने में असफल रहा। छोटे-छोटे राष्ट्रों का राष्ट्रसंधि से विश्वास समाप्त हो गया। इसलिये उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिये सैनिक संधियाँ करनी प्रारम्भ कर दीं। परिणामस्वरूप समस्त संसार पुनः दो शस्त्र शिविरों में विभक्त हो गया। यूरोप में शस्त्रीकरण की होड़ से सैनिकवाद का जन्म हुआ जिसका परिणाम द्वितीय विश्व-युद्ध के रूप में प्रकट हुआ।

3. निशस्त्रीकरण की असफलता—मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी का तो निशस्त्रीकरण कर दिया था परन्तु अपनी सैन्य शक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया था। जब मित्र राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करते रहे तो इससे अन्य राष्ट्रों में सदेह तथा भय की वृद्धि हुई। प्रथम विश्व-युद्ध की

द्वितीय विश्व युद्ध

समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रसंघ के सत्वाधान में तथा बाहर मित्र राष्ट्रों ने निशस्त्रीकरण के लिये कई सम्मेलन आयोजित किये परन्तु वे असफल रहे।

जर्मनी और रूस ने कई बार निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा परन्तु फ्रांस और इंग्लैण्ड के विरोध के कारण उसे सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था कि फ्रांस अपनी सुरक्षा पहले और निशस्त्रीकरण बाद में चाहता था। इसी प्रकार इंग्लैण्ड अपनी नौ-सैनिक शक्ति को कम करने के लिये तैयार नहीं था। जब राष्ट्रसंघ विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण नहीं कर सका तो अन्य राष्ट्रों ने भी अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसे समय में हिटलर ने भी जर्मनी की सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी शुरू कर दी। जापान जर्मनी और इटली की आक्रामक कार्यवाहियों से धबकाकर सभी देशों ने अपनी सैन्य शक्ति में तेजी के साथ वृद्धि करना प्रारम्भ किया। इससे यूरोप में शस्त्रीकरण की होड़ प्रारम्भ हो गई, जिसका अन्तिम परिणाम द्वितीय विश्व-युद्ध हुआ।

4. तुष्टीकरण की नीति—इंग्लैण्ड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व-युद्ध का कारण बनी। म्युनिख समझौते में यह नीति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई थी। इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन इस तुष्टीकरण की नीति का जन्मदाता था। उसका मानना था कि यदि हिटलर और मुमोलिनी की छोटी-छोटी मांगों को स्वीकार कर लिया तो वे सन्तुष्ट हो जायेंगे। इससे युद्ध को टाला जा सकेगा। चेम्बरलेन की इस नीति को तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है। इस नीति के अपनाने के कुछ अन्य कारण निम्नलिखित थे :—

(i) इंग्लैण्ड एक पूंजीपति देश था। उसे सबसे ज्यादा खतरा साम्यवाद से था। उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। इंग्लैण्ड साम्यवाद का विरोध करने वाले प्रत्येक देश को सहायता करने के लिये तैयार था। चाहे वह राष्ट्र शांति संधियों का उल्लंघन ही क्यों न करे। साम्यवाद विरोधी देशों को इंग्लैण्ड सब प्रकार की छूट देने के लिये तैयार था। इटली, जर्मनी और जापान ने इंग्लैण्ड की इस कमजोरी का लाभ उठाया। उन्होंने अपने आपको साम्यवाद विरोधी घोषित करते हुए खुले आम शांति संधियों का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं उन्होंने दूसरे राज्यों को हड़पने का सफल प्रयास भी किया।

(ii) इंग्लैण्ड ने अपनी आर्थिक नीति के कारण भी जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इंग्लैण्ड जानता था कि युद्ध के पूर्व जर्मनी उमका बहुत बड़ा ग्राहक था। युद्ध के पश्चात् भी इंग्लैण्ड के लिये जर्मनी बहुत अच्छा ग्राहक सिद्ध हो सकता था। इसलिये उसने

व्यापारिक हित को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के प्रति उदार रख अपनाये रखा ।

(iii) चेम्बरलेन हिटलर के असली रूप को नहीं पहचान सका । उसे यह विश्वास हो गया था कि यदि हिटलर की माँग पूरी कर दी गई तो वह फिर दुबारा माँग नहीं करेगा । हिटलर को यह विशेषता थी कि वह जब कभी किसी संधि का उल्लंघन करता या किसी प्रदेश की माँग करता तो यह वायदा करता था कि इसके बाद इसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और अब वह सतुष्ट है । चेम्बरलेन ने यहीं पर हिटलर को समझने में भूल की थी । ज्यों-ज्यों वह हिटलर को सन्तुष्ट करता गया त्यों-त्यों उसकी तृष्णा बढ़ती गई । यदि प्रारम्भ में ही उनके प्रति तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई जाती और शक्ति से उनको दबाया जाता तो आज का इतिहास ही दूसरा होता ।

(iv) इंग्लैण्ड शक्ति सन्तुलन को बनाये रखना चाहता था । जबकि फ्रांस ने अपने को सब तरह से सुरक्षित करके यूरोप का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनने का प्रयास किया । इसलिये दोनों महायुद्धों के बीच इंग्लैण्ड और फ्रांस के बीच मतभेद बने रहे । ब्रिटेन न तो फ्रांस की भाँति जर्मनी को क्षीण बनाना चाहता था और न ही फ्रांस को शक्तिशाली देखना चाहता था । इसलिये जहाँ फ्रांस ने जर्मनी को पंगु बनाने का प्रयास किया, इंग्लैण्ड ने इसका विरोध किया । वह जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना चाहता था । हिटलर के उत्कर्ष के पश्चात् भी फ्रांस और इंग्लैण्ड के बीच मतभेद बने रहे ।

1930 ई० के बाद शक्ति सन्तुलन बिगड़ जाने से ब्रिटेन ने जर्मनी के प्रति उदारवादी तुष्टीकरण की नीति अपनाई । शक्ति सन्तुलन बिगड़ने का मुख्य कारण यह था कि साम्यवाद का तेजी से प्रसार होता जा रहा था । इस समय इटली, जर्मनी और जापान भी काफी शक्तिशाली बन चुके थे । इसलिये ब्रिटेन ने साम्यवाद के विरुद्ध तानाशाहों को खड़ा किया । उसका यह मानना था कि या तो रूस और जर्मनी एक दूसरे पर नियन्त्रण बनाये रखेंगे अथवा लड़ने-लड़ते दोनों की शक्ति समाप्त हो जायेगी । इसलिये ब्रिटेन ने हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई । जिसके फलस्वरूप हिटलर को वर्साय की संधि की धाराओं का उल्लंघन करने में सफलता मिली । ब्रिटेन और फ्रांस के मतभेदों का लाभ उठाकर धुरी राष्ट्र दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनते गए । जापान ने मन्चूरिया पर, इटली ने एरीसीनिया पर और जर्मनी ने आस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और रूस की इच्छा के विरुद्ध चेकोस्लोवाकिया के बॉटवारें का उल्लंघन किया । धुरी राष्ट्रों ने खुले आम राष्ट्रसंघ के आदेशों की अवहेलना की और राष्ट्रसंघ इनके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सका । धुरी राष्ट्रों की अग्रगामी नीति का परिणाम द्वितीय विश्व-युद्ध हुआ ।

5. तानाशाही का उदय और उनकी विस्तारवादी नीतियाँ—प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् जर्मनी, आस्ट्रिया और हंगरी में जबरन प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इस नवीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फासिस्टवाद, रूस में साम्यवाद और जापान में सैनिकवाद का उदय हुआ। हिटलर, मुसोलिनी और जनरल फ्रैंको जैसे तानाशाहों के उदय के कारण विश्व-शांति खतरे में पड़ गई क्योंकि ये अधिनायक सिद्धान्ततः युद्ध की प्रतिवार्य मानते थे।

ब्रिटेन, फ्रांस व अमेरिका विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य के स्वामी थे, जबकि जर्मनी, जापान और इटली के पास उपनिवेश नहीं थे क्योंकि ये देश उपनिवेशों की दौड़ में देर से शामिल हुए थे। ये तीनों राष्ट्र भी अपने लिए नवीन उपनिवेश चाहते थे, ताकि अपना माल वहाँ बेच सकें, और वहाँ से कच्चा माल सस्ती दरों पर प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को वहाँ बसा सकें। इन तीनों धुरी राष्ट्रों ने उपनिवेशों की स्थापना के लिये विस्तारवादी नीति को अपनाया। इसलिये इनका उन राज्यों से संघर्ष होना स्वाभाविक था, जो पहले से बिनाल साम्राज्य के स्वामी थे।

6. धुरी राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रवाद और सैनिकवाद—धुरी राष्ट्रों का (जापान, जर्मनी और इटली) उग्र राष्ट्रवाद और प्रबल सैनिकवाद द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। जर्मनी वनरिय की संधि के अपमान का बदला लेना चाहता था। हिटलर ने इस कर्त्तव्य को घों डालने का वायदा किया। इससे नाजीदल जर्मनी में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। नाजीदल ने जर्मनी में "करो या मरो" का नारा प्रचलित किया। हिटलर ने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की और आस्ट्रिया को हड़प लिया। उसने चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार कर लिया। हिटलर ने जर्मन जनता को विश्वास दिला दिया कि "मेरे समय में युद्ध छिड़ जाना चाहिये।" जर्मनी के उग्रराष्ट्रवाद और हिटलर की आग्रहामी नीति ने द्वितीय विश्व-युद्ध को अवश्य-स्मायी कर दिया।

जर्मनी की भाँति इटली व जापान में भी उग्रराष्ट्रवाद और सैनिकवाद का उदय हुआ। मुसोलिनी युद्ध का पुजारी था। उसके लिये युद्ध जीवन और शांति शून्य थी। जापान के नेता भी उग्र सैनिकवादी थे। इन तीनों धुरी राष्ट्रों के उग्र राष्ट्रवाद और सैनिकवाद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शांति खतरे में पड़ गई और विश्व-युद्ध अनिवार्य हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी ने लिखा है कि "उग्र राष्ट्रवादिता मनुष्य का बड़ा शत्रु है, जिसका दो शताब्दी तक दुरुपयोग किया गया और त्रिकलक पतस्वरूप द्वितीय विश्व-युद्ध हुआ।"

7. धुरी राष्ट्रों की आर्थिक आशयकताएँ—जर्मनी, जापान, और इटली ने अपने संसार माल को बेचने के लिये एवं कच्चे माल की प्राप्ति के लिये बाजारों की

खोज करनी प्रारम्भ कर दी। इसके अतिरिक्त अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिये उन्होंने उपनिवेशों की स्थापना करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये धुरी राष्ट्रों ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। तीनों ही धुरी राष्ट्रों के उद्देश्य एक समान होने से ये मित्रता के मूत्र में बंध गये और पारस्परिक सहयोग से अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति में लग गये। इससे द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया। जापान ने मंचूरिया पर इटली ने एबीसीनिया पर विजय प्राप्त की। जर्मनी ने आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। जब हिटलर ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया तो विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया।

8. विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष—पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र-राष्ट्रों ने “आत्म-निर्णय” के सिद्धान्तों का पालन करने का आश्वासन दिया था परन्तु अनेक स्थानों पर इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया। वर्साय की संधि और बाद में अन्य कई संधियों द्वारा अल्पसंख्यक जातियों का निर्माण किया गया। इसमें अनेक स्थानों पर एक दूसरे की विरोधी अल्पसंख्यक जातियों को एक ही शासन के अधीन रखा गया। एक ही राष्ट्रीयता के व्यक्तियों को दूसरे देशों में अल्पसंख्यक जाति की तरह रखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक देशों में बसी हुई अल्पसंख्यक जातियों में असंतोष बढ़ना गया। हिटलर ने इस असंतोष का लाभ उठाते हुए आस्ट्रिया और सूडान पर अधिकार कर लिया। इसके परचात् उसने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया।

9. आर्थिक संकट (1929-30 ई०)—1930 ई० में सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक संकट छा गया। इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष संभव हो सका। इटली में फासिस्टवाद तथा यूरोप के अन्य देशों में साम्यवाद का तेजी के साथ प्रसार होने लगा। आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिये सभी देशों ने विदेशी माल पर भारी आयात कर लगा दिये। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार टपक हो गया। ऐसी स्थिति में जर्मनी, जापान और इटली ने अपने तैयार माल को बेचने के लिये एक बच्चे माल को प्राप्त करने के लिये साम्राज्यवादी नीति अपनाई। इस नीति पर चलते हुए जापान ने 1931 ई० में मंचूरिया पर और इटली ने 1935 ई० में एबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणों ने विश्व को द्वितीय महायुद्ध की ओर ढकेल दिया।

10. संधियों की अमान्यता—वर्साय और पेरिस की शांति संधियों के द्वारा सन्धि में युद्ध की सम्भावनाओं को टाटने का प्रयत्न किया था। सभी राष्ट्रों ने यह स्वीकार किया था कि ये अधिक युद्धोपयोगी सामग्री अपने पास नहीं रखेंगे। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी का निगमनीकरण तो कर दिया, लेकिन अपनी सैन्य शक्ति में बमी करने के स्थान पर वृद्धि करनी प्रारम्भ कर दी। इस तरह संधि के निर्माताओं ने ही

द्वितीय विश्व युद्ध

संधि को अमान्य कर दिया। जब हिटलर का उदय हुआ तो उसने साफ कहा कि जर्मनी वर्साय की संधि का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है। मित्रराष्ट्र हिटलर को इस चुनौती का जवाब नहीं दे सके। अतः हिटलर ने उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया, जिससे द्वितीय विश्व-युद्ध अवश्यम्भावी हो गया।

11. रोम-बर्लिन-टोकियो घुरी का निर्माण—प्रथम विश्व-युद्ध की भांति द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले सम्पूर्ण संसार दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गया। 1937 ई० में रोम-बर्लिन टोकियो घुरी का निर्माण हुआ। इससे यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट घुरी राष्ट्रों का, दूसरा मित्र राष्ट्रों का था। एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली ये तीनों राष्ट्र घुरी राष्ट्र कहलाये, जो कभी सन्तुष्ट होने वाले नहीं थे। दूसरा गुट मित्र राष्ट्रों का था। इस गुट में इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका आदि थे। इस ने युद्ध के आरम्भ में जर्मनी का साथ दिया परन्तु बाद में मित्र राष्ट्रों में जाकर मिल गया और युद्ध के अन्त तक उनके साथ रहा। ब्रिटेन और फ्रांस ने जैसे ही पोलैण्ड की रक्षा के लिये युद्ध की घोषणा की, वैसे ही द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया।

12. अमेरिका का विश्व युद्ध की राजनीति में भाग न लेना—प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् अमेरिका पृथक्ता की नीति का पालन कर रहा था। इसलिये उसने विश्व राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। यदि अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य बनकर समस्याओं को सुलझाने में अपना सहयोग प्रदान करता तो सम्भवतः जर्मनी, जापान और इटली इतने आगे नहीं बढ़ पाते। अमेरिका घुरी राष्ट्रों की शक्ति पर अंकुश लगा सकता था।

13. घटनाक्रमों से सम्बन्धित—

- (i) जापान ने 1931 ई० में चीन के मंचूरिया प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और राष्ट्रसंघ के आदेश की अवहेलना करते हुए 1931-32 में सम्पूर्ण मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकार स्थापित कर दी।
- (ii) 1935 ई० में इटली ने एबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया और राष्ट्रसंघ के आदेश की अवहेलना करते हुए 1936 ई० में एबीसीनिया पर अधिकार कर लिया।
- (iii) हिटलर ने छुले धाम वर्साय की संधि की धाराओं का उल्थपन किया और उसने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। जापान तथा इटली से संधि करने के पश्चात् हिटलर ने आस्ट्रिया को हड़प लिया। इसके पश्चात् हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया में वहुमध्यक जर्मन प्रदेश सुडेनलैण्ड की मांग की। इस पर इंग्लैण्ड और फ्रांस ने म्युनिख समझौते के अनुसार हिटलर को सुडेनलैण्ड का प्रदेश दे दिया। उसने

म्युनिख समझौते का उलंघन करते हुए सम्पूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया।

- (iv) 1936 ई० में जनरल फ्रैंको ने स्पेन की गणतन्त्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इससे स्पेन में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया। यद्यपि इंग्लैण्ड और फ्रांस की सहानुभूति स्पेन की गणतन्त्रीय सरकार के साथ थी परन्तु उन्होंने किसी प्रकार की सहायता नहीं देने का निश्चय किया। जबकि इंग्लैण्ड और फ्रांस के विरोध में हिटलर तथा मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को खुलकर सक्रिय सहायता पहुँचाई। जिसके परिणामस्वरूप फ्रैंको ने स्पेन के प्रजातन्त्र को समाप्त कर तानाशाही शासन स्थापित कर दिया। गृह-युद्ध में जनरल फ्रैंको की विजय से फासिस्ट शक्तियों का साहस बढ़ा। अब वे इंग्लैण्ड और फ्रांस की धमकियों को कोरी गौदड़ भभकी समझने लगे। इसलिये वे अग्रगामी नीति का पालन करते रहे। जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया।

14. हिटलर का पोलैण्ड पर आक्रमण—द्वितीय विश्व-युद्ध का तत्कालीन कारण हिटलर द्वारा पोलैण्ड पर आक्रमण करना था। हिटलर ने पोलैण्ड से डानजिग बन्दरगाह की मांग की। इंग्लैण्ड और फ्रांस ने पोलैण्ड की सुरक्षा का वचन दे रखा था, इसलिये उसने हिटलर की मांग को ठुकरा दिया। इस पर 1 सितम्बर 1939 ई० को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। इसलिए इंग्लैण्ड और फ्रांस ने हिटलर को चेतावनी दी कि यदि उसने 48 घंटे में पोलैण्ड से अपनी सेनाएँ नहीं हटाई तो वे उसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर देंगे परन्तु हिटलर ने पोलैण्ड से सेना हटाने से इन्कार कर दिया। इस पर 3 सितम्बर 1939 ई० को इंग्लैण्ड और फ्रांस ने पोलैण्ड की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया।

युद्ध के प्रारम्भ में रूस जर्मनी के साथ था परन्तु जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया तो रूस मित्रराष्ट्रों के पक्ष में गया। जब जापान ने अमेरिका के विरुद्ध आक्रमण की कार्यवाही की तो अमेरिका ने युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया, परन्तु हिटलर और मुसोलिनी के मित्र जनरल फ्रैंको ने युद्ध में उनका साथ नहीं दिया। वह युद्ध में तटस्थ रहा। उसने उनके उपकार का बदला नहीं चुकाया।

द्वितीय विश्व-युद्ध की घटनाएँ—(सितम्बर, 1939 ई० से अगस्त, 1945 ई० तक)—द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ में धुरी राष्ट्रों को शानदार सफलताएँ मिली और मित्र राष्ट्रों को निरन्तर पराजयों का मुंह देखना पड़ा। जर्मनी ने पोलैण्ड पर अधिकार करने के पश्चात् फ्रांस (पेरिस) पर आक्रमण कर दिया। 1940 ई० तक

द्वितीय विश्व युद्ध

हटलर ने डेनमार्क और नार्वे पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात् उसको उत्तर में डेनमार्क और नार्वे पर अधिकार करने में सफलता मिली। इस समय हालैंड, बेल्जियम तथा फ्रांस पर अधिकार कर दिया परन्तु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। ऐसी स्थिति में हिटलर मुसोलिनी की सहायता के लिये पहुँच गया। इस प्रकार यूगोस्लाविया और ग्रीस पर भी हिटलर ने अधिकार कर लिया।

22 जून, 1941 ई० को हिटलर ने रूस पर अकस्मात् हमला कर दिया। यद्यपि शुरू में जर्मनी को शानदार सफलताएँ मिली परन्तु जर्मनी को सैनिक रूस की भीषण शीत को सहन नहीं कर सके। इसलिये रूसी सेना ने जर्मनी को खदेड़ दिया। अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। वह केवल मित्र राष्ट्रों को आर्थिक एवं सैनिक सहायता पहुँचा रहा था परन्तु जापान ने अमेरिका के पल्लेहार्बर के नौमैनिक बल पर हमला किया। इस कारण अमेरिका ने मिय-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। जापान को युद्ध के दौरान, शानदार सफलताएँ प्राप्त हुईं। उसने हांगकांग, फिलिपाइन द्वीप समूह, मलाया, ब्रह्मा, थाइलैंड, बर्मा, इण्डोचीन और स्याम आदि पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् जापान ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया।

1942 ई० में युद्ध ने करवट बदली। अब मित्र राष्ट्रों की शानदार सफलताएँ मिलने लगी और धुरी राष्ट्रों को पराजय का मुँह देखना पड़ा। 1944 ई० में रटली ने हृदयार डाल दिये। वहाँ के देश-भक्तों ने मुसोलिनी और उसकी पत्नी को गोली से उड़ा दिया। 7 मई, 1945 ई० को जर्मनी ने भी हथियार डाल दिये। इस समय हिटलर ने आत्महत्या कर ली और उसका शव जला दिया गया था। इस प्रकार यूरोप में युद्ध बन्द हो गया परन्तु जापान के आत्म समर्पण नहीं करने से एशिया में युद्ध चलता रहा। परिणामस्वरूप अमेरिका ने 6 अगस्त, 1945 ई० को नागासाकी नगर पर अणु बम गिराये। इस भयंकर विध्वंस को देखते हुए 14 अगस्त, 1945 ई० को उसने आत्म-समर्पण कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति हुई।

द्वितीय विश्व-युद्ध के परिणाम—द्वितीय विश्व-युद्ध (1939-1945) लगभग 6 वर्ष तक चलता रहा। इसके परिणाम संसार के इतिहास में सबसे अधिक विनाशकारी मिट्ट हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हुए:—

(1) जन और धन की अपार क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति मारे गये तथा 3 करोड़ 30 लाख व्यक्ति घायल हुए। इस महायुद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी और इटली आदि बड़े देशों के अलावा पोलैंड, बेल्जियो-वाकिया और डेनमार्क जैसे छोटे-छोटे राष्ट्रों की भी अपार क्षति उठानी पड़ी। इन छोटे राष्ट्रों के लाखों सैनिक और नागरिक इस युद्ध में मारे गये। पोलैंड के 60

लाख एवं फिनलैण्ड के एक लाख सत्ताइस हजार व्यक्ति इस युद्ध में मारे गये। यूतान जर्मनी और इटली की फौजों के बीच घुरी तरह पिस गया। इस प्रकार छोटे राष्ट्रों को भी अपार जन घन की क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध से उनकी अर्थ व्यवस्था बिलकुल नष्ट हो गई। मैकनेल बर्नंस ने अमेरिकन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार आंकड़ों के आधार पर यह बताया है कि इस युद्ध में विश्व ने 13 खरब, 84 अरब, 90 करोड़ डालर व्यय किये।

(2) सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में प्रभाव—विश्व-युद्ध के कारण मजदूरों का मिलना कठिन हो गया। ऐसे समय में स्त्रियों ने कारखानों में काम करना प्रारम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त स्त्रियाँ सरकारी कार्यालयों में भी काम करने लगीं। इस युद्ध के कारण विश्व की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय हो गई। उद्योग धन्धे चौपट हो गये। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के भाव आकाश को छूने लगे। युद्ध के कारण खाद्यान्न का अभाव हो गया। युद्ध के दौरान सभी राष्ट्र अमेरिका से माल मंगाने रहे। अमेरिका युद्ध भूमि से दूर था, इसलिये वह बिना किसी बाधा के अपना औद्योगिक विकास करता रहा। फलस्वरूप अमेरिका विश्व का एक सम्पन्न वैभवशाली एवं पूंजीपति राष्ट्र बन गया। इससे विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद का नेता अमेरिका और साम्यवाद का नेता रूस बना।

(3) जर्मनी, जापान तथा इटली का बंटवारा—युद्ध की समाप्ति के पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को युद्ध के लिये दोषी माना। इसको आधार मानकर जर्मन नेताओं पर अभियोग चलाये गये। जो युद्ध अपराध सिद्ध हुए, उन्हें यथोचित दण्ड दिया गया। विश्व इतिहास में यह पहली घटना थी, जबकि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् पराजित देशों के नेताओं पर अभियोग चलाये गये थे।

जर्मनी की शक्ति को नष्ट करने के लिये इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस, और अमेरिका ने उसको आपस में बांट लिया। जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों का एवं पूर्वी जर्मनी पर रूस का अधिकार रखा गया। यह विभाजन अन्तर्राष्ट्रीय कलह का कारण बन गया।

जापान के क्यूराइल द्वीपों पर रूस का अधिकार रखा गया। फारमोसा चीन को दे दिया। कोरिया पर रूस तथा अमेरिका ने अपने-अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उचित समय पर स्वतन्त्रता दे दी जायेगी। इटली के उपनिवेशों पर भी मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया।

(4) इटली में प्रजातन्त्र की स्थापना—घुरी राष्ट्रों में इटली ने सर्वप्रथम आराम समर्पण किया था। इसके पश्चात् इटली में दो दल शक्तिशाली बन चुके थे। एक साम्यवादी दल जो इटली में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित करने के पक्ष

में था। दूसरा दल गणतन्त्रीय था, जो इटली में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इन दोनों दलों में संघर्ष चल रहा था। मित्त राष्ट्रों के सहयोग के कारण इस संघर्ष में गणतन्त्रवादी दल ने साम्यवादी दल को पराजित कर दिया। इस प्रकार इटली में मित्त राष्ट्रों के समर्थक गणतन्त्र दल की सरकार स्थापित हुई।

(5) जापान में राजतन्त्र की समाप्ति—द्वितीय विश्व-युद्ध के समय तक जापान में राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम थी परन्तु जापान के आत्मसमर्पण करते ही अमेरिका ने उस पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् उसने वहां राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इस प्रकार जापान में पहली बार प्रजातन्त्र स्थापित हुआ।

(6) अधिनायकवादी शासन व्यवस्था की विफलता—इस युद्ध में लोकतान्त्रिक शक्तियों ने जर्मनी, जापान तथा इटली के अधिनायकों को धुरी तरह से पराजित किया। लोकतान्त्रिक शक्तियों की विजय से जनता का प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास जाग्रत हुआ। इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि लोकतन्त्र को कुचल कर तानाशाही शासन अधिक समय तक नहीं चल सकता।

(7) शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में रूस का उदय—इस युद्ध के पश्चात् रूस विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। स्टोनिया, आघ्रा पोलैण्ड, लैटविया, लियुथनिया, फिनलैण्ड का भाग तथा पूर्वी प्रशा पर रूस का अधिकार हो जाने से उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। रूस ने रूमानिया, हंगरी, बल्गेरिया, अल्बानिया और युगोस्लाविया आदि देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित की। बाल्कन प्रदेश पर भी रूस का अधिकार हो गया। अब रूस की बढ़ती हुई शक्ति के कारण पश्चिमी राष्ट्र भयभीत हो गये।

(8) विश्व में सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अमेरिका का उदय—मैकनेल बर्नस ने लिखा है कि "द्वितीय विश्व-युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संसार का सबसे शक्तिशाली देश बन गया।"¹

द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व तक इंग्लैण्ड विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश था परन्तु युद्ध की समाप्ति के पश्चात् अमेरिका विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। विश्व का नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन के हाथ से निकलकर अमेरिका के हाथ में आ गया। इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि अब विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ महान् शक्तियां रह गई हैं। अमेरिका समस्त भूमि में द्रष्टुं दूर था, इसलिये उसे बहुत कम मुश्किल पहुंचा। उसे जन-धन की भी बहुत कम शक्ति हुई। इस युद्ध के दौरान अमेरिका का बहुत अधिक औद्योगिक विकास हुआ, क्योंकि

वह यूरोपियन देशों को माल भेज रहा था। अमेरिका के उद्योगों में 50 प्रतिशत और खेती में 36 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई। विश्व के महान राष्ट्र उसके कर्जदार बन गये।

(9) विश्व का दो गुटों में विभाजित होना—द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् रूस यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। इसके पश्चात् उसने साम्यवाद का प्रसार करना प्रारम्भ कर दिया। सम्पूर्ण पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का नियन्त्रण स्थापित हो गया। चीन में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। एशिया तथा अफ्रीका के देशों में साम्यवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। रूस की बढ़ती हुई शक्ति से पश्चिमी राष्ट्र भयभीत हो गये। पश्चिमी राष्ट्रों में रूस का मतभेद होने से वह शीघ्र ही उनके गुट से अलग हो गया। परिणामस्वरूप विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। (1) पूर्वी गुट (2) पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट का नेता साम्यवादी रूस और पश्चिमी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका बना। रूस साम्यवाद का और पश्चिमी गुट पूंजीवाद का प्रतीक है।

अतः साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट के बीच शीत युद्ध प्रारम्भ हो गया। इससे दोनों गुटों के बीच तनाव और मतभेदों में निरन्तर वृद्धि हुई है। अमेरिका अपनी पूंजी की ताकत से साम्यवाद के प्रसार को रोकने में लगा हुआ है। परन्तु अविकसित देशों में साम्यवाद का तेजी के साथ प्रसार होता जा रहा है।

(10) विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति—द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। इस युद्ध के कारण सत्तर अणु शक्ति से परिचित हुआ। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की। 1961 ई० में मानव ने अन्तरिक्ष की यात्रायें प्रारम्भ की और 1969 ई० में दो अमेरिकन चाद की सतह पर पहुँच गये। इसके अतिरिक्त कृषि तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी मानव ने अभूतपूर्व उन्नति की।

(11) चीन में साम्यवादी शासन की व्यवस्था की स्थापना—द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व ही चीन जापान से युद्ध कर रहा था। जब द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ तो चीन मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ था। जापान से युद्ध करने के कारण उसकी शक्ति काफी क्षीण हो चुकी थी। चीन के राष्ट्रपति च्यांग काई शेख को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, जबकि चीन के साम्यवादी दल को रूस का समर्थन प्राप्त था। चीन में साम्यवादी दल दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था। द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् चीन में गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस गृह युद्ध में साम्यवादी दल की विजय हुई। च्यांग काई शेख को चीन से भाग कर फारमूसा नामक टापू में शरण लेनी पड़ी, जो आज भी अमेरिका के संरक्षण में है। साम्यवादी दल ने चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था

द्वितीय विश्व युद्ध

की स्थापना की जिनके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय जगत में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ।

(12) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन—प्रथम विश्व-युद्ध की भाति मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व-युद्ध भी प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर सड़ा या किन्तु जब साम्राज्यवादी देशों ने युद्ध की समाप्ति के पश्चात् अपने अधीन देशों को स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की तो उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। साम्राज्यवादी देशों ने इन राष्ट्रीय आन्दोलनों को कुचलने का प्रयास किया परन्तु युद्ध में भाग लेने के कारण इन देशों की शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि उनके लिये जन आन्दोलनों को कुचलना असम्भव हो गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् इंग्लैण्ड में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में चर्चिल हार गया और एटली इंग्लैण्ड का प्रधान-मन्त्री निर्वाचित हुआ। उसने सदियों से गुलाम भारत को 15 अगस्त, 1947 ई० स्वतन्त्रता प्रदान की। इसके साथ ही एशिया में एक नवीन राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ।

ब्रिटेन ने बर्मा, मलाया, मिय, आदि देशों को भी स्वतन्त्र कर दिया। बाद में अनेक अफ्रीकी देशों को भी स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। इसके अनिश्चित हिन्द चीन, थैलैण्ड, हिन्देशिया (जावा, सुमात्रा और बोर्नियो) ने हिन्देशिया नामक संघ राज्य की स्थापना की। लीबिया, ट्युनिस, कांगो आदि अनेक देशों को भी स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। इस प्रकार एशिया और अफ्रीका के देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन सफल रहा।

(13) संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म—यद्यपि राष्ट्रसंघ को विश्व में शांति स्थापित करने में सफलता नहीं मिली परन्तु विश्व के राजनीतिकों ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना पर जोर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री चर्चिल ने इस विचारधारा का समर्थन किया। इसलिए 24 अक्टूबर, 1945 ई० को संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भी विश्व में शांति स्थापित करना था। इस साथ ने विश्व की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके कारण ही संसार तीसरे महायुद्ध से बचा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संघ ने पिछड़े तथा अविकसित देशों की जनता की भलाई के लिये सहायनीय कार्य किये हैं।

(14) विभिन्न शान्ति सम्मेलन—युद्ध समाप्ति के पश्चात् कई वर्षों तक विभिन्न देशों ने युद्धकालीन समस्याओं को हल करने के लिये कई शान्ति संधियों की। इसमें अटलाण्टिक चार्टर, कासा ब्लाका सम्मेलन, मास्को सम्मेलन, काहिरा सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, मास्का सम्मेलन, सान फ्रांसिस्को सम्मेलन और बर्लिन सम्मेलन आदि प्रमुख हैं।

(15) सैनिक संधियों का प्रादुर्भाव—पूँजीवाद और साम्यवादी संपर्क के कारण अनेक सैनिक संधियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें नाटो, सीटो, मॅन्टो और वारसा आदि प्रमुख हैं। हमारा देश भारत इस प्रकार की सैनिक संधियों से बंधा हुआ नहीं है। इस प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध के भयंकर विनाशकारी परिणाम निकले। इस युद्ध के पश्चात् विश्व का नेतृत्व ब्रिटेन के हाथ से निकल कर अमेरिका के हाथ में आ गया।

प्रस्तावित सन्दर्भ पाठ्य पुस्तकें :—

- 1—लैंगसम—दी वर्ल्ड सिन्स 1919
 - 2—मैकनैल वनंस—वैस्टर्न सिवलीजेशन्स
 - 3—एलिस और जौन- संसार का इतिहास
 - 4—वेल्स, एच० जी०—दी आऊट लाइन आफ हिस्ट्री
 - 5—शूमा—इन्टरनेशनल पोलिटिक्स
 - 6—प्लैट जीन और ड्रमंड—विश्व का इतिहास
-

संयुक्त राष्ट्र संघ

प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिये राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। यद्यपि राष्ट्रसंघ शान्ति स्थापित करने में असफल रहा। उसकी आंखों के सामने द्वितीय विश्व-युद्ध हो रहा था और वह उसको रोकने के लिये कुछ नहीं कर सका। फिर भी राष्ट्रसंघ की असफलता से यूरोप के राजनीतिज्ञ निराश नहीं हुए। इसी समय द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया। जिसके भयंकर विनाशकारी परिणाम हुए। इन भयंकर परिणामों को देखते हुए विश्व के राजनीतिज्ञों ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए एक संघ की स्थापना पर जोर दिया। पर्याप्त वाद-विवाद तथा कई सम्मेलनों के उपरान्त विश्व के राजनीतिज्ञों के प्रयासों से 24 अक्टूबर, 1945 ई० को संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के जन्म का इतिहास—द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान राजनीतिज्ञों ने भविष्य में युद्धों को रोकने के लिये और विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना पर जोर दिया। इस युद्ध के दौरान मिल राष्ट्रों के कई सम्मेलन हुए। जिनमें इस संघ के घोषणा-पत्रों की व्यवस्था की गई और कई विशेषज्ञों ने मिलकर इसका निर्माण किया। 6 जनवरी, 1941 ई० में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने प्रसिद्ध भाषण में भाषण, उपासना, भय और स्वातन्त्र्य आदि चार स्वतन्त्रताओं की घोषणा की। रूजवेल्ट ने अपने भाषण में कहा कि "हम ऐसे भावी संसार पर आशा लगाये हैं जिसकी आधार शिला....भाषण .. और विचार स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीकों से ईश्वर की अराधना की स्वतन्त्रता" अभाव से स्वतन्त्रता और भय से स्वतन्त्रता हो।"

इस घोषणा के कारण 1941 ई० में लंदन में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें 14 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि यद्यपि राष्ट्रसंघ को विश्व में शान्ति स्थापित करने में सफलता नहीं मिली है तथापि विश्व की शान्ति और सुरक्षा के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए।

युद्ध के दौरान 14 अगस्त, 1941 ई० को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिये अटलांटिक महासागर में एक पत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसे 'अटलांटिक चार्टर' कहा जाता है। इस चार्टर में उन्होंने सभी राष्ट्रों की समानता, स्वतन्त्रता और निशस्त्रीकरण पर बल देते हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना पर जोर दिया। इस चार्टर में यह घोषणा की गई थी कि "नाजी अत्याचारों को अन्तिम रूप से नष्ट करने के उपरान्त वे ऐसी शांति की स्थापना की आशा करते हैं, जो सभी राष्ट्रों को अपनी सीमाओं में सुरक्षित रहने के साधन प्रदान कर सके और यह आश्वासन भी दे सके कि सभी मनुष्य सभी देशों में भय तथा युद्ध से स्वतन्त्र होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।"

कुछ विद्वानों के अनुसार यही घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधार थी। 1942 ई० में वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 26 राष्ट्रों ने भाग लिया। इन सभी देशों ने अटलांटिक चार्टर को स्वीकार करते हुए एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसको "संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा" कहा जाता है। इस प्रकार पहली बार किसी घोषणा पत्र में "संयुक्त राष्ट्र" शब्द का प्रयोग किया गया।

सोवियत संघ भी अटलांटिक चार्टर को स्वीकार कर चुका था परन्तु पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट के परस्पर संदेह के कारण अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पा रहा था। 30 अक्टूबर, 1943 ई० में मास्को में एक सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें अमेरिका और इंग्लैण्ड और रूस के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विश्व की शांति और सुरक्षा के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना पर जोर दिया गया।

इसके पश्चात् वाशिंगटन के निकट डम्बर्टन ओक्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ। जिसमें अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस और चीन आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा तैयार करना था। यह सम्मेलन 1944 ई० तक चलता रहा। परन्तु प्रतिनिधियों के पारस्परिक मतभेदों के कारण कोई निर्णय नहीं हो सका। इसलिये डम्बर्टन सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रसंघ के चार्टर (संविधान) का निर्माण करने के लिये 25 अप्रैल, 1945 ई० को सेन फ्रांसिसको में सभी राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया। तदनुसार 1945 ई० में सेन फ्रांसिसको में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का निर्माण किया गया। 26 जून, 1945 ई० को सभी राष्ट्रों ने इस पर अन्तिम रूप से अपने हस्ताक्षर कर दिये। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह कहा था कि "संयुक्त राष्ट्रसंघ का संविधान, जिस पर आपने अभी हस्ताक्षर किये हैं, वह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर एक सुन्दर

संयुक्त राष्ट्र संघ

सार का निर्माण कर रहने हैं। अतः इस कार्य के लिये इतिहास आपका सम्मान करेगा।”

इस प्रकार 24 अक्टूबर, 1945 ई० को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इस संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयार्क में रखा गया। 8 अप्रैल, 1946 ई० को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रसंघ की इतिथी कर दी। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने चीनी, स्पेनिश, रूसी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं को मान्यता दे रखी है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर—

संयुक्त राष्ट्रसंघ के संविधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 10,000 शब्द, 111 धाराएँ और 19 अध्याय हैं। इस चार्टर में संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंगों, उनके कार्यों, अधिकारों, उद्देश्यों एवं संघ के सिद्धान्तों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य—

संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र की 111 धाराओं में संघ के उद्देश्यों और सिद्धान्तों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। चार्टर के अनुसार संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाये रखना। यदि कहीं भी शांति की सुरक्षा को खतरा हो तो उसे रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास करना।

2. राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को विकसित करना।

3. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना।

4. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना।

ये। जब तक कोई भी राष्ट्र चार्टर के अनुसार कार्य करता रहेगा, तब तक उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्त—संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की धारा 2 के अनुसार इसके प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :—

1. सभी राष्ट्रों के साथ एक समान व्यवहार किया जायेगा।

2. संघ का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र चार्टर के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करेगा।

3. सदस्य राष्ट्र अपने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे।

4. सदस्य राष्ट्र अपने आपसी विवादों को हल करने के लिये न तो युद्ध का आश्रय लेंगे और न ही युद्ध की धमकी देंगे।

5. जब संघ चार्टर के अनुसार कोई भी कार्यवाही करेगा तो सभी राष्ट्र उसे सभी प्रकार की सहायता देने के लिये वचन बद्ध है।
6. सध शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये हर संभव प्रयास करेगा। यदि गैर सदस्य राष्ट्रों ने शांति भंग करने का प्रयास किया तो संयुक्त राष्ट्रसंघ उस पर रोक लगायेगा।
7. यदि किसी भी राष्ट्र ने शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास किया तो संघ उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकेगा।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि इस संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा की रक्षा करने के लिये की गई थी।

सदस्यता :—

ऐसा कोई भी राष्ट्र जो शांति स्थापित करने का इच्छुक हो और चार्टर का पालन करने का आश्वासन देता हो वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के बाद साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से किसी भी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान कर सकती है। इस समय इस संघ के सदस्यों की संख्या 147 है। कोई भी राष्ट्र इस संघ की सदस्यता को नहीं छोड़ सकता है परन्तु यदि कोई सदस्य राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन करे तो उसे संघ की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है किन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग :—

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की धारा 7 के अनुसार इसके 6 मुख्य अंग हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

1. साधारण सभा (जनरल असेम्बली)
2. सुरक्षा परिषद
3. आर्थिक और सामाजिक परिषद्
4. संरक्षण परिषद्
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
6. सचिवालय

1. साधारण सभा (जनरल असेम्बली)—

यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी संस्था है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं। इसमें प्रत्येक राष्ट्र को पांच सदस्य भेजने का अधिकार है, परन्तु मतदान में केवल एक ही सदस्य भाग ले सकता है। असेम्बली में एक अध्यक्ष तथा सात उपाध्यक्ष होते हैं। जिनका चुनाव प्रतिवर्ष सितम्बर के दूसरे सप्ताह में किया जाता है। साधारणतः असेम्बली की बैठक वर्ष में एक बार सितम्बर माह में होती है परन्तु विशेष कारणोंवश या सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। असेम्बली में साधारण विषयों पर बहुमत से निर्णय

संयुक्त राष्ट्र संघ

लिया जाता है परन्तु शान्ति सुरक्षा, नये राष्ट्रों को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाना, और राष्ट्रों को संघ की सदस्यता से वंचित करना जैसे असाधारण विषयों पर दो तिहाई बहुमत से निर्णय लिया जाता है।

कार्य :—

असेम्बली के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. साधारण सभा विश्व की शान्ति और सुरक्षा को रतारा पहुंचाने वाले विषयों पर सुरक्षा परिषद् को अपनी सलाह दे सकती है। राष्ट्रों के आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सकती है। इसके अतिरिक्त निरासत्रीकरण के लिये सिफारिश कर सकती है।
2. साधारण सभा संयुक्त राष्ट्रसंघ के निम्न पदाधिकारियों का चुनाव करती है—
 - (i) वह सुरक्षा परिषद् के अस्थाई सदस्यों का चुनाव करती है।
 - (ii) आर्थिक और सामाजिक परिषद् के 27 सदस्यों का चुनाव करती है।
 - (iii) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है।
 - (iv) सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर संघ के महासचिव की नियुक्ति करती है।
 - (v) असेम्बली अपने एक अध्यक्ष और सात उपाध्यक्षों का प्रतिवर्ष चुनाव करती है।
 - (vi) सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर असेम्बली दो तिहाई बहुमत से किसी भी नये राष्ट्र को संघ की सदस्यता प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त चार्टर की अवहेलना करने वाले राष्ट्रों को दण्ड दे सकती है अथवा संघ की सदस्यता से वंचित कर सकती है।
 - (vii) संरक्षण परिषद् के सदस्यों का चुनाव करती है।
3. सुरक्षा परिषद् तथा अन्य विभागों से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार कर अपना निर्णय देती है।
4. साधारण सभा निम्नलिखित कार्य भी करती है।
 - (i) उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट को पास करने का अधिकार है।
 - (ii) यह किसी भी कार्यवाही को रोकने के लिये सुरक्षा परिषद् को सिफारिश कर सकती है।
 - (iii) धरोहर प्रदेशों के शासन का निरीक्षण कर सकती है।
 - (iv) सदस्य राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को विकसित करती है।

इस सभा का कार्य छः समितियों के द्वारा चलाया जाता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और चीनी आदि भाषाओं में यह सभा अपना कार्य करती है। साधारण सभा सुरक्षा परिषद् की समस्या पर बिना उसकी सहमति के विचार नहीं कर सकती है।

2. सुरक्षा परिषद्

सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। पांच स्थाई और दस अस्थाई।

1. इंग्लैण्ड

2. अमेरिका

3. फ्रांस

4. रूस और

5. साम्यवादी चीन आदि इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके 10 अस्थाई सदस्यों का चुनाव साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से करती है। इनका कार्यकाल दो वर्ष होता है। इस परिषद् के स्थायी सदस्यों को वीटो (निषेधाधिकार) प्राप्त होने के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ में काफी शक्तिशाली बने हुए हैं। सुरक्षा परिषद् युद्धों को रोकने, एवं विश्व में शांति और सुरक्षा बनाये रखने का कार्य करती है। इसकी बैठक महीने में दो बार होती है। अपनी सुविधानुसार परिषद् अपनी बैठक कहीं भी बुला सकती है।

सुरक्षा परिषद् एक सभापति चुनती है, जो परिषद् की कार्यवाही का संचालन करता है। सभापति का कार्यकाल एक माह होता है। सभापति का चुनाव सदस्य राष्ट्रों के प्रथम अक्षर के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला से किया जाता है। इससे परिषद् के प्रत्येक सदस्य को सभापति बनने का अवसर प्राप्त हो जाता है। परिषद् के सदस्य राष्ट्र अपना एक प्रतिनिधि संघ के केन्द्र स्थान न्यूयार्क नगर में रखते हैं, ताकि कभी भी आवश्यक बैठक बुलाई जाने पर वे उसमें भाग ले सकें। यह संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है।

सुरक्षा परिषद् के कार्य :—

घाटंर के अनुसार सुरक्षा परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सुरक्षा परिषद् चार प्रकार के तरीके अपनाती है :—

1. विवादी राष्ट्रों को शांति पूर्ण ढंग से समस्या को हल करने की सलाह देती है।
2. इस उपाय के असफल रहने पर परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा विवाद को हल करने की सलाह देती है।
3. इस प्रयत्न के असफल रहने पर परिषद् आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध

आर्थिक प्रतिबन्ध लगाती है।

4. जब यह प्रयत्न भी असफल रहता है तो परिपद् आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर सकती है परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये पाँच स्थायी सदस्यों एवं दो अस्थाई सदस्यों का एकमत होना आवश्यक है।

परिपद् के कार्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। साधारण कार्य और असाधारण कार्य। परिपद् का कार्यक्रम, स्थान एवं समय से सम्बन्धित साधारण प्रश्नों पर 9 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने पर निर्णय लिया जा सकता है परन्तु शांति और सुरक्षा जैसे असाधारण विषयों पर 9 सदस्यों का एकमत होना आवश्यक है यदि पाँच स्थायी सदस्यों में से एक भी महत्वपूर्ण निर्णय के विरुद्ध मत देता है तो प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जाता है। यही वीटो की सुप्रसिद्ध व्यवस्था है। वीटो केवल स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। वीटो के पक्ष और विपक्ष में काफी चर्चा होती है क्योंकि इसके कारण कई बार परिपद् के कार्य में बाधा उपस्थित हो जाती है।

यदि परिपद् वा कोई भी स्थायी अथवा अस्थाई सदस्य किसी क्षण से सम्बन्धित है, तो वह चार्टर की धारा 27 के अनुसार उस विषय पर अपना मत नहीं दे सकता है। सुरक्षा परिपद् संयुक्त राष्ट्रसंघ के गैर सदस्य राष्ट्र को किसी भी क्षण पर निर्णय के विषय में सलाह देने के लिये आमन्त्रित कर सकती है परन्तु आमन्त्रित सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं है।

3. आर्थिक और सामाजिक परिपद् :—

प्रारम्भ में इस परिपद् के सदस्यों की संख्या 18 थी। जिसे 1965 में बढ़ा कर 27 कर दी गई। इसके नौ सदस्यों का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष साधारण सभा बहुमत से करती है। इसमें छोटे और बड़े राष्ट्रों के बीच में कोई अन्तर नहीं होता। सदस्य अपनी प्रथम अवधि समाप्त होने पर दुबारा चुनाव लड़ सकता है। इसकी वंछक वर्ष में दो बार होती है। परिपद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्य काल एक वर्ष होता है जिसका चुनाव यह स्वयं करती है। गैर सदस्य राष्ट्रों को भी इसके अधिवेशन में बुलाया जा सकता है परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। इस परिपद् का प्रत्येक सदस्य एक मत दे सकता है।

उद्देश्य :—

चार्टर की धारा 55 के अनुसार इस परिपद् के प्रमुख उद्देश्य निम्न-लिखित हैं :—

1. विश्व के सभी देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास करना। इसके अतिरिक्त उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के स्तर का विकास करना।

2. बिना किसी भेदभाव के सभी राष्ट्रों को एक समान मानव अधिकार प्रदान करना ।
3. विश्व के सभी देशों के नागरिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करना ।
4. आर्थिक विकास के लिये टेक्नीकल सहायता देना ।
5. आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा सुलझाना ।

आर्थिक और सामाजिक परिपद् ने कुछ विशिष्ट समितियों की स्थापना कर रखी है, जो विश्व के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक स्तर का विकास करने के लिये प्रयास करती है । ये समितियां निम्नलिखित हैं :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (I. L. O.)
2. खाद्य और कृषि संगठन (F. A. O.)
3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.)
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन (W. H. O.)
5. विश्व डाक संगठन (U P O.)
6. संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय
बाल संकटकालीन कोष (U N I C E F.)
7. अन्तर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण तथा विकास बैंक (I. B R D.)
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निकाय (I. F. C.)
9. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई संगठन (I C. A. O.)
10. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा
सांस्कृतिक संगठन (U N E S. C. O.)

परिपद् के कार्य :—

इस परिपद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक समस्याओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
2. साधारण सभा और अन्य समितियों को अपने सुझाव भेजना ।
3. सामाजिक तथा आर्थिक समझौते के प्रारूप को स्वीकृति हेतु साधारण सभा में प्रस्तुत करना ।
4. अपने कार्य का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिये आयोगों की स्थापना करना ।
5. अपनी समस्याओं को हल करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना ।

परिपद् द्वारा तैयार किये गये मानव अधिकारों की घोषणा के प्रारूप पर असेम्बली ने 10 सितम्बर, 1948 ई० को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी । यह

संयुक्त राष्ट्र संघ

परिषद् केवल सिफारिशें कर सकती हैं इसे अपने निर्णय को क्रियान्वित करने का अधिकार नहीं है।

4. संरक्षण परिषद् :—

राष्ट्रसंघ की संरक्षण व्यवस्था के स्थान पर इस परिषद् की स्थापना की गई है। संरक्षण परिषद् तीन प्रकार के प्रदेशों के शासन-व्यवस्था का संचालन करती है—

1. राष्ट्रसंघ के शासनाधीन रहे हुए प्रदेशों पर
2. द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रों से छीने गये प्रदेशों पर
3. महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे गये प्रदेशों पर।

इस प्रकार के प्रदेशों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ बड़े राष्ट्रों के माध्यम से शासन करता है। इसके सदस्यों की संख्या अनिश्चित है। इसके प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। इसके सदस्यों का चुनाव साधारण सभा के द्वारा तीन वर्ष के लिये किया जाता है। इसमें किसी भी विषय पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इस परिषद् की वर्ष में दो बार बैठक होती है। बैठक में परिषद् के सदस्य समापति का निर्वाचन करते हैं।

इस परिषद् का प्रमुख कार्य पिछड़े हुए एवं परतन्त्र राष्ट्रों को स्वायत्त शासन करने योग्य बनाना है। जब तक वे इस योग्य नहीं हो जाते तब तक परिषद् बड़े राष्ट्रों के माध्यम से उन पर शासन करती रहती है। बड़े राष्ट्र इन संरक्षण प्रदेशों की प्रगति का विवरण प्रतिवर्ष परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। परिषद् उन पर विचार करने के पश्चात् भावी प्रगति के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देती है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय :—

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं परन्तु एक देश का एक से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकता। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से एक वर्ष के लिये करती है। न्यायाधीश की अवधि समाप्त होने पर वह दुबारा भी निर्वाचित हो सकता है। न्यायाधीशों को 21 हजार डालर वार्षिक वेतन मिलता है। न्यायाधीश अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय हार्लैण्ड की राजधानी हेग में है। यह न्यायालय फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा में अपना निर्णय देता है और सारा कार्य करता है।

इस न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति में ही कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर किये जाते हैं। जिस देश से सम्बन्धित विवाद पर न्यायालय में मुनबाई चल रही हो उस देश का न्यायाधीश निर्णय में भाग नहीं ले सकता है। इस न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है और इसकी वही अपील नहीं हो सकती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों के अलावा

गैर सदस्य राष्ट्र भी इस न्यायालय में अपने विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु उन्हें सुरक्षा परिषद् के द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है।

कार्य—

इस न्यायालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. सीमा विवाद, संघियों और अन्तर्राष्ट्रीय कानून से सम्बन्धित विषयों पर अपना निर्णय देना।
2. सुरक्षा परिषद् को किसी भी वैधानिक मामले पर परामर्श दे सकता है परन्तु परिषद् उस सलाह को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करना सुरक्षा परिषद् का कार्य है।

6. सचिवालय—

संयुक्त राष्ट्रसंघ का कार्यालय सचिवालय कहलाता है। यह संघ का कार्य चलाता है। इसका कार्यालय न्यूयार्क में है। सचिवालय का प्रधान "महामन्त्री" कहलाता है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से 5 वर्ष के लिये करती है। महासचिव निर्धारित निषेधों के अनुसार सचिवालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

कार्य—

सचिवालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. सचिवालय के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट असेम्बली के समक्ष प्रस्तुत करना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को छतरा पहुँचाने वाले विषय की ओर महासचिव सुरक्षा परिषद् का ध्यान आकर्षित कर सकता है।
3. संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंगों के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को पूरा करता है।

सचिवालय में आठ भाग हैं। प्रत्येक विभाग में एक एक सहायक महासचिव होता है। ये आठ विभाग निम्नलिखित हैं—

1. प्रशासनिक और धन सम्बन्धी विभाग
2. सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विभाग
3. आर्थिक मामलों का विभाग
4. सांख्यिक सूचना विभाग
5. प्रशासित प्रदेशों सम्बन्धी सूचना विभाग
6. कानून विभाग
7. सम्मेलन सम्बन्धी तथा साधारण सेवाएँ
8. सामाजिक मामलों का विभाग

चार्टर में संशोधन :—

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की धारा 108 से 109 में इसकी संशोधन प्रणाली

का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार चार्टर की किसी भी धारा में संशोधन करने के लिये साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत के अलावा सुरक्षा के पांच स्थायी सदस्यों सहित सात सदस्यों का एकमत होना आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता नहीं छोड़ सकता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की मुख्य समितियाँ :—

उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधीन मानव के कल्याण व विकास के लिये निम्न समितियाँ कार्य कर रही हैं :—

1. यूनेस्को
2. खाद्य एवं कृषि संगठन
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन
4. अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन
5. अन्तर्राष्ट्रीय बैंक आदि।

1. यूनेस्को—संयुक्त राष्ट्रसंघ के शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन को यूनेस्को कहा जाता है। विश्व के राष्ट्रों में शिक्षा और विज्ञान की प्रगति के लिये नवम्बर, 1946 ई० में इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसका कार्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के गैर सदस्य राष्ट्र भी इसके सदस्य बन सकते हैं। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के द्वारा मानवीय एवं मौलिक अधिकारों के प्रति आदर की भावना का विकास करता है। इस संगठन के प्रमुख कार्य निम्न-लिखित हैं :—

1. मैक्सिको में शिक्षा के एक केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसका कार्य शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की उन्नति एवं विश्व समुदाय में रहने की शिक्षा प्रदान करना है।
2. सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत यह संगठन सभा, सम्मेलन और विचार गोष्ठियाँ आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त साहित्य का प्रकाशन भी करवाता है।
3. यह संगठन सामूहिक ज्ञान का प्रचार फिल्म, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों और पुस्तकों आदि के माध्यम से करता है।
4. यह संगठन तकनीकी सहायता भी देता है ट्रिपोली में स्त्रीविद्या के निवासियों को शिक्षा देने के लिये एक टेक्नीकल शिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।
5. विज्ञानों का आदान-प्रदान करता है।
6. प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के लिये प्रयास

यह संगठन विश्व शांति की स्थापना एवं मानववाद के विकास में महत्वपूर्ण भाग ले रहा है।

2. खाद्य एवं कृषि संगठन—यह संगठन विश्व के देशों की खाद्य और कृषि अवस्था में सुधार करने के लिये महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। 1942 ई० में अमेरिका के खाद्यान्न का उपयोग करने के लिये इंग्लैण्ड और अमेरिका की एक समिति गठित की गई थी। अमेरिका ने 1943 ई० में हाट स्प्रिंग्स में एक कृषि सम्मेलन बुलाया। इसमें नियुक्त समिति की सिफारिशों पर खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई। अकाल पीड़ित देश को यह संगठन अनाज भेजता है।

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन—7 सितम्बर, 1948 ई० को विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींव रखी गई। इस संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. संघ के सदस्य राष्ट्रों में संक्रामक रोगों को नष्ट करना।
2. मनुष्य को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिये प्रयास करना।

4. अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—विश्व के देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास करने के लिये 1944 ई० में एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया। यह बैंक अपने सदस्यों को उनके आर्थिक विकास के लिये ऋण प्रदान करता है। इसके सदस्य राष्ट्र के दूसरे देश से ऋण लेने पर यह उसकी जमानत देता है। अपने सदस्य राष्ट्रों को उनके आर्थिक विकास के लिये सलाह भी देता है। वास्तव में इस बैंक ने सदस्य राष्ट्रों के विकास के लिये काफी सहयोग दिया है।

राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ की तुलना—

यद्यपि राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना शान्ति और सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर की गई थी परन्तु राष्ट्रसंघ असफल रहा। संयुक्त राष्ट्रसंघ भी अपने उद्देश्यों में पूर्णरूप से सफल तो नहीं हो पा रहा है परन्तु फिर भी इसकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इन दोनों में काफी समानता होते हुए भी निम्नलिखित असमानताएँ भी हैं—

1. राष्ट्रसंघ के चार्टर में 26 धाराएँ थी जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में 111 धाराएँ हैं।
2. राष्ट्रसंघ पराजित राष्ट्रों के साथ की गई संधियों का एक अंग था जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ का युद्धोत्तर संधियों से कोई सम्बन्ध नहीं है।
3. अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था इसके अतिरिक्त पराजित राष्ट्रों को भी संघ का सदस्य नहीं बनाया गया था जबकि आज लगभग सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं।
4. राष्ट्रसंघ के साधारण सभा, सुरक्षा परिषद् और सचिवालय तीन अंग थे, जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के 6 अंग हैं।

5. राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक थी, जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में 2/3 बहुमत से निर्णय लिये जाते हैं।
6. राष्ट्रसंघ सिर्फ आधिक प्रतिबन्ध ही लगा सकता था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ आधिक प्रतिबन्ध लगाने के साथ-साथ सैनिक कार्यवाही भी कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपलब्धियाँ :—

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना को 35 वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि में इस संघ के सामने अनेक राजनीतिक और गैर राजनीतिक समस्याएँ आईं, जिनको संघ ने हल करने का हर सम्भव प्रयास किया। संघ को जितनी सफलता गैर राजनीतिक कार्यों में प्राप्त हुई है उतनी राजनीतिक कार्यों में नहीं।

ईरान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को शिकायत की कि युद्ध काल की समाप्ति के पश्चात् भी रूस अपनी सेनाएँ वहाँ से नहीं हटा रहा है। पश्चिमी राष्ट्रों ने ईरान का समर्थन किया। इस पर संयुक्त राष्ट्रसंघ ने रूस पर दबाव डाला कि वह अपनी सेनाएँ ईरान से हटावे। फलस्वरूप उसने अपनी सेनाएँ ईरान से हटा लीं। इसी प्रकार सीरिया और लेबनान से इंग्लैण्ड और फ्रांस को अपनी सेनाएँ हटानी पड़ी।

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् रूस ने यूनान में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। रूस के इशारे पर साम्यवादी देश अल्बानिया, बल्गेरिया और युगोस्लाविया ने यूनान के साम्यवादी छापामारों को सहायता देना प्रारम्भ कर दिया। यूनान ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिये संघ से शिकायत की। संघ ने जांच के दौरान यूनानी शिकायत को सही पाया। इस पर संघ ने साम्यवादी देशों को यूनानी छापामारों की सहायता बंद करने का आदेश दिया। संघ को फिलीस्तीन की समस्या हल करने के लिये काफी परिश्रम करना पड़ा। जैसे ही ब्रिटिश सेना ने फिलीस्तीन को स्वतन्त्र देश घोषित कर दिया। इस पर अरब देशों ने अपनी सेनाएँ वहाँ भेज दी। इस प्रकार दोनों पक्षों में घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया। संघ की मध्यस्थता ने कारण युद्ध बन्द हो गया लेकिन यह समस्या आज तक बनी हुई है। यद्यपि 1948 ई० में ही संघ ने इजराइल को स्वतन्त्रता दिलावादी थी, तथापि संघ के द्वारा फिलीस्तीन का दो बँटवारा किया गया था जमके प्रति दोनों पक्षों में अमंजोर होने के कारण आज भी वहाँ अस्थिर है।

1949 ई० में संघ ने इन्डोनेशिया को स्वतन्त्रता दिलाई। द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व इन्डोनेशिया पर हॉलैण्ड का अधिभार था। युद्ध के दौरान जापान ने इस प्रदेश पर अधिभार कर लिया था। जापानी सेना के वहाँ से हटने ही इन्डोनेशिया ने स्वतन्त्रता की घोषणा करने का प्रयास किया तो दोनों ने बीच में प्रारम्भ

गया। संघ के प्रयासों से दोनों के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार इण्डोनेशिया को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई।

15 अगस्त, 1947 ई० को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। काश्मीर पर अधिकार करने के प्रश्न को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इस समय काश्मीर पर हिन्दू शासक शासन कर रहा था जबकि यहां की अधिकांश जनता मुस्लिम थी। काश्मीर का शासक भारत और पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था अपितु वह एक स्वतन्त्र शासक की तरह शासन करना चाहता था। पाकिस्तान को उसकी यह नीति पसन्द नहीं आई। इसलिये उसने पश्चिमी क्वाइलियों को काश्मीर पर आक्रमण करने के लिये सहायता दी। इससे उत्साहित होकर क्वाइलियों ने काश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ऐसे समय में काश्मीर शासक ने भारत में सम्मिलित होने की घोषणा की और उसने भारत से सहायता देने की मांग की। इस पर भारत ने अपनी सेना काश्मीर के शासक की सहायता के लिये भेजी। भारत ने पाकिस्तान से यह अनुरोध किया कि वह क्वाइलियों को सहायता न दे और उन्हें काश्मीर की सीमा से हटने के लिये आदेश दे परन्तु पाकिस्तान ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अब पाकिस्तान उन क्वाइलियों को अधिक से अधिक सहायता देने लगा। इस पर भारत ने सुरक्षा परिषद् से इस समस्या को हल करने के लिये अनुरोध किया। संघ की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच युद्ध बन्द हो गया। इसके पश्चात् संघ ने इस समस्या को हल करने के लिये कई प्रयास किये परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। यह प्रश्न अभी तक संघ के विचाराधीन है। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।

संघ को कोरिया के प्रश्न को हल करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् उत्तरी कोरिया में साम्यवादी शासन और दक्षिणी कोरिया में प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना हुई। जून, 1950 ई० में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में संघर्ष प्रारम्भ हो गया। सुरक्षा परिषद् ने उत्तरी कोरिया को आक्रामक राष्ट्र मानते हुये उसे दक्षिण कोरिया से सेना हटाने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन न करने पर संघ ने सदस्य राज्यों से सेना एकत्रित कर कोरिया में भेज दी। इस पर संघ की सेना और उत्तरी कोरिया की सेना के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। प्रारम्भ में उत्तरी कोरिया की सेना को काफी सफलताएँ मिली क्योंकि साम्यवादी चीन उसकी सहायता कर रहा था। परन्तु अन्त में संघ की सेना ने उत्तरी कोरिया की सेना को युद्ध में घुरी तरह पराजित किया। इसके पश्चात् उत्तरी कोरिया की सेना को दक्षिण कोरिया की सीमा से हटा दिया गया। 1953 ई० में युद्ध विराम समझौता हो गया। इस प्रकार संघ ने अपने आदेश का पालन करवाने के लिये सैनिक कार्यवाही की। संघ ने 1951 ई० में लीबिया को स्वतन्त्रता दिलवाई।

संयुक्त राष्ट्र संघ

1956 ई० में स्वेज नहर के प्रश्न को लेकर इंग्लैण्ड और फ्रांस ने मित्र पर आक्रमण कर दिया। संघ ने शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या को हल किया। रूस हंगरी में दमन चक्र चला रहा था। इस पर हंगरी ने संघ से शिकायत की। संघ ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की। 1954 ई० में संघ को मित्र और लेबनान के आपसी विवाद को नियंत्रित करने में सफलता मिली।

इरियन द्वीप समूह के प्रश्न को लेकर इंग्लैण्ड और इण्डोनेशिया में विवाद प्रारम्भ हो गया। संघ ने इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया। कांगो-कॅटंगा की समस्या को हल करने में भी संघ को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। ब्यूवा के प्रश्न को लेकर रूस और अमेरिका में युद्ध की नींवत आ गई। संघ के प्रयासों से यह युद्ध टल गया। भारत-पाकिस्तान संघर्ष, अरब-इजराइल संघर्ष आदि अनेक मामलों में संघ को युद्ध-विराम सीमित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। परन्तु कोरिया की समस्या, काश्मीर की समस्या अरब-इजराइल समस्या, दक्षिणी अफ्रीका में रंग-भेद नीति आदि कई समस्याओं पर संघ को युद्ध-विराम के वाद कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ये समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ को उपनिवेशवाद समाप्त कराने में आशातीत सफलता मिली है। संघ ने इण्डोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया व अल्जीरिया आदि देशों को स्वतन्त्रता दिलवाई। इसके अतिरिक्त संघ की संरक्षण पद्धति के अन्तर्गत प्रशासित अधिकांश प्रदेशों को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई है। संघ अफ्रीका में बचे साम्राज्यवादी उपनिवेशों को स्वतन्त्रता दिलाने के लिये हर समभव प्रयास कर रहा है। संघ ने निःशस्त्रीकरण के लिये काफी प्रयास किया है और आज भी शस्त्रों के निर्माण को रोकने का प्रयास कर रहा है।

संघ को मानव अधिकारों की रक्षा, मानवीय संघ एवं कल्याण के कार्यों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। इतने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में साराहनीय कार्य किया है। उसके अधीन खाद्य एवं कृषि मंडलन ने विश्व के देशों को उत्पादन बढ़ाने में हर समभव सहयोग दिया है। विश्व के देशों को अकाल और भूखमरी से बचाया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मजदूरों के जीवन-स्तर को उन्नत करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। उमकी प्रेरणा से विश्व के विभिन्न देशों ने मजदूरों की सुरक्षा और उनके जीवन-स्तर को उन्नत बनाने के लिये अनेक कानून पास किये हैं। स्वास्थ्य संगठन ने संक्रामक रोगों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। यूनेस्को ने शिक्षा और सस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाल आगत बालीन कोष ने विश्व के बच्चों की सुरक्षा के लिये अनेक साराहनीय कार्य किये हैं। हम प्रकार संघ ने विश्व को सुखी एवं समृद्ध बनाकर अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की दुर्बलताएँ :—

संयुक्त राष्ट्रसंघ अपनी दुर्बलताओं के कारण अपने कार्यों में अधिक सफलताएँ प्राप्त नहीं कर सका है। उसे युद्ध के खतरे को कम करने में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। संघ की असफलता का कारण उसकी निम्नलिखित दुर्बलताएँ हैं :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव कम नहीं होने का प्रमुख कारण यह है कि विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो गुटों में विभाजित हैं। पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट का नेतृत्व रूस कर रहा है, जबकि पश्चिमी गुट का अमेरिका। इन दोनों गुटों में मतभेद होने से प्रत्येक साधारण प्रश्न भी गुट की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। इसलिये हर समय यह भय बना रहता है कि पता नहीं कब विश्व-शांति भंग जाय। दोनों ही गुट अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिये शस्त्रों में वृद्धि कर रहे हैं। अमेरिका और रूस में आज अणु बम और हाइड्रोजन बम बनाने की होड़ लगी हुई है। इस होड़ के कारण गुटबन्धियाँ बढ़ती जा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, हालैण्ड, पुर्तगाल, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नार्वे आदि देशों ने साम्यवाद के विरुद्ध एक सैनिक सगठन बनाया है जिसे उत्तरी एटलांटिक संधि संघ (N A T O) कहा जाता है। इस संघ का उद्देश्य साम्यवाद का विरोध करना है और उसके प्रसार को रोकना है। पश्चिमी देशों ने यह सगठन रूस के विरुद्ध बनाया है। रूस ने इसके उत्तर में पूर्वी यूरोप के देशों का एक सगठन बनाया है जिसे "वारसा पैक्ट" कहा जाता है। अमेरिका एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिये पिछड़े हुए देशों को आर्थिक सहायता दे रहा है। उसने ईरान, ईराक और तुर्की के साथ बगदाद पैक्ट कर रखा है, ताकि वहाँ पर साम्यवाद का प्रसार नहीं हो सके। इन संधियों के कारण गुट बन्धियों ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इसीलिये संयुक्त राष्ट्रसंघ को किसी भी समस्या को सुलझाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विश्व के बड़े राष्ट्रों को संघ के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं है। इसलिये संघ अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा है। शीत युद्ध से विश्व की शांति भंग होने का हमेशा भय रहता है। संघ आज तक कई परतंत्र राष्ट्रों को स्वतन्त्रता नहीं दिलवा सका है। यह सब उसकी असफलता का प्रतीक है।

2. संघ में पाश्चात्य देशों का बहुमत होने के कारण वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा है। इसमें पूर्वी गुट की अपेक्षा पश्चिमी गुट अधिक शक्तिशाली है।

3. इस संघ का स्वरूप भी बड़े राष्ट्रों की विजय का प्रतीक है। किसी भी नये राष्ट्र को संघ का सदस्य बनाने के लिये सुरक्षा परिषद् की स्वीकृति आवश्यक है। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य, जो विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र हैं, अपने स्वार्थ

संयुक्त राष्ट्र संघ को ध्यान में रखते हुए इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति देते हैं। यह संघ का एक

बहुत बड़ा दोष है।

4. संघ के पास स्वयं की अन्तर्राष्ट्रीय सेना नहीं है। यद्यपि वह आवश्यकता पड़ने पर सदस्य राष्ट्रों से सेना भेजने के लिये कह सकता है लेकिन सदस्य राष्ट्र सेना भेजने के लिये बाध्य नहीं है। वे इसके लिये इन्कार भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्र अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु ही सेना भेजते हैं। यह संघ के भविष्य के लिये शुभ लक्षण नहीं है। संघ के पास सेना नहीं होने से उसे सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण संघ को अपने आदेशों का पालन करवाने के लिये काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये संघ के पास स्वयं की एक शक्तिशाली स्थायी सेना होनी चाहिये ताकि वह अपने निर्णयों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध उसका उपयोग कर सके।

5. सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्य राष्ट्रों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। जबकि अस्थाई सदस्यों को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार एक स्थायी सदस्य अन्य कई अस्थायी सदस्यों से अधिक शक्तिशाली है। एक भी स्थायी सदस्य यदि किसी भी प्रस्ताव वा विरोध करे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। इससे संघ की काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संघ वीटो के कारण अशक्त है। इसका पिछला इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि स्थायी सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध अपने स्वयं की पूर्ति के लिये वीटो का अधिकाधिक प्रयोग किया है। इस प्रकार परिषद् के स्थायी सदस्य वीटो का दुरुपयोग करते हैं।

6. सदस्य राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना वा अभाव होने के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। सदस्य राष्ट्रों का संघ के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं है। इसलिये वे एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपनी शक्ति पर विश्वास करता है। इसलिये विश्व के सभी राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं और विश्व को अमान्ति के मुख में डबेल रहे हैं।

7. संयुक्त राष्ट्रसंघ महाशक्तियों के संघर्ष का अनाड़ा बना हुआ है। आज विश्व की महान शक्तियों में एक दूसरे के प्रति शंका, भय और अविश्वास की भावनाएँ व्याप्त हैं। संघ के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक समस्या पर वे मानवीय हितों के स्थान पर अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए उगे हल करने का प्रयास करते हैं। इससे संघ की महाशक्तियों का सहयोग नहीं मिल पाता है।

8. संयुक्त राष्ट्र की असफलता का एक कारण यह है कि उसे सदस्य राष्ट्रों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जाम्बिक हस्त-

क्षेप की कोई स्पष्ट परिभाषा चार्टर में नहीं दी गई है इसलिसे बहुत से देश इस धारा का लाभ उठाकर जातीय भेदभाव और आत्म निर्णय सम्बन्धी प्रश्नों को भी आन्तरिक मामला मान लेते हैं और संघ के आदेशों का उल्लंघन करते रहते हैं।

9. संघ की असफलता का एक कारण यह है कि विश्व के बहुत से राष्ट्र इस संघ के सदस्य नहीं हैं। जैसे जर्मनी, कोरिया और वियतनाम अभी तक संघ के सदस्य नहीं बन पाये हैं। साम्यवादी चीन को काफी वर्षों पश्चात् संघ का सदस्य बनाया गया था। इस प्रकार सभी राष्ट्रों के लिये संघ के द्वार खुले नहीं होने के कारण उसे असफलता का सामना करना पड़ रहा है।

10 संघ को अपने खर्चों के लिये सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक अनुदान पर निर्भर रहना भी उसकी असफलता का एक कारण है। जब तक सदस्य राष्ट्रों की आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के अनुकूल कार्य होता रहता है, तब तक वे संघ को आर्थिक सहायता देते रहते हैं। कई बार जब संघ बड़ी शक्तियों की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो वे संघ के कार्यों को प्रभावित करने के लिये उसको आर्थिक सहायता देना बन्द कर देते हैं।

यद्यपि संघ में अनेक दोष हैं फिर भी इस सत्यता को मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि संघ को अब तक कई युद्धों को रोकने में और उन्हें सीमित करने पर बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। इसने शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये हर सम्भव प्रयास किया है। संघ विश्व शांति के लिये एक उपयोगी संस्था है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

